

**DUE DATE SLIP****GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj )

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DTATE	SIGNATURE

# भारत की आर्थिक समस्याएँ

## (Economic Problems of India)

[विक्रम व सागर विश्वविद्यालयों के वी० कॉम० त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स एवं  
अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों के स्वीकृत पाठ्य क्रमानुसार]

प्रथम संस्करण

आगरा

साहित्य भवन

शिक्षा सम्बन्धी साहित्य के प्रकाशक

अन्य उपयोगी प्रकाशन—

- १ कम्पनी अधिनियम एवं सचिवीय पद्धति  
(Company Law & Secretarial Practice)  
लेखक—एस० एम० शुक्ल
- २ भारत में उद्योग लेखक—डा० एस० सी० सक्सेना
- ३ भारतीय व्यापार एवं परिवहन (प्रश्नोत्तर)  
प्राक्खन लेखक—डा० एस० डी० सिंह चौहान

मूल्य सात रुपये मात्र

प्रकाशक—साहित्य भवन

२७३२ मुई कटरा,

आगरा ।

मुद्रक — आगरा पापूलर प्रेस,

मोतीकटरा,

आगरा ।

# भूमिका

प्रारम्भिक :—

वर्तमान युग हमारे देश के लिये 'आर्थिक विकास का युग' है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की आर्थिक समृद्धि के लिए हमने प्रथम पंच-वर्षीय योजना का निर्माण किया, जिसकी सफल पूर्ति सन् १९५५ में हुई। तत्पश्चात्, देश में तीव्र औद्योगीकरण के लिए हमने द्वितीय पंच-वर्षीय योजना का निर्माण किया, जिसके अन्तर्गत कुटीर, लघु एवं विशाल उद्योगों की प्रगति के लिए समन्वित योजनाएँ बनाई गई हैं। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में आज आर्थिक पुनरुत्थान की एक लहर सी दिखलाई पड़ती है। प्रत्येक नागरिक के हृदय में उत्साह है और वह अपने राष्ट्र के निर्माण में तत्पर सा दृष्टिगत होता है। शासकीय एवं नागरिक दोनों ही क्षेत्रों में राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिये आयोजित ङग से कार्य हो रहा है। स्वच्छन्द श्रद्धा करने वाली नदियों को नियन्त्रण में रखकर विकास योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं। सस्ती जल शक्ति प्राप्त करने के लिये बड़ी बड़ी योजनाएँ चल रही हैं। भिलाई, रुर्केला तथा दुर्गापुर के विशालकाय लौह-इस्पात के कारखाने औद्योगिक क्षेत्र में हमारी प्रगति के चोकर हैं। कृषि उत्पादन के बढ़ाने के लिये सहकारी कृषि के विकास पर बल दिया जा रहा है। यातायात के साधनों की भी वृद्धि हो रही है। परन्तु, इतना सब होते हुए भी जन साधारण सुखी नहीं है। कृषि, उद्योग, औद्योगिक भ्रम-प्रबन्धन, आर्थिक नियोजन आदि सभी क्षेत्रों में कुछ न कुछ जलजने हैं। उदाहरण के लिए, कृषि के विकास में भारतीय किसानों की ऋणप्रस्तुता, भूमि का उप विभाजन व अपखण्डन, ग्रामीण साक्षरता आदि से सम्बन्धित अनेक समस्याएँ हैं। सहकारी कृषि का भी बड़े जोरा के साथ विरोध किया जा रहा है। विचारे भूमिरहित कृषकों की भी बड़ी गहन समस्या है, जिसके निवारण के लिये बिना भूदान आन्दोलन में सलग्न हैं। इसी प्रकार भारत के प्रायः सभी संगठित उद्योग, जैसे सूती वस्त्र मिल उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग जूट उद्योग आदि, विवेकीकरण, आधुनिकीकरण, भ्रमभाव आदि समस्याओं से ग्रस्त हैं। जनशक्ति की समस्या भी हमारे देश के लिए एक सिर दर्द है। 'श्रम' का क्षेत्र भी समस्याओं से घाली नहीं है। इन आर्थिक समस्याओं को बिना हल किए हम मनोवांछित आर्थिक विकास नहीं कर सकते। प्रस्तुत पुस्तक में देश की विविध आर्थिक समस्याओं पर गम्भीरता से प्रकाश डाला गया है तथा उनको मुलभूत के लिए किए गए प्रयत्नों व सुझावों की भी विवेचना की गई है।

पुस्तक की उपयोगिता —

"भारत की आर्थिक समस्याएँ" शीर्षक विषय विक्रम व सागर विश्वविद्यालय

को निवर्णीय वाणिज्य वशाओं के लिए अनिवार्य है। निम्न पाठ्य-क्रम के अनुसार अभी तक इस विषय पर कोई भी पुस्तक नहीं थी। विद्यार्थियों को 'भारतीय अर्थशास्त्र' अथवा भारत के आर्थिक विकास से सम्बन्धित पुस्तकों में से आवश्यक सामग्री निकालनी पड़ती थी। उनकी इस कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से ही प्रस्तुत पुस्तक की रचना की गई है। आशा ही नहीं करना पूर्ण विश्वास है कि अब हमारे विद्यार्थियों को इस विषय की सामग्री के हेतु कहीं अन्यत्र भटकना नहीं पड़ेगा वरन् यह एक पुस्तक ही 'कल्पवृक्ष' की भाँति उनकी समस्त आवश्यकताओं की मनुषिणी कर देगी।

प्रस्तुत पुस्तक को सात तन्त्र पुस्तिकाओं में बाँटा गया है — वृषि, उद्योग, औद्योगिक अर्थ प्रवर्धन, भारत की जन-संख्या, भारत में आर्थिक नियोजन की आधुनिक प्रवृत्तियाँ और भारत की श्रम समस्याएँ। प्रथम पाँच पुस्तिकाएँ सागर व विक्रम दोनों ही विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, शेष दो पुस्तिकाएँ केवल विक्रम विश्वविद्यालय के लिए हैं।

**वृत्तिपर्य विशेषताये —**

(I) पुस्तक की रचना अत्यन्त सरल व मुहावरेदार हिन्दी में की गई है।

(II) "भारत सन् १९६०" व अन्य आर्थिक व वाणिज्यिक पत्र-पत्रिकाओं के आधार पर नवीनतम आंकड़ों का समावेश किया गया है।

(III) परीक्षा की दृष्टि से अधिक उपयोगी बनाने के लिए प्रत्येक अध्याय के अन्त में अध्यास के प्रश्न दिए गए हैं तथा पुस्तक के अन्त में सागर व विक्रम विश्वविद्यालयों की सन् १९६० की परीक्षा के प्रश्न-पत्र भी दे दिए गए हैं।

(IV) पुस्तक के प्रारम्भ में विक्रम व सागर विश्वविद्यालयों का सन् १९६१ की परीक्षा के हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम भी दिया गया है।

**आभार प्रदर्शन —**

प्रस्तुत पुस्तक की रचना में अनेक प्रमाणिक पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं एवं विशेषज्ञों में पर्याप्त सहायता मिली है जिनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना मे अपना कर्तव्य समझता हूँ। पाण्डुलिपि के लेखन में श्री एम० एम० धारोवाल ने जो सहयोग दिया है उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

सुभाष के हेतु मेरा सबको निमन्त्रण है।

आनन्द निवास,  
जेश्वर परेड,  
ग्यानिधर।

एस० सी० सक्सेना

# SYLLABUS OF THE VIKRAM UNIVERSITY

(For B Com Part II of the Three Years Degree Course)

## ECONOMIC PROBLEMS OF INDIA

### 1 AGRICULTURE

Causes of Rural indebtedness Causes and evils of subdivision and fragmentation of holdings Consolidation of holdings with special reference to M P Co-operation Co-operative Farming , Rural Finance Community Projects

### 2 INDUSTRIES

A brief survey of the following industries

1 Cotton textile

2 Sugar ,

3 Iron and Steel and

4 Jute

Problems of Industrial Finance

### 3 TRADE UNION MOVEMENT IN INDIA

Indian Labour problems

### 4 RECENT TRENDS IN ECONOMIC PLANNING IN INDIA

### 5 INDIA S POPULATION PROBLEM

# SYLLABUS OF THE SAUGAR UNIVERSITY

(For B<sup>o</sup>Com Preliminary)

## ECONOMIC PROBLEMS OF INDIA

### 1 AGRICULTURE

Causes of Rural indebtedness A brief survey of important legislative measures against this evil, Sub division and fragmentation of Holdings, Consolidation of Holdings with special reference to M P Rural Finance—Short and long term Co operative Societies The problem of rural finance Problems of landless labour Community projects

### 2 INDUSTRIES

A brief survey of the following Indian Industries

- 1 Cotton ,
- 2 Iron and Steel ,
- 3 Sugar ,
- 4 Jute , and
- 5 Coal

Problems of Industrial Finance

### 3 GROWTH OF POPULATION IN INDIA AND ITS PROBLEMS

# विषय-सूची

अध्याय

:

पृष्ठ

## प्रथम भाग

### प्रथम पुस्तिका-परिचय

१	विषय प्रवेश	१
---	-------------	---

### द्वितीय पुस्तिका-कृषि

२	भारतीय कृषि-व्यवस्था में कृषि का महत्व ...	६
३	कृषि की श्रृंखला प्रस्तुत ...	१३
४	उप विभाजन तथा अपसंडन के कारण, परिणाम तथा उपाय .	२८
५	प्राचीन कृषि	५०
६	सहकारिता	६४
७	सहकारी कृषि	८५
८	भूमिरहित कृषि की समस्याएँ व भूदान आंदोलन	११७
९	सामुदायिक विकास योजनाएँ	१३३

## द्वितीय भाग

### तृतीय पुस्तिका-उद्योग

१०	भारत का सूती वस्त्र उद्योग	१
११	भारतीय जूट उद्योग	१२
१२	भारतीय लोह एवं इस्पात उद्योग .	२४
१३	भारतीय चीनी उद्योग	३६
१४.	भारतीय कायला उद्योग	४४

### चतुर्थ पुस्तिका-औद्योगिक अर्थप्रबन्धन

१५	औद्योगिक अर्थप्रबन्धन की समस्याएँ	५१
१६	औद्योगिक अर्थप्रबन्धन के लिए विनिष्ट सस्याएँ I	७३
१७	औद्योगिक अर्थप्रबन्धन के लिए विनिष्ट सस्याएँ II	८०



पंचम पुस्तिका-भारत का जन-संख्या

१८	भारत में जन संख्या का वितरण का समस्या	१०३
१९	क्या भारत में जन-संख्या का आधिक्य है ?	११३
२०	परिवार नियोजन	११८

षष्ठम् पुस्तिका-भारतीय श्रम समस्याएँ

२१	भारत में श्रम संघ आन्दोलन	१२२
२२	हमारी कुछ प्रमुख श्रम समस्याएँ I	१३४
२३	हमारी कुछ प्रमुख श्रम समस्याएँ II	१४४

सप्तम पुस्तिका-भारत में आर्थिक नियोजन की आधुनिक प्रवृत्तियाँ

२४	प्रथम पंच वर्षीय योजना	१७२
२५	द्वितीय पंच वर्षीय योजना	१७८
२६	तृतीय पंच-वर्षीय योजना	१८६

परीक्षा प्रश्न वर्ष १९६०

I नागर विन्वविद्यालय

II विनम विन्वविद्यालय

## अध्याय १

# विषय-प्रवेश

## (Introduction)

### प्रारम्भिक—

वर्तमान युग में 'अर्थशास्त्र' के अध्ययन का महत्व दिन प्रति दिन बढ़ता ही जा रहा है। अर्थशास्त्र के अध्ययन के द्वारा हम मानव के आर्थिक जीवन से सम्बन्धित अनेक विद्वानों का प्रतिपादन करते हैं, किन्तु अर्थशास्त्र का महत्व केवल मानव जीवन की आर्थिक पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में अनेक विद्वानों के प्रतिपादन मात्र में ही नहीं है, बल्कि इस कारण भी अधिक है कि इनके द्वारा हम अपने दैनिक व्यावहारिक जीवन की जटिल से जटिल समस्याओं को सुलभाने में समर्थ होते हैं। प्रत्येक देश में कालान्तर से ही नवीन परिस्थितियों के पत्रस्वरूप नवीन समस्याएँ उत्पन्न होती रही हैं। आधुनिक युग के मानव की आवश्यकताएँ चाहे कितनी ही गण्य व सरल रही हो, उसने लिए भी आर्थिक समस्याएँ प्रवृद्ध रही होंगी और उसने उन पर अपने ढंग से विचार भी किया होगा। फिर जैसे-जैसे मनुष्य का बौद्धिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास होता गया, उसकी आर्थिक, समस्याओं का स्वरूप भी परिवर्तित होता गया। आधुनिक वैज्ञानिक युग में भी जबकि हम चन्द्रशेखर की यात्रा के लिए प्रयत्नशील हैं, आर्थिक समस्याओं का अभाव नहीं है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका व रूस जैसे उन्नतिशील औद्योगिक राष्ट्र भी अनेक आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, फिर भारत जैसे अर्द्ध-विकसित राष्ट्र के लिए क्या कहा जाय। अर्थशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य इन आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए उपयुक्त उपाय प्रस्तुत करना है, जिससे देश एवं मानव समाज का अधिकतम भौतिक कल्याण हो सके। 'भारत की आर्थिक समस्याओं' के अध्ययन का भी यही उद्देश्य है।

वर्तमान युग हमारे देश के लिए आर्थिक विकास का युग है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत की आर्थिक समृद्धि के लिए हमने प्रथम पंच-वर्षीय योजना का निर्माण किया, जिसकी सफल पूर्ति सन् १९५५ में हुई। तत्पश्चात् देश में तीव्र औद्योगीकरण के लिए हमने द्वितीय पंच-वर्षीय योजना का निर्माण किया, जिसके अन्तर्गत कुटीर लघु एवं विराट उद्योगों की प्रगति के लिए समन्वित योजनाएँ बनाई गई हैं। भारत

के प्रत्येक क्षेत्र में आज आर्थिक पुनरुत्थान की एक लहर भी दिखनाई पड़ता है। शामकीय एवं नागरिक दोनों ही क्षेत्रों में राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए आयोजित ढंग में कार्य हो रहा है। स्वच्छन्दरीड करन वाली नदियाँ को नियंत्रण में रखकर विकास योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं। सगती जल शक्ति प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएँ चल रही हैं। भिलाई, रूरकेला व दुर्गापुर के विशाल उद्योगों में नोहा उगलना शुरू कर दिया है। यानायन के साधनों की भी वृद्धि हो रही है। कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सहकारी कृषि पर बल दिया जा रहा है इत्यादि। परन्तु उतना सब होसकता है भी जन साधारण सुखी नहीं है। कृषि, उद्योग औद्योगिक प्रयत्न प्रबन्धन आर्थिक नियोजन आदि सभी क्षेत्रों में कुछ न कुछ उलझते हैं। उदाहरण के लिए कृषि के विकास में भारतीय किसानों की श्रम प्रवृत्ति, भूमि का उप विभजन व अपसंयोजन, ग्रामीण साक्षरता आदि से सम्बन्धित घने समस्याएँ हैं। सहकारी कृषि का भी बड़े जोरों के साथ विरोध किया जा रहा है। विचारें भूमि रक्षक कृषकों की भी बड़ी दयनीय दशा है। इसी प्रकार भारत के प्रायः सभी सगठित उद्योग, जैसे मूनी वस्त्र मिल उद्योग लोह एवं इस्पात उद्योग पट उद्योग, आदि बँकानिष्ठ, आधुनिकीकरण प्रयत्न आदि समस्याओं में घुसने हैं। जनअधिकारी की समस्या भी हमारे आर्थिक विकास में बाधक सिद्ध हो रही है। इन समस्याओं के निवारणार्थ हम तृतीय पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने जा रहे हैं। आज हमको एक युग का निर्माण करना है एक नई आजाद का संचार करना है, प्रथमवा यों कहिए कि हमें देश में एक प्रगतिशील आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करना है किन्तु आर्थिक समस्याओं की पूर्ण जानकारी के अभाव में देश में प्रगतिशील आर्थिक व्यवस्था का निर्माण पूर्णतया असम्भव है।

आज से २५-३० वर्ष पूर्व जब हम में पंचवर्षीय योजना का अंगणेश किया गया था, उस समय वहाँ के नागरिकों में उत्साह और आनन्द की एक नई लहर व नई उमंग पैदा हो गई थी। सारा देश पंचवर्षीय योजना चार वर्ष में पूरी करो के नारे से गुंजायमान हो उठा था। हम का प्रत्येक पुत्र, प्रत्येक महिला, यहाँ तक कि छोटे-छोटे बालक व बूढ़—सभी उस योजना को पूर्ण करने में अपना अपना योग देने लगे थे। इसी प्रकार समुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी प्रेसीडेंट रुजवेल्ट ने घोर आर्थिक संकट के दिनों में जब देश से अपेक्षा की थी कि 'त्रैका में राशि जमा करो' तब मारे देश में उत्साह की नई लहर दौड़ गई थी। समस्त देश ने आर्थिक संकट की अवधि को हसते हसते पार कर लिया था। इन दोनों उदाहरणों में वहाँ की सफलता का रहस्य छिपा है। सफलता का एक मात्र कारण था जनता का अर्थसमस्याओं के प्रति अकेले होता और अरकाट के अर्थ देने में आनन्द रहना। अतः स्पष्ट है कि किसी देश की आर्थिक समृद्धि केवल सरकार के बनाए गए कानूनों अथवा आर्थिक योजनाओं पर भी निर्भर नहीं करती। वह निर्भर करती है जनता के उत्साहपूर्ण सहयोग पर। परन्तु जनसाधारण का सहयोग तब तक प्राप्त

वाले उपायों के विश्लेषण को समष्टि रूप से हम 'भारतीय चर्चशास्त्र' से अभिहित कर सकते हैं। यह राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देश की आर्थिक स्थिति का अध्ययन है।

**विषय का क्षेत्र—**

भारत की आर्थिक समस्याओं के अध्ययन का क्षेत्र अत्यन्त ही व्यापक है। भूतकाल में हमारे देश का आर्थिक कलेवर कसा या वर्तमान युग में उसमें कहा तक सुधार हो सका है एक भविष्य में आर्थिक विकास किस प्रकार होता है, इन सब बातों का विषय विवेचन ही भारतीय आर्थिक समस्याओं के अध्ययन का क्षेत्र है। विश्व के अन्य सभी देशों की भाँति भारत का आर्थिक कलेवर भी अनेक मीढ़ियों के पार करने के बाद वर्तमान स्थिति पर पहुँचा है। भारत की आर्थिक समस्याओं के अन्तर्गत हम देश के प्राचीन आर्थिक संगठन, उसके पश्चात् हुए परिवर्तन तथा उन परिवर्तन के परिणामों का विश्लेषण करते हैं। किन्तु हमारा क्षेत्र यही समाप्त नहीं हो जाना। प्रथम विश्व युद्ध से लगाकर सन् १९२६-३० की विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी द्वितीय विश्व युद्ध और इसके बाद तक की आर्थिक प्रगति की प्रत्येक समस्या का अध्ययन एवं विश्लेषण हमारे अध्ययन का क्षेत्र है।

१५ अगस्त सन् १९४७ के पूर्व लगभग डेढ़ सौ वर्षों तक हम दासता की गृहस्थता में जकड़े रहे। यदि राज्य की आर्थिक नीति हमारे प्रतिबल न होती तो सम्भव था कि हम उस युग में ही कहीं आगे बढ़ गये होते। प्रथम महाभारत के पूर्व तक हमारे देश में मुख्यतः वस्त्र मिल उद्योग, जूट उद्योग एवं चाय उद्योग ही बृहत् स्तर पर स्थापित हो सके थे। युद्ध के बाद स्वर्गीय बापू के स्वदेशी आन्दोलन एवं औद्योगीकरण की मांग के फलस्वरूप राजकीय नीति में कृत्रिम परिवर्तन हुआ और कुछ उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया गया। संरक्षण की गोद में लौह एवं इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग वायज उद्योग दिशमलाई उद्योग आदि ने विद्येय प्रगति की। तत्पश्चात् सन् १९२६-३० की विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी में भारतीय कृषि एवं उद्योग दोनों के ही पैर लड़खलाने लगे। सन् १९३६ के द्वितीय विश्व युद्ध ने औद्योगीकरण के क्रम को पुनः प्रोत्साहित किया। अत्यधिक मांग को पूरा करने के लिए अनेक उद्योग-धंधे स्थापित किये गये। मुद्रा की कमी का स्थान मुद्रा-स्फीति ने ले लिया। वस्तुओं के मूल्य गगन-चुम्बी स्तर तक पहुँचने लगे। परिणाम यह हुआ कि कृषकों की आर्थिक दशा भी कुछ सुधरी एवं उनकी ऋणग्रस्तता कम हो गई। विदेशी वस्तुओं के आयात में कठिनाई के कारण अनेक छोटी-मोटी चीजों का निर्माण देश में ही होने लगा जैसे—सिलाई की मशीनें साइकिलें विजली का सामान, रेडियो, सेट, फरीलों के फुर्के, दूरदर्शक।

१५ अगस्त सन् १९४७ की अर्द्ध रात्रि के बाद भारत के आर्थिक विकास में एक नये युग का प्रारम्भ हुआ। ब्रिटिश शासन काल में आर्थिक क्षेत्र में हमने जो प्रगति की वह ब्रिटेन के स्वार्थ के कारण नगण्य थी—उसमें भारतीय जन समाज का

नहीं वरन् ब्रिटेन अथवा भारत के ही किंचित व्यक्तियों की लाभ हुआ। स्वतन्त्रता के समय भारत के आर्थिक संगठन में किंचित अछूताइयों के साथ हमें अनेक बुराईया भी उत्तराधिकार में मिली। आर्थिक समस्याओं की एक बाढ़ सी आ गई, जैसे—खाद्य समस्या, रिस्थापिता की समस्या, मुद्रा-स्थिति एवं मूल्य वृद्धि की समस्या, यातायात एवं संचारवाहन के साधनों की कमी, भूमि सुधार की समस्या, इत्यादि।

उपरोक्त समस्याओं के निवारणार्थ हमारी जन-प्रिय सरकार ने 'योजनाकरण' का आश्रय लिया। यह प्रथम अवसर था, जबकि देश की आर्थिक प्रगति के निम्ने, पूर्ण नियोजित लक्ष्यों को लेकर हम आगे बढ़े। योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत भारत की प्रथम पंच-वर्षीय योजना हमारी आर्थिक समस्याओं का सर्वश्रेष्ठ विस्तरेण है और देश की भावी आर्थिक विकास की एक सुन्दर रूप-रेखा है। इसका प्रधान उद्देश्य भारत का प्राकृतिक प्रमाधना के समुचित उपयोग एवं बढ़े हुए उत्पादन द्वारा जनता के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना है। कुछ क्षेत्रों में तो हमने योजनानुसार अपने नियोजित लक्ष्यों से अधिक सफलता प्राप्त कर ली है। आजकल हमारी द्वितीय पंच-वर्षीय योजना, जिसका प्रधान उद्देश्य देश का औद्योगिक औद्योगीकरण करना है, दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति से कार्यान्वित की जा रही है। आजकल तृतीय पंच-वर्षीय योजना की तैयारियाँ भी बड़े जोरों के साथ हो रही हैं। ये योजनाएँ हमारी भावी आर्थिक प्रगति की आधारस्तम्भ हैं।

इस प्रकार ये सब भूत, वर्तमान एवं भावी आर्थिक समस्याएँ ही हमारे अध्ययन का क्षेत्र हैं। परन्तु हमारा अध्ययन यहाँ पर ही समाप्त नहीं हो जाता। हमको विभिन्न समस्याओं के कारणों का विस्तरेण करके उनके हल करने के उपायों का अध्ययन करना होगा तथा उनको हल करने के लिए जो भी आर्थिक नीति अपनाई गई हो अथवा अपनाई जा रही हो, उसकी भी उपयोगिता देखनी होगी। इस प्रकार भारत की आर्थिक समस्याओं का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक विस्तृत एवं बहुत्वपूर्ण है।

**विषय का महत्व—**

"भारत की आर्थिक समस्याओं" के अध्ययन के जितने भी गुण पाए जाएँ कम ही होंगे। भारत की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन केवल सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से ही नहीं, वरन् व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। निम्न बातों से इस विषय के अध्ययन की उपयोगिता स्पष्ट हो जाती है—

(१) देश की धीमी आर्थिक प्रगति के कारणों का ज्ञान करने के लिए— हमारा देश प्रत्येक दृष्टिकोण से अत्यन्त घनाङ्ग है। भौगोलिक दृष्टि से हमारी स्थिति सर्व श्रेष्ठ है। हमारे मिर पर हिमालय का ताज है, जो राजनीतिक एवं भौगोलिक दृष्टि से हमारी रक्षा करता है। देश के वसस्थल पर गया, यमुना और ब्रह्मपुत्र अपने विस्तृत परिवार सहित बहती हैं और उनका यह क्रीडा स्थल अत्यन्त उर्वरा भूमि के कारण अनाज का विशाल भण्डार है। दक्षिण का प्राचीनतम

(४) देश की सही आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक मूल्यांकन—भारत की आर्थिक समस्याओं के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण लाभ यह भी है कि हम विश्व का मनन परिवर्तनशील परिस्थितियाँ में भारत की आर्थिक स्थिति का सही अनुमान लगा सकते हैं। वर्तमान युग में सभी राष्ट्र एक दूसरे के इतने निकट आ गए हैं कि किसी भी देश की नई आर्थिक घटना में हम अछूत नहीं रह सकते। आधुनिक युग में हमारे लिए यह आवश्यक हो गया है कि विश्व के विभिन्न देशों की तुलना में हम भारत की वर्तमान आर्थिक स्थिति का सही-सही मूल्यांकन कर सकें जिससे कि देश की आर्थिक प्रगति के लिए किसी देश में कुछ सीखना हो, तो निमकोच होकर ऐसा कर सकें।

(५) योजना-निर्माणकर्तारों के लिए सहृदय—जब तक हमको किसी देश की विगत एवं वर्तमान आर्थिक समस्याओं का समुचित ज्ञान न हो, तब तक हम भावी विकास के लिये योजनाएँ नहीं बना सकते। जब तक हम अपने देश के कृषक उद्योगपतियों व्यापारियों, श्रमजीवियों एवं जन साधारण की आर्थिक समस्याओं का हल न करें तब तक हम उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में सफल नहीं हो सकते। कृषकों की दशा को सुधारने के लिए उनकी वर्तमान परिस्थिति से परिचित होना आवश्यक है और इसी प्रकार श्रमजीवियों के जीवन-स्तर में वृद्धि करने के लिए उनकी वर्तमान गृह दशा, काम के घण्टे मजदूरी और महंगाई की दर कारगराने में दी जाने वाली सुविधाएँ, श्रम-गण, श्रम सम्बन्धी मन्त्रियत राज्य की औद्योगिक नीति का ज्ञान होना अनिवार्य है। जिस लोग के हाथ में राज्य की चाँकड़ी है, जैसे हमारे मन्त्रीगण लोक सभा एवं राज्य सभा के सदस्य आदि—यदि इन्हें भारत की आर्थिक दशाओं और समस्याओं का भली प्रकार न ज्ञान होगा तो वे जन साधारण की दशा सुधारने के लिए मन्त्रियत बर्गे बना सकेंगे। भोजन एवं वस्त्र की समस्या दृष्टि और निश्चयता दूर करना कृषि सुधार और जन हित की योजनाएँ सब कुछ भारतीय धर्मशास्त्र के अध्ययन पर निर्भर है जिसके बिना देश का आर्थिक पुनरुत्थान नहीं हो सकता।

(६) जन सहयोग एवं राष्ट्रीय कल्याण के लिए अध्ययन आवश्यक है—स्वतन्त्रता के उपरान्त अपने देश के आर्थिक विकास का उत्तरदायित्व स्वयं हमारे कंधों पर पड़ा गया। अब हम अपनी दुर्बलता के लिए किसी अन्य व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकते। स्वयं अपनी समस्याओं का अध्ययन करके देश के आर्थिक पुनर्निर्माण में हमें सहयोग देना चाहिए। हमारी सरकार समय-समय पर कृषि, उद्योग व्यापार, यातायात एवं जन नीति में संशोधन करती रहती है। सरकार की मिश्रित आर्थिक नीति एवं तत्परवान् घोषित समाजवादी ढाँचा हमारे भावी आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन की ओर सकेत करते हैं। इन सब परिवर्तनों का प्रायः प्रत्येक नागरिक पर प्रभाव पड़ेगा, अतः हम सबका यह कर्तव्य हो जाता है कि देश के भावी

आर्थिक संगठन में अपनी व्यक्तिगत स्थिति का मूल्यांकन कर जिससे कि भारत आर्थिक पुनर्स्थान में सक्रिय सहयोग प्रदान कर सके ।

### Standard Questions

- (1) What do you understand by the term 'Economic Problems.'  
Discuss the meaning and scope of Indian Economic Problems
- (2) Carefully discuss the importance of the study of Economic Problems of India under the present circumstances
- (3) 'India is a land of Plenty amidst Poverty' Comment

को उन-विभाजना एवं अप-संशुद्धि के दोषों तथा चक्कन्दी के लाभों से अवगत कराते थे। इस हेतु विभिन्न स्थानों पर सभायाँ का आयोजन किया जाता था और व्याख्याता तथा पारस्परिक चर्चा-विचार के द्वारा कृषकों को इस दिशा में समस्त ज्ञान प्रदान करने एवं सहकारी चक्कन्दी के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने का प्रयत्न किया जाता था। जब किसी विशिष्ट स्थान पर अनुकूल वातावरण तैयार हो जाता था, तो भूमि की चक्कन्दी के लिए सहकारी समिति का निर्माण कर दिया जाता था। व्यवहार में, इस दिशा में भी अनवरत कठिनाइयों का अनुभव किया गया। श्री हालिंग के दृष्टि में, विभिन्न स्वार्थों का समन्वय करके प्रत्येक व्यक्ति को सन्तुष्ट करना, अज्ञान को दूर करके अशिक्षित व्यक्तियों को समझाना, धनी, शक्तिशाली एवं लाचार लोगों के साथ निर्धन अशक्ति एवं शान्त लोगों का ही उत्तम ध्यान रखना बड़ा ही कठिन कार्य है, विशेषकर जबकि केवल समझाना सुझाना ही हमारा साधन हो और जिज्ञा ही हमारा अस्त्र हो। इसके अलावा पड़ोसियों की ईर्ष्या, प्रवृत्ति एवं कृषक का पँचूक भूमिगतिक प्रवि प्रगाढ़ प्रम और अधिर कठिनाइयाँ पैदा कर देते हैं। अतः समस्त योजना पर विचार करने के उपरान्त यदि कुछ व्यक्ति चक्कन्दी सुझाना को ठुकरा दें, तो सारे कार्य को पुनः आरम्भ में करना पड़ेगा और इस दिशा में किया हुआ समस्त परिश्रम व्यर्थ जायगा। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी क्षेत्र के किञ्चित् जिद्दी लोगों का अल्पमत भी बहुमत में बाधा पैदा कर सकता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए सन् १९३६ में कानून बनाया गया, जिसके अनुसार यदि बहुमत चक्कन्दी के पक्ष में हो जाय, तो अल्पमत उनकी प्रगति में बाधा नहीं डाल सकता। यद्यपि पञ्जाब ने इस दिशा में मार्ग-प्रदर्शन करके बड़ा सराहनीय कार्य किया है, किन्तु फिर भी सहकारी ढंग से चक्कन्दी करने के प्रयत्न में अत्यन्त मोहित सफलता मिली है।

सहकारी समितियाँ द्वारा चक्कन्दी के क्षेत्र में दूसरा उल्लेखनीय प्रयास उत्तरप्रदेश राज्य में किया गया है। सहारनपुर तथा रिजनीर के क्षेत्र में सन् १९२५ में सहकारी समितियाँ द्वारा चक्कन्दी का कार्य किया गया है। बाद में यह योजना मेरठ व बस्ती जिला में भी शुरू की गई। सन् १९३६-४० में उत्तरप्रदेश राज्य में १८२ सहकारी समितियाँ कार्य कर रही थी। सन् १९४७ में यह कार्य समाप्त कर दिया गया, क्योंकि कमचारियों में भ्रष्टाचार अधिक बढ़ रहा था। सहकारी आधार पर इतनी लम्बी अवधि में अब तक कुल १२० लाख एकड़ भूमि की ही सहकारी विभाग द्वारा चक्कन्दी की, जो, यथार्थ है। सहकारी चक्कन्दी की गति को तीव्र करने के उद्देश्य से सन् १९३६ व १९५३ में चक्कन्दी के लिए नए कानून बनाए गए। मद्रास राज्य में भी सहकारी आधार पर ही चक्कन्दी का कार्य किया गया है, परन्तु उसका क्षेत्र अत्यन्त सीमित रहा है।

(३) राजकीय अधिनियम द्वारा चक्कन्दी—चक्कन्दी की दिशा में जो



भी २ जकीय आधार पर प्रयास किये गये हैं उनमें मध्य प्रदेश का नाम उल्लेखनीय है मध्य प्रदेश में सन १८२८ में चक्करी अधिनियम पास हुआ जिसके अनुसार अनियाय चक्करी का मिद्वान सबसे पहले भारत में लागू हुआ । यदि किसी गांव के ५० प्रतिशत कच्चा जिनके पास ३ भूमि से कम न हो चक्करी के लिये राजी हो जाय तो फिर अन्य लोगों पर भी यह अनिवार्य रूप में लागू कर दी जायगी । यह अधिनियम सब प्रथम छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में लागू किया गया और वहां इसके द्वारा पर्याप्त सफलता भी मिली सब श्री नानावती व अजगिया ने भारतीय ग्रामीण समस्याओं की पर पुस्तक में एक स्थान पर लिखा है कि सन १९३७ तक १ लाख स्थायी कपड़ों की १ १३ ३०० एकड़ भूमि के २४ ३३ ००० क्षेत्रों की मर्याद चक्करी के द्वारा घटाकर ३ ६१ ००० कर दी गई ।

मध्य प्रदेश के चक्करी अधिनियम के उद्देश्य सन १९३६ में पंजाब ने चक्करी अधिनियम पास किया और इसके बाद सन १९३८ में उत्तर प्रदेश में और सन १९४० में जम्मू व काश्मीर में इसी प्रकार के अधिनियम पास किये गये । इन समस्त अधिनियमों में इसी मिद्वान की प्राथमिकता दी गई है कि यदि किसी ग्राम के एक निश्चित प्रतिशत व्यक्ति जोकि एक निश्चित प्रतिशत भूमि के स्वामी हों चक्करी के लिये अपनी छोटी प्रगट कर तो फिर राज्य अनिवार्य रूप में उन योजनाओं को समस्त गांव पर लागू कर सकता है यहां यह उल्लेखनीय है कि चक्करी सम्बंधी इस अधिनियम का लाभ उठाना मुख्यतः ग्रामीणों की दृष्टि पर छोड़ा गया है परन्तु यदि बहुमत हमें पक्ष में अपनी छोटी प्रगट करे तो चक्करी अनिवार्य रूप में पर भी लागू का जा सकती है ।

यह अधिनियम कृषि के माहुर क्षमताओं की विचारणा के आधार पर बनाया गया था इनमें सबसे बड़ा भाग यह था कि यह सीमित क्षेत्रों में ही लागू किया गया जिन क्षेत्रों में चक्करी के लिये उपयुक्त व तावरण नहीं था वही हमें लागू नहीं किया गया था किन्तु भी यह क्योंकि कोई भी राज्य सरकार ५ बल नसी दंगा में कदम उठा सकती था जबकि बहुमत चक्करी के लिये दृढ़ है । अनिवार्य चक्करी के लिये विभिन्न रंगों में जो अधिनियम पास किये गये वे निम्न हैं —

- (१) बम्बई अपखंडन निवारण एवं चक्करी अधिनियम १९४७
- (२) पूर्वी पंजाब अपखंडन निवारण एवं चक्करी अधिनियम १९४८
- (३) पूवा पंजाब पटियाला मघ चक्करी अधिनियम १९५१
- (४) सौराष्ट्र अपखंडन निवारण एवं चक्करी अधिनियम १९५१
- (५) उत्तरप्रदेश भूमि चक्करी अधिनियम १९५३

चक्करी की दृष्टि में सबसे पहला अधिनियम बम्बई राज्य में पास हुआ प्रम सन १९४७ के बाद जिन जिन राज्यों में हमें दिया गया प्रयास किये वे प्रायः सभी

वर्गों में अप-खण्डन निवारण एवं चकबन्दी अधिनियम पर ही अवलंबित हैं। चकबन्दी के क्षेत्र में भारत के विभिन्न राज्यों में जो प्रगति हुई है उसका संक्षिप्त व्योरा इस प्रकार है—

**पंजाब**—भारत में सर्व प्रथम १९२०-२१ में पंजाब में श्री कानवर्ट की निगरानी में सहकारी समितियाँ बनाकर प्रचार और ज़रूरत के आधार पर चकबन्दी का कार्य शुरु किया गया। इसमें गृहस्वामियों की स्वीकृति एवं इच्छा की आवश्यकता थी अतः प्रगति बहुत धीमी रही और ३० वर्ष की अवधि में केवल ७०७ लाख एकड़ भूमि की ही चकबन्दी की जा सकी। इस कार्य को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिये नवम्बर १९३६ में एक चकबन्दी अधिनियम (Consolidation of Holdings Act) बनाया गया जिसने चकबन्दी की गति को कुछ अधिक तीव्र किया। इस अधिनियम के अनुसार अल्प मूल्यक व्यक्तियों के विरोध के होने हुए भी चकबन्दी को अनिवार्य बनाया गया। चकबन्दी से पंजाब राज्य की कृषि को बहुत अधिक लाभ पहुँचा है। जोनी जान वाली भूमि के संतुल्य तथा उत्पादन में काफी वृद्धि हुई, पारस्परिक भण्डे, तथा मुकदमवाजी काफी कम हो गई एवं जन-साधारण में सुधार के लिये एक अभिलाषा पैदा हो गई। पंजाब में चकबन्दी योजना की सफलता के लिये वहाँ की विशेष परिस्थिति—जैसे मिचाई की सुव्यवस्था तथा भूमि के बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों में बँटे होने की न्यूनता काफी सीमा तक उत्तरदायी है।

**उत्तर प्रदेश**—उत्तर प्रदेश राज्य में सहकारी आधार पर चकबन्दी का काम तो सन् १९२५ में ही शुरु हो गया था, परन्तु वहाँ पर प्रगति बहुत धीमी रही। सन् १९३६ के चकबन्दी अधिनियम के अंतर्गत कुछ प्रगति हुई किन्तु सन् १९४७ तक ६४ ६४ गाँवों में केवल ४ लाख ६४ हजार एकड़ की ही चकबन्दी की जा सकी। सन् १९४० में चकबन्दी के सम्बन्ध में मुद्दा देने के लिये राज्य द्वारा एक समिति नियुक्त की गई। इस समिति की सिफारिशों के अनुसार उत्तर प्रदेश चकबन्दी अधिनियम १९५३ पारित किया गया, जिसके अनुसार राज्य को अनिवार्य रूप से चकबन्दी की योजना लागू करने का अधिकार मिला। कम मूल्य की भूमि के लिये तथा खेती फसल की हानि के लिये क्षति पूर्ति की व्यवस्था रखी गई है, गाँव की भूमि को उपज व मिट्टी के प्रकार के अनुसार कुछ वर्गों में विभाजित कर दिया जायेगा और फिर यथासंभव प्रत्येक को उसी वर्ग में भूमि दी जायेगी, जिसमें उसकी मूल्य अधिक भूमि है। एक ही परिवार के व्यक्तियों को पास-पास भूमि दी जायेगी। भूमि देते समय, खेत पर यदि किसी का निवास गृह है अथवा कोई अन्य स्थायी विकास किया गया है, तो उसका भी ध्यान रखा जायेगा। छोटे-छोटे भूमिधारियों को गाँव के निकट ही भूमि दी जायेगी। अहाँ तक सम्भव होगा  $6\frac{1}{2}$  एकड़ या इससे अधिक के चक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वप्रथम सहारनपुर एवं मुजफ्फरनगर जिलों की एक-एक तहसील में लागू किया गया और बाद में अन्य

भूमा में ना यह धार धार बंटा गया । एसा अनुमान है कि द्वितीय पंच वर्षीय यात्रना व अन तब भार राज्य में चक्करी का काम पूरा कर दिया जायगा । इस सम्पूर्ण कार्य में लगभग १८ लाख रुपये व्यय हान का अनुमान है ।

**सम्बर्द्ध—**सम्बर्द्ध राज्य में सन १९०७ में छोट जाल बिल (Small Holdings Bill) राज्य का विधान परिषद में पेश किया गया था किन्तु तीव्र विरोध व कारण यह स्वीकार न हो सका । इसके बाद सन १९४७ में चक्करी अधिनियम पार किया गया । यह अधिनियम मजबूत में एक छोटा अधिनियम था जिसका अनुकरण जाल में अनक राज्या न किया । इस अधिनियम में चक्करी की व्यवस्था अनुनामक बिल (Permissive Act) की अपेक्षा अनिवार कानून (Compulsory Act) के रूप में की गई थी । यद्यपि यह अधिनियम ८ अप्रैल १९४८ में पार हो गया परन्तु कार्य रूप में इस सन १९५० में ही परिणित किया गया । इसके बाद सन १९४३ में इस अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए । चक्करी का समस्त व्यय राज्य सरकार का भार होना है और कृषक में कोई फीस नहीं लेनी पानी ।

**मध्य प्रदेश—**अनिवार चक्करी व निय मध्य प्रदेश राज्य में सन १९०८ में चक्करी अधिनियम बनाया गया । इस अधिनियम में अनुसार गाँव व कम में कम छोटे स्याया भूमिवासी जितने पाम गाँव की कम में कम दो तिहाई भाग भूमि है यदि भूमि की चक्करी व लिए राजा हो तो छप छोटे भूमिवासी का ऐसा करने का निय बान्य होना पडगा ।

भू अनिवार सचानय मध्य प्रदेश में प्राज सूचनाया व अनुसार जोना का चक्करी यात्रना मध्य प्रेश व ६ जिला में कार्याविन की जा रही है । सन् १९५६ ६० में २०६ गाँव व २०८ ३३४ एकड़ जना में यह काम पूरा कर लिया गया । ३५६ गाँव व लगभग २ ४६ ००० एकड़ जना में यह कार्य विभिन्न स्तरा पर चल रहा है ।

**अन्य राज्य—**अनक अनिवार दिल्ली जम्भू तथा बाइसीर बिहार और उडामा प्रादि राज्या में भी चक्करी सम्बर्द्धी अधिनियम बनाए गये हैं । प्रथम एक द्वितीय पंचवर्षीय यात्रनाया में ना प्रत्येक राज्य में भूमि की चक्करी को प्रोत्साहित करने का भूमाव दिया गया है । यात्रना आयोग ने इस बात की सिफारिश की है कि सामुदायिक विकास एक राष्ट्रीय विस्तार भवा सङ्घा में चक्करी की कृषि विकास कार्यक्रम व अन्तगत प्रसारना दनी चाहिये ।

**भूमि की चक्करी और पंच-वर्षीय योजनायें—**

प्रथम योजना कार्य में कुछ प्रमुख राज्या में चक्करी की प्रगति इस प्रकार है—सम्बर्द्ध २१ लाख एकड़, मध्य प्रदेश २६ लाख एकड़ पंजाब ४८ लाख एकड़ पश्चिम १० लाख एकड़ व उत्तर प्रदेश ४६ लाख एकड़ । द्वितीय यात्रना का मध्य २६० लाख एकड़ भूमि की चक्करी करना है । जून १९५६ तक कुछ प्रमुख राज्या

में निम्न सीमा तक चकवन्दी की जा चुकी थी — पंजाब ६५ ५५ लाख एकड़, उत्तर-प्रदेश ३० ७० लाख एकड़, बम्बई १८ १२ लाख एकड़ और मध्य प्रदेश ३३ ३६ लाख एकड़ ।

### संयुक्त ग्राम व्यवस्था (Joint Village Management)

उप-विभाजन व अप-खण्डन की समस्या को मुलभूतने के लिये श्री त्रिलोकमिह ने एक नया प्रस्ताव रखा है । उन्होंने अपनी पुस्तक 'Poverty and Social Change' में संयुक्त ग्राम प्रबन्ध का सुझाव दिया है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस जनतन्त्रात्मक विचारधारा को बड़ा महत्व दिया गया है । योजना आयोग ने इस प्रणाली को देश के लिए आदर्श माना है और इसी कारण अपनी भूमि नीति को इसी पर आधारित किया है ।

#### योजनाओं की विशेषताएँ—

संयुक्त ग्राम व्यवस्था वे अन्तर्गत गाँव की समस्त भूमि को एकत्रित कर लिया जायगा और इसका प्रबन्ध ग्राम-प्रबन्धक सस्था (ग्राम पंचायत व ग्राम सभा) को सौंप दिया जायगा । यही सस्था इस बात का निर्णय करेगी कि कौनसी फसल बोनी चाहिये अथवा फसल के हेर फेर का कौनसा तरीका अपनाना चाहिये । यह वित्त, सुन्दर बीज, उत्तम खाद और उचित कृषि-यन्त्रों आदि का प्रबन्ध करेगी । यह कुटीर व कृषि के अन्य सहायक उद्योग-धन्धों की भी व्यवस्था करेगी । कृषि उपज को बढ़ाने के उद्देश्य से भूमि को उचित जोनों में बाँटा जा सकता है, जिनको प्रबन्धक सस्था एक या एक से अधिक परिवारों को काश्त के लिये दे देगी । जिन शर्तों पर भूमि लेती के लिए दी जायगी, वे ऐसी होंगी, जिनसे कृषकों के हृदय में उत्साह तथा कार्य की भावना जागृत हो सके । गाँव की ग़रब भूमि, तालाबों, बनो और सिंचाई के छोटे छोटे साधनों का प्रबन्ध भी यही सस्था करेगी । इस प्रणाली की एक अनोखी विशेषता यह है कि साधारण सहकारी कृषि समिति से उसके सदस्य जब चाहे अलग हो सकते हैं, परन्तु सहकारी ग्राम प्रबन्ध के अन्तर्गत गाँव की समस्त भूमि सदैव के लिये एकत्रित कर ली जाती है । यहाँ भू-स्वामित्व का अधिकार तो रहता है, परन्तु संयुक्त कृषि से पृथक् होने का अधिकार नहीं रहता है । जहाँ तक सहकारी, ग्राम प्रबन्धक सस्था के आय के बँटवारे का सम्बन्ध है, वह दो तरीकों से बाँटी जायगी ।

(१) आय का कुछ भाग तो स्वामित्व अधिकारों के अनुसार बाँटा जायगा और (२) कुछ खेत पर लगाये गये श्रम के अनुसार । इस प्रणाली को हम हम की सम्मिलित कृषि और साधारण सहकारी कृषि के मध्य की प्रणाली की सज़ा दे सकते हैं । यह प्रणाली सम्मिलित कृषि की अपेक्षा अधिक थोष्ट है, क्योंकि इसमें

उन दोनों नियमों (अर्थात् स्वामित्व अधिकार तथा समानाधिकार) जिन पर कि हमारे ग्रामीण समाज का आधार है को स्वीकार कर लिया जाता है। यही कारण है कि हमारे देश की वर्तमान परिस्थितियों के अन्तर्गत यह प्रणाली भारत के नियमों में अधिक उचित है। यह प्रणाली गांधारण सहकारी कृषि से इस निम्न श्रेणी है क्योंकि इसमें उनमें अधिक संगठन होता है।

इन प्रकार संयुक्त ग्राम व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक गांव में तीन प्रकार के कार्य होना चाहिये —

- (१) निज्जा कार्य
- (२) एक्छिक सहकारी कार्य
- (३) सम्मिलित पंचायती क्षेत्र।

हमें हमें सहकारी कार्य को इस प्रकार विस्तृत किया जायगा कि अंत में समस्त ग्रामीण अंतर्गत सम्मिलित कार्य में सम्मिलित हो जाय। सहकारी आन्दोलन का मुख्य मंत्र यह उद्देश्य होगा कि वह माल तैयार करने और उसे बचत में इसी सिद्धान्त का पालन करे। आजकल संयुक्त ग्राम प्रबंध की लागू करने में निम्न लिखित साधन तथा साधनों सहयोग दे रही हैं —

- (१) राष्ट्रीय विमान भवायें
- (२) ग्राम-पंचायत
- (३) सहकारी माल विक्रय तथा गोदाम समितियाँ में उन्नति
- (४) उद्योगों की उन्नति
- (५) एक्छिक सहकारी समितियाँ और
- (६) ग्राम में पंचायती क्षेत्र का विकास

इस योजना के अन्तर्गत उन्नत पंचायतों द्वारा एकत्रित किया जायगा और व्यक्तिगत रूप से तो पंचायत की जमानत पर अथवा सम्मिलित कृषि में व्यक्तिगत भावों की जमानत पर दिए जाने चाहिये।

संयुक्त-ग्राम प्रबंध के लाभ—

(१) कृषि उत्पादन में वृद्धि—संयुक्त ग्राम प्रबंध की प्रणाली के अन्तर्गत कृषि की उत्पादन क्षमता अवश्य बढ़ेगी। आजकल कृषि उत्पादन में न्यूनता का सबसे बड़ा कारण जोता के अकार का छोटा और विस्तरा हुआ होता है। इस प्रणाली के अनुकरण में जोतें बनी जा जायेंगी एवं विभिन्न प्रकार की मिश्र-प्रणितियाँ प्राप्त हो सकेंगी। कृषि करने के तरीक़ों में उन्नति होगी वित्त का सुप्रबंध हो सकेगा और किसान केरी का बिना काइय खानी नहीं छोड़ सकेंगे। मन्त्रों में हम यह कह सकते हैं कि पंचायत की उन्नत की योजना एक व्यावहारिक का कारण कर लगी।

(२) समान अधिकार—यह प्रणाली एक ऐसी अवस्था उत्पन्न कर देगी जिसमें गाँव के सभी लोगों को समान अधिकार मिल सकेंगे। थोड़े से स्वामित्व अधिकारों को छोड़ कर शेष समस्त आय खेत पर लगाए गए थम व अनुसार बाँट दी जायगी। गाँव के सभी लोगों को खेता पर काम पड़ेगा। उदाहरण के लिए जमींदारों को भी काश्तकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना पड़ेगा। ग्रामीण वानावरण में यह परिवर्तन लोकन्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अत्यन्त श्रेष्ठ एवं हितकारी है।

(३) एकता में वृद्धि—इन प्रणाली के द्वारा जमींदारों तथा काश्तकारों और जमींदारों एवं श्रमिका के पारस्परिक संपर्क भंग हो जायेंगे तथा समाज में स्नेह व सहकारिता का वानावरण फैल जायगा।

(४) यह प्रणाली अन्य सभी प्रणालियों की अपेक्षा अधिक व्यावहारिक है। योजना के विरोध में विचार—

इतने लाभ होते हुए भी इस प्रणाली के विरोध में लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये हैं —

(१) कुछ लोगों के मतानुसार हमारा देश अभी इतनी बड़ी कालि की स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि यह वास्तव में प्रणाली का दोष नहीं है। कुछ भी हो, इस नक्ष्य को सामने रख कर हम धीरे-धीरे प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं।

(२) कुछ लोगों के विचारानुसार इस योजना को कार्यान्वित करने से गांव की बहुत सी जनता बेरोजगार हो जायगी, क्योंकि पुनर्निर्माण के पश्चात् थोड़े श्रमिका की आवश्यकता पड़ेगी। यह दलील भी विरोध महत्वपूर्ण प्रतीत नहीं होती, क्योंकि यह तो तभी होगा जबकि परिवर्तन आकस्मिक हो।

(३) वामपक्षियों (Leftists) का मत है कि स्वामित्व अधिकार के लाभ की प्राप्ति केर भू स्वामित्व अधिकार को कायम रखा गया है। वास्तव में तो यह अधिकार उन्हीं काश्तकारों को मिलना चाहिये, जो स्वयं कृषि करता हो, किन्तु जब तक भारत में व्यक्तिगत सम्पत्ति की प्रणाली की स्वीकार किया जायगा, तब तक ऐसा करना ही पड़ेगा।

(४) सरकारी अथवा गृहकारी दोनों प्रकार के कार्यों के विरुद्ध प्रायः यह कहा जाता है कि ऐसे प्रबन्धों से कार्य करने की भावना में कोई वृद्धि नहीं होती, वरन् यह केवल एक नित्य-कर्म (Routine) रह जाता है।

योजना आयोग ने भी उपर्युक्त बर्तनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह सुझाव दिया है कि इस प्रणाली को धीरे-धीरे लागू किया जाय। प्रारम्भ में ग्राम पंचायतों को वजर भूमि का प्रबन्ध सभाबद्धा चाहिये और बाद में इसके क्षेत्र को

धीरे धीरे ममस्त गाँव पर बढ़ाना चाहिये । स्थिति के अनुसार खेतों को कई जोतों में बाँट दिया जाय और प्रत्येक जोत को एक परिवार को अथवा अनेक परिवारों के समुदाय को काश्त या खेती के लिए दे दिया जाय । जैसे-जैसे आर्थिक प्रगति के साथ अन्य क्षेत्रों में श्रमिकों की आवश्यकता बढ़ती जाय, वैसे-वैसे जोतों के आकार को भी बढ़ा लिया जाय और गृहकारी ढंग में उसकी काश्त की जाय ।

अतः में यह कहा जा सकता है कि समुक्त ग्राम-व्यवस्था में जो साधारण हैं, वे इतनी कठिन नहीं हैं कि उनकी दूर न किया जा सके । अतः हमें इस प्रणाली के अनुसार कार्य करना आरम्भ कर देना चाहिये ।

(५) उत्तराधिकार तथा पैतृक सम्पत्ति के अधिनियम में परिवर्तन—भूमि के उपविभाजन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए पैतृक सम्पत्ति तथा उत्तराधिकार के नियमों में हम प्रकार संशोधन करना चाहिए, जिससे भू सम्पत्ति का अधिकार पिता के बाद सबसे बड़े लड़के को ही मिले । हाँ, वर्तमान परिस्थितियों के अन्तर्गत यह संशोधन अविशेष लोगों को मान्य न होगा । साथ ही, अन्य उत्तराधिकारियों की व्यवस्था भी करनी होगी । देश में उद्योग-बन्धों के प्रभाव में ऐसा संशोधन बेकारी की समस्या को प्रेरणाहित कर सकता है । इससे समाज में भूमिहीन कृषकों की संख्या भी बढ़ेगी । अतः इन कठिनाइयों के फलस्वरूप हम प्रसार की व्यवस्था देश की वर्तमान परिस्थितियों के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होती । परन्तु फिर भी यह व्यवस्था की जा सकती है कि एक न्यूनतम क्षेत्र में कम की जोता का विभाजन नहीं हो सकता और इस प्रकार परिवार के सदस्यों को उन पर समुक्त कृषि के लिये बाध्य किया जा सकेगा ।

(६) भूमि की आर्थिक इकाई नियत करना—एक मुद्दा यह भी है कि कानूनी द्वारा यह नियत कर दिया जाय कि भूमि का विभाजन केवल आर्थिक जोतों में ही हो सकता है । कृषि व्यवस्था में स्थाई भुधार करने के उद्देश्य से यह आवश्यक प्रतीत होता है । हमारे योजना आयोग ने भी सभी राज्यों द्वारा आर्थिक जोत निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया है । सरकार द्वारा आर्थिक जोत की सीमा निर्धारित कर दी जाय और किसी भी व्यक्ति को आर्थिक जोत से छोटे टुकड़े में भूमि विभाजित करने का अधिकार नहीं दिया जाय । सीमावर्ष का विषय है कि भारत के अधिकांश राज्यों में इस दिशा में अधिनियम बनाये जा चुके हैं । मध्य प्रदेश में सन् १९५६ तक सीमित भूमि के लिये ५ एकड़ और असंजित भूमि के लिये १० एकड़ की न्यूनतम सीमा निश्चित की गई है जिसमें परे विभाजन नहीं हो सकता ।

उप-संहार—

जोतों के उप-विभाजन एवं अप-सृष्टन को रोकने के लिए ऊपर जिन उपायों

की चर्चा की गई है, उनमें सहकारी कृषि ही सर्व श्रेष्ठ उपाय है। हमारे देश की वर्तमान परिस्थितियों के अंतर्गत यह सबसे अधिक उपयुक्त प्रस्ताव है। इसके द्वारा खेती, पशु और श्रम के सभी माध्यमों को एकत्रित कर उनका समुचित उपयोग किया जा सकता है। इससे छोटे छोटे कृषक का बड़ा पैमाने की कृषि में भागीदारी का प्राप्त कर सकते हैं।

### STANDARD QUESTIONS

1. Carefully distinguish between an Economic Holding and Opimum Holding, and briefly point out the factors which affect the economic holdings of an agriculturist.
2. What are the causes of subdivision of holding in India ? How does this affect our agricultural production ?
3. Discuss the causes of Subdivision and Fragmentation of holdings in India. Suggest measures for their solving these problems.
4. Discuss the lines on which attempts have been made in some parts of India to remedy the evils of excessive subdivision and fragmentation of holdings.
5. What do you mean by consolidation of holdings ? What measures have been taken by the Govt to achieve it ?
6. "Small and uneconomic holdings are at the root of many of the difficulties in the way of agricultural development." Examine this Statement.



## ग्रामीण साख

( Rural Credit )

### ग्रामीण साख का महत्व—

वर्तमान युग में साख का बहुत महत्व है। बिना साख के बड़े पैमाने पर उद्योग धर्मों का विकास हो ही नहीं सकता। किसी भी उद्योग को भलि-प्रकार संचालित करने के लिये रखाई एक सन्निय पूँजी की आवश्यकता होती है। उद्योगकर्ता यह पूँजी यथामन्त्र अपने व्यक्तिगत साधनों द्वारा जुटाता है। यदि उसके निजी साधन अपर्याप्त होते हैं, तो वह बाहरी साधनों से ऋण प्राप्त करके पूँजी का प्रबंध कर लेता है। कृषि भी एक उद्योग है और अन्य उद्योगों की भाँति कृषि के लिए भी साख की आवश्यकता होती है। परन्तु अन्य उद्योगों की तुलना में कृषि उद्योग अपनी कुछ अनोखी विशेषता रखता है, यही कारण है कि साधारण औद्योगिक साख संस्थाओं द्वारा कृषि साख की पूर्ति नहीं हो सकती। साख की दृष्टि से कृषि एक अन्य उद्योगों में पाँच प्रमुख अन्तर है। प्रथम, कृषि में निम्नलिखित पूँजी का प्रतिकूल दर से प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई कृषक आज बीज बोता है, तो कई महीनों के बाद उसको उपज प्राप्त होती है। अतः कृषि में अपेक्षाकृत लम्बी अवधि के लिये ऋण की आवश्यकता होती है। दूसरे, कृषि व्यवसाय में जोखिम अधिक है। प्राकृतिक प्रकोपों एवं वर्षा की अनिश्चितता के कारण लाभ भी अनिश्चित होता है। तीसरे, कृषि व्यवसाय में माँग और पूर्ति में समन्वय करना सम्भव नहीं होता उदाहरणार्थ, एक बार पसल बीज के बाद फिर उत्पादन को घटाया नहीं जा सकता। इसके विपरीत अन्य निर्माण उद्योगों में मूल्य स्तर के गिरने के साथ-साथ उत्पादन भी कम किया जा सकता है। चौथे, व्यापार एवं अन्य उद्योगों की तुलना में कृषकों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ नहीं होती और जब ऋण की सुरक्षा का प्रश्न आता है, तो कृषकों के पास भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत नहीं होती। पाँचवें, कृषि एक मौसमी उद्योग है, अतः ऋण की माँग भी साल भर न रह कर कुछ विशेष महीनों में ही होती है।

उपसृक्त विवरण में स्पष्ट है कि कृषि उद्योग का भी अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं की सम्पुष्टि के लिए साख की आवश्यकता होती है। यदि कृषकों के सीमित

साधनों को ध्यान में रखते हुये सब पूछा जाय, ता कृषि के क्षेत्र में साख का महत्व और भी अधिक हो जाता है। यहाँ यह लिखना अनावश्यक होगा कि भारतीय कृषि के पिछड़े होने के विभिन्न कारणों में उचित साख व्यवस्था का अभाव भी एक महत्वपूर्ण कारण है। भारतीय कृषक की दरदरता एक सर्व विदित तथ्य है। भारतीय कृषक के पास कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त पूँजी का अभाव रहता है।

ऐसी परिस्थिति में उसे भूमि में मुधार साने तथा नये नये यन्त्रों, उत्तम बीज उत्तम खाद, स्वस्थ पशु आदि के प्रयोग के लिये बहुधा ऋण पर निर्भर रहना पड़ता है। भारतीय गाँव में एक कहावत प्रचलित है कि, "वही गाँव बसने योग्य है, जहाँ पर आवश्यकता पड़ने पर ऋण देने के लिए महाजन हों, दवा दारु के लिये बंध हो, पूजा-पाठ आदि के लिए पंडित हो तथा जल का एक ऐसा साधन हो, जो कभी भी सूखता न हो।" इस कथन से भारतीय कृषक के जीवन में साख का महत्व स्पष्ट है। परन्तु हमारे देश में थोड़े साख संस्थाओं के अभाव में महाजनो का बड़ा बोल बाला है। ये महाजन लेन देन में कृषक को विविध ढंगों से शोषण करते हैं। अतः उचित साख व्यवस्था का महत्व हमारे देश की कृषि की उन्नति के लिए नितांत आवश्यक है। इस प्रकार 'साख की कृषि का जीवन' कहना कोई अत्युक्ति नहीं होगी।

हमारे देश में कृषि साख का कोई नियत रूप नहीं है। इसका प्रमुख कारण यह है कि कृषक बहुधा गाँव में निवास करते हैं, जहाँ संगठित साख की कोई व्यवस्था नहीं पाई जाती। प्रोफेसर हैमलटन के शब्दों में, "भारतीय गाँव में अनेक बंकर हैं, परन्तु बंक एक भी नहीं है।"

**कृषक की साख सम्बन्धी आवश्यकताएँ—**

किसानों की साख सम्बन्धी आवश्यकता की काल के अनुसार तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है—

(१) दीर्घकालीन ऋण—किसानों की भूमि खरीदने, कुँआ बनवाने तथा पुराने ऋण का निपटारा करने के लिये ऋण की आवश्यकता होती है, जिसे वह थोड़े समय में नहीं चुका सकता। इस प्रकार के ऋण की अवधि प्रायः तीस-चासी वर्ष होती है। यह कृषक की प्रदेय क्षमता के अनुसार अधिक और कम हो सकती है। केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति के अनुसार इस प्रकार के ऋण की आवश्यकता वार्षिक रूप से कम ५ अरब रुपये है।

(२) मध्यकालीन ऋण—कृषि यन्त्रों, मशीनों, बैलों आदि के खरीदने के लिये कृषक को मध्यकालीन ऋण की आवश्यकता पड़ती है, जो प्रायः ११-२ वर्ष से पाँच वर्ष तक की अवधि के लिये लिए जाते हैं, बिवाह, भोज, आदि के लिये जो ऋण लिये जाते हैं। वे भी इसी अवधि के लिये होते हैं, क्योंकि राशि प्रायः इनकी

अधिक होती है कि एक वर्ष में उसका मुद्यतान नहीं हो सकता। मध्य कालीन साख की मात्रा में भी प्रादेशिक विभिन्नता पाई जाती है।

(३) अल्पकालीन ऋण—किसान को अपनी वर्तमान आवश्यकताओं, जैसे बीज, खाद, हल, भोजन सामग्री तथा अन्य कम मूल्य के साधारण भोजारों को खरीदने, मन्दी तक पैदावार को ले जाकर बेचने एवं खेतों की अन्य क्रियाओं के लिये अल्पकालीन ऋण की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार की साख 'मौसमी साख' भी कही जा सकती है, जो ६ माह से लेकर १५ माह तक की अवधि के लिए दी जा सकती है। केन्द्रीय बैंकिंग ऑफ समिति के अनुमानानुसार कृषकों की अल्पकालीन साख की आवश्यकता कम से कम तीन अरब से चार अरब रुपये तक है, यद्यपि डा० बलजीतसिंह के अनुसार इसकी न्यूनतम सीमा ६ अरब रुपये है।

कृषि साख प्राप्ति के साधन—

औद्योगिक व व्यापारिक साख पूर्ति के साधनों का संगठित विकास भारत में १९वीं शताब्दी के अन्त से ही आरम्भ हो गया था, किन्तु ग्रामीण साख सम्बन्धी सुविधाओं के विकास की दिशा में कोई विशेष प्रयत्न नहीं किये गये। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ( All India Rural Credit Survey Committee ) के अनुसार किसानों को साख प्रदान करने के लिये निम्नलिखित सहायक हैं—

साधन	प्रतिशत
सरकार ( Government )	३.६
सहकारी समितियाँ ( Co operative Societies )	३.७
सम्बन्धी ( Relatives )	१४.२
जमींदार ( Landlord )	१.५
कृषक साहूकार ( Agriculturist money lenders )	२४.६
पेशेवर साहूकार ( Professional Moneylenders )	४४.६६
व्यापारी वगैरे ( Traders and Commission Agents )	५.५
व्यापारिक बैंक ( Commercial Bank )	०.६
अन्य साधन ( Other Sources )	
कुल	१००.००

आजकल हमारे देश में कृषकों के लिये साख प्राप्ति के निम्न मुख्य साधन हैं—

- (१) माँव के महाजन एवं देशी बैंकर,
- (२) सहकारी साख समितियाँ,
- (३) भूमि बन्धक बैंक,

- (४) सरकार,
- (५) सयुक्त पूँजी वाले बैंक,
- (६) रिजर्व बैंक, और
- (७) स्टेट बैंक ।

## (१) गाँव के महाजन एवं देशी बैंकर

प्रथा—

गाँव में कृषि की व्यवस्था करने में गाँव के महाजन का बहुत बड़ा महत्व है। इन महाजनों को हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं—पहले वे महाजन जो द्रव्य उधार देने का पेशा करते हैं और दूसरे वे जो उधार देने का पेशा नहीं करते हैं। पेशेवर महाजन द्रव्य उधार देने के साथ ही साथ गाँव की उत्पादित वस्तुओं का व्यापार भी करते हैं और वे गाँवों में ही अधिक पाये जाते हैं। भिन्न भिन्न राज्यों में ये भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं, जैसे—बनिया, महाजन, साहूकार, किस्त वाला, पठान इत्यादि। पेशेवर न होने वाले लोगों में जमींदार, धनिक किसान तथा विधवा स्त्रियाँ मुख्य हैं, जो प्रायः उन्हीं लोगों को ऋण देते हैं जिन्हें वे अच्छी तरह से जानते हों। अपने स्थानीय ज्ञान तथा अनुभव के आधार पर वह स्पष्ट सम्पत्ति के बिना भी ऋण दे देता है और इतना होते हुए भी हानि से अपनी रक्षा करता है।

बोध—

किन्तु महाजनों के इस कार्य में कई दोष हैं। वह किसान को, इस बात की चिन्ता किये बिना कि वह किस काम के लिये ऋण ले रहा है, उत्पादक भ्रष्टाचार अनुत्पादक ऋण दे देता है। वह प्रायः इस शर्त पर भी ऋण देता है कि गाँव की फसल उसको ही भ्रष्टाचार उसके द्वारा ही बेची जावेगी। इसका परिणाम यह होता है कि किसानों को दबाव में आकर सस्ते भाव में अपनी फसल बेचनी पड़ती है। वह सूद-दर सूद लगाता है, जिससे ऋण का भार बहुत ही जल्दी बढ़ जाता है। इसके प्रतिरिक्त और भी कई दोष हैं। जैसे—

(१) जब महाजन किसानों को ऋण देते हैं, तो मूलधन की रकम में से पूरे वर्ष का सूद काट कर बाकी रकम ही देते हैं और बन्ध (Bond) पूरी रकम का लिखवाते हैं। इसके प्रतिरिक्त काटे हुए सूद की रसीद भी नहीं देते और बड़ी ही सरलता से १ वर्ष की अवधि समाप्त होने पर उसी वर्ष का दूसरी बार सूद माँग लेते हैं। जब कजदार निश्चित अवधि के समाप्त होने पर ऋण नहीं चुका पाता, तो महाजन कोरे बन्ध पर उसके हस्ताक्षर ले लेते हैं और बाद में ऋणी की वास्तविक रकम

मे अधिक रकम का बच लिखने में सकोच नहीं करते । कभी कभी तो ऋण देते समय भी दिये जान वाले ऋण की राशि से अधिक रुपये का बच लिखकर अनिश्चित किसानों के हस्ताक्षर करवा लेते हैं ।

(२) समय समय पर कजदारों की ओर से ऋण के पत्र जो किरतें महाजनो को दी जाती हैं उनको रसीद किसानों (कजदारों) को नहीं दी जाती और बड़ीछाता में जमा की गई रकम का विवरण भी नहीं लिखते । इस प्रकार किसानों में दिए गये ऋण से भी अधिक वसूल किया जाता है ।

(३) कहीं कहीं ऋण के प्रतिरिक्त गद्दी खच, 'सत्तामी' 'कटौती,' 'बटावन' गिरह खुलाई इत्यादि दोषका क अतगत खर्च भी महाजनो द्वारा वसूल किये जाते हैं । इस प्रकार किसानों पर ऋण भार दिन प्रति दिन बढ़ता जाता है ।

**सुधार के प्रयत्न—**

इन सब दोषों के रहते हुए भी हम यह तो मानना ही होगा कि गाँव में महाजन किसानों की आवश्यकता के समय ऋण देकर जितनी सहायता करते हैं उतनी कोई नष्ट करता, अतः किसानों की अल्पकालीन तथा मध्यकालीन आर्थिक आवश्यकताओं के पूरी करने में भविष्य में भी उनका काय चलता रहेगा । वास्तव में आवश्यकता है महाजनो पर नियन्त्रण धरन की, न कि उनके काय को बन्द करने की । इसके लिए कृषि ग्रन्थ प्रबन्धन उप समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार नियन्त्रण होना चाहिए, जिसकी मुख्य बातें ये हैं—साहूकारों का रजिस्ट्रेशन तथा उन्हें अनुमति पत्र देना, निर्धारित दृङ्ग पर खाता का रखना, प्रत्येक ऋण का पूर्ण विवरण कजदारों को देना । कजदारों के रुपये चुकाने पर (प्रत्येक किस्त के समय) रसीद देना, मूद दर मूद की सीमा निश्चित करना, कजदारों की साहूकारों के प्रचलित दोषों (धाँदा देने से सम्बन्धित) में रक्षा करना एवं राज्य की ओर से निरीक्षण तथा देख रेख के लिए प्रबन्ध करना इत्यादि ।

हमारे देश के बम्बई, आसाम, बङ्गाल मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, पंजाब, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों में उपयुक्त दोषों से किसानों की रक्षा करने तथा ऋण सम्बन्धी लेन देन के ढंगों पर कानून बना कर नियन्त्रण करने का प्रयत्न किया, जिसका फल अच्छा हो हुआ है । अखिल भारतीय ग्रामीण माल मर्के के अनुसार उपयुक्त श्रोत से भी भारतीय कृषकों की लगभग ७०% साख आवश्यकतायें पूर्ण होती हैं, अतः कुछ दुर्गुणों के होते हुए भी इस प्रथा का पूर्णतः उन्मूलन नहीं किया जा सकता । श्री एम० एल० डालिंग का भी यही विचार है ।

## (२) सहकारी साख समितियाँ

व्यवस्था एवं षोष—

ये समितियाँ अपने सदस्यों को थोड़े समय के लिए बीज, खाद, हल, मीजार, आदि मोल लेने के लिए ऋण देती हैं। पहले ये सदस्यों को विश्वास पर ही ऋण दिया करती थी, परन्तु अब परोहर के रूप में भी कुछ लेती हैं और अपने सदस्यों को लाभान्वित भी देती हैं। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वे के अनुसार कृषक की आवश्यकताओं का १०% भाग इसी श्रोत द्वारा पूरा होता है। अतः स्पष्ट है कि इनसे कृषकों को बहुत कम लाभ पहुँचा है। अभी तक इनकी उन्नति बहुत कम हुई है। वास्तविकता यह है कि इनके सदस्य अधिक्षिप्त, अज्ञानी एवं रुढ़िवादी हैं। समितियों के ऊपर राजकीय नियन्त्रण बहुत अधिक है, अतः सदस्यगण कार्य में विशेष रुचि नहीं लेते हैं। समितियों के सदस्य रुपया नहीं लोटाते, इसलिए वह बट्टे खाते में जाता है। समितियाँ इस बात पर कभी भी विचार नहीं करती कि सदस्यगण ऋण व्यय किस प्रकार कर रहे हैं। अधिकोश ग्रामीण आज भी इन समितियों की अपेक्षा गाँव के महाजन को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि—(१) गाँव के महाजन बिना किसी परोहर के ऋण देता है। (२) सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार एवं लाल फीता के कारण ऋण बहुत महंगा पड़ता है। (३) किसान को यह भय रहता है कि सहकारी समिति ऋण की वसूली में कठोरता बरतेगी। (४) सहकारी व्यवस्था के अन्तर्गत गिरिशिखर स्टाफ द्वारा देखभाल होने एवं ऋण लेने की बात फैलने का भी किसान को संकोच रहता है। समितियों की दसा मुधारने तथा उनको अधिक उपयोगी बनाने के लिए यह प्रस्ताव है कि इन समितियों को बहु-उद्देशीय समितियों में बदल दिया जाय, जहाँ कि किसान की नमक से लेकर हल, बल तक की समस्त आवश्यकताएँ पूर्ण हो सकें। हर्ष का विषय है कि उत्तर-प्रदेश, बम्बई आदि राज्यों में ऐसी समितियाँ स्थापित की जा रही हैं।

भाजकल सरकार इस बात का प्रयत्न कर रही है कि कृषकों को लघुकालीन व मध्यकालीन ऋण सहकारी साख समितियों द्वारा दिये जाएँ और इस हेतु द्वितीय योजना-काल के अन्त तक इन समितियों की सदस्यता ६० लाख से बढ़ा कर १३ करोड़ करने की है। इस बीच इन समितियों द्वारा १५० करोड़ रुपया लघुकालीन ऋण के रूप में, ५० करोड़ रुपया मध्यकालीन ऋण के रूप में और २५ करोड़ रुपया दीर्घकालीन ऋण के रूप में दिया आया। इस प्रकार सन् १९६०-६१ तक सहकारी समितियाँ कृषि साख का २५% प्रदान कर सकेंगी।

## (३) भूमि बन्धक बैंक

सहकारी साख समितियाँ अल्पकालीन व अधिक से अधिक मध्यकालीन साख

दे सकती है। दीर्घकालीन साख देना उनके बच के बाहर की बात है। इसके लिए तो भूमि प्रबन्धक बैंक ही उपयुक्त समझी गई हैं। ये निम्न कार्यों के लिए साख देती है— (१) किसानों की भूमि तथा मकानों को छुड़ाना, (२) खेती की भूमि तथा खेती बारी के धन्धे को उन्नत करना और किसानों के मकानों को बनवाना, (३) पुराने ऋण चुकाना, और (४) भूमि खरीदने के लिए खपा देना। इन कार्यों के लिये वे ऋण पत्र जारी करती हैं एवं दीर्घकालीन डिपॉजिट लेती हैं।

**असफलता के कारण—**

अनेक राज्यों में ये बैंक असफल रही हैं, क्योंकि (१) कन्धक जायदाद का ठीक ठीक मूल्य नहीं आँका जा सकता, (२) मन्दी के कारण भूमि के मूल्य में कमी होने में बैंकों की जमानत कम पड़ गई, (३) भूमि पृथक्करण कानून (Land Alienation Act) के कारण भूमि पर अधिकार नहीं किया जा सकता था, (४) बैंक के टाइम्पटर वगैरह स्वयं बैंक से बहुत ऋण लेते थे और (५) फसल की कीमत गिर जाने पर ऋणी किसानों को ऋण चुकाने की शक्ति कम हो गई।

इन बैंकों की आवश्यकता को कोई भी सम्बोधित नहीं कर सकता, परंतु इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है कि राज्य सरकारें इनके द्वारा निर्गमित ऋण पत्रों के मूलभूत तथा व्याज की गारन्टी करें और रिजर्व बैंक इनके ऋण पत्रों को ट्रस्टी निक्कोरिटी घोषित करे।

## (४) सरकार से साख प्राप्ति

केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारें भी किसानों को ऋण दकर आर्थिक सहायता करती हैं। ऐम ऋण को 'सकाबी ऋण' कहा जाता है। प्रांतीय सरकारें किसानों को सन् १८८३ के भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत दीर्घकालीन ऋण देती हैं, जो कृषि के स्थायी सुधार में जैसे—कुँआ खोदना, बाँध बनाने इत्यादि के लिए लगाया जाता है।

इसी प्रकार सन् १८८४ के किसान ऋण अधिनियम के अन्तर्गत भी बीज, औजार, खाद, हल, बल इत्यादि खरीदने के लिए अल्पकालीन ऋण (जो एक या दो वर्षों के लिए दिया जाता है) देती हैं। इन ऋणों की अदायगी लम्बी अवधि तथा छोटी किस्तों में की जाती है। मूल की दर भी कम होती है, यही विशेषता है।

**दोष—**

किन्तु सकाबी ऋण से हमारे देश के किसानों को विशेष सहायता नहीं मिल पाई है, जिसके कारण ये हैं—ऋण की स्वीकृति करने में विलम्ब, सरकारी कम चारित्र्यो द्वारा अवैधानिक रिश्वतें माँगना, ऋण की अदायगी के लिए बंदोबस्त, दख रेख की कठिनायता और प्रबन्ध की अस्थिरता इत्यादि मुख्य हैं। इन अमुविधाओं के

अन्तर्गत जो ऋण दिया जाता है वह किसानों की आवश्यकताओं से कम होता है (वह भी केवल खेतों के ही लिए)। अविकसित किसानों को तत्काली ऋण किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, इसका भी ज्ञान नहीं होता। यदि ये बुराइयाँ दूर हो जाएँ तो सरकार इन ऋणों को देकर कृषि सुधार के पवित्र कार्य में अपना कर्तव्य पूरा कर सकती है। अकाल की कठिनाइयों को दूर करने में अल्पकालीन ऋण अच्छा फल दे सकते हैं और विशेषकर उन अविकसित एवं पिछड़े क्षेत्रों में जहाँ सहकारी साख समितियाँ सफल नहीं हो सकती।

ऐसा अनुमान है कि सब राज्य सरकारें किसानों की कुल ३% आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। इन ऋणों को देने में सरकार बहुत दूर लगाती है। इन ऋणों से कृषकों को लाभ पहुँचाने के लिए केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति ने निम्न सुझाव दिये हैं—(१) ऋणों को देने में देरी नहीं करनी चाहिए। (२) धूमखोरी को रोकने का प्रवन्ध किया जाय। (३) यदि फसल खराब हो जाय, तो ऋण छोड़ देना चाहिए। (४) कृषकों को पता होना चाहिए कि ये ऋण किस प्रकार दिये जाते हैं। और (५) ये ऋण सहकारी समितियों द्वारा दिये जाने चाहिए।

### (५) संयुक्त पूँजी वाली बँक

ये बँकें भी कृषि साख के लिये प्रत्यक्ष रूप में विशेष सहायता नहीं पहुँचाती। उनके साधारण व्यवसाय में कृषि अर्थ-प्रबन्धन का कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि उनका संगठन अल्पकालीन या दीर्घकालीन ग्राम्य साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए नहीं होता। फिर भी ये परोक्ष रूप में व्यापारियों के द्वारा कृषि अर्थ-प्रबन्धन के कार्य में सहायता प्रवृत्त होती है। इसके अतिरिक्त किसानों के पास खेतों की सुरक्षा की योग्यता नहीं रहती, कृषि अर्थ-प्रबन्धन की विशेष प्रकृति, उद्योग की मौसमी आवश्यकता एवं अनियमित प्रकृति, किसानों की अज्ञानता एवं अशिक्षा इत्यादि ऐसी बातें हैं, जो व्यापारिक बँकों को प्राप्ताह्न नहीं देती। यदि किसानों के द्वारा उत्पादन की जाने वाली फसलों पर तथा मारें अथवा खेती के धन (पन्ना) पर पहिला अधिकार व्यापारिक बँकों को दिया जावे तो वे अवश्य ही कृषि की ओर अपने व्यापार का विकास कर सकती हैं।

### (६) रिजर्व बँक

रिजर्व बँक ने कृषकों की आर्थिक सहायता के हेतु एक कृषि-साख विभाग खोला है, जो निम्न ढङ्गी से साख सुविधा प्रदान करता है :—

- ( १ ) यह सहकारी प्रतिभूतियों के पीछे अधिक से अधिक ६० दिन के लिए राज्य सहकारी बँकों एवं केन्द्रीय भूमि बन्धक बँकों को ऋण दे सकता है।



३०% मकान बनवान या मरम्मत का २५% और अन्य मदों का १०% व्यय उधार से पूरा किया जाता है ।

(६) सम्पूर्ण देश के लिये ग्रामीण परिवारों का पूँजा बनान पर कुल व्यय ६५० करोड़ रुपया है जिसमें से ३०० करोड़ रुपये कृषि में (श्रूमि और दोरो का व्यय छोड़कर) लगभग २५० करोड़ रुपया रिहायशी मकानों आदि में और १०० करोड़ रुपया गर कृषि व्यवस्था में व्यय होन का अनुमान था ।

(७) कृषि में पूँजी विनियोग की कुछ विशेष मदों के लिये खतिहर परिवारों की साख आवश्यकताय वास्तविक व्यय की तुलना में उच्च स्थिति के परिवारों की दशा में २ से ६ गुनी अधिक और निम्न स्थिति के परिवारों की दशा में ३ से २७ गुना अधिक है ।

(८) खतिहर जो प्रतिभूति दे सकते हैं उनके सम्बन्ध में यह पता लगा कि लगभग ५०% परिवार अपनी अचल सम्पत्ति जमानत के रूप में देते हैं । बाकी में से लगभग १/४ अपनी व्यक्तिगत जमानत पर रुपया लेते हैं । बाकी में से अधिकांश न अपनी जमानत का आधार नहीं बताया । यहाँ नहीं उच्च व्यय का कारण आवश्यकताय प्रति परिवार १ ३००) है और नीचे के वर्ग की ८००) जबकि उनकी जमीन-जायगीर का मूल्य क्रमशः ७ ०००) और २ ०००) प्रति परिवार है ।

( ९ ) मोटा तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में दिय गये कुल धन का लगभग १/२ में २/३ तक गायद शहरी क्षेत्रों से आता है ।

( १० ) विचारार्थीन व्यय में प्रति खतिहर परिवार उधार ली गई रकम औसतन २१०) थी जिसमें से लगभग ३०% सरकार से ३% सहकारी संस्थाओं से १४% सम्बन्धियों से २% जमादारा से २५% खतिहर सहकारियों से ४५% पेंशनर महाजनो से ६% व्यापारियों से और १% का कुछ कम बाणिज्य बैंकों से प्राप्त होता है । बाकी अन्य प्रकार के ऋणदाताओं से प्राप्त हुआ है ।

समिति की महत्त्वपूर्ण निष्कारिणें—

( १ ) नवीन कृषि साख नीति के अन्तर्गत राजकीय बैंक की स्थापना का सुझाव सबसे महत्त्वपूर्ण है—केन्द्रीय सरकार ने इस स्वीकार कर लिया है और प्रथम जुलाई सन् १९५५ से इम्पारियल बैंक आफ इण्डिया की भारत की राज्य बैंक में परिवर्तित कर दिया गया है । बैंक प्रचलित उन क्षेत्रों में नई गाँवों बढ़ायेगा जहाँ अभी तक अन्य बैंकों की ग्राह्यता नहीं है और जहाँ सहकारी गाँवों समितियों का विकास नहीं हुआ है । बैंक का विकास के साथ-साथ सहकारी ऋण संस्थानों का ऋण मुविधाय सुलभ हो गेँगी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रा के स्थानान्तरण में सरलता होगी ।

( २ ) राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं भाण्डारण बोर्ड—एक 'राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं भाण्डारण बोर्ड' (National Co-operative Development and Warehousing Board) बनाया जाय, जिसके निम्न दो उद्देश्य हों—सहकारी संगठन, विशेषकर विक्रय समितियों का विकास करना और कृषि उत्पादन के संग्रहीकरण की सुविधाओं का विकास करना । इसके अन्तर्गत दो कोष होंगे—राष्ट्रीय सहकारी विकास फण्ड एवं दूसरा राष्ट्रीय भाण्डारण विकास फण्ड । राष्ट्रीय सहकारी विकास फण्ड केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई ३ करोड़ रुपये की निधि से प्रारम्भ किया जायगा और राज्य सरकारों को दीर्घकालीन ऋण देने में प्रयोग होगा, जिसमें राज्य सरकारें राज्य की सहकारी विकास समितियों की पूँजी में रुपया लगा सकें । दूसरा कोष केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई २ करोड़ रुपये की निधि से प्रारम्भ होगा और इसका उपयोग 'अखिल भारतीय भाण्डारण निगम' की अथवा पूँजी में लगाने तथा राज्य सरकारों को राज्य भाण्डारण कम्पनियों में रुपया लगाने के लिए ऋण देने में होगा ।

( ३ ) राष्ट्रीय कृषि साख फण्ड—रिजर्व बैंक द्वारा दो फण्ड स्थापित किये जायेंगे । राष्ट्रीय कृषि साख ( दीर्घकालीन ) फण्ड में ५ करोड़ रुपया होगा और प्रति वर्ष रिजर्व बैंक इसमें ५ करोड़ रुपया जमा करती रहेगी । इस फण्ड में से रिजर्व बैंक राज्य सरकारों की दीर्घकालीन ऋण दगा, जिसमें वे राज्य की सहकारी साख समितियों की गेयर पूँजी में रुपया लगा सकें । राज्य सरकारों द्वारा प्रमाणित भूमि वन्धक बैंकों को भी इस निधि में से रुपया दिया जायगा । 'राष्ट्रीय कृषि साख ( स्थायीकरण ) फण्ड' ( National Agricultural Credit ( Stabilisation ) Fund ) में रिजर्व बैंक प्रति वर्ष १ करोड़ रुपया जमा करेगी, जिसका उपयोग राज्य सहकारी बैंकों ( Apex Banks ) को मध्यकालीन ऋण देने में किया जायगा । हाँ, इन बैंकों के पास इस बात के संतोषजनक कारण होने चाहिए कि अमुक राज्य बैंक दुर्भिक्ष या बाढ़ अथवा अन्य किसी कारण से अल्पकालीन ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है । ऐसी दशा में इन अल्पकालीन ऋणों का मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तन किया जा सकेगा और वह रुपया राष्ट्रीय कृषि साख ( स्थायीकरण ) कोष में से दिया माना जायगा । राज्य सहकारी बैंकों को भी अपने अपने क्षेत्रों में इस प्रकार के फण्ड खोलने होंगे, ताकि वे केन्द्रीय बैंक के वकाया अल्पकालीन ऋणों को इस फण्ड के द्वारा मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित कर सकें ।

( ४ ) सहकारी संस्थाओं में राज्य द्वारा सह-स्वामित्व—यह सुभाव भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है । समिति का कहना है कि यह सह-स्वामित्व ( State Partnership ) केन्द्रीय व प्राथमिक साख समितियों में भी इस प्रकार से स्थापित किया जाना चाहिये, जिसमें शीर्ष-स्तर केन्द्रीय स्तर एवं प्राथमिक स्तर पर सेयर

पूँजी का कम से कम ५१% भाग किसी न किसी रूप में राज्य के स्वामित्व में आ जाय : वस्तुतः राज्य सरकार राज्य के सहकारी शीप-बैंकों में पूँजी विनियोजित करेगी और शीप बैंक केन्द्रीय बैंक में तथा अन्ततः केन्द्रीय बैंक प्राथमिक सहकारी साख समितियों में । इस प्रकार राज्यों का सारा सहकारी साख संगठन एक सूत्र में बंध जायगा और उसमें राज्य द्वारा पूँजी के विनियोग में ऋण सुविधाओं का विकास होगा तथा कृषि साख सम्बन्धी नीति के प्रचलन में सुविधा रहेगी ।

( ५ ) प्रशिक्षण एवं निरीक्षण—समिति ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया है, जिससे नवीन संगठन का कार्य-संचालन एवं निरीक्षण कुशलतापूर्वक हो सके ।

इस प्रकार समिति ने एक ऐसी नीति का सुझाव दिया है जिसमें राज्य नवल संचालक हो नहीं बल्कि सार्वभौमिक ही होगा । यद्यपि यह सहकारिता के सिद्धान्तों के विरुद्ध है कि संगठन में राज्य का इतना प्रभुत्व हो, तथापि भारतीय कृषि की वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुये यह मार्ग उचित है । इस नीति का लक्ष्य यह है कि राज्य द्वारा प्रतिपादित एवं संचालित सहकारी साख संगठन के विकास में कृषि के क्षेत्र में इतनी अधिक प्रतियोगिता उत्पन्न हो कि प्राइवेट साख संस्थाओं के वर्तमान दाय स्वयं दूर हो जायें और अविष्य में वे राष्ट्रीय कृषि नीति के हित को ध्यान में रखकर ही साख सुविधायें प्रदान कर सकें । केन्द्रीय सरकार ने समिति की अधिकांश सिफारिशों को सिद्धान्तगत मान लिया है । भारत की राज्य बैंक स्थापित हो चुकी है तथा अखिल भारतीय भाण्डारण निगम की स्थापना प्रगति के पथ पर है ।

**पंच-वर्षीय योजनाओं में कृषि साख—**

भारत की प्रथम पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार तथा सहकारी संस्थाओं द्वारा सन् १९५५-५६ तक १३५ करोड़ रुपये की कृषि साख प्रदान करने का आयोजन था, किन्तु कुछ कारणों से इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकी । प्रथम योजना अवधि में केवल ४३ करोड़ रुपये की कृषि साख की ही व्यवस्था की जा सकी । द्वितीय-पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार तथा सहकारी समितियों द्वारा कुल २२५ करोड़ ६० की कृषि साख व्यवस्था का आयोजन है, जिसमें अल्पकालीन साख की मात्रा १५ करोड़ रुपये, मध्यकालीन साख की मात्रा ५५ करोड़ रुपये और दीर्घकालीन साख की मात्रा केवल २५ करोड़ रुपये हो गई ।

## STANDARD QUESTIONS

(1) Examine the existing agencies for financing agriculture in

India What have been their limitations ? What Steps have been taken in recent years to remove them ?

- (2) Give the main findings of the All India Rural Credit Survey Outline the principal recommendations made therein for the reorganisation of the system of rural credit
- (3) Discuss the position of Village Moneylenders in our rural Economy
- (4) What are the financial requirements of Indian agriculturist How and from what sources do they get the necessary finance

## अध्याय ६

# सहकारिता

### ( Co-operation )

प्रारम्भिक—

सहकारिता शब्द का शाब्दिक अर्थ है—‘एक साथ मिल जुल कर कार्य करना ।’ अतः सृष्टि के आरम्भ से ही सहकारिता किसी न किसी रूप में मानव समाज में विद्यमान रही है । मनुष्य स्वभाव में ही एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर उसे अन्य व्यक्तियों के सहयोग से ही कार्य करना पड़ता है । मानव ही पशु, पक्षी, कीड़े मकौड़े आदि भी मिल कर कार्य करते हुए देखे जाते हैं । यह एक सामान्य अनुभव है कि सम्मिलित प्रयत्न द्वारा जो कार्य किया जाता है, वह निश्चय ही सफल होता है एवं सम्पन्न हो जाता है । सम्मिलित प्रयास के द्वारा मानव बड़ी बड़ी योजनाओं को सरलता से ही पूरा कर डालता है ।

गत कुछ शताब्दियों से (विशेषकर औद्योगिक क्रान्ति के बाद) विश्व के कुछ प्रमुख राज्यों में ऐसी शक्तियाँ त्रिआशीस रही हैं, जिनके कारण मानव द्वारा मानव का शोषण बढ़ गया है । जो शक्तिशाली हैं एवं भौतिक दृष्टि से साधन सम्पन्न हैं, वे अनाथ एवं निधन व्यक्तियों का प्रतियोगिता में टिकने नहीं दत्त । ‘जिसकी माटी उसकी भस्’ वाले इन युग में पूँजीपतियों, उद्योगपति एवं बड़ बड़ व्यापारियों की ऐसी धनक सहाय्य है, जिनके समक्ष असह्य छोटे छोटे उत्पादक एवं धर्मिक अपना जीवन निर्वाह नहीं कर पाते । परिणामतः उनका निरन्तर शोषण होता रहता है और भौतिक उत्थति करने में वे अपने की विवश पाते हैं । ‘सहकारिता’ ऐसे ही असह्य व्यक्तियों की भौतिक प्रगति के लिए रामबाण है जो सक्तिहीन हैं, निर्धन हैं तथा निरन्तर शोषण के कारण जिनका आत्मविश्वास खो गया है— सहकारिता उनमें नवीन शक्ति का संचार करती है और सर्वत्र के लिए उनकी मुख्य समृद्धि का मार्ग खोल देती है ।

सहकारिता में आशय—

सहकारिता एक ऐसा—आर्थिक संगठन है—जिनके द्वारा एक-दूसरी तथा सक्तिहीन व्यक्ति दूसरों के सहयोग से ऐसी भौतिक लाभ प्राप्त करता है, जो केवल धनाढ्य व

शक्तिशाली लोगों को ही उपसंध्य है। सहकारिता की योजना के अन्तर्गत निर्बल व्यक्ति अथवा बग अपने हितों की रक्षा करने अथवा उन्नति के लिए मिल जुल कर कार्य करते हैं। इस प्रकार यह एक मिला जुला प्रयत्न है। जिसका उद्देश्य पारस्परिक सहायता द्वारा सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना अथवा सामूहिक कठिनाइयों को दूर करना होता है। इसका आधार यह होता है कि ‘प्रत्येक मनुष्य के लिए ही और सब प्रत्येक के लिए।’ सहकारिता के द्वारा जीवन के ऐसे उच्चतम एवं उन्नत स्तर की वास्तविक मिद्धि की प्राप्ति की जाती है जिससे श्रेष्ठतम व्यापार, श्रेष्ठतम कृषि तथा समृद्ध जीवन सम्भव हो सके।

**कुछ परिभाषायें —**

श्री फे (Fay) " अनुसार, 'एक सहकारी समिति मिलकर व्यापार करने का वह संगठन है, जो दुर्बल व्यक्तियों में बनता है और निष्काम भावना से ऐसी शक्तों पर संचालित किया जा सकता है कि सभी व्यक्ति, जो इसकी सदस्यता से सम्बन्धित कर्तव्यों को ग्रहण करते हैं, उसके लाभ में उसी अनुपात में भाग पायेंगे, जिसमें उन्होंने संगठन का प्रयोग किया है।'

श्री हैरिक (Harric) का कथन है—‘सहकारिता स्वेच्छा से संगठित हुए उन व्यक्तियों का कार्य है जो अपनी सम्मिलित शक्ति या प्रसाधना का सम्मिलित प्रबन्ध के अन्तर्गत सबके साधारण उपयोग करना चाहते हैं।’

सर्व होरेस प्लन्केट के शब्दों में "सहकारिता वास्तव में आत्म-सहायता है, जो कि संगठन के कारण अधिक प्रभावशाली हो जाती है।"

श्री एच० कलब्रेंट कहते हैं, 'सहकारिता उस प्रकार का संगठन है, जिसमें समानता के आधार पर और अपने आर्थिक हितों की उन्नति के लिए व्यक्ति स्वेच्छा से भाग लेते हैं।'

सहकारी योजना समिति १९४६ के अनुसार, 'सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें लोग समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों की वृद्धि के लिए स्वेच्छा से सम्मिलित होते हैं। जो लोग शामिल होते हैं, उनका एक सामान्य हित होता है, जिसे वे व्यक्तिगत प्रयास द्वारा पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें से अधिकांश व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति दुर्बल होती है। इस व्यक्तिगत दुर्बलता पर अपने अलग अलग साधनों का एकीकरण करके, पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म-सहायता का प्रभावशाली बनाकर और आपस में ईमानदारी का व्यवहार रखते हुए विजय प्राप्त कर लेती जाती है।'

संक्षेप में सहकारिता एक प्रकार का संगठन है, जिसमें विभिन्न व्यक्ति अपने

किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ निश्चित नियमों के अन्तर्गत अधिकतम लाभ के लिए मिलकर कार्य करते हैं।

सहकारिता के आवश्यक तत्व—

सहकारिता की उपर्युक्त परिभाषा के अध्ययन से इसके निम्न तत्त्व स्पष्ट हैं—

(१) ऐच्छिक संगठन—सहकारी संगठन एक ऐच्छिक संगठन है अर्थात् किसी पर इसमें दामिल होने या भलग हो जाने के लिए दबाव नहीं डाला जाता। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है कि वह जब चाहे इसका सदस्य बन जाए और जब चाहे भलग हो जाय। श्री एच० कलवर्ट महोदय ने एक स्थान पर लिखा है कि 'जब व्यक्तियों का सम्मिलित होने की अथवा भलग होने की स्वतन्त्रता होगी, तभी बफादारी, ईमानदारी और निष्कामभाव वाली वास्तविक सहकारिता की भावना का विकास हो सकता है और सहकारिता की भावना के बिना 'सहकारिता' अधिक दिनों तक नहीं चल सकती।

(२) प्रजातन्त्रीय प्रशासन—एक सहकारी समिति का प्रबन्ध जनतन्त्र के सिद्धान्तों पर किया जाता है। यह एक ऐसा ऐच्छिक संगठन है, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों को संयुक्त करने वाली कड़ी एक सामान्य आर्थिक आवश्यकता का होता है, अतः यह नितान्त आवश्यक है कि सब व्यक्ति इसमें समान रूप से 'भाषाज' रहें, जिससे किसी को भी हानि न पहुँचे। जनतन्त्रीय शासन में व्यक्ति का व्यक्ति द्वारा शोषण नहीं होता। इसके अन्तर्गत शक्ति का दुरुपयोग सम्भव नहीं। सहकारिता के अन्तर्गत लोगों का उद्देश्य एक दूसरे को सहायता देकर अपनी सहायता करना होता है, लाभ कमाना नहीं। पूँजी के आधार पर मताधिकार भी नहीं दिए जाते और न संगठन के लोग का पूँजी के अनुपात में वितरण होता है। 'एक व्यक्ति एक वोट' का सिद्धान्त अपनाया जाता है, अर्थात् सभी का प्रबन्ध में बराबर अधिकार मिलता है और व्यापार के लाभों का सदस्यों में वितरण कर दिया जाता है।

(३) पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता—सदस्यगण अपने-अपने आर्थिक हितों की वृद्धि के लिए संगठित होते हैं, दूसरे के लाभार्थ नहीं। वे सहकारी संस्था के लिए और सहकारी संस्था उनकी सहायता के लिए जोती है। 'पारस्परिक सहायता के द्वारा आत्म सहायता करना' उनका मूल मन्त्र है। सदस्यगण आवश्यकता बाल व्यक्ति को इसलिये सहायता करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब उन्हें सहायता की आवश्यकता होगी, तो दूसरे उनकी सहायता करेंगे। इस प्रकार वे सहायता चाहते हैं और जा सहायता करते हैं उनका हिना में विरोध भाव नहीं होता। इसीलिये उनका नारा है कि, 'प्रत्येक सदस्य के लिए सब प्रत्येक के लिए।' इसी कारण सहकारिता अपने सदस्यों को समय से चलन का उपदेश करती है।

(४) संयुक्त प्रयास द्वारा सामान्य कल्याण की वृद्धि—स्वार्थ-भावना से प्रेरित प्रयत्नों को एक सहकारी संगठन में कोई स्थान नहीं है। एक सहकारी संगठन स्वार्थी व्यक्तियों का संगठन नहीं होता। व्यक्तिवाद अथवा 'प्रत्येक अपने लिए' की भावना, जोकि प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है, एक सहकारी संगठन में नहीं पाई जाती।

• (५) सेवा की भावना—जैसा कि तालमकी (Talmaki) ने कहा है कि 'सहकारिता केवल व्यापार मात्र नहीं है बल्कि व्यापार के साथ साथ सेवा की भावना का भी संयुक्तिकरण है, जो बफादारी, आनुभासना और सामूहिक भावना जागृत करती है।' पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता करने के लिए एक निष्काम भावना और ईमानदारी का होना बहुत आवश्यक है। सहकारी संस्था का कार्य लाभ की भावना से नहीं बल्कि सेवा भावना में चलाया जाता है। इस प्रकार सहकारी आन्दोलन वास्तव में नैतिक आन्दोलन है। चूंकि इसके व्यापार के संचालन में ईमानदारी और निस्वार्थपरता का पालन होता है, इसलिए बहूतों के लिए सहकारिता एक 'विश्वास' और 'धर्म' है। यह वास्तव में एक ऐसा व्यापारिक संगठन है, जिसमें आर्थिक उन्नति की उपेक्षा चरित्र के मूधार पर अधिक धन दिया जाता है।

### सहकारी आन्दोलन का प्रारम्भ—

यद्यपि सहकारिता का इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है किन्तु फिर भी विश्व के प्रमुख देशों में इसके विकास की सीमा को देखने हुए हमें आश्चर्य होता है। इसका प्रारम्भ सर्व प्रथम उपभोग के क्षेत्र में हुआ, जबकि इंग्लैंड में सन् १८४४ में रोकडेल (Rochdale) के कुछ बुनकरों ने उपभोग की वस्तुओं प्राप्त करने के लिए एक सहकारी समिति स्थापित की, जिसका मुख्य निद्धान्त ये—प्रति व्यक्ति को केवल एक ही मत देने का अधिकार, प्रचलित बाजार मूल्य पर विक्रय एवं खराद के अनुपात में लाभ का वितरण—में विवरण। किन्तु सहकारिता के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना जर्मनी में १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ में हुई। उस समय जर्मनी के किसानों तथा शिल्पियों की आर्थिक दशा बहुत खराब थी। महाजन इनका विविध ढंगों में शोषण करते थे। उसी समय जर्मनी के रैफाईजन (Raiffesin) तथा शुल्ज़-डेलिज़ (Schulze-Delitsch) नामक दो समाज सुधारकों ने सहकारिता द्वारा इस समस्या के हल का प्रयत्न किया। रैफाईजन ने ग्रामीण जनता के हितार्थ और शुल्ज़-डेलिज़ ने नगरी जनता के कल्याणार्थ सहकारी साख समितियों की स्थापना की। हमारा ध्यान में भी इनकी आधार पर सहकारी साख समितियों का निर्माण किया गया है, अतः इनकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालना आवश्यक न होगा।



शहरी ऋण समितियों की अपेक्षा ग्रामीण ऋण समितियों पर विशेष बल दिया गया, क्योंकि वे अपेक्षित अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण थीं। प्रत्येक प्रान्त में एक सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया एवं निरीक्षण तथा अपेक्षा की भी व्यवस्था की गई। सहकारिता आन्दोलन को प्रोत्साहन देने के लिये कुछ छूटें भी दी गईं, जैसे—घास-चर स छूट, मुद्राक कर में छूट आदि, किन्तु कुछ दिशाओं में यह अधिनियम दोषपूर्ण था—प्रथम, गैर साक्ष समितियों की स्थापना के लिये इसमें कोई व्यवस्था न थी। दूसरे इसका उद्देश्य केवल प्रारम्भिक समितियों की स्थापना करने का था। इसमें निरीक्षण तथा नियन्त्रण के लिए केन्द्रीय समितियाँ क विनाश और संगठन की व्यवस्था नहीं की गई थी। ग्रामीण तथा शहरी समितियाँ का भेद भी कृत्रिम था, अतएव इन दोषों को दूर करने के लिये सन् १९१२ का नया अधिनियम बनाया गया।

सन् १९०४ के अधिनियम के आधार पर देश में अनेक सहकारी साक्ष समितियों का संगठन किया गया, जो नीचे दी हुई तालिका में स्पष्ट हो जाता है।

वर्ष	समितियों की संख्या	सदस्यों की संख्या हजार में	कामक्षील पूँजी (साक्ष रुपयों में)
१९०६-०८	८४३	७० ८	२३.७
१९१०-१२	८१७७	४०३.३	१३४.७

### सन् १९१२ का सहकारी अधिनियम—

सन् १९०४ के अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए सन् १९१२ में, जो नया अधिनियम बनाया गया, उसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्न थीं—

(१) केवल साक्ष समितियाँ ही नहीं, बल्कि अन्य प्रकार की समितियाँ भी, जिनका उद्देश्य सहकारिता के सिद्धान्तों पर सदस्यों का आर्थिक विकास करना हो, इस नियम के अन्तर्गत स्थापित की जा सकती थी।

(२) प्रारम्भिक समितियों के साथ उनके कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए समितियों के साथ, केन्द्रीय साथ एवं प्रान्तीय सघों की भी वैधानिकता प्रदान की गई। इन सघों में सदस्यों का उत्तरदायित्व सीमित रखने का निश्चय किया गया एवं ग्रामीण प्रारम्भिक समिति में उत्तरदायित्व पूर्ण की सीमा असीमित रहा।

(३) कोई भी समिति रजिस्ट्रार की आज्ञा लेकर अपने लाभ का चतुर्थांश सुरक्षित कोष में जमा करने के बाद, छेप लाभ का १०% शिक्षा एवं दान सम्बन्धी कामों के लिये दे सकती है।

(४) सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत जो व्यापारिक मस्यारों रजिस्टर्ड नहीं हैं, वे 'सहकारी' शब्द का प्रयोग नहीं कर सकेंगे।

(५) समिति के सदस्यों के अशो को ऋण चुकाने के लिये समवद्ध नहीं किया जा सकेगा।

(६) अपने ऋण की राशि की वसूल करने में भूमि कर के दाव समितियों को प्राथमिकता दी जावेगा।

इस प्रकार सन् १९१२ के अधिनियम ने देश में सहकारिता आन्दोलन को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया। इसके फलस्वरूप गैर साख समितियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। जैसा कि नीचे दिए हुए आंकड़ों से स्पष्ट है, इससे समितियों की संख्या, उनके सदस्यों तथा उनकी क्रियाशील पूँजी में बहुत विकास हुआ :—

वर्ष	समितियों की संख्या (हजार में)	सदस्यों की संख्या (लाखों में)	सक्रिय पूँजी (करोड़ों में)
१९११-१५	११.७६	५.४८	५.४८
१९१६-२०	२८.४८	११.२६	१५.१८

इसी बीच सहकारिता आन्दोलन की प्रगति से पूर्ण अवगत होने के लिए सन् १९१४ में सरकार ने श्री मंकलगन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जिसकी रिपोर्ट सन् १९१५ में प्रकाशित हुई।

**मंकलगन समिति के सुझाव**

(१) समितियों के लिये उचित मध्यमों के चुनाव तथा उन्हें सहकारिता के सिद्धान्तों से परिचित बनाने पर विशेष जोर देना चाहिये।

(२) लेन देन केवल सदस्यों तक ही सीमित रखा जाय।

(३) किसी भी सदस्य को ऋण देने के पूर्व उसकी आर्थिक स्थिति की पूर्ण जाँच कर लेनी चाहिये।

(४) ऋण का उपयोग केवल उत्पादक कार्यों के लिये ही होना चाहिये।

(५) सदस्यों के बीच मितव्ययिता का प्रचार करना चाहिये।

(६) नई समितियों के निर्माण में दीनता से काम नहीं करना चाहिये। जो सहकारी समितियाँ सहकारिता के सिद्धान्तों तथा आदर्शों के अनुबद्ध कार्य नहीं करती हैं, उन्हें बन्द कर देना चाहिये।

यद्यपि उपर्युक्त सुझाव सहकारी आन्दोलन की प्रगति के लिये बहुत आवश्यक थे, परन्तु प्रथम विश्व-युद्ध में व्यस्त होने के कारण सरकार ने इन सुझावों पर विशेष ध्यान नहीं दिया।

सन् १९१६ से सन् १९२६ तक सहकारिता का प्रसार—

सन् १९१६ के राजनैतिन सुधारों के अनुसार सहकारिता प्रान्तीय विषय बन गया, अतएव इसके संचालन का भार प्रान्तीय सरकारों के हाथ में आ गया। फलतः भिन्न भिन्न प्रान्तों ने अपनी आवश्यकतानुसार नये नये अधिनियम बनाये। उदाहरण के लिए बम्बई ने सन् १९२५ में, मद्रास ने सन् १९३२ में, बिहार एवं उड़ीसा ने सन् १९३५ में और कुग ने १९३७ में अपनी अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अलग अलग अधिनियम बनाये। इनसे सहकारी आन्दोलन को काफी बल मिला एवं उसकी गति तीव्र हो गई। कुछ प्रान्तों में तो आन्दोलन की प्रगति का अध्ययन करने तथा आवश्यक सुझाव देने के हेतु समितियों की नियुक्ति की गई। कृषि के सही आयोग ने भी सहकारिता के विकास पर अधिक जोर दिया। इस प्रकार सन् १९१६ से लेकर सन् १९२६ तक के बीच सहकारिता आन्दोलन की प्रगति काफी तीव्र रही। निम्नलिखित आँकड़ों से आन्दोलन की गति का आभास मिलता है—

वर्ष	समितियों की संख्या (हजार में)	सदस्यों की संख्या (लाख में)	नि्यासील पूँजी (करोड़ में)
१९२१ से १९२५	५७.७१	२१.५५	१६.३६
१९२६ से १९३०	६३.६४	३६.५६	७४.५६

परन्तु इस अवधि में समितियों द्वारा दिये गये ऋण का अधिकांश भाग लौटाया नहीं जा सका, अतः सहकारी समितियों की बहुत अधिक पूँजी मारी गई। संक्षेप में इस काल में सहकारिता का प्रसार अनियोजित ढंग से होता रहा।

सन् १९२६ से सन् १९३६ तक सहकारिता का प्रसार—

सन् १९२६ से विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी के कारण सहकारी आन्दोलन को बड़ा धक्का पहुँचा। अनाज के भाव गिर जाने के कारण कृषकों से ऋण की वसूली करना कठिन हो गया। ऐसी परिस्थिति में समितियों की संख्या में वृद्धि की अपेक्षा उनके पुनर्निर्माण पर अधिक जोर दिया जाने लगा। सन् १९३५ में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना की गई, जिसके अन्तर्गत एक कृषि साख विभाग भी खोला गया, जिसका कार्य कृषि के विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना था। इस प्रकार सन् १९२६ से सन् १९३६ तक की अवधि को 'सहकारिता आन्दोलन की अवधि' तथा पुनर्निर्माण का समय' कहा जाता है।

द्वितीय महायुद्ध में प्रगति—

द्वितीय महायुद्ध के काल में कृषि वस्तुओं के मूल्य स्तर में वृद्धि से सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ। इनकी संख्या, पूँजी तथा उनके

कार्य-क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई। सदस्यों ने ऋण का चुकाना आरम्भ किया, निक्षेप बढ़े और नये ऋणों की मांग कम होगई। युद्ध-काल में एव उसके बाद उपभोक्ता सहकारी भण्डारों तथा सहकारी विप्रेय समितियों में विशेष रूप से वृद्धि हुई।

**स्वतन्त्रता ■ पश्चात् सहकारी आन्दोलन—**

स्वतन्त्रता के पश्चात् सहकारी आन्दोलन को एक नवीन मोड़ मिला। रिजर्व बैंक ने सहकारी आन्दोलन के विषय में एक निर्देशक समिति (Committee of Direction) नियुक्त की, जिमने यह निश्चार प्रगट किया कि भारत में सहकारी आन्दोलन के विकास की महान् सम्भावनायें हैं। आवश्यकता है सफलता के हेतु धनु कूल वातावरण की। इसके लिये समिति ने कई अमूल्य सुझाव दिये—(१) पर्येक स्तर पर सहकारी सस्थाओं से सरकार की साभेदारी हो, (२) साख णो फसल की बिक्री और गोदाम में रखने के कार्य आदि से सम्बन्धित कर दिया जाय, (३) प्रारम्भिक कृषि साख समितियों का आधारशिला के रूप में विकास किया जाय, (४) अनाज गोदामों की स्थापना, (५) सहकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था और (६) इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण, जिससे वह सहकारी साख सस्थाओं को सहायता दे सके।

इन सुझावों के प्रकाश में सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये—

(१) १ जुलाई सन् १९५५ को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना (इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके) हुई। सन् १९६०-६१ तक इसकी ४०० नई शाखायें स्थापित की जानी हैं।

(२) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट में सन् १९५५ में संशोधन किया गया, जिसके अन्तर्गत दो प्रमुख कोष स्थापित किये गये—'राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन) कोष' और 'राष्ट्रीय कृषि साख (स्थिरीकरण) कोष'। १० करोड़ रु० से स्थापित राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन) कोष के निम्न उद्देश्य हैं—(अ) राज्य सरकारों को दीर्घकालीन कर्ज देना, जिससे सरकार सहकारी सस्थाओं की साभेदारी में काम कर सके, (ब) मध्यकालीन कृषि साख की स्थापना, (ग) केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों को दीर्घकालीन साख देना, और (द) केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों के डिबेचर खरीदना।

१ करोड़ रु० से स्थापित दूसरे कोष (राष्ट्रीय कृषि साख 'स्थिरीकरण' कोष) का उद्देश्य राज्य सहकारी बैंकों को मध्यमकालीन साख देना है, जिससे सूखे व अकाल की दशा में वे अल्पकालीन साख को मध्यम साख में बदल सकें।

(३) सन् १९५६ में एक राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा गोदाम बोर्ड और २ मार्च सन् १९५७ को एक केन्द्रीय गोदाम नियम स्थापित की गई।

(४) सहकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए एक सहकारी प्रशिक्षण की केन्द्रीय समिति बनाई गई है और इस कमेटी की योजना के अनुसार उच्च अधिकारियों

के प्रशिक्षण का केन्द्र पूना में स्थापित किया गया। मध्यम श्रेणी के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए भी ५ क्षेत्रीय केन्द्र तथा ८ केन्द्र सामुदायिक विकास खंडों के अधिकारियों के प्रशिक्षण के हेतु खोले गये हैं।

स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक भारत के सहकारी आन्दोलन की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। ५ व्यक्तियों के एक औसत भारतीय परिवार को आधार मानकर साधारणतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सन् १९५६ ५७ के अंत तक ६६ करोड़ व्यक्तियों या २५% भारतीय जनसंख्या को सहकारिता का लाभ मिलन लगा था।

**भारतीय सहकारी आन्दोलन की आधुनिक प्रवृत्तियाँ—**

इस आन्दोलन की कुछ आधुनिक प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं—

(१) सहकारी संस्थाओं, उनकी सदस्यता तथा पूँजी में वृद्धि—स्वतंत्रता काल में सहकारी संस्थाओं की संख्या, इनकी सदस्यता एवं वित्तीय पूँजी में काफी वृद्धि हुई है। इस सम्बन्ध में निम्न आंकड़ें दिए जा सकते हैं—

वर्ष	हजार में	लाख में	करोड़ ₹० में
१९८८-४६	१६३ ८८	१२७ ००	२१६ ४६
१९५०-५१	१८१ १६	१३७-१५	२७५ ७५
१९५१-५२	१८५-६५	१३७-६२	३०६-३४
१९५५-५६	२४० ०४	१७६ २२	४६८-८२
१९५६-५७	२४४-७७	१९३ ७३	५६७ ६७
१९५७-५८	२५७ ८१	२१४ ३५	६६६-४६

(२) सरकार की उदारतापूर्ण नीति—द्वितीय महायुद्ध के काल में खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के वितरण के हेतु तथा 'अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन' को सफल बनाने के लिए भारत सरकार ने सहकारिता के विकास पर अधिक बल दिया। यही नहीं, देश की आर्थिक समृद्धि में सम्बंधित पंच वर्षीय योजनाओं में भी इस उपयुक्त स्थान दिया गया।

(३) साक्ष के अतिरिक्त अन्य पहलुओं पर भी बल दिया जाना—युद्ध एवं युद्धोत्तर काल में सहकारी सहकारिताओं (Urban Co-operatives) ने बड़ी उन्नति की। खाद और उर्वरक, कृषि औजार एवं बीज वोटन का कार्य भी अनेक राज्यों में सहकारी समितियों द्वारा किया जाना गया है। सहकारी सत्ता का भी विश्वास हुआ है। हाँ, नियन्त्रणों के हटने पर उपभोक्ता सहकारी समितियों में बर्बादी हुई है और अब गैर साक्ष समितियों में युद्ध और युद्धोत्तरकालीन वृद्धि रुक गई प्रतीत होती है।

(४) एकाकी-कार्य समितियों का बहु-उद्देशीय समितियों में परिवर्तन—यह बड़ी स्वागतयोग्य प्रवृत्ति है। नव-संचालित बहु उद्देशीय समितियाँ ग्रामीण व्यक्तियों के व्यवसाय और दैनिक जीवन पर प्रभाव डालती हैं। उत्तरप्रदेश, बिहार और बम्बई नई बहु उद्देशीय समितियाँ संगठित कर रहे हैं। कुछ एक उद्देशीय समितियों का बहु उद्देशीय समितियों में परिवर्तित करने का भी सुभाव है।

(५) सीमित दायित्व का समर्थन—उत्तर प्रदेश, बम्बई और मद्रास में नई बहु उद्देशीय समितियाँ सीमित दायित्व के आधार पर संगठित की जा रही हैं और उनका कार्य क्षेत्र कई गाँवों तक विस्तृत है।

(६) रिजर्व बैंक का बढ़ता हुआ सहयोग—माग दान के अनिश्चित रिजर्व बैंक अन्य ऋणों में भी ग्राहकों की सहायता करने लगी है। उसने राज्य सहकारी बचत की वित्तीय सहायता में वृद्धि कर दी है। सन् १९४२-४३ में रिजर्व बैंक द्वारा राज्य बैंकों का दी जाने वाली वित्तीय सहायता केवल १३ लाख रुपये थी, सन् १९४१-४२ में १२३ करोड़ और सन् १९४४-४५ में यह सहायता २१-२१ करोड़ रुपये तक पहुँच गई। ब्याज दर भी केवल १३% थी। सहकारी भूमि बन्धक बचत को भी इसने अनुदानों में १० से २०% तक वृद्धि कर दी है। इसके अनिश्चित रिजर्व बैंक न सहकारी ग्राहकों की प्रगति का विषय में ध्यानहीन करने के हेतु कई कमेटीयाँ नियुक्त की हैं और कई सर्वेक्षण कराये हैं। इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय ग्रामीण साख्त सर्वे का बड़ा महत्व है, क्योंकि इसी की सिफारिशों के अनुसार ही आजकल भारत में सहकारी आन्दोलन को संचालित किया जा रहा है।

(७) अखिल भारतीय ग्रामीण साख्त सर्वे और सरकार की नीति—उक्त सर्वे कमेटी की रिपोर्ट सन् १९४४ में प्रकाशित की गई, जिसमें उसने अनक महत्वपूर्ण सुझाव दिये। भारत सरकार ने इन सुझावों को मानकर सहकारी आन्दोलन की प्रगति के लिए समुचित कदम उठाये हैं। ये सुझाव निम्नलिखित हैं—

( अ ) प्रत्येक स्तर पर सरकार सहकारी संस्थाओं के साथ सान्नेशरी स्थापित करे।

( आ ) छाद्य सम्बन्धी बाय को फसल की बिक्री एवं भण्डार सम्बन्धी कार्यों के साथ सम्बन्धित किया जाय।

( इ ) प्रारम्भिक समितियाँ बड़ आकार की बनाई जायें और उनके सदस्यों का दायित्व सीमित होना चाहिए।

( ई ) सारे देश में अनाज के गोदामों का जाल सा बिछा दिया जाय जिससे किसानों को अपनी फसल की बिक्री में सहायता हो।

( उ ) सहकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के हेतु स्कूल खोले जायें।

- ( ऊ ) इम्पीरियल बैंक का स्टेट बैंक के रूप में राष्ट्रीयकरण कर दिया जावे, जिससे यह बैंक सहकारी संस्थाओं की अधिक सहायता कर सके ।
- ( ए ) रिजर्व बैंक के नियमों में उपयुक्त परिवर्तन करके ग्रामीण ऋण की सुविधा के लिये अधिक धन उपलब्ध करना चाहिये ।
- ( ऐ ) एक अखिल भारतीय सहकारी विकास तथा गोदाम बोर्ड की स्थापना की जाय, जिसके प्राधीन एक विकास कोष एवं एक गोदाम सम्बन्धी कोष रखा जाय ।

इन सुझावों के प्रकाश में भारत सरकार ने मई सन् १९५५ में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट में संशोधन करके दो कोषों की स्थापना की — ( १ ) राष्ट्रीय कृषि साख कोष ( दीर्घकालीन ) एवं ( २ ) राष्ट्रीय कृषि साख कोष ( स्थिरीकरण ) । राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा गोदाम बोर्ड की स्थापना १ सितम्बर सन् १९५६ को की गई । १ जुलाई सन् १९५५ को इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण करके उसे स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का रूप दे दिया गया । सहकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार के संयुक्त प्रयत्न से एक केन्द्रीय समिति की स्थापना की गई है । इस योजना के प्राधीन पूना में एक अखिल भारतीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र तथा ५ क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है । इनके अतिरिक्त ८ अन्य प्रशिक्षण संस्थाएँ स्थापित की गईं जिनमें सामुदायिक योजनाओं में कार्य करने वाले सहकारी अधिकारियों की प्रशिक्षण दिया जाता है ।

पञ्च-वर्षीय योजनाओं में सहकारिता का महत्त्व—

पहली योजना में तीन प्रकार की साख के लिये प्रबन्ध किया गया था—ग्राम्य-कालीन ऋण, मध्यम-कालीन ऋण एवं दीर्घकालीन ऋण । भारत सरकार ने सहकारी बैंकों की सहायता के लिये ५ करोड़ रु० और रिजर्व बैंक ने मध्यकालीन ऋण के लिये ५ करोड़ रुपये का प्रबन्ध किया । प्रथम योजना में सहकारिता के विकास के लिये ६६१.२ लाख रुपये का प्रायोजन किया गया था । क्रय-विक्रय समितियों के संगठन पर अधिक बल दिया गया । बहु-उद्देश्य समितियों का महत्त्व स्पष्टतः स्वीकार किया गया, जिससे गाँव की सभी समस्याएँ समन्वित रूप से हल की जा सकें । जून सन् १९५५ में भारत में २२ प्रांतीय सहकारी बैंक ४६६ केन्द्रीय सहकारी बैंक और २६,६५४ कृषि साख समितियाँ थी । नगरीय न इस वर्ष ७१६ सहकारी बैंक, ८,३८६ साख समितियाँ और ३,६५१ धर्मिणी की समितियाँ थी । प्रथम योजना में सहकारी प्रशिक्षण के लिये १० लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी ।

दूसरी पञ्च वर्षीय योजना का उद्देश्य यह है कि गाँव की होती की सारी पैदावार का प्रबन्ध ग्रामीणों और गाँव का व्यापार सब सहकारी संस्थाओं के द्वारा हो ।

उद्योगों, मरानों और मजदूरी आदि के लिये भी सहकारी व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में द्वितीय योजना के प्रमुख तत्त्व निम्नलिखित हैं :—

बड़े पैमाने की सहकारी समितियाँ	१०,४००
अल्पकालीन ऋण	१५० करोड़ रु०
मध्यकालीन ऋण	५० करोड़ रु०
दीर्घकालीन ऋण	२५ करोड़ रु०
प्रारम्भिक विपणन समितियाँ	१,८००
सहकार चीनी मिल	३८
सहकारी रुई धुनने के कारखाने	४८
अन्य सहकारी समितियाँ	११८
केन्द्रीय और प्रदेशीय गोदाम	३५०
विपणन समितियों के गोदाम	१,५००
बड़ी समितियों के गोदाम	४,०००

सहकारिता विकास के हेतु योजना में ४७ करोड़ रु० का प्रायोजन किया गया है।

**भारतीय सहकारी आन्दोलन की धीमी प्रगति के कारण—**

जिस समय सहकारी आन्दोलन भारतवर्ष में प्रारम्भ हुआ था, उस समय कृषि एवं ग्रामीण ऋण की समस्याएँ हल करने के लिये इसे 'राम बाण' समझा जाता था। ऐसी आशा की जाती थी कि इसके द्वारा कृषकों में वित्तव्ययिता की भावना पैड़ेगी तथा वे अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जायेंगे। किन्तु दुर्भाग्य का विषय है कि गत अर्द्ध शताब्दी में इस आन्दोलन से उतना लाभ नहीं हुआ, जितनी कि आशा की जाती थी। इस आन्दोलन की धीमी गति के प्रधान कारण निम्नलिखित हैं :—

(१) सहकारिता के सिद्धान्तों से अनभिज्ञता—इस आन्दोलन की धीमी प्रगति का मुख्य कारण यह है कि भारतीय ग्रामीण जनता सहकारिता का धर्म भली प्रकार नहीं समझती है। सहकारिता क्या है, इसकी आधारशिला क्या है तथा इसके उद्देश्य क्या हैं—इन बातों से वे पूर्ण परिचित नहीं हैं। परिणामतः वे सहकारी समितियों की कार्यवाहियों में रुचि नहीं रखते। सहकारी समितियों एवं उनके सदस्यों की सख्या में आन्दोलन की वास्तविक सफलता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(२) अति अधिक राजकीय हस्तक्षेप—सहकारिता की सफलता के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि सहकारिता की भावना लोगों के हृदय में उमड़े एवं स्वेच्छा से वे इस शुभ कार्य में सम्मिलित हों, परन्तु दुर्भाग्य का विषय है कि यह आन्दोलन भारतीय ग्रामीण जनता पर बरबस लादा गया है। इस आन्दोलन में सरकारी नियन्त्रण आज भी इतना अधिक है कि सहकारी समितियों के सदस्य उन्हें 'सरकारी समितियाँ'



समझते हैं। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को इतनी शक्ति है कि सहकारी समिति के सदस्य स्वेच्छा से कुछ भी सहो कर सकने वास्तव में तो यह 'लोगों द्वारा लोगों के हितार्थ' (राजकीय हस्तक्षेप से परे) आन्दोलन है।

(३) पक्षपात तथा भ्रष्टाचार—भारतीय श्रमजीवी जनता शिक्षा के कारण जातिवाद तथा पक्षपात आदि की बुराइयों में फँसी हुई है। वेईमानी, भ्रष्टाचार, ऋण देने में जाति बान्धों एवं मित्रों आदि का पक्षपात करना, ऋण का समय पर भुगतान न करना आदि दोष प्रायः सभी समितियों में पाये जाते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि प्रायः सभी समितियों का प्रबन्ध अकुशल तथा अधिक्षित लोगों के हाथों में है।

(४) सहकारी साख पर अत्यधिक जोर—आन्दोलन की धीमी गति का एक कारण यह भी है कि इसमें केवल कृषकों को ऋण देने की ओर ही ध्यान दिया गया है। किसान कभी कभी ऋण का दुरुपयोग भी करता है अर्थात् वह उसे कृषि कार्य में न लगा कर अपने निजी कार्य में व्यय कर देता है। सन् १९४६ में सहकारी नियोजन समिति ने इस कमी का अनुभव करते हुए भारत में बहुत उद्देशीय समितियों की स्थापना का सुझाव दिया था।

(५) सदस्यों की शिक्षा, अज्ञानता एवं रुढ़िवादित्व—इस आन्दोलन का पाँचवाँ दोष यह है कि सहकारी समितियों के सदस्य अधिक्षित, अज्ञानी एवं रुढ़िवादी हैं, अतः प्रयत्न करने पर भी उन्हें सहकारिता के सिद्धान्त समझ में नहीं आते।

(६) सदस्यों में वचन की आदत का अभाव—वचन की आदत तथा सहकारिता एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। भारतीय कृषक अधिकतर फिज़ूलखर्चों होते हैं और इसी कारण वे सहकारिता के अनेक लाभों से वंचित रह जाते हैं।

(७) हिसाब की उचित जाँच न होना—सहकारी समितियों के हिसाब की जाँच पड़ताल भली प्रकार नहीं होती, अतः प्रबन्धकों की हिसाब किताब में गोल-माल करने का मौका मिल जाता है तथा गबन आदि की घटनाएँ होती रहती हैं।

(८) अपर्याप्त साधन—इस आन्दोलन का एक अन्य दोष यह है कि समितियों के पास धन का अभाव है। अतएव वे ग्रामीण जनता की पर्याप्त रूप से सहायता करने में असमर्थ रहते हैं। विविध होवर कृषकों को ऋण देने के लिये महाजन के चरम में फँसना पड़ता है।

(९) अपेक्षाकृत ऊँची व्याज-दर—साधारणतः व्याज की दर ६% से १२% तक रहती है। यद्यपि सरकार तथा रिजर्व बैंक द्वारा आन्दोलन को सहायता प्राप्त होती है, किन्तु अत्यधिक व्याज की दर का कारण यह है कि सहकारी समितियों की मुख्यतः बाहरी साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। इनके निजी साधन अपर्याप्त हैं।

(१०) आर्थिक व्यय—इस आन्दोलन का एक दोष यह भी है कि समितियों

का आर्थिक व्यय बहुत होता है। अतः इन्हे बहुत कम लाभ बचता है। कम लाभ के कारण ही ग्रामीण जनता इनके प्रति उदासीन रही है।

उपयुक्त दुर्बलताओं के ही कारण सर एम० विस्वेश्वरैया ने व्यंगपूर्वक कहा है—“सहकारी आन्दोलन की दिशा में अभी तक जो कुछ किया गया है, वह केवल सतह खरोबने के समान है।” भारतीय सहकारी आन्दोलन की दुर्बलताओं को दूर करने के लिये निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं :—

दोषों को दूर करने के उपाय—

(१) प्रारम्भिक समितियों का पुनर्गठन—प्रारम्भिक सहकारी साख समितियों को यह प्रयत्न करना चाहिये कि कृषकों की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करें, अर्थात् प्रारम्भिक समितियों को इस उद्देश्य की पूर्ति के हेतु बहु उद्देशीय समितियों में बदल देना चाहिये।

(२) सहकारी समितियों की कार्य-विधि में सुधार—जिन पुराने ऋणों का भुगतान सदस्यों पर बाकी है उन्हें कम कर दिया जाय और भविष्य में केवल उत्पादक कार्यों के लिये ही ऋण दिये जायें। सदस्यों में बचत की भावना को बढ़ाना चाहिये। समितियों के पास अधिक से अधिक धन सुरक्षित कोष में रहना चाहिये, जिससे कि आपत्ति काल में वे अपनी रक्षा कर सकें।

(३) सरकारी हस्तक्षेप में कमी—सरकारी कर्मचारियों द्वारा सहकारी समितियों के काम में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। सरकार को केवल आवश्यक देखभाल तथा परामर्श तक अपने को सीमित रखना चाहिये।

(४) सहकारिता की शिक्षा एवं प्रशिक्षण—ग्रामीण शिक्षा प्रणाली में सहकारिता की शिक्षा अनिवार्य रूप में दी जानी चाहिये तथा सहकारी कर्मचारियों के लिये विशेष प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

(५) सरकारी साभेदारी—जैसा कि अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने सुझाव दिया है, सभी स्तरों पर सरकार को सहकारी समितियों के साथ साभेदारी में सम्मिलित होना चाहिये।

(६) केन्द्रीय एवं राज्यीय सहकारी बैंकों का पुनर्गठन—केन्द्रीय तथा राज्यकीय सहकारी बैंकों का कार्यक्षेत्र सीमित कर दिया जाये, जिससे वे अपनी सम्बन्धित समितियों का भली प्रकार निरीक्षण कर सकें। व्यापारिक बैंकों से भी आर्थिक सहायता उम्मीद घनिष्ट सम्बन्ध होना चाहिये।

(७) सहकारी विक्रय प्रथा का विकास—सहकारी आन्दोलन की उन्नति के लिए यह जरूरी है कि सहकारी विक्रय प्रथा का विकास किया जाय। इससे समिति के सदस्यों तथा उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा।

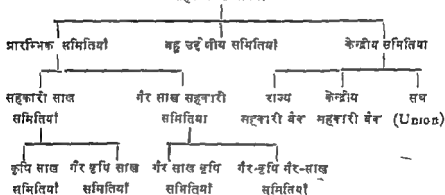
(८) सहकारी अनुसन्धान—भारत एक अत्यन्त विशाल देश है, अतः यहाँ की आर्थिक, सामाजिक तथा नैतिक समस्याओं को सहकारिता के आधार पर सुलझाने के लिये यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र में वैज्ञानिक ढंग के अनुसन्धान किये जायें।

अन्त में यह कहना अनावश्यक न होगा कि हमारे देश में सहकारिता का भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल है। देश की प्रायः सभी समस्याओं को सहकारिता के आधार पर सुगमतापूर्वक हल किया जा सकता है। इसी कारण किसी ने कहा है कि “सहकारिता की असफलता माते भारत की आजादी की असफलता होगी।” अतः सहकारी समितियों की दशा को धीमे ही मुधार कर उनका पुनर्गठन करना चाहिये।

## सहकारी समितियों का ढाँचा

हमारे देश में तीन प्रकार की सहकारी समितियाँ पाई जाती हैं।

### सहकारी समितियाँ



## (१) प्रारम्भिक सहकारी समितियाँ

(Primary Co-operative Societies)

जैसा कि उपर्युक्त चार्ट से स्पष्ट है, प्रारम्भिक सहकारी समितियों के चार प्रमुख भेद हैं :—

- (अ) प्रारम्भिक कृषि साख समितियाँ (Primary Agricultural Credit Societies)
- (ब) प्रारम्भिक गैर कृषि साख समिति (Primary Non-Agricultural Societies)

(न) प्रारम्भिक गैर-साख कृषि समितियाँ (Primary Non-credit Agricultural Societies)

(द) प्रारम्भिक-गैर-साख गैर-कृषि समितियाँ (Primary Non-credit Non Agricultural Societies)

(घ) प्रारम्भिक कृषि साख समितियाँ—

भारतीय सहकारी संगठन में कृषि साख समितियों की प्रधानता रही है। ये समितियाँ कृषि कार्यों के लिए साख की समुचित व्यवस्था करती हैं। सन् १९५६-५७ में इनकी संख्या १,६१,५१० थी जो कुल समितियों की प्रायः ७२% थी। उसी वर्ष इन समितियों के सदस्यों की संख्या ९१,१६,८४६ तथा पूँजी १६५७ के अन्त में इनकी क्रियाशील पूँजी १८\*३ करोड़ ४० थी।

विशेषतायें—

प्रारम्भिक कृषि साख समितियों की प्रधान विशेषतायें निम्नलिखित हैं:—

(१) समिति के सदस्य—सहकारी साख समितियों जो भारत में पाई जाती हैं उनका स्वल्प जर्मनी के रेफेज़न (Raiffeisen) समितियों के सिद्धान्तों पर स्थापित की गई है। समिति के निर्माण के लिए कम से कम १० व्यक्तियों की स्वेच्छात्मक स्वीकृति की आवश्यकता होती है और वे इस नुस्खे के अनुसार की जायेंगी कि वे एक-दूसरे के ही हों या न हों, इस प्रकार की समितियाँ ग्राम्य गाँव में होती हैं, अर्थात् इनके सदस्य के ही हो सकते हैं, जो एक ही गाँव में रहते हों, जिसमें वे एक-दूसरे की प्राथमिक स्थिति से पुराना परिचित हों। यद्यपि सदस्यों की उच्चतम संख्या पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, परन्तु यह उचित है कि कार्य की मुचासता के लिए सदस्यों की संख्या १०० से अधिक न होने पाए।

(२) दायित्व—समितियों के सदस्यों का दायित्व समीक्षित होता है। समीक्षित दायित्व बाह्य संगठनानाओं में विश्वास पैदा करता है और सदस्यों में पारस्परिक नियन्त्रण व निरीक्षण का आत्माह्वन देकर उन पर नैतिक एवं शिक्षणात्मक प्रभाव डालता है। किसी किसी समिति का दायित्व सीमित भी जाना है, लेकिन इसका लिए सरकार की विशेष स्वीकृति लेनी पड़ती है।

(३) कार्य क्षेत्र—इन समितियों का कार्य क्षेत्र बहुत ही सीमित जाना है और प्रायः एक गाँव ही एक समिति के लिए प्रादुर्भाव क्षेत्र है, क्योंकि विस्तृत क्षेत्र में सदस्यों में पारस्परिक सम्बन्ध नहीं हो सकता और इनलिय सदस्यों में नैतिक दृष्टिकोण के विकास की पूर्ति नहीं हो सकती।

(४) प्रबन्ध—इन समितियों का प्रबन्ध एक संचालन पूर्णरूपसे प्रज्ञान-प्रीत्य सदा अवैतनिक जाना है। समिति के सदस्यों की एक साधारण सभा होती है जो

वार्षिक या जब आवश्यकता हो बैठके (Meetings) करती है। साधारण सभा में प्रबन्ध समिति के सदस्यों का चुनाव किया जाता है जिनकी संख्या ५ या ७ होती है। प्रबन्ध समिति सहकारी समिति का दैनिक कार्य करती है। इसके कुछ प्रधान कर्त्तव्य निम्न हैं:—ऋण के हेतु दिये गये प्राधान्यपत्रों पर विचार करके ऋण दिये जाने की स्वीकृति देना, ऋण की वसूली करना एवं नये व्यक्तियों को समिति का सदस्य बनाना। इसके अतिरिक्त मन्त्री के हिसाब-किताब के जाँच एवं नई पूँजी की व्यवस्था करना भी प्रबन्ध समिति के कर्त्तव्यों में आता है। साधारण सभा में सदस्यों के व्यवहार, उधार की सीमा आदि के सम्बन्ध में उपनियम निश्चित कर दिए जाते हैं एवं प्रबन्ध समिति द्वारा प्रस्तुत वार्षिक हिसाब पर विचार भी साधारण सभा में होता है तथा लाभ, सुरक्षित कोष एवं शिक्षा तथा सेवा पर होने वाले व्यय की राशि निश्चित की जाती है।

(५) पूँजी—समिति की पूँजी के प्रधान ध्येय निम्नलिखित हैं—(१) सदस्यों द्वारा जमा राशि, (२) सदस्यों के प्रवेश शुल्क, (३) रक्षित कोष की राशि, (४) केन्द्रीय बैंको द्वारा प्रदत्त ऋण इत्यादि। समिति की सबसे महत्वपूर्ण निधि सुरक्षित कोष है। जिस सहकारी समिति के पास सुरक्षित काय अधिक होया, उसकी साख उत्तम होगी और केन्द्रीय बैंको द्वारा ऋण सरलता से प्राप्त हो सकेगा।

(६) उद्देश्य एवं कार्य—सहकारी साय समिति का प्रमुख उद्देश्य सदस्यों को सस्ती ऋण सुविधायें प्रदान करना है। प्रायः सदस्यों की निम्न कार्यों के लिए ऋण दिए जाते हैं—(१) उत्पादक कार्यों के लिए, (२) पुराने ऋणों से मुक्त करने के लिए और (३) अनुत्पादक कार्यों के लिए। उत्तम बीज, खाद तथा मजदूरी आदि उत्पादक कार्यों पर व्यय करने के लिए अल्पकालीन ऋण और गाय बिल इत्यादि खरीदने व भूमि के विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है। कभी कभी पुराने सदस्यों को ऋण से मुक्त करने के लिए एवं उन्हें महाजनो के चंगुल से बचाने के लिए अनुत्पादक कार्यों के लिए भी ऋण दिया जाता है।

(७) ऋण की वसूली—समितियाँ अपने सदस्यों को महाजनो के चंगुल से बचाने के लिए ऋण प्रदान करती हैं। ऋण की वसूली निस्तो में होती है। साधारणतः किन्तु का समय फसल कटने के बाद का समय होता है, क्योंकि फसल तैयार होने पर किसान स्व-व्रतापूर्वक अपने ऋण चुका सकत हैं। हाँ, फिर भी ऋण की वसूली में इन समितियों की काफी कठिनाई होती है। अधिकतर कृषक ऋण देने में तत्परता नहीं दिखाते, अतः ऋण की वसूली के लिए सदस्यों पर दबाव डालना पड़ता है।

(८) व्याज की दर—इन समितियों का मुख्य उद्देश्य कृषकों को महाजनो के चंगुल से छुड़ाने के लिए कम से कम व्याज की दर पर ऋण देना होता है। परन्तु

साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि व्याज की दर कम होने के कारण कृषक आवश्यकता से अधिक मात्रा में ऋण नहीं ले पाये।

(६) जमानत—समिति के सदस्यों का दायित्व असीमित होने के कारण इनकी व्यक्तिगत जमानत ही ऋण देने के लिए पर्याप्त मान ली जाती है। सदस्यों की ईमानदारी, मितव्ययिता तथा परिश्रम ही सर्वश्रेष्ठ जमानत है।

(१०) लाभ का वितरण—कृषि साख समितियों में प्रायः सारा लाभ सुरक्षित कोष में जमा कर दिया जाता है और लाभार्थ के रूप के सदस्यों को वितरित नहीं किया जा सकता। हाँ, सन् १९१२ के अधिनियम के अन्तर्गत सुरक्षित कोष में लाभ का एक निश्चित भाग जमा करने के बाद शेष राशि शिक्षा एवं दान के कार्यों के लिए दी जा सकती है और जिन समितियों में भ्रष्ट पूर्णों है, वहाँ कुछ सीमित लाभार्थ सदस्यों में वितरित किया जा सकता है।

(११) ग्राम ध्य की जाँच—समितियों के ग्राम ध्य की जाँच तथा देख भाल के लिए सरकार द्वारा अन्वेषको व निरीक्षको की नियुक्ति की जाती है। देख-भाल के लिए सहकारी सम भी होते हैं, जो इन समितियों को उचित रूप से हिसाब रखने, उनकी जाँच करने तथा रूपया वसूल करने में सहायता देने हैं।

(१२) भगडों का निपटारा एवं विघटन—सदस्यों के भगडों का निपटारा करने के लिए कहीं-कहीं पंचों की व्यवस्था है, जिससे कि धर्म की मुकुटमेवाजी में उनका पैसा बरबाद न हो। विघटन की आज्ञा देने का अधिकार केवल रजिस्ट्रार को है। समिति के कार्यों की जाँच के बाद यदि वह उचित समझे तो ऐसी आज्ञा दे सकता है। रजिस्ट्रार को इस अधिकार का प्रयोग केवल उसी दशा में करना चाहिये जबकि सदस्यों की बेईमानी के कारण समिति की वार्षिक दशा इतनी खराब हो जाय कि सुधार की कोई आज्ञा ही न रहे।

**कृषि साख समितियों की असफलता के कारण—**

भारत में कृषि साख समितियों को विशेष सफलता नहीं मिल सकती है। इनकी असफलता के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :—

(१) ऋण की वसूली में कठिनाई—इन समितियों द्वारा प्रदान किए हुए अधिकांश ऋण वसूल न हो सके। रिजर्व बैंक द्वारा प्राप्त आँकड़ों के अनुसार सन् १९५७-५८ में इन समितियों की अदत्त ऋण (Loans outstanding) राशि १०७ करोड़ ४० और बकाया ऋण (Overdues) २३ करोड़ ४० के लगभग थे। कृषक ऋण का अधिकांश भाग अनुत्पादक कार्यों में लगा देते हैं, जिससे ऋण का चुकारा समय पर नहीं हो पाता।

(२) पूँजी की अपर्याप्तता—कृषकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए

इन समितियों के पास पूँजी की भी कमी है। औसत रूप से प्रत्येक समिति की काय-शील पूँजी सन् १९५७-५८ में लगभग १३४ कराड रु० थी। उसी समय इनकी प्रत्येक सदस्य औसत पूँजी केवल २२ रु० और कायशील पूँजी १०२ रु० थी। पूँजी की न्यूनता के कारण कृषकों को विवश होकर महाजनो का सहारा लेना पड़ता है।

(३) ब्याज की ऊँची दर—इन समितियों द्वारा प्रदान किए गए ऋण पर ब्याज की दर भी अधिक होती है। उदाहरणार्थ, सन् १९५१-५२ में ब्याज की दर उत्तरप्रदेश में १२ से लेकर १५% तक, विन्ध्यप्रदेश में १२ से लेकर १६% तक और बंगाल में १२% तक थी। ये दरें निश्चय ही बहुत ऊँची हैं। इस ऊँची दर का प्रभाव समितियों की सफलता पर अच्छा नहीं पड़ता।

(४) अन्य दोष—इनके अतिरिक्त समितियों के संचालन, निरीक्षण तथा हिमाव आदि रखने में भी अनेक दोष पाए जाते हैं, जिनके कारण ये सफलतापूर्वक कार्य करने में असमर्थ सिद्ध होते हैं।

(ब) प्रारम्भिक गैर कृषि साख-समितियाँ—

गैर कृषि साख समितियों में तात्पर्य ऐसी समितियाँ हैं जो कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों में लग हुए व्यक्तियों का साख प्रदान करके उनकी सहायता करती हैं। ये समितियाँ मुख्यतः नगरी क्षेत्र में स्थापित की जाती हैं, जहाँ अधिकतर धर्मजीवी तथा गिरफ्तार रहते हैं। ये शुन्ज डेल्टा (Schulze Delitz) समितियों का आधार पर स्थापित की जाती हैं। इनका दायित्व भी सीमित होता है। इन समितियों का मुख्य उद्देश्य धर्म जीवियों तथा गिरफ्तारों का सस्ती दर पर साख सुविधा प्रदान करके उन्हें महाजनो व साहूकारों से जगुन से बचाना होता है। इन समितियों का विकास मद्रास व बम्बई राज्यों में बहुत अधिक दृष्टा है। इन्हें नगर साख समितियाँ (Urban Credit Societies) भी कहते हैं।

नगर साख समितियाँ दो वर्गों में विभाजित की जा सकती हैं—(अ) नगर बैंक और (ब) अन्य नगर साख समितियाँ। नगर बैंकों के साथ साधारण बैंकों में मिलने जुलने हैं, किन्तु अन्य नगर साख समितियाँ केवल सदस्यों में जमा लेन तथा उन्हें साख प्रदान करने का कार्य करती हैं। नगर साख समितियाँ बारखानों में काम करने वाले धर्मियों तथा अन्य कमचारियों द्वारा संगठित की जाती हैं। इनका सहकारा सचय समितियाँ (Co-operative Thrift Societies) तथा सहकारी शिल्पी समितियाँ आदि का प्रमुख स्थान है। देश के औद्योगीकरण के विकास के साथ साथ नगर साख समितियों की भूमिका अत्यन्त बढ़ेगी। अतएव उनका अग्रिम गन्तापन्नक प्रतीत होता है।

(स) प्रारम्भिक कृषि गैर-साख समितियाँ—

किमानों को ऋण प्रदान करना कृषि सहकारिता का केवल एक पहलू है। ऋण के अतिरिक्त कृषकण अन्य कार्यों में भी सहकारिता को अपना सकते हैं। कृषि

साख के अतिरिक्त ग्रामीण जीवन के शेष सभी पहलू गैर साख-सहकारिता (Non Credit Co operative) के अन्तर्गत आते हैं। सन् १९१२ के अधिनियम के पूर्व गैर साख समितियाँ स्थापित हो नहीं की जा सकती थी, क्योंकि उस समय योग्य एवं शिक्षित कर्मचारियों का अभाव था। हमारे देश में इनका विकास मुख्यतः द्वितीय महायुद्ध के बाद हुआ। युद्ध के समय सरकार नियंत्रित वस्तुओं के वितरण के हेतु सहकारी समितियाँ को प्रदानसा देती थी, क्योंकि इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सेवा करना होता है। अतः उस समय इस प्रकार की अनेक समितियाँ कपड़ा, चीनी, अम्ल तथा तेल आदि वस्तुओं के वितरण के लिये स्थापित की गईं। 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन ने भी इन समितियों की स्थापना को प्रेरित किया। अनेक अन्न राज्यों में सहकारी कृषि तथा बजर भूमि को कृषि योग्य बनाने की व्यवस्था करने के लिये एवं उन्नत बीज, खाद व कृषि यन्त्रों के वितरण के लिये भी अनेक समितियों का निर्माण किया गया।

गैर साख-कृषि समितियाँ के अन्तर्गत प्रायः निम्न का समावेश किया जाता है—

- (१) सहकारी जीवन सुधार समितियाँ (Better Living Societies)
- (२) सहकारी कृषि (Co operative Farming)
- (३) सहकारी विपणन (Co operative Marketing)
- (४) सहकारी उपभोग समितियाँ (Co operative Consumer's Societies)
- (५) सहकारी चकबन्दी समितियाँ (Co operative Consolidation of Holdings Societies)
- (६) सहकारी उपज सुरक्षा समितियाँ (Co operative Crop Protection Societies)
- (७) सहकारी सिंचाई समिति (Co operative Irrigation Societies)
- (८) सहकारी शिक्षा समितियाँ (Co operative Educational Societies)

गैर-साख-साख कृषि समितियों का संक्षिप्त परिचय—

(१) सहकारी जीवन सुधार समितियाँ—ग्रामीण समाज की अज्ञानता, भाग्य आदिना तथा अन्य कुरीतियों का उन्मूलन करने के लिये सहकारी जीवन सुधार समितियाँ स्थापित की जाती हैं। इनका व्यापक उद्देश्य उन्नत एवं उचित जीवन के प्रति कृषकों की अभिरुचि उत्पन्न करना है। ये समितियाँ सामाजिक कुप्रथाओं, सामाजिक एवं व्यक्तिगत अपव्यय, अन्ध विश्वास आदि को दूर करना आत्म विश्वास एवं आत्म निर्भरता की भावना को उत्पन्न करती हैं, जिससे कि कृषकगण स्वास्थ, रक्षा, सहाई, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि के द्वारा अपने व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को उन्नत बना सकें।



(२) सहकारी कृषि—ऐसे कृषक, जिनकी भूमि का आकार उप विभाजन एवं अप-व्ययन के कारण अनाधिक हो गया है, सहकारी कृषि के द्वारा भूमि के आधिक आकार की प्राप्ति कर सकते हैं। छोटे छोटे खेतों पर कृषि के आधुनिक साधन एवं मशीनों आदि का प्रयोग सुविधा से नहीं किया जा सकता और यदि किया भी जाता है, तो साधनों का अप-व्यय अधिक होता है और उत्पादन कम। अतः, एवं गाँव के अनेक कृषक मिलकर अपनी भूमि की सीमायें तोड़कर एक कर लेते हैं, और इस प्रकार कृषि के हेतु उन्हें बड़े आकार की भूमि मिल जाती है, जिस पर कृषि के आधुनिक साधनों का प्रयोग करके उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। सहकारी कृषि के अन्तर्गत कृषकों का उनकी भूमि में व्यक्तिगत स्वामित्व रहता है तथा अपनी भूमि के अनुपात में ही उन्हें लाभान्वित प्राप्त होता है। जो कृषक खेतों पर काम करते हैं, उन्हें वेतन दिया जाता है। वर्ष के अन्त में जो लाभ बचता है, उसमें से व्यय, सुरक्षा कोष आदि की राशि निकाल कर सदस्यों से भूमि के आकार के अनुपात में बाँट दिया जाता है। जिस प्रकार स व्यापार या व्यवसाय में साझेदारी होती है, उसी प्रकार कृषि में यह साझेदारी के ही समान है, जिसमें कृषकों के व्यक्तिगत अधिकार सुरक्षित रहते हैं और वे केवल सुविधाओं के लिये ही आपस में मिलकर खेती करते हैं।

(३) सहकारी विपणन समितियाँ—कृषि उत्पादन के विपणन व्ययों को न्यूनतम करने एवं अनावश्यक मध्यस्थों की सहायता को कम करने के लिये सहकारी विपणन प्रत्यक्ष आवश्यक है, जिसके द्वारा हम कृषकों को उसके उत्पादन का उचित मूल्य प्रदान कर सकते हैं।

(४) सहकारी उपभोक्ता समितियाँ—सहकारी उपभोक्ता स्टोर वे समितियाँ हैं, जिन्हें उपभोक्ता उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुयें प्राप्त करने तथा मध्यस्थों के शायण से बचने के लिये बनाते हैं। स्टोर सब सदस्यों का समान एक साथ खरीदते हैं, जिसमें उसकी थोक दामों पर सामान मिल जाता है। वस्तुओं की कीमत कम होने के साथ उनकी किस्म भी अच्छी होती है, फलतः सदस्यों को स्टोर में माल खरीदने में अधिक लाभ होता है। इन स्टोरों का जन्म सर्व प्रथम इंग्लैण्ड में हुआ। रॉकवेल क २५ जुलाहा ने एक ऐसी स्टोर का संगठन किया, जिसकी आदर्शचर्यजनक सफलता ने प्रेरित होकर धीरे धीरे बहुत से स्टोर इंग्लैण्ड में खुल गये और अन्य देशों में भी यह आन्दोलन फैलने लगा। इन स्टोरों के कुछ सिद्धान्त होते हैं, जिन्हें पालन करना प्रत्येक स्टोर के लिये आवश्यक होता है। प्रथम, वस्तुयें थोक दामों पर खरीद कर बाजार भावों पर बेची जाती है, दूसरे, वस्तुयें नगद बेची जाती हैं, उधार नहीं, एवं तीसरे, स्टोर का वार्षिक लाभ सब सदस्यों में उनकी खरीदारी के अनुपात में बाँट दिया जाता है।

भारत में स्टोर आन्दोलन की प्रगति—

भारत में स्टोर आन्दोलन का श्रीगणेश मद्रास में हुआ। यह राज्य आज भी

- ( ३ ) सरीदारी करने में दूरदर्शिता का अभाव ,
- ( ४ ) सदस्यों का स्टोर के साथ वफादार न होना ,
- ( ५ ) उधार व्यापार करना ,
- ( ६ ) थोक और विक्री मूल्यों में कम अन्तर होना ;
- ( ७ ) हिमाव ठीक तरह में न रखना ,
- ( ८ ) स्टोर के भवनों की व्यवस्था की अधिक्ता ,
- ( ९ ) निशुल्क सेवा पर अत्यधिक निर्भरता , एवं
- ( १० ) खुले बाजार में वस्तुओं मरलना में मिलन लगना ,

स्टोर ग्रान्दोलन की प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि इन कारणों को यथामन्त्र दूर करके उसे अधिक लाभप्रिय बनाने का उपाय किया जायें । इस सम्बन्ध में हमारे निम्न सुझाव हैं:—

- ( १ ) स्टोर में कम से कम ५,००० सदस्य बनाए जाय ।
- ( २ ) व्यापार के लिए आवश्यक पूँजी हिस्से बेच कर एवं केन्द्रीय बैंक से ऋण लेकर इकट्ठी की जाय ।
- ( ३ ) स्टोर्स की थोक समितियों का संगठन किया जाय । लगभग ५० शहरी और ग्रामीण स्टोर्स को एक कर्त्रीय उपभोक्ता मण्डल के अधीन रखा जाय ।
- ( ४ ) प्रत्येक राज्य में एक राज्यीय उपभोक्ता समिति संगठित की जाय, जिसका ५०% व्यय ५ वर्षों तक सरकार भेजे । यह समिति समन्वय का काम करेगी ।
- ( ५ ) सहकारी विभाग उपभोक्ता सहकारी स्टोर्स के संगठन में अधिक रुचि ले ।
- ( ६ ) औद्योगिक केन्द्रों में मजदूरों के लिए भन्द की दरें कम रखी जाएँ, जिसमें वे इनका लाभ उठा सकें ।
- ( ७ ) मजदूरों का माल उधार बेचा जाय, किन्तु प्रगत वेतन दिवस पर ही वसूल कर लिया जाय ।
- ( ८ ) सदस्यों को उपयोगिता समझाने के लिए लिखित साहित्य वितरित किया जाय ।
- ( ९ ) योग्य व्यक्ति जोकर रखे जायें । इसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए ।
- ( १० ) स्टोर में सदस्यों की भी भाव बेचे, जिसमें वे इसकी उपयोगिता में परिचित होकर सदस्य बन जायें ।

प्रथम योजना ॥ इन मण्डारों की प्रगति को विशेष स्थान दिया गया था । द्वितीय एवं तृतीय योजना में भी इनके लिए समस्याओं का विशेष अध्ययन करके विकास कार्यक्रम बनाने पर जोर दिया गया है । गाँवाँ में इनके विकास पर बल दिया गया है ।

(५) सहकारी चकबंदी समिति—उप विभाजन एवं अप खडन के दाप का निवारण करने के लिए सहकारी चकबंदी समितियों की स्थापना की जाती है । इनका विस्तृत वर्णन हम एक गत अध्याय में कर चुके हैं ।

(६) सहकारी उपज सुरक्षा समितियाँ—इन समितियों का प्रधान उद्देश्य सहकारी ढग पर सदस्यों का उपज का जगला वस्तुओं और प्रमाधिकृत पत्तियों से सुरक्षा करना है । इस उद्देश्य की पूर्ति का दार तार का बाँड लगाकर या चौकदार का प्रबंध करके का जाती है ।

(७) सहकारी सिंचाई समितियाँ—इन समितियों का मुख्य उद्देश्य सहकारी ढग पर सिंचाई की छोटी-छोटी योजनाओं का सम्पन्न करना है ।

(८) सहकारी शिक्षा समितियाँ—इनका मुख्य उद्देश्य ग्रामोपकरण में शिक्षा समस्याओं का व्यवस्था करना होता है और इस हेतु ये गाँवों में स्कूल, वाचनालय, ग्रो'रिगलिय, रात्रि पाठशाला, पुस्तकालय आदि की स्थापना करता है ।

(९) प्रारम्भिक गर-कृषि गर-माल समितियाँ—

जसा कि इनके नाम में स्पष्ट है ये समितियाँ गिरिपरा तथा श्रमिका के साल के अतिरिक्त अन्य आर्थिक कार्यों में सहायता प्रदान करता है । इनके अंतर्गत औद्योगिक समितियाँ (Industrial Co-operatives) गृह निर्माण समितियाँ (Co-operative Housing Societies) उपभोक्ता समितियाँ (Consumers Co-operatives) आदि का समावेश किया जाता है । हमारे ढग में औद्योगिक सहकारी समितियों का अभी पयात मात्रा में विकास नहीं हो सका है । कुटार एवं लघु उद्योगों के विकास के हेतु इन समितियों की स्थापना करना नितात आवश्यक है । इसी प्रकार मध्यम वर्ग के लोगो का गृह निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिए सहकारी गृह निर्माण समितियाँ स्थापित की जाती हैं । गृह निर्माण समितियों दो प्रकार की होती हैं—(अ) एक वह जो सदस्यों का मकान बनाने के लिए तांत्रिक राय तथा सामान आदि का खरादन में सहायता देती है और (ब) दूसरा वह जो मकान बनाता है और दाध समय में अपना लागत का पूरा करने के लिए अपने सदस्यों से कियाया वसूल करता है । इनके अतिरिक्त आनेवाले अय प्रकार की सहकारी समितियों का भी निर्माण होता है । इनमें श्रमिक शिक्षा गिरिपरा विद्यालयों, चानकालों का सहकारी समितियों के नाम उल्लेखनीय हैं । ग्रामों के कार्य के लिए भी सहकारी समितियों का निर्माण हुआ है ।

## (२) बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ

(Multipurpose Co operative Societies)

गत कुछ वर्षों से यह विवाद का प्रश्न है कि सहकारी समितियों का स्वरूप एक उद्देशीय हो या बहुउद्देशीय। अभी तक जितनी भी सहकारी समितियाँ प्रारम्भ की गई हैं, वे प्रायः एक विशिष्ट उद्देश्य का दृष्टि में रखकर शुरू की गई हैं तथा उनसे कृषकों की आर्थिक स्थिति में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है। इसी कारण अधिकतर लोगों की यह धारणा है कि सम्भवतः बहु उद्देश्याय समितियों द्वारा कृषकों की समस्त समस्याओं का हल हो सक। एक उद्देशीय समिति की दशा में बेचारे कृषकों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु एक समिति से दूसरी समिति के द्वार खटखटाने पड़ते हैं। इसका अनिर्दिष्ट कभी कभी यह भी होता है कि उन्होंने सहकारी साख समिति के पैसों में जा कृषि उत्पादन किया है, उसके बेचने के लिये, उसके सम्मुख समस्या हो, अथवा उसका पास पैसा तो है किन्तु समस्या यह हो कि उत्तम बीज अथवा उत्तम खाद कहां से प्राप्त की जाय। यही कारण है कि आजकल देश में यह विचारधारा बड़े पैमाने पर प्रचलित है कि सहकारी समितियाँ एक-उद्देशीय न होकर बहु उद्देशीय हों। सन् १९३९ की एक सभा में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों ने यह प्रस्ताव पास किया था कि देश में बहु उद्देशीय सहकारी समितियाँ खोली जानी चाहिये। विश्व के कुछ अन्य देश भी, जैसे—डेन्मार्क, जर्मनी, फिनलैण्ड, न्यूजीलैण्ड, स्वीडन आदि भी बहु-उद्देशीय समितियों के पक्ष में हैं।

बहु उद्देशीय समितियाँ वे हैं, जो केवल किसी एक कार्य को न करके अनेक कार्यों को करती हैं। इनका उद्देश्य अपने सदस्यों को केवल साख प्रदान करना ही नहीं, बल्कि अनेक प्रकार से उनकी सहायता करना भी होता है। इनका उद्देश्य कृषकों के आर्थिक जीवन का सर्वाङ्गीण विकास करना होता है। रिजर्व बैंक के अनुसार महत्वा रिता कृषकों के लिए केवल उसी दशा में लाभदायक हो सकती है जब वह उनके जीवन के प्रत्येक पहलू में सहायक हो। इसी आधार पर रिजर्व बैंक ने बहु उद्देशीय सहकारी समितियों का जोरदार समर्थन किया है। योजना आयोग का भी यह मत है कि भारत के आर्थिक क्षेत्र में बहु उद्देशीय सहकारी समितियों को विशेष स्थान मिलना चाहिये।

**बहु-उद्देशीय समितियों के लाभ—**

इन समितियों से कृषकों को निम्न लाभ प्राप्त होने की आशा है—

(१) ये समितियाँ कृषक वृत्त की आर्थिक कृषकों की समस्त समस्याओं को हल कर देती हैं एवं उनके जीवन को पुनर्गठित करके सुखमय बना देती हैं।

(२) इनकी सहायता से ग्रामीण साहूकारी पद्धति का विनाश होता जा रहा है ।

(३) इन समितियों में भीमस दायित्व होने से सभ्य स्थिति के व्यक्ति—गरीब, शरीर व मध्यम वर्गीय—इनके सदस्य बन सकते हैं । परिणामतः समिति की पूर्णता बढ़ जाती है और उद्देश्यों की पूर्ति सुगम हो जाती है ।

(४) बिना पटे-लिखे कृषक के आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिये इन समितियों द्वारा मात्र ध व विपणन व सीधा सम्बन्ध स्थापित हो जाता है ।

(५) विस्तृत कार्यक्रम होने के कारण इन समितियों को ज्ञान की प्राप्ति कम एवं लाभ की प्राप्ति अधिक होती है ।

(६) सामाजिक सुराडियों को दूर करके एव ग्रामीण जनता का नैतिक पुनरुत्थान करके गाँव का पुनर्निर्माण करने में भी इन समितियों ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया है ।

**बहु-उद्देशीय समितियों के दोष—**

(१) विभिन्न कामों का बोझ अपने ऊपर लेने के कारण बहु उद्देशीय समितियों का कार्य बहुत जटिल हो जाता है । सम्पूर्ण कार्य छोटे से प्रभावशाली व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित हो जाता है और सहकारिता की सच्ची भावना नष्ट हो जाती है ।

(२) समिति के समस्त कार्यों का ध्यान एक ही जगह प्रकट किया जाता है, जिससे किसी कार्य विशेष में होने वाली क्षति का सच्चा ज्ञान नहीं हो पाता ।

(३) इनका कार्य-क्षेत्र भी बहुत अधिक व्यापक होता है, अतएव योग्य सचालकों के प्रभाव में कभी-कभी समितियाँ असफल हो जाती हैं ।

उपयुक्त लाभों के ही कारण हमारे देश में बम्बई, मद्रास, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के राज्यों में बहु उद्देशीय समितियों का बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है । गत दस वर्षों में बहु-उद्देशीय समितियों ने प्रशसनीय प्रगति की है, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बम्बई, बंगाल और मध्य प्रदेश में । उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या सन् १९४५-४६ की ६६६२ में बढ़कर १९५५-५६ में ४१,६६० हो गई । बम्बई में सन् १९४५-४६ की २६४ संख्या सन् १९५३ में बढ़कर ३६६५ हो गई । सन् १९५० तक मद्रास सरकार ने ८८०२ समितियों को बहु उद्देशीय सहकारी समितियों में परिवर्तित कर दिया । सन् १९५१-५२ में उसने ऐसी ही और भी ३,००० समितियों का रूप बदला । बिहार में १९५५-५६ में इनकी संख्या १०,४८३, उड़ीसा में १७६, पश्चिमी बंगाल में १३६६ और मध्य प्रदेश में ५,००,००० थी । उनकी संख्या सदस्य संख्या, ऋण कार्यों लाभ आदि में सर्वाङ्गीण उन्नति हुई है ।

### (३) केन्द्रीय सहकारी समितियाँ

केन्द्रीय सहकारी समितियों का प्रमुख कार्य प्रारम्भिक समितियों का संगठन, निरीक्षण तथा उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है। आजकल इनके तीन प्रधान रूप हैं—

(१) मध (Union) -

(२) केन्द्रीय सहकारी बैंक (Central Co operative Bank) तथा

(३) राज्य सहकारी बैंक (State Co operative Bank)

(१) मध—मध तीन प्रकार के होते हैं—(अ) सरक्षित मध, (ब) निरीक्षक मध और (स) साहूकार मध। सरक्षित मध (Guaranteeing Union) बम्बई में है। ये मध सदस्य समितियों को केन्द्रीय बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण का सुरक्षा प्रदान करते हैं। निरीक्षक मध, जिसका काम निरीक्षण करना होता है, मुख्यतः बम्बई व मद्रास में है। साहूकार मध (Banking Union) का निर्माण किसी निश्चित क्षेत्र में विभिन्न समितियों के सम्मिलन से होता है। ऐसे मध पंजाब में हैं। ये कभी कभी प्रारम्भिक समितियों एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक के बीच सहयोग का कार्य भी करते हैं।

(२) केन्द्रीय सहकारी बैंक—मार्च प्रथम सन् १९१२ के सहकारी अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिक समितियों के अतिरिक्त उनके सदस्यों एवं केन्द्रीय बैंकों की स्थापना को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इनका मुख्य कार्य प्रारम्भिक समितियों का संगठन करना तथा उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है। प्राथमिक समितियों की आर्थिक सहायता के अतिरिक्त, ये समितियाँ साधारण बैंक सम्बन्धी कार्य भी करती हैं जैसे जनता की ऋण जमा के रूप में स्वीकार करना, वित्त बैंक, टुन्डी आदि का चलाना, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय तथा कभी कभी व्यक्तियों का अचल सम्पत्ति पर ऋण देना इत्यादि। द्वितीय महायुद्ध के कारण केन्द्रीय बैंक का आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। मूल्य में वृद्धि के कारण, युद्ध युग में, इनकी कार्यशाला पूर्ण, जमा की राशि तथा ऋण की वृद्धि में अत्यधिक वृद्धि हुई है। सन् १९५७-५८ में हमारे देश में ४१८ केन्द्रीय बैंक थे जिनके सदस्यों की संख्या ३२२,८१६ थी। इनकी कार्यशाला पूर्ण १४७ करोड़ रु० थी तथा इन्होंने १५६ करोड़ रुपये अग्रिम तथा ऋण के रूप में दिया था।

(३) राज्य सहकारी बैंक—प्रत्येक राज्य में राज्य सहकारी बैंक (State Co operative Bank) उच्चतम बैंक (Apex Bank) होता है। ये केन्द्रीय सहकारी बैंक के समन्वयन गृह (Clearing house) के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार राज्य

सहकारी बैंक केन्द्रीय बैंको के द्वारा प्रारम्भिक समितियों के कार्यों की प्रगति को भी प्रभावित करते हैं। देश का सहकारी आन्दोलन बहुत कुछ इन बैंको पर निर्भर करता है। यही कारण है कि सन् १९१५ में बैंकलगत समिति ने ऐसी उच्चतम बैंको की स्थापना पर जोर दिया था। सन् १९५७-५८ में इस प्रकार के बैंको की संख्या २१ थी, जिनके सदस्यों की संख्या ३२,१८१ थी। इनकी कार्यशील पूँजी १०६'०७ करोड़ रु० तथा संचित कोष ८'४७ करोड़ रु० थी।

(४) भूमि-बन्धक बैंक—भूमि-बन्धक बैंक कृषकों की भूमि को बन्धक रखकर उन्हें दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं—(अ) प्राथमिक भूमि बन्धक बैंक और (ब) केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक। सन् १९५१-५२ में भारत में ६ केन्द्रीय तथा २८६ प्राथमिक भूमि बन्धक बैंकें थी। सन् १९५७-५८ में केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंको की संख्या बढ़कर १५ हो गई। इनकी सदस्य संख्या १,५१,४८३, कार्यशील पूँजी ७५'८८ करोड़ रु० थी और इन्होंने ४'६२ करोड़ रुपये ऋण के रूप में दिये थे। सन् १९५७-५८ में कुल मिलाकर ३४७ प्राथमिक भूमि-बन्धक बैंक थे, जिनके सदस्यों की संख्या ३,७५,६८० थी तथा जिन्होंने २'५२ करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया था। इनकी कार्यशील पूँजी १४'०६ करोड़ रुपये थी। अभी तक इन बैंको का प्रमुख कार्य पुराने ऋणों के भुगतान के लिए ही ऋण देना रहा है। हाँ, गत कुछ समय में इन्होंने भूमि सुधार कार्यों के लिए भी ऋण दिए हैं। ग्रन्थ राज्यों की अपेक्षा मंसूर मद्रास तथा आन्ध्रप्रदेश में भूमि बन्धक बैंको की संख्या अधिक है।

## STANDARD QUESTIONS

- (1) Define Cooperation and point out its essentials.
- (2) Discuss the importance of Co operation in India.
- (3) Trace a brief history of the Co operative Movement in India from 1904 upto date.
- (4) Account for the slow growth of Co-operative movement in India. What methods would you suggest to remove its defects ?
- (5) Discuss the organisation and functions of a primary agricultural co-operative society.

- (6) Describe the functions of a multipurpose co-operative society. How far such societies can improve the economic life of village ?
  - (7) What is a central co-operative bank ? How does it help primary credit co-operative societies ?
  - (8) What is meant by a multi purpose co-operative society ? Would you prefer this type of society to a Single-purpose society ?
-



## सहकारी-कृषि

(Co-operative-Farming)

प्रारम्भिक—

अभी हाल में प्रकाशित भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उनके अनुसार सन् १९६६ तक भारत अनाज में आत्मनिर्भर हो जायगा। कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य में योजना में कृषि के विकास पर पर्याप्त बल दिया गया है। वर्तमान भारतीय कृषि की मौलिक एवं सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह है कि किन-किन उपायों से भूमि की उपज की मात्रा एवं प्रकार में वृद्धि की जाय। इस समस्या के अनेक आर्थिक व सामाजिक कारण हैं। आर्थिक कारणों में भूमि का अविविभाजन व अपखण्डन, उत्तम बीज व खाद का अभाव, सिंचाई की समुचित सुविधाओं का अभाव, कृषि के पुराने उपकरण आदि मुख्य हैं। कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इन समस्याओं को मुलभूताना अत्यन्त आवश्यक है तभी न्यूनतम व्यय पर अधिकतम उपज हो सकती है एवं देश के औद्योगीकरण के लिए पर्याप्त मात्रा में आवश्यक कच्चा माल प्राप्त हो सकता है। किन्तु अखंडी कृषि के कोई भी उपाय तब तक फलदायक नहीं हो सकते जब तक कृषि के लिए भूमि के यत्न तब बिखरे हुए खण्डों को आर्थिक भूखण्डों में न बदल दिया जाय।

बड़े पैमाने पर खेती की आवश्यकता—

कृषि के उत्पादन में वृद्धि करने के मार्ग में एक सबसे बड़ी बाधा अनाधिक जोतो की विद्यमानता है। खेत का आकार कृषि की लाभदायकता पर एक निरुपेक्ष प्रभाव रखता है। सच तो यह है कि ग्रामीण ऋण प्रवृत्ति और दोषपूर्ण निपटण की समस्याओं का मूल कारण जोतो का अनाधिक होना है। जब जोतें बहुत छोटी होती हैं, तो वे पर्याप्त भाग नहीं दे पाती। फल यह होता है कि किसान को ऊँची दर में ऋण देकर ऋण प्राप्त करने के लिये विवश होना पड़ता है और भाग की अपर्याप्तता के ही कारण इसके चुकने का अवसर नहीं आता। जोते वर्तमान में ही अनाधिक हो, ऐसी बात नहीं है, वरन् पीढ़ी दर पीढ़ी घटती होने के साथ-साथ उनके बँटने और

बिखरने से जीते अधिकाधिक अनाधिक होती जा रही है। कृषि उत्पादन की समस्या के स्थायी हल के लिये किसी न किसी रूप में बड़े पैमाने की खेती आवश्यक हो जाती है। संसार के विभिन्न देशों में बड़े पैमाने की खेती विभिन्न ढङ्गी से की जाती है, जो निम्नलिखित हैं—

(१) व्यक्तिगत कृषि—भारत में व्यक्तिगत कृषि (Individual Farming) सबसे अधिक लोकप्रिय है। इसके अन्तर्गत कृषक अपने व्यक्तिगत सीमित साधनों के द्वारा कृषि का कार्य करता है। अतः कृषि की इस प्रणाली में बड़े पैमाने पर कृषि के लाभ प्राप्त करना सम्भव है एवं अनेक अनावश्यक आर्थिक हानियाँ होती हैं। इस दोष के निवारणार्थ यदि अधिनियम के बल पर भूखण्डों का एकत्रीकरण करके कृषि की प्राथमिक इकाई निर्माण करने की चेष्टा की जाय, तो इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह होगा कि छोटे छोटे किसानों की स्वतन्त्रता समाप्त हो जायगी। वे विशाल कृषि क्षेत्रों के बतन भागी श्रमिक माने रह जावेंगे। अतः व्यक्तिगत कृषि हमारी समस्या का समुचित समाधान करने में असमर्थ है। यदि भारतीय उत्तराधिकार कानून के अन्तर्गत होने वाले भूमि के उत्तरोत्तर उपविभाजन को रोकना है, तो हमें कृषकों के किसी न किसी प्रकार के सहयोग के आधार पर कृषि को व्यवस्था करनी ही पड़ेगी।

(२) पूँजीवादी अथवा कम्पनी के आधार पर कृषि—कम्पनी के आधार पर कृषि (Corporate Farming) पूँजीवादी तरीके पर निभर करती है। इस पद्धति में एक संचालक समिति के प्रबन्ध में कृषि कार्य के लिए एक सम्मिलित संगठन का निर्माण किया जाता है, जिसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है एवं प्रत्येक सदस्य का उस पूँजी के अनुपात में लाभ का अंश मिलता है। इस प्रकार की कृषि में वृत्त कृषि के आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की कृषि का उद्देश्य मुख्यतः यह होता है कि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जाय न कि किसानों के हित की रक्षा की जाय। इस प्रकार की खेती में वे सब गुण दोष विद्यमान हैं जो कि एक पूँजीवादी संगठन में हैं। भारत में आजकल खाद्य समस्या बड़ी जटिल हो गई है। इस प्रकार की खेती के द्वारा फसलों की मात्रा में काफी वृद्धि हो सकती है। परन्तु देश की और किसानों की सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह न तो किसानों का ही भला कर सकती है और न देश का ही उपकार हो सकता है।

(३) सरकारी कृषि—सरकारी कृषि (State Farming) के अन्तर्गत कृषक फार्म पर भजद्वी पर कार्य करते हैं और फार्म पर स्वामित्व पूर्णतः सरकार का होता है और प्रबन्ध भी सरकार ही करती है। रूम में सरकारी खेती के प्रयोग किये गये हैं। भारत में भी सरकारी खेती को कुछ सीमा तक स्वीकार किया जा सकता है। देश में घटूत घटी मात्रा में ऐसी भूमि पड़ी है, जिस पर खेती नहीं की जा रही है, क्योंकि भूमि में कुछ ऐसे दोष हैं जिनको बहुत बड़ी मात्रा में खपया खर्च करके हटाया जा सकता

है। इतना रुपया एक साधारण व्यक्ति या कम्पनी नहीं जुटा सकती, केवल सरकार ही इस कार्य को कर सकती है। यहाँ प्रश्न उठता है कि सरकार स्वयं अपनी ओर से खेती कराये या किसी एजेंट के द्वारा। इसका कोई अन्तिम उत्तर नहीं दिया जा सकता। हमारी सम्मति में तो सरकार को चाहिये कि वह पहले अपने ही प्रबन्ध में देश के कुछ भागों की भूमि के बड़े-बड़े खेतों में कार्य आरम्भ करे और फिर यह देखे कि ऐसा करने में कुछ लाभ हो सकता है या नहीं। सच तो यह है कि जब सरकार खेती जैसी विद्यात्मक सम्पत्ति का अपनी ओर से, बिना किसी एजेंट के, सफल प्रबन्ध करती है, तो यह आशा करना अनुचित नहीं होगा कि वह इस नये क्षेत्र में भी अक्षय्य सफल होगी। चूँकि भूमि और कृषि व्यवसाय राज्यों के सामान-क्षेत्र में है, इसलिये सरकारी ढंग की खेती पर निरीक्षण उससे अधिक हो सकता है।

(४) सामूहिक खेती—इस प्रकार की खेती (Collective farming) फिलिस्तीन और रूस में आश्चर्यजनक रीति से सफल हुई है। सामूहिक खेती वह खेती है जिसमें व्यक्ति अपने साधनों को एकत्र कर एक प्रबन्ध समिति के आधीन, जिसे वे स्वयं चुनते हैं, मिल जुल कर काम करने का दायित्व ग्रहण करते हैं। यह प्रबन्ध समिति फार्म के प्रबन्ध के लिये, कार्य व आमदनी के बितरण तथा आधिक्य के निपटारे के लिये दोषी होती है। सभी नायकता सदस्यों को अम समूहों में बाँट दिया जाता है और कार्य का बँटवारा इन समूहों के आधार पर होता है। समूह का नेता अपने सदस्यों के कार्य की मात्रा व किस्म के लिये जिम्मेदार होता है। कार्य दिवस की इकाइयों (Work day units) के आधार पर पारिश्रमिक की गणना की जाती है अर्थात् पारिश्रमिक उन कार्य के मूल्य के अनुसार होता है जोकि एक औसत सामूहिक कृषक एक दिन में करता है। योग्यता में अन्तर या विशेष निपुणता के लिये कुछ कार्यों को अन्य कार्यों की अपेक्षा ऊँची थोड़ी की, इकाइयाँ प्रदान की जाती हैं। उत्पादन की योजना सरकार बनाती है। प्रत्येक सामूहिक फार्म को अपनी फसल का एक निश्चित अनुपातिक भाग सरकार को नियत दर से बेचना पड़ता है। सामूहिक खेती के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर यंत्रीकरण सम्भव हो जाता है, जिसमें कृषि उत्पादन में बड़ी वृद्धि की जा सकती है।

सरकारी खेती और सामूहिक खेती में एक अन्तर है। एक सरकारी फार्म पर काम करने वाले किसान केवल मजदूरी कमाते हैं जबकि एक सामूहिक फार्म पर काम करने वाले किसानों को दीर्घ कार्य के लिये मजदूरा मिलता है और फार्म व शुद्ध लाभ में भी भाग मिलता है। इस प्रकार सामूहिक खेती में फार्म का सुधार करने के लिये बड़ा प्रोत्साहन रहता है। यही नहीं, उत्पादन के साधनों पर

सामूहिक स्वामित्व का कारण समस्या को फाम क प्रबध म भी अधिक स्वतन्त्रता हाती है ।

यह कहा गया है कि सामूहिक स्वता का भारत म गलन सम्भा जा सकता है और सामाजिक आर्थिक समस्याय उपलब्ध हो सकती है । भारतीय कृषक एस प्रणाली म अपरिचित है । इस स्वाकार करना या न करना उस रीति पर एवं उस एजमा पर निर्भर है जिसके द्वारा इस प्रचलित किया जाय । भारतीय कृषक को भूमि के स्वामित्व म बड़ा प्रम है और उसका यह प्रम सामूहिक स्वता के प्रचलन के भाग म बड़ा बाधक बनगा । जबकि उद्योग व अथ धात्री म उत्पादन के साधनों के स्वामित्व म उनकी वस्तु नही छीनी जा रहा तो फिर बेकारे किसानों का ही अपना स्वामित्व छाड़ने के लिये क्या विवग किया जाय ? अतः यह मुझव दिया गया कि वर्तमान परिस्थितिया म ममूहिक स्वता भारत के लिये उपयुक्त नहा है ।

निस्संदह यदि सामूहिक स्वता का ढग भारत म चल पडा तो भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व का अंत हो जायगा । परंतु इसम उत्पादन म अद्वितीय वृद्धि हो जाती है जो किसान आय साधन द्वारा सम्भव नही है । यही नही रूप म इस प्रणाली का जो सफलता प्राप्त हुई है उसका कारण अब इसके पक्ष म एस तोग भी हो गये है जो पहले इस ठीक नही समझते थे । राज्या म जमींदारी उन्मूलन कानून पास हो जान म सामूहिक स्वता के पक्षपाता अब यह जोर के साथ कहन सगे है कि हर प्रकार की व्यक्तिगत स्वता बंद कर दनी चाहिये ।

इन परिस्थितिया म हमारा मत है कि हर राज्य क हर जिल के कुछ गावा म सामूहिक ढग की खेती प्रारम्भ कर दी जाये । ये गाव ऐसे हा जिन पर या तो पहल एक ही व्यक्ति का स्वामित्व था या दो चार का । यदि इन प्रयोगों म सफलता हो तो फिर इस प्रकार की स्वता म विस्तार किया जा सकता है ।

**सहकारी खेती—**

सहकारी खेती ॥ आग्य उस व्यवस्था का है जिसके अंतगत प्रत्येक किसान अपना भूमि का स्वामी बना रहता है लेकिन कृषि सम्बन्धी कार्यों को अथ लोग का साथ मिल कर करता है । सम्पूर्ण खेती एक सम्मिलित काय (Common Fund) म स किया जात है और मुल आय म स बांट लिये जाते है । कुछ आय विभिन्न किसानों म उनकी भूमियों के अनुपात म बांट दी जाता है । इस प्रकार जैसा कि योजना आयोग न भी कहा है सहकारी खेती का अर्थ है भूमि का एकत्रीकरण एवं समुक्त प्रयत्न ।

सहकारी, खेती, और सामूहिक स्वता म अंतर इस प्रकार है —

(१) सामूहिक स्वता म भूमि का स्वामित्व और भूमि की कृषि सामूहिक

होती है। व्यक्ति स्वामित्व का अधिकार 'समूह' के प्रति त्याग दिया जाता है। लेकिन, सहकारी खेती के अन्तर्गत, सदस्य उन भूमियों के स्वामी बने रहते हैं, जिन्हें वे एक निर्दिष्ट अवधि के लिये या मर्दब के लिये सहकारी खेती के हेतु सयुक्त कर लेते हैं।

(२) सामूहिक खेती में भूमि का प्रत्येक धारी (Holder) या किमी स्थान में वहाँ का प्रत्येक कृषक सदस्यता प्राप्त करने का अधिकार रखता है। उसे अलग नहीं रहने दिया जा सकता है। लेकिन सहकारी खेती का ऐच्छिक संगठन है और किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं होता कि उसे सदस्य बना ही लिया जाय।

(३) सामूहिक खेती के अन्तर्गत सरकार कृषि की योजना बनाती है, जिस शक्ति एवं शक्ति के प्रयोग द्वारा पूरा किया जाता है। लेकिन सहकारी खेती में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना।

(४) सामूहिक खेती के अन्तर्गत कार्य करत वालों को कुल शुद्ध आमदनी में से 'कार्य दिवस' (Work day) के सिद्धान्तानुसार कुछ भाग दिया जाता है। लेकिन सहकारी खेती के अन्तर्गत सदस्य मजदूरों की और गैर सदस्य मजदूरों को भी प्रचलित दरों में मजदूरी दी जाती है। असल लाभों को प्रदान की गई भूमि के मूल्यानुसार बाँट दिया जाता है।

मन बातों को ध्यान में रखते हुये बड़े पैमाने की खेती प्रारम्भ करने का सबसे अच्छा ढंग सहकारी खेती का है। इसमें न तो जनता के मौलिक रीति रिवाजों या आर्थिक अधिकारों पर ही कोई प्रभाव पड़ता है और न व्यक्तिगत सम्पत्ति में ही कोई परिवर्तन होता है। परन्तु उत्पादन की मात्रा में बहुत वृद्धि हो सकती है। यही कारण है कि अनेक विभिन्न समितियों ने इस प्रकार की खेती को भारत में अपनाय जाने के लिए मत प्रगट किया है।

सहकारी कृषि निम्न विशेषताओं में उपयुक्त होती है :—

(१) जबकि किसी नई भूमि को कृषि के लिये प्रयोग में लाना हो, तो काफी भूमि एक सहकारी समिति के अन्तर्गत निर्धारित की जा सकती है।

(२) जबकि वर्तमान भूमि किसी बड़े भूमि-पति के अधिकार में हो और उस पर वह स्वयं खेती नहीं करता, तो सहकारी समिति का निर्माण कर ऐसी भूमि सहकारी खेती के लिये बाँपक किराये या पट्टे पर प्राप्त की जा सकती है।

(३) जब विद्यमान भूमि पति यह चाहते हैं कि वे अपनी भूमियों को संचित करके सहकारी-समिति के रूप में कृषि करें।

सहकारी कृषि को विशेषतायें—

सहकारी खेती का निम्न विशेषतायें हैं :—

(१) भूमि पर एक इकाई के रूप में खेती की जाती है।

(२) भूमि के भिन्न भिन्न टुकड़ मिलाकर एक चक्र कर दिया जात है, उनके बीच ब वंश हटा दिया जात है जिससे खेती का प्रकार बड़ा हो जाय ।

(३) सदस्य का भूमि पर वैयक्तिक अधिकार बना रहता है किंतु अपनी कृषि करने का अधिकार वे समिति को सौंप देने है । खेती का उष्ण धनफल खाद, बीज, योजार आदि के निष्पन्न का अधिकार समिति को मिल जाता है ।

(४) समिति ही कुल उपादन का विवरण करेगी ।

(५) पदावार में मत्त या बिक्री धन में से प्रत्येक सदस्य को उसका भूमि अथवा भूमि के अनुपात में भुगतान किया जाता है ।

(६) कृषि पर कड़ा नियंत्रण होता है ।

(७) प्रत्येक सदस्य का प्रत्येक दिवस का भूमि सम्बन्धी रिकार्ड रखा जाता है ।

(८) एक प्रबंध समिति हिसाब किताब रिकार्ड व प्रबंध क सिय दायी होती है ।

**सहकारी खेती के विभिन्न स्वरूप—**

सहकारी खेती के चार रूप हो सकते हैं —

(१) सहकारी उन्नत खेती (Cooperative Better Farming)

(२) सहकारी समुच्च खेती (Cooperative Joint Farming)

(३) सहकारी किसान खेती (Cooperative Tenant Farming)

(४) सहकारी सामूहिक खेती (Cooperative Collective Farming) ।

अब इन चार प्रकार की सहकारी खेती के विषय में लिखा जायगा क्योंकि हर प्रकार की खेती के लिए कुछ भागों में समितियां बन गई हैं ।

(१) सहकारी उन्नत खेती समिति—एसी समिति वैयक्तिक स्वामित्व (individual ownership) और वैयक्तिक वास्तव्य (individual operatorship) के सिद्धान्त पर बनाई जाती है । इसका उद्देश्य कृषि के उन्नत ढंगों का प्रचलन करना है । इस प्रणाली के अंतर्गत किसान अपनी भूमि का स्वयं ही स्वामी बना रहता है और स्वतंत्र रूप से अपनी भूमि पर खेती भी करता रहता है । लेकिन कुछ बायों में उस सबकुछ का—मिलकर चलना पड़ता है । जैसे—समिति खेती के सम्बन्ध में विशेष योजना बनाती है, सदस्य उसी के अनुसार कार्य करते हैं । बाज और खाद सबकी ओर से समिति खरीदती है और इसी प्रकार जो उपज हाता है उस साफ करन व बेचन का काम भी समिति करती है ताकि मूल्य अच्छा मिल जाय । खेती का जोतना, फसलों का काटना और भणाना का प्रयोग मिला जुला रहता है । इसके अतिरिक्त अन्य सब बातों में सदस्य स्वतंत्र रहता है । समिति की इस सेवा व बढ़ने

म वह समिति को ज़ब्त कभीशन देता है और वष के अन्त में उसे कुछ लाभ (Patronage dividend) प्राप्त होता है। इस प्रकार की समितियाँ यूरोप के बहुत स देशों में विनापकर डे माफ़ म पाई जाता है।

(२) सहकारी समुक्त खेती समिति—इस समिति के अन्तर्गत व्यक्ति स्वामित्व व अधिकार का सम्मान किया जाता है लेकिन छोटे छोटे भू स्वामी अपनी भूमियाँ को (जो इतने कम आकार की है कि उन पर खेती करना आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता) मिला कर एक कर सेते है ताकि समुक्त रूप से खेती की जा सके पर्याप्त वैयक्तिक स्वामित्व किन्तु समुक्त कृषि की व्यवस्था की जाती है। सब जातों का आकार काफी बड़ा हो जाता है और सारी भूमि को एक इकाई मान कर खेती की जाती है। समिति एक कमेटी बना देती है और एक मैनजर नियुक्त कर देती है। सब सदस्यों को इस मैनजर के कहने के अनुसार भूमि पर काम करना होता है। प्रत्येक सदस्य का उसका दैनिक धर्म के बदले में मजदूरी दी जाती है। यह सब होने हुये भी हर सदस्य अपनी जोत का स्वामी बना रहता है, जिसका प्रमाण उस लाभांश व भुगतान में मिलता है जो वह अपनी भूमि के मूल्य के अनुपात में प्राप्त करता है। जो उपज समुक्त प्रयत्न द्वारा भूमि से प्राप्त होती है उसे बेचकर और आमदनी में स खर्चा निकालकर जा बचता है वह समिति सदस्यों में बांट देती है। खर्च में भूमि का लगान सदस्यों को मजदूरी, प्रबंधक का वेतन और सुरक्षित कोष में रखी जाने वाला रकम सम्मिलित होती है। समिति के मुख्य कार्य निम्न होते हैं—फसल की यात्रना बनाना, लाना सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं की समुक्त खरीद, खेती की उपज का समुक्त विज्रय, भूमि मुधार के लिए भूमि, फसलों एवं ग्रय सम्पत्ति की जमानत पर ऋण प्राप्त करना। सदस्यों के साथ यह समझौता होता है कि अलग हान पर व अपनी भूमि पर किये गये सुधार का खर्चा लौटा देंगे।

(३) सहकारी किसान खेती समिति—ऐसी समिति के अन्तर्गत स्वामित्व तो सामूहिक होता है लेकिन कृषि कार्य व्यक्तिगत आधार पर किया जाता है। समिति सरकार से या किसी बड़े जमींदार से भूमि या तो बिना लगान के या बहुत लम्बा अवधि के लिए पट्टे पर ल लेती है। फिर इस भूमि के कितने ही छोटे-छोटे भाग बँटके जाना की कुछ सख्या बना देती है और प्रत्येक जोत को अपने किसी सदस्य को पट्टे पर देती है जो इस समिति का लगानदार कहलाता है। सम्पूर्ण भूमि उस योजना के अनुसार जानी और बाँटी जाती है जो समिति बना देती है लेकिन यात्रना किस प्रकार कार्यावित्त की जाय, यह प्रत्येक सदस्य की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है। यद्यपि समिति प्रत्येक सदस्य को आवश्यकतानुसार ऋण, बीज, खाद और बहु-मूल्य कृषि औजार दान तथा सदस्यों की उपज मण्डी में बेचने का दायित्व अपने ऊपर लेती है तथापि सदस्य की इच्छा है कि वह इन सुविधाओं का लाभ उठाये या नहीं।

वे अपना समय लाने के लिये और वचन में पूर्ण स्वतन्त्र होंगे। एक जगहदार मध्यम अथवा जो कि नियमित रूप से जगहदार करता है। इस प्रकार समिति जमींदार का स्थान ले लेता है और जो लाभ प्राप्त होता है वह सब वर्गों के लिये वितरित कर सचिव काय में कुछ निश्चित रकम डालकर सदस्या में उस अनुपात में बाँट दिया जाता है जिसमें वह जगह दाने है।

(४) सहकारी सामूहिक खेती समिति—इस प्रणाली में जमीन भूमि का स्वामि या वह कृषि कार्य संचालन दोनों ही सामूहिक आधार पर होते हैं। इस प्रकार की समिति के पास भी भूमि या तो बिना जगह के होती है या लम्बे पट्टे पर होती है। सम्पूर्ण भूमि पर वह नियुक्त होती करती है जिसमें सब मध्यम मिल कर काम कर रहे हैं और इस काम के करने में उनकी नियमित वेतन दिया जाता है। वेद के अन्त में लाभ मालूम किया जाते हैं और मजदूरी प्रत्येक सम्बन्ध व्यय में सचिव काय में जमा की जाने वाली रकम निकाल कर जो लाभ बचता है वह प्रत्येक सदस्य को उसका कुल मजदूरी के अनुपात में बाँट दिया जाता है। इस प्रकार की समिति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि बड़े पैमाने पर खेती करने के कारण उत्पादन में मशीनों का प्रयोग असाधारण किया जा सकता है। इस दृष्टि में काम के मजदूर न तो व्यक्तिगत स्वामी रहते हैं और न व्यक्तिगत कार्यकर्ता (neither individual owners nor individual operators)।

भारत में सहकारी खेती का सबसे उपयुक्त रूप—

मरीया कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सहकारी सामूहिक खेती या सहकारी किसान खेती समिति का संगठन तब किया जा सकता है जबकि समिति के पास भूमि हो। अतः यह उन देशों में सबसे अधिक उपयुक्त है जबकि मुधार कर या अन्य किंमतों के द्वारा भूमि प्राप्त की गई है। जैसे—धारणाभिदा रिटायर्ड सैनिकों या भूमिहीन मजदूरों के बचाने के हेतु। सरकार को चाहिए कि वह कृषि यंत्रों के लिए या कृषि कार्यों के लिए पूँजीगत व्यय में सहायता करे।

सहकारी उन्नत खेती समितियों व्यापक पैमाने पर संगठित की जानी चाहिए। राज्य इस निम्न सहायता दे सकता है—(अ) नियुक्त स्टाफ (आ) इमारतें स्थायी मुधार और कीमती कृषि यंत्रों के लिए दीर्घकालीन ऋण (इ) पत्र एवं साज सामान के लिए मध्यमकालीन ऋण।

सहकारी नियुक्त खेती समितियों की स्थापना करना भारत में सभा जगह पर उचित न होगा। सरकार को चाहिए कि वह इन समितियों के संगठन में प्राथमिक सहायता प्रदान कर सहायता परामर्शदाता मैनजर के अथवा नियुक्त कम आर्थिक सहायता प्रदान कर सकता है। सरकार को चाहिए कि समिति



के प्राग्भिक वर्षों के खर्च स्वयं चुकाये। केन्द्रीय सहकारी बैंक अपने काय क्षेत्र में आने वाली मयुक्त खेती समिति का लघु एवं मध्यकालीन ऋण दे और दीर्घकालीन ऋण भूमि अधक बेचो या सरकार द्वारा दिये जायें।

सहकारी खेती के लाभ—

यदि भारत में सहकारी खेती को अपनाया जाय, तो इसके अनन्य आर्थिक और सामाजिक लाभ होंगे जबकि सामूहिक खेती के कोई दोष इसमें नहीं हैं। ये लाभ निम्नलिखित हैं:—

(१) किमान उत्पादन बढ़ाने में प्रमत्त होंगे और साथ ही कार्य के व्यय भी कम हो जायेंगे, क्योंकि केन्द्रित प्रबन्ध व विकेन्द्रित नियंत्रण के लाभ उसे प्राप्त हो जाते हैं, वह कृषि विशेषज्ञों की सलाहों का प्रयोग कर सकता है, खेती की उत्तम टेक्नीक ग्रहण कर सकता है, अच्छा मान खरीदने में मितव्ययिता हो जाती है, फसल का विपणन सुविधापूर्वक किया जा सकता है, कीमती कृषि मशीनों तथा साज सामान का प्रयोग हो सकता है।

(२) सहकारी खेती कृषकों में एक सामाजिक चेतना और सुरक्षा की भावना विकसित करेगी, उनके आवास सम्बन्धी दशाओं में सुधार हो जायगा, काम करने की दशाएँ अच्छी हो जायगी, काम के घण्टे कम हो जायेंगे, मनोरंजन के लिए अधिक समय मिल सकेगा, चिकित्सा, शिक्षा एवं अन्य सुविधाएँ भी उत्तम स्तर पर प्राप्त हो सकेंगी। श्रम का पुरस्कार भी बढ़ जायगा, क्योंकि सहकारी विधि के अन्तर्गत प्रत्येक सदस्य खेती में प्रत्यक्ष रुचि लेना लगता है। लालच, स्वार्थ आदि सामाजिक प्रवृत्तियाँ मन्द पड़ जाती हैं।

(३) उक्त लाभ न केवल किसानों को, जोकि सहकारी खेती में भाग लेंगे वरन् सम्पूर्ण समाज को ही मिलेंगे। उत्पादन बढ़ने से ग्रामीण कार्यकर्तियों का जीवन स्तर भी ऊँचा हो जायगा, सदस्यों में जनतन्त्रीय भावना विकसित होगी, भूमि रहित नवयुवक मजदूरों को भी भूमि पर बसने का अवसर मिलेगा।

(४) सयुक्त सहकारी समितियों के गठन से कृषक और सरकार के मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध की स्थापना हो सकेगी। सहकारी कृषि समितियों के द्वारा सरकार अधिक व्यापक पैमाने पर अपने विभिन्न अनुसन्धानों के परिणामों का सत्रिय प्रदर्शन कर सकेगी, क्योंकि उसके अपने प्रदर्शन फार्मों की मर्यादा अभी कम है। आकस्मिक मकद के समय सरकार अपनी कृषि नीतियों को (जैसे फसल उत्पादन, गन्ना वसूली आदि के सम्बन्ध में) सरलता से कार्यान्वित कर सकेगी। सहकारी कृषि समितियों के द्वारा सरकार को कृषि सम्बन्धी आँकड़े संग्रह करने में भी सहायता मिलेगी।

किया है कि दश में सहकारी खेती को प्राप्ताह्न दिया जाए। साथ ही भूमिस्वामित्व की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का भी निर्देश दिया गया है। अधिकतम सीमा निर्धारित करने के पत्रस्वरूप सरकार जो भूमि हस्तगत करेगी, उस भूमिहीनों में वितरित नहीं किया जायेगा, बल्कि भूमिहीनों की सहकारी समितियाँ बनाई जायेंगी और यह प्रतिरिक्त भूमि इन समितियों को खेती करने के लिये दी जायेगी। पहले तो सहकारी कृषि सम्बन्धी प्रश्नों पर अधिवेशन में ही बहुत ज़ारों में बहस हुई थी। उसका बाद मसदा में तथा मसदा के बाहर विभिन्न सभा सम्मेलनों में इस पर बहस बिना रुकती चला आ रहा है। यह कितना विवादास्पद विषय बना है उसका अनुमान हम बात में ही लगा लिया जा सकता है कि राजाजी, श्री मुशी, श्री रंगा जैसे व्यक्तियों ने भी प्रस्तावित सहकारी कृषि की आलोचना की है। लेकिन सरकार इसको कार्यान्वित करने के लिये कृत मकल्प है क्योंकि इसे वह देश में सामाजिक तथा आर्थिक क्रान्ति का अनिवार्य अंग मानती है।

सहकारी कृषि के प्रश्न पर विचार करने समय हमें सबसे पहले यह विचार करना चाहिये कि किसानों के सामने क्या कठिनाइयाँ हैं और कृषि व्यवस्था के सम्बन्ध में हमारे मुख्य लक्ष्य क्या हैं। कृषि समस्याओं का संक्षेप में इस प्रकार वर्णन किया जा सकता है — (१) भूमि की कमी तथा बिखरे हुए खेत, (२) मज़दूरी तथा धारों की अपर्याप्तता, (३) अल्प आय, (४) पर्याप्त तथा कम व्याज वाले ऋण की व्यवस्था का अभाव, (५) जमीन के मुकाबले जन संख्या की भारी बहुतायत, (६) गाँवों में उद्योग धंधों की कमी, (७) मिचवाई, अच्छे बीजों तथा मवाद की उन्नत व्यवस्था का अभाव, (८) पशुओं की होन दशा, (९) बुनियादी शिक्षा का अभाव, (१०) मुधारों तथा परिवर्तन के प्रति आत्मरक्षाशील मनोवृत्ति तथा किसी हद तक प्रतिरोध की भावना।

विचारणीय विषय तो यह है कि इन समस्याओं का समाधान कैसे हो और कृषक राष्ट्र के आर्थिक विकास का अंग कैसे बने। जब हम भूमि मुधारों तथा कृषि नीति की बर्चा करते तो हम इन महत्वपूर्ण उद्देश्यों को सतत दृष्टि में रखना चाहिए — (१) किसानों की आर्थिक तथा सांस्कृतिक उन्नति हो, (२) खाद्य उत्पादन में इतनी वृद्धि हो कि देश आत्मनिर्भर बन जाए तथा (३) वह लोकतन्त्रीय पद्धति अधुणा बनी रहे जिसमें व्यक्ति तथा समाज के हितों का साथ-साथ निर्वाह हो सके।

जो लोग बिना सोचे विचारें एक दम सामूहिक कृषि के गीत गाने लगते हैं उन्हें यह नहीं भूलना चाहिये कि सावियन सभ में सामूहिक कृषि का प्रयोग सफल नहीं रहा। जब पहले किसानों से जमीन छीनकर उन्हें कृषि मजदूरों के रूप में परिणत किया गया तो उन्होंने प्रबल विरोध किया था और इस प्रतिरोध में बहुतों का मफापा हुआ। १९३० में सोवियत सरकार की अपनी गलती का अनुभव हुआ

हागा । इस पर सामूहिक कृषि फार्मों को अधिक उत्पादन के लिये प्रोत्साहित करने के हेतु कुछ गियायतें दी गई । उनमें से एक उल्लेखनीय है और वह यह है कि प्रत्येक किसान परिवार अपना एक 'उद्यान भूमि खंड' रख सकता था । लेकिन सामूहिक कृषि फार्मों के परिणाम सब भी आशाप्रद न रहे । फलतः १९४६-५० में कृषि नगर की योजना चली । वह भी कुछ दिनों बाद त्याग दी गई । अतः किसानों का प्रोत्साहित करने के लिए उनका द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मूल्य वृद्धि की गई तथा कृषि सम्बन्धी कर घटाये गये । इस प्रकार ३५ वर्षों के इन बड़े परीक्षणों का वह परिणाम न निकला जिसकी कि आशा की गई थी । चीन ने 'कम्प्यूनी' के प्रयोग के रूप में कम से भी आगे जो कदम बढ़ाया है, उसके बारे में भी निष्पक्ष विवेचन आशावादी नहीं मानूँ देते । उनका कहना है कि चीन के औद्योगिकीकरण के मुकाबले जापान में औद्योगिकीकरण का अनुपात अधिक है । बात यह है कि उसने वैज्ञानिक साधनों का अधिक उपयोग किया है ।

सहकारी खेती का प्रयोग देश में सफल हो सकेगा, इस बारे में सफाये उठाई जा रही है ।

सहकारी खेती के प्रस्ताव के विरोध में—

राजाजी का कहना है, 'साम्यवादी देशों को छोड़कर जहाँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अभाव है और लोगों में जबरदस्ती काम कराया जाता ॥ वही भी सहकारी खेती का प्रयोग नहीं किया गया । सहकारी खेती बिना बल प्रयोग के संभव नहीं होगी । लोग खुशी में मजदूर बनने के लिये राजी नहीं होंगे और किसान तो और भी कम । हमारे देश में सहकारी खेती भयकर रूप में विफल होगी । जो पचायती द्वारा खेती कराने की बात करते हैं उन्हें मद्रास के उस प्रयोग का अध्ययन कर लेना चाहिये जबकि छोटे जंगल पचायती के समुदाय कर दिये गये थे ।

मुन्शी जी को भी सहकारी खेती में जोर जबरदस्ती की आशंका है । उन्होंने सहकारी खेती के विरुद्ध ये आपत्तियाँ प्रस्तुत की हैं :—(१) हमारे पास काफी साधन प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं हैं । इस समय का अधिकांश सहकारी समितियाँ हैं, उनका काम केवल पत्र देना है । उनमें पैसा बैंकों से मिलता है । साधनों के रूप में सदस्यों का योग तो मुश्किल से दसवाँ हिस्सा भी नहीं होता । भूमिहीन श्रमिकों को कुशल किसानों के रूप में नहीं बदला जा सकेगा । (२) सहकारी खेती का प्रयोग भारत में कहीं भी सफल नहीं हुआ । मद्रास, पंजाब और अन्य जहाँ भी वह किया गया अन्त में उसे छोड़ देना पड़ा । किसान की अपनी भूमि में बेहद मोह होता है और वह उसे सहकारी खेती में शामिल करने के लिए राजी नहीं होगा । (३) दुनिया में सहकारी खेती में कहीं भी उत्पादन नहीं बढ़ा । जापान और इंग्लैंड में अन्त

उत्पादन बढा है, किन्तु उसका श्रेय व्यक्तिगत खेती का है। किसान लाभ की आशा में काम करता है। सहकारी समितियाँ किसानों को खाद, अच्छे बीज, यंत्र को सुरक्षित रखने और बिकवाने में मदद दे सकती हैं। युगोन्मादिया में वन प्रयोग द्वारा सहकारी खेती जारी की गई तो उत्पादन १५-२० प्रतिशत घट गया। हमारे देश में वर्तमान खेती की व्यवस्था हजारों वर्षों में चली आ रही है। पारिवारिक इकाई ही इसके लिए सर्वोत्तम होगी।

श्री रघुवीरमहाय ( वा-उ. प्र ) ने कहा कि देश के सहकारी आन्दोलन में एक गाँधी "कू" आनी है क्योंकि अधिकारियों का सहकारी समस्याओं में निकट सम्पर्क है। श्री वाजपेयी ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि सहकारी खेती का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना है और कुछ लोग कहते हैं कि साम्यवादियों का बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के लिए है। इसमें उत्पादन का बढ़ नहीं सकता। बलिक गाँव में अव्यवस्था और नौकरशाही बढ़ेगी। अगर आप सहकारी खेती में शामिल करने के लिए जबर-दस्ती नहीं करेंगे तो किसान सहकारी खेती में शामिल नहीं होंगे। आप सहकारी खेती का ज्यादा आर्थिक सहायता देंगे और निजी खेती को नहीं। बिना दबाव के सहकारी खेती की स्थापना न किसी देश में हुई है और न यहाँ होगी।

श्री रघुनारायण ने कहा कि जापानी खेती बड़े बड़े खेतों के लिए उपयुक्त नहीं है। इस व्यवस्था में छोटे खेतों में ही हम अधिक उत्पादन कर सकते हैं। आपने छोटे खेतों को मिलाकर बड़े खेतों में परिणत किये जाने का सुझाव रखा। कुछ सदस्यों ने यह भी कहा बताया जाता है कि अनिश्चित भूमि के लिए जाने की बात कहते हैं। पूर्व हमें यह जान लेना चाहिये कि हमारे पास कितनी अनिश्चित भूमि है जिस हम बाँटेंगे। यह जानकारी नहीं रहने से इस बात की पूरी आशंका है कि जिनके पास भूमि है वे भूमि की उपयोगिता पर कम खर्च कर सकते हैं और उसका उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अतः इन मामलों में सरकार को जल्दी करना चाहिए ताकि भूमि की समस्या हल करते हुए उत्पादन में भी कमी न होने पाए।

हमारी भारत सरकार एक राज्य सरकार बार-बार यह जोर दे रही है कि सहकारिता के आधार पर कृषि होनी चाहिए। यह तो बिल्कुल ठीक है किन्तु हमारे देश की स्थिति के अनुकूल सहकारिता किस प्रकार की हो इसका कोई ठीक-ठीक ढाँचा उनके दिमाग में नहीं मानूँ होता। नतीजा यह हो रहा है कि आजकल जितनी सहकारी समितियाँ बनी हुई हैं उनका लाभ केवल पट्टे-लिखे लोग ही उठाते हैं और उनमें अधिकतर भाई-भतीजावाद का बोलबाला रहता है। वे प्रायः एक ही परिवार के सदस्य होते हैं जिसमें अनपढ़ किसानों को कोई लाभ नहीं होता। आजकल जितनी कृषि सहकारी समितियाँ हैं तथा बन रही हैं वे ऐसे लोगों की हैं जिनके पास सँकड़ो एकड़ जमीन है, जो मौलस नगने पर उनके कब्जे में निकलने वाली है,

मफनता प्राप्त की है उनसे भी हम कुछ सीख सकते हैं और भारी दुनिया इस सिद्धान्त को तमनाम कर चुकी है कि सहकारिता के जरिए ही अनाज का उत्पादन और नांगो का रहन सहन ऊँचा हो सकता है ।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग सहकारिता के उमूल का विरोध कर रहे हैं, वे उम वग म सम्बन्ध रखते हैं जिसे अपन निहित स्वार्थों को ठम लगने का खतरा है । इन लोगों ने अपने दिमाग को ऐसी कोठरी में बन्द कर रखा है जहाँ न हवा आती है, न धूप । शायद ही कोई समझदार आदमी ऐसा भित्तिगा जो सहकारिता के तरीक का विरोध करता हो, यहाँ तक कि पूजोवादी देव भी सहकारिता को मानते हैं । आखिर हम यही तो चाहते हैं कि किसान अपनी अपनी जमीनें रखें, लेकिन खेती मिल कर करें और पैसावार का उसी हिसाब में बाँट ले । यह ठीक है कि इसमें कुछ सीखे हुए आदमियों की आवश्यकता है । पुराने ढग की सहकारी समितियाँ यहाँ काम नहीं दे सकती, क्योंकि उनमें अफसरवाही का बोलबाला है । आजकल हिन्दुस्तान में खेती का कोई तरीका अच्छा नहीं है, मिसाल इसके कि हम सहकारिता के उमूल को उसमें लागू करें । इसलिए सहकारिता आज का युग धर्म है । श्री नेहरू ने सहकारिता का भारत की मयुक्त परिवार प्रणाली के साथ मुकाबला किया है । उन्होंने कहा कि बहुधा एक मयुक्त परिवार में आद्यों का किमी सम्पत्ति पर प्रपक रूप से स्वामित्व का अधिकार होता है, परन्तु उमके बावजूद परिवार के सभी सदस्यों के लाभाय सम्पत्ति की व्यवस्था मयुक्त रूप में होती है । उन्होंने कहा—सहकारी कृषि भी इसी प्रकार ध्यनित स्वामित्व को नहीं हटाती और न ही किसान को उसकी भूमि से बचिन करती है, बनि-भूमि की बहतर व्यवस्था होने की मभावना बढ़ाती है ।

नेहरूजी ने अपने भाषण में कुछ नई बातें कही । एक यह कि कुछ लोग कहते हैं कि सहकारिता में शामिल होने के लिए किसानों पर दबाव डाला जायगा । उन्होंने कहा कि जब तक वलमान मविधान लागू रहेगा तब तक इस तरह का भय निराधार है । हाँ, यदि मविधान बदन गया तो ये नहीं कह सकता । लेकिन यह एक दम गलत बात होगी कि एक किसान गाँव में सहकारिता के निर्माण में बाधक बने और उसे बर्दास्त किया जाए । दूसरी नई बात इन्होंने यह बताई कि लोग कहते हैं कि क्या किसान जब सहकारिता में शामिल हो जायेंगे तब वे अपने खेतों के मालिक बने रहेंगे । उन्होंने कहा कि ये यह नहीं कह सकता कि मयुक्त किसान अपने ही खेत का मालिक बना ही रहेगा, इस बदनती हुई दुनिया में स्वामित्व का अर्थ भी बदल रहा है । आचार्य विनोबा भावे कहते हैं कि जमीन का स्वामित्व समाप्त कर देना चाहिए । सहकारी खेती में यह कटना मभव नहीं है कि मयुक्त किसान अपने ही खेत का मालिक बना रहेगा । हाँ, वह सहकारिता में अितने हिस्से का मालिक पहले रहेगा उतने का मालिक बाद में भी बना रहेगा । उनके कहने का अर्थ यह था कि

यदि एक हजार एकड़ की सहकारी खेती में अशुभ किसान को ५ एकड़ भूमि है तो वह ५ एकड़ का हिस्सा बनता रहता है लेकिन जिस ५ एकड़ का वह पहले मालिक था उसी भूमि का मालिक सम्भवतः वह नहीं रह सकता। तीसरी नई बात उन्होंने यह बताई कि सहकारी खेती में शामिल होने वालों को यानी सहकारी खेती को सरकार जितनी अधिक सहायता देगी उतनी सहायता निजी किसान को नहीं दी जाएगी। नरहरी जी ने कहा कि सरकार इस बात में संभाव करेगी। चौथी नई बात उन्होंने यह बताई कि सहकारी खेती में सामान में अच्छा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि उसमें परिस्थितियों के अनुसार हरफर किया जा सके। उदाहरण के लिए गेहूँ वाले क्षेत्रों की स्थिति चावल के क्षेत्रों से भिन्न होती है।

नरहरी जी ने बताया कि गांवों को गरीबी दूर करने के लिये दो मांग हैं एक है सहकारी खेती और दूसरा है कि खेती पर काम करने वाले लोग उद्योग में जायें। यदि आप वर्तमान स्थिति में परिवर्तन करने के लिये काम नहीं उठाते हैं तो गरीबी दूर नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि सहकारी खेती का उद्देश्य गरीबी दूर करना और उद्योग बढ़ाना है। यदि हम कार्य ऐसा कर देंगे तो जिससे सत्रहवां साल में नया धन में जाकर उत्पादन कम होता है तो वह बहुत बढ़ेगा। सहकारी खेती निश्चय ही अच्छा कदम है लेकिन कुछ स्थानों पर इसका पहल परीक्षण किया जाए यह अनिवार्य काम होगा इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। लेकिन कम ही सहकारी खेती प्रारंभ करना व्यवहारिक काम नहीं होगा क्योंकि इसके लिये लोग में वातावरण तैयार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मनुष्य के सभी कार्यों के लिए लाभदायक है। हमें कृषि के क्षेत्र में यह बात लागू नहीं होनी चाहिये। उन्होंने कहा कि वैदिक युग और आज के युग में बहुत फर्क है। आज आबादी अधिक और भूमि कम है।

श्री मन्नारायण ने सहकारी कृषि के साथ बताते हुए कहा कि मेडल काम कर दिया जाना है ५० लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि खेती के लिये उपलब्ध हो जाएगी। इसमें बताया इसमें श्रम और पूँजी का अधिक व्यक्तिगत उपयोग हो सकेगा। उन्होंने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वालों को सहकारी कृषि के ये लाभ किसानों का बताते चाहिए जिससे वे सहकारी कृषि को एक विश्वास के साथ अपनायें इस भावना में नहीं कि उन पर कोई चीज थोपी जा रही है।

नरहरी जी ने कहा कि हम कृषि के क्षेत्र में महान प्रगति करने की आवश्यकता है क्योंकि कृषि विकास के बिना औद्योगिक प्रगति रुक जायेगी। यह ठीक है कि देश की समस्याओं का निराकरण उद्योगीकरण आवश्यक है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बिना नया प्रगति नहीं कर सकता किंतु देश का उद्योगीकरण भी स्थिर कृषि की समस्या पर निर्भर करता है।

प्रधान मन्त्री ने कहा कि भारत में प्रति एकड़ उत्पादन विश्व में सबसे कम है। इस बढ़ाकर दुगुना किया जाना चाहिये। यह तभी संभव है यदि हम कृषि का वृद्धि पद्धति अपनाएँ जैसी कि अन्य विदेशों में अपनाई जाती है। प्रधानमन्त्री ने कहा कि देश में जो विभिन्न भूमि प्रयोग चालू था वह उत्पादन में बाधक था। अतः स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सब प्रथम भूमि व्यवस्था का प्रातिकारी रूप लिया गया। जमींदारों से भूमि कब्जा कर दी गई परन्तु अब भी इस विषय में और कार्य था। उन्नीस के दशक में नागपुर का प्रस्ताव के निराकरण हेतु। महर्षिजी ने कहा कि इस प्रकार की भूमि सुधार प्रयोग देश में भी किया गया है। वे साम्यवादी देशों का बातें नहीं कहना क्योंकि उनका विचार प्रक्रिया के आधार भिन्न है। जापान में जो साम्यवादी देश नहीं है। भूमि सुधार किया गया तथा भूमि को अधिकतम मात्रा निश्चित की गई। अतः यह नहीं सोचना चाहिये कि इन सब बातों का किताब मिडाल्मा में सम्बंध है। यह तो विश्व में सबसे प्रमुख समस्याओं के समाधान का एक उपाय है।

महकारिता का मिडाल्मा आजकल सभी बातों में आवश्यक है। यह दखना होगा कि महकारिता का स्वरूप बड़ा हो या छोटा। नागपुर का प्रस्ताव में महकारी सत्ता जार करने के लिए बल प्रयोग का कहा जा रहा है। महर्षिजी ने नई दिल्ली की नागरिक सभा में बोलते हुए कहा कि यह काम लागू की स्वच्छता होगा। लोगों को महकारी सत्ता के फायदे समझाये जायेंगे और वे समझौते कर हों इस प्रयोग में शामिल होंगे। नागपुर प्रस्ताव में तो यह भी कहना का है कि महकारी समिति में शामिल होंगे जिनके पास किसानों की भूमि का मालिक बने रहेंगे। उन अपने भूमि और काम के हिसाब से जमाने का उपज में हिस्सा मिलेगा।

नागपुर प्रस्ताव में संयुक्त महकारियों कृषि का परिवर्तन एक अंतिम प्रयास के रूप में की गई थी। तब से की अवधि तक हमारे मुख्य कार्य सवा महकारि समितियों का निर्माण होना चाहिये। संयुक्त महकारी कृषि का घनिष्ठ सम्बंध सवा महकारि समितियों के सक्रियता में है जो कि लागू में दहली की जीवन के अनेक क्षणों में महकारि के स्वभाव एक हस्तिकाएँ बना कर दली। तब संयुक्त महकारि कृषि का उत्पादन प्रक्रिया में भी महकारिता के प्रसार के रूप में चालू किया जाएगा।

सर्व सभा ने नागपुर प्रस्ताव का उक्त अंग स्वीकार कर लिया है। उप राजना मन्त्री ने बताया है कि सरकार ने यह तय कर लिया है कि प्रत्येक सवा महकारी संगठन का १ वर्ष तक प्रति वर्ष (६००) दफ्तर संचालन व्यय के लिए दिया जायगा।

## सहकारी खेती कैसे सफल हो ?

आज हमारे ग्रामीण समाज की जो स्थिति है उसमें अभी सहकारिता की भावना बहुत कम है। एक दूसरे के प्रति सहनशीलता नहीं है। आपस में झगड़ बहुत हैं। जो सहकारी समितियाँ अभी गांवों में चली हैं उनका काम भी ठीक नहीं चल रहा है। समितियों के चुनाव में झगड़ होता है। चुनाव हो जाने के बाद भी बराबर पार्टीबाँटियाँ चलती रहती हैं। ऐसी स्थिति में यदि इसका कोई उपाय नहीं किया गया तो सहकारिता के द्वारा खेती जैसा कार्य सफल होना असम्भव है। वही ऐसा न हो कि आपस की पार्टीबाँटों तथा वैमनस्य के कारण सहकारी खेती में उत्पादन और फिर कटौत।

आजकल गांवों की सहकारी समितियाँ में सरकारी अधिकारियों का हस्तक्षेप है और एक तरह से जो छोटे काम चल रहा है वह सरकारी अधिकारियों के बल बूते पर ही चल रहा है। सरकारी हस्तक्षेप में ऐसे ही काम चल सकता है, इसमें अधिक क्षमता उसमें नहीं आ सकती। इसी से आज मांग है कि सरकारी हस्तक्षेप समाप्त होना चाहिए। हमारे प्रधान मंत्री भी यहो चाहते हैं।

हम कोई व्यवस्था ऐसी नहीं चाहते कि जिसमें सहकारी समितियों में पार्टियों की चलत रहने पर भी उनका काम आगे बढ़ता जाए और उसमें रुकावट न हो। एक बार काम जम जाने का जरूरत है फिर तो जब भूमि के उत्पादन में बढ़ाव हो जायेगा तथा सहकारी खेती के साथ ही साथ दूसरे सहायक उद्योग जैसे भी कुछ खड़े हो जायेंगे और इनके द्वारा गांवों के लोगों का राजस्व भी बढ़ जाएगा तब तो ग्रामीणों का स्वयं उसका मीठा फल अनुभव करने लगेगा। उनकी आय बढ़ जाएगी। कम से कम वह काफी स्थायी हो जाएगा। मजदूरी का पैसा उनकी नियम में बराबर उपलब्ध होने लगेगा।

जिस प्रकार व्यावसायिक कंपनियाँ में व्यवस्था का काम कुछ सचालकों (डायरेक्टरों) के हाथ में रहता है उसी में मिलती जुती कोई व्यवस्था सहकारी समितियों में भी नहीं होगी ताकि सभी साझेदारों का व्यवस्था के रोजमर्रा के कामों में हस्तक्षेप न रहे।

**चुने गांवों में प्रचार—**

सहकारी खेती का सफलता के लिए पहला आवश्यक कदम तो यह है कि प्रारम्भ में प्रत्येक क्षेत्र में हम कुछ गांवों का चुन लें। ये गांव ऐसे हों चाहिए कि वहाँ अभी तक सहकारिता तथा पंचायत का काम सबसे अच्छा चल रहा हो तथा पार्टीबाँटों, संपत्ति तथा वैमनस्य सबसे कम हो। इन चुने हुए गांवों में पहला सूत्र अच्छा



तरह से सहकारी खेतों का प्रचार किया जाए ताकि गांवों का प्रत्येक व्यक्ति सहकारी खेती का क्या रूप होगा तथा उसमें उसे क्या लाभ होगा, यह समझ जाए और यह भी वह जान जाए कि उसके पास जो जमीन आज है वह सहकारी खेती होने पर उसी की मितिव्ययत रह्यो। उसे यह समझ देना जरूरी है कि सामेदारों का मतभेद है कि सब जमीनों की बुलाई, बुवाई, नलाई आदि का काम एक व्यवस्था के द्वारा संचालित होने लगे। जिसकी जितनी निजी जमीन होगी अथवा जिसका जितना खेती का सामान हल, बैल आदि होंगे, उन सबका मूल्यांकन एक निश्चित मित्यान्त के आधार पर कर लिया जाएगा और इस प्रकार प्रत्येक के हिस्से की जो धनराशि होगी वह उसकी पूँजी के रूप में सहकारी समिति के हिसाब में अंकित हो जाएगी। इस पूँजी के अनिवार्य जो नकद रुपया वह अपने हिस्से के रूप में देगा वह भी उसके हिसाब में सम्मिलित हो जाएगा। इस प्रकार किसी की जितनी भी पूँजी सहकारी खेती की समिति के हिसाब में निकलेगी वह व्यक्ति का वाकता समिति पर रहेगा। उद्योग धंधों की जहरत—

यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक सामेदार को इस बात का आश्वासन प्राप्त हो कि सहकारी खेती के चालू हो जाने पर सहकारी समिति के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह किसान को उसकी योग्यता के अनुसार काम दे तथा उस काम के हिसाब से उसे मजदूरी का पैसा नियमित रूप में भुगत करे। सम्भव है कि सहकारी खेती की व्यवस्था चालू हो जाने पर सब सामेदारों को खेती में काम न मिल सके। उसके लिए फालतू धनियो को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गांव में बाई और उद्योग धंधा चालू करना पड़ेगा।

दिया चुने हुए गांवों में इन बातों का प्रचार करने पर यदि यह लगे कि वहाँ के अधिकांश व्यक्ति सहकारी खेती की उपादेयता को अनुभव करने लगे हैं और उसमें सम्मिलित होने की तैयार हैं तो उन्ही गांवों में सहकारी खेती पहले चालू की जाए। सब सहकार समितियाँ भी जो योजना अभी पहले चालू की जा रही हैं और जिस पर आगामी तीन वर्षों में पूरा बन दिया जाएगा, उसमें भी पता लग सकेगा कि कौन-कौन से गांवों में सहकारिता की अधिन स अधिक आवश्यकता घर घर गई है। सेवा सहकार समितियों के द्वारा किसानों को खेती के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध की जाएगी। किसानों को इन समस्याओं के द्वारा अच्छा बीज, खाद खेतों के औजार तथा तकली दी जाएगी। इन समितियों में किसान ही सदस्य होंगे और वे स्वयं ही उनका संचालन करेंगे। सहकारिता का मूल मंत्र यही है कि किसान अपनी सहायता के लिए किसी दूसरे के प्रति न ताव, बल्कि वे स्वावलम्बी बनें, मिला-जुलकर अपनी मदद स्वयं करें। अपनी-अपनी पूँजी मिला-जुलाकर उनके द्वारा एक दूसरे को आवश्यक सहायता प्रदान करें। यह सही है कि उनकी अपनी पूँजी मिला-जुलाकर भी अभी उनकी

सहायता के लिए पर्याप्त नहीं होगा। प्रारम्भ में इसके लिए सरकार उनको आवश्यक पूँजी ऋण के रूप में देगी। परन्तु उद्देश्य सन्तुष्ट नहीं रहेगा कि किसान स्वयं अपने परो परो खर्च हो।

दैनिक कार्य—

सहकारी समितियों में कोई ऐसा व्यवस्था हानी चाहिए कि जिससे प्रबंध का दैनिक कार्य कोई एक व्यक्ति बिना दूसरे के किसी हस्तक्षेप के अपनी योग्यता के अनुसार संचालित करता रहे। यह संचालक अवश्य ही सभासदों द्वारा ही चुना जाएगा। परन्तु एक बार चुन जाने पर उस कुछ निर्धारित समय अथवा तीन या चार वर्ष के लिए बिना हस्तक्षेप के कार्य संचालन का अवसर प्राप्त रहना। उसकी सहायता के लिए एक निश्चित व्यक्ति वस्तुभोगी मनजर के रूप में भी रखना आवश्यक होगा। इस मनजर की योग्यता सरकार समय समय पर निर्धारित कर सकती और आवश्यकता हुई तो सरकार ऐसे योग्य व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी और समिति के लिए प्रतिपादित होगा कि वह उसी सूची में से ही नियुक्ति करे। इन मनजरी के वस्तुभोग्यता आदि बातों के लिए उचित नियम होंगे।

सभासदों की समितियाँ गांव गांव में स्थित होनी चाहिए और ठास नींव पर उनका निर्माण हो इसके लिये आवश्यक है कि कुछ योग्य व्यक्ति उन्हें स्थापित करने का भार अपने ऊपर लें। ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है। ऐसी समिति को दृढ़ होने के लिए कम से कम तीन चार वर्ष की अवधि आवश्यक होगी। उस अवधि के अन्तर्गत उसी योग्य व्यक्ति पर इसके संचालन का भार रहना चाहिए कि जिसने उसका संगठन किया है और उस उम्र काय के लिये पर्याप्त वेतन मिलना चाहिये। कानून में उसकी उचित व्यवस्था रहनी चाहिये। कोई योग्य व्यक्ति समिति को स्थापित करे उसका संगठन सुवर्धित कर और फिर प्रचलित शर्पा-द्वय के कारण दूसरे सभासदों पार्टीबन्दी में अपना बहुमत करके उस निकाल बाहर कर इससे संस्था की नाव तथा उसका संगठन दृढ़ नही हो सकता और न आगे उमंग काय संचालन ही सुचारु रूप से हो सकता है। एक निर्धारित अवधि तक उस कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए। इसके दूसरी ओर यह भी आवश्यक है कि यदि कार्य संचालन स्थायी वैधमान अयोग्य तथा अनुपयुक्त सिद्ध हो तो उसे हटाए जाने की भी कानून में व्यवस्था हानी चाहिए। ऐसा न होने में वह अपने स्वयं माधन में ही खत रहता और समिति वर्धित हो जायगी। इसके लिये उस अपना सफाई दन का पूरा अवसर उपलब्ध रहना चाहिए। ऐसी व्यवस्था हानी चाहिये कि उसका साथ परा काय हो तथा न्याय की वह निर्णायक न, बल्कि, एक, सत्य, सत्य, के लिये सत्य, कानून के अन्तर्गत नियम समर्थ जयग।

सहकारी कृषि के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति—

२८ मार्च सन् १९५६ को लोक सभा ने एक गैर-मरकरारी प्रस्ताव स्वीकार किया, जिसके अनुसार सेवा-सहकारिताओं का संगठन किया जायगा, जो कि देश में सहकारी कृषि के प्रवर्तन के लिये उपयुक्त वातावरण निर्माण करेंगी। भारत सरकार ने जून ११ को एक समिति का गठन किया है जो कि उन लोगों को, जो देश में स्वेच्छा से समुक्त कृषि समितियों स्थापित करने का निश्चय करते हैं, वित्तीय, टेक्नीकल एवं अन्य सुविधायें प्रदान करने के हेतु एक कार्यक्रम तैयार करने में सहायता देगी। इस समिति की रिपोर्ट १५ फरवरी सन् १९६० को प्रकाशित हुई थी। रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि प्रत्येक जिले के लिये एक सप्रगामी योजना (pilot project) के हिमाच ने ३२० योजनाएँ चुने लिये जाएँ जिनमें से चार वर्षों के अन्दर चलाई जायें। उसकी सम्मति में अल्पमत कृषकों को किसी सहकारी समिति में सम्मिलित होने पर विवश करना ऐच्छिकता के आधारभूत मिद्धान्त के विरुद्ध है तथा व्यावहारिक दृष्टि से भी यह वाञ्छनीय नहीं है। निम्न तालिका में विभिन्न राज्यों में सहकारी समितियों का वितरण दिखाया गया है—

सहकारी कृषि समितियों (३० जून १९५८)

राज्य	समाप्तियों का संख्या	बाधणीय वस्तुओं की संख्या	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ों में)
आंध्र प्रदेश	८	४११	७१८
आसाम	१८४	४,६७७	१३,४४४
बिहार	२६	२५२	३,९१६
बम्बई	५१०	१४,६६६	४६,५३५
जम्मू व काश्मीर	५	५८२	१,०७६
केरल	६	१,७१४	४,०५१-६६
मध्य प्रदेश	२०१	२,८३०	३६,१८२
मद्रास	४४	२,७१७	६,२६६-३६
मैसूर	१२८	३,४०६	१७,५८०
उड़ीसा	३८	१३८	२,५३३
पंजाब	६७८	६,२५३	१,२७,५८७
राजस्थान	१०३	६२७	७,६१०
उत्तर प्रदेश	२६२	२,६८०	३७,७१७
पश्चिमी बंगाल	१६१	२,५००	११,७७०
मडमन एवं निकोबार द्वीप	३१	८००	—
दिल्ली	७१	१,७४७	५,९६०
हिमाचल प्रदेश	८	—	—
मनीपुर	१५	४८५	५६६
त्रिपुरा	२०	१,१८०	४,८६५

### STANDARD QUESTIONS

- 1    Mention the various forms of large scale farming and state which of them is the most suitable in Indian conditions
- 2    Distinguish between co-operative farming and collective farming What are the obstacles to co operative farming in India ?
- 3    What are the different forms of co-operative farming societies ? State the practicability of organising such societies in Indian Agriculture
- 4    Mention the various forms of co operative farming recommended for adoption in India Which of them do you prefer and why ?
- 5    Describe a co operative farming society What are its different forms ? Make out a case for the wide establishment of such societies in India
- 6    Write a critical essay on co operative farming in India ?”

# भूमिरहित कृषकों की समस्याएँ व भूदान आन्दोलन

(Problem of landless Labourers and Bhoodan movement)

**भूमिरहित कृषकों की समस्या का महत्व—**

भूमिरहित कृषक (Landless Labourer) से हमारा आशय गाँव में काम करने वाले उन व्यक्तियों से है, जोकि कृषि के धंधे में मजदूरी पर काम करते हैं और जिनके पास अपनी कोई भूमि नहीं होती और यदि होती भी है तो इतनी कम कि उससे उमका तथा उसके परिवार के सदस्यों का पालन-पोषण नहीं हो सकता। हमारी ग्राम्य जनता का एक बहुत बड़ा भाग ऐसे कृषि श्रमिकों का ही है, जैसा कि क्वेसने महोदय (Quesnay) ने एक बार कहा था—‘गरीब किसान, गरीब राजा, गरीब देश’—यह कथन ग्राम्य देशों के सम्बन्ध में भले ही सत्य न हो, किन्तु जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है, यह कथन- सत्य प्रतीत होता है। जिस देश के कृषक स्वयं ही गरीब हों, वहाँ हमरो के खेतों पर काम करके अपनी जीविका चलाने वाले कृषकों को क्या स्थिति हो सकती है इसका अनुमान लगाना सरल काम नहीं है। इन भूमिरहित कृषि श्रमिकों को दिन में दो बार भर पेट भोजन नहीं मिल पाता और न पहनने के लिए पर्याप्त वस्त्र ही मिलने हैं। सामाजिक सुविधायें क्या होती हैं, इनका उन्हें ज्ञान तक नहीं है। समाजवादी धर्म-व्यवस्था (Socialistic Pattern) के इस युग में इन श्रमिकों के रहने के लिए घर, दवाइयों की सुगम महायता, न्यूनतम मजदूरी इत्यादि का महत्व औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों में किसी प्रकार भी कम नहीं होता चाहिए किन्तु बड़े दुःख की बात है कि हमारे देश के स्वतन्त्र होने तक इनकी दशा को सुधारने का प्रयत्न न तो ब्रिटिश सरकार ने ही किया और न ग्राम्य समाज सुधारकों, राजनैतिक कार्यकर्ताओं तथा खोज करने वाले व्यक्तियों ने ही इस ओर ध्यान दिया।

प्रायः कुछ वर्ष पूर्व तक भारत की ग्राम्य व्यवस्था में ‘मजदूर’ शब्द का अर्थ मर्दव मण्डल उद्योगों में काम करने वाले श्रम-जीवियों से ही समझा जाता था।

भारत सरकार भा ओलोगिक श्रमिका की समस्याओं पर विचार ध्यान देती थी तथा कृषि श्रमिका की समस्याओं की उपस्था की जाती थी। परिणामतः दश म कृषि श्रमिका की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। कृषि मन्त्रालय समिति (Agrarian Reforms Committee) के अनुसार, 'कृषि विभाग की किसानों की योजना में भूमि रहित कृषकों की समस्या पर समुचित ध्यान न देना, देश की कृषि व्यवस्था की एक दृढ़ता की समस्या की उपस्था करना होगा। आज जबकि देश में अन्न संकट है, देश का विभाजन हो जाना के कारण लाखों किसानों की दृष्टि से भारत की स्थिति और भी खराब हो गई है तथा एक्सचेंज एंड कपास जैसे आवश्यक औद्योगिक कच्चे माल का भी देश में टाटा है, सब हमें अपनी कृषि एवं कृषि श्रमिकों की दशा में घामूल परिवर्तन करने हान। यदि हमने अपने कृषि व्यवसाय में क्रांतिकारी परिवर्तन किए और अपने भारतीय कृषकों को पुराने देश में अर्थज्ञानिक लेनी करने दी, तो न हम अपना बदनाम हुई जन समस्या का जीवन निर्वाह कर सकेंगे और न अपने धन्य की उपलब्धि कर सकेंगे। आज जिस अवस्था में हमारा कृषि श्रमिक रहा है, उस अवस्था में रहकर वह कभी भी वैज्ञानिक कृषि के लिए उपयोगी मित्र नहीं हो सकता। मानवीय नीति और आर्थिक हित दोनों ही दृष्टिकोणों में हमारे कृषि श्रमिकों की समस्या बहुत महत्वपूर्ण है।

### कृषि श्रमिकों की समस्या—

भारत में कृषि श्रमिकों की समस्या का अनुमान समय समय पर लगाया गया है। राष्ट्रीय योजना समिति (N. P. C.) के विवरण में प्राक्केतव्य देश में भारत में कृषि श्रमिकों की संख्या १० करोड़ बताई थी। यह तत्कालीन जन-संख्या के आधार पर देश की कुल जन संख्या का २५% भाग थी। सन् १९५१ की जन गणना के अनुसार गाँव में रहने वाली २६ करोड़ ५० लाख जनता में से २४ करोड़ ६० लाख व्यक्ति केवल कृषि में लगे हुए थे। कृषि में लगे हुए इन व्यक्तियों का १८% भाग मजदूर बनने वाले मजदूर एवं उन पर आश्रित व्यक्तियों का था।

कृषि श्रमिकों के सम्बन्ध में कृषि श्रम जाँच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कुछ विश्वसनीय आंकड़े प्रकाशित किए हैं। कन्द्रीय श्रम सचिवालय द्वारा कृषि श्रमिकों के सम्बन्ध में की गई जाँच तीन भागों में प्रकाशित की गई है। उनकी कुटुम्ब सम्बन्धी आर्थिक स्थिति तथा रोजगार आदि के विषय में जा जांच की गई है, वह नमूने के आधार पर ही की गई है क्योंकि समस्त देश के कृषि श्रमिकों की पूरा पूरी जांच करना अत्यन्त कठिन है। नमूने की जाँच ८१२ गाँवों में रहने वाले केवल १,०३,५४८ परिवारों की है। इन गाँवों में ७६ ०८% परिवार कृषि पर निर्भर हैं और ३०.४%

कृषि श्रमिकों के परिवार है। कृषि श्रमिकों के परिवारों का आधा भाग, अर्थात् १५.२% ऐसा है, जिनके पास स्वयं की कुछ कृषि योग्य भूमि है और दोष १५.२% परिवार भूमि रहित कृषि श्रमिक है। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि हमारे देश के गाँवों में रहने वाले परिवारों की संख्या लगभग ५८० लाख है, जिनमें से १७६ लाख परिवार कृषि श्रमिकों के हैं। देश में पाये जाने वाले कृषि श्रमिकों का देश की कृषक जनता से अनुपात भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एकसा नहीं है। निम्नलिखित शीकड़ी में यह भन्नी प्रकार स्पष्ट हो जाता है :—

**ग्रामीण जन-संख्या में कृषि श्रमिकों का स्थान**

राज्य	समस्त प्रतिशत	भूमि मुक्त मजदूरों का प्रतिशत	भूमिहीन मजदूरों का प्रतिशत
उत्तर प्रदेश	१४.३	५.७	८.६
आन्ध्रप्रदेश	१०.७	६.७	४.०
बिहार	३६.६	७५.६	१४.३
उड़ीसा	४३.०	२३.८	१६.२
पश्चिमी बंगाल	२३.८	१०.५	१३.३
मद्रास	५३.०	२८.३	२४.७
केरल	३६.५	२०.८	१८.७
बम्बई	२०.४	६.६	१०.८
मध्य प्रदेश	४०.१	१४.६	२५.२
पंजाब	१०.१	१.६	८.५
सम्पूर्ण भारत	३०.४	१५.२	१५.२

कृषि श्रमिकों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। सर्व श्री वाडिया व मर्चेंट के अनुसार देश में भूमिहीन श्रमिकों की संख्या सन् १८८१ में केवल ७५ लाख थी। यही संख्या बढ़कर सन् १९२१ में २१५ लाख और सन् १९३१ में ३३० लाख हो गई।\* सन् १९५१ की जन गणना के अनुसार कृषि श्रमिकों की संख्या ४६० लाख थी। कृषि श्रम जाँच समिति के अनुसार देश की सम्पूर्ण ग्रामीण जन-संख्या का ३०.४% भाग कृषि श्रमिकों का है। कृषि श्रमिकों की संख्या में इस निरन्तर वृद्धि के अनेक कारण हैं, जैसे कृषि पर जन संख्या का अत्यधिक बोझ, औद्योगिक विकास की धीमी गति, कृषि-उद्योगों की अवनति, ग्रामीण ऋण प्रवृत्ति, कृषि श्रमिकों में गतिशीलता का अभाव, इत्यादि।

\* देखिये Our Economic Problems by Wadia and Merchant, Page 365.

कृषि श्रमिकों के भद—

कृषि मजदूरों का निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—(१) खेतों पर काम करने वाले जैसे—हल चलाने वाले, सिंचाई करने वाले, निराद एवं खेत खोदने वाले, फसल काटने वाले इत्यादि। (२) साधारण मजदूर, जैसे—कुँआ खोदने वाले खेत के आस पास पत्थर या मिट्टा की बाढ़ लगाने वाले पत्थर खोदने एवं ढाने वाले इत्यादि। (३) निपुण मजदूर जैसे—मुनार राज लुहार, इत्यादि। इनके प्रतिरिक्त कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके पास अपनी स्वयं की भूमि कम होता है और वे उस भूमि पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रह सकते अतः अपना जीवन निर्वाह के लिए दूसरे किसानों के खेतों पर कभी-कभी मिलने वाले छोटे-माल काम करने के लिये जाना पड़ता है। पिछले वर्षों में यह दत्ता गया है कि कृषि श्रमिकों की संख्या में प्रति वर्ष बड़ी तेजी से वृद्धि होती जा रही है जो हमारे देश की एक महान् बेकारी की समस्या को और भी जटिल बनाने में सहायक हो रही है।

कृषि श्रमिक जांच समिति के अनुसार देश के कुल कृषि श्रमिकों में ८१% आकस्मिक तथा १९% आसजित श्रमिक (Attached labourers) हैं। कृषि श्रमिकों में से कुछ के पास छोटी भूमि होती है तथा कुछ के पास बिल्कुल भूमि नहीं होती। जिनके पास बिल्कुल भूमि नहीं होती उन्हें भूमिरहित श्रमिक (Landless Labourer) कहते हैं। कृषि श्रम जांच समिति की खोज के अनुसार भारत के कुल ग्रामीण परिवार का ३०.४% भाग कृषि श्रमिकों का था जिनमें १५.२% के पास कुछ भूमि थी तथा १५.२% भूमिहीन श्रमिक थे।

## भारतीय कृषि-श्रमिकों की समस्याएँ

भारतीय कृषि श्रमिकों की अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं —

(१) मजदूरों की दरें एवं उसे चुकाने की विधि—हमारे कृषि श्रमिकों की इतनी कम मजदूरी मिलती है कि वे न तो भरपूर भोजन ही कर पाते हैं और न पर्याप्त कपड़ा ही धारण कर सकते हैं। कृषि श्रमिकों का मजदूरों केवल नकद दरम अनाज कपड़ा तथा अन्य सुविधाओं के रूप में भी चुकाने की प्रथा हमारे देश में प्रचलित है। विभिन्न स्थानों में इन प्रथाओं की विभिन्नता के कारण मजदूरों को नकद रूप में आकर्षक अत्यंत बठिन है। कृषि श्रमिक जांच समिति के अनुसार सन् १९५०-५१ में प्रति कृषि श्रमिक परिवार की औसत वार्षिक आय ४८७.६० तथा औसत प्रति-श्रमिक वार्षिक आय केवल १०४ रुपये थी, जबकि उसी वर्ष एक औसत भारतीय की वार्षिक आय २६३.६० थी। इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि हमारे देश के



कृषि-श्रमिकों की मजदूरी कितनी कम है। नोचें दो हुई तातिका में कृषि तथा औद्योगिक श्रमिकों की प्रति व्यक्ति औसत आय का तुलनात्मक ढंग से अनुमान लगाया जा सकता है—

### प्रति-व्यक्ति वार्षिक आय

( रुपये में )

राज्य	कृषि-श्रमिक	औद्योगिक श्रमिक	कृषि श्रमिक की आय औद्योगिक श्रमिकों के प्रतिशत में
पश्चिमी बंगाल	१६०	२६८	५६
बिहार	११६	३३२	३६
मध्यप्रदेश	८७	२६२	३३
उड़ीसा	७६	१४५	५४
पंजाब	१२१	२१६	५६
बम्बई	८८	३६८	२४

(२) काम के घटे—काम के घटे भिन्न भिन्न स्थान, ऋतु तथा फसलों के लिये एक से नहीं हैं। इन कारणों के काम के घटे औद्योगिक श्रमिकों की भांति निश्चित नहीं। साधारणतः मजदूर मृगं उगने पर खेतों पर जाते हैं और केवल दापहर के समय रोटी खाने और थोड़ा माराम करने के एक दो घण्टे को छोड़कर सध्या हाते तक काम करते रहते हैं। कृषि श्रमिकों के सम्बन्ध में एक विशेष बात यह है कि जिन खेतों में अधिक काम रहता है उन दिनों काम के घटे और भी अधिक बढ़ जाते हैं।

(३) कृषि श्रमिकों की मौसमी बेकारी—कृषि श्रमिकों की मासिक स्थिति कमजोर बनाने में उनका वर्ष भर लगातार काम न मिलना भी एक कारण है। केवल खेती के दिनों में, जब मजदूरी की मांग अधिक रहती है, अधिक लोगों को मजदूरी मिल जाती है, किन्तु वह भी लगातार नहीं, बीच बीच में छोड़कर। यदि वर्ष भर के बेकारी के दिनों को जोड़ा जाय, तो कदाचित् ६० से १८० दिन हा सकते हैं। इन दिनों ये लोग या तो फालतू बैठे रहने हैं अथवा काम की तलाश में दर दर ठोकरें खाते हैं।

(४) कृषि श्रमिकों के मकान की दशा—नयाकि कृषि मजदूरों की स्वयं भूमि नहीं होती, अतः बितले ही ऐसे हैं, जिनके पास कुछ भूमि का टुकड़ा हो जिस पर वे अपना मकान बना सकें, अतः उन्हें या तो भूमिपतिथों की या गाँव की मध्याह्न के स्वामित्व की भूमि पर उनकी स्वीकृति लेकर मकान या आपडियाँ बना कर रहना

पड़ता है। व रहन की भोपड़िया बहुत ही छोटी होती है। १० आर० के० मुकर्जी न भी इनके रहन के स्थानों के सम्बन्ध में लिखा है कि ये भोपड़ियाँ केवल ऐसे स्थान में हैं जहाँ कि मजदूर केवल अपनी टांगें लम्बी करके रात को सो सकता है और प्रत्येक उदाहरण ऐसे है जहाँ एक ही भोपड़ी में अनेक व्यक्तियों के सोने में घास में पर्दा न होना के कारण मर्यादा भी समाप्त हो जाती है। ठण्ड के मौसम में एक ही कमरे में स्त्री और पुरुष युवक एवं वृद्ध और कभी-कभी जानवर तथा बकरे साथ साथ ठुमे रहते हैं। इन मकानों में गुद हवा तथा प्रकाश आने के लिये खिड़कियों का पता नहीं दीवान तथा घागन गीत के कारण गीने अर्थात् दुस्वार में पोंडित और बच्चों की तानुहन्ती इतनी खराब रहती है कि मृत्यु का डर बना ही रहता है। घर के आस पास गंदगी के कारण मच्छरों इत्यादि का जार भी कम नहीं रहता।

(५) कृषि श्रमिकों की दासता—हमारे देश के कुछ भागों में कृषि श्रमिकों की स्थिति उनकी अधिभूत गराबों के कारण दासों जसी ही गई है। दास व प्रथा उन स्थानों में अधिभूत पाई जाती है जहाँ निम्न एवं अल्प वय के लोगों की अधिभूतता हो। बम्बई राज्य में दुबला तथा कुला कहलान वाला ऐसे लोग हैं जिनमें से अनेक परिवार कई पीढ़ियों में अपना स्वामी के यहाँ दासों की तरह नीरस जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनको खान के लिए भोजन व पहिनाके के लिए बल्ल मालिकों की ओर से मिलता है। मद्रास राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भाग के इन्डियावात विरमम पलेया तथा होलिया इत्यादि का स्थिति भी दासों के समान है।

(६) कृषि श्रमिकों की श्रम प्रवृत्ति—श्रमिकों का पर्याप्त मजदूरी तथा लगातार काम न मिलने के कारण इन्हें अपनी मुनतम आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिए श्रम लेना पड़ता है जिसमें वे सदैव के लिए महाजन के बशुल में फँस जाते हैं। कृषि-श्रमिक अधिकांशतः अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गिरवी रखकर ही श्रम प्राप्त करते हैं। कृषि श्रम जाच समिति की खोज के अनुसार कुल १७६ लाख कृषि-श्रमिक परिवारों में से ७८ लाख परिवार श्रम के बोझ में प्रसिद्ध हैं। औसत श्रम की मात्रा प्रति परिवार १०५ रु० थी। अतः यह कहा जा सकता है कि सन् १९५०-५१ में कृषि श्रमिकों पर ८० करोड़ रुपये के लगभग श्रम था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कृषि जाच समिति का इस अनुमान में हमारे कृषि श्रमिकों का वास्तविक स्थिति का पता नहीं लग सकता क्योंकि वास्तविकता तो यह है कि 'गायन न को' एसा कृषि श्रमिक परिवार होगा जो श्रम के बोझ में मुक्त हो।

बढ़ते हुए भू-मूल्यों की समस्या—

भूमि की वर्तमान वृद्धि का भी हमारे कृषि श्रमिकों की दशा पर बहुत बरा प्रभाव पड़ा है। भू-मूल्यों के अनुपात में मजदूरी में वृद्धि के कारण इनकी आर्थिक

कठिनाई और भी भयंकर हो गई है। इनमें सगठन का भी बड़ा अभाव है, अतः किसी प्रकार की मुविधा प्राप्त करने में भी इनको बड़ी कठिनाई होती है। बीमारी, बुढ़ापे तथा अन्य परिस्थितियों ने इन्हें बचाने के लिए सामाजिक सुरक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इस वर्ग की समस्या को मुलभाये बिना भारत की आभीण व्यवस्था की नींव मुट्ठ नहीं हो सकती।

### कृषि-श्रमिकों की होनावस्था के कारण

भारतीय कृषि श्रमिकों की होन दशा क प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं —

(१) जन संख्या की वृद्धि एवं भूमि का उप विभाजन—हमारे देश में जन-संख्या बड़ी तीव्रगति में बढ़ रहा है और इससे परिणामस्वरूप कृषकों की भू सम्पत्ति का उप विभाजन भी बढ़ता जा रहा है। जितना छान्नी छान्नी हान के कारण अनाधिक हाती जा रही है। छोटे आकार के खेतों में कृषि कार्य में अनाधिक हो जाता है। फलतः कृषक, का निर्वाह बचल अपना भूमि नहीं हो पाता और उन्हें विविध होकर कम मजदूरी पर काम करना पड़ता है।

(२) कुटीर उद्योगों की अवनति—भारत में अग्रणी राज्य का प्रारम्भ ॥ हमारे कुटीर उद्योगों का विनाश होन लगा। कुटीर तथा कृषि के ॥ यह सहायक उद्योग-धंधों के पतन के कारण अनेक कारीगर बेकार हो गये तथा उन्हें विविध होकर केवल कृषि कार्य करना पड़ा। अतः कृषि श्रमिकों की समस्या में वृद्धि हो गई, जिसमें इन्हें कम मजदूरी पर काम करने के लिए विविध होना पड़ा।

(३) ऋण का भार—जैसा कि हम पीछे सक्त कर चुके हैं, हमारे देश में कृषि श्रमिकों की आमदनी इनकी कम है कि उन्हें अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की अनुपेक्षा के लिए ऋण लेना पड़ता है। वे ऋण में अग्रते, ऋण में पसते एवं ऋणग्रस्त हो मर जाते हैं। कम मजदूरी के कारण वे समय पर अपनी ऋणों का नहीं चुका पाते एवं विविध होकर अग्रत में उन्हें अपनी सम्पत्ति बेचनी पड़ती है। कभी कभी तो ऋण लेन के लिए इन्हें अपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को भी गिरवी रखना पड़ता है जिसमें वे महाजनों के दास की तरह हो जाते हैं। इस प्रकार बज्र व बोझ से भी ऋणग्रस्त मजदूरों की आर्थिक बेकारी बढ़ती जा रही है।

(४) साल भर काम का न मिलना—हमारे देश में कृषि श्रमिकों को कम मजदूरी पर भी साल भर काम नहीं मिल पाता। वे वर्ष के अधिकांश भाग में बेकार हो रहते हैं। कृषि श्रम जीवन समिति की खोज के अनुसार कृषि-श्रमिकों को वर्ष में औसत १८६ दिन कृषि कार्य में तथा २६ दिन और कृषि कार्य में काम मिलता है। देश के कुछ भागों में तो हमारे सेतिहर मजदूर ६-७ महीने तक बेकार हो रहते हैं। कृषि श्रमिकों का बेकारी का यह समय अत्यन्त दुःखदायी होता है। इस अवधि में उन्हें पान, पेय पालन वगैरह कोई आश्रय प्राप्त हो नहीं, अन्न, भोजन, वस्त्र, आदि के लिये उन्हें ऋण लेना पड़ता है। अतएव निरन्तर काम न मिलने के कारण भी भारतीय कृषि श्रमिकों की आर्थिक दशा बड़ी हीन होन जा रही है।

(५) मजदूरी चुकाने की दोषपूर्ण पद्धति—कृषि श्रमिकों का दा जान वाली मजदूरी की प्रणाली भा अ यत्त दूषित है। दश के कुछ भागा त त उ ह मरुद रूपो म मजदूरी दी जाती है कुछ भागा म मरुद बल्ल प्राप्ति क रूप म और वही कही दोनो क रूप म। आजकल मजदूरी अधिकांश नगद रूपया के रूप में ही दी जाता है। इससे श्रमिकों को सचमुच घाटा ही हाता है क्योंकि विभिन्न वस्तुओं के मू य म वृद्धि जान के कारण मजदूरी म उस अनुपात म वृद्धि नहीं हुई है। अत उनकी वास्तविक मजदूरी बहुत कम है। कम मजदूरी भी उनकी हीन दशा का एक मह वपूर्ण कारण है।

(६) दोषपूर्ण रयती कानून तथा जमींदारी प्रथा—हमारा वर्तमान रयती कानून (Tenancy Legislation) भी कृषि श्रमिकों की सहाय म वृद्धि के लिय उत्तरदायी है। यह श्रमिक अथ सागो की भूमि पर काय करते हैं और स्वयं केवल अपनी मजदूरी पान के लिये ही अधिकारी होते हैं। भूमि का स्वामी बहुधा कृषि काय म बहुत दूर रहता है किंतु फिर भी वह सम्पूर्ण उपज का अधिकारी होता है। इसी प्रकार जमींदारी प्रथा भी कृषि श्रमिकों की दयनीय स्थिति के लिये काफी सीमा तक उत्तरदायी है। अनेक जमादार गावा म न रहकर नगरा म रहन ॥ और उनकी अनुपस्थिति म जमींदारी की व्यवस्था उनके कारिंदों द्वारा की जाती है। ये लोग कृषका का तरह तरह से शोषण करते हैं। जमींदारी प्रथा क अ तगत अनेक कृषक भूमि म बेचबल कर लिय गय और उ ह बाध्य होकर कृषि श्रमिका की श्रेणी म आना पडा।

(७) कृषि श्रमिकों से सगठन का अभाव—भारताय कृषि श्रमिकों म सगठन की भा बहुत बड़ी कमी है। विभिन्न राजनतिक दला क प्रयाम के कलस्वरूप देश के औद्योगिक श्रमिक तिन प्रतिदिन सगठित होन जा रह ह और शक्तिमान। सगठन के परिणामस्वरूप उनकी आर्थिक एव सामाजिक स्थिति म भी सतोषजनक सुधार हुआ है। परंतु कृषि श्रमिका म अभी तक सगठन का बहुत अभाव है। यहा कारण है कि स्वतंत्र राष्ट्र होन हुए भी इनकी दशा अधिक उन्नत नहीं हो सकी है।

(८) सरकार व समाज की उदासीनता—कृषि श्रमिका के प्रति भारत सरकार एवं जन समाज भी प्रारम्भ स ही उदासीन रह है। ब्रिटिश शासन काल म इनकी दशा को सुधारन क लिय कभी भी सक्रिय कर्म नहीं उठाया गया। हाँ जबस हम स्वतंत्रता मिली है तब से कृषि श्रमिका का समस्या का हल करन क लिये प्रयान किय जा रह है परंतु फिर भी इस लिंगा ॥ अभी कोई मह वपूर्ण सुधार नहा हो सका है।

मौल म हम यह कह सकते हैं कि जन सहाय का वृद्धि कुटीर उद्योगो का हानि शायीण कला अन्नता निरंतर काम न मिलना सगठन का अभाव एवं जनता

व सरकार की उदामानता के कारण भारतीय कृषि श्रमिकों की दशा बड़ी दयनीय है। इनका जीवन बड़ी निराशा में बीतता है। भूख नंगे पैदा होकर, भूख नंगे तथा आश्रयहीन मर जान तक हा उनके जीवन का सारा इतिहास सीमित है। अतः आज देश की सबसे बड़ी मांग है कृषि श्रमिका की दशा को उत्तरी करना।

## कृषि-श्रमिकों की दशा को सुधारने के उपाय

कृषि श्रमिका की समस्या का वास्तविक समाधान उस समय संभव होगा जबकि हमारी कृषि का नए सिरे से पुनरुत्थान हो और भूमि पर से जन सख्या का भार कम करके अग्र्य सहायक व्यवसायों का विकास हो। भारत सरकार इस समस्या को मुलभान के लिए निम्न प्रयत्न कर रही है—

(१) जमींदारी उन्मूलन तथा शोषण का अन्त—स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद हमारी राष्ट्रीय सरकार का ध्यान भूमि व्यवस्था की ओर गया और विभिन्न राज्यों में जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार कानून पास किये गए जिनका मुख्य उद्देश्य शोषण को समाप्त करके किसानों की आर्थिक दशा में सुधार करना था।

(२) यूनितम मजदूरी का निर्धारण—सन् १९४८ में यूनितम मजदूरी अधिनियम पास किया गया और राज्य सरकारों को यह भार सौंपा गया कि कृषि श्रमिका के लिये यूनितम मजदूरी की दर निश्चित करे। इस उद्देश्य को पूर्ण के हेतु सन् १९४९ में एक अखिल भारतीय जाच समिति स्थापित की गई जिसमें सम्बन्धित देश के ८१३ गांवों में आकड़ प्राप्त किए गए। इस जाच के फलस्वरूप प्रथम पंच वर्षीय योजना के काल में पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा अन्य राज्यों में यूनितम मजदूरी की दर निश्चित कर दी गई है और गेय राज्य इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने जा रहे हैं।

(३) कृषि योग्य बजर भूमि का सुधार—केन्द्रीय टैंक्टर सस्था द्वारा कृषि योग्य बजर भूमि का सुधार किया जा रहा है और यह भूमिहीन कृषिकों को सहकारिता के आधार पर दी जा रही है। पंच वर्षीय योजना में १५ लाख एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने तथा २० लाख एकड़ भूमि को सुधारने का अनुमान है। इससे भूमिहीन कृषिकों की समस्या बहुत कुछ हल हो जायेगी।

(४) व्यक्तिगत जोत की उच्चतम सीमा निर्धारित करना—सरकार एक उच्चतम सीमा निर्धारित करने जा रही है जिससे अधिक भूमि किसी व्यक्ति के पास नहीं रह सकेगी। जिन लोगों के पास अधिक भूमि है वह उनसे प्राप्त करके भूमिहीन किसानों में बांट दी जायेगी।

(५) भूदान यज्ञ—आचार्य विनायक भावे द्वारा प्रतिपादित भूदान यज्ञ में भूमि

दान के रूप में प्राप्त की जाती है और उसे भूमिहीन कृषकों के रूप में सहकारिता के आधार पर वितरित किया जाता है ।

(६) सहकारी ग्राम प्रबन्ध—योजना आयोग का मत है कि गाँव की समस्त भूमि को एक साथ एकाग्र करके सहकारिता के आधार पर खेती कराई जाय और इसका प्रबन्ध ग्रामवासियों की एक समिति द्वारा हो । ऐसा हो जाने से भूमिहीन कृषकों की समस्या स्वयं हल हो जायेगी और समस्त ग्रामवासियों के सामूहिक परिश्रम के फल में ये लोग भी भागीदार बन जायेंगे । इस प्रकार उत्पादन में वृद्धि होगी और किसी न किसी रूप में सबको रोजगार मिल सकेगा ।

(७) राजकीय बोर्डों की स्थापना—योजना कमिशन ने इस बात की सिफारिश की है कि राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर सरकारी व्यक्तियों के बोर्डों की स्थापना की जाय, जिनका उद्देश्य भूमिहीन किसानों को धमने के सम्बन्ध में परामर्श देना तथा समय समय पर कार्य की प्रगति को देख रेख करना भी हो ।

(८) कृषि-श्रमिकों का संगठन—जिस प्रकार उद्योगों में काम करने वाले श्रमजीवियों के श्रम सघ स्थापित हो गये हैं, उसी प्रकार कृषि श्रमिकों के भी संगठन स्थापित होने चाहिये । प्रत्येक गाँव में एक कृषि श्रम सघ की स्थापना हो और एक कन्द्रीय सरदा बनाई जाय जो इन श्रम सघों के कार्य का संचालन करे । इस योजना से कृषि श्रमिकों की अज्ञानता दूर होगी और उनमें श्रुति तथा जागृति पैदा होगी । योजना आयोग ने सुझाव दिया है कि सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत प्रत्येक गाँव में श्रमसहकारी समितियों की स्थापना होनी चाहिये, और प्रत्येक विकास खण्ड में सहकारी यूनियन होनी चाहिये, जो प्रत्येक गाँव की श्रम समितियों की देखभाल कर सके ।

(९) ग्रामीण-उद्योगों का विकास—ग्रामीण उद्योगों के विकास से जन समस्या का भूमि पर अत्यधिक भार बहुत कुछ कम हो जायगा । किसानों की रोजगार मिलेगा और कृषि की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी । सावजनिक विकास कार्यों में इन लोगों की रोजगार देने का प्रयत्न किया जाता है जैसे—कुँये खोदना, सड़कें बनाना, तहरें बनाना आदि । उत्तरप्रदेश की ग्राम्य औद्योगीकरण योजना के अन्तर्गत सन् १९५८ के मध्य तक राज्य की लगभग १६% जनसंख्या शामिल हो गई है । इस योजना में प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र स्थापित किये गये हैं । यह योजना अब १३,८८४ गाँवों में चल रही है, जिनकी जनसंख्या ५९,८५ ००० है ।

**उपसंहार—**

भूमिहीन कृषकों की दशा का सुधारने के लिये तथा उनके पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करने के लिये उपरोक्त उपायों व अलावा कुछ अन्य सुझाव भी दिये जा सकते

है। सिधार्ई का सुविधाया तथा कृषि कला म सुधार किया जाय जिसस कृषि-श्राय म वृद्धि हो। दूसर भाव में रोजगार के दफ्तरो की स्थापना की जाय। इसका तापय यह है कि जिस प्रकार रोजगार के दफ्तर बेकार लोगो को काम दिलान का काम करते हे उसी प्रकार ग्रामीण श्रम एक्सचेंज भूमिहीन कृषको की सहायता कर सकते हे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यातायात के सस्ते साधनो का विकास होना भी जरूरी है।

## भूदान आन्दोलन (Bhoodan Movement)

**भूदान आन्दोलन से आशय—**

गत कुछ वर्षों से भारतीय कृषि के इतिहास म हम जिस नई घटना को देख रहे हे वह है भूदान आन्दोलन जिसके प्रणेता हे सत विनोबाभावे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब हैदराबाद क तेलगाना क्षेत्र म अशधिक विषमता का दूर करन के लिए कुछ साम्यवादिया न हिंसा की गरण नी ता उस खूनी क्रांति को अहिंसात्मक ढंग से परिवर्तित करन क उद्देश्य से सत विनाबा न अपनी पदल यात्रा प्रारम्भ कर दी। तेलगाना के नालबुण्डा क पोचमपल्ली गाव म प्राथना के समय विनोबाजी न भूमि हान हरिजना के लिए ५० एकर भूमि को माग की थी। एक उदार हृदय जमींदार न उसी समय १०० एकड़ भूमि अपनी इच्छा से हरिजना को दे दी। तभी से सत विनाबा न यह नियुक्त किया कि वे पदल घूम घूम कर जमींदारो स स्वेच्छापूर्वक भूमि का कुछ भाग नकर भूमि हीन कृषका म वितरित करेंगे। भूदान यज्ञ के द्वारा सत विनोबा भावे यह प्रयत्न कर रहे हे कि गावा म मनोवैज्ञानिक जागरण हो प्रार्थान् उन लोगो ल भूमि लकर जिनके पास वह आवश्यकता स अधिक है उन लोगो को दे दी जाय, जिनके पास वह विस्तृत नही हे। विनोबाजी के अनुसार भूमि जल एव वायु की भांति प्रकृतिदत्त पदार्थ है जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का नही धरन् समाज का अधिकार है अतः यह मायसगत प्रतीत नहा होता कि किंचित लोग ता भूमि का उपयोग करें और लाखों लोगो को वे भूमि के लाभ स वंचित कर द।

हमार देश म लगभग ५ कराड व्यक्ति भूमि हान कृषक हे जो भूमि क अभाव म अत्यंत निम्न जीवन व्यतीत कर रहे हे। कृषि हमार देश का प्रमुख व्यवसाय है जिसम लगभग ६७% व्यक्ति लगे हुए हे अतः यदि उच्चांग म ही हम भूमि का समान वितरण कर देने हे ता स्वतः ही आर्थिक विषमता दूर हा सकती है। सत विनाबा भावे न अहिंसा का मार्ग लकर इस वाय के करन का बीडा उठाया है। वे पदल यात्रा करके गाँव गाव एव घर घर घूमत हे तथा अपन पवित्र एव हृदयस्पर्शी प्रवचना के द्वारा लोगो का हृदय परिवर्तन करने ल। इनके इस आन्दोलन की सफलता को देख

वर देश के अनेक नेता एवं समाज-सेवक भी इसमें शामिल हो गये हैं। इस आन्दोलन की उपयोगिता इसी बात से स्पष्ट है कि हमारे प्रधान मन्त्री नेहरू एवं भारत सरकार के अन्य सभी मन्त्री गण तथा कांग्रेस के कार्यकर्त्ता गण इसके प्रति सहानुभूति रखते हैं। यही नहीं, अमृतसर कांग्रेस के अधिवेशन में भूदान आन्दोलन की सफलता के लिए एक प्रस्ताव पास किया गया तथा देश के सभी राज्यों में भूदान अधिनियम बनाये गए हैं। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में भी इसे पर्याप्त स्थान दिया गया है।

### आन्दोलन का क्षेत्र—

आजकल यह आन्दोलन केवल भूमि के दान तक ही सीमित नहीं है, परन्तु 'सम्पत्ति दान' एवं 'ग्राम दान' भी साथ साथ चल रहे हैं। सम्पत्ति दान का उद्देश्य यह है कि भूमि-हीन कृषकों को जमीन के साथ साथ इतनी सम्पत्ति भी मिले, जिससे कि वे हल, बीज, बीज इत्यादि खरीद सकें। ग्राम दान आन्दोलन इसलिए है, जिससे कि सर्वोदय के सिद्धान्तों पर गाँव की समस्त भूमि का पुनः वितरण करने की प्रतीति कृषि का पुनः संगठन किया जा सकें। यह बड़े सतोष का विषय है कि दुबला पतला सन्त बिनोबा १३,००० मील की पंखल यात्रा कर चुका है तथा कुल लगभग ५० लाख एकड़ भूमि प्राप्त हो चुकी है। भूमि के साथ समर्थ व्यक्ति सम्पत्ति का भी दान दे रहे हैं तथा अब तक १०० ग्राम सम्पूर्ण रूप से बिनोबाजी को प्राप्त हो चुके हैं।

### भूदान पक्ष की महिमा—

भूदान पक्ष की प्रशंसा करते हुए श्रीमन्नारायण अग्रवाल ने अपने एक लेख में लिखा है कि इस आन्दोलन के परिणाम स्वरूप भूमि हीन कृषकों के पास छोटे-छोटे खेत हो जायेंगे। यद्यपि कुछ लोगों के विचार में यह आलोचना का विषय है, परन्तु श्री अग्रवाल का मत है कि बड़े बड़े खेतों की अपेक्षा छोटे छोटे खेतों पर खेती करना अधिक लाभप्रद है। उन्होंने बताया है कि जापान में प्रायः २५ एकड़ के खेत हैं। प्रायः उन्होंने लिखा है कि चीन की नई सरकार बड़े बड़े खेतों को समाप्त करके छोटे-छोटे खेत बनाकर भूमि का पुनः वितरण कर रही है। यही नहीं, रूस में भी कृषकों के पास ३ एकड़ से २३ एकड़ तक भूमि है। इन छोटे छोटे खेतों में तन, मन, धन लगाकर हमारे कृषक सुविधा से अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की सन्तुष्टि कर सकते हैं, अतः यह नहना कि भूदान आन्दोलन द्वारा खेती के छोटे होने के कारण कृषि अनाधिक हो जायेगी, असत्य है। श्री अग्रवालजी ने यह भी लिखा है कि छोटे पैमाने पर की गई कृषि के स्तर को ऊँचा करने के लिए कृषकगण अपनी सहकारी समितियों बना सकते हैं तथा सामूहिक रूप से बीज, खाद, मिर्चाई व बिक्री आदि का प्रबन्ध कर सकते हैं। श्री नेहरूजी के शब्दों में—“इस आन्दोलन के द्वारा एक ऐसा अनुकूल मनोवैज्ञानिक वातावरण समाज में उत्पन्न होता जा रहा है जिसने हमारी



भावी समस्याओं को बहुत कुछ मरल बना दिया है।" इस आन्दोलन के सम्बन्ध में श्री भगवानदास केला ने लिखा है—“यह पद्धति ग्रहिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त करती है। इसके पीछे विकेन्द्रीयकरण और स्वावलम्बन की प्रेरणा है।” भूदान यज्ञ के सम्बन्ध में श्री रामेश्वरदयाल ने लिखा है—“भारत की भूमि की यह विशेषता है कि यहाँ जब धर्म चक्र चल जाता है, तब जनता मन्त्रमुग्धसी सर्वस्व अर्पण कर देती है। साथ ही, हमें यह भी समझना चाहिए कि भूदान आन्दोलन से उत्पन्न जन-शक्ति के प्रभाव से हमारी आर्थिक रचना सर्वोदय की दिशा में प्रगति करेगी। किसी के भी हाथ में अत्यधिक पूँजी का केन्द्रीयकरण न होगा, क्योंकि प्राथमिक आवश्यकताओं के विषय में विकेन्द्रीत स्वावलम्बी व्यवस्था होगी। दोष बड़े उद्योग जो केन्द्रीत रूप में चल रहे हैं, उनके राष्ट्रीयकरण के लिए, जिस वातावरण की आवश्यकता है, वह भूदान आन्दोलन में छिपा है। इसी से समाज की जाति, वर्ण, ली-पुरुष आदि की असमानतायें दूर होंगी।”

### भूदान-यज्ञ की आलोचना

कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इस प्रकार भूमि का वितरण निर्धनता का वितरण है, क्योंकि जो भूमि कृषकों को दी जाती है वह प्रायः निष्कृष्ट होती है और इतनी अप्रयोज्य है कि उस पर कृषि करना असम्भव हो जाता है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक आलोचना की है कि इससे उप-विभाजन एवं अप-खण्डन की प्रेरणा मिलती है एवं इससे कृषि के प्राचीन एवं पिछड़े हुए तरीकों को मान्यता दी जाती है, परन्तु यदि हम गम्भीरता से विचार करें, तो हम यह ज्ञात होता है कि ये किञ्चित् आक्षेप आन्दोलन की महिमा को किसी प्रकार कम नहीं करते। वास्तव में भूमि का वितरण करते समय यह विचार रखा जाता है कि जात अनाधिक न हो। कुछ सीमा तक उप-विभाजन अवश्य होता है, परन्तु वितरण के बाद सहकारी कृषि द्वारा यह दोष भी दूर हो सकता है। सम्पत्ति-दान एवं ग्राम दान से तो कोई समस्या ही पैदा नहीं होती।

### भूदान-आन्दोलन की प्रगति—

द्वितीय योजना में यह स्वीकार किया गया है कि ग्राम दान वाले गाँवों के विकास के सम्बन्ध में प्राप्त व्यावहारिक सफलता सहकारी ग्राम विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी। “अखिल भारत सर्व सेवा मंच” द्वारा मितम्बर सन् १९५७ में यलवाल (मैसूर राज्य) में आयोजित सम्मेलन में इस बात पर बल दिया गया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा ग्रामदान आन्दोलन के बीच निकटतम सम्बन्ध स्थापित किया जाये। सामुदायिक विकास मन्त्रालय के तत्सम्बन्धी कर्मचारियों ने इस पर विचार किया और मई सन् १९५८ में माउन्ट आबू में हुए विकास आयुक्त सम्मेलन में इस पर और अधिक विचार किये जाने के बाद भूदान और ग्रामदान के बीच

निवृत्ततम सबंध स्थापित करने का निर्णय किया गया। सामुदायिक विकास खण्ड स्थापित करने और सामुदायिक विकास के अन्य नये कार्य आरम्भ करने के मकसद में सबसे पहले ग्रामदान वाले गांवों में कार्य आरम्भ किया जायेगा। भूदान के लिये भूमि दान दिये जान तथा उसके वितरण को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश पंजाब, बम्बई (मोराष्ट्र) बिहार, मद्रास, मध्यप्रदेश, राजस्थान, दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश में आवश्यक कानून बनाये जा चुके हैं। बम्बई में प्रशासन सबन्धी आदेश जारी किये जा चुके हैं।

सन् १९५५-५६ में विभिन्न राज्य सरकारों ने इस आन्दोलन की सफलता के हेतु जो वित्तीय सहायता प्रदान की है, उसका व्योरा इस प्रकार है —

### भूदान की वित्तीय सहायता

(हजार रुपये में)

राज्य अथवा केन्द्र नामित क्षेत्र	१९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८	१९५८-५९	१९५९-६०
(१) आन्ध्र प्रदेश	—	—	३०	२०	०*५
(२) बिहार	३३०	१०००	१८६०	१५००	५००
(३) बम्बई					
(अ) विधवा	†	†	२००	*	*
(ब) मोराष्ट्र	२५३	२५३	१६६	४५०	४५०
(४) केरल					
(५) मध्यप्रदेश	—	—	६६	२८०	—
(अ) मध्यप्रदेश	५००	५००	३००	१५०	—
(ब) मध्यभारत	१५०	३००	२००	१००	६००
(ग) भापाल	—	—	—	२५	—
(द) त्रिचयप्रदेश	—	—	५०	३७	—
(६) मद्रास	—	—	—	१०	१३८
(७) उड़ीसा	३५४	३०६	३३५०	२००	३३५२
(८) पंजाब	—	—	५०	५०	—
(९) राजस्थान	१००	२५०	३००	५०	—
(१०) उत्तर प्रदेश	—	—	—	५००	५००
(११) हिमाचल प्रदेश	—	—	२०	—	—

भारत सरकार द्वारा सन् १९५६-५७ में ११.६२ लाख रुपये और सन् १९५७-५८ में १० लाख रुपये भूदान आन्दोलन की वित्तीय सहायता के लिए स्वीकार किए गए। सन् १९५७-५८ में बिहार राज्य में एक नई योजना स्वीकार की गई जिसके अंतर्गत भूदान से सम्बन्धित भूमि रहित थमियों का बकाया गया। यह कार्य सहायिता के आधार पर किया गया एवं इस पर कुल २३ लाख रुपये खर्च हुआ। एक दूसरी योजना, जिसके अंतर्गत भूमिरहित कृषि परिवारों की वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गई, भी

† पूर्व मध्यप्रदेश में सम्मिलित

\* कुल बम्बई राज्य के लिए

कार्यान्वित हुई। इस पर कुल ३० लाख रुपया खर्च किए गए और यह योजना भी बिहार के भूदान से सम्बन्धित क्षेत्रों में लागू की गई। सामुदायिक विकास एवं सहकारिता मन्त्रालय (Ministry of Community Development and Co operation) द्वारा सामुदायिक विकास क्षेत्रों में भूदान सम्बन्धी साहित्य वितरित किया गया। इस कार्य में सन् १९५८-५९ में १.८२ लाख रुपये खर्च हुए और सन् १९५९-६० में २.६५ लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। ग्रामदान एवं ग्राम संकल्प गाँवों में ग्रामीण एवं लघु उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए उक्त मन्त्रालय ने सन् १९५९-६० में क्रमशः १.६६ व २.१ लाख रुपया देना स्वीकार किया है। ग्रामदान से सम्बन्धित गाँवों में विकास कार्य के हेतु श्रृंखला देने की योजना अनेक राज्यों ने स्वीकार कर ली है जिनमें से प्रमुख ये हैं—ग्राध्यपदेश, आसाम, बम्बई, केरल और मद्रास।

३० नवम्बर १९५९ तक राज्य वार भूमि एवं ग्रामों का दान इस प्रकार था —

### भूदान एवं ग्राम-दान

राज्य अथवा क्षेत्र	भूदान का क्षेत्रफल (एकड़ में)	वितरित भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	ग्रामदान (संख्या)
(१) ग्रामप्र प्रदेश	२,४१,९५०	९५,२७८	४८१
(२) आसाम	२३,१९९	२२५	१२७
(३) बिहार	२१,२२,९१०	२,४२,२५३	१५३
(४) बम्बई			
(i) गुजरात	४७,४८६	११,५२७	६३
(ii) सौराष्ट्र	३१,२३७	८,१८५	२
(iii) विन्ध्य प्रदेश	८६,७७८	४५,०००	—
(५) वेहली	३९६	१५७	—
(६) हिमाचल प्रदेश	१,५६८	२१	—
(७) केरल	२९,०२१	२,१०६	५४३
(८) मध्य प्रदेश :			
-(i) मध्य भारत	२,७४,६५७	३३,९२४	७४
(ii) महाकौशल	१,१८,३५३	५५२	
(iii) विन्ध्य प्रदेश	११,१९५	३,६७०	
(९) मैसूर	१९,९८९	२,६९४	६६
(१०) पंजाब	१९,९२९	५,६५३	२
(११) राजस्थान	४,२८,१७३	८१,१०१	२३४
(१२) तामिलनाडु (Tamilnad)	७०,८०३	२,३४९	२५४
(१३) उत्तर प्रदेश	४,११,४८४	१,२७,८३५	५९
(१४) उत्कल (Utkal)	३,९३,४६६	१,१८,३३५	१,९४६
(१५) वेस्ट बंगाल (West Bengal)	१२,६८१	३,६७३	२६
योग	४४,०९,६३६	८,४०,९०९	४,५६५

### STANDARD QUESTIONS

- 1 Carefully describe the Economic condition of Agricultural Labourers in India. How would you improve your lot ?
  2. Discuss the present condition of land-less Agricultural Labourers in India. How far Bhoodan can solve their problems ?
  - 3 Discuss the various factors responsible for the bad Economic condition of Indian Agricultural Labour. Suggest suitable remedies for its improvement.
  4. What do you understand by the term 'Bhoodan Yagya' ? How far has it solved the problem of landless labour in India ?
  - 5 Write a critical essay on 'Bhoodan Movement.'
-

## सामुदायिक विकास योजनाएँ

( Community Development Projects )

### प्रारम्भिक—

हमारा देश 'गाँवों का देश' है, जिसकी ८२.७% जन संख्या ५३ लाख गाँवों में निवास करती है। अत्यन्त प्राचीन काल से भारत के समस्त राष्ट्रीय जीवन की इकाई हमारे गाँवों में ही केन्द्रित रही। परन्तु यह दुर्भाग्य का विषय है कि आज हमारे गाँवों की दशा अत्यन्त दयनीय है। वे अपने अतीत का गौरव खो चुके हैं। अंग्रेजों ने इनकी समृद्धि का अपहरण किया। यही कारण है कि हमारे गाँव शोषित, अशिक्षित, दरिद्रों आदि के शमशान भानव-जीवन से समस्त दोष घेरे विद्यमान हैं। समाज के शिथिल एवं साहसी व्यक्ति गाँवों में रहना नहीं चाहते। यदि हम भारत के आर्थिक स्तर का ऊँचा उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले भारतीय गाँवों की दशा को सुधारना होगा। भारत के आर्थिक विकास के लिए यहाँ के ५३ लाख गाँवों के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना अनिवार्य है। हमको गाँवों के सभी अंगों का विकास करना चाहिये। स्फुट प्रयत्नों से इनका विकास नहीं हो सकता। हम एक ही साथ गाँव का आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पुनर्निर्माण करना है। इसके लिए कृषि की उन्नति, मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था, शिक्षा, सफाई तथा चिकित्सा का प्रबन्ध पारम्परिक ढंग, सधर्ष तथा मुकदमेबाजी का अन्त, बेकारी, ऋणश्रृंखला तथा पशुधन की समस्या का समाधान, गाँवों के आन्तरिक एवं सदस्यवाहन के साधनों का विकास, ग्रामीणों में नई भाषा का संचार आदि अनेक कार्यों की आवश्यकता है।

ब्रिटिश शासन काल में भारतीय गाँवों के विकास के लिए सरकार द्वारा प्रायः कोई प्रयत्न नहीं किया गया। ग्रामीण उन्नति के प्रति विद्वानों शासन की नीति सर्वत्र उपेक्षापूर्ण रही। डॉ. देश-भरों कुछ समान सुधारकों ने इस दिशा में सराहनीय कार्य किये हैं। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय सश्रम के साथ-साथ ग्रामीण विकास को भी अपना परम कर्तव्य समझा तथा ग्रामीण जीवन के उत्थान के लिए उनके नेतृत्व

में अखिल भारतीय सरखा सघ तथा अखिल भारतीय ग्रामीणोद्योग सघ ने ग्रामीण भारत में एक नई जान फूंक दी। इसी प्रकार स्वर्गीय श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर ने इस दिशा में प्रशसनीय कार्य किया है। सन् १९३५ के वैधानिक मसौदा के पश्चात् भारत सरकार का ध्यान भी इस ओर आकर्षित हुआ और तब से केन्द्रीय सरकार ने प्रांतीय सरकारों को इस कार्य के लिए एक करोड़ रुपये अनुदान के रूप में देना स्वीकार किया। सन् १९३७ में देश के विभिन्न प्रान्तों में काग्रसी सरकारों की स्थापना के बाद ग्राम सुधार का कार्य तीव्र गति से प्रारम्भ हुआ। प्रत्येक प्रांत में ग्राम सुधार के हेतु एक अलग विभाग खोला गया और ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिये योजनाएँ कार्यान्वित की गईं। परन्तु इन प्रयत्नों की सबसे बड़ी दुखलता यह थी कि सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि अपने विभागीय उद्देश्यों की गरूर पृथक् पृथक् रूप से ग्रामीणों के पास पहुँचने में जिससे ग्रामीण विकास के विमूढ़ हो जाता था और इसके सारे प्रयत्न निष्फल हो जाते थे। सच बात तो यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जो भी योजना बनाई जाय वह सम्बद्ध होनी चाहिए एवं उसमें ग्रामीण जीवन का कोई भी पहलू छूट न जाय। ग्रामीण विकास के लिये गाँवों के लोगों में उत्साह की भी बड़ी आवश्यकता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु हमारी जन प्रिय सरकार ने सामुदायिक विकास योजना (Community Development Project) बनाई है।

### सामुदायिक विकास योजना का अर्थ—

सामुदायिक विकास योजना वास्तव में बहुमुखी आधार पर ग्रामीण विकास की एक विस्तृत योजना है। श्री सैंडर्सन के अनुसार, “सामूहिक संगठन उन उद्देश्यों को प्राप्त करने जो कि सामूहिक कल्याण के लिये आवश्यक है तथा उनको प्राप्त करने के सर्वोत्तम उपाय दोनों को ही उपलब्ध करने की एक कार्य विधि है।”

### भारत में सामुदायिक विकास योजनाओं की आवश्यकता—

सामुदायिक विकास योजनाओं की हमारे देश के आर्थिक पुनर्गठन में विशेष आवश्यकता है। यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों की सम्पन्नता चाहते हैं, तो उनका एकमात्र उपाय सामुदायिक योजनाएँ ही हैं। ऐसी योजनाएँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विस्तृत हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि, उद्योग, सामाजिक कार्य आदि सभी सम्मिलित हैं। ग्रामवासियों का जीवन स्तर ऊँचा करने में भी ये योजनाएँ बाकी सीमा तक सहायक होंगी। यदि सच्चा सामाजिक सुधार करना है, ग्रामवासियों को आदर्श नागरिक बनाना है तो गाँव को अच्छा, साफ और रहने योग्य बनाना आवश्यक है। इसके प्रतिरिक्त खाद्य समस्या का समुचित हल करने के लिए एवं आर्थिक स्वावलम्बिता प्राप्त करने के लिये भी सामुदायिक योजनाओं का विशेष महत्त्व है। ऐसी योजनाओं से

कृषको में यह विश्वास उत्पन्न किया जा सकता है कि वे अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा अपनी दशा को स्वयं भी सुधार सकते हैं।

**सामुदायिक विकास योजनाओं का उद्देश्य—**

भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 'सामुदायिक योजना की रूपरेखा' शीर्षक पुस्तक में इसका उद्देश्य इस प्रकार बताया गया है—“योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के पुरुषों, स्त्रियों एवं बच्चों के जीवित रहने के अधिकार में, एक मार्ग-प्रदर्शक व्यवस्था के रूप में सेवाएँ प्रदान करना। “सामुदायिक विकास योजना का प्रमुख उद्देश्य क्षेत्र के मानव और भौतिक साधनों का पूर्णतः विकास करना है। श्री वित्तन नं, जो भारत में टैकनीकल कोऑर्पेरेशन फॉर इण्डिया के सचालक हैं, बताया है कि सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य सभी दिशाओं में विकास करने के लिये, समाज के लिये भोजन, स्वास्थ्य तथा आवश्यक ज्ञान उत्पन्न करना है।

**सामुदायिक विकास योजनाओं के प्रमुख अङ्ग—**

- ( १ ) इन योजनाओं की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ग्रामीण जीवन के बहुमुखी विकास के लिये प्रयत्नशील हैं। जैसा कि कृषि के शाही कमिशन ने कहा था—“कृषि सुधार की समस्या भारतीय ग्रामीण जीवन के सुधार की समस्या है और उसे सामूहिक रूप में ही हल करना होगा। ग्रामीण जीवन के सभी पहलू प्रायः परस्पर सम्बन्धित हैं अतः सर्वश्रेष्ठ विधि यही होगी कि ग्रामीण जीवन की समस्याओं पर एक ही समय में और एक-दूसरे के साथ समुचित सहयोग से आक्रमण किया जाय।” सामुदायिक विकास योजना की भी यही कार्यशैली है।
- ( २ ) ये योजनाएँ किंचित चुने हुये क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। ऐसा करने का यह आशय नहीं है कि शेष भागों की अपेक्षा कर दी जाये, बरन् उसका उद्देश्य यह है कि छोटे-छोटे क्षेत्रों में केन्द्रीभूत प्रयत्नों में अधिक सफलता मिलने की आशा है।
- ( ३ ) ये योजनाएँ एकाकी बहु-उद्देशीय साधन की व्यवस्था करती हैं, जो मीचे किसानों के घर तक पहुँचाने वाला है। अभी तक सरकार के विभिन्न विभाग ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं को पृथक्-पृथक् हल करने में लगे थे। इसमें व्यय भी अधिक होता था एवं सफलता भी नहीं मिली, किन्तु सामुदायिक विकास योजना लोगों को स्वयं अपने घरों पर खड़ा होना सिखलाती है एवं उनकी भारी समस्याओं को एक साथ हल करने का प्रयत्न करती है।

( ४ ) इन सामुदायिक विकास योजनाओं का सार अपना सहायता करने के नियम बनाना का सहायता करना है ।

( ५ ) इनका सफलता के हेतु पर्याप्त आर्थिक तथा औद्योगिक व्यवस्था बनाना है । पूर्व प्रयत्न में इन बातों का बड़ी कमी थी ।

**सामुदायिक योजनाओं का कार्य-भार—**

इन योजनाओं के अन्तर्गत विकास के निम्न कार्य क्रिये जायेंगे —

( क ) खेती तथा उसमें सम्बन्धित अन्य कार्य—

( १ ) भूमि को उपजाऊ बनाना और सिंचाई के छद्म छोड़ना ।

( २ ) अच्छे बीज खेती का मुख्यवस्थित करने तथा पशु चिकित्सा करना के मुख्य हुये छोड़ने बीजा का त्रय विनियम क्रम की सुविधाएँ पशु पालन तथा मत्स्य सुधारण के कार्य भूमि तथा खाद्य का अनुसंधान ।

( ३ ) मीनालय कक्षा और तस्करीया की खेती वन तथापन का विकास और भोजन का सुधार ।

( ख ) यातायात—

सड़क का प्रबंध यातायात यंत्र ट्रांसपोर्ट को उत्तम करना जहाँ पशुओं का यातायात तथा अन्य कार्यों के लिए उनका प्रयोग किया जाता वहाँ उस कार्य की उत्तमि करना ।

( ग ) शिक्षा—

निम्न स्तर की शिक्षा प्रारम्भिक शिक्षा हाईस्कूल मिडिल स्कूल सामाजिक शिक्षा और वाचनालयों का प्रबंध करना ।

( घ ) स्वास्थ्य—

सफाई और जन स्वास्थ्य का व्यवस्था रोगियों का चिकित्सा इच्छा हान में पहल और मृतकों की दल भान तथा शवों का व्यवस्था करना ।

( ङ ) प्रशिक्षण—

( १ ) विद्यमान कारागारों के स्तर का नवीन अध्ययन द्वारा ऊँचा करना ।

( २ ) सतिठरा विस्तार कार्य सहायकों निराक्षकों कारागारों प्रबंधकों स्वास्थ्य सत्राधी कार्यकर्ताओं और व्यक्तियों के प्रशिक्षण का प्रबंध करना ।

( च ) व्यवस्था प्रबंध—

देहाती प्रस्था में बेरोजगारों का दूर करने के लिए मजदूरी देना तथा अधिक से अधिक व्यवसाय निम्न के लिए —

( १ ) छात्र तथा मध्यम स्तर के घरेलू उद्योगों का विकास करना ।

( २ ) मायाजिन निवरण व्यापार महापर और व्यापार सभाओं द्वारा व्यवसाय निम्न का प्रबंध करना ।



## ( ■ ) गृह निर्माण—

देहाती तथा नागरिक प्रश्र्णा म मकानों के आधुनिक डिजाइन और नक्के तयार करना ।

## ( ज ) लोक-कल्याण—

( १ ) स्थानाय कलाकारों का मुलभूता और सस्कृति के अनुसार सामूहिक मनोरंजन की व्यवस्था करना फिल्म द्वारा शिक्षा देना और मनोरंजन करना ।

( २ ) स्थानीय तथा ग्र य खानों और भला का प्रवर्ध करना ।

( ३ ) सहकारी समितियाँ और पञ्चायतो द्वारा जनता के आर्थिक तथा नागरिक आ दोसन का संगठन करना ।

## योजना का संगठन—

इस कार्यक्रम का संपूर्ण उत्तरदायित्व सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय पर है । आधारभूत नीति संबंधी प्रश्न के द्वाय समिति के समुख रख जाते हैं । इस समिति म योजना आयोग के सदस्य खाद्य तथा कृषि मन्त्री और सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्री होते हैं । प्रधान मंत्री इस समिति का अध्यक्ष होता है । विशेष समितियों द्वारा त संबंधी मन्त्रालयों के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है ।

इस कार्य को कार्याचित करने का दायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों पर है । राज्य सरकार इस कार्यक्रम को राज्यीय विकास समितियों द्वारा कार्याचित करती है । इन समितियों म राज्यो के मुख्य मन्त्री विकास मन्त्री तथा विकास आयुक्त होते हैं । मुख्य मन्त्री इनके अध्यक्ष तथा विकास आयुक्त इनके कार्यालय सचिव होते हैं । कार्यक्रम का कार्यपालक प्रधान विकास आयुक्त होता है । जिलों म इसको पर्याप्त किये जान का दायित्व कमिश्नरों पर होता है । खण्डों म खण्ड विकास अधिकारियों की सहायता के लिए कृषि पशु पालन कुटीर उद्योग तथा सहकारिता जैसे विषयों के विभाग = विस्तारी अधिकारी होते हैं । गावों म ग्राम सबक बहुधंधी विस्तार अभि कर्ता एजेंट के रूप म १० गावों का कार्य सम्भालता है ।

## विस्तार संगठन—

खड़ा तथा गडवा म विस्तार संगठन दो कार्य करता है—(१) ग्रामीणों को व्यावहारिक ज्ञेय आदि की जानकारी कराता है और (२) सरकार द्वारा दी जान वाली वित्तीय तथा ग्र य प्रकार का सुविषाय उपलब्ध कराता है । ग्रामीणों की समस्याओं को सह संगठन विभाग अध्ययन आन् के लिये गोप्य सन्धियों तक पहुँचाना है ।

सामुदायिक संगठन—

आयाजन और कार्यायन का दायित्व लोक संगठना पर है। चुनी हुई पचायत आवश्यक आवाज का समग्र करता तथा महत्व के अनुसार क्रम से योजनाय निर्धारित करता है। प्राथमिक सहकारी समितिया तथा गावा के स्कूल भी इस काम क्रम में संबंधित रहते हैं।

खण्ड विकास समिति—

एक विकास समितिया में पचायता तथा सहकारी समितियों के प्रतिनिधि कुछ प्रगतिमान कृषक सामाजिक कार्यकर्ता तथा कार्यकर्त्रिया तत्संबंधी क्षेत्र के समस्त महत्त्व तथा विधान मभाइ सदस्य रहते हैं। ये समितिया अपन अपन क्षेत्रों की विकास योजनाओं का आयाजन उनका संबंध में पहल करन उनको स्वीकृति दितान तथा उन्हें कार्यायन करन के लिये उत्तरदायी हाती हैं। कुछ राज्यों में खंड पचायत समितिया स्थापित करन के लिये कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है।

वित्त व्यवस्था—

कायक्रम का कार्यायन करन के लिये वित्त की व्यवस्था जनता तथा सरकार मिलकर करता है। प्रत्येक खण्ड क्षेत्र की विकास योजनाओं के लिये जनता में नग्न तथा धर्म के रूप में प्राप्त होन वाले स्वेच्छिक योगदान की मात्रा निर्धारित हाती है। वितीय सहायता सरकार की ओर स मिनन की स्थिति में कर्दाय तथा राज्य सरकार आवश्यक मदा पर होन वाले व्ययों का समान रूप में तथा अनावतक मदा पर होन वाले व्ययों का ११ के अनुपात से वहन करती है। मिचार्ड तथा भूमि पुनरुद्धार जम कार्यों के लिये केन्द्रीय सरकार ऋणों के रूप में राज्य सरकारों को आवश्यक वितीय सहायता देती है। खंडा में नियुक्त कमचारिया पर राज्य सरकारों द्वारा किये जान वाले व्यय में से भी आधा भाग केन्द्रीय सरकार वहन करती है।

माच ३१ १९५६ तक जनगणना ७४५६ करोड़ ८० के मूल्य का योगदान किया जो १४०.८६ करोड़ रुपये के कुल सरकारी व्यय का लगभग ५.०% है। प्रथम योजनाकाल के निर्धारित ६६५.० करोड़ ८० के व्यय की तुलना में इस अवधि में केवल ५२४.० करोड़ ८० ही व्यय किये गये। इसी प्रकार ४४१.० करोड़ ८० की गेय निर्धारित राशि का उपयोग द्वितीय योजनाकाल में किया जायेगा। द्वितीय योजना के लिये लगभग २ अरब रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपकरणों का आयात के लिये प्राविधिक सहयोग मण्डल सकार्य करार के अनुसार अमेरिका सरकार में १ करोड़ ४२ लाख ८० हजार डालर प्राप्त हुये। योजनाकाल कमचारिया के प्रशिक्षण के लिये फाउ प्रनिष्ठान में भी सहायता प्राप्त हुई।

निम्न तालिका में व विभिन्न मद नी गई है जिन पर प्रथम एवं द्वितीय योजना के अन्तर्गत व्यय किया गया —

# व्यय तथा जनता का योग-दान

(अप्रैल १, १९५६)

(लाखों रुपये में)

( २०० )

विवरण	प्रथम योजना		द्वितीय योजना अर्वाध म		महा योग
	अर्वाध मे	१९५६-५७	१९५७-५८	१९५८-५९	योग
(१) राजकीय व्यय :					
ग्लॉक हेडक्वार्टर	६,६२	५,१३	६,२८	११,५२	२५,६३
(यातायात, कार्यालय भवन आदि को सम्मिलित करते हुए)					
कुपि तथा पशु सम्पदा	३,५२	१,७६	१,६८	१,८२	६,७८
सिंचाई तथा भूमि प्राप्ति	८०८	५,७५	६,६७	६,१२	२०,८३
स्वास्थ्य एवं प्रामीण					
सफाई	५,५२	२,२६	३,१२	३,०१	१२,६५
शिक्षा	२,६५	२,५२	२,५५	२,१६	९,८७
सामाजिक शिक्षा	१,६५	६६	१,५३	१,६७	५,५१
सदेवावाहन	६,६५	६५	२,११	१,८०	११,५०
ग्रामीण उद्योग	१,७८	१,०५	८५	७८	४,५५
गृह	३६	१,३५	१,२६	२,१६	५,१५
अ-वर्गीत व्यय	७,७६	२,६६	१,३६	५,२२	१७,३०
योग	५६,८८	२३,७०	३०,७२	३६,७६	१,४०,८६
(२) जनता का योग .					
	२५,१३	१६,३१	१६,३०	१६,८५	७४,५९

नोट—२ अक्टूबर १९५६ को राजकीय व्यय एवं जनता का योग क्रमशः १५३,६६ लाख रुपये तथा ७६ ७८ लाख रुपये था।

## विकास खण्डों पर ध्यान—

राज्यों की योजना में कोषों का विभाजन खण्ड वार किया गया है। प्रथम स्तरीय खण्डों (Stage I Block) के लिये पाँच वर्षों की अवधि के हेतु १२ लाख रुपये का व द्वितीय स्तरीय खण्डों के लिये पाँच वर्षों के हेतु ५ लाख रुपये का आयोजन किया गया है। पूर्व विस्तार अवधि के लिये कृषि विकास के हेतु १८,००० करोड़ उपलब्ध किये गये हैं।

## प्रशिक्षण—

ग्राम सेवका का दस वर्ष की ट्रेनिंग दी जाती है और इसके लिए ६१ विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र (Extension Training Centres) खोल गये हैं। सितम्बर १९५६ के अन्त तक १४०० ग्राम सेविकाओं का ३५ प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षित किया गया। सामाजिक शिक्षा के संगठनकर्त्ताओं की प्रशिक्षा के लिये १३, मुख्य सेविकाओं की प्रशिक्षा के लिए २ तथा स्वयं विकास अधिकारियों के लिये ८ प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों की प्रशिक्षा के लिये ३ प्रशिक्षण केन्द्र हैं। ६६ केन्द्र नर्सों की ट्रेनिंग के लिये व ६ केन्द्र महिला स्वास्थ्य अधिकारियों के लिये खोले गये हैं। विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों के आचार्यों की ट्रेनिंग के लिये देहरादून के पास एक प्रशिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र (Trainers' Training Institute) खोला गया है। उच्चाधिकारियों की ट्रेनिंग के लिये मसूरी में एक केन्द्रीय संस्था स्थापित की गई है। अल्पकालीन प्रशिक्षण कैंप भी चलाये जाते हैं जहाँ गैर सरकारी व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी जाती है। ३१ मार्च १९५६ तक १६ लाख ग्राम सहायक ग्राम सेवकों के काम में सहायता देने के लिये प्रशिक्षित किये गये थे।

## सामुदायिक विकास योजनाओं का आरम्भ एवं विकास—

सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य भारत की विशाल ग्रामीण जन संख्या का व्यक्तिगत तथा सामूहिक कल्याण करना है, का भारत में २ अक्टूबर सन् १९५२ को शुरू हुए ५५ योजना कार्य क्षेत्रों में आरम्भ किया गया था। प्रत्येक योजना कार्य में ५०० वर्ग मील के क्षेत्रफल में फैले हुए लगभग २ लाख की जनसंख्या के करीब ३०० गाँव आते हैं। यह कार्यक्रम खण्डों (Blocks) के रूप में कार्यान्वित किया जाता है। प्रत्येक खण्ड में सामान्यतः १५० वर्ग मील में फैले तथा ६०-७० हजार की जनसंख्या युक्त १०० गाँव आते हैं। पाँच वर्ष भरपूर विकास का कार्य किए जाने के बाद प्रत्येक खण्ड के दूसरे चरण का कार्य का आरम्भ होता है। जैसा कि नीचे दी हुई तालिका में प्रगट होता है, १ अप्रैल १९५६ तक इस योजना के अन्तर्गत २,५४८ खण्ड, ३,३६,५१८ गाँव तथा १७-३ करोड़ व्यक्ति आ गए—

# सामुदायिक विकास योजना की कार्य प्रगति (१ अप्रैल १९५६ तक)

राज्य व के द्र शासित क्षे	सीमा रहित (Delimited)		खण्डों की संख्या (१-४-५६)		जनसंख्या		गोव	क्षेत्रफल (वर्ग मील)
	खण्डों की संख्या	प्रथम स्तंभ	दूसरी स्तंभ	याव	(हजारों में)			
(१) आंध्र प्रदेश	४४७	१६१	६१	२२२	१,५६,७५	१,५६,७५	१५,८७१	५०,८२१
(२) आसाम	१५२	४२	२७	६६	३७,६६	३७,६६	१२,२८७	२२,७०६
(३) बिहार	५७५	२५४	३८	२६२	१,६६,२५	१,६६,२५	३,७५६	२३,३६०
(४) बम्बई	६४६	२११	८४	२६५	१,६६,५२	१,६६,५२	३,७५६	६१,६५४
(५) उन्मुघोर काश्मीर	५२	४८	५	१२	२३,५८	२३,५८	१,८४२	४७,५६२
(६) केरल	१४२	५५	१८	७३	६७,३०	६७,३०	८६२	१,६६६
(७) मध्य प्रदेश	४१६	१५१	७२	२२३	१,३८,१३	१,३८,१३	४२,७२०	८०,२०५
(८) मद्रास	२१८	१०६	१८	१६७	१,४१,६०	१,४१,६०	८,६६१	१२,८८०
(९) मैसूर	२६८	६६	३७	१३६	१,०८,५३	१,०८,५३	१५,५१३	५०,७३७
(१०) उड़ीसा	३०७	११६	२५	१४३	६२,०६	६२,०६	३१,४०८	३०,६८४
(११) पंजाब	२२८	६०	५३	१३३	६२,६७	६२,६७	१८,१३३	२५,७०३
(१२) राजस्थान	२३२	८६	३३	११६	७८,७५	७८,७५	१८,१०७	१५,५१८
(१३) उत्तर प्रदेश	८६६	३१७	८६	४०७	२,६५,५६	२,६५,५६	१,७,६६२	५५,७२३
(१४) वेस्ट बंगाल	३४१	१२३	२३	१४६	१,०८,६३	१,०८,६३	१६,६१६	१५,८५२
(१५) वे द्र प्रशासित क्षेत्र	१५१	५१	२०	७३	२६,२६	२६,२६	१,७,८६५	२६,६११
योग	५,२१७	१,६६६	६३३	२,५५८	१,७,३०	१,७,३०	५,३६,५१८	६,०६,०११

नोट—२ अप्रैल १९५६ तक इस योजना ने प्रगत २,७०८ व्यक्तियों ३,६० हजार गोव तथा १,७,६२ करोड़ व्यक्तियों का प्रदान किया।

अक्टूबर १९६३ तक सामुदायिक विकास का काम सारे दश में फैल जायगा ।

**दोष और सुझाव—**

ये योजनायें सफल रही हैं, परन्तु इनमें कई दोष हैं—

- ( १ ) पूर्व योजना की कमी । यह दोष अधिकाधिक अनुभव से दूर होगा ।
- ( २ ) राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों में सहयोग अथवा सहकारिता की भावना में कमी । अब यह माना जाने लगा है कि विकास कार्यक्रमों को लागू करने का दायित्व मुख्यतः डिप्टी कमिशनर पर होना चाहिये । इस व्यवस्था से उन्नत सहयोग एवं कार्यप्राप्तन सम्भव हो जायगा ।
- ( ३ ) गैरसरकारी बग का सहयोग पर्याप्त नहीं है । मूल्यांकन सङ्गठन ने बताया है कि राज्यों में योजना महासंस्था समितियों की स्थापना नहीं हुई है । जहाँ हुई है, वहाँ वे मिलकर नियमित रूप से विचार नहीं करती । योजना अधिकारियों ने इसे लाभदायक न पाकर बाधक पाया है, अतः अधिकाधिक सहयोग को प्रोत्साहन मिलना चाहिये ।
- ( ४ ) उपकरण के प्राप्त होने में देरी लगती है ।
- ( ५ ) कई योजनाओं में भौतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनुचित दीर्घता की गई है । इससे कई बार भौतिक उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है, परन्तु आन्दोलन जड़ नहीं पकड़ता, अतः प्रभाव अस्थायी होगा । जन प्रोत्साहन तो यथेष्ट है, किन्तु ऐसी स्थायी संस्थाएँ बनाने की आवश्यकता है जो इस प्रोत्साहन तथा सामूहिक कार्यक्रम का स्थायी ढङ्ग से चलावे । इसके लिये वचामतों एवं सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन देने और ध्यान देने की आवश्यकता है ।
- ( ६ ) विस्तार सेवा कमचारियों के चरित्र, प्रशिक्षण एवं चुनाव की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये ।

## राष्ट्रीय विस्तार सेवा

(National Extension Service)

जबकि सामुदायिक विकास योजना ग्रामीण पुनसङ्गठन का एक अङ्ग है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा उसकी एजेंसी है । इसके चालू करने की सिफारिश 'अधिक उन्नत उपजाओ' जाँच समिति तथा योजना आयोग ने की थी और यह २ अक्टूबर १९५९

१९५३ में चालू की गई। उद्देश्य एक सा हाने के कारण केन्द्र तथा राज्यों में सामूहिक विकास योजना एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा को मिला दिया गया है, परन्तु राष्ट्रीय विस्तार सेवा स्थायी है, जबकि सामूहिक योजना ३ वर्ष के लिए है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा के द्वारा योजना काल के अन्त तक सारे देश के लोगों तक पहुँचने का प्रयत्न किया जावेगा।

किमान बिना सहायता एवं उच्च प्रदर्शन के स्वयं वैज्ञानिक कृषि अपनाते में असमर्थ है। इस योजना के अन्तर्गत अनेक व्यक्तियों को ग्रामीण जनो की सहायताएं प्रशिक्षित किया गया है। वे गाँव वालों को अपने घर एवं गाँव साफ, स्वास्थ्यवर्द्धक रखने, सड़कें बनाने व मरम्मत करने, कुटीर उखाँव बनाने एवं सहकारी समितियों संगठित करने के लिये कहते हैं। दूसरे शब्दों में, वे ग्रामीणों को अपने ही प्रयत्नों द्वारा अपने प्रसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रत्येक १० गाँव के पीछे एक ऐसा कार्यकर्ता रखा गया है। ग्राम स्तर कार्यकर्ताओं का यह संगठन 'राष्ट्रीय विस्तार सेवा' के नाम से बोला जाता है।

सामुदायिक योजना क्षेत्रों में अन्य न्यातों की अपेक्षा प्रशिक्षित कार्यकर्ता कहीं अधिक सख्या में होते हैं। उदाहरण के लिये, एक योजना क्षेत्र में प्रति ४ या ५ गाँव पीछे एक ग्राम स्तर कार्यकर्ता होता है। वह ग्राम स्तर कार्यकर्ता गाँव वालों का मित्र एवं मार्ग दर्शक होता। स्वयं वह ब्लॉक प्रधान कार्यालय के ब्लॉक विकास अधिकारी एवं अन्य तान्त्रिक विषयों से मार्ग-दर्शन प्राप्त करता है।

आरम्भ में यह सेवा सम्पूर्ण देश भर में २४० ब्लॉकों में चालू की गई थी। प्रथम पंच वर्षीय योजना काल में लक्ष्य सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अन्तर्गत ग्रामीण जन-सख्या के लगभग  $\frac{2}{3}$  भाग तक पहुँचने का था। अक्टूबर सन् १९५५ तक यह कार्यक्रम ६८६ करोड़ व्यक्तियों को, जो कि १,०६,०५७ गाँवों में (६५१ सामुदायिक योजना एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा ब्लॉकों में विभाजित) निवास करते थे, विस्तृत किया। ये सामुदायिक योजना ब्लॉक १५२ और राष्ट्रीय विस्तार सेवा ब्लॉक १३५ थे। इस प्रकार भारत में प्रत्येक पाँच गाँवों में एक गाँव उपरोक्त किसी एक या दोनों ही सेवाओं का लाभ पा रहा था।

प्रथम योजना के अन्त तक १,१६० विकास ब्लॉक बनाये गये, जिनमें से प्रत्येक में १०० गाँव और ६०७० हजार जनसंख्या है। इनमें से लगभग ३०० को गहन सामुदायिक योजनाओं में परिवर्तित कर दिया गया और शेष राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अन्तर्गत था। द्वितीय योजना में इस कार्यक्रम के लिये २०० करोड़ रुपये रखे गये हैं, ताकि यह सम्पूर्ण भारत में विस्तृत हो जाय। कुल ३,६०० प्रतिष्ठित ब्लॉक विस्तार सेवा के अन्तर्गत बनाये जायेंगे, जिनमें से १,१२० को गहन विकास के लिये चुन लिया जायगा।

**STANDARD QUESTIONS**

1. Explain the importance of villages in the economic system of India and discuss the attempts made for rural reconstruction in our country.
2. Examine the main aim of the Community Development in our Country. How far they have succeeded in achieving their aims ?
3. What are the main features of Community Development Projects launched in the Country ? Examine their usefulness as an instruments of rural reconstruction
4. Write a full note on the achievements of Community Development Projects in India.
5. Write an Explanatory note on India's National Extension Service



## भारतीय सूती वस्त्र उद्योग

( Indian Cotton Textile Industry )

प्रारम्भिक—

“भारत का सूती वस्त्र मिल उद्योग देश के अतीत का गौरव, वर्तमान और भविष्य का सदेह, परन्तु सदैव आशा की वस्तु रहा है।” यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है, किन्तु परिमाण एवं गति की दृष्टि से इसके विकास में विशेष रूप से विगत शताब्दी का समय अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा है। आजकल कृषि उद्योग के बाद सूती वस्त्र उद्योग ही देश के सर्वाधिक व्यक्तियों को जीविका प्रदान करता है, इसके साथ ही हमारे देश के कुल उत्पादन का ३५ प्रतिशत भाग उत्पन्न करने का भी इस उद्योग को श्रेय है। इस उद्योग में ८ लाख श्रमजीवी लगे हैं एवं १२२ करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई है। सन् १९४७ में जब कि हमारा देश स्वतन्त्र नहीं हुआ था, यहाँ ३८८ सूती मिलें थी, जिनमें १ करोड़ तकवे एवं २ लाख करवे थे और अब इस उद्योग में ४८२ सूती मिलें हैं, जिनमें १३ करोड़ ४० लाख तकवे हैं। १९४८ में जो उत्पादन १४,४७० लाख पौंड सूत और ४३,१९० लाख गज कपड़ा था, १९५७ में वही उत्पादन बढ़कर १७,८०० लाख पौंड सूत और ५३,१७० लाख गज कपड़ा हो गया। सन् १९५९ में कपड़े का उत्पादन ४९,२८० लाख गज और सूत का उत्पादन १७,१८८ लाख पौंड हुआ। आज यह उद्योग ४०० करोड़ रुपये की उत्पत्ति कर रहा है। सूती वस्त्र के परिमाण को ध्यान में रखते हुए यह विश्व के तीसरे दर्जे का उद्योग है एवं सूत उद्योग में इसका विश्व में दूसरा स्थान है। भारतीय मिल उद्योग में सूत एवं कपड़े के उत्पादन में निरंतर प्रगति हो रही है।

सन् १९४७ में भारत के विभाजन के समय भारत की बहुत सी अन्धरी कपास उत्पन्न करने वाली भूमि पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गई, इसके बावजूद भी उत्पादन में वृद्धि इस बात का द्योतक है कि भारतीय वस्त्र उद्योग में अपार उत्पादन-क्षमता निहित है। उद्योग के लिए कपास की खपत भी १९४८ की ३५ लाख गांठों से

बढ़कर १६५८ म ५० लाख गांठें हो गईं। इनमें ६ लाख कपास का गांठ विदेशों में निर्यात की गई जब ४० लाख गांठों का देश में ही उत्पादन किया गया।

भारत में सूती कपड़ों के निर्यात में भी प्रगति का है। निर्यात करने वाले देशों में जापान के बाद भारत का स्थान है। सूती वस्त्र का निर्यात भारत पश्चिम में कनाडा में लेकर पूर्व में इंडोनेशिया तक और उत्तर में फिनलैंड तक और दक्षिण में आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड तक करता है। आज हमारा देश ७५ म ८० करोड़ गज मिन का कपड़ा विदेशों में निर्यात कर रहा है जब कि कुछ समय पूर्व हमारा देश विदेशों में कपड़ों का आयात करता था। इस उद्योग में हुई इस तरह की क कुछ अन्तर्राष्ट्रीय कारण हैं किन्तु वास्तव में देश में हुई प्रगति का ही इसका श्रेय प्राप्त है। हमारा देश द्वारा सन् १९५४ ५४ ५६, ५७ में क्रमशः ६४१ ८७३ ८०४ ७६५ मिलियन गज कपड़ा निर्यात किया गया और सन् १९६० ६१ म १ ००० मिलियन गज कपड़ा निर्यात करने का लक्ष्य है।

### उद्योग का अतीत एवं विकास—

हमारे देश में सूती वस्त्र उद्योग बहुत प्राचीन काल से ही उत्पन्न स्थिति में था। भारतीय संस्कृति के प्राचीन स्मारक माहानाद्यों के अवशेषों में सूती वस्त्र भी प्राप्त हुए हैं प्रसिद्ध वैज्ञानिक जेम्स टनर और ए० एन० गुलाक के मतानुसार ये प्राप्त सूती वस्त्र कई सौ वर्षों के हैं। ग्राम के मुप्रमिड इतिहासकार हैराडोटस का श्रेय वर्णित होकर कहते हैं कि भारतीय एक ऐसी जन कल्पा रहने लगे हैं जो भंड बेरगिया के शरीर से प्राप्त नहीं होता बल्कि पड़ा पर उगाई जाता है। घनत्व का काल कृतिर्वा भी इस उद्योग के गौरवपूर्ण अतीत की कहानी कहता है। भारतीय वस्त्र उद्योग को मुस्लिम काल में बहुत गौरव प्राप्त हुआ। श्री टी० एन० मुर्जी के मतानुसार मनमन का एक २० गज लंबा तथा १ गज चौड़ा मुंदर टुकड़ा अंग्रेजी के बीच में से मुगलता पूर्वक निर्यात करता था इस कपड़ों के निर्माण में लगभग ६७ माह लगते थे। श्री टैबॉनियर के शब्दों में—“भारतीय संस्कृति उनका महान भा है जिस से वह अनुभव नहीं का जा सकता था।

सूती कपड़ों के अतीत का विवरण भारत में सन् १८१८ में हुगली नदी के किनारे प्रेमरा नगर स्थान पर स्थापित की गई थी परन्तु वास्तविक रूप में इस उद्योग का प्रगति का प्रारम्भ सन् १८५४ में उस समय हुआ जब कि एक पारसी उद्योगी श्री बाबूजी जी नाभा भाट्टावर ने वास्को स्प्रिंग्स एंड वीविंग कम्पनी की स्थापना की और इसके बाद एक अग्रज उद्योगपति न भंडाव में दूसरा मिन स्थापित किया। इन दोनों कारखानों की प्रगति सफलता ने परिणामस्वरूप सन् १८७५ तक समस्त देश में ४८ वस्त्र मिन स्थापित हुईं। इन कारखानों का प्रगति में प्रभावित होकर

अहमदाबाद गोलपुर मद्रास कानपुर आदि नगरो म सूती वस्त्र मिलों की स्थापना का गई और सन् १९१४ तक २६४ वस्त्र मिल स्थापित की गई ।

**प्रथम महायुद्ध काल मे उद्योग की स्थिति—**

दुर्गी सूती कपड़ा मिल की उन्नति और सासकर सन् १९१४ के बाद की प्रगति में परात नहीं तो मुख्य रूप से महायुद्ध स्वदेशी आन्दोलन एवं इस उद्योग के उत्पादन से विदेशी प्रतियोगिता की समाप्ति आदि का याग रहा । किन्तु इस उद्योग के विकास को सर्वाधिक रूप से देश में बड़ी हुई कपड़ की माग ने प्रभावित किया ।

प्रथम महायुद्ध काल में इस उद्योग को विशेष प्रोत्साहन मिला । क्योंकि इस समय विदेशों से कपड़ का आयात बन्द हो गया और साथ ही भारतीय सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शासन ने देश में ही बहुत से सामान खरीदा । युद्धोपरात ६ वर्ष तक यह उद्योग निर्बाध रूप से चलता रहा किन्तु इसके बाद जापान एवं अमेरिका से प्रतिस्पर्धा युद्ध के पश्चात् माग में कमी हुईताम एवं कोयल के मूल्य में वृद्धि होने से उद्योग को भारी क्षति उठाना पड़ी । इस समय तक सूती वस्त्र मिला की संख्या बढ़ कर २७१ हो गई थी । इन परिस्थितियों में जबकि उद्योग की स्थिति अत्यंत दयनीय थी सरकार को माग की गई । सन् १९२७ में स्थापित टारिफ बोर्ड द्वारा आयात मशीनों के कर को सरक्षण दिया गया । सन् १९३० में वर्ष उद्योग सरक्षण अधिनियम बना इस अधिनियम के अनुसार विदेशी आयात पर १५ प्रतिशत तथा अन्य देशों के आयात पर २० प्रतिशत कर लगाया गया । इस कर में सन् १९३४ में ५ प्रतिशत की वृद्धि की गई । सन् १९३४ में एक अधिनियम और पास हुआ जिसके अनुसार सरक्षण की अवधि १९४ तक बढ़ा दी गई ।

**द्वितीय महायुद्ध काल में उद्योग की स्थिति**

द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ में ३६८ सूती वस्त्र मिल थीं युद्ध की शुरुआत के साथ ही उद्योग को पुनः प्रोत्साहन मिला । युद्ध के कारण विदेशों से आयात बन्द हो गया एवं निर्यात को प्रोत्साहन मिला जिसके कारण मूल्य में वृद्धि हुई । साथ ही विदेशी वस्त्र उद्योग युद्ध की आवश्यकताओं के उत्पादन में लग गया एवं जापान में सैन्यता होने के कारण भारत को उपभोक्ताओं एवं मित्र देशों की सहायता का आन्तरिकता पूर्ति का एकाधिकार प्राप्त हो गया । उद्योग की स्थिति में विचलित होकर सरकार का कपड़ पर कंट्रोल लगाना पड़ा इसके लिए सरकार ने चार आदेश जारी किए । प्रथम आदेश Cotton Cloth and Yarn Control Order 1943 के अनुसार कपड़ का उत्पादन वितरण एवं कीमत पर सरकार द्वारा नियंत्रण दिया

गया। दूसरे आदेश द्वारा कपड़े का स्थानीय उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न एवं तीसरे आदेश के अनुसार कपड़े के यातायात पर नियन्त्रण रखने का प्रयत्न किया गया एवं चौथे आदेश का उद्देश्य कपड़े के उत्पादन के लिए आवश्यक बच्चे माल तथा अन्य साधनों के मूल्यों पर नियन्त्रण करना था। इस नियन्त्रण के प्रभाव से सन् १९४६ में उद्योग की स्थिति में प्रभाव हुआ, अतः सन् १९४७ में वस्त्र उद्योग पर ये नियन्त्रण सम्बन्धी सभी आदेश हटा लिए गए। नियन्त्रण से पूर्व सन् १९४२ में कपड़े का मूल्य सन् १९३९ की अपेक्षा चार गुना बढ़ गया, साथ ही भारतीय वस्त्रों का निर्यात भी बढ़ता जा रहा था एवं देश में भी कपड़े की मांग में वृद्धि हो रही थी। किन्तु सन् १९४८ तक उद्योग की स्थिति सामान्य हो गई और इस समय तक कपड़ा मिलों की संख्या बढकर ४०७ हो गई।

**देश के विभाजन का वस्त्र उद्योग पर प्रभाव—**

१५ अगस्त सन् १९४७ को देश स्वतन्त्र होने के साथ साथ भारत एवं पाकिस्तान, दो हिस्सों में विभाजित हो गया, जिसके परिणामस्वरूप सूती वस्त्र उद्योग को गहरा घक्का लगा। ७५ प्रतिशत श्रेष्ठ कपास उत्पन्न करने वाली भूमि तथा १४ सूती वस्त्र कारखाने पाकिस्तान को हस्तांतरित किये गये। इस समय उद्योग के लिए कपास एक समस्या बन गई। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अनेक व्यापारिक सम्झौते होते हुए भी पाकिस्तान के दुर्व्यवहार से भारत को हानि उठानी पड़ी। अन्त में विवश होकर भारत ने मिथ, अफ्रीका आदि देशों से सम्झौते किये एवं देश में 'अधिक कपास आन्दोलन' चलाया गया, परिणामस्वरूप वस्त्र उद्योग पुनः प्रगति के मार्ग पर बढ़ने लगा एवं उत्पादन में वृद्धि हुई।

**प्रथम पंचवर्षीय योजना से सूती वस्त्र-उद्योग—**

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अधीन ४७० करोड़ गज कपड़ा और १६४ करोड़ पींड सूत पैदा करने का लक्ष्य था और उत्पादन के ये लक्ष्य अपनी योजना की अवधि ३१ मार्च १९५५ के समाप्त होने के बहुत पूर्व ही पूरे कर लिये गये थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वस्त्र उद्योग हेतु रखे गये एक निश्चित कार्य क्रम के अनुसार लक्ष्य था कि भारत पर्याप्त मात्रा में वस्त्रों का निर्यात करता रहे और देश के आन्तरिक उपभोग के लिए भी आवश्यकता से अधिक कपड़ा प्राप्त हो।

कर्वे कानूनसो समिति की सिफारिशों के अनुसार योजना काल में हस्त करघा उद्योग को विशेष प्रोत्साहन दिया गया, जिसके कारण करघों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि से कम वृद्धि हुई। समिति की सिफारिशों के अनुसार हस्त चलित एवं शक्ति-चलित करघों का उद्योग में अधिक उपयोग होना चाहिए, जिससे बेकार बैठे लोग रोजगार पर लग सकें। सरकार ने इस योजना-कास में कपड़े का निर्यात बढ़ाने के लिए एक सूती वस्त्र निर्यात प्रवर्धक परिपद (Cotton Textile Export Promotion

Council) की नियुक्ति की, जिसका कार्य वस्त्र निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए हर सम्भव उपाय करना था।

**द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सूती-वस्त्र उद्योग—**

द्वितीय आयोजना के अन्त तक ८४० करोड़ गज के कुल उत्पादन का अनुमान है। इस योजना काल के लिए वस्त्र उद्योग के उत्पादन-लक्ष्य की घोषणा सन् १९५६ में की गई थी, जिसके अनुसार सन् १९६०-६१ तक २४ प्रतिशत उत्पादन में वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें ३,५०० मिलियन गज कपड़े का उत्पादन हस्त-करधा उद्योग के लक्ष्य की सीमा है। इस अनुमान के अनुसार योजना के अन्त तक देश में प्रति व्यक्ति कपड़े का औसत उपभोग बढ़कर १८.५ गज हो जायगा एवं सारे देश की आवश्यकता पूर्ति के लिए ७४० करोड़ गज वस्त्र प्रति वर्ष उत्पादन करने का लक्ष्य है, साथ ही १०० करोड़ गज कपड़े के निर्यात करने का लक्ष्य है। उपरोक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु १४,६०० नये चलित करघे लगाने की व्यवस्था है। वस्त्र उद्योग में मिल क्षेत्र का जहाँ तक सम्बन्ध है, इस योजना के अन्तर्गत यह निर्धारित नहीं किया गया है कि देश की खपत के लिए उस कितना उत्पादन बढ़ाना है। ऐसा करने का उद्देश्य मिलों द्वारा कपड़े का उत्पादन ५०० करोड़ गज के आस-पास ही स्थिर रखने का है, जिससे कपड़े की अतिरिक्त मांग को हस्तकरघों एवं विद्युत चलित करघों के उत्पादन में पूरा किया जा सके। इस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा वस्त्र उद्योग के सम्बन्ध में जो नीति निर्धारित की गई, देश के उद्योगपतियों द्वारा उसका स्वागत किया गया। किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि मिल उद्योग एवं करधा उद्योग में समन्वय स्थापित किया जावे, जिसमें विशाल उद्योग के साथ साथ ही छोटे पैमाने के करधा उद्योग भी उन्नति कर सकें। इस योजना के अन्तर्गत इस विषय पर विशेष रूप में ध्यान दिया गया है।

**भारत सरकार की नई वस्त्र-नीति—**

भारत सरकार द्वारा सूती वस्त्र उद्योग के सम्बन्ध में घोषित अपनी नई नीति के अनुसार मिलों द्वारा ३५.३ करोड़ गज, विद्युत चलित करघों द्वारा २०.१ करोड़ गज एवं हस्त करधा द्वारा १०० करोड़ गज अतिरिक्त कपड़ा बुना जाना चाहिए। सरकार की इस नीति की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं—

(i) नवीन तकलियों के लाइसेंस केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिये जाएँ जो उनको शीघ्र चालू करने का प्रयत्न कर सकें, जिससे बढ़ती हुई मांग को शीघ्रता से पूरा किया जा सके।

(ii) सूती वस्त्र मिलों को १४,६०० नवीन करघों को लगाने की अनुमति इसलिए दी गई है कि उनका समस्त उत्पादन, जो लगभग ३५ करोड़ गज है प्रति वर्ष निर्यात किया जा सके।

(iii) ३५ ००० विद्युत चलित करघे सहकारी समितियों द्वारा लगाये जाने की व्यवस्था की गई है, और

(iv) इस नीति के अन्तर्गत अबर चरखा को विशेष महत्व दिया गया है। उपरान्त नीति के अनुसार कुटीर एवं ग्रामोद्योगों का काफी विकास होगा। अबर चरखा एवं नई सूती मिला के बीच के राजनीतिक मतभेद भी समाप्त हो जाने की आशा है। अनुमान है कि इससे भारतीय सूती वस्त्र के निर्यात व्यापार पर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कृष्ण आनोचको के मतानुसार यह नीति वर्तमान स्थिति में अनुपयुक्त प्रतीत होती है। राष्ट्रादता के विकास एवं प्रतियोगिता की तीव्रता से यह मान लना कि २ वर्ष में उद्योग ३५ कराड गज वस्त्र निर्यात करने लगेगा, मदहसपद है। इस नीति के अनुसार सरकार ३५ हजार विद्युत चलित करघों की स्थापना का विचार रखती है, अतः हस्तचरखा उद्योग पर इसका बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका है। वस्त्र जाँच समिति (१९५६) के अनुसार भी द्वितीय योजना में प्रति व्यक्ति रुपय की खपत १७ ५ गज से अधिक होने की सम्भावना नहीं है जबकि निर्धारित मूल्य १८ ५ गज का है, इसका कारण यह बताया गया है कि देश की आर्थिक प्रगति उस गति में नहीं हो रही, जिसका अनुमान किया गया था।

**उद्योग की समस्याएँ और हल—**

वर्तमान में सूती वस्त्र उद्योग की प्रधान समस्याएँ निम्न हैं,—

(१) यंत्र सामग्री का आधुनिकीकरण एवं स्वचालन—पिछले दो महायुद्धों में अत्यधिक उत्पादन के कारण यंत्र सामग्री बहुत घिन गई है। युद्ध काल एवं उसके पश्चात् यंत्रों का मिलन में कठिनाई होने एवं उनका अधिक मूल्य होना के कारण उन यंत्रों को परिवर्तित नहीं किया गया अतः इन पुरानी मशीनों में अत्यधिक टूट फूट एवं घिसाई हुई है। साथ ही अन्य देशों की अपेक्षा हमारा उत्पादन व्यय भी उपरोक्त कारणों से अधिक हो गया है। वर्तमान समय में इस उद्योग में लगी हुई सभी मशीनें लगभग ४० वर्ष पुरानी हैं। अतः आज इस उद्योग की महत्वपूर्ण समस्या यंत्र सामग्री के पुनः स्थापन एवं आधुनिकीकरण की है। 'ममत्स उद्योग में उपयुक्त आधुनिकीकरण के बिना लागत में कभी अथवा क्वालिटी में कोई बड़ा सुधार होना सम्भव नहीं है।'

सूती वस्त्र उद्योग में विश्व में अत्यधिक प्रगति की है। भारत जान कि सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है, उस प्रगति के साथ चलना होगा, यह विश्व की बढ़ती प्रतियोगिता में अपना स्थान बनाये रखने के लिये भी नितात आवश्यक है। आज विश्व के अन्य देशों में स्वचालित करघों का उपयोग होता है, हम पुराने यंत्रों के प्रयोग में इस उद्योग में सूती वस्त्र के उत्पादन में गुण एवं मर्यादा में वृद्धि नहीं कर

सकने । मूली वस्त्र मिलो में जिस तेजी के साथ पुरानी यंत्र सामग्री के स्थान पर नवीनतम उपकरणों का प्रतिस्थापन किया जायेगा, वैसे वैसे मूली वस्त्र के उत्पादन में गुण एवं सख्या में वृद्धि सम्भव होगी । इस समय आधुनिकीकरण की आवश्यकता केवल उद्योग की दृष्टि में ही महत्वपूर्ण नहीं है अपितु स्वदेश एवं विदेश की निरंतर बदलती हुई माँग को योग्यता एवं सुविधा से पूरा करने के लिये भी आधुनिकीकरण आज की माँग है । वस्त्र-उद्योग में प्रयुक्त होने वाली कुछ मशीनें जैसे—रिंग फ्रेम, करचे एवं धुनाई इजन आदि का निर्माण अब देश में ही बृहद परिमाण में होता है, इसके साथ ही फ्रेम, स्वचालित करचे, फ्लाई फ्रेम तथा रीलिंग मशीनों के निर्माण का काम भी प्रारम्भ हो चुका है । फिर भी देश में निर्मित कपड़े की किस्म में सुधार एवं माल के समापन के काम में लायी जान वाली मशीनों का आयात आवश्यक है ।

इस उद्योग में भारतीय अपने उत्पादन क्षेत्र (निर्यात) में अभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जबकि उत्पादन व्यय में कमी आये और यह अभी सम्भव है, जबकि उद्योग में पुराने यंत्रों के स्थान पर नवीनतम यंत्रों का उपयोग हो तथा स्वचालित यंत्रों का प्रयोग किया जावे ।

(२) वस्त्र उद्योग के लिये आवश्यक यंत्रों का निर्माण—विज्ञान के क्षेत्र में हमारा देश पिछड़ा होने के कारण, वस्त्र उद्योग देश का प्राचीनतम उद्योग होते हुए भी, उद्योग के लिये आवश्यक यंत्र सामग्री के लिये विगत १०० वर्षों से विदेशी आयात पर निर्भर था । इसके अलावा विदेशों में, विशेषकर अबभूतपूर्व के बाद, यंत्र सामग्री के दाम बहुत ऊँचे हो गये हैं । अतः विदेशी विनिमय की सुरक्षा एवं आत्म-निर्भरता की दृष्टि से यह आवश्यक है कि हमारे देश में आवश्यक यंत्रों का निर्माण हो, जिसमें हम विदेशों पर निर्भर नहीं रहें ।

हमारे देश में विगत कुछ समय में वस्त्र उद्योग में प्रयुक्त होने वाले कई यंत्र एवं उनके हिस्से बनाने की दिशा में काफी प्रगति हुई है । आज हमारे देश में तकुएँ, सादा करचे, रिंग फ्रेम इत्यादि का निर्माण पर्याप्त परिमाण में होता है, साथ ही स्वचालित करचो, ड्रा फ्रेम्स, फ्लाई फ्रेम्स आदि यंत्रों का निर्माण कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है । बहुत शीघ्र ही यंत्र सामग्री के अन्य कई भागों का निर्माण देश में ही प्रारम्भ किया जायेगा । वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित यंत्रों के निर्माण के लिये निपुण की गई काम चलाऊ समिति द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में वस्त्र उद्योग मशीनरी ने हिस्सों के तैयार करने के सम्बन्ध में शीघ्र उठाये जाने वाले कदमों पर विचार करेगी । इस दिशा में कुछ उद्योग पतियों द्वारा भी कदम उठाया गया है ।

(३) हस्त-करघा एवं मिलों में समन्वय—हस्त-करघा एवं मिलें स्वस्थ प्रति योगिता के साथ कदम-ब-कदम मिलाकर चल सकें, इसके लिए आवश्यक है कि हस्त करघा उद्योग एवं मिल उद्योग में समन्वय स्थापित हो सके । द्वितीय पंचवर्षीय योजना

क अतगत सूती वस्त्र का उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार ने ३५,००० विद्युत चक्ति करघों के लगान का न्यून निर्धारित किया है इससे निश्चित रूप से उत्पादन में तीव्र वृद्धि होगी, किंतु सरकार के इस कदम से वेकारी फैलन का भय है। इसलिए प्राज्ञ आवश्यकता इस बात की है कि सरकार हस्त करघा उद्योग का अधिक से अधिक संरक्षण दे जिससे मिल उद्योग एवं हस्त करघा उद्योग में समन्वय स्थापित किया जा सके। हमारी सरकार की नवीन सूती वस्त्र नीति इस दिशा में प्रयत्नशील है।

(४) पर्याप्त कच्चे माल का अभाव—दश के विभाजन से पूर्व तो यहाँ पर्याप्त मात्रा में कपास उत्पन्न होता था देश की आवश्यकता पूर्ति के साथ साथ विदेशों को कपास का निर्यात भी किया जाता था। किन्तु दश के विभाजन के परिणामस्वरूप कपास उत्पादन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया और हमारे देश में कपास एक महत्वपूर्ण समस्या बन गयी। हमें अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए विदेशों से अधिक मूल्य देकर कपास का आयात करना पड़ा। यह कठिनाई इस उद्योग में प्राज्ञ भी है, यद्यपि १९४८ में उत्पन्न १८ लाख गाँठ में बढ़कर १९५८ में उत्पादन ३४ लाख गाँठ हो गया।

इस समस्या के समाधान हेतु अन्धे किस्म एवं लंबे रेशे वाली रई का उत्पादन बढ़ाने हेतु अनुसन्धान होना चाहिए जिससे कच्चे माल के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हो सकें। साथ ही समस्या समाधान हेतु Research Institute for Cotton Industries (वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित प्रत्येक समस्या) खोली जावे, जिससे कच्चे माल के उत्पादन एवं गुणों में सुधार हो सके।

(५) विदेशी प्रतियोगिता—विदेशों में भारतीय माल की जापान, ब्रिटेन एवं अन्य देशों के मध्य तीव्र प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा है। भारत की वस्त्र मिश्र, सरकार की वस्त्र उद्योग सम्बंधी अनिश्चित नीति के कारण अपने निर्यात के वायदे पूरे नहीं कर सकी है इसके साथ ही भारतीय माल की किस्म एवं पैकिंग भी निर्यात गतों के अनुकूल नहीं हो सका और इन सब कारणों में हमारे हाथ में निर्यात बाजार निकलते जा रहे हैं एवं विदेशों में भारतीय उद्योग की प्रतियोगिता शक्ति दुबल हो गयी है।

सन् १९५८ की प्रथम एवं विनोद रूप में द्वितीय तिमाही में भारतीय वस्त्र निर्यात में तीव्रता में वमी अन्त के अन्त कारणों में से एक कारण भारतीय उद्योग का चीन जापान एवं अन्य देशों के उद्योगों में होने वाला प्रतियोगिता थी। भारत को विदेशों में अपनी प्रतियोगिता की स्थिति सुधारन की विशेष आवश्यकता है। बदलती हुई माँग को ध्यान में रखते एवं विदेशी बाजारों का गहन अध्ययन ही इस समस्या का उचित हल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार आज आहूक प्रधान बाजार है, वहाँ प्रत्येक की इच्छा का विनोद रूप में ध्यान रखा जाता है, इसका अन्तर्गत वस्त्र उद्योग में नवानतम



तरीकी से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाली प्रतियोगिता के कारण माल का मूल्य एवं उसके गुण ग्राहक को विशेष रूप में प्रभावित करते हैं । जापान की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में दृढ़ स्थिति का कारण उसके द्वारा माल के गुण एवं मूल्य में प्रतियोगिता करने की शक्ति है । अतः भारतीय उद्योग को विदेशी प्रतियोगिता में अपना स्थान सर्वोच्च बनाने के लिए यह आवश्यक है कि यहाँ भी इन तरीकों को अपनाया जाये । इस समस्या के समाधान हेतु हमें उत्पादन बढ़ाना चाहिये, उच्च कोटि का माल निर्माण करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, उत्पादन यन्त्रों में सुधार होना चाहिये एवं श्रमिकों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए हर सम्भव उपाय करना चाहिए । इसके साथ ही करो में कमी होना भी अनिवार्य आवश्यक है ।

**अन्य सुझाव—**

वस्त्र मिल उद्योग की समस्याओं को हल करने के लिए राष्ट्रीय योजना आयोग ने निम्न सुझाव दिये हैं—(i) मशीनों की उत्पादन शक्ति का पूरा उपयोग किया जाये । (ii) वे मिलें जो घाटे पर कार्य कर रही हैं, उनका विस्तार करके आर्थिक बनाया जाये । (iii) साढ़े तीन लाख नये लकड़ें लगाये जाएँ । (iv) केवल श्रेष्ठ माल का निर्यात करके विदेशी बाजार में अपना स्थान बनाने का प्रयत्न किया जाये एवं प्रति वर्ष १०० करोड़ गज कपड़ा निर्यात करने की अनुमति दी जाए । (v) जहाँ तक सम्भव हो, धागे का निर्यात नहीं किया जाये ।

मई सन् १९५८ में भारत सरकार द्वारा नियुक्त सूती-वस्त्र उद्योग जाच समिति का अनुसार उद्योग के सभी क्षेत्रों—मिला, विद्युत करघा एवं हस्त-करघा—का अभिनवीकरण किया जाये । यह कार्य १५ वर्षों में तीन खंडों में किया जाना चाहिए । मिल उद्योग के कताई विभाग का भी विस्तार किया जाना चाहिये तथा उसको विद्युत करघा एवं हस्त-करघा विभाग से मिला दना चाहिये । सिफारिश के अनुसार यह कार्य ६ वर्ष में पूरा किया जाना चाहिये तथा इस पर ५० करोड़ से अधिक धन राशि के व्यय की व्यवस्था की जानी चाहिये । समिति ने आवश्यक विदेशी विनिमय मुद्रा प्राप्त करने और मिल-उद्योग में रोजगारी बनाये रखने के लिए १०,००० लाख गज सूती वस्त्र निर्यात करने का भी सुझाव दिया है । समिति के अनुसार महीन और अधिक महीन वस्त्रों के निर्यात से भारत अधिक आय प्राप्त कर सकता है । हस्तकरघा उद्योग के लिए जो कपड़े की उत्पादन मात्रा निश्चित की गई है, सिफारिश के अनुसार सन् १९६० तक उसे कायम रखना चाहिए । हस्तकरघा उद्योग को मूलमूल एवं वायव्य जैसे कपड़ों के उत्पादन में रोका जाना चाहिये ।

**उत्पादकता अध्ययन—**

उद्योग की उन्नति में उत्पादकता अध्ययन का भी अत्यधिक महत्व है । इसलिए प्रबन्ध एवं श्रम दोनों वर्गों के हित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि वे अपनी अधिक

शक्ति इस प्रकार क अध्ययन में लगाएँ। निश्चयात्मक रूप से ऐसे अध्ययन प्रबन्ध, श्रम एवं सारे उद्योग के लिए ही लाभप्रद होंगे।

यन्त्र सामग्री की देख रेख—

यन्त्र सामग्री की उचित देख रेख की आवश्यकता में इन्कार नहीं किया जा सकता। इस पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिये था, अभी तक नहीं दिया गया। मिन के उत्पादन यन्त्र को सुधार एवं सुव्यवस्थित बनाये रखने के लिए यन्त्रों के हिस्सों की बदलाव उचित निरीक्षण एवं देखभाल बहुत जरूरी है। इस कार्य में नात्रिकों को मिन के प्रदर्शकों के साथ ज्यादा से ज्यादा मदद करना चाहिये।

लागत मूल्य में कमी एवं किस्म में सुधार—

यन्त्र उद्योग में लागत मूल्य में कमी एवं किस्म में सुधार लाने के लिए आवश्यक है कि मिन उद्योग के उत्पादन, प्राधुनिकीकरण एवं पुरातन यन्त्रों के स्थान पर नवीनतम यन्त्रों का प्रतिस्थापन किया जाये। इसमें गति लाने के लिए एक निश्चित कार्यक्रम की आवश्यकता है। उत्पादन कार्यों में दक्ष शक्तियों को मिन के प्रबन्धकों को इस बात की सलाह दी जानी चाहिये कि उद्योग में किस प्रकार से तीव्र प्राधुनिकीकरण एवं पुनः संस्थापन हो सकता है। इस प्रकार नात्रिकों को भी महत्वपूर्ण कार्य करना है क्योंकि वे प्रबन्ध एवं श्रम को मिलान वाली एक कड़ी हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगीकरण पर बल दिया गया है, इसलिए यह आवश्यक है कि नात्रिक प्रतिक्षण की उचित व्यवस्था हो।

निर्यात करना आवश्यक—

भारतीय वस्त्रों का निर्यात न सिर्फ वनमान स्तर पर, अपितु उसके बढ़ाये जान के लिए निरन्तर प्रयत्न अति आवश्यक है। मिन उद्योग में सामान्य आर्थिक स्थिरता एवं विदेशों में आपात की जाने वाली ६०-५० करोड़ रुपये की रकम, आवश्यक यन्त्र सामग्री एवं अन्य माल के आयात के भुगतान के लिए यह आवश्यक है।

निर्यात बढ़ाने के लिए हम जिन बाजारों में भारतीय वस्त्र की मांग है, वहाँ मांग कायम रखन एवं बढ़ान के लिये नौ प्रयत्न करने ही चाहिये, साथ ही साथ उन बाजारों में भी बपटा बेचन व प्रयत्न बहुत आवश्यक है, जहाँ पर हमारे यहाँ के कपड़े का विप्रेय खाम बड़ पैमाने पर नहीं होता। मध्य योरोप व पश्चिमी जर्मनी जैसे देशों में जहाँ हमारे वस्त्रों की अच्छी खामाद बिक्री हो सकती है, वगैरें कि वहाँ के बाजारों के प्रतिमादा के अनुसार हम माल निर्यात कर सकें। बिक्री बढ़ान के नये मार्ग निबालने के लिये धान के उत्पादन में विविधता लाना, समीपित मान तैयार करना एवं अधिक निर्यात करना जरूरी है। हम देश की औद्योगिक स्थिति एवं कुछ अन्य कारणों, जिनसे

देश में पर्याप्त रुई का उत्पादन होता है, ऐसी स्थिति में है कि अन्य देशों को उनकी आवश्यकता का कपड़ा निर्यात कर सकते हैं।

**उपसंहार—**

आज मिलों में कपड़े का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है। इस दिशा में १९५७-५८ की अपेक्षा काफी परिवर्तन हुआ है। इस समय ३ लाख बेली एवं बिना बेली हुई गांठों का स्टॉक मिलों में है। निर्यात की दशा में भी गत वर्ष का अपेक्षा काफी सुधार हुआ है।

अन्त में उपरोक्त समस्याओं का समाधान हो जाना के बाद एवं मुक्तियों को कायम रूप में परिणित किया जाना के बाद भारतीय वस्त्र उद्योग का भविष्य निश्चित रूप में और भी उज्ज्वल होगा। हम विदेशी प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने में पूर्ण-रूपण समर्थ होंगे एवं अधिक से अधिक स्वदेश एवं विदेश की भाग का पूरा कर सकेंगे और वह दिन दूर नहीं है, जब हम अपने अतीत के गौरव का फिर से प्राप्त कर लेंगे।

भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना की जो रूपरेखा ६ जुलाई, १९६० का प्रकाशित हुई है उसमें कपड़े के उत्पादन का लक्ष्य ८,४५,००,००,००० गज रखा गया है। निर्यात के लिये ८५,००,००,००० गज का लक्ष्य इसमें अलग है। दूसरी योजना के अन्त तक सूती कपड़ा का उत्पादन ५ अरब गज तक पहुँच जाने की सम्भावना है। यह आशा है कि तृतीय योजना का लक्ष्य पूर्ण होने पर प्रत्येक व्यक्ति का १७।१ गज कपड़ा प्रति वर्ष उपलब्ध होने लगेगा।

## STANDARD QUESTIONS

1. Trace the history of Indian Cotton Textile Industry since independence upto date.
2. What are the present problems of our Cotton Textile Industry? Give suggestions to solve them.

## भारतीय जूट-उद्योग

( Indian Jute Industry )

प्रारम्भिक—

जूट उद्योग भारत का गौरव है। समारंभ का धार्मिक इतिहास में भारत के जूट उद्योग का प्रथम एवं महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। देश में उत्पादित विभिन्न प्रकार के रेशों में जा औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ईई के बाद केवल जूट का स्थान प्राप्त है। यह उद्योग सुदूरस्थित मुमगठिन एवं केन्द्रीय उद्योग है। इस उद्योग में ८३४ करोड़ रुपये की पूंजी लगाने आई है एवं ३ लाख थम जीवियों को कार्य भिता हुआ है। संपूर्ण देश में ११३ जूट का मिल है। देश का जूट उद्योग वास्तव में निर्यात उद्योग है। भारत में निर्मित जूट के माल का लगभग ३० प्रतिशत विदेशों का निर्यात किया जाता है। अमरीका भारत के जूट निर्मित माल का सबसे बड़ा ग्राहक है। इसलिये यह उद्योग डालर प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है।

भारतीय जूट उद्योग की महत्वपूर्ण दो विषयवस्तु हैं—प्रथम यह उद्योग समन्वित उद्योगों में एक प्राण उद्योग है निम्न प्रबंध निदेश एवं प्रथम व्यवस्था सुनिश्चित है। दूसरे यह उद्योग एक स्थान पर व्यवसायिक रूप में केन्द्रीय है। केवल ११ मिला की छोड़कर जा उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में १०२ मिन अमुक भौगोलिक परिस्थितियां यान्त्रिक व साधन पर्याप्त रूप में एवं समाना गति के कारण पश्चिमी बंगाल में स्थित हुगना नगर व किनारा वनकत में २५ मील ऊपर एवं २५ मील नीचे का ओर लगभग २ मील चौड़ा एवं ६० मील लम्बा क्षेत्र में स्थित है।

विश्वी मुक्त का उपाजन करने का दृष्टि में जूट के द्वारा निर्मित वस्तुओं का सर्वोत्तम स्थान है। देश में निर्मित सम्पूर्ण जूट के मात्रा का ८० प्रतिशत निर्यात माल के कारण हम इसके द्वारा कुल विदेशी विनिमय के लगभग २० प्रतिशत का प्राप्ति

होती है। यद्यपि मान का अधिकांश उत्पादन देश में ही हो जाता है, किन्तु जो माल निर्यात किया जाता है उससे हमें प्रभूत्व विदेशी विनिमय प्राप्त होता है, जिससे हम विदेशों से आयात की हुई खाद्य एवं अन्य वस्तुओं के मुक्तान कर सकते हैं।

**उद्योग का अतीत एवं विकास—**

देश में जूट की खेती अत्यन्त प्राचीन काल से होती है। पूर्व में यह उद्योग यहाँ पर कुटीर-उद्योग के रूप में संगठित था, किन्तु योरोपीय देशों से जूट का व्यापार ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना के बाद प्रारम्भ हुआ। पाली से चलने वाले जहाजों के लिए रस्सी की आवश्यकता थी। इसके द्वारा ब्रिटीश, एवं बोरो का भी निर्माण होता था। सन् १७६५ से १८३० तक भारत ने भारी मात्रा में टाट के टुकड़ों का निर्यात किया, किन्तु १८३५ में डची धलित करण के आविष्कार से कच्चे जूट की माँग बढ़ गयी। अतः कुटीर-उद्योग नष्ट होने लगा। धर्म-धर्म: जूट के उद्योग को प्रोत्साहन मिला, १९वीं शताब्दी के पूर्व ही स्काटलैंड का जूट-उद्योग भारत में स्थापित हुआ। प्रारम्भ में उद्योग की धीमी गति ने उद्योग के असफल होने का भय था, किन्तु इसके निरन्तर विकास ने इसे भारत का प्रमुख उद्योग बना दिया। विगत १०० वर्षों में जूट उद्योग में यन्त्रों द्वारा निर्माणी किया प्रारम्भ हुई है।

हमारे देश में सबसे पहला जूट मिल थी रामपुर में १८५४ में स्थापित हुआ, परन्तु आर्थिक विषम परिस्थितियों के कारण कुछ समय बाद यह मिल बंद हो गई। इसके बाद सन् १८१६ में भारत में एक जूट मिल की और स्थापना हुई और सन् १८८२ तक मिलों की संख्या २२ पहुँच गई, जिनमें २०,००० श्रमजीवी कार्य करते थे। इन मिलों को आर्थिक लाभ एवं सफलता प्राप्त हुई, इन सभी मिलों के स्वामी अंग्रेज थे। मिल-उद्योग की उन्नति से डची के जूट मिलों को काफी हानि हुई। मिल उद्योग की उन्नति के कारण भारत ने अमरीका एवं आस्ट्रेलिया को बड़ी मात्रा में निर्यात प्रारम्भ किया, जिससे जूट-उद्योग को प्रोत्साहन मिला। उपरोक्त २२ जूट कारखानों में से १३ कलकत्ते के ही समीपवर्ती क्षेत्रों में ही थे। विदेशों की बढ़ती हुई माँग से जूट-उद्योग को प्रोत्साहन मिला। परस्पर मिलों में अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण भी पैदा नहीं हुआ और संगठन भी अशक्त रहा। पटसन का उत्पादन हमारे देश की माँग की अपेक्षा विदेशों की माँग पर अधिक निर्भर करता था, यन्त्रों से दबाया हुआ पटसन विदेशों को निर्यात किया जाने लगा। विदेशों में पटसन से निर्मित माल की माँग में वृद्धि होने से मिलों की संख्या में वृद्धि हुई। इसमें सगे श्रमजीवियों की संख्या लगभग दुगुनी हो गयी, बरघो एवं तकुओं की संख्या भी बढ़कर लगभग ढाई गुनी एवं तीन गुनी हो गयी। उत्पादन वृद्धि ने उत्पादन व्यय में बचो की, साथ ही लाभ की मात्रा में वृद्धि हुई। कच्चे माल की समीपता ने उद्योग के विकास में सहयोग दिया।

यद्यपि १८६६ स १९०० के मध्य पट दक्षिण म इस उद्योग का धनि उठाने पटा परन्तु २०वें शताब्दी के प्रारम्भ म कृषि की उत्तति न पाट के घड़े म गति प्रदान की । जूट उद्योग की समस्याया के हल एवं उनम समन्वय स्थापित करने के लिए सन् १८८४ म जूट निर्माण मण की स्थापना प्रतिस्पर्धा मान का स्वत के निम्ने नय बाजारो की खोज के उद्देश्य स का गई । सन् १९०२ म इस उद्योग का नाम जूट मिल सप्त रखा गया । सन् १९०५ ०६ म विस्वव्यापी म नी के कारण पुन उद्योग म निधिनता आ गई इसक साथ हा जमनी व अमरीका आदि देश म पटमन का स्थानापन्न वस्तुधा का प्राप्ताप्तन लिया जा रहा था किन्तु इसक कारण उद्योग को बिनाप धति नहा उठाना पया । सन् १९१३ १४ तक जूट मिला की संख्या बढ कर ६४ हा चुका था ।

**प्रथम महायुद्ध काल मे उद्योग की दशा—**

प्रथम महायुद्ध काल म जूट उद्योग म यत हा नाशप्रद स्थित म रहा । एक तो फौजा आवश्यकताआ के लिए जूट का मांग बढ गई दूसरे यत्र सामग्री का विन्गो ॥ आयात बढ हा गया जिसम नई मिला का स्थापना एवं उनम प्रतिस्पर्धा का डर नहा रहा नीमर विन्गो म भी जूट की मांग बढ गई । मिल मालिका म रुद्ध मगठन था इस लिए जूट का उपात्तन पूरा काम असमा म किया गया । कच्चे मान का निर्यात अवन्म रोक लिया एवं कारखाना अधिनियम भा होना कर दिया गया । सन १९१५ १८ की इस अवधि म मिल मालिका न खूब लाभ कमाया । जूट की स्वपन भी ५५ लाख गांठ प्रति वष हा गयी जबकि युद्ध के पूर्व ४४ लाख गांठें प्रति वष की स्वपन थी। इसी समय मजदूरी का दर एक पाट के मूँघ म भी विन्गो वृद्धि हुई ।

**मन्दी के समय उद्योग—**

युद्ध समाप्ति के पश्चात मन्दी का एक भाका आया । सरकारा मांग लुप्त हो गयी किन्तु मजदूरी एवं कच्चे मान के दाम बढ गये । युद्धकालीन लाभ ॥ उत्साहित होकर कुछ नई मिलो की स्थापना हुई एवं कुछ पुरानी मिला न अपन काम क्षत्र में वृद्धि का । इन प्रकार उत्पात्तन वृद्धि का हान लगी किन्तु स्वपत घटन म मन्दी बढना गई । धमन अच्छी होन से कच्चे जूट का पूर्ति बढ गई जिसम मूल्य म कमा हुइ । इधर कोयल का भा कमो अनुभव हुई । यन्तु जूट मिल सप्त के निणयानुसार काम के धन घटा दिया गय एवं किसी भी मिल का और अधिक विस्तार न करने का निश्चय किया गया । सन् १९३१ म काम करने के घटा की संख्या ४० प्रति सप्ताह कर ली गई एवं १५ प्रतिशत अतिरिक्त करष भा बढ कर लिये । यह निणय सन् १९३८ तक चलता रहा । यद्यपि इस नियन्त्रण म कुछ मिला न महयाग नही दिया फिर भी मगठन अच्छा होन के कारण स्थिति म धारे धीरे सवार हुआ ।

## द्वितीय महायुद्ध में उद्योग की दशा—

सन् १९३९ में द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ के साथ ही देश के जूट-उद्योग को बहुत प्रोत्साहन मिला। विदेशी माँग में वृद्धि होने से, बोरे और अन्य जूट निर्मित सामान के लिए सरकार की माँग में वृद्धि होने से, उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई, फलतः कार्य्य अवधि पर मे रोक-थाम हटाकर सभी मिलें अपनी पूरी क्षमता से ६० घण्टे प्रति सप्ताह कार्य्य करने लगी। १९४० तक तो उद्योग की स्थिति ठीक रही, इसके बाद माँग कम हो जाने से उद्योग में सङ्कट की स्थिति दृष्टिगोचर होने लगी, परिणामस्वरूप कार्य्यविधि ४५ घण्टे प्रति सप्ताह कर दी गई। उद्योग में समय-समय पर इस प्रकार से उतार-चढ़ाव होते रहे। सन् १९४२ में जूट मिल सघ द्वारा उद्योग के विवेकीकरण का मुझाव दिया गया, सन् १९४३ में तो कोयले की कमी के कारण कुछ मिलों को स्वयं ही अपना कार्य्य बन्द करना पड़ा। यहाँ तक कि जौनाई के अन्तिम सप्ताह में तो सभी मिलें कोयले व विद्युत-शक्ति की कमी, यातायात की कठिनाई एवं १९४३ के बंगाल के अकाल के कारण बन्द रही और इसके पश्चात् जूट-उद्योग में विवेकीकरण की नयी योजना लागू की गई, जो सन् १९४४ की जौलाई में १९४६ के मार्च तक लागू रही। इस प्रकार सन् १९४७ तक जूट-उद्योग की ऐसी ही स्थिति रही।

## देश के विभाजन का उद्योग पर प्रभाव —

सन् १९४७ में देश का भारत एवं पाकिस्तान के दो हिस्सों में विभाजन होने के बाद उद्योग की स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ा। विभाजन से पूर्व देश में विश्व का ६७ प्रतिशत जूट उत्पाद होता था, किन्तु विभाजन के परिणामस्वरूप जूट उत्पाद करने वाली ७५ प्रतिशत भूमि पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गई। भारत में प्रायः दात प्रतिशत जूट मिलें थी, किन्तु पाकिस्तान द्वारा पाट के निर्यात पर कर लगा देने के कारण, कच्चे माल के अभाव में देश की जूट मिलें कई माह तक बन्द रही। पाकिस्तान भारत को १९४८ के एक समझौते के अनुसार ५० लाख गांठे जूट की देता था, परन्तु यह समझौता १९४९ में टूट गया। सितम्बर १९४९ में भारतीय रुपये का अवमूल्यन हो गया, पाकिस्तान द्वारा ऐसा नहीं किया गया, फलतः पाकिस्तान से कच्चा माल प्राप्त करने के लिए ४४ प्रतिशत मूल्य अधिक देना पड़ा और १९४९-५१ के बीच तो भारत-पाक के मध्य व्यापार भी रुक गया, इस कारण देश की कुछ मिलें बन्द हो गईं एवं कुछ ही कार्य्यविधि में कमी करनी पड़ी। उधर पाकिस्तान जूट के निर्यात का चिटगांव बन्दरगाह को केन्द्र बनाना चाहता है एवं पाक सरकार ने ब्रिटिश विरोधियों को जूट-उद्योग के विरसित करने के लिए आमन्त्रित किया है एवं वहाँ नई जूट मिलें खोलने के आदेश भी दिये गये हैं। ऐसी दशा में देश में जूट-उद्योग के विकास एवं कच्चे माल की आत्मनिर्भरता के लिए विशेष रूप से प्रयत्न किये गए हैं। जूट-उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए सन् १९५२ में निर्यात शुल्क में कमी की जाना शुरू हुई, जो सन्

१९५६ में विनियुक्त उद्योग लगे हैं। इस प्रकार मन् १९४५ म १९५५ तक के ये १० वर्ष जूट-उद्योग के लिए बहुत नाजुक थे।

विमानन के पक्षस्वरूप जूट उद्योग पर आर्टिफिशियल बाजारों को दूर करने के लिए अब देश का ध्यान कारखानों की पूर्ति हेतु स्वयं आयातक मात्रा में कच्चा माल उत्पन्न करना होगा। यह हर्ष का विषय है कि बिहार, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश एवं द्राविडकोर प्राचीन आदि राज्यों में जूट की खेती का प्रोत्साहित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। अब एक पुष्क विभाग के द्वारा गाँव-गाँव जाकर जूट की खेती का प्रचार किया जाता है, उत्तम बीज बाँटता है एवं खेती सम्बन्धी सभी प्रकार की जानकारी देता है एवं नृपका का विज्ञान सम्बन्धी अनुविधानों से बचाने के लिए स्थान स्थान पर उत्पन्न माल के खरीदने का प्रबन्ध करता है। जूट-उद्योग में सम्बन्धित नवीन अनुसंधान किये जा रहे हैं। इस समय उत्तरप्रदेश में जूट उत्पादन क्षेत्र में कई सी मील दूर होने हुए भी जो प्रगति की है, वह सराहनीय है। यहाँ तीन बड़ी जूट की मिलें हैं। कच्चे माल की पर्याप्तता के लिए यहाँ चार क्षेत्र, लखीमपुर, भीतापुर, गोहा तथा गोरखपुर, "अधिक जूट उत्पादन" के हेतु बनाए हैं। राजकीय प्रयत्नों के परिणामस्वरूप अब उत्तरप्रदेश में जूट का उत्पादन ६,००० मन पाट से बढ़कर ६,००,००० मन पाट उत्पन्न होता है। यद्यपि यहाँ का पाट घटिया किस्म का "जगली पाट" है, किंतु अच्छे पाट के उत्पादन के लिए प्रयत्न जारी हैं। इसी प्रकार अन्य राज्यों में भी जूट उद्योग के विकास के लिए हर संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

**प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग की दशा—**

योजना आयोग के द्वारा जूट उद्योग के विकास के लिए भविष्य की कोई योजना नहीं बनायी गई है, अपितु वर्तमान स्थिति को ही दृढ़ एवं ठोस बनाने का निश्चय किया गया है। आयोग द्वारा कच्चे जूट के उत्पादन पर अधिक धन दिया गया है, क्योंकि हमारे अनुसार भारतीय जूट मिलों की उत्पादन क्षमता का अधिक है, किंतु आवश्यकता कच्चे जूट की है। घन सरकार द्वारा जूट उत्पादन के लिए खेती व फसल के तरीकों में सुधार, मिर्चाई की उचित व्यवस्था, उत्तम बीज व खाद के वितरण एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने विभिन्न राज्यों में सशुचित प्रयत्न किये जा रहे हैं। विमानन के समय पटमन का वार्षिक उत्पादन १.७ मिलियन गाँठों था, मन् १९५०-५१ में उत्पादन बढ़कर ३.३ मिलियन गाँठों हो गया, १९५५-५६ में ३ मिलियन गाँठों का उत्पादन था और मन् १९६०-६१ तक ५ मिलियन गाँठों उत्पादित करने का लक्ष्य है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में मन् १९५५-५६ के लिये १२ लाख टन जूट के उत्पादन का एवं १० लाख टन जूट निर्मित मान के उत्पादन का लक्ष्य था। १९५६ एवं १९५७ में क्रमशः १०.६३ हजार टन एवं १०.३० हजार टन जूट का उत्पादन



हुआ । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जूट के उत्पादन का लक्ष्य १९६०,६१ तक १२ लाख टन स्थिर किया गया है । सन् १९५८ तथा १९५९ में जूट का उत्पादन क्रमशः १०.६२ हजार टन एवं १०.५९ हजार टन हुआ ।

उद्योग की वर्तमान समस्याएँ एवं हल—

जूट उद्योग की वर्तमान समस्याओं के हल द्वारा ही उद्योग की उन्नति संभव है । भारतीय जूट मिल एसोसियेशन के प्रधान श्री के० डी० जालान के मतानुसार उद्योग की निम्न समस्याएँ हैं—बाढ़िया बिस्म के जूट की कमी, जूट के मूल्य में कमी एवं प्रतियोगिता आदि ।

(१) अच्छी बिस्म व सस्ती जूट का अभाव—देश के विभाजन से उद्योग के एवाधिकार की अवस्था छिन्न भिन्न हो गयी है, आज सबसे जटिल समस्या जूट के उत्पादन की है । पाकिस्तान में आने वाली जूट पर देश की मिलें निर्भर नहीं रह सकती हैं, क्योंकि न मानूम जब पाकिस्तान भारत को जूट देना बन्द करदे । आवश्यकता इन बातों की है कि देश में ही अच्छी बिस्म का, सस्ता जूट उत्पन्न किया जावे, इसी उद्योग में 'अधिक जूट उपजाओ आन्दोलन' प्रारंभ किया गया, फलतः १५.८ लाख एकड़ भूमि पर ४१.४ लाख गाँठें जूट १९५५,५६ में उत्पन्न हुआ, जबकि १९४६,४७ में केवल ५.४ लाख एकड़ भूमि पर १३.२ लाख गाँठों का उत्पादन हुआ था । प्रथम योजना का जूट उत्पादन का लक्ष्य ५३.९ लाख गाँठें यद्यपि पूरा नहीं हो सका, फिर भी हम अब पाकिस्तान पर अधिक निर्भर नहीं हैं । इस समय देश की अपनी आवश्यकता का केवल १० प्रतिशत कच्चा जूट पाकिस्तान से आयात करना पड़ता है । जूट के उत्पादन के लिए किये गये प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप १९५८,५९ में जूट की फसल देश में बहुत अच्छी रही, अतः कच्ची जूट तथा जूट निर्मित माल के भाव गिर गये । सरकार द्वारा जूट उत्पादक विभिन्न राज्यों की गति विधियों का एकीकरण करने के लिये एवं केन्द्रीय देख रेख संगठन स्थापित किया गया है । यह संगठन जूट-उत्पादन के कार्यक्रम को कार्य रूप देना है, प्रति एकड़ अधिक उपज करने एवं फसल की बिस्म आदि सुधारने का भी ध्यान रखता है । यह सङ्गठन जूट उद्योग से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण कार्यों को करता है । यदि इस वर्ष किसानों की कच्ची जूट का उचित मूल्य नहीं मिल पाया तो फिर जूट का उत्पादन देश में कम हो सकता है ।

यद्यपि पाट उत्पादन के नवीन क्षेत्रों में जलवायु सम्बन्धी (जैसे—मूला, वाड, आदि) कठिनाइयाँ भी एक प्रमुख समस्या हैं । फिर भी सरकार कृत्रिम वर्षा, वाड नियंत्रण, उन्नत बीज एवं खाद द्वारा जूट की फसल प्रति एकड़ वृद्धि के लिये प्रयत्न कर रही है ।

(२) जूट का स्थानापन्न वस्तु का भय—विज्ञान न आने के युग में बहुत प्रगति की है अनेक विरहित देशों में जूट की स्थानापन्न वस्तुओं का निरमाण किया है। अनेक-वधाताओं का मान देने के लिये उत्पादन का नई नए प्रणालियाँ का विकास हुआ है। जूट के स्थान पर अब एक ऐसा वस्तु का उत्पादन किया जाना लगा है जो कपड़े के समान है एवं जूट के बोरा का जगह उपयोग में आती है। अनेक देशों में जूट के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले नये रंग खाद्य निकाले गये हैं तथा नवीनतम उपकरणों में पूर्ण जूट मिल खाद्य जा रहा है। ऐसा स्थिति में यदि ये जूट का स्थानापन्न वस्तु जूट से मिला प्राप्त होने लगा तो इस उद्योग के नष्ट हो जाने का भय है। अतः आज इस बात का आवश्यकता है कि जूट निर्मित मानव का उत्पादन बढ़ाया जाय उसका गुण में सुधार किया जाय तथा विभिन्न एवं नवीन क्षेत्रों में उसके प्रयोग के लिये अनुसंधान किया जाय।

(३) प्रतिभोगिता—दुर्ग के विभाजन के परिणामस्वरूप जूट उद्योग करने वाला ७१ प्रतिशत भूमि पाकिस्तान का सौंप दी गई और वहाँ का सरकार इस उद्योग का हर प्रकार में प्रोत्साहित कर रही है नवान उपकरणों में सुसज्जित कारखानों का निर्माण किया जा रहा है एवं अन्य क्षेत्रों में त्रिनिटि कंपनियों द्वारा भी संशोधन हो जा रहा है। अतः निश्चित है कि वहाँ की मिल भारत का अपेक्षा अधिक कार्य में लगी तथा वहाँ जूट की भी अधिकता है। भारत को पाकिस्तान से कृत्रिम प्रतिभोगिता का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि हानि भी उठाना पड़े। इसलिए सरकार को अधिक मात्रा में जूट उद्योग करने के लिये आवश्यकता में आधुनिकतम उपकरणों के प्रयोग पर बल देना अच्छी से अच्छी विधि की जूट उत्पादन करने के प्रयत्न करना चाहिये।

(४) आधुनिकीकरण—जूट उद्योग में आधुनिकीकरण के प्रयत्न बहुत बड़े वर्षों में हो रहे हैं। सरकार ने उद्योग में आधुनिकीकरण का आवश्यकता का स्वीकार किया है। इन समय जूट उद्योग का सहायता प्रदान करने में सरकार का ४० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है एवं ८ हजार अधिकारी के बजट गारंटी की समस्या का सामना करना पड़ेगा फिर भी ऐसा सब सामानों का वन्दन का व्यवस्था का नहीं है। वे जो या तो उत्पादन के विनष्ट अवस्था है या जिसके प्रयोग में उत्पादन व्यर्थ अधिक आता है। उद्योग आधुनिकीकरण की १० प्रतिशत योजना पूरा कर चुका है। सरकार द्वारा उद्योग का राय औद्योगिक विकास निगम द्वारा सहायता प्रदान करने का भी व्यवस्था का है। जूट उद्योग के आधुनिकीकरण के लिये राय औद्योगिक विकास निगम द्वारा ३१ मार्च १९५६ तक ४५६ करोड़ ६० के ऋण लिये गया जिसमें जूट मिला में आधुनिकीकरण का कार्य पूरा करने में बहुत सहायता मिला है तथा बड़ी मात्रा में नए अधिकारी का यात्राणा भी बनायी

हे । आशा है कि दो या तीन वर्षों में उद्योग आधुनिकीकरण याजना का ७५ प्रतिशत पूरा कर लगेगा । यद्यपि उद्योग में सम्पूर्ण रूप से आधुनिकीकरण की आवश्यकता है किन्तु मिला के कताई बुनाई विभाग में नवीनतम उपकरण होना बहुत आवश्यक है क्योंकि इसमें उत्पादन लागत में कमी के साथ काम भी अच्छा होगा ।

(५) जलवायु सम्बन्धी कठिनाई—देश के विभाजन के बाद जूट का उत्पादन अधिक मात्रा में करना बहुत आवश्यक है । उद्योग में अच्छे मान में आत्म निर्भर होना है, इसके लिये किये गये प्रयत्न में जूट उत्पादन के जो नये क्षेत्र बनाये गये हैं वहाँ जलवायु सम्बन्धी (जैसे—मृदा, बाढ़, अनावृष्टि आदि) कठिनाइयाँ की एक प्रधान समस्या है । इनके हल के लिये कृत्रिम वर्षा बाढ़ नियंत्रण उत्तम बीज एवं खाद का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है जिससे प्रति एकड़ फसल अधिक बढ़ाई जा सके ।

(६) पाकिस्तान का असंतोषजनक व्यवहार—भारत एवं पाकिस्तान के बीच ठीक सम्बन्ध नहीं होने से जूट उद्योग की प्रगति में बाधक सिद्ध हुआ है । पाकिस्तान ने दोनों देशों के मध्य हुए सम्झौतों को कभी पूरा नहीं किया । ५ अगस्त १९५२ का नई दिल्ली में हुआ एक सम्झौता भी पूरा नहीं हुआ मरका जिसमें भारतीय व्यापारियों में निराशा छा गई । सम्झौते के अनुसार भारत का आयात थी कि २३ रु० प्रति मन का विवेचनात्मक लाइसेंस फील्ड (Discriminative License Fee) जोकि पाकिस्तान ने लगा रखा था, हटा दिया जायेगा परन्तु इसका विपरीत पाकिस्तान द्वारा सम्झौते का तोड़ा गया । यही नहीं पाकिस्तान अयत्नशाली निर्यात का जान बाला जूट का गाड़ी पर निर्यात कर ३ रु० प्रति मन प्राप्त करता था और भारत में भी चार रु० प्रति मन नियाम कर वसूल करता था । अब पाकिस्तान के इन असंतोषजनक व्यवहार से पाकिस्तानी जूट का निर्यात करने एवं उसके द्वारा बस्तुएँ तैयार करने में बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है ।

(७) मुद्रा सम्बन्धी कठिनाई—२१ सितम्बर १९४६ को भारत ने मधुन राउ अमेरिकन के डालर के सम्बन्ध में अपना ह्रास का अवमूल्यन किया । स्टैलिग क्षेत्र के सभी देशों ने अपना मुद्रा का अवमूल्यन किया परन्तु पाकिस्तान ने इन सबके विपरीत अपनी मुद्रा का अवमूल्यन नहीं करने का निश्चय किया । परिणामस्वरूप पाकिस्तान का १०० रु० के स्थान पर भारत द्वारा १४४ रु० दिये गये । इस प्रकार भारत द्वारा पाकिस्तानी माल निर्यात करने के लिये ४४ प्रतिशत मूल्य अधिक दिया गया । भारत अपने जूट के मूल्य में कमी नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि ऐसा करने से भारतीय निर्यात व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा । बिना होकर पाकिस्तानी जूट का निर्यात भारत की जूट मिन एमोमिनेशन द्वारा कम कर दिया गया । इसमें उद्योग को बड़ा हानि पानी पानी और आज भी हानि उठानी पड़ रही है ।

निम्नलिखित इस अवस्था का पूरा करने के लिये जूट निर्यात निगम द्वारा

कच्चाप जूट ममिति व सकेत पर अलमा व छिन्नक म रेगा त्रिकारन का बना म विकास किया है हम रेगा को जूट म मिलाते हैं । किन्तु हमसे कोई विशेष लाभ नहीं है । मकता क्याकि स्थानापन्न रेगा का मूल्य अधिक है ।

(८) विदेशी प्रतिस्पर्धा का भय— भारतीय ट उद्योग का एक बहुत बड़ा समस्या विदेशी माल विपणन जूट की स्थानापन्न वस्तुओं में प्रतिस्पर्धा की है । विदेश के विभिन्न देशों में जूट की स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन म काफी प्रगति हुई है एवं वे विभाजन के बाद तो इन देशों का और भी प्रसारण मिला है । भारतीय मिला का उत्पादन क्षमता भी कम हो गई है अतएव अल्पमूल्य भय देशों का जूट मिल उद्योग काफी उत्थिति कर रहा है । पाकिस्तान भी जूट निर्माण के लिये प्रयत्न कर रहा है एनी परिस्थितियों में भारत को सावधानी लेकर काम करना चाहिये ।

(९) पाट के मूल्य का प्रश्न—जूट के दामों में अत्यन्त स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य का अचला जा अधिक वृद्धि हुई है उसका एक कारण यह भी है कि पाकिस्तान में आयात किये गये पाट के मूल्य में वृद्धि हो गई है । मन् १९४७ में प्रतिम टिना में पाकिस्तान का सामान बाहर जान बल पाट पर वहाँ की सरकार द्वारा जूट पर लगा कर लगा दिया तथा पाकिस्तान में आयात की गई जूट में मौसम के कारण नमी अधिक होने से १९४४ लाख रु० की हानि हुई । दूसरे भय वागता में भी वृद्धि हो गई । भारतीय मजदूरों की काय करने की गति कम होने के कारण १ मजदूर का काय ४ मजदूर करने में । अतः इन सब कारणों का उद्योग पर प्रभाव पड़ा । अत्यन्त देश में अधुनिकीकरण का तीव्र गति का अर्थ है भारत में यह गति बहुत कम हो गई क्योंकि उपराल कारणों में उद्योग की श्रम पर बड़ा प्रभाव पड़ा था ।

अतः यदि हमने उद्योग के वाणिज्यीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिये उचित प्रयत्न नहीं किये तो सामान मूल्य में कमी नहीं आ सकती हमें लिय सरकार द्वारा जूट के माल पर नियामत कर की जरूरत भी कम करना आवश्यक है जो भारतीय मूल्य के अवमूल्यन के बाद बहुत कम हो रहे हैं । साथ ही सरकार नियामत की जाया पद्धति को समाप्त करे । ही वह श्रम बना रहे जो विदेशों में जूट उद्योग समझौते का प्रतिफल के लिये आवश्यक है ।

परन्तु जांच आयोग—

उपरोक्त समस्याएँ मुकामों के लिए सरकार द्वारा एक पत्रमन जांच आयोग नियुक्त किया किन्तु उद्योग के विकास के लिये अनेक सुझाव दिये । सरकार द्वारा आयोग की यह सिफारिश मानली गई कि अविश्व म पत्रमन का स्थापना की जायता है किन्तु म सुधार करने के लिये प्रयत्न किया जाना अधिक आवश्यक है ।

प्रत्येक सरकार ने नई मिला का स्थान की अन्त नई इन का भी

निश्चय किया है क्योंकि वतमान मिलो म हा पूरा काम नहीं है अतः हमारा लक्ष्य मात्र प्रथम यह होना चाहिये कि वतमान मिलो को पूरा काम मिले । आयोग का यह सिफारिश भी स्वीकार कर ला गई है कि पटसन के विद्युत के बारे म दम्बई के ईस्ट इंडियन कायन एसोसियेशन का तरह पटसन के लिये भी एक व्यापारिक संगठन कायम किया जाये ।

सरकार न जूट उद्योग का ध्यान भी आयोग के सुझावों की ओर आकर्षित किया है । हमरी अग्र बातों के साथ इन सुझावों म से कलकत्ता म पटसन के गोदामों का उचित उपयोग काम के घट बढ़ाकर सप्ताह म ४८ घं करके विविध प्रकार का साम बनाने तथा उद्योग के विकास एवं उन्नति के लिए अन्न ही साधनों पर निर्भर रहने के लिय विशेष रूप से जोर दिया गया है । अन्न ही साधनों पर निर्भर रहने के लिये उद्योग को कम साभान रहने की मनाह दी गई है ।

सुझाव—

अच्छे कारखानों में उत्पादन किया जाये—जूट उद्योग के युक्तियुक्त संगठन करने के उद्देश्य से यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जो कारखाने प्रक्षम हैं जिन में पुराने घिमे हुए यंत्र लगे हैं उनमें होने वाले उत्पादन को ऐसे कारखानों में किया जाये जो आधुनिकतम यंत्र सामग्री में सुसज्जित हों । इस ओर पिछले दो वर्षों में विशेष रूप से ध्यान दिया गया है । उपरोक्त विधि के अन्वय से न तो कुल उत्पादन म कोई कमी आई है और न ही श्रमिकों की संख्या का कम करना पड़ा है । इस प्रकार का परिवर्तन भारतीय जूट मिल एसोसियेशन द्वारा निर्धारित कार्य के समय सम्बंधा सम्भौता के अनुसार कार्य करके किया गया है । इस सम्भौता के अनुसार एक मिल के लिये निश्चित किय गये मासाहिक करघा घण्टा दूसरे मिल का दिये जा सकते हैं । यह सम्भौता जूट उत्पादन की विविधता मांग पर उत्पादन नियमन कर देता है । उत्पादन का एकाकरण करने एवं अत्यधिक उत्पादन को रोकने म भी यह सम्भौता विविध रूप से सहायक सिद्ध हुआ है ।

उद्योग म आधुनिकतम यंत्र सामग्री स पूरा कारखानों म उत्पादन करना कितना महत्वपूर्ण है यह इस बात में प्रकट है कि इसमें उत्पादन लागत म कमी आजायेगा एवं अन्न देणों से प्रतिस्पर्धा करने म उद्योग समर्थ हो जायेगा ।

उत्पादनों की विविधता—विश्व के कुछ देशों में जूट उद्योग का अन्न विकास अन्न के कारण य अन्न का य अन्न देण की उत्पाति म ही अन्न लने है । अतः इन देशों म अन्न का जूट निर्यात होना अन्न सा होगया है । इसके साथ ही जूट की निम्न वस्तुओं के स्थान पर अन्न चीजों से निमित्त वस्तुओं का प्रयोग होने लगा है । यद्यपि विश्व म अन्न का पदावार बढ़ी है फिर भी उस अनुपात म जूट निमित्त अन्न की मांग नहीं बढ़ी । इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए आज जूट उत्पादन

तृतीय पञ्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत ६५ लाख गॉठ कच्चा पटसन पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है । इसमें हम जूट उद्योग के लिये कच्चे माल की उपलब्धि व बाजार में बहुत वृद्धि निश्चित हो जायेगी ।

इस प्रकार जूट-उद्योग को पूर्णरूपेण प्रोत्साहन दिया जा रहा है और वह दिन दूर नहीं जब भारत को विश्व में जूट-उत्पादन का एकाधिकार पुनः प्राप्त होगा ।

### STANDARD QUESTION

1. Discuss briefly the effects of partition on India's Jute Mill Industry. How have they been tackled ? What are your suggestions in this connection

---

# भारतीय लोह एवं इस्पात उद्योग

(Indian Iron And Steel Industry)

प्रारम्भिक—

आज के युग में विसा देग का औद्योगिक उन्नति का बसीटा यह है कि कहा कितना इस्पात बनता है और उपयोग में आता है। बिना क आधारभूत उद्योगों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लोहा एवं इस्पात उद्योग है। वर्तमान युग यंत्रोत्तरण का युग है क्योंकि चाहे कोई भी उद्योग हो सभी में यंत्रों के प्रयोग द्वारा उत्पादन एवं विकास किया जाता है और यंत्रोत्तरण लोहा एवं इस्पात उद्योग पर ही निर्भर है। विसा देग की अधिक प्रगति विकास एवं राजनैतिक सुरक्षा के लिये भी इस उद्योग द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। लोह का महिमा व महत्व में ऐसा कच्चे है कि — लोहा महान की शक्ति के लिये आवश्यक है क्योंकि महान की शक्ति का लोहा और ताँबा एक साधारण कारीगर के लिये किन्तु लोहा इन सभी धातुओं का स्वामी है।

इस उद्योग में अमेरीका का प्रथम स्थान है जहाँ १० करोड़ टन में भी अधिक इस्पात बनता है। रूस में ५ करोड़ टन एवं ब्रिटेन तथा जर्मनी में २ करोड़ टन प्रति वर्ष इस्पात का उत्पादन होता है। यह उद्योग भारत में बहुत तात्पर्य गति में विकास कर रहा है। उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल तथा उपकरण मात्रा में है। योगोपीय देशों में स्वतन्त्र का छोड़कर अन्य बाजारों में लोहा तथा भारत के समान उच्च कोटा का लोहा एवं कोयला मिलता ही। हमारे देश में लोह के अनेक साधारण नष्ट हैं कवल सिंधु भूमि मात्र में ही १ हजार करोड़ टन से भी अधिक लोहा है जिसका प्रयोग यदि वर्तमान गति में हो तो भी वह २००० वर्ष तक चल सकता है। भारत में द्वितीय योजना के अन्तर्गत ६० लाख टन प्रति वर्ष उत्पादन तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

उद्योग का अतीत एवं विकास—

लोह एवं इस्पात उद्योग भारत का अति प्राचीन उद्योग है। आज में ५७

हजार वर्ष पूर्व भा भारतीय लाह का उपयोग जानते थे । भारतीय इस्पात का मूल विज्ञान भा जाता था एवं अपना सुदरता के लिये लोकप्रिय था । जि ला का लोह स्तम्भ हमारे देश के प्राचीन इंजीनियरों की कला का जाता जागता उदाहरण है । इस उद्योग की प्राचीनता पर प्रकाश डालते हुए प्राफ़सर विल्सन ने लिखा है कि— 'लाह का ढलाई तो इंग्लैंड में थोड़ा ही वर्षों से प्रारम्भ की गई है परन्तु हिंदू लोग लाहा गलाने, ढालने तथा इस्पात बनाने की कला का ज्ञान अत्यंत प्राचीन काल से रखते हैं ।

आधुनिक समय में इस उद्योग का इतिहास बिगन १५० वर्षों का है । इसके पूर्व कुछ योरोपियों ने इस उद्योग को खनाने का प्रयत्न किया पर वह सफल न हो सका । इन प्रयत्नों में सन् १७७७ में फ्रान्सीसी कोयले की खान के निष्पट एक लोहे एवं इस्पात का कारखाना खोला गया जो दो वर्ष के बाद बंद हो गया । इसका नाम सन् १८७७ में बारकपुर आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की गई ६ वर्षों तक यह कारखाना कार्य करता रहा फिर इस ईस्ट इण्डिया कंपनी ने खरीद लिया । दो वर्ष के बाद इस कारखाने का नाम बदलकर दी बगान आयरन एंड स्टील कंपनी रखा गया एवं कारखाने का आधुनिकीकरण भी किया गया । यह कारखाना इस्पात उत्पादन में तो असमर्थ रहा किन्तु इसमें आधुनिक पद्धति से पिग आयरन का उत्पादन किया जाने लगा ।

आधुनिक काल में लोह एवं इस्पात उद्योग की नींव डालने का श्रेय था अमेरिका जी नीमरवान जा टाटा को है जिन्होंने सन् १८०४ में जर्मनी एवं अमेरिकन विनेपेसो द्वारा देश के मध्य प्रांत की जांच करवाई । सरकारी विभाग से स्वीकृति लेकर विदेशों में भ्रमण करके एवं अन्य अनकानूक कठिनाइयों को पार करके पश्चात् कारखाना प्रारम्भ करने का निश्चय किया गया किन्तु यह कारखाना जिस स्थान पर स्थापित करना था वह कोयले एवं लोह की खानों में समान दूरी पर था अतः अस्वीकार कर दिया गया । तत्पश्चात् श्री पी० एन० बसु की महायत्ना में निरीक्षण आदि करा कर मुरभञ्ज (उड़ीसा) में सन् १८११ में जिस स्थान पर कारखाने का प्रारम्भ किया गया वही स्थान आज जमशेदपुर के नाम से प्रसिद्ध है । इस कारखाने का नाम दा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (Tisco) रखा गया इस कारखाने में कार्य प्रारम्भ होने के बाद सन् १८१२ में इस्पात तैयार होने लगा । टिस्को (Tisco) आज भारत का नही बल्कि एशिया का गौरव है

**प्रथम सहायक के उद्योग की स्थिति—**

सन् १८१४ में योरोपीय महायुद्ध का प्रारम्भ हो इस्पात उद्योग के लिए स्वर्ण अवसर लाने वाला सिद्ध हुआ । इस समय देश का माँग में वृद्धि हुई एवं विज्ञान से लोह इस्पात का आयात कम हो गया । इस समय टाटा द्वारा अत्यधिक लाभ कमाये



पूर्ति मन्त्रालय द्वारा बताया गया कि वार्षिक उत्पादन २५ लाख टन होना चाहिए, मूल्य पर नियन्त्रण रखा जाना चाहिये एवं उद्योग का आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहिये। सरकार ने उद्योग को निम्न रूप में उत्पादन बढ़ाने के लिए सहायता दी— टाटा का १० करोड़ रु०, बंगाल स्टील कार्पोरेशन का ३ करोड़ व इण्डियन आयर्न एण्ड स्टील कम्पनी को १ करोड़ रु० ऋण के रूप में दिया गया।

पुनर्निर्माण के उद्योग का उत्पादन गिर गया एवं निर्यात कम हो गया। इसके अनेक कारण हैं, जैसे—कोयला प्राप्त करने में कठिनाई, मजदूरी बढ़वाने के लिए श्रमिका द्वारा हड़ताएँ आदि और यानायाग की अमृदिधा, इत्यादि। इनमें इनमें विदेशी विनिर्माता का हानि उठानी पड़ी। इन व अनेक प्राप्तीय कोटें कम कर दी गईं, व विकास की योजनाएँ स्वर्ग में चढ़ गईं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में उद्योग—

इन के विभाजन के बाद हमारा देश में बनो राष्ट्रीय सरकार ने लाल "बम" उत्पादन उद्योग की उत्पत्ति एवं विकास का भार अपने ऊपर ले लिया। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार ने उद्योग को विशेष सहायता देने का मन किया। योजनानुसार सरकार ने सन् १९४६ तक सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) में ३० करोड़ रु० खर्च करने एवं निजी उद्योगपतियों को उनकी विकास योजनाएँ वार्षिक रूप में ४५ करोड़ रु० देने का निश्चय किया। सरकार का उद्योग की उत्पत्ति निम्न रूप में बढ़ने की आशा थी—

सन् १९५०-५१ में उत्पत्ति

सन् १९५५-५६ में उत्पत्ति

गला हुआ लोहा— १७.८ लाख टन

१६.५ लाख टन

तैयार स्थान— १०.७५ ,, ,

१२.८ ,, ,

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सरकार द्वारा, ५ लाख टन उत्पादन पिछे तैयार करने की क्षमता वाला एक कारखाना स्थापित करने का कार्यक्रम रखा गया था, किन्तु उस समय विदेशी सहयोग प्राप्त करना कठिन था। अतः सन् १९५३ में डा. जर्मनी की जर्मन व रेमर कर्मों के सम्मिलित सहयोग में एक कारखाने के निर्माण का समझौता किया गया। यह कारखाना 'हिन्दुस्तान स्टील लि०' के नाम से प्रारम्भ हुआ तथा इस पर १० करोड़ रु० व्यय किया गया। सरकार द्वारा, देश में लाल एवं उत्पादन का उत्पादन बढ़ाने के लिए २ जनवरी सन् १९५३ का स्टील कार्पोरेशन ऑफ बंगाल तथा इण्डियन आयर्न एण्ड स्टील कम्पनी का एकीकरण (IISCO and SCOB Marger) किया गया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग—

भारत की विकास योजनाओं के साथ ही साथ देश में लाल एवं उत्पादन की गति में भी वृद्धि हुई, अतः भारत सरकार ने उद्योग के महत्व को समझकर इस द्वितीय

पंच वर्षीय योजना में महत्वपूर्ण स्थान दिया। उस उद्योग पर ४३१ करोड़ रुपया व्यय करने का निश्चय किया गया। इस योजना के अंतर्गत उद्योगों का उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तथा नये कारखाने खुलने का भी निश्चय किया गया। इस योजना के अंतर्गत स्वयं सरकार ने तीन नये कारखाने खोले हैं—प्रथम स्क्वेला (उड़ीसा) द्वितीय भित्तार (मध्य प्रदेश) तृतीय दुर्गापुर (पश्चिमी बंगाल) भित्तार का कारखाना हम सरकार का महायन्त्रों में स्थापित किया गया है। स्क्वेला इस्पात कारखाने का प्रथम धमन भट्टा का कार्य ३ फरवरी १९५८ का तृतीय भित्तार स्क्वेला कारखाने का धमन भट्टा का कार्य दिनांक ४ फरवरी १९५८ का प्रारम्भ हुआ गया। दुर्गापुर इस्पात कारखाने को धातु कम मजदूरी बढ़िया किस्म की कालिका उपलब्ध कराने के लिए पश्चिमी बंगाल द्वारा स्थापित कालिका भट्टा मयूरी का माच १९५६ में उद्घाटन हुआ।

## योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा स्थापित नवीन कारखाने

### (१) स्क्वेला (उड़ीसा)—

कलकत्ता में ५७ मीटर दूर गंगे और कावेरी नदियों के संगम पर स्थित स्क्वेला जहाँ ग कलकत्ता बम्बई रेल लाइन जाता है एक छाया सा गाँव है। यहाँ पर सरकार द्वारा इस्पात का कारखाना बनाया जा रहा है जिसमें १० लाख टन इस्पात बनाया जायगा किन्तु इसके यंत्रों में बाँटने वाला विस्तार करके इसका उत्पादन १५ लाख टन तक किया जा सकेगा। योजनानुसार इसका उत्पादन क्षमता २० लाख टन रखा गई है।

३ फरवरी १९५८ का स्क्वेला इस्पात कारखाने का प्रथम धमन भट्टा का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति डा० राजेंद्रप्रसाद ने कहा था कि स्क्वेला भित्तार एवम् अन्य योजनाएँ हमारा महत्वाकांक्षी का प्रतीक हैं। हमने हितकारि राज्य का स्थापना का संकल्प किया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ है और उस पर्याप्त भाजन तथा कपड़ा मिले। ये भारी उद्योग उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रथम प्रयास हैं। मुझे आशा है कि इस कारखाने में हम अपने हितकारि राज्य का स्थान प्राप्त करने में सफल होंगे।

राष्ट्रपति ने आगे कहा कि इस क्षेत्र में तनिका काया मात्रा में है। स्क्वेला और अन्य छान कारखानों में इसका उपयोग होगा। राष्ट्रपति ने आगे प्रश्न का कि कलकत्ता में यह जमीनी के प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र का सुधारना करने लगता है। स्क्वेला कारखाने एवं द्वारा कलकत्ता में इस क्षेत्र के लोगों का जीवन होगा। यहाँ पर कलकत्ता में का आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी।

रूरकेला कारखाने के समीप ही पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध है। तमिज़ लोहा प्राप्त करने के लिये यहाँ में ४५ मील दूर वरमुघ्रा में नई खान खोदी जा रही है। इस कारखाने के लिये कोयला बिहार की करगर्सा, वोकारो एवं भरिया की खानों से प्राप्त किया जायेगा। करगर्सी में कोयला घोंने का कारखाना भी स्थापित किया जायेगा। इसके अनावा कारखाने के लिये चूने के पत्थर की व्यवस्था हाथीबाड़ी और वीरमिनपुर में किया जा रहा है, जो कारखाने में १५ मील दूर है।

वर्तमान में इस्पात दो तरीकों से बनाया जाता है, प्रथम खुली भट्टियों द्वारा, यह तरीका बहुत प्राचीन है एवं दूसरा एल० डी० प्रणाली द्वारा, यह तरीका बिल्कुल नया है। इन तरीके के द्वारा कम खर्च होता है, स्थान कम घिरता है, समय आदि कम लगने हैं और उत्पादन भी अधिक होता है। साथ ही उत्पादकों से उर्वरक और अन्य रासायनिक पदार्थ तैयार किये जा सकते हैं, किन्तु इस प्रणाली के द्वारा उत्तम किरम का ज्वलन, टेन्साइल और विद्युत प्रकार का इस्पात शायद न बनाया जा सके, इसलिये खुली भट्टियों द्वारा भी इस्पात बनाना अति आवश्यक है। रूरकेला कारखाने में पहले तरीके में २,५०,००० हजार टन इस्पात बनाया जायेगा तथा दूसरे एल० डी० तरीके में ७,५०,००० हजार टन इस्पात बनाया जायेगा। इस कारखाने में कुल उत्पादन ७,२०,००० टन प्रतिवर्ष होगा तथा इस कारखाने पर १७० करोड़ रु० के लगभग व्यय किये जायेंगे।

## (२) भिलाई (मध्य प्रदेश)—

दिनांक ४ फरवरी १९५६ को राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने भिलाई कारखाने की धमन भट्टा का उद्घाटन करत हुए कहा कि—“कारखाने का यह प्रारम्भ देश की आर्थिक स्थिति को बदलने तथा अपने अग्रगण्य प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके लोगों के रहन सहन के स्तर को ऊँचा उठाने की हमारी आशाओं का प्रतीक है। मैं समझता हूँ कि वह दिन दूर नहीं, जब देश के लोगों के ये प्रयत्न फलदायी होंगे। उन्होंने कहा कि यह विशाल कारखाना उज्ज्वल भविष्य के प्रति देश के विश्वास और आशाओं का प्रतीक है। भारी उद्योग खड़े करने के हमारे कार्यक्रम में इन इस्पात कारखानों का महत्वपूर्ण स्थान है। कल मैंने रूरकेला का उद्घाटन किया और आज इस भिलाई कारखाने का उद्घाटन कर रहा हूँ। ये दोनों दिन भारत के औद्योगीकरण के इतिहास में अविस्मरणीय रहेंगे।

नागपुर से १५६ मील दूर बम्बई कलकत्ता की मुख्य रेलवे लाइन पर स्थित है भिलाई। अभी लगभग १७ माह पूर्व ही इसका कार्य प्रारम्भ किया गया था और इस छोटीसी अवधि में भिलाई कारखाने की योजना ने काफी तरफ़ी की है। भिलाई कारखाने में ७,७०,००० टन इस्पात की मिलें तैयार की जायेंगी, जिनसे रेल की पटरियाँ और स्लीपरें, इमारतों में काम आने वाला सामान तथा चहरे आदि बनाई

जायगा। योजनाद्वारा कारखाने का विस्तार कर इसका उत्पादन क्षमता का २५ लाख टन इस्पात की मिनो तक बढ़ा जा सकता है।

नये कारखाने के लिये रखरखाव का खाना से खनिज माट्टा मंगाया जायगा यह मिनो में ६० मील पर है। कायना विचार का करणना चुकारा एवं भरिया तथा मय प्रणय का कोखा का खाना में जायगा। जून का पंचर भिनाई में १२ माल दूर लाना का खानो में लिया जायगा।

मिनो इस्पात कारखाना कम के सहयोग से खोला जा रहा है। कम के द्वारा इस कारखाने का आर्थिक तथा निम्निक सहायता दी जा रही है। वह इसमें लिये ६० करोड़ १० लाख ८० के मूल्य का मुख्य मशीन तथा अन्य यंत्रादि ढाढ़ प्रतिगत मूल्य के निमाय में दे चका है। इसका अनुमान १२ मासाना किम्तो में किया जायगा। कुछ घन कम में लगे भा खराब गये हैं। समझीन के अनुसार कम तथा भारत पर काम का बन्वारा इस प्रकार है।

रस—

(१) यानना का विम्नून रिपाय तयार करना तथा बनाना घोर कारखाना गड करन का कार्यक्रम तयार करना।

(२) मुख्य मशीन तथा अन्य सामान आदि देना।

(३) मशीन लगान तथा चालू करन में निम्निक सहायता देना।

(४) कम में भारतया के प्रतिगत का व्यवस्था करना तथा भारत में भी इजानियर तथा कारीगरों का प्रतिगत देने का व्यवस्था करना।

भारत—

(१) कारखाने के लिये उबड़ लावड़ जमान का चीरत बनाना।

(२) कारखाने के लिये उपयुक्त स्थान का प्रारम्भिक जांच करना।

(३) लकी विपणनी की दख रस में यंत्र आदि लगाना।

(४) कम में आने वाले सामान का बन्वाराह में निश्चिन स्थान तय स्थान की व्यवस्था एवं भारत में मिनन बाय सामान की पूर्ति (Supply) की व्यवस्था करना।

(५) कारखाने के थमिका के लिये बन्धिया तथा सड़कें एवं रस की पन्री विधान की व्यवस्था।

(६) कारखाने तक बिजला और पाना पहुँचाने की व्यवस्था और

(७) कच्चे माल की पूर्ति।

म कारखाने का निमाण कार्य एवं भारतया मुख्य इजानियर के हाथ में है। कम कारखाने पर लगभग १२० करोड़ ८० लख टाका एवं इसका आर्थिक उत्पादन

७ ७० ००० लाख टन हागा । गिल्वाई इस्पात कारखाने में १२ अप्रैल १९५६ में इस्पात का उत्पादन प्रारम्भ हुआ यहाँ ११ अप्रैल १९६० तक १ लाख टन इस्पात तैयार हो चुका है ।

### (२) दुर्गापुर (पश्चिमी बंगाल)—

दुर्गापुर का इस्पात कारखाना का निर्माण अथवा दानो कारखाना का काम प्रारम्भ हुआ फिर भी काम विधिवत एवं अत्यंत शीघ्रता से चल रहा है । इस कारखाने का निर्माण में कुछ ब्रिटिश फर्मों भी सहयोग दे रहा है । दुर्गापुर कारखाने का लागत का लिये ब्रिटेन के बका का एक मिडोकेन ११५ लाख पौंड और ब्रिटिश सरकार १५० लाख पौंड दे रहा है ।

दुर्गापुर कारखाने के लिये बारक तथा भरिया का खानों का कामला उपयोग में लाया जायेगा । चून का पथर बोरमिचपुर तथा हाथीबाड़ा क्षेत्र में मगाया जायेगा । दुर्गापुर में दामाचर घाटा निगम १ लाख ५० हजार किलावाट क्षमता का एक ताप बिजली घर बना रहा है । इसके अलावा कारखाने का अपना १२ हजार किलावाट की क्षमता का ताप बिजली घर काम करेगा ।

दुर्गापुर का इस इस्पात कारखाने पर १३८ करोड़ रु० का लगभग व्यय करने का अनुमान है । इस कारखाने का वार्षिक उत्पादन ६ ६० ००० टन हागा ।

भारत के केंद्राध्यक्ष इत्यादि एवं ईंधन में भी सरकार स्वयंसेवक न लाकसभा में वक्तव्य देते हुए कहा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ६० लाख टन इस्पात पिंड बनाने का लक्ष्य है । इन इस्पात पिंडों में से ४५ लाख टन का टयार सामान बनाया जायेगा । दूसरा योजना के अंतर्गत जमशेदपुर धमपुर भद्रावती कारखाना का बहाने की व्यवस्था का गई है । जमशेदपुर में २० लाख टन बलपुर में १० लाख टन और भद्रावती में १ लाख टन इस्पात बनाने का लक्ष्य रखा गया है ।

इस प्रकार सरकार एवं निजी दानो क्षेत्रों का सम्मिलित उत्पादन ६० लाख टन हागा जिसमें से इस्पात का ४५ लाख टन तैयार मान बनाने और बिक्री के लिये ७ लाख ५० हजार टन दानो लाहा बनाने का लक्ष्य पूरा हो जायेगा ।

### उद्योग की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य—

देश में लौह एवं इस्पात के लगभग १३६ कारखाने बिहार बंगाल मद्रास उडुगुम मध्य प्रदेश आदि राज्यों में केंद्रित हैं । इस उद्योग में लगभग ८६ हजार श्रमजीवी कार्य करते हैं । इस समय निजी क्षेत्र में हमारे देश में टिस्को इस्को तथा स्टाव की संयुक्त संस्था एवं समूह आयरन वनम भद्रावती—तीनों प्रमुख कारखाने लोहे एवं इस्पात का उत्पादन कर रहे हैं । इन सब का उत्पादन क्षति १८ ७८ ००० टन बाधा हुआ बाधा व १० ५०० टन इस्पात है । इन उत्पादकों

का प्रजी ६४ करोड़ रुपये है। मनु १९५६ तक हमारी माँग २५ लाख टन तक पन्ध्र चका है किन्तु हम समय तक देश में इस्पात का उत्पादन बहुत कम है।

दूसरा योजना के अन्तर्गत लोहा इस्पात के कारखानों का उत्पादन ८ लाख टन में बढ़कर प्रतिवर्ष १५ लाख टन हो जायगा और इस पर ८४६ करोड़ रु० व्यय होगा। इसी प्रकार इंडियन स्टील कोर्पोरेशन लिमिटेड का उत्पादन क्षमता भी ३ लाख टन में बढ़ कर ८ लाख टन हो जायगा और इस पर ४२५ करोड़ रु० व्यय होगा। सरकारी मिलाई तथा दुगापुर के नवहन स्थापित कारखानों में १९६०-६१ तक २० लाख टन लौह इस्पात तथा ४५ लाख टन कच्चा लोहा उत्पन्न होने लगगा।

## देश में लौह एवं इस्पात का उत्पादन

वर्तमान उत्पादन १९६०,६१ का अनुमान

### १—वर्तमान कारखानों की क्षमता में

(रुको ल.)

(टनों में)

लौहा स्टील कोर्पोरेशन लिमिटेड का वर्तमान  
इंडियन स्टील कोर्पोरेशन लिमिटेड का वर्तमान  
समूह स्टील कोर्पोरेशन लिमिटेड का वर्तमान

७ लाख ८० हजार  
५ लाख २० हजार  
३० हजार

१५ लाख  
८ लाख  
१ लाख

### २—सरकारी क्षेत्र के नये कारखानों में—

सूर्यपुर  
मिलाई  
दुगापुर

—  
—  
—

७ लाख २० हजार  
७ लाख ७० हजार  
८ लाख

कुल उत्पादन

११ लाख ४० हजार ४६ लाख ६० हजार

### उद्योग की समस्याएँ—

भारतीय लौह एवं इस्पात उद्योग का निम्नलिखित मुख्य समस्याएँ हैं—

(१) बिजली—इस उद्योग का नदों से प्राप्त जल तथा पुराने भूतलों से पीक करने के लिए बहुत धन की आवश्यकता है। इस काम के लिए ३१५ करोड़ टन तक का एक प्रयोग किया जा सकता है।

(२) श्रम—उद्योग के समुदाय दूसरा मुख्य समस्या श्रम का है। श्रमिकों कायदा करना चाहिए, परन्तु वे ऊँचा मजदूरी लेकर काम करने का लोहा है। श्रम का काम करना भी भाई नहीं मिलता है।

(३) सरकारी नीति—सरकार का श्रम उद्योग के प्रति काम करना चाहिए नीति नहीं है। सरकार निजता प्रणाली का अधिक प्रयोग करना चाहती, वह उसकी श्रमिकों का शक्ति में दखल है। इस कारण से उद्योग के अभाव में उद्योग में उद्योग में उद्योग में।

(४) थ्रोष्ठ कोयले का अभाव—उद्योग के लिये आवश्यक थ्रोष्ठ कोयले का अभाव है। भारत में थ्रोष्ठ कोयला (कोकिन) बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। साथ ही यहाँ पर अच्छे कोयले का प्रयोग रेलगाड़ियों को चलाने में भी किया जाता है।

(५) कर्मचारियों का प्रशिक्षण—नव निर्मित इस्पात के प्रत्येक कारखाने के लिये ६७० इन्जीनियर तथा अन्य उच्च निरीक्षक एवं कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, इसके साथ ही ६३०० कारीगर एवं शिक्षित मजदूर भी चाहिये। भारत में योग्य कारीगरों, इन्जीनियरों, श्रमिकों, कर्मचारियों का अभाव है, क्योंकि इस उद्योग का विकास हुए यहाँ अधिक समय नहीं हुआ है। अतः उद्योग के लिये कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की भी महत्वपूर्ण समस्या है।

इस समस्या के हल के लिये निजी क्षेत्र में प्रयत्न जारी है। सरकार की ओर से २४१ इन्जीनियर क्लस में प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजे गये हैं, कुल ६८३ इन्जीनियरों को प्रशिक्षण देना है। कुरुकेला एवं दुर्गापुर कारखानों के लिये फोर्ड फाउण्डेशन की सहायता से अमरिका में बहुत से इन्जीनियरों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। कोलम्बो योजना के अन्तर्गत ब्रिटेन में भी ३०० इन्जीनियरों को दुर्गापुर कारखाने के लिये प्रशिक्षण दिया जायेगा।

जमशेदपुर में भी प्रशिक्षण का एक विशाल केन्द्र चल रहा है, जिसमें विदेशों को जोने के पूर्व इन्जीनियरों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस प्रकार सरकार इस समस्या की ओर पूरा ध्यान दे रही है।

(६) उत्पादन की लागत—इन कारखानों में निर्माण पर जो अधिक खर्च पड़ रहा है, उससे तैयार इस्पात की लागत भी अधिक पड़ेगी। इन कारखानों में पूँजी अधिक लगने के कारण उत्पादन लागत अधिक पड़ेगी। किन्तु इस समस्या को संचालन लागत कम करके हल किया जा सकता है। नये कारखानों में नये यन्त्रों को खाने से कम मनुष्यों की आवश्यकता होगी। इनका अच्छा संगठन होने की आशा है, फलतः पूँजीगत लागत अधिक होने पर भी उत्पादन लागत के बराबर ही पड़ेगी।

(७) विवेकीकरण एवं आधुनिकीकरण—उत्पादन की लागत की समस्या को सुलझाने के लिये उद्योग का निस्तार एवं नवीनीकरण किया जाना चाहिये। उत्पादन ध्ययों में अभिनवीकरण एवं वैज्ञानिक प्रबन्ध के द्वारा भी कमी की जा सकती है। हमारी औद्योगिक नीति भी ऐसी होनी चाहिये, जिसमें उद्योग का पर्याप्त विकास हो सके। फोर्ड फाउण्डेशन की रिपोर्ट के अनुसार बिना विवेकीकरण के भारतीय श्रमिकों की कार्य-क्षमता एवं दक्षता का अनावश्यक रूप में ह्रास होता है। आधुनिकीकरण

व अभाव में व वर्तमान तकनीका का सदुपयोग नहीं कर पाते । फलतः प्रत्येक राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा में भाग लेना नहीं हो सकता है । आधुनिकीकरण व विरोध में अम सधो का जो दमोले है व पूरण सधो प्रतीते होती है और उनका ह्मता व साथ सामना किया जाना चाहिए । यह अर्थ है कि विवेकीकरण व परिणामस्वरूप जिन अर्थिको की छद्मता का जाये उनको रोजगार देने की पूरा व्यवस्था होना चाहिये ।

(८) कर की समस्या—समस्त बीकारोपण न भी भारतीय उद्योगपतियों को निरोधित किया है । सन् १९४८ की सभा का भारत सरकार ने मसौदों पर मूल्य ह्रास का २२ का काफा बना दिया है और इससे लिये भारत सरकार बर्धाई की पात्र है परन्तु फिर भी समाज उद्योगपति यह अनुभव करते हैं कि माय कर व मुद्रा अर्थ की दर बहुत ऊँचा है जिसके कारण व विस्तार व आधुनिकीकरण में सम्बन्धित योजनाओं का कार्यान्वित करने व निर्यात बाधा में पूजा का सचम नहीं कर पाते ।

तीसरे इस्पात परामर्शदाता समिति—

६ फरवरी सन् १९६० को चौथे एवं इस्पात परामर्शदाता समिति का प्रथम बैठक हुई जिसमें दश के विभिन्न इस्पात उद्योगपतियों ने इस उद्योग में सम्बन्धित समस्याओं पर विचार विमर्श किया । एमोसियर चार्ल्स आफ कामस व सरवाल्डर मिशेल मोरा (Sir Walter Mischelmore) ने श्रद्धा विस्मय व बोधन एवम् विद्वानि के अभाव पर प्रकाश डाला । उन्होंने मसौदा किया कि रेना के विद्युत्करण में नौ एवम् इस्पात उद्योग के लिये गति की समस्या अत्यन्त महत्त्व हो जायेगी क्योंकि उद्योगिक विद्युत्निर्माण का उपयोग रेना में अधिक किया जायेगा । टिस्का के आस्मास (Mr. Steeles) ने यह सुझाव दिया कि इस्पात व मूल्य में कुछ कमी की जाना चाहिये इन्होंने इस बात का भी मसौदा किया कि नौ व इस्पात उद्योग की उचित प्रगति के लिये एक उच्च स्तरीय बधानिक बोर्ड स्थापित किया जाये । इण्डियन मायरम एंड स्टील व कापूर (Mr. Kapoor) ने सुझाव दिया कि दश में इस्पात के उपभोग का प्रवर्धन का अर्थ करने से भी बहुत लाभ हो सकता है । मसौदा के स्वामी एम० एल० ए० ने बतलाया कि भारत के अर्थ में इस्पात की बहुत कमी है अतएव इसका उपयोग का बचत का ध्यान रखनी चाहिये । फर्ग्युसन आफ इण्डियन चार्ल्स कामस इन्स्टीट्यूट के ग्राजी० एल० बमन (Mr. G. L. B. Boman) ने इस्पात के वितरण पर मसौदा किया होना का सुझाव दिया ।

तीसरे पंचवर्षीय योजना में उद्योग—

जुलाई १९६० में प्रकाशित तृतीय पंचवर्षीय योजना के अनुसार एमो आया है कि सन् १९६१ तक लोहा इस्पात का उत्पादन ६७ मिलियन टन हो जायेगा । अद्यत्त एंगो का उत्पादन (Ingot Production) लगभग ४१ मिलियन टन हो



जायेगा। इसके अतिरिक्त १॥ मिलियन टन पिग आयरन के उत्पादन का आगा है जिसका उपयोग विद्युत के लिए किया जायेगा।

उपसंहार—

६ फरवरी १९६० को हुई लौह इस्पात परामर्शदाता समिति का प्रथम बैठक में के. द्राय इस्पात एवम् इंधन मंत्री सरदार स्वर्णसिंह ने बतनाया कि देश में लौह एवम् इस्पात उद्योग का भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल है। उन्होंने यह संकेत किया कि निकट भविष्य में एक ऐसा संस्था का निर्माण किया जायेगा जो निजी व राजकीय क्षेत्र के इस्पात के कारखानों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं (विशेषतः कच्चे माल का पूर्ति में सम्बंधित) की मनुष्यता का ध्यान रखेगा।

उसी अवसर पर उद्योग मंत्री श्री मनुभाई गाहने बतनाया कि अभी तक दो वर्षों तक हमारे पास इस्पात का आधिकार्य नहीं होगा क्योंकि हमारी निजी आबश्यकताएँ ही बहुत हैं। यदि थोड़ा बहुत आधिकार्य होगा तो उसका लिए हमका निश्चय कामगार मिल जायेगा। जिन जिन देशों से भारत के व्यापारिक सम्बंध हैं उनमें से अनेक में ५५-७७ वर्ष के लौह इस्पात आयात करने की इच्छा प्रकट की है। इसमें उद्योग के उज्ज्वल भविष्य का आभास मिलता है।

## STANDARD QUESTIONS

1. 'Briefly trace the origin progress present position and problems of the Iron and Steel Industry
2. Discuss the principal problems of the Indian Iron and Steel Industry and suggest remedies to solve them

## भारतीय चीनी उद्योग

(Indian Sugar Industry)

प्रारम्भिक—

भारत के सशक्त उद्योगों में सूती कपड़े के बाद चीनी उद्योग ही प्रमुख उद्योग है। यह उद्योग भारत का प्राचीन उद्योग है। जब विश्व के अन्य देश इन वस्तु के नाम पर घनभिन्न थे, उस समय भारत इनमें परिचित था। ईसा से चार सताब्दी पहले कौटिल्य ने अपने 'अर्थशास्त्र' में गन्ने के द्वारा चीनी बनाने तथा घीरे में मध्य-सार निवासने की विधियों का उल्लेख किया है। १७वीं सताब्दी के प्रारम्भ में मूरत व कालीकट से बहुतसी मपेद चीनी घीर खांड निर्यात की जाती थी। बनारस की निम्न चीनी विदेशों में बड़ी प्रसिद्ध थी और देश की आन्तरिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी इसमें होती थी। आस भी हमारे देश में ससार की कुल गन्ने की उपज का २६% भाग होता है। सरकार को इस उद्योग में लगभग ८५ करोड़ रुपये की वार्षिक आय होती है। उद्योग की कार्यशील पूँजी भी १०० करोड़ रुपये से अधिक है।

उद्योग का विकास—

भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की नींव सन् १८६६ में पड़ी, 'जबकि' सरकार ने चीनी के आयात पर कर लगा दिया। इस प्रतिबन्ध की आड़ में चीनी व आधुनिक कारखाने उत्तरी भारत में खोले गये, परन्तु सताब्दी के प्रारम्भ में प्रायः यह कुटीर उद्योग अवनति कर रहा था। उत्पादन के ढंग अर्वाचानिक थे, जिसमें कीमत अधिक होती थी और भारत अन्य देशों की स्पर्धा में लड़सड़ा रहा था। प्रथम युद्ध तक आने-आने भारत इसने उद्योग के लिये आयात पर निर्भर हो गया। सन् १९०१-१९२० के मध्य भारतीय गन्ने की नस्ल सुधारने तथा उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयत्न किये गये। सन् १९०१ में गन्ने के सुधार के लिये एक अनुसन्धान-केन्द्र खोला गया। सन् १९१६, २० में एक चीनी समिति भी स्थापित की गई। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप गन्ने का उत्पादन बढ़ा।

उद्योग की सरलण—

सन् १९२६ में चीनी समिति ने सिफारिश की कि आधुनिक ढंग के चीनी के कारखाने खोलने पर विचार किया जाय और विदेशों में चीनी आयात करन में कटौती,

रूपों की हानि को रोका जाय । फलतः भारत सरकार ने इस प्रश्न पर विचार करने के लिये टैरिफ बोर्ड नियुक्त किया, जिसकी सिफारिशों के आधार पर सरकार ने इस उद्योग को सन् १९३१ से १५ वर्ष के लिए संरक्षण देना स्वीकार किया । संरक्षण के लिए चीनी के आयातों पर पहले सात वर्षों के लिए ७३ प्रति हन्डरवेट के हिमाब में संरक्षण कर लगाया । सन् १९३१ में चीनी का आयात १० लाख टन था, जो सन् १९३६, ३७ में १६ हजार टन रह गया । आयात के कम होने से जो हानि हुई उसकी पूर्ति के लिए आवश्यक कानून के अन्तर्गत २।) प्रति हन्डरवेट की दर से कर लगाया गया । गन्ने के क्षेत्र में भी वृद्धि की गई । सन् १९३१, ३२ में भारत में कुल ३२ चीनी मिलें थी, किन्तु अगले पाँच वर्षों में हो सख्या ३२ से बढ़कर १३० हो गई । निम्न-लिखित तालिका में चीनी उद्योग का आभास मिलता है—

### चीनी उद्योग का विकास\*

वर्ष	मिलों की संख्या	गन्ने का उत्पादन (हजार टनों में)
१९३१-३२	३२	१,६०
१९३८-३९	१३२	६,४२
१९४४-४६	१३८	६,२३
१९४०-४१	१३६	११,१६
१९४१-४६	१४३	१८,५६
१९४६-४७	१६६	२०,३६
१९४७-४८	—	२०,०६
१९४९	—	२०,८४

उत्पादन बढ़ने ही चीनी का मूल्य बहुत बढ़ गया तथा पारस्परिक प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ने लगी ।

सन् १९३७ में भारतीय चीनी संघ की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य पारस्परिक प्रतिस्पर्धा दूर करना, बिक्री का नियमन एवं उद्योगों को संरक्षित करना था । इसके प्रयत्नों में चीनी बाजार की दशा में सुधार हुआ । सरकार ने कुछ कानून बनाये, जिससे सब मिलें इस संघ की सदस्य बन जाये । जब मूल्य अनुचित रूप से बढ़ने लगे, तो सरकार ने इससे मान्यता हटा ली । फलतः अधिकांश मिलें इस संघ से हट गई और पारस्परिक प्रतिस्पर्धा फिर बढ़ गई । सन् १९४० में उद्योगपतियों की प्रार्थना पर सरकार ने संघ को फिर मान्यता दे दी, किन्तु निम्न बातों का पालन आवश्यक कर दिया—संघ केवल बिक्री एजेंट का कार्य करेगा, प्रत्येक मिल के लिए

और मद्रास में अनेक महकारा चाना मिल स्थापित हान का आगा २ । सन् १९६० ६१ तक चीनी मिठाई के विस्तार पर २० करोड़ रुपये मगानो के आधुनिकीकरण पर ५० करोड़ रुपये तथा नई चाना मिला पर २४ करोड़ रुपये खर्च होगा । केंद्रीय सरकार प्रदेशीय सरकारों का गन्ना का उत्पादन बढ़ाने के विभिन्न मुद्धारन के लिए ४० लाख रुपये का ऋण व ३० लाख रुपये का अनुदान देगा । भविष्य में मिठाई के आधार पर हा गन्ना का श्रेणीकरण एवं मूल्य निर्धारित किया जावेगा जिसमें किसान अच्छी काटि का गन्ना पेश करे । द्वितीय याजना काल में इस उद्योग के विस्तार के कारण २१ ००० अनिश्चित व्यक्तियों को राजगार मिल जावेगा । यह आगा का जाती है कि द्वितीय याजना की पूर्ति होने तक भारत चीना के सम्बन्ध में स्वयं ता आराम निभर होगा हा साथ ही निर्यात भी बना सकेगा और देशवासियों का मस्ता चीनी मिल सकेगी । सन् १९५० ५१ में गन्ना का उत्पादन ५६ मि० टन था जो ६० ६१ में ७२ मि० टन हो जायगा । प्रस्तावित तृतीय याजना के अनुसार सन् १९६६ तक गन्ना का उत्पादन ६२ मि० टन हान की आगा है तथा चीनी का उत्पादन लगभग ३ मि० टन हो जायगा ।

**चीनी उद्योग की विशेष समस्याएँ—**

चीनी उद्योग के सामने निम्न समस्याएँ हैं जो इसकी प्रगति में बाधक हैं—

(१) प्रति एकड़ पशुवार में कमी—उत्तरा भारत में प्रति एकड़ लगभग १४ १५ टन और दक्षिणी भारत में २० टन गन्ना उगाया जाता है जबकि जावा तथा हवाई द्वीपों में यह क्रमशः ५६ और ८२ टन है । इसके अनिश्चित शोधों भाई देश के अधिकतर गन्ना का गुड बना लेते हैं । इससे चीनी उद्योग को पर्याप्त क्षति होती है ।

(२) गन्ने की निम्न कोटि—भारतीय गन्ना की किस्म भी बहुत खराब है । गन्ना में चीनी की मात्रा कम होती है । सन् १९४७ ४८ में गन्ना से केवल ८ ८५% चीनी निकलती थी जबकि जावा फारमूसा और मलायल में क्रमशः ११ ४६ १२ ०५ और १४ २२% निकलता है ।

(३) गन्ने का अधिक मूल्य—भारत में सरकार गन्ना का मूल्य निश्चिन करती है जो चीनी की कुल लागत का ६०% होता है अतः मिल मालिकों का कथन है कि उनको कुछ भी बचन नहीं होता । गन्ना का इतना अधिक मूल्य इसलिए है कि भारत में चीनी मिलाई के पास खपत के बजाए खन रहा है वगैरह किमान पर निभर रहना पड़ता है जो उसे छोटे छोटे अनाधिक खतों पर उगाता है । मूल्य के सम्बन्ध में एक समस्या यह भी है कि गन्ना का मूल्य केवल तेल के आधार पर तय किया जाता है जिससे उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता । इससे मिलाई का काफी हानि होती है ।

(४) त्रिपूरण स्थानीयकरण—देश का अधिकांश मिल उत्तरा भारत में स्थित

चीनी उद्योग की विकास सभा के मुभाव पर भारत सरकार ने एक प्रतिनिधि मंडल भ्रास्ट लिया व इंडोनिशिया भ्रम था जिसकी रिपोर्ट मन् १९५६ में प्रस्तुत हुई । इसमें चीनी उद्योग का उन्नति के लिये निम्न सुभाव दिये गये हैं—

( १ ) चीनी के मूल्य पर कन्ट्रोल न लगाया जाय क्योंकि भारत तथा ब्रास्ट लिया की अनुभव है कि इसका कारण उद्योग के विकास में बाधा पड़ती है । (२) चीनी व गुड की बिक्री के लिये कोई केन्द्रिय सभा नियुक्त न की जाय । (३) चीनी के मूल्य तथा बटवारे पर जो नियन्त्रण है तथा सरकार जो २५ ० चीनी को नियन्त्रित मूल्य पर वेधन का अधिकार रखता है उसे चीनी को विदेशों में मगाकर उसका निश्चित मूल्य पर बेचना है उस नीति का बलमान में बायम रखा जाय । (४) सरकार की चाहिए कि हर वर्ष गुड की घुनतम कीमत निश्चित कर जिसमें गुड व चीनी के मूल्य तथा उपनि म समन्वित रहें । यदि गुड का मूल्य बाजार में निश्चित मूल्य में कम हो तो स्वयं उस दरराद तथा गुण के दररातन के लिये गुड के मुख्य उत्पादन क्षेत्रों में मजू कारग ममिति या स्थापित करे । (५) गन् का मूल्य निश्चित करने में परामर्श देन के लिये सरकार को एक स्थायी मलाहकार ममिति नियुक्त करनी चाहिये जिसमें गन्ना उगाने वालों व मिलों के बराबर बराबर प्रतिनिधि हों और जिसका मभापति एक जन हो । ( ६ ) गन्ना उगाने वालों का गन् का मूल्य उसके गुण के अनुसार दिया जाय । (७) गन् की प्रति एकड़ उपज की बतान के लिए निम्न उपाय किए जाय— (अ) गन् का उन्नत बीज बनाना तथा गन् को वामारिया में बचाना (ब) ब्रास्ट लिया तथा जावा में ब्रिटिश गन् का आयात करना और उस भारत में उत्पन्न करने का प्रयत्न करना । गन् के विभिन्न प्रकारों को अलग अलग मिट्टियों तथा जलवायु में उगा कर रखना व किसानों को उगाने के लिये देना (इ) चीनी उत्पादन करने के विषय में एक अखिल भारतीय पत्रिका चालू करना (ई) एक से अधिक मिलों वाले क्षेत्रों में गन् के बीड़ों तथा रोगों को रोकने वाले बीड़ स्थापित करना । (८) गीरे पर अनुभव करके देखना कि वह कहाँ तक पशुधन के उपयोग में काम आ सकता है उसमें गति उत्पादन की सम्भावनाय देखना व खोई में पट्टा बनाना । गीरे का रचित वटवारा करने के लिये उसे केन्द्रीय सरकार के आधान लाना । (९) गन् के आम का साफ करने के लिये अनुसंधान करना जिसमें वह बहुत से उद्योगों के काम आ सके । (१०) ब्रास्ट लिया की भांति गन्ना उगाने तथा चीनी बनाने वालों की सस्थाप स्थापित करना । (११) भारतीय टूट मिगना तथा दूतावागा द्वारा विदेशों में गुण के बाजार तलाश करना । (१२) चीनी अनुसंधान का स्थापना करना व अनुसंधान करने वाले लोगों का विदेशों में भेजना । (१३) फल वाला वस्तुग्रा तथा दूध वाले उद्योगों का उस मूल्य पर चाना देना । (१४) बनमान मिला का बनाना न कि नई मिल स्थापित

करना । (१५) विदेशों से खनी के औजार तथा चीनी उत्पन्न करने वाली मशीन का बिना किसी आयात कर लगाये मँगाना ।

### STANDARD QUESTIONS

1. Briefly trace the origin, progress, present position and problems of the Indian Sugar Industry.
2. Discuss the principal problems of the Indian Sugar Industry and suggest remedies to solve them.

## भारतीय कोयला उद्योग

(Indian Coal Industry)

## प्रारम्भिक—

कायला होश मयान् कायला आधुनिक उद्योग का जन्मदाता है। यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक ईंधन म म एक है। मागे ब्रिटिश कामनवेल्थ म भारत दूसरे नम्बर का एक विश्व म आर्थिक नम्बर का उत्पादक है। कायला निर्यातन क सम्बन्ध म सबसे पहला अधिकृत वगुन सन् १७८४ का है जबकि वारेन हर्स्टिंग न मसम समनर १७८८ स्ट्रीटल को बगाल म कोयला नी लाना स कायला निर्यातन की आता प्रमाण का। यह प्रयत्न असफल रहा और इसक बाद सन् १८१४ तक समय बन्द प्रयत्न न हुआ। इसा वर्ष रानागज क निकट कोयला निर्यातन का काम पुन आरम्भ किया गया। सन् १८६० तक वार्षिक उत्पादन ३ ०० ००० टन हो गया। सन् १८५५ म कनकन की ई० आई० रेल्वे न इस क्षेत्र का उपयोग किया और इस प्रकार उद्योग का भविष्य सुरक्षित हो गया। सन् १८६८क बाद कायल क उत्पादन म प्रगतिशील प्रगति हुई। निम्नलिखित आकड़ इस बात के साक्ष्य हैं —

## कोयले का उत्पादन\*

वर्ष	उत्पादन (लाख टनो म)
१८६८	५
१८८०	१०
१८९०	५
१९००	११
१९१०	१२०
१९२०	१८०
१९३०	२३८
१९४०	२५१
१९४६	२६०
१९५०	२७०
१९५५	२८०
१९५६	२८४
१९५७	४३५
१९५८	४५२
१९५९	४६४

सन् १८७१ में रेल्वे ने गिरडीह क्षेत्र में प्रवेश किया और घातान्दी के आरम्भ से इस क्षेत्र का उत्पादन ३० लाख टन हो गया। भरिया के क्षेत्र में भी विकास हुआ डाल्टन गज क्षेत्र, रीवा राज्य, मध्य प्रान्त, हैदराबाद, आसाम और विलोचिस्तान के क्षेत्र भी विकसित हुए १६००,०१ में आयात १,४७,४६७ टन० निर्यात ५,४२,०-२३ टन और उत्पादन ६१,१८,६६२ टन था, जिसका लगभग ६०% बंगाल व बिहार में प्राप्त हुआ। सन् १९१४ तक कुल उत्पादन बढ़कर २६० लाख टन हो गया।

### प्रथम महायुद्ध और उद्योग—

बढ़ी हुई औद्योगिक कार्यवाहियों के दबाव में कोयले की मांग उसकी पूर्ति से अधिक हो गई और इस अवधि भर उद्योग का यह प्रयत्न रहा कि यह बढ़ती हुई मांग के साथ अपनी गति कायम रखे। उत्पादन तेजी से सन् १९१८ में २०० लाख टन हो गया। इसका ८५% उत्पादन रानीगंज और भरिया क्षेत्र में प्राप्त हुआ। कोकिंग कोल की मांग एक दम बढ़ गयी थी, अतः बोकारो के कोयला क्षेत्र का अत्यधिक विकास किया गया। कोक के घन कुन्टी में और भरिया क्षेत्र की सोदना कोयला खान के पाम लगाये गये। यही नहीं, कोयला-क्षेत्रों का विद्युतीकरण तेजी से किया गया और दो केन्द्रीय विद्युत स्टेशन बनाये गये।

लेकिन युद्ध काल का यह विकास सीमित था और मशीन एवं यन्त्र मिलने की कठिनाई के कारण जारी न रह सका। वृद्धि का क्रम सन् १९१६ में अपने सर्वोच्च बिन्दु पर पहुँच गया और इसके बाद उत्पादन में कमी आरम्भ हुई। आशावादी प्रबन्धकों ने अपने लोगों को भी उद्योगों में ही विनियोग कर दिया। युद्धोत्तर काल की अन्य घटना इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा भट्टिया बनाना था, जिन्होंने सन् १९२२ में कार्य आरम्भ किया। मांग में कमी होने के साथ यह कठिनाई भी हुई कि अम सवर्ष हुये और निर्यात व्यापार में तेजी में कमी आई। सरकार की नीति के कारण स्थिति में सन् १९३६ तक कोई सुधार नहीं हो सका। आर्थिक मन्दी का तत्कालीन प्रभाव मूल्य गिराना था और वास्तव में इस गिरावट के कारण ही उत्पादन में अधिक कमी हुई। सन् १९३६ के बाद औद्योगिक कार्यों में तीव्रता में वृद्धि हुई, जिनका प्रभाव यह हुआ कि कोयले की मांग पुनः बढ़ने लगी।

### द्वितीय महायुद्ध के बाद—

द्वितीय महायुद्ध ने, जो मितम्बर सन् १९३९ में आरम्भ हुआ कोयला उद्योग को पिछले दो दशकों में हुई गम्भीर निराशा में उभरने की सामर्थ्य प्रदान की। मांग बढ़ने में मूल्यों में सुधार हुआ। कोयले की कमी घटती हुई यातायात सम्बन्धी कठिनाइयों और कोयले के गिरते हुये आयात के कारण और भी अधिक अनुभव होने लगे। फिर सैनिक योजनाओं में धामकी को अधिक अच्छा काम मिलने लगा, अतः उत्पादन में बड़ी कमी आई। अन्त में, सन् १९४४ के मध्य तक मूल्यों पर कड़ा नियन्त्रण रखना



आवश्यक हो गया। इस बात का भा प्रवर्ध किया गया कि आवश्यक उपभाक्ताओं का कायना एक यात्रावृद्ध क्रम से हो प्राप्त हो। सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिये कायना धनरा म बाहर धमिका का भरता करके बानस ह्याम और अतिरिक्त लाभकर के समर्थ म रियायती के रूप में आर्थिक प्रलाभन देकर उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न भी किया। इन उपायों में उत्पादन में वृद्धि हुई। मन् १९५८ में लगभग ४५२ करोड़ टन कायन का उत्पादन हुई।

मन् १९२२ में भारत सरकार ने कायना खान (सरमिश व सुरक्षा) कानून पास किया जिसके द्वारा सरकार का निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हो गये—

- (१) कायन का खाना की सुरक्षा व सरक्षण के लिये कायना खाना छोड़ने का कार्यवित्त करना।
- (२) कायला परिषद (Coal Board) का कायना उद्योग की समस्याओं का मूलभूत का अधिकार देना।
- (३) कोयला तथा काक के उत्पादन पर कर लगाना।
- (४) कायला उद्योग का कर्मचारीवर्ग चयन के लिए तथा उस नियंत्रित करने के लिए नियम बनाना।

मन् १९५३ में सरकार ने एक कायला समिति नियुक्त की थी, जिसका उद्देश्य कायन खान का प्रगति लक्षण के विषय में सरकार को सलाह देना था। इस प्रकार कायन के उत्पादन वितरण मूल्य निर्धारण तथा श्रमिका के बतन आदि पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण है।

**पंचवर्षीय योजना में कोयला उद्योग—**

पंच वर्षीय योजना में काकिंग कोल के सुरक्षित रखने और नान काकिंग कोल में अन्तर का विस्तृत जाँच करने का आवश्यकता पर बड़ा बल दिया गया है। उसमें कायन के प्राथमिक उत्पादन और वितरण का जिसमें कोयन का गतिविधि के पुनर्गठन का भी शामिल किया गया है पक्ष लिया गया है। इसमें कठारिक मूल्य, राश और नमा तथा काकिंग विपणनाओं के अनुसार बशर्तिका आधार पर कायन के वर्गीकरण पर पुनर्विचार करने का मुझाव दिया गया। उसमें यह भी मुझाव दिया गया है कि इन अनुसंधान समस्या काक के कायनादनान एवं उत्पादन काक आक्मिक के टिकायन कायन का धाना और मिथित करना तथा मयक दूर करने के सम्बन्ध में अनुसंधान कर।

द्वितीय योजना के अंतर्गत ६ करोड़ टन कायल के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। २२० करोड़ टन कायन के अनिर्दिष्ट उत्पादन में से १ करोड़ टन कायला निजा क्षेत्र में पड़ा होगा। सावर्जनिक क्षेत्र में कायन के उत्पादन की देखभाल करने के लिए अक्टूबर मन् १९५८ में स्थापित गणराय कायना विकास निगम (प्राइवट) लिमि

कोयला उत्पादक मन्त्रिष्व रूप में उन व्यावसायिक संस्थाओं का सम्बन्ध में भी मोचन पड़ेगा जिसमें हमारी योजना का सक्षय होगा हा मन्त्र । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये २२ करोड़ टन कोयला प्रति वर्ष अधिक निकालना होगा । अनिश्चित उत्पादन बढान के लिये विभिन्न कायना क्षेत्रों में निम्न मात्रा में उत्पादन बढान की योजना है—

(लाख टन में)

कोयला क्षेत्र का नाम	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग
शानागज	३६	२६ ८	६२ ८
भरिया		३५ ०	३५ ०
करनपुरा	४०	५ ६	४५ ६
बोकारो	१६		४ ०
कोरबा	४०		४० ०
कोरिया और रीवा	२०	५ ०	२५ ०
मिर्जापुर		१० ७	१० ७
	१५०	८३ १	२३३ १

(३) रेलों की व्यवस्था—यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि अनिश्चित वांछित उत्पादन में से १८ करोड़ टन कोयला इधर से उधर जान की व्यवस्था रेल कर भी मक्की या नहीं । २३ करोड़ टन कोयले में से मात्र ५० लाख टन कोयले का कुछ भाग कोयला खानों पर प्रयुक्त होगा और कुछ भाग ट्रेकों द्वारा ठाया जायगा । इस समय जो ३७ करोड़ टन कोयला खानों में निकाला जाता है उसमें से २३ करोड़ टन कोयला ही होती है । वर्तमान उत्पादन में से बचा ५० लाख टन और अनिश्चित उत्पादन में १८० लाख टन कायला रेलों में १९६० तक अधिक होना होगा । इस तरह २३० लाख टन कोयला अधिक ढान की मास्य बढा लना चाहिये किन्तु नहीं है । रेल प्रशासन की एक कठिनाई यह भी है कि जब निम्न उद्योग का देश के दूर भाग में स्थापित करने की योजना बनाई जाती है तो रेल विभाग में यह मलाह नहा भी जाती कि रेल आवश्यक परिमाण में बिना कठिनाई के उस उद्योग के लिये कोयला आदि पहुँच भी सक्ता या नहा ।

(४) कोयला उद्योग का मुत्तियुक्त संगठन—द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है कि कोयले का चार प्रतीशत मुत्तियुक्त संगठन करना, जिसकी आवश्यकता एक ही कोयले के प्रादेशिक वितरण की दृष्टि में भी है और दूसरे धानु मोचन के लिए श्रेष्ठ कायने का मुरखित रखन की ना दृष्टि में है । कोयले के प्रादेशिक उत्पादन

में वृद्धि होने से रेलें निकटस्थ कोयला क्षेत्र में माल को निर्दिष्ट स्थान तक जल्दी पहुंचा सकेगी, और रेलों कोल बनान का श्रद्धिया कोयला बचा सकेंगी क्योंकि रेल बढ़िया कोयला या तो लम्बे सफर में भाग बनान के लिय प्रयोग करनी है अथवा दुगम प्रदेशों में जान पर । जब कम दूर माल डोना होगा तो वे योजनानुसार घटिया कोयला ही जलान लगनी । इस प्रकार कोयला उत्पादन की द्वितीय याजना के अनुसार भले ही निर्दिष्ट लक्ष्यों की पूर्ति में एक या दो वर्षों का विलम्ब हो जाये, फिर भी इससे कोयला उद्योग का काफी भीमा तक युत्तिपुत्त पुनगठन हा सकेगा ।

(५) कोयला उद्योग का यंत्रीकरण—भारत में प्रति व्यक्ति पाली उत्पादन २७ टन है, जब कि मधुत्त राज्य में ६२६ टन, जपान में ८६६ टन और अमेरिका में २१६८ टन है । इसमें प्रगट होता है कि प्रति पाली उत्पादन भारत में बहुत कम है । कोयले के मूल्य का ७५ % यंत्रिका को, १५ से २०% करी को और केवल ५१०% मानिको का प्राप्त होता है । इसका कारण ढूँढने के लिय दूर जान की आवश्यकता नहीं है । उद्योग हम बात की बड़ी आवश्यकता में है कि उत्पादन का यंत्रीकरण के विस्तृत प्रयोग से विवेकीकरण किया जाय । सन् १९५० में कोयला समिति ने सुझाव दिया था कि भारत में कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये मशीना का प्रयोग करना परम आवश्यक है । यह भी सिफारिश की गई थी कि यंत्री कारण का काम एक अवधि पर फना दिया जाय और एक कोयला खान से दूसरी कोयला खान में धीरे धीरे किया जाय जिससे परिवर्तन एवं सुधार सरल हो जाय । भारत सरकार ने सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और कोल बोर्ड को यह पता लगान का आदेश दिया है कि विद्यमान कोयला खानों में बिना अधिक बेवारी उत्पन्न किये विद्युनीकरण कि सीमा तक किया जा सकता है । साथ ही, एक एसी शत भी लगा दी गई जिसमें मालिका का यह अनिवार्य हो गया है कि जब नई खान खोलने की आज्ञा मिले, तो समस्त नये विकास कार्यक्रम कोयला खोदन और ले जान में मशीना का अधिक ॥ अधिक प्रयोग करेग ।

(६) राष्ट्रीयकरण का प्रश्न—राष्ट्रीयकरण के बारे में भी बहुत मा हाह्ला मचाया गया है । हमें विद्वाम है कि सरकार कबन राष्ट्रीयकरण की ही छातिर वत मान कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण नहीं करगा कि तु जब सरकार यह दख कि राष्ट्रीय हित की दृष्टि से काक बनान के कोयले के भण्डारा को सुरक्षित रखने के लिये क्षति पूर्ति करके कोयला खानों का आधिग्रहण आवश्यक है अथवा ५०० टन प्रति घंटा घोन वाल विशाल कारखाना में जिसकी लागत एक करोड रुपये से अधिक होगा और जिस स्थापित करना निजी पूँजीपतियों के बश की बात न होगी प्रयोग करने के लिये कोयले का उत्पादन इतना आवश्यक है अथवा न सरकार देना जान वाली

एसी भूमि खरीदे जिसमें बढ़िया कोयल की खानें हों और जिन्हें उसके मालिक प्रति योगितापूर्वक न खोद सकें या उन्हें खोदने में इतना खर्चा हो जा उनके साधनों में बाहर हो तो सरकार द्वारा खानें प्रपन अधिकार में लेने में किसी को कोई प्राप्ति नहीं होनी चाहिए ।

(७) थमिको की समस्या—खानों में काम करने वाले थमिको की दशा भी खराब है जिसके सुधार के लिए भारत सरकार प्रयत्नशील है । एक नये अधिनियम के अनुसार प्रत्येक कोयला खानों में काम करने वाले थमिको से ४८ घंटे प्रति सप्ताह से अधिक काम नहीं लिया जा सकता । इसमें भूमि के ऊपर काम करने वालों के लिये ६ घंटे प्रति दिन तथा भूमि के नीचे काम करने वालों के लिए ३ घंटे प्रति दिन का काम निर्धारित किया गया है ।

### STANDARD QUESTIONS

- 1 Briefly trace the origin progress present position and problems of the Indian Coal Industry
- 2 Discuss the principal problems of the Indian coal Industry and suggest remedies to solve them



# औद्योगिक अर्थ प्रबन्धन की समस्याएँ

(Problems of Industrial Finance)

## प्रारम्भिक—

देश के जनसाधारण का जीवन स्तर ऊँचा करने के लिए औद्योगीकरण नितान्त आवश्यक है। औद्योगीकरण के बिना देश के आर्थिक कलेवर में मत्तुलन नहीं आ सकता। परन्तु औद्योगीकरण का माग कोई पुण्य की श्रद्धा नहीं है, इसमें अनेक कठिनाइयाँ हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण कठिनाई उद्योगों के लिए पूँजी प्राप्त करने की है। नए-नए उद्योग स्थापित करने के लिए, पुराने उद्योगों का पुनर्मूँकटन तथा पुनर्निर्माण करने के लिए तथा युद्ध एवं मन्दी जैसे आर्थिक मकटों से उद्योगों का निराला कर उनसे बचाने के लिए पूँजी की आवश्यकता होती है।

किसी भी व्यापार को, चाहे वह अल्प परिमाण पर हो अथवा बहुपरिमाण पर हो, प्रारम्भ करने एवं अविष्य में उसके विस्तार के लिए पूँजी की आवश्यकता होती है। पूँजी के बिना कोई व्यापार चल नहीं सकता। यह आधुनिक औद्योगिक तथा व्यापारिक संस्थाओं का जीवन है। पूँजी की ही कमी के कारण अनेक औद्योगिक संस्थाएँ असफल हो जाती हैं तथा व्यापार भी निधिल हो जाता है। प्रत्येक औद्योगिक संस्था को मुख्यतः दो कार्यों के लिए पूँजी की आवश्यकता होती है—(१) स्थाई सम्पत्तियाँ, जैसे—भूमि, मशीन, यन्त्र आदि के त्रय के लिए, जिसे अस्थाई अथवा अचल पूँजी कहते हैं और (२) अस्थायी सम्पत्तियाँ, जैसे बच्चा माल खरीदने, उसे निर्मित करने, विभाजन आदि दैनिक खर्चों के लिए, जिसे कार्यशील अथवा चल पूँजी कहते हैं।

भारत में सर्व प्रथम तो पूँजी का अभाव है और जो पूँजी है भी उसे औद्योगिक विकास में लगाने के लिए कोई सङ्गठित संस्थाएँ नहीं हैं। हमारे देश में औद्योगिक बैंकों का विकास नहीं हुआ है और देश के व्यापारिक बैंक न तो इतने साधन रखते हैं कि उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और न ही उन्हें इस कार्य में कोई रुचि है। यह समस्या केवल दहे पैमाने के उद्योगों के सामने ही नहीं है बरन्

मध्यम तथा छोट पैमाने के उद्योग भा इससे पीछे के । ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उत्पादकों को अच्छा माल खरीदने के लिये वस्तु के उत्पादन व्यय को पूरा करने के लिए तथा अपने जीवन निर्वाह के लिए धन की आवश्यकता होती है । इस कार्य के लिये उन्हें गाँव के महाजन का सहारा लेना पड़ता है जोकि बहुत ऊँचा दर सत्याज वसूल करता है । मध्यम प्रकार के उद्योगों को भी अपनी आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिए साहूकारों अथवा व्यापारिक बकों पर निर्भर रहना पड़ता है । उनकी ज़रूरत भी उतनी ही दयनीय है जितनी छोटे उपायों की । बड़े पैमाने के उद्योगों की हालत भी पूरक सन्तुष्टिजनक नहीं बड़ी जा सकती ।

औद्योगिक संस्थाओं के लिए पूँजी के स्रोत—

भारतवर्ष में उद्योगों को निम्न साधनों से आर्थिक सहायता प्राप्त होती है —

स्थायी पूँजी—

(१) भण्ड निगमन द्वारा ।

(२) ऋण पत्र निगमन द्वारा ।

कार्यशील पूँजी—

(३) जन निक्षेप अथवा जनता की चरौहर द्वारा ।

(४) बक में ऋण लेकर ।

(५) प्रबंध अभिकर्त्ताओं से ऋण लेकर ।

(६) विशिष्ट ऋण संस्थाओं से ऋण लेकर ।

## (१) अक्ष निगमन द्वारा

अधिकारित अक्षों द्वारा ही पूँजी प्राप्त की जाती है । स्थायी पूँजी प्राप्त करने का यह अत्यंत लोकप्रिय साधन है । स्थायी सम्पत्तियों के ब्रह्म के लिए जो पूँजी लगाई जाती है वह स्थायी रूप से उद्योगों में फल जाती है इसलिये उसे एक साधन से प्राप्त किया जाता है जो स्थायी रूप से उस उद्योगों में लगाए रहे और वापिस निबालन पर आग्रह न कर । स्पष्टतः ऐसी पूँजी अक्ष निगमन द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है । अक्षों के निगमन की दशा में उद्योगों का अपनी सम्पत्ति पर बिना किसी प्रकार का भार डाले स्थायी पूँजी प्राप्त हो जाती है, अस्तु यदि उद्योग आवश्यक समर्थन ऋण द्वारा आवश्यकता के समय अतिरिक्त अक्ष का भी प्रबंध कर सकते हैं । अक्षों पर लाभ भी उसी दशा में दिए जाते हैं जब पर्याप्त लाभ होता है अथवा लाभान्वित दशा अनिवार्य नहीं होता । परन्तु इतने लाभ होने हुए भी पूँजी के इस स्रोत में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि अक्ष पूँजी एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती । इसी प्रकार

यदि अशो के अधिकारों में कुछ परिवर्तन करना हो, तो कम्पनी ऐसे अगुधारियों की सम्मति के बिना जिनके अधिकार प्रभावित होने हें, उनके अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती ।

## (२) ऋण-पत्र निर्गमन द्वारा

बढ़ने हुए व्यापार की पूँजी सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कभी कभी औद्योगिक मस्याओं को ऋण लेने की आवश्यकता पड़ जाती है । दीर्घकालीन ऋण की प्राप्ति अधिकारण-बन्ध (Bonds) तथा ऋण पत्रों द्वारा की जाती है । ऋण-पत्र एक प्रकार का अनुबन्धात्मक प्रलेख होता है, जिसके द्वारा ऋण प्राप्त किया जाता है तथा जिसमें मूलधन का भुगतान होने तक किसी निश्चित समयिक अवधि में प्रतिशत ब्याज देने की प्रतिज्ञा होती है । ऋण-पत्रों के निर्गमन द्वारा उन रुढ़िवादी व्यक्तियों से पर्याप्त पूँजी प्राप्त की जा सकती है, जो बिना अधिक जोखिम उठाए निश्चित आय चाहते हैं । अशो के निर्गमन की अपेक्षा यह साधन मितव्ययी भी है, क्योंकि इस प्रकार का ऋण यदि अन्य किसी रीति से लिया जाय, तो अधिक ब्याज देना पड़ता है, किन्तु ऋण पत्रों पर निश्चित रूप से कम ब्याज चुकाना पड़ता है । इतना होने हुए भी ऋण पत्र भारत में अभी लोकप्रिय नहीं हुए हैं । मन् १९२७-२८ में भारत की कुल औद्योगिक पूँजी का ६०% भाग पूर्वाधिकार अशो में, ७५% साधारण अशो में और शेष ६% ऋण पत्रों के रूप में प्राप्त किया जाता है । हमारे देश में ऋण-पत्रों की अप्रियता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं —

भारत में ऋण पत्र अप्रिय क्यों ?—

(१) स्वतन्त्र बाजार का अभाव—ऋण पत्रों के लिए हमारे देश में अन्य देशों की भाँति स्वतन्त्र बाजार नहीं है । भारतीय विनियोगक तब तक अपना धन किसी उद्योग में नहीं लगाने जब तक उन्हें लाभ का पूरा आश्वासन नहीं होता । वे प्रायः भूमि त्रय में अथवा कृषि कार्य में रुपया लगाना अधिक उपयुक्त समझते हैं । यही कारण है कि निश्चिन्त लाभ या ब्याज वाले ऋण पत्र भी उन्हें आकर्षित नहीं करते । फिर भारतीय ऋण पत्र अधिक ऊँचे अधिमान के होने हैं, इसलिए साधारण विनियोगक की पहुँच के बाहर हैं । बीमा कम्पनियाँ बीमा अधिनियम की धारा २७ के कारण औद्योगिक ऋण पत्रों का क्रय नहीं कर सकती । भारतीय बैंक भी इस विषय में स्टेट बैंक की नीति का अनुसरण करते हैं तथा विनियोग प्रणामों (Investment Trusts) का तो अभी उदय ही हुआ है, इसलिए वे औद्योगिक व्यवसायों में धन विनियोग करने में असमर्थ रहते हैं ।

ऋण पत्रों पर तथा उनके हस्तान्तरण पर मुद्रांक-कर भी अधिक देना पड़ता है, जिससे ऋण पत्रों का हस्तान्तरण स्वतन्त्र रूप से नहीं हो सकता । उदाहरणार्थ,

बम्बई में पृष्ठांकित होकर अथवा अन्य किसी प्रलेख द्वारा हस्तान्तरित होने वाले ऋण पत्रों पर ७ रु० ८ भा० प्रति हजार रुपये मुद्रांक कर (Stamp Duty) लिया जाता है। प्रत्येक हस्तान्तरण पर इतना ही और अनिश्चित शुल्क लगता है। बाह्य ऋण-पत्रों पर निगमन के समय ही १५ रु० प्रारम्भिक शुल्क लगता है। ये बम्पनी के लिए अत्यन्त भार रूप हैं। इसके साथ ही विनियोजनों का भी प्रत्येक हस्तान्तरण पर काफी व्यय देना पड़ता है, इसलिए भी जनता विनियोग के ऐसे खर्चों से साधन को अपनाना नहीं चाहती। इसके अनिश्चित ऋण पत्रों का कम संख्या में निगमन होना भी उनके स्वतन्त्र बाजार हान में बाधक है। अभी तक केवल नूतन मिना के ऋण पत्रों को छोड़कर अन्य सभी बम्पनियों के ऋण पत्र जनता तक पहुँच ही नहीं पाये हैं, क्योंकि जैसा भी उनका निर्गमन होता है वैसे ही कनिष्ठ धनी लोग उन्हें खरीद लेते हैं। यहाँ यह कहना अनावश्यक न होगा कि टाटा आयरन एण्ड स्टील बम्पनी के ६० लाख रुपये के सम्पूर्ण ऋण पत्र मध्य भारत के राजप्रमुख न ही खरीद लिये थे। भारतीय ऋण पत्र अधिक मूल्य वाले होते हैं, जैसे—(१००), (१,०००), (१०,०००) के इत्यादि, अतएव सब साधारण जनता की पहुँच के बाहर होते हैं।

(२) बैंकों की प्रवृत्ति—ऋण पत्रों की लोकप्रियता में बैंकों का व्यवहार भी अधिक बाधक हुआ है। ऋण पत्र भी निगमित करने वाले प्रमण्डल भारतीय बैंकों की दृष्टि में गिर जाने हैं और उन्हें वे फिर बैंकों साख मुविधायें प्रदान नहीं करते जैसे अन्य देशों में करते हैं, क्योंकि बम्पनी की सम्पत्ति पर ऋण पत्रों का पहला प्रवरण होता है, इसलिए बैंक द्वारा लिए हुए ऋण के लिए प्रतिभूति कम रहनी है।

(३) निर्गमन की अनाक्यक शर्तें—भारतीय ऋण पत्रों में वे विनियमन नहीं होती, जिनसे जनता स्वयं लासलियत होकर उन्हें खरीदने के लिए दौड़ें। भारतीय विनियोगों को उनकी विभिन्न शक्तियों के अनुकूल विभिन्न विनियमन बाल ऋण पत्र उपलब्ध नहीं हैं। अन्य देशों में ऋण पत्र विभिन्न आकषक मुविधायों वाले होते हैं, जैसे—वहाँ कुछ ऋण-पत्र प्रत्याभूति होते हैं, कुछ के लिए भुगतान होने पर अधिक प्रव्याज देने का प्रलोभन दिया जाता है, कुछ ऋण पत्रधारियों को एक या अधिक संचालक नियुक्त करने का अधिकार होना है तथा कुछ ऋण पत्र ऐसे होते हैं जो साधारण अशा की रियायती दर पर खरीद सकते हैं, किन्तु भारत में जहाँ मुद्रा-मण्डी भी सुसंगठित नहीं है वहाँ यह निरान्त आवश्यक है कि ऋण पत्रों के निर्गमन की शर्तें उदार एवं आकर्षक हों।

(४) राजकीय अर्थनीति से उदारता का अभाव—ऋण पत्रों की अप्रियता का कारण यह भी है कि यहाँ सरकार की सावजनिक अर्थ एवं प्रमुख नाति उदार नहीं रही। भारत में विदेशी शासन की नीति यहाँ के उद्योग धन्धों को विदेशी स्पर्धा में पर्याप्त और उचित सरक्षण प्रदान नहीं कर सकी। जब कभी कोई उद्योग प्रारम्भ हुआ,



भारतीय विनियोगक निश्चित लाभ अथवा सफलता के आश्वासन के अभाव में उसमें पूँजी लगान में हिचकते रहे। सरकार के प्रश्न के अतिरिक्त अन्य भी कई चीजें हैं जो उद्योगों में पूँजी के प्रवाह को रोकता रही हैं जैसे—उपादन करों का लगाना उपभोग की वस्तुओं के सम्बन्ध में अराष्ट्रीय आयात नीति का अनुसरण करना इत्यादि। ये बातें ऐसी हैं कि जिनसे यहाँ का औद्योगिक व्यापार प्रगतिशील नहीं होता और फिर न यहाँ के विनियोगक ऋण पत्रों में धन लगाना उचित ही समझते हैं।

(५) अत्यधिक निगमन व्यय—ऋण-पत्रों के निगमन में व्यय भी बहुत पड़ता है। निगमन करते समय हाँ व्याज की दर भा निश्चित कर दी जाती है। अभा तक ५ से ६ प्रतिशत तक यह व्याज की दर प्रचलित है। भारत में इन पर भारी व्याज के अतिरिक्त जिसकी दर केवल प्रमण्डल की साख पर ही नहीं बल्कि निगमन के समय निगमन की मात्रा तथा अभिगापन की स्थिति पर भी निर्भर करती है प्रारम्भिक वधानिक एवं मुद्राक व्यय व अभिगापन कमीशन भी देन पड़ते हैं अतः कभी-कभी तो ऋण पत्र निगमन में इतना अधिक व्यय हो जाता है कि कम्पनी उनका निगमन करना भी उचित नहीं समझती।

(६) सलाह देने वाली संस्थाओं का अभाव—भारतवर्ष में ऐसी कोई माय संस्था नहीं है जहाँ विनियोगक ऋण पत्रों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकें। बल्कि अवश्य अपने ग्राहकों को इस विषय में उचित सल्लाह प्रदान करती हैं पर दुर्भाग्य से भारत में आज भी ऐसे नगर हैं जहाँ बँक नहीं हैं। स्कॉच विनिमय विपणि (Stock Exchanges) भा केवल बन्दरगाह के गहरों में ही हैं अतएव दूर-दूर तक फैले हुए विनियोगकों को इनके विश्वसनीय एवं स्वीकृत मस्यो से सम्पर्क स्थापित करने में बहुत धाड़ पड़ती है।

### (३) जन-निक्षेप

भारतीय कम्पनियों की अथ पूर्ति के लिए जन निक्षेप स्वीकार करना भी इस देश की औद्योगिक व्यवस्था की एक अनोखी विशेषता रही है। जनता द्वारा कम्पनियों में निक्षेप इसलिए रख जाते थे कि बँकिंग विकास की प्रारम्भिक स्थिति में जनता का विश्वास बँका में इतना नहीं था जितना कि कम्पनियों में। अथ पूर्ति की यह पद्धति बम्बई और अहमदाबाद की सूती वस्त्र मिल कम्पनियों में अधिकता से पाई जाती है जिनकी कुल पूँजी का क्रमशः ११% तथा ३६% जन निक्षेपों से आते थे।\* बात यह है कि जिन लोग न इन स्थानों में उद्योग प्रारम्भ किए थे महाजन आदि थे जिनमें जनता का बड़ा विश्वास था इसलिए वे अपनी वचत की राशि उन्हें व्याज

पर सौद देत थ। एक बड़ा आस्पख सो उह ( जमा करन वालो को ) प्रवध अभिवृत्तत्व धतन म भाग मिलन वर था। यदि प्रवध अभिवृत्तगिरा अच्छा स्थिति क हुए तो वे केवल व्याज पर ही निक्षेप प्राप्त कर सकने हे। इस प्रकार प्राप्त की हुई पूँजी की वागत ऋण पत्रा पर प्राप्ति की हुई पूँजी से बड़ी अधिन मितव्ययी बँटता हे और सबसे बड़ा बात तो यह हे कि किसी प्रकार का प्रभाव इसम उदय नहीं होता क्योंकि निक्षेपको का अथ आपसमान ऋणताभा के समान अधिकार होते हे। बम्बई राज्य के प्रमण्डल केवल अपने वायगीय पूँजी का भाग हा नहीं बरन् विस्तार एवं विकास योजना की अथ पूर्ति भा जन निक्षेप क द्वारा करते हे। निम्नलिखित आकड़ो म स्पष्ट हे कि अहमदाबाद का मूना बन्ध व्यवसाय जन निक्षेप पर काफी सीमा तक निर्भर हे।

पूँजी का स्रोत	कुल पूँजी का प्रतिशत	
	बम्बई	अहमदाबाद
अपन पूँजी	( १२१४ ला० रु० ) ४६%	३१% ( ३४० ला० रु० )
ऋण पत्र	( २३८ ला० रु० ) १०%	१% ( ८ ला० रु० )
प्रवध अभिवृत्ताप्रो से	( ५३२ रु० ) २१%	२४% ( २६४ ला० रु० )
जन निक्षेपो म	( २७३ रु० ) ११%	३६% ( ४९ ला० रु० )
वकी स	( २२६ रु० ) ९%	४% ( ४२ ला० रु० )

उपशुक्त आकड़ो म यह स्पष्ट हे कि बम्बई का बन्ध व्यवसाय जन निक्षेपो पर कम अनुपात म निर्भर रहता हे। भारत क अथ औद्योगिक क्रांति म यह पद्धति नहीं पाई जाती हे।

जन निक्षेपो की व्याज की दर बम्पनिया एवं प्रवध अभिवृत्ताप्रो का साख एवं स्थायित्व की दृष्टि से भिन्न भिन्न बम्पनिया म भिन्न भिन्न हाता हे। शुरू में तिभप ६ मे १२ माह की अवधि के लिये रख जात थ किन्तु बाद म उनका नवकरण होता रहता था। साधारणत व्याज का दर ४.१०% म ६.३०% तक रहती हे। जिन कम्पनिया का साख अच्छा होती हे वे कम व्याज पर भा निक्षेप आकर्षित करन म सफल हा जाते हे किन्तु म दा के समय निक्षेप कम हो जात हे। जन निक्षेप क द्वारा औद्योगिक संस्था का पूँजी का बनेवर साधनार रहता हे क्योंकि वह निक्षेप जन क कारण बचक आदि से मुक्त रहती हे। यदि जन निक्षेप उम्मी अवधि क लिए हा तो फिर कम्पनी को ऋण पत्र निगमन करन की आवश्यकता नहीं पडती। यही नहीं यदि

कम्पनी को अधिक लाभ हो रहे हो, तो सामान्य न बढ़ाते हुए लाभों का कुछ भाग सचिव कोष में रखा जा सकता है, जिसमें उसकी भावी विस्तार योजनाओं को बिना नवीन पूँजी के कार्यान्वित किया जा सकता है।

इतने लाभों के होत हुए भी निक्षेपों की सबसे बड़ी हानि यह है कि मन्दी अथवा आपत्ति के समय में जनता भयभीत होकर उनको वापस माँग लेती है और ऐसी परिस्थिति में कम्पनी का बड़ा हानि उठानी पड़ती है तथा अर्थ सङ्कट का सामना करना पड़ता है, अतएव इन्हें कभी-कभी 'अच्छे समय का साथी' कहा जाता है। यह आवश्यकता के समय के साथी '(Friends in need)' नहीं हैं और इसलिए इन पर पूर्णतः निर्भर नहीं रहना जा सकता। दूसरे सरलता एवं न्यून ध्यान पर ऋण-प्राप्त किये जाने की मुविधा से पारिकाल्पनिक व्यापार का प्रोत्साहन मिलता है। इसी से औद्योगिक सत्याये अति व्यवसायिक प्रलोभन में पँस जाते हैं, जिसे कम्पनियों एवं निक्षेपकों तथा धनदायिधों, सभी को हानि उठानी पड़ती है।

### (४) बैंकों से ऋण लेकर

सामान्यतः कम्पनी की प्रारम्भिक स्थायी पूँजी अथ एव ऋण पत्रों के निर्गमन से ही प्राप्त करनी चाहिये। आदर्श व्यवस्था तो वह है, जिसमें न्यूनतम कार्यशील पूँजी भी इन्हीं साधनों द्वारा प्राप्त की जाय। हाँ, न्यूनतम कार्यशील पूँजी के अतिरिक्त भावी पूँजी सम्बन्धी आवश्यकताओं को बैंक से ऋण लेकर पूरा किया जा सकता है। कम्पनी जिन बैंकों से आर्थिक सहायता प्राप्त करती है, वे प्रायः दो प्रकार के होते हैं—(क) व्यापारिक बैंक और (ख) औद्योगिक बैंक। भारत में जितने भी सङ्गठित स्वयं बैंक हैं, वे सभी व्यापारिक कार्यों के लिए ही ऋण देने हैं, औद्योगिक कार्यों के लिये नहीं। भारत में अभी तक ऐसा कोई भी औद्योगिक बैंक नहीं है जो इस अर्थ की पूर्ति कर सके, अतः औद्योगिक कार्यों के हेतु औद्योगिक बैंक की स्थापना अति आवश्यक है। इस बात की मिश्रित औद्योगिक कमीशन तथा 'बैंक इन्वॉयरी कमिटी' ने भी की है।

व्यापारिक बैंक सभी अवधि के लिए उद्योगों को ऋण दे भी नहीं सकन, क्योंकि अल्पकालीन निक्षेपों से दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना मुहृद बेकिंग सिद्धान्तों के विरुद्ध होता है, अतएव भारतीय बैंक कम्पनियों को केवल कार्यशील पूँजी अल्पकालीन ऋणों द्वारा देन रह ह, किन्तु अल्पकालीन ऋण भी विविध शर्तों पर दिया जाता है। वे शर्तें निम्नलिखित हैं—

बैंक ऋण की कीटन शर्तें -

( १ ) बैंक कम्पनी व व्यापार में लगे हुए स्टॉक का अधिकांश भाग रहन या धन्यक के रूप में रखकर ऋण दिया करता है। रहन तथा धन्यक (Pledge

and Hypothecation) में अन्तर है। जब किसी कम्पनी का स्टॉक गृहण किया जाता है तो वह ऋण लेने वाली कम्पनी के मादामा ही एकत्रित रहता है। कम्पनी का अपन स्टॉक का विवरण निश्चित अवधि पर बैंक को भेजना पड़ता है। बन्धक रखने की दशा में स्टॉक बैंक की सुरक्षा में रखना पड़ता है और जिन मादामों में वह एकत्रित होता है, उन पर बैंक का नाम डाल दिया जाता है तथा कम्पनी का उसमें कोई मरकाज नहीं रहता। स्पष्ट है कि बन्धक की शर्त कितनी कठिन है, शर्त कोई भी कम्पनी अपन स्टॉक को गृहण अथवा बन्धक के रूप में रखना पसन्द नहीं करती क्योंकि इसमें कम्पनी को मान्य एवं प्रतिष्ठा पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

( २ ) जब किसी कम्पनी के स्टॉक का गृहण बैंक कोई बैंक ऋण दिया करती है तो वह ऋण लेने वाली कम्पनी में एक प्रतिज्ञा पत्र लिखवाती है, जिस पर कम्पनी तथा उसका प्रबन्ध अधिकर्ता के हस्ताक्षर होंगे। अगर कम्पनी का स्टॉक बैंक के पास बन्धक के रूप में रखा जाता है तो प्रबंधक अधिकर्ता की वैयक्तिक प्रतिभूति नहीं ली जाती है।

( ३ ) ये ऋण प्रारम्भ में प्रायः १२ माह के लिए ही दिए जाते हैं, बाद में उनका नवकरण करना बैंक का इच्छा पर निर्भर करता है।

( ४ ) व्याज की दर ऋण लेने वाले प्रमंडल का साल के अनुसार कम अथवा अधिक होता है। जो कम्पनी सुव्यवस्थित होती है, उसमें तो इम्पीरियल बैंक आफ इटाली की दर पर ही व्याज लिया जाता है, किन्तु यदि किसी कम्पनी की दशा अच्छी नहीं होती तो उसमें ये बैंकें १% या २% अधिक व्याज लिया करती हैं।

( ५ ) अगर कोई रोकड़ ऋण (Cash Credit) लेता है तो ये बैंकें नये हुए ऋण का लगभग आधा भाग व्याज के रूप में देने के लिए विवश करती हैं जोकि अत्यन्त कठिन बात है।

( ६ ) ये बैंकें बिना किसी प्रतिभूति के ऋण नहीं देती। यदि प्रतिभूति के रूप में रखा हुआ मान निर्मित माल है तो लगभग ३०% का अन्तर ऋण राशि एवं माल के मूल्य में रखते हैं किन्तु निर्मित माल न होने की दशा में यह अन्तर और भी अधिक हो जाता है।

अन्तु स्पष्ट है कि वका में ऋण प्राप्त करने में भारतीय प्रमंडलों को कितनी असुविधाएँ एवं कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है। निम्न रीति में बैंक उनकी सहायता कर सकती हैं —

बैंक सहायक कैसे हों ?—

( १ ) जर्मन बैंक का आदर्श—वर्तमान व्यापारिक बैंक जमनी के व्यापारी अधिकतम की तरह उद्योग की आर्थिक सहायता कर सकती हैं। जमनी में कम्पनी

तथा बैंक के बीच चल लेखा (Current A/c) द्वारा व्यापार होता है, जिसका सन्तुलन दैनिक न होकर सामयिक, विशेषतः पटमासिक होता है, किन्तु इन चल लेखों में तथा भारतीय बैंकों में पाये जाने वाले प्रचलित चल लेखों में काफी अंतर है। वहां दोना के बीच पहले से ही निश्चित हो जाता है कि—(अ) उद्योग अधिक मे अधिक कितना ऋण बैंक से ले सकेगा, (ब) लिया हुआ ऋण कितनी अवधि के भीतर वापस करना होगा, (स) लिए हुए ऋण की प्रतिभूति क्या होगी, तथा (द) अग्र्य दानें क्या होगी। जो राशि बैंक में मिलनी है वह कायदोल पूँजी के रूप में ही प्रयोग की जानी चाहिए, एना प्रतिवाय नहीं होता। उस ऋण राशि का उपयोग उद्योग के विस्तार के लिए, भाँ बियाँ जरूरत करना है। नवीन उद्योग को प्रारम्भ करने के लिए जिन अग्र्य पूँजी का आवश्यकता होती है, उनका अधिकांश भाग भी उन्हीं अधिकोषों द्वारा दिया जाना है। यदि कोई एन समस्या सम्पूर्ण भार को नहीं सभाल पाती तो हम प्रकार की अनक सस्थाएँ, मानकर उत्तरदायित्व का अपन ऊपर ले लेती हैं। उनक इस प्रकार के संगठन का कन्सोर्टियम पद्धति (Consortium Model) कहते हैं। इस कार्य को करने के लिए इन अपना एक पृथक उद्योग विभाग रखती थी, जिसकी विनियोग पूँजी भी पृथक रखी जाती थी। इस विभाग के संचालन के लिए तात्कालिक सलाह दान के हतु एन औद्योगिक सम्पत्ति का मूल्यांकन करने के लिए बिने पज्ञा की निपुत्ति की जाती थी।

उद्योगों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखने के लिए बैंक अपने प्रबन्धक अथवा उनके अग्र्य प्रतिनिधि औद्योगिक प्रमण्डल की संचालन समिति में भजती थी, जिससे उनके कार्यों का नियन्त्रण होता था तथा बैंक भी निश्चित हो जाती थी कि उनका ऋण राशि का अवन्यय नहीं हो रहा है।

( २ ) व्यापारिक बैंक कुछ ऐसे निश्चित राशि के अग्र्य का निगमन करें, जिसकी पूँजी में केवल उद्योगों को ही आर्थिक सहायता दी जाय।

( ३ ) उदार नीति का पालन हो—यद्यपि प्रतिभूति की प्रकृति एवं उसकी यथेष्टता के निणाय करने का अधिकार पूर्ण रूप से बैंक का ही है, फिर भी उन्हें कुछ उदार नीति का पालन करना चाहिए। यह जमान बैंक की नीति का रहस्य था, जिसे वे औद्योगिक सम्पत्ति के लिये उपयोग में लाती थी। बैंक को चाहिए कि वे औद्योगिक प्रमण्डल को आर्थिक सुविधाएँ वित्तिक साख पर भी दिया कर, जिससे उनके कार्यशील पूँजी मिलती रहे, क्योंकि वे तरल सम्पत्ति की प्रतिभूति नहीं दे सकते।

( ४ ) जिन बैंक का औद्योगिक प्रमण्डल से सम्बन्ध रहता है, वे अपनी प्रबन्ध व्यवस्था में ऐसे व्यक्ति रखें जो सामान्य औद्योगिक प्रबन्धन में पूर्ण ज्ञान रखते हों। इसमें औद्योगिक सस्थाओं से व्यवहार रखने में सरलता रहेगी।

( ५ ) जयन बका की भांति अपन आहूक प्रमण्डला मे निवृत्त सम्बन्ध स्थापित करन के लिए वे अपनी प्रबन्ध समिति वा एन मदस्य उनकी पर्यवेक्षण समिति (Board of Supervisors) मे अपन प्रतिनिधि के रूप मे रखे। अथ प्रबन्धन क विषय मे अनुभव के कारण ये प्रतिनिधि प्रमण्डला क लिए नो हितकर सिद्ध हागे हा सम्बन्धित बक को भी प्रमण्डल की वास्तविक स्थिति वा ज्ञान करान और इस प्रकार आगन्तवाजनिह हानि की सम्भावनाय कम करन मे सहायक होगे।

( ६ ) बक प्रमण्डला को उनक नवान पूजी प्राप्त किए जान बाल अथ एङ्ग अभिगापन ऋण पत्रा के निगमन मे जमन बक की भांति निगमन के कुल अथवा कुछ भाग को स्वयं स्वीकार करके और बाद मे सुगुणवत्तर उपस्थित होन पर उह जनता को सोप करके सहायता कर सकती हे। इसमे अपनी हानि के भय को कम करन के लिए कई बक परस्पर समुत्त रूप से काय का बीडा उठा सकती हे। एसी बका मे सामान्य बर्किंग विभाग के अतिरिक्त एन विनियोग विभाग और हों जिसमे उनके निजो अथ साधनों का कुछ सीमित भाग समय समय पर एमे कार्यो क विण जान पर लगाया जाय। निश्चय ही इन कार्यो को करन मे बनी विगान पूजा एक औद्योगिक धनुभक्त की आवश्यकता होगी। प्राय बड़ी बड़ी बक भी इस काय को करन मे हिचकती हे। कनाडा आदि देणो मे तो केवल यही काम करन वाला बक पृथक स्थापित हा गई हे।

( ७ ) प्रायक प्रसिद्ध यापारिक कर्द्र मे बका की एक एक स्थानीय सलाह समिति होनी चाहिए। ये समितियाँ केवल अपनी सम्बन्धित कम्पनिया की अथ पूति करन मे सहायता प्रदान ही करती अरन् बका के धनुदान एव ऋणवह रक्षार्थ क सहाय वा भी अपन ऋण लेन बाला के मस्तिष्क मे निवास करी हे।

**दूसरा सुझाव औद्योगिक अधिकोपो की स्थापना—**

यह तो निश्चय है कि उदार नीति के उपरान्त भी व्यापारिक बक ही अकेल कम्पनिया की अथ पूति नहीं कर सकता बरान उनका औद्योगिक क्षय वा पान सीमित हुता है तथा औद्योगिक सहायता क लिए एक बड़ा मात्रा मे स्थाई पूजी का आवश्यकता होती है। यापारिक बका मे इतनी सामर्थ्य नहीं होना कि वे दण का औद्योगिक आवश्यकताओं का पूरा कर सकें अतएव अन्तर्जालीन तथा दीघकालीन ऋणा की समस्याय भिन्न भिन्न होन मे काय क्षमता की दृष्टि मे यह उत्तम होगा कि पृथक रूप से औद्योगिक बको की स्थापना की जाय। आजकल भारत मे इस प्रकार का बकन एक ही मस्था है जो गत २५ वर्षों मे काम कर रहा है और वह है कनाडा इंडस्ट्रियल एण्ड बर्किंग मिडीकेट लिमिटेड उन्नीषी। यह भा स्पष्ट है कि केवल एक अधिकोप से सम्पूर्ण दण की औद्योगिक अथ आवश्यकताय कैंम पूरी हो सकता हे अन् तबों औद्योगिक अधिकोपा का आवश्यकता है जिनके पास दीघकालीन विनियोग क

लिए पर्याप्त साधन हो। इन अधिकोपो को केवल औद्योगिक अर्थ मुविधायें ही देनी चाहिए, जिससे व्यापारिक बेकिङ्ग क्षेत्र औद्योगिक बकिङ्ग क्षेत्र से भिन्न हो एवं उनकी क्रियायें भी पृथक पृथक हो।

## (५) प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली

(Managing Agency System)

भारतवर्ष के प्रत्येक महत्वपूर्ण उद्योग में प्रबन्ध अभिकर्ताओं का बहुत बड़ा भाग रहा है। भारतीय प्रभुत्वक मण्डल ने सूती वस्त्र उद्योग के विषय में जा रिपोर्ट १९३१ में प्रकाशित की थी, उसमें यह स्वीकार किया गया था कि “केवल उन बड़े उद्योगों को छोड़ कर जिन्हें भारत में राज्य ने सङ्गठित किया अथवा जो उसकी देख-रेख में स्थापित किए गये, लगभग प्रत्येक महत्वपूर्ण उद्योग इन्हीं प्रबन्ध अभिकर्ताओं के साहम के कारण जन्म पा सचा है।” अब भी अधिकतर औद्योगिक सस्थायें, विशेषकर सीमित उत्तरदायित्व वाली पब्लिक कम्पनियां इन्हीं के हाथ में हैं। उदाहरण के लिए, जमशेदपुर का लोह व इस्पात का उद्योग, बम्बई व ग्रहमदावाद का सूती वस्त्र उद्योग, बंगाल व बिहार का जूट उद्योग देश के सबसे अधिक सङ्गठित उद्योगों में से हैं, परन्तु इन उद्योगों में ऐसा शायद ही कोई मिल हो जो किसी प्रबन्ध अभिकर्ता के परोक्ष नियन्त्रण में नही है। प्रबन्ध अभिकर्ता देश के औद्योगिक क्षेत्र में यह स्थिति कमे प्राप्त कर सके, इस प्रश्न का उत्तर हमें उन परिस्थितियों में मिलेगा जो भारत की अपनी अनोखी विशेषता रही है।

### प्रबन्ध अभिकर्ताओं का उदय—

वास्तव में प्रबन्ध अभिकर्ता पद्धति का उदय भारत के औद्योगिक विकास के साथ-साथ हुआ। यहाँ उद्योग के प्रारम्भिक प्रमुख विकासकर्ता अंग्रेज व्यवसायी थे, जो पहले यहाँ कुछ व्यापारिक सस्थाओं के प्रतिनिधियों की भाँति आये। पहिले तो इन्होंने सामान्य व्यापार का काम किया, परन्तु बाद में अन्य कामों की ओर भी आकर्षित हुए। इन्होंने देखा कि भारत एक विशाल कृषि देश है, जहाँ भरपूर प्राकृतिक साधन हैं, जोकि विशाल धावादी, पर्याप्त भ्रम की सुलभता होते हुए भी औद्योगिक दृष्टि से बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, क्योंकि जनता दूसरों को उद्योग में लगाने के लिए द्रव्य देने में सकोच करती है। पूँजी के अतिरिक्त और सब साधन यहाँ है, जिनका कि होना औद्योगिक उन्नति के लिए आवश्यक है।

अस्तु अपने लाभ के लिए उन्होंने आवश्यक पूँजी स्वयं प्रदान करने का निश्चय किया एवं अपने मित्रों को भी इसके लिए तैयार किया। उद्योग स्थापित कर दिये गए, सम्बेदारी बन गई और उद्योग चलाने के लिए आवश्यक पूँजी दे

दाँ गई। हानि एवं अन्य आपत्तियों के समय में भी उन्होंने उद्योग को बचाने के लिए आर्थिक मदद दी, क्योंकि बाहरी जनता से तब ही पूँजी प्राप्त करने की आशा की जा सकती थी जबकि यह उद्योग स्पष्टतः सफल होता प्रतीत हो। जब यह दवा पहुँच जाती थी तो वे उसे कम्पनी में परिवर्तित कर देते और अपनी पूँजी का बड़ा भाग वापिस लेकर उसे फिर किन्हीं अन्य प्रयत्नों में लगा देने थे। कम्पनी के जन्मदाना तथा प्रमुख पूँजी प्रदान करने वालों एवं अनुभवी प्रबंधकर्त्ता होने के रूप में उनका उम्र कम्पनी के नियन्त्रण में काफी हाथ रहता था। एक ही प्रबन्ध अभिकर्त्ता गृह व आधीन कई प्रमण्डल नियन्त्रित रहते थे। प्रबन्ध अभिकर्त्ता पदार्थ बगाल में मुक्त हुई और फिर अन्य भागों में भी फैल गई। कुछ भारतीय पूँजीपतियों ने भी उनकी देखा देखी उनकी सफलता से प्रेरित हो इस प्रकार का कार्य करना प्रारम्भ किया और इसमें उन्हें विदेशियों से बड़ी सहायता मिली।

एक दूसरी बात जो इस पद्धति के जन्म का कारण बनी वह थी बैंकों की यह हठ कि प्रमण्डला का तब ही ऋण दिया जाय (वह भी सन्धे समय के लिये नहीं, यादों की अवधि के लिये) जबकि उसके प्रबन्ध अभिकर्त्ता इस ऋण की गारंटी दे। उनका यह आग्रह इस कारण था कि वे प्रमण्डलों की आन्तरिक स्थिति से तो परिचित हान नहीं थे, परन्तु प्रबन्ध अभिकर्त्ता सब कुछ जानते थे, अस्तु यह स्वाभाविक ही था कि बैंक उनकी गारंटी की माँग करें। ऊँची आर्थिक स्थिति व प्रमण्डल भी सेवा से तब ही ऋण प्राप्त कर सकते थे जबकि उनके प्रबन्ध अभिकर्त्ता गारंटी देन को तैयार हो।

तीसरे, उम्र समय के भारतीय कम्पनी अधिनियम की दुर्बलताओं ने भी प्रबन्ध अभिकर्त्ता पद्धति को प्रासङ्गिक किया। सन् १९१३ तक कम्पनियों के लिए संचालकों की नियुक्ति करना अनिवार्य न था, अतः जो भी व्यक्ति किसी कम्पनी के निर्माण में हित रखते थे, वे स्वयं उसके प्रबन्ध अभिकर्त्ता बन जाते थे। जब सन् १९१३ के अधिनियम ने पब्लिक कम्पनियों के लिए संचालकों की नियुक्ति अनिवार्य कर दी, फिर भी प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के लिये कोई कठिनाई पैदा न हुई क्योंकि अपने व्यापारिक सहयोगियों एवं मित्रों में से ही वे कुछ लोगों को चुन कर संचालक नियुक्त कर देते थे और इस प्रकार नियन्त्रण की बागडार वास्तव में उन्हीं के हाथ में रहती थी।

अस्तु इन परिस्थितियों में प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं का औद्योगिक संगठन में प्रमुख स्थान या तत्ता स्वाभाविक ही था।

प्रबन्ध अभिकर्त्ता प्रथा के लाभ—

भारत के औद्योगीकरण के इतिहास में प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं का महत्वपूर्ण स्थान



रहा है, क्योंकि इनकी विभिन्न सेवाओं द्वारा ही देश की औद्योगिक प्रगति सम्भव हो सकी। इस प्रणाली के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं—

(१) प्रवर्तन एवं निर्माण—जैसा हम ऊपर संकेत कर चुके हैं, प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने प्रारम्भिक अनुमत्यान करके एवं अनुविधाओं तथा असफलताओं का सामना करते हुए अनेक सफल उद्योगों की नींव डाली थी। इनकी सहायता के बिना चाय, जूट, कपास, कोयला आदि बड़े बड़े व्यवसाय न तो स्थापित हो किये जाते और न उनकी शीघ्र उन्नति ही होती। प्रबन्ध अभिकर्ताओं का कम्पनियों से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है, अतः वे मुहूर्त कम्पनियों की ही स्थापना करते हैं। यही नहीं, कम्पनी की स्थापना के लिए समस्त वैधानिक कार्रवाही करते हैं और याग्य एवं अनुभवों व्यक्तियों की संचालक पद के लिए चुनते हैं।

(२) आर्थिक सहायता—प्रबन्ध अभिकर्ता विभिन्न रीतियों से, जिनका उल्लेख हम कर चुके हैं, कम्पनी को आर्थिक सहायता पहुँचाने हैं। इनके व्यावसायिक जीवन और वाणिज्य जगत में ख्याति के बल पर अनन्तता को नष्ट निमित्त कम्पनियाँ स सम्पर्क स्थापित करने में सुविधा रहती है।

(३) बैज्ञानीकरण एवं सूचीकरण—इन नवाग्रा के प्रतिरिक्त प्रबन्ध अभिकर्ता अपने अन्तर्गत कम्पनियों की व्यवस्था में एकसूत्रता लाते हैं, जिससे उनमें मितव्ययिता होती है और कार्यक्षमता बढ़ती है। प्रबन्ध अभिकर्ताओं के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक संस्थाएँ होती हैं, जिनके विशिष्टीकरण के लिए वे अपने कार्यालय में अलग अलग विभाग रखते हैं, जिससे उनके अन्तर्गत जितनी कम्पनियाँ हैं उनको उनकी विशेष योग्यता का लाभ हो सके। व्यक्तिगत रूप में कम्पनियाँ के लिए यह सम्भव नहीं होता कि विशिष्ट योग्यता वाले अनुभवों व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकें, किन्तु प्रबन्ध अभिकर्ताओं के माध्यम से न्यूनतम व्यय पर उन्हें विशेषज्ञों की सेवा का लाभ प्राप्त हो जाता है। दूसरे, पूरक व्यवसायों की दशा में एक व्यवसाय का लाभ दूसरे व्यवसाय में सुविधा से खप जाता है। उदाहरण के लिए सूती वस्त्र, यातायात तथा कोयला ये तीन उद्योग एक दूसरे के पूरक होने के कारण कोयले की खपत वस्त्र मिल उद्योगों में हो सकती है एवं वस्त्र व्यवसाय का यातायात की सुविधाय मिल जाती है तथा यातायात उद्योग का स्थाई ग्राहक मिल जाता है। यदि ये तीन उद्योग अलग अलग प्रबन्ध अभिकर्ताओं के नियंत्रण में हैं तो सम्भवतः यह लाभ न होगा। तीसरे, प्रबन्ध अभिकर्ता अपना क्रय विप्रेषण विभाग भी रखते हैं, जिससे उनके प्रबन्ध में जो व्यवसाय हैं उनकी आवश्यकताओं का न्यून तथा विषय इसी विभाग के द्वारा सुगमता से हो जाता है।

(४) विशेषज्ञों द्वारा सहायता—प्रत्येक प्रबन्ध अभिकर्ता अपने यह। कुशल एवं अनुभवों विशेषज्ञ रखता है। इस प्रकार थोड़ा व्यय में ही सरलतापूर्वक इन विशेषज्ञों

का परामर्श प्राप्त हो जाता है जिससे समय समय पर व्यवसाय की अत्यन्त आवश्यकता है।

(५) विनियोगों की सुरक्षा—प्रबंध अधिकर्ता अपनी व्याप्ति का बड़ा ध्यान रखते हैं और जहाँ तक बन पड़ता है इस पर कड़ा कानून बन देने इसलिये जनता तथा विनियोगदाता का यह विश्वास हो जाता है कि प्रतिष्ठित प्रबंध अधिकर्ताओं के प्रबंध में जा सम्पत्तियाँ हूँ उनमें उनका धन सुरक्षित रहेगा।

(६) प्रतिभूतियों का अभिगोपन—अपना दान का भ्रति हमारे देश में औद्योगिक प्रतिभूतियों का अभिगोपन करने के लिए विविध संस्थाओं का प्रभाव है अतः परिस्थितियों यह कार्य विचारें प्रबंध अधिकर्ता को ही करना पड़ता है, इसलिए उनकी इन सहायों के परिणामस्वरूप कम्पनी के अंग सूर्यपत्तादि गीष्म विक्रय उन्हें पूँजी की प्राप्ति हो जाती है तथा जनता के निष्क्रिय धन का भी उपयोग में अनुपयोग हो जाता है।

(७) प्रतिस्पर्धा का अभाव—एक ही प्रबंध अधिकर्ता के नियंत्रण में रहने में कम्पनियों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का उन्मूलन हो जाता है अतः उनमें सहायों की भावना बढ़ती है जिसमें प्रबंध एवं व्यवस्था में निरव्ययिता पाती है।

**प्रबंध अधिकर्ता पद्धति के दोष—**

उपरोक्त गुणों के हान हुए भी प्रबंध अधिकर्ता पद्धति को दोष रहित नहीं कहा जा सकता। यहाँ कारण है कि इसके दोषों का उन्मूलन करने के लिए समय समय पर कम्पनी अधिनियम में संशोधन किया गया एवं सन् १८५६ के कम्पनी अधिनियम में तो कायापलट ही कर दिया गया है। इन प्रणाली के प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं—

(१) आर्थिक प्रभुत्व—प्रबंध अधिकर्ता पद्धति में प्रायः सभी उद्योगों में एक ही व्यक्ति प्रतिकूल की अपेक्षा आर्थिक प्रभुत्व की ही महत्ता लिखाई जाती है। इसका कारण यह है कि इन संस्थाओं में मुख्यतः पूँजीपति हो जाते हैं या तांत्रिक योग्यता उत्तरी नहीं रखने जितनी की आर्थिक सहायता प्रदान कर सकते हैं। रोम हुए बच्चे का पुत्र पालन की भाँति ये लोग सबके की अस्त में कम्पनी की केवल आर्थिक सहायता देकर उनमें पुनर्जीवन का संकार कर देते हैं परन्तु उन कम्पनी की सच्चा प्रगति के लिए जिस तांत्रिक एवं व्यापारिक योग्यता की आवश्यकता होता है उसकी पूर्ति में नहीं कर पाते। फलतः कम्पनी की व्यवस्था में अनेक दोष आ जाते हैं। इस आर्थिक प्रभुत्व का यह परिणाम होता है कि यदि किसी समय कम्पनी अनेक सबके दलदल में पड़ जाती है और इन लोगों के पास भी पर्याप्त धन नहीं होता तो समा कटकपूरे परिणामित हैं प्रबंध अधिकर्ता अनेक अधिकार हमारे प्रबंध अधिकर्ताओं का जिनके अन्त आर्थिक साधन हान हैं सौंपकर स्वयं अलग हो जाते हैं। ऐसा करने समय व अधिधारियों के हितों की संगमात्र भाँति ना नहीं करते।

(२) अंशों की अधिक परिकल्पना—इस प्रणाली के अनुसार अनेक स्कन्ध विपरिणयो में, विशेषकर बम्बई में कम्पनियों के अंशों में अत्यधिक परिकल्पना (Speculation) पाई जाती है। ये लोग प्रायः कम्पनी या असाधारणों के हितों की ओर ध्यान न देते हुए सट्टेबाजी में व्यस्त हो जाते हैं। अपने हित के लिए कम्पनी के धन की बलि चढ़ा देते हैं, जिससे कभी-कभी कम्पनी को महान आर्थिक सङ्कट का सामना करना पड़ता है। आर्थिक स्थिति विगड़ने पर अंशों का मूल्य दिन पर दिन गिरने लगता है। यही नहीं, ये लोग एक प्रकार के अंशों को दूसरे प्रकार के अंशों में परिणत करके भी उनके मूल्यों को प्रभावित करते हैं। जिन अंशों को वे स्वयं खरीदना चाहते हैं उन पर लाभांश की दर कम कर देते हैं, जिससे उनका मूल्य गिर जाए तथा गिरे हुए मूल्य पर वे उन्हें खरीद लें। इसके विपरीत जिन अंशों को वे बेचना चाहते हैं उन पर लाभांश की दर बढ़ा देते हैं। इन दूषित कार्यवाहियों से विनियोक्तान्त्रों को बड़ी हानि होती है।

(३) सञ्चालकीय नियन्त्रण की शिथिलता—अभी तक सञ्चालकों की नियुक्ति में प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं का बहुत बड़ा हाथ रहता है, अतः यद्यपि कम्पनी की व्यवस्था का समस्त भार सञ्चालकों पर डी होता है और उन्हीं की प्रबन्ध नीति का निर्धारण करना चाहिए, किन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि सञ्चालकगण कठपुतली की भाँति नाचते हैं और इनको मचाने वाले हैं परदे के पीछे कार्य करने वाले प्रबन्ध अभिकर्त्ता। नये अधिनियम में इस सम्बन्ध में काफी सुधार कर दिये गये हैं।

(४) अन्तर्विनियोग—प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं ने अपने नियन्त्रण के अन्तर्गत आधिक्य राशि को दूसरी कम्पनियों को श्रृणु देने में भी लगाया। यदि दोनों ही कम्पनियों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती तब तो इसमें कोई हानि नहीं थी, किन्तु विपरीत परिस्थिति में यदि अच्छी स्थिति की कम्पनी का कोष एक दुर्बल कम्पनी को दे दिया जाय तो इससे अच्छी स्थिति वाली कम्पनी को हानि उठानी पड़ती है। नये अधिनियम के अन्तर्गत अन्तर्विनियोग पर रोक लगा दी गई है।

(५) अयोग्य व्यवस्था—प्रबन्ध अभिकर्त्ता पद्धति के अन्तर्गत कौटुम्बिक अनुशासन के कारण व्यावसायिक सगठन में स्थिरता आ जाती है। व्यवसाय में कार्य-कुशल व्यक्तियों का प्रवेश रुक जाता है। पिता के बाद पुत्र को, पुत्र के बाद प्रपौत्र को तथा इसी प्रकार अनेक प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं को पौत्रिक अधिकार मिलते हैं। इससे यह आशंका रहती है कि पुत्र अथवा प्रपौत्र उतने कार्य कुशल न हो जितने कि उनके पूर्वज थे।

(६) शोषण—प्रबन्ध अभिकर्त्ता विभिन्न ढङ्गों से कम्पनियों का शोषण करते हैं। प्रथम तो, इन लोगों की कम्पनी की व्यवस्था सम्बन्धी समस्त आन्तरिक बातों

का ज्ञान रहता है, जोकि अशधारियों को नहीं होता, अतः वे आन्तरिक व्यवस्था में ऐसा परिवर्तन करते हैं कि जिसमें केवल इनको ही लाभ होता है, अन्य अशधारियों को तो उसकी हवा भी नहीं लगती। अपने स्वार्थ को मिट्ट करने के लिए ही वे लाभान्ना की दर कम या अधिक करत रहते हैं। दूसरे, प्रबन्ध अभिकर्त्ता अपने पारिश्रमिक के लिए जो अनुभव करत हैं वे अनुचित एवं व्यायविच्छ होने हैं। ये निम्न प्रकार के विभिन्न रूपों में पारिश्रमिक लेत रहते हैं — व्यक्तिगत भत्ता, उत्पादन पर कमीशन, बच्चे माल के अग्र पर कमीशन, निर्मित माल के विक्रय पर कमीशन, लाभ पर कमीशन, अन्य विशेष कमीशन तथा कार्यालय भत्ता आदि। इस प्रकार कम्पनी के लाभ का एक बहुत बड़ा भाग जिसे 'लेन का भाग' (Lion's Share) कह सकते हैं प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं की जेब में जाता है एवं भूतन जाउन विचारे अशधारियों को जाती है। तीसरे, कभी कभी ये लोग कम्पनी के धन को भी व्यक्तिगत कार्यों में प्रयोग कर लेते हैं। चाल लेल (Current A/c.) को खात द्वारा वे लाभ कम्पनी का धन पर्याप्त मात्रा में ऋण लेकर अपना काम चलाया करते हैं। चौथे, प्रबन्ध अभिकर्त्ता बहुधा कम्पनी के लाभ को लाभान्ना के रूप में बिनरख न करके कम्पनी के कार्यों में लगा देते हैं और अन्य लोगों को दिखाने के लिए कम्पनी की कार्यशीलता बढ़ जाती है। कभी कभी भवन निर्माण और मशीनरी के अग्र में रुपया लगा देते हैं। यह विस्तार चाहे अनुचित भले ही हो, किन्तु ये कार्यालयता का आडम्बर करने के निचे ऐसी रचना करते रहते हैं।

( ७ ) किन्हीं किन्हीं प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं ने अपने दिये हुए ऋण को ऋण-पत्रों में परिवर्तित कर लिया और इस प्रकार सत्थायें उनके हाथ में पहुँच गईं। वेचारे अशधारियों की वह पूँजी जो उन्होंने कम्पनी में लगाई थी, उनके हाथ में चली गई।

( ८ ) कम्पनियों की सत्था में लगातार वृद्धि में प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं की सत्था में भी बरमाती नदी के पानी की भाँति वृद्धि होने लगी है। नये प्रबन्ध अभिकर्त्ता गृह पुराना की भाँति अनुभवी, योग्य और साधन सम्पन्न भी नहीं हैं, जो सुन्दर सेवायें कर सकें, जैसी कि इन पद्धति के अन्तर्गत अब तक होती रही है।

प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं पर अंतर्निहित नियन्त्रण—

सन् १९१३ के कम्पनी अधिनियम में प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं की स्थिति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई थी। तत्पश्चात् इस प्रणाली का इतना पतन हुआ और प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं की शक्तियों का इतना दुरुपयोग किया गया कि सन् १९३६ के कम्पनी (संशोधन) अधिनियम में विशेष व्यवस्थाओं की आवश्यकता अनुभव की गई। सन् १९३६ के संशोधन ने आरम्भ में ही कुछ ऐसी व्यवस्थायें की हैं, जिससे अशधारि अधिक सतक तथा सावधान रहेंगे। इस सम्बन्ध में निम्न व्यवस्थायें की

गई—(अ) कम्पनी के प्रविवरण में प्रबन्ध अभिकर्त्ता के साथ किए गए समझौते की शर्तों का दिखाना अनिवार्य किया गया, प्रबन्ध अभिकर्त्ता के सामेंदारों के नाम तथा उस हित की प्रकृति, जो कम्पनी के संचालकों को मॅनेजिंग एजेंसी में है, साफ-साफ दिखाना आवश्यक कर दिया गया और (आ) प्रबन्ध अभिकर्त्ता के लिए समुचित लेखों का रखना तथा विस्तृत चिट्ठों एवं साम-हानि खातों का प्रकाशन आवश्यक कर दिया गया। किन्तु फिर भी स्थिति में कोई सन्तोषजनक सुधार नहीं हुआ। प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं ने शोधण का मार्ग निकाल लिया, अतः बिबदा होकर सरकार को सन् १९५१ में एक ऑर्डिनेन्स जारी करना पड़ा। ऑर्डिनेन्स के द्वारा भारतीय कम्पनी अधिनियम सन् १९१३ की धारा ८७ में संशोधन किया गया और यह व्यवस्था की गई कि प्रबन्ध अभिकर्त्ता द्वारा अपने अधिकारों को सौंपना उस समय तक बंध न होगा, जब तक कि कम्पनी तथा केन्द्रीय सरकार उसे स्वीकार न कर लें। सन् १९५६ से बैंकिंग कम्पनियों के लिए प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति करना अवैध घोषित कर दिया गया है।

**वर्तमान स्थिति—**

कम्पनी अधिनियम सन् १९५६ के अनुसार 'प्रबन्ध अभिकर्त्ता से आशय उस व्यक्ति, फर्म या समामेलित सत्था से है, जो किसी कम्पनी के साथ हुए ठहराव या उसके पार्षद सीमानियम अथवा अन्तनियमों के अन्तर्गत कम्पनी के सम्पूर्ण या अधिकांश कार्यों के प्रबन्ध करने का इस अधिनियम के आदेशों के आधीन अधिकारी है, अर्थात् अब प्रबन्ध अभिकर्त्ता संचालक सभा के प्रशासनिक नियन्त्रण तथा निरीक्षण के आधीन कार्य करता है। नए कम्पनी अधिनियम द्वारा इस पद्धति पर निम्न नियन्त्रण लगा दिए गए हैं :—

(१) नियुक्ति एवं अवधि—कोई भी कम्पनी, केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना अपना कार्य प्रबन्ध चलाने के लिए प्रबन्ध अभिकर्त्ता की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति नहीं कर सकती। १ अप्रैल सन् १९५६ को विद्यमान सभी प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के पद १५ अगस्त सन् १९६० तक अवश्य समाप्त हो जाएंगे, जब तक उनकी पुनर्नियुक्ति न हो जाय। १५ अगस्त सन् १९६० के बाद कोई व्यक्ति एक समय में १० से अधिक कम्पनियों का प्रबन्ध अभिकर्त्ता नहीं रह सकता। जिस अवधि के लिए प्रबन्ध अभिकर्त्ता नियुक्त किए जा सकते हैं, वह प्रथम नियुक्ति की दशा में १५ वर्ष से और बाद की नियुक्तियों के लिए १० वर्ष से अधिक नहीं हो सकती।

(२) पारिश्रमिक—मॅनेजिंग एजेंटों को निम्नलिखित दर से क्षमोशन दिया जाता है—

पहले १० लाख रुपये अथवा इसके प्रमाण पर

१० प्रतिशत

अगले १० लाख रुपये अथवा इसके प्रमाण पर

६ प्रतिशत

अगले १० लाख रुपये अथवा इसके प्रमाण पर	८ प्रतिशत
अगले १० लाख रुपये अथवा इसके प्रमाण पर	७ प्रतिशत
अगले १० लाख रुपये अथवा इसके प्रमाण पर	६ प्रतिशत
अगले २५ लाख रुपये अथवा इसके प्रमाण पर	५ १/२ प्रतिशत
अगले २५ लाख रुपये अथवा इसके प्रमाण पर	५ प्रतिशत
और १ करोड़ रुपये से ऊपर कितनी भी रकम पर	४ प्रतिशत

अभिकर्त्ता को कोई भी कार्यालय भत्ता नहीं दिया जाएगा। हाँ, उसके द्वारा कम्पनी के निमित्त किए गए खर्चों का भुगतान अवश्य होगा।

(३) कोषों का अन्तर्विनिर्देश—कोई कम्पनी (जिसे यहाँ विनियोगिता कम्पनी कहा गया है), एक ग्रुप के अन्तर्गत किसी सम्मिलित सस्था के प्रश या श्रृंखला-पत्रों को नहीं खरीद सकती।

(४) अन्य आदेश—कोई प्रबन्ध अभिकर्त्ता अपने पद का तभी हस्तान्तरण कर सकता है जबकि कम्पनी की साधारण सभा तथा केन्द्रीय सरकार दोनों ही की अनुमति प्राप्त हो जाय। अब प्रबन्ध अभिकर्त्ता का पद पंरुक नहीं है। कोई भी प्रबन्ध अभिकर्त्ता अपने द्वारा व्यवस्थित अन्य कम्पनियों को श्रृंखला नहीं दे सकता। प्रबन्ध अभिकर्त्ता अथवा दो (यदि कुल सचालक ५ से अधिक है) अथवा एक (यदि सचालकों की कुल संख्या ५ से कम है) सचालक से अधिक की नियुक्ति नहीं कर सकता। कोई भी प्रबन्ध अभिकर्त्ता अपनी प्रबन्धित कम्पनी के समान और उससे प्रत्यक्ष स्पर्धा करने वाला कोई अपना व्यापार नहीं कर सकेगा, जब तक कि वह प्रबन्धित कम्पनी विदेश प्रस्ताव द्वारा उसे ऐसा करने की आज्ञा न दे।

**प्रबन्ध-अभिकर्त्तृत्व पद्धति के पक्ष में विचार—**

अगस्त सन् १९५५ में लोक सभा में कम्पनी लॉ बिल पर बड़ी बहस हुई और अधिकांश वक्ताओं ने प्रबन्ध अभिकर्त्ता पद्धति की कड़ी घालोचना की थी। स्नय कांग्रेस दल के आलोचकों ने इस पद्धति के उन्मूलन की माँग की और इस सम्बन्ध में एक निश्चित समय निर्धारित कराने का प्रयास किया। वे 'सेक्रेटरी एवं कोषाध्यक्ष' की नई व्यवस्था से भी सन्तुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनके विचार में इसमें आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण नहीं एक सकता। दूसरे शब्दों में, वे कम्पनियों के प्रबन्ध पर अधिक नियन्त्रण रखना चाहते थे, किन्तु सरकार ऐसा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इससे व्यक्तिगत उपक्रम को घटका पहुँचता और पंच वर्षीय योजना की सफलता ख़टाई में पड़ जाती। तत्कालीन वित्तमन्त्री श्री देवामुख ने प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के पक्ष में निम्न दलीलें प्रस्तुत की—

(१) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में औद्योगिक विकास के लिए व्यक्तिगत उपक्रमों पर बहुत सीमा तक निर्भरता रखी गई है। अब बीच में ही प्रबन्ध,

अभिकर्ता पद्धति को किसी उद्योग विरोध में रखने की घोषणा से व्यक्तिगत उपक्रम को बड़ा धक्का लगेगा और वह अपने दायित्व ठीक तरह से नहीं निभा सकेगा ।

(२) स्वतन्त्रता के पूर्व जब प्रबन्ध अभिकर्ता पद्धति के विरोध में आवाज उठाई गई थी तो अधिकान व्यापार विदेशियों के हाथ में था, किन्तु अब परिस्थिति बदल गई और व्यापार देशवासियों के हाथ में आ गया है । फिर अनेक दाप प्रबन्ध अभिकर्ता पद्धति के ऐसे हैं जोकि उन्हीं परिस्थितियों में, सचानक समा या मेकेंटरी एव कोषाध्यक्ष अथवा अन्य प्रबन्ध व्यवस्था के अन्तर्गत भी उत्पन्न हो सकते हैं । यही नहीं, आज अनेक ऐसे प्रबन्ध अभिकर्ता भी हैं जो अपने ज्ञान और अनुभव से देश को लाभ पहुँचाना चाहते हैं ।

(३) हमें प्रबन्ध अभिकर्ताओं के कार्यों का लेखा-जोखा केवल समापित कम्पनियों की सख्या से ही नहीं लगाना चाहिए, बरन् नई रजिस्टर्ड कम्पनियों को भी विचार में लेना चाहिये । पुढोत्तर काल में कम्पनियों की सख्या दुगुनी से अधिक हो गई है और प्राप्त पूँजी भी पढ़ने से तिगुनी हो गई है, जोकि देश के हित में है ।

(४) यह कहना असत्य है कि कम्पनियों के प्रवर्धन और अर्थ प्रवर्धन में प्रबन्ध अभिकर्ताओं का अधिक भाग नहीं । १,७२० कम्पनियों की परीक्षा से यह पता लगा है कि लगभग १३.६% अर्ध पूँजी एव २६.६५% ऋण एव अग्रिम प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा प्राप्त हुआ था । यदि प्रबन्ध अभिकर्ताओं को हटा दिया जाय तो इतने वित्त की व्यवस्था सरकार कहाँ तक करेगी ?

(५) जहाँ तक आर्थिक सत्ता के वितरण हाथों में केन्द्रीयकरण का प्रश्न है, यह दाप केवल प्रबन्ध अभिकर्ता पद्धति का ही हो, ऐसी बात नहीं । उदाहरण के लिये, अमेरिका में भी, जहाँ कि ऐसी पद्धति प्रचलित नहीं है, आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण की समस्या पाई जाती है । फिर छोटे ही (लगभग ३३) प्रबन्ध अभिकर्ता देश में ऐसे हैं जिनके पास १० या अधिक कम्पनियों का प्रबन्ध है ।

(६) प्रबन्ध अभिकर्ता देश की व्यवसायिक वृद्धि के प्रतीक हैं । यदि केवल नियन्त्रण द्वारा इनका सहयोग देश के अधिक आर्थिक विकास में प्राप्त हो सकता है तो फिर इनके उन्मूलन की हिसाबक नीति अपनाना स क्या लाभ ?

(७) प्रबन्ध अभिकर्ताओं का पुर्नवार शुद्ध लाभ का १०% निर्धारित किया गया है, जोकि अधिक नहीं है । प्रबन्ध मंचालकों का वेतन के औत्तरीय शुद्ध लाभ का ५% मिलता है और मेकेंटरी एव कापाध्यक्ष का ७.३% निर्दिष्ट किया गया है । इनका तुलना में प्रबन्ध अभिकर्ता का १०% पुर्नवार अधिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रबन्ध अभिकर्ता विभिन्न प्रकार का अनुभव रखते हैं और वित्त की व्यवस्था भी

करते हैं, जबकि सचालक और सेक्रेटरी एव कोषाध्यक्ष इतनी चहुँमुखी योग्यता नहीं रखते और न ही उनको वित्त व्यवस्था का भार उठाना पड़ता है। अभी तक प्रबन्ध अभिकर्ताओं को मिलने वाला पुरस्कार औसतन शुद्ध लाभ का २७% था, यतः पुरस्कार में इतनी बड़ी कमी करना वास्तव में गरीब सफलता है, जोकि समाज के समाजवादी दावे के अनुकूल है।

(८) यदि किसी विशेष उद्योग या व्यापार में प्रबन्ध अभिकर्ता रखना उचित न समझा जाय तो भी अन्य क्षेत्रों में, जहाँ प्रवर्तन एव अर्थ प्रबन्धन की आवश्यकता है, उस पद्धति का लाभ बयो न उठाया जाय, जोकि भूतकाल में उपयोगी थी और भविष्य में उपयोगी होगी।

**प्रबन्ध-अभिकर्ता पद्धति का भविष्य—**

कम्पनी अधिनियम सन् १९५६ का उद्देश्य प्रबन्ध अभिकर्ता पद्धति को निम्न लिखित ढंग से धीरे धीरे खत्म करना है —

(१) १५ अगस्त सन् १९६० तक तो इस पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, किन्तु तत्पश्चात् इसका महत्व कम होने लगेगा। कोई भी प्रबन्ध अभिकर्ता १० से अधिक कम्पनियों का प्रबन्ध नहीं कर सकेगा। १ अप्रैल सन् १९५६ के बाद किसी भी समय केन्द्रीय सरकार यह सूचित करने का अधिकार रखती है कि एक विशेष उद्योग या व्यापार में सलग्न सभी कम्पनियाँ कोई प्रबन्ध अभिकर्ता नहीं रख सकेंगी। इस सूचना का प्रभाव यह होगा कि जिन कम्पनियों में सूचना की तिथि पर प्रबन्ध अभिकर्ता नहीं थे वे भविष्य में प्रबन्ध अभिकर्ता नहीं रख सकेंगे और जिन कम्पनियों में प्रबन्ध अभिकर्ता हैं उनका कार्यकाल निर्दिष्ट तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने पर या १५ अगस्त सन् १९६० में, जो भी तिथि बाद में पड़े, समाप्त हो जायगा।

(२) वे कम्पनियाँ जो उपरोक्त नियम में नहीं आती, तब तक प्रबन्ध अभिकर्ता नियुक्त नहीं कर सकेंगी जब तक केन्द्रीय सरकार से विशेष स्वीकृति प्राप्त न हो जाय और केन्द्रीय सरकार ऐसी स्वीकृति निम्न बातों का संतोष प्राप्त होने पर ही देगी :—

- (अ) कि कम्पनी को प्रबन्ध अभिकर्ता नियुक्त करने की अनुमति देने में जन-हित को नुकसान नहीं पहुँचेगा।
- (आ) कि प्रस्तावित प्रबन्ध अभिकर्ता एक उपयुक्त एव योग्य व्यक्ति है।
- (इ) कि उसके ठहराव की शर्तें उचित हैं, और
- (ई) कि प्रबन्ध अभिकर्ता ने उन तीन शर्तों को पूरा कर दिया है जो केन्द्रीय सरकार ने उसके लिए निश्चित की हो।



इस प्रकार सन् १९६० के पश्चात् प्रबन्ध अभिकर्ता पद्धति का भविष्य बड़ा अनिश्चित है और बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि इन पांच वर्षों की अवधि के भीतर प्रबन्ध अभिकर्ताओं का आचरण कसा रहता है। यदि उनका आचरण समाजवादी ढांचे के अनुसार रहता है यदि उन पर लगाये प्रतिबंधों के फलस्वरूप इस पद्धति के सब मुख्य दोष दूर हो जाते हैं और आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण नहीं होता तो उनके बने रहने की सम्भावनाएँ बढ़ जायेंगी यद्यपि सिद्धांततः प्रबन्ध अभिकर्ताओं का उन्मूलन उचित है किन्तु व्यावहारिक दृष्टिकोण से उनके उन्मूलन की समय-सीमा निश्चित कर देना बुद्धिमानी नहीं होगी।

**मैनजिंग एजन्सी पद्धति की उपयोगिता पर अनुसंधान परिपद का मत—**

भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य मण्डल के आग्रह पर राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान परिपद ने मैनजिंग एजन्सी पद्धति के विभिन्न पहलुओं एवं उसकी उपयोगिता का अध्ययन करके सम्मति प्रकट की है कि देश के आर्थिक विकास में मैनजिंग एजन्सी पद्धति महत्वपूर्ण भाग प्रदा कर रही है इसलिये इस पद्धति को समाप्त करने के लिये कोई वास्तविक कारण नहीं दिखाई देता है।

परिपद का कहना है कि देश की बदलती हुई परिस्थितियों का दृष्टि में रखते हुए इस पद्धति में समय-समय पर आवश्यक परिवर्तन परिवर्द्धन एवं सुधार किए जा सकते हैं। कुछ बेईमान व्यक्तियों द्वारा इस पद्धति का दुरुपयोग करके अनुचित लाभ उठाना इस बात का प्रमाण नहीं है कि यह पद्धति ठीक नहीं है इसलिए इसे समाप्त कर दिया जाय।

परिपद के महासचालक डा० पी० एस० लोकराथन ने परिपद द्वारा किए गए शोध के परिणाम की पत्र प्रतिनिधियों को बताया और कहा—यह पद्धति निजी क्षेत्र को विनोदित दो दिशाओं में सक्रिय योगदान दे रही है।

(१) यह अपने आय खोता तथा बचत से प्रबंधकृत कम्पनियों की पूँजी की व्यवस्था करती है और

(२) अपने प्रबंध में कम्पनियों के उद्योगों का बहुमुखी विस्तार कर रही है।

गोध में कहा गया है कि भारतीय पूँजी बाजार में जो कमी है वह मैनजिंग एजन्ट औद्योगिक वित्तीय योगदान कर पूरा करता है क्योंकि भारतीय ग्रन्थ व्यवस्था की प्रगति के साथ साथ वित्तीय संस्थाओं का विकास नहीं हुआ है। उस कमी को मैनजिंग एजन्ट पूरा कर रहे हैं। जबकि औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों के साथ भारत में पूँजी विनियोजन ट्रस्ट नहीं है, जो अल्प बचत की प्राप्त राशि को उद्योगों में लगाय, कम्पनी कानून में सरकार को यह अधिकार मिल जान से औद्योगिक क्षेत्र में एक

अनिश्चितता फैल गई है कि सरकार किसी भी उद्योग एवं व्यवस्था में मैनेजिंग एजेंसी पर रोक लगा सकती है। सरकार एक नीति बनाकर उसे दूर कर सकती है। शोध में सरकार द्वारा मैनेजिंग एजेंसियों के पारिश्रमिक की दर घटा देने पर सहमति एवं उनके बाय काल के विषय में विमति प्रकट की गई है। मैनेजिंग एजेंसी पद्धति पर सबसे बड़ा आरोप अधिकार एक सत्ता के केन्द्रीयकरण का है। परन्तु अध्ययन से पता चलता है कि यूरोप के देशों में यह पद्धति बहुत अधिक प्रचलित है और वहाँ इस प्रकार का केन्द्रीयकरण नहीं हुआ। भारत में एकाधिकार की ओर प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि बहुत से उद्योग धन्ये इस पद्धति के दायरे के बाहर स्थापित हो रहे हैं।

### (६) विशिष्ट अर्थ-संस्थाएँ

विशिष्ट अर्थ संस्थानों का विस्तृत परिचय अगले अध्यायों में दिया गया है।

### STANDARD QUESTIONS

1. Describe the existing system of Industrial Finance in India. Offer your own suggestions for improving it and say what is at present being done in this connection
2. Write critical notes on (a) Issue of Shares, (b) Public Deposits and (c) Issue of debentures as sources of industrial finance.
3. Discuss carefully the reasons for the unpopularity of debentures in India
4. Discuss the defects of the Indian Commercial Banks in providing finance to Indian industries. How can they be made more useful ?
5. Discuss the services of the Managing Agents in providing finance to Indian industries. Are there any defects in this system ?
6. What provisions have been made in the Indian Companies Act, 1956, to remedy the defects of the Managing Agency System ?
7. Write an essay on the present position and future of the Managing Agency system.

# औद्योगिक अर्थ प्रवन्धन के लिए विशिष्ट संस्थान (I)

(Special Institutions for the financing of Industries)

## औद्योगिक अर्थ-निगम

औद्योगिक अर्थ निगम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि—

प्रथम महायुद्ध के बाद भारत सरकार का ध्यान देश में उद्योगों की उन्नति की ओर गय और तब से पूँजी की कमी बहुत खटकन लगी। पिछली ३०-३५ वर्षों से (और विशेषतः सन् १९१८ के बाद) जब औद्योगिक कमीशन न अपनी रिपोर्ट में देश के उद्योगों की आर्थिक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया तो इस कठिनाई को हल करने के लिये गम्भीरतापूर्वक विचार किया जान लगा। औद्योगिक कमीशन का भी यही मत था कि उद्योगों को आर्थिक सहायता देने के लिये विशेष संस्थाओं का आवश्यकता है। सन् १९३१ में केन्द्रीय महाजनी जाच समिति ने भी देश में बढ़ते हुए औद्योगीकरण के लिए जिससे भविष्य में देश का विकास होने की आशा है, पूँजी की आवश्यकता पर अधिक जोर दिया। इन उद्योगों में लगन वाली आवश्यक पूँजी की अवधि की दृष्टि से तीन भागों में बाटा जा सकता है—(अ) दीर्घकालीन, (आ) मध्यकालीन और (इ) मध्यकालीन, अतः इस कमी को पूरा करने के लिये जल्दी ही आवश्यक कदम उठाने की सिफारिश की गई किन्तु खद की बात है कि इन सिफारिशों का कोई भी सतोषजनक परिणाम नहीं निकला। इसी प्रकार वैदेशिक पूँजी कमेटी (External Capital Committee) ने सन् १९२४ में देश की औद्योगिक वित्त समस्याओं को हल करने के लिए विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की थी किन्तु कई राजनैतिक व आर्थिक कारणों से उक्त प्रस्तावों को उस समय कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

विदेशों में उद्योगों की आर्थिक सहायता करने के लिये कई विशिष्ट संस्थाएँ हैं। उदाहरणार्थ, जर्मनी में औद्योगिक संस्थाओं की अर्थ पूर्ति के लिए औद्योगिक बैंक है। योरोप के अन्य देशों में भी (जैसे—बेल्जियम फ्रांस इटली आदि में) इस प्रकार की संस्थाओं ने उन देशों के उद्योगों को आर्थिक सहायता पहुँचाकर उन्नति के पथ पर अग्रसरित किया है। जापान की आर्थिक स्थिति भी हमारे देश के समान ही थी। वहाँ की

जनता भी गरीब थी, अतः वहाँ पूँजी की कमी रहा करती थी, किन्तु सन् १९०२ में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित की गई, जो आज तक उस देश के उद्योगों को आर्थिक सहायता पहुँचा रही है। सन् १९२६ ३० में, जबकि सारे ससार में मन्दी का प्रभाव था, यदि इन सस्थाओं ने जापान के उद्योगों को आर्थिक सहायता न दी होती तो ये छोटे छोटे सभी उद्योग उस समय समाप्त हो जाते।

अमेरिका के बड़े-बड़े प्रमण्डलों को आर्थिक सहायता देकर उनकी उन्नति करने का श्रेय उस देश के अधिकारियों को है। सन् १९३४ के पश्चात् इन सस्थाओं के कार्य में और भी अधिक उन्नति पाई जाती है। ये सस्थाएँ न केवल सक्रिय पूँजी की ही सहायता करती हैं अपितु अग्रिम राशि देकर उनकी अन्य आर्थिक कठिनाइयों को भी दूर करती हैं।

इंग्लैंड में भी वहाँ के अधिकारियों ने अपनी पुरानी परिपाटी 'व्यापारिक ट्रिस्ट-कोम्प' त्याग कर अपना संकुचित कार्य क्षेत्र व्यापक बना कर उद्योगों की प्रत्यक्ष सहायता करने का श्रेय प्राप्त किया है। आज हम देखते हैं कि वहाँ के मोहे तथा फोलाद मूल तथा बम इत्यादि के उद्योगों को कान्ती आर्थिक सहायता पहुँचाई जा रही है। सन् १९३० में 'बैंकर्स इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कम्पनी' की स्थापना उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ही की गई थी। इसी प्रकार 'फाइनेंस कॉरपोरेशन फॉर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड' एवं 'इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड' नामक दो सस्थाओं की स्थापना भी लघुमाप तथा दीर्घमाप उद्योगों की आर्थिक सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से की गई है।

ऑस्ट्रेलिया में भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वहाँ के 'कॉमनवेल्थ बैंक' ने औद्योगिक अर्थ प्रबन्ध का एक स्वतन्त्र विभाग बैंक के अधीन ही खोल दिया है। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य उस देश के उद्योगों की सहायता के लिए दीर्घकालीन ऋण देना है।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि विदेशों में उद्योगों की आर्थिक सहायता के हेतु नई नई सस्थाएँ स्थापित की गई हैं, किन्तु हमारे देश में ऐसे प्रयत्नों की कमी रही है। भूतपूर्व प्रस्तावों से प्रेरित होकर व वर्तमान परिस्थितियों से विवश हो, माननीय आर० के० शरणमुख चट्टी ने भारतीय संसद में औद्योगिक अर्थ-प्रमण्डल की स्थापना के लिए एक बिल प्रस्तुत किया। २७ मार्च सन् १९४८ को गवर्नर जनरल ने इस बिल पर स्वीकृति मिली तथा १ जुलाई सन् १९४८ से इस कॉरपोरेशन का कार्य प्रारम्भ हुआ।

**औद्योगिक अर्थ-निगम के उद्देश्य तथा अधिकार—**

कॉरपोरेशन का मुख्य उद्देश्य उद्योगों की दीर्घ एवं मध्यकालीन आर्थिक सहायता प्रदान करना है। हमारे देश के अधिकारियों भी इस प्रकार की सहायता प्रदान

करते हैं, किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि प्रमण्डल अधिकोपो से प्रतियोगिता करना चाहता है अथवा उनको इस कार्य से विचलित करना चाहता है। प्रमण्डल का उद्देश्य आर्थिक क्षेत्र में अधिकोपा की सहायता करना है, जिससे ये दोनों सस्थायें मिलकर देश में पूँजी की कमी को दूर कर उद्योगों की उत्थिति में सहायक हो। अधिकोपो का मुख्य कार्य तो उद्योग को अल्पकालीन सहायता और प्रमण्डल का कार्य लम्बी अवधि के लिए या मध्यम समय के लिए आर्थिक सहायता देना है। विकास का अर्थ केवल नवीन उद्योगशालायें खोलना नहीं है। नई उद्योगशालायाँ के स्थापन के साथ साथ आज भारत में चालू उद्योगों के युक्तिमगत विवेकीकरण की आवश्यकता भी है। औद्योगिक सस्थायों की प्राप्त पूँजी का लगभग सारा भाग मशीन, भूमि व अन्य औजारों के खरीदने में ही खर्च जाना है और समय पर कार्यशील पूँजी की बड़ी भारी कमी पड़ जाती है जिसका परिणाम उद्योग की सफलता के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, इसलिए कॉरपोरेशन का प्रधान उद्देश्य चालू व नवीन सावजनिक कम्पनियों को मध्यकालीन व दीर्घकालीन आर्थिक सहायता प्रदान करना है, किन्तु वे उद्योग जो बुनियादी उद्योगों की श्रेणी में हैं अथवा जिनका राष्ट्रीयकरण हो चुका है, इस साख सहायता के भागीदार नहीं बन सकते। इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रमण्डल केवल उन्हीं उद्योगों को आर्थिक सहायता देगा, जो सावजनिक अथवा लोक सीमित होंगे अथवा जो महकारिता के सिद्धान्तानुसार कार्य कर रहे हों। यह आर्थिक सहायता केवल उन क्षेत्रों तक सीमित रहेगी जिनमें प्रमण्डल सक्षम लागू होता है, अतएव स्पष्ट है कि अलोक सीमित प्रमण्डल तथा साभेदारी सस्थायें प्रमण्डल द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता का लाभ न उठा सकेंगी। प्रमण्डल ने अपन द्वितीय तथा तृतीय वार्षिक वृत्त लेख में सूचित किया है कि जनता प्रमण्डल के उपयुक्त कार्य क्षेत्र को भली प्रकार नहीं समझ सकी है, अतः अनेक प्रार्थना पत्रों को बिना विचारे ही वापस करना पड़ता है।

### औद्योगिक अर्थ निगम के कार्य (Functions of I. F. C)---

(१) किसी भी सीमित प्रमण्डल को एक सहकारी समितियों को वस्तुओं का उत्पादन अथवा प्रिया कलाप (Processing) करता है, खान, बिजली अथवा अन्य किसी शक्ति का उत्पादन एवं वितरण करता है। अधिक से अधिक २५ वर्ष की अवधि के लिए निगम ऋण दे सकता है।

(२) औद्योगिक कम्पनी के अंश तथा ऋण पत्रों का अभिगोपन करना, किन्तु अभिगोपन समझौते के अनुसार निगम को चाहिए कि ७ वर्ष की अवधि में उन अंशों अथवा ऋण पत्रों को जनता को बेच दे।

(३) अर्थ निगम औद्योगिक कम्पनियों के ऋण पत्रों के ब्याज तथा मूल

राशि के भुगतान की गारंटी दे सकता है यदि ऋण पर धुले बाजार में बेचे गये हों और उनकी अवधि २५ वर्ष से अधिक न हो। इस कार्य के लिए अथ निगम कमीशन लेन का भी अधिकारी है।

(४) यदि किसी उद्योग को विदेशी मुद्रा में ऋण लेन की आवश्यकता हो तो अथ निगम के द्वारा सरकार की अनुमति के बाद पुनसंरुद्धन और विकास की अंतरराष्ट्रीय बैंक (I. B. R. D.) से अथवा अन्य विदेशी स्रोतों से ऋण ले सकता है और इस प्रकार सुविधा के लिए अथ निगम के पास जो भी सम्पत्ति जमाने के लिए हो उसे वह देगी सेनदारों के पास रहन रख सकता है।

(५) अथ निगम को ऋण लेने वाले उद्योग की संचालक सभा में अपना प्रतिनिधि मनोनीत करने का तथा ऋण की शर्तों को भङ्ग करने पर उद्योग को अपने नियंत्रण में लेने का अधिकार है।

(६) अथ निगम ऋण लेने वाले उद्योग को तात्त्विक सलाह देने के लिये सार्वजनिक सलाहकार समिति नियुक्त कर सकता है।

(७) अथ निगम का संचित कोष (Reserve Fund) जब तक दस पूंजी के बराबर न हो जाय एवं लाभ पूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार से प्राप्त राशि का भुगतान न हो जाय तब तक यह २३% से अधिक वाभांश नहीं दे सकता परन्तु किसी भी वर्ष ५% से अधिक लाभांश नहीं दे सकता और यह लाभ इन के बाद जा राशि बचेगी उस पर केन्द्रीय सरकार का भाग होगा।

(८) अथ निगम को अन्य कम्पनियों की भांति आय कर तथा प्रतिरिक्त कर (Super tax) भी देना होगा किंतु केन्द्रीय सरकार से गारंटी लाभ की पूरा करने के लिए जो राशि मिलेगी वह कर मुक्त होगी।

(९) केन्द्रीय सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना अथ निगम को अपना समापन करने का अधिकार नहीं है।

(१०) अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निगम अन्य कार्य भी कर सकता है।

(११) अथ निगम किसी एक उद्योग को अपना दस पूंजी के १०% या ५० लाख रुपये (जो राशि कम हो) से अधिक ऋण नहीं दे सकता और न किसी उद्योग के अंश को ही खरीद सकता है।

ऋण देने की शर्तें—

अपने उद्देश्यानुसार अथ निगम किसी सीमित पब्लिक कम्पनी तथा सहकारी समिति को निम्न शर्तों पर ऋण दे सकता है—

(१) ऋण मुख्यतः स्थायी एवं अचल सम्पत्ति खरीदने के लिये अचल सम्पत्ति जम—भू-मुहाडि यंत्र औजार आदि, की प्रथम रहन (First Mortgage) पर

दिया जाता है। यह कम्पनी कायशील पूँजी के लिए बच्चे पक्के माल के आधीन ऋण न देगी, क्योंकि यह काम व्यापारिक बँकों का है। अर्थ निगम उनके साथ प्रतियोगिता नहीं करना चाहता।

(२) दिये हुए ऋण का समुचित प्रबन्ध एवं व्यय हो रहा है या नहीं इस बात को निश्चित करने के लिये ऋण लेने वाली कम्पनी के संचालकों से उनकी व्यक्तिगत स्थिति में वैयक्तिक तथा सामूहिक जमानत ली जाती है, जिससे उद्योग का प्रबन्ध समुचित रीति से हो सके।

(३) अर्थ निगम को उद्योग की संचालक सभा में दो संचालकों की नियुक्ति करने का अधिकार है, जिससे वे संचालक उद्योग के प्रबन्ध का निरीक्षण करते हैं तथा यह भी देखते हैं कि उसका प्रबन्ध अर्थ निगम के हित में हो रहा है या नहीं।

(४) औद्योगिक कम्पनी को उन्नतिशील वर्षों में होने वाला लाभ साभाश देने में ही न बाँटा जाय, इसलिए जब तक ऋण का भुगतान न हो तब तक वह उद्योग ६% से अधिक लाभांश न दे सकेगा। हाँ, दोनों की सहमति से इस दर में परिवर्तन सम्भव है।

(५) ऋण भुगतान की अवधि माधारणतः १२ वर्ष है, परन्तु अभी तक जो अधिकतम अवधि दी गई है वह १५ वर्ष है। इस शर्त के अतिरिक्त ऋण भुगतान की अवधि ऋण लेने वाली कम्पनी के व्यापारिक स्वरूप और उसके भविष्य के अनुमान निश्चित की जाती है।

(६) ऋण का भुगतान सामान्यतः समान प्रभागों (Equal Instalment) में होता चाहिये, परन्तु ये प्रभाग कितने होंगे, यह दोनों की सहमति से निश्चित होता है।

(७) अर्थ निगम के पास रहन रखी हुई सम्पत्ति का भाग, साम्प्रदायिक बलह, विद्रोह आदि की सुरक्षा के लिए किसी अच्छे बीमा प्रमण्डल से बीमा कराना अनिवार्य है।

(८) जब उद्योग की ऋण दे दिया जाता है तो उसका उपयोग जिस कार्य के लिये ऋण लिया गया है उसी कार्य के लिये हो रहा है अथवा नहीं, यह देखने के लिये अर्थ निगम आवश्यक कदम उठाता है।

**निगम का प्रबन्ध—**

निगम का प्रबन्ध एक संचालक समिति द्वारा होता है, जिसकी सहायता के लिये एक शासकीय समिति (Executive Committee) और एक जनरल मनेजर भी होता है। संचालक समिति में कुल १२ सदस्य हैं, जो निम्नलिखित पद्धति से निर्वाचित अथवा मनोनीत होते हैं :—

- ( अ ) केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत— ३  
 ( आ ) रिजर्व बैंक द्वारा मनोनीत— २  
 ( इ ) अनुमूचित अधिकारियों द्वारा निर्वाचित— २  
 ( ई ) सरकारी अधिकारियों द्वारा निर्वाचित— २  
 ( उ ) उपयुक्त अधिकारियों के अलावा अशधारियों द्वारा निर्वाचित— २  
 ( ऊ ) प्रबन्ध सचालक, जिसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार ने की है— १

प्रबन्ध अथवा शासकीय समिति में ५ सदस्य हैं, जिनमें से प्रबन्ध सचालक तथा निर्वाचित सचालकों के निर्वाचित २ तथा मनोनीत सचालकों द्वारा निर्वाचित २ सचालकगण उद्योग, व्यापार तथा जनहित को सामने रखते हुए व्यापारिक सिद्धान्तों का पालन करेंगे, ऐसी उनसे आशा की जाती है। यदि सचालक समिति उचित समझे तो विभिन्न बातों के विचारार्थ सलाहकार समितियाँ नियुक्त कर सकती है। कॉरपोरेशन की सामान्य नीति का संचालन केन्द्रीय सरकार करेगी। केन्द्रीय सरकार को अन्य अशधारियों के अंशों को खरीदने का भी अधिकार है। ऐसे प्रय पर वह १०% से अधिक प्रब्याजि न देगी। केन्द्रीय सरकार को कॉरपोरेशन के ऋणों का, विनियोग का, प्रत्याभूति (Guaranteed) ऋणों का तथा समिगोपन के अनुबन्धों का परीक्षण करने का भी अधिकार है। इस प्रकार प्रमण्डल की कार्य प्रणाली पर केन्द्रीय सरकार का पूर्ण नियन्त्रण है।

#### पूँजी का इस्तेमाल—

कॉरपोरेशन की अधिष्ठत पूँजी १० करोड़ रुपये है जो ५,००० ह० के २०,००० अंशों में विभाजित है। अंशों की मूल राशि तथा २५ लाभांश की प्रत्याभूति केन्द्रीय सरकार ने दी है। इनमें से केवल १०,००० अंशों का ही निर्गमन किया गया है, शेष आवश्यकता के समय निर्गमित किये जायेंगे। इन अंशों का प्रय करने का अधिकार केवल केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक, अनुमूचित बैंक, बीमा कम्पनी, पूँजी लगाने वाल ट्रस्ट तथा इसी प्रकार की वित्त संस्थाओं को है, अतएव यह स्पष्ट है कि कॉरपोरेशन के शेयर खरीदने व पूँजी में योग देने का अधिकार किसी व्यक्ति विशेष को नहीं है।

#### लाभ वितरण—

प्रमण्डल के नियमों में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कॉरपोरेशन एक बचत कोष रखेगा। मन्देहाभ्युद कृष्ण, सम्पत्ति का मूल्य ह्रास तथा इस प्रकार के अन्य व्यापारिक घाटों के लिए निश्चिन करने के बाद यदि कुछ लाभ शेष बचे तो उसे कॉरपोरेशन अशधारियों में बाँट देगा, किन्तु इस भाग की दर उस समय तक सरकारी गारण्टी से अधिक नहीं हो सकती, बल्कि यह कि उक्त बचत कोष का वह कॉरपोरेशन की प्राप्त पूँजी के बराबर न हो जाय।



निगम द्वारा किए गये कामों का व्यौरा—

औद्योगिक अर्थ निगम ने ३० जून सन् १९५६ को ११ वर्ष पूर्ण किए और इन ११ वर्षों में निगम ने अनेक प्रकार की औद्योगिक सस्याओं को ऋण दिए हैं। निगम के पास इन ११ वर्षों में जितने आवेदन पत्र आए एवं जिन्हें ऋण स्वीकृत होने पर तथा जिन आवेदन-पत्रों को अस्वीकार किया गया, उसका व्यौरा इस प्रकार है :—

### तालिका I

(हजार रुपये में)

क्रमांक	विवरण	क्रमांक	३० जून सन् १९५७ तक	क्रमांक	३० जून सन् १९५८ तक	क्रमांक	३० जून सन् १९५९ तक
१.	प्राप्त आवेदन-पत्र	६७	२१,३६,२५	४८	१४,८८,५०	२६	११,१६,५७
२.	स्वीकृत आवेदन पत्र	५१	११,६०,७५	२२	७,७८,५०	१६	३,७६,००
३.	मुग्तान किए गए ऋण	—	६,७७,५०	—	८,३३,३५	—	७,४७,७१
४.	अस्वीकृत प्रार्थना पत्र	१४	४,८७,५०	१	१०,००	३	३१,५०
५.	वापस लिए हुए अथवा लैप्स्ड(lapsed) प्रायना पत्र	१०	७,७३,१०	१०	२,११,५०	२२	६,७६,५०
६.	वर्ष के अन्त में विचारा धीन प्रार्थना पत्र	२६	११,३७,००	४१	१४,६८,४०	२३	११,७०,६७

इस वर्ष ऋण सम्बन्धी प्रार्थना पत्र गत वर्ष की तुलना में कुछ कम रकम के लिए प्राप्त हुए। प्रार्थना-पत्रों की संख्या भी कम थी। इसी प्रकार स्वीकृत कुल रकम भी पहले की अपेक्षा कुछ कम है। इन कमियों का प्रमुख कारण विदेशी विनिमय सम्बन्धी कठिनाइयाँ हैं जिसने परिणामस्वरूप औद्योगिक संस्थाएँ पूँजीगत सामान आयात नहीं कर पा रही हैं।

औद्योगिक अर्थ निगम (संशोधन) अधिनियम सन् १९५७ के अन्तर्गत निगम को स्थगित चुकारों (Deferred Payments) की गारन्टी करने का भी अधिकार मिल गया है। औद्योगिक संस्थाओं द्वारा विदेशों से पूँजीगत मान्य (Capital Goods) आयात करने के सम्बन्ध में जो स्थगित मुग्तान थे, उनकी गारन्टी अथ निगम ने दी। इसका संक्षिप्त व्यौरा इस प्रकार है :—

## तालिका II

क्रमांक	विवरण	२१ जून सन् १९५७ से ३० जून सन् १९५८ तक रु०	३० जून सन् १९५८ तक रु०
१.	स्वगित भुगतान के हेतु गारन्टी के लिए प्राप्त प्रार्थना पत्र	६ ५,२४,००,०००	११ १६,५०,५०,५००
२.	स्वीकृत प्रार्थना पत्र "	३ ३,६६,००,०००	२ ३५,००,०००
३.	अस्वीकृत " " "	—	—
४.	वापस ले लिए गए प्रार्थना पत्र "	—	५,१४,१७,७००
५.	विचाराधीन प्रार्थना-पत्र "	३ १,२८,००,०००	७ १२,२६,६२,८००

गत वर्षों में अर्थ निगम द्वारा ऋण के हेतु कुल ३०० प्रार्थना पत्र स्वीकार किए गए, जिनमें से १८५ उन नई औद्योगिक समस्याओं से सम्बन्ध रखते हैं जिनका उत्पादन कार्य १५ अगस्त सन् १९६७ के बाद शुरू हुआ। इन समस्याओं को कुल मिलाकर ४४,२२,५०,००० रुपये की आर्थिक सहायता ऋणस्वरूप दी गई। दोप ११५ सस्याय पुरानी थी, जिन्हें नवकरण, आधुनिकीकरण तथा कार्य विस्तार के हेतु २२,४६,५०,००० रु० की पूँजी दी गई।

जो प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किये गये उनकी अस्वीकृति के कारणों को मोटे तौर पर निम्न प्रकार वर्गित किया जा सकता है :—

- (१) प्रार्थी द्वारा योजना का त्याग देना या स्थगित करना,
- (२) प्रार्थी द्वारा योजना में संशोधन करना,
- (३) प्रार्थी की आर्थिक स्थिति में सुधार,
- (४) अन्य श्रोता से ऋण उपलब्ध हो जाना,
- (५) निगम की शर्तों को पूरी न कर पाना।

औद्योगिक अर्थ निगम द्वारा गत ११ वर्षों में भारत के जिन विभिन्न उद्योगों को ऋण स्वीकार किए गए, उनका संक्षिप्त व्यौरा इस प्रकार है :—

## तालिका III

क्र. सं.	उद्योग का प्रकार	३० जून सन् १९५८ तक स्वीकृत ऋण रु०	३० जून, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रु०	योग रु०
१.	बत्त मशीनरी	८३,००,०००	—	८३,००,०००
२.	मेकैनिकल इंजीनियरिंग एलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	२,०८,००,०००	२०,००,०००	२,२८,००,०००
४.	मृत्ती बत्त	१,७५,७०,०००	६,००,०००	१,८१,७०,०००
५.	ऊनी बत्त	८७२,७५,०००	६५,००,०००	९,३७,७५,०००
६.	रेयन	३५,००,०००	—	३५,००,०००
७.	रासायनिक	१,१०,००,०००	—	१,१०,००,०००
८.	सीमेण्ट	८,५३,२५,०००	—	८,५३,२५,०००
९.	सेरेमिक एण्ड ग्लास	५,००,००,०००	१,१०,००,०००	६,१०,००,०००
१०.	तेल मिल	१,६१,७५,०००	—	१,६१,७५,०००
११.	विद्युत शक्ति	११,००,०००	—	११,००,०००
१२.	विद्युत शक्ति	८२,७०,०००	—	८२,७०,०००
१३.	मेकैनीकल उद्योग	४५,५०,०००	—	४५,५०,०००
१४.	लोह व स्पात	२,२७,५०,०००	३३,००,०००	२,६०,५०,०००
१५.	अल्यूमीनियम	५०,००,०००	—	५०,००,०००
१६.	शक्कर या चीनी	१६,१३,००,०००	१,४५,००,०००	१७,५८,००,०००
१७.	तनिश	३७,००,०००	—	३७,००,०००
१८.	कागज	५७१,५०,०००	—	५७१,५०,०००
१९.	ऑटोमोबाइल व ट्रेक्टर	१,६४,५०,०००	—	१,६४,५०,०००
२०.	प्लाईवुड	३०,००,०००	—	३०,००,०००
२०.	अवशेष	१,१६,८०,०००	—	१,१६,८०,०००
	योग	६२,६०,००,०००	३,७६,००,०००	६६,३६,००,०००

गत वर्ष अन्तरिम ऋण (Interim Loan) के प्रदान करने में भी निगम ने बड़ी नमी दिखवाई । ऐसे ऋणों की मात्रा ४,२४,६५,००० रु० थी ।

औद्योगिक अर्थनिगम संशोधन अधिनियम सन् १९५३—

औद्योगिक अर्थनिगम का कार्य क्षेत्र तथा आर्थिक साधन बढ़ाने के लिए उपयुक्त

अधिनियम बनाया गया, जिससे दीर्घकालीन ऋण देने में वह अधिक उपयोगी हो सके। इस सशोधित अधिनियम के अन्तर्गत निगम को निम्नलिखित अधिकार मिल गए हैं —

(१) औद्योगिक संस्थाओं की परिभाषा के अन्तर्गत जहाजों कम्पनियों का भी समावेश होगा, जिन्हें अधिनियम ऋण दे सकेगा।

(२) प्रत्येक उद्योग प्रमण्डल की अधिनियम १ करोड़ रुपये अधिकतम ऋण दे सकेगा।

(३) सरकार अथवा अन्तर्राष्ट्रीय बैंक द्वारा भारतीय उद्योगों को जो ऋण दिए गए हैं, उनका निरीक्षण सरकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के प्रतिनिधि के नाते अर्थ-निगम स्वयं करेगा।

(४) अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने अधिनियम जो ऋण लेगा, उसकी जमानत भारत सरकार देगी तथा इस प्रकार के विनियम व्यवहारों में निगम को जो हानि होगी उसकी क्षति पूर्ण केन्द्रीय सरकार करेगी।

(५) केन्द्रीय सरकार की जमानत पर अधिनियम किसी एक उद्योग प्रमण्डल को एक करोड़ रुपये से अधिक ऋण दे सकेगा, परन्तु ऐसी जमानत के लिए अधिनियम द्वारा दिये की स्वीकृति की सिफारिश आवश्यक है।

(६) अर्थनिगम अपनी राशि रिजर्व बैंक की सहाह से किसी भी सूचीबद्ध बैंक अथवा प्रांतीय सहकारी बैंक के पास निक्षेप (Deposit) में रख सकेगा। इस सहायन से यह आवश्यक नहीं है कि वह अपनी राशि का विनियोग सरकारी प्रतिभूतियों में ही करे। इससे अर्थनिगम को व्याज की हानि नहीं होगी।

(७) अर्थनिगम अपनी कायशील पूँजी के लिए १८ माह में अधिकतम अवधि के लिए ३ करोड़ रुपये का ऋण दे सकेगा। इससे निगम को स्वीकार करते ही बन्ध अथवा ऋण पत्रों के निगमन की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब तक अधिनियम का संचित कोष ५० लाख रुपये तक नहीं हो जाता, तब तक रिजर्व बैंक एवं केन्द्रीय सरकार की मिलने वाले लाभांश इसी में जमा होंगे।

(८) किसी ऋण लेने वाले उद्योग का नियन्त्रण अर्थनिगम ले सकेगा। इस सम्बन्ध में ३० A से ३० E तक नई धारारें जोड़ दी गई हैं। इससे नियन्त्रित उद्योग में वह अपने संचालकों की नियुक्ति करेगा, जिसके बाद पूर्व संचालक अपना पद छोड़ देंगे। दूसरे, मैनेजिंग एजेंट्स का उद्योग प्रमण्डल के साथ जो अनुबन्ध होगा उसका दिना किमी क्षति पूर्ति के अन्तर्गत हो जायगा। तीसरे, अदालतों के मनोनीत संचालकों की नियुक्ति निरस्त होगी और बिना अधिनियम की अनुमति के अदालतों द्वारा स्वीकृत कोई भी प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं हो सकेगा। चौथे, अर्थनिगम की अनुमति के बिना किसी उद्योग प्रमण्डल का समावेश नहीं हो सकेगा।

(९) अधिनियम की संचालक सभा पर केन्द्रीय सरकार के मनोनीत ४ सच-

लक होंगे तथा उप प्रबन्ध-संचालक (Deputy Managing Director) संचालक सभा में बैठ सकेगा, किन्तु उसे मत देने का अधिकार न होगा। इसी प्रकार प्रबन्ध-संचालक को किसी भी समय निकाला जा सकता है। हाँ, ऐसी परिस्थिति में प्रबन्ध संचालक को स्पष्टीकरण करने के लिए समुचित अवसर दिया जायगा, किन्तु दो-तिहाई बहुमत से संचालक सभा चाहे तो उसे कर सकती है।

**प्रमण्डल की कठिनाइयाँ—**

गत वर्षों में कॉरपोरेशन ने करोड़ों रुपये के ऋण औद्योगिक संस्थाओं को प्रदान किये, किन्तु फिर भी प्रमण्डल पूर्णरूपेण सहायता नहीं पहुँचा सका। कॉरपोरेशन का तो अनुभव यह है कि भारतीय औद्योगिक कलेंबर की नाखी कमजोर है। प्रमण्डल के मार्ग में मुख्य बाधाएँ निम्न हैं :—

( १ ) योजना का अभाव—अनेक उदाहरणों में ऐसी योजनाएँ कॉरपोरेशन के पास भेजी गईं, जिसमें तान्त्रिक पहलुओं व वित्त समस्याओं पर पूर्ण विचार नहीं किया गया था। कुछ में तो यह भी नहीं बताया गया कि भूमि, इमारत, मशीनरी आदि अन्य विभागों पर अलग अलग कुल कितनी राशि व्यय होगी। ऐसे भी उदाहरण हैं, जहाँ मशीन आदि इसलिए खरीद ली गई है, क्योंकि वे सस्ते दामों में उपलब्ध ह। ऐसी अधूरी कागजी योजनाओं में वास्तविक योजना के मूल तत्वों का अभाव होना स्वाभाविक ही है। माँग और पूर्ति की समस्याओं पर तो अधिकाँश संस्थाएँ पर्याप्त रूप से साँचने में असमर्थ रही हैं, अतः ऐसी दशा में कारपोरेशन के लिए अन्धाधुन्ध ऋण देना क्योंकर सम्भव हो सकता है ?

( २ ) अपर्याप्त साधन—अनेक उदाहरण ऐसे हैं, जिनमें पूँजी आवश्यकता से बहुत कम है। ऐसी संस्थाओं को ऋण देकर उनका अहित करना है।

( ३ ) कुछ उदाहरणों में यद्यपि प्राप्त पूँजी पर्याप्त थी, किन्तु संस्था की अधिकाँश सम्पत्ति गिरवी रखी जा चुकी थी। ऐसे भी उदाहरण हैं, जहाँ संस्था के सारे अक्ष प्रवक्तों को उनसे ली गई सम्पत्ति के बदले में दे दिए गए हैं और ऐसी सम्पत्ति बहुत अधिक मूल्य पर प्राप्त की गई है।

( ४ ) ऐसे भी प्रमण्डल हैं जो ऋण स्वीकृत हो जाने पर भी वैधानिक कार्यवाही पूरी नहीं करते और न इस दिशा में प्रयत्न ही करते हैं।

अतः औद्योगिक अर्थ प्रमण्डलों को चाहिए कि वे उच्च कठिनाइयों को दूर करने में तथा अधिकाधिक सहायता प्रदान करने में औद्योगिक अर्थ प्रमण्डल को सहयोग दें, तभी विकास सम्भव है।

**कॉरपोरेशन के कार्य-क्रम की आलोचना—**

( १ ) अर्थ प्रमण्डल का आरम्भ इतना अच्छा नहीं रहा, जिससे प्रेरित होकर

इसकी अत्यधिक प्रशंसा की जाय : अन्य देशों की अपेक्षा भारतीय प्रमण्डल ने देश की बहुत थोड़ी सेवा की है ।

( २ ) प्रमण्डल द्वारा दिए गये ऋणों पर व्याज की दरें सभी सस्थाओं के लिये समान रही है । यह बात अगमन प्रतीत होती है, क्योंकि प्रत्येक औद्योगिक सस्था की आर्थिक स्थिति भिन्न होती है, अतएव प्रत्येक सस्था की हठना तथा भविष्य की दृष्टान में रखकर व्याज की दर निश्चित करनी चाहिये ।

( ३ ) ऋण के आवेदन पत्रों पर विचार करते समय कॉरपोरेशन इस बात से अधिक प्रभावित हुआ है कि किस प्रमण्डल के असो का मूल्य बाजार में अधिक है और किसका नहीं । यह पद्धति दापपूर्ण है, क्योंकि 'असो की कीमत' के अतिरिक्त भी ऐसे अन्य महत्वपूर्ण विषय हैं (जैसे, कम्पनों के पिछले वर्षों का प्रभाव, वर्तमान आय शक्ति, प्रबन्ध सुचारुता इत्यादि) जिनका ध्यान रखना आवश्यक है ।

( ४ ) अधिकांश ऋणों की अवधि, जो प्रमण्डल ने औद्योगिक सस्थाओं को दिए हैं, केवल १२ वर्ष की है । यह अवधि बहुत कम है । नियमानुसार अवधि २५ वर्ष हो सकती है, किन्तु इस नियम का अभी तक उपयोग नहीं उठाया गया है ।

( ५ ) प्रमण्डल ने अभी तक अग्न अवस्था में ऋण पत्रों के अभिगोपन तथा प्रत्याभूति का कार्य नहीं किया है ।

( ६ ) प्रमण्डल की ओर से अभी तक कोई आर्थिक अनुसन्धान विभाग नहीं खोला गया है, जिसकी बड़ी आवश्यकता है ।

( ७ ) असो खरीदने का अधिकार केवल वित्त मन्त्रालय मन्थाना व केन्द्रीय सरकार को ही है, अतः प्रमण्डल जन साधारण की सस्था नहीं कहੀ जा सकती ।

( ८ ) प्रमण्डल द्वारा ऋण केवल सावजनिक तथा सहाकारी सस्थाओं को ही मिल सकता है, अतः अलाक प्रमण्डल (Private Companies) तथा सामेदारी की सस्थाएँ इन लाभ से वंचित हैं ।

"आलाचना की कई बातों में तथ्य ही नहीं मार्गदर्शन की देखा भी मिलता है, किन्तु सारी बातें न सही हैं और न सारपूर्ण ही हैं । यदि कॉरपोरेशन अपने असा को सभी व्यक्तियों तथा सस्थाओं के लिए केवल अपने नाम के छोटे एक जनवादी विस्तार लगाने के लिए ही उपलब्ध करदे तो लाभ के विपरीत हानि और अनर्थ अधिक होगा ।

जहाँ तक कॉरपोरेशन के प्रारम्भ का प्रश्न है, वह अन्य देशों की अपेक्षा कुछ कम आशामय लगता है, किन्तु हमें अपने देश की स्थिति और आर्थिक साधनों का भी आलोचना करते समय ध्यान रखना चाहिये । कॉरपोरेशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ही सावजनिक उद्देश्यों को विकसित करना है, अतः सामेदारी व्यापार व निजी उद्योगों की माँग वाली उक्ति भी समझ में नहीं आती ।"

हर्ष का विषय है कि कॉर्पोरेशन अपने कार्यक्रम सम्बन्धी कतिपय कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न कर रहा है। ऋण की स्वीकृति और वितरण के बीच जो सबा व्यवधान पड़ जाता था उसे कम करने के लिए और साथ ही ऋण लेने वाली कम्पनियों पर कानूनी व्ययों का भार कम करने के हेतु कॉर्पोरेशन ने प्रयोग के तौर पर अपनी दो शाखाओं पर कानूनी अधिकारी नियुक्त किये हैं, जो कॉर्पोरेशन के पास बन्धक रखी जाने वाली जायदाद के स्वत्वाधिकार की जांच किया करेंगे और ऋण सम्बन्धी प्रलेख तैयार करेंगे। यदि यह प्रयोग सफल रहा तो प्रत्येक शाखा पर एक-एक कानूनी अधिकारी नियुक्त कर दिये जायेंगे। अपने ग्राहकों की अधिक सुविधा के लिये कॉर्पोरेशन ने अन्तरिम ऋण (Interim Loans) देने की शर्तें उदार कर दी हैं, विशेषतः उन दशाओं में जबकि ऋण सम्बन्धी कानूनी कार्यवाही करनी रह गई है और अन्तिम निर्णय हो चुका है।

**औद्योगिक ऋण प्रमण्डल का भविष्य—**

जिस समय औद्योगिक वित्त निगम स्थापित किया था उस समय केवल वही एक बृहत सरकारी वित्त संस्था थी, लेकिन अब अन्य संस्थाओं का भी विकास हो गया है, जैसे—औद्योगिक साख एवं वित्त निगम, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, राज्य वित्त निगम, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम। इसके विपरीत पंच वर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत औद्योगिक ऋण लेने वाली की संख्या एवं आवश्यकता में भी बहुत वृद्धि हो गई है, अतः निगम के लिए सेवा के अवसर विस्तृत हो गए हैं, किन्तु इस सम्बन्ध में निगम के चेयरमैन की यह चेतावनी उल्लेखनीय है कि यदि निगम पिछले वर्षों की भांति ही अपने विनियोग का क्षेत्र बढ़ाता गया तो बहुत शीघ्र उसके अपने मौद्रिक प्रसाधन लोप हो जायेंगे और उसे अनुचित शर्तों पर ऋण लेने के लिए विवश होना पड़ेगा, जिसके फलस्वरूप व्यय काट कर शायद ही कुछ लाभ बचे, अतः इस सम्बन्ध में उचित ध्यान देना आवश्यक है।

निगम के कार्यों की जांच के लिए सन् १९५३-५४ में सरकार ने जो कमेटी नियुक्त की थी, उसने निम्न सुझाव दिये थे:—

(१) जिन उद्योगों में पूर्ण क्षमता पहुँच गई है, उनको ऋण नहीं देना चाहिए।

(२) ऋण स्वीकृत करते समय जिन सिद्धान्तों का पालन वाछनीय समझा जाय उनके बारे में सरकार निगम को निर्देश दिया करे।

(३) सरकार निगम को स्पष्ट सकेत कर दे कि वह किन क्षेत्रों को पिछड़ा हुआ माने। इससे निगम इन क्षेत्रों को प्राथमिकता दे सकेगा।

(४) कॉर्पोरेशन इक्विटी केपीटल में विनियोग न करे, जब तक कि उसका संचित कोष ५ करोड़ रुपया न हो जाय।

इन मिफाधिकों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

जबकि ऋण मागने वाला उद्योगपति अपने उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्रार्थना पत्र दता है, निगम को सरकारी आदेशों का पालन करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में ऋण प्राप्ति और निगम में समन्वय नहीं हो पाता। इसके लिए हमारा सुझाव है कि निगम के अधिकारी ऋण प्राप्ति और व्यापारिक मण्डलों के प्रतिनिधियों व समक्ष विचार विमर्श ( Personal discussion ) करें। यदि ऐसा किया जाय तो एक दूसरे की कठिनाइयों को अधिक समझ सकेंगे।

**प्रांतीय अर्थ निगम (State Finance Corporations)—**

अखिल भारतीय औद्योगिक अर्थ प्रमण्डल का क्षेत्र सीमित है, अतः औद्योगिक क्षेत्र व लिए प्रांतीय अर्थ प्रमण्डलों की आवश्यकता है, जो सामंदायी सस्थाओं, अलोक प्रमण्डलों तथा व्यक्तियों का भी ऋण प्रदान करें। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि प्रांतीय अर्थ प्रमण्डल तथा औद्योगिक अर्थ प्रमण्डल परस्पर सहयोग में कार्य करें, जिसमें वे एक दूसरे के पूरक हों, क्योंकि मध्यम एवं लघु उद्योगों की अधिक सहायता देने का काम क्षेत्र विस्तृत होने में औद्योगिक अर्थ निगम को यह क्षेत्र अपनाते में कठिनाइयाँ भी होंगी। इसी हेतु संसद ने २८ दिसम्बर सन् १९५१ को 'प्रांतीय औद्योगिक अर्थ प्रमण्डल सन्निधय' पास किया, जो सम्पूर्ण भारत में लागू होता है।

इस विधान व अनुमति प्रत्येक प्रांतीय सरकार अपने प्रांत में प्रांतीय अर्थ प्रमण्डल स्थापित कर सकती है। इस सन्निधय की अधिकांश धाराएँ औद्योगिक अर्थ प्रमण्डल सन्निधय सन् १९४६ में मिलनी चुनती हैं। केवल तीन बातों में भिन्नता है—  
(१) 'औद्योगिक' संस्थाओं की परिभाषा इस प्रकार विस्तृत की गई है कि प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों, सामंदायियों एवं यहाँ तक कि एकाकी स्वामित्व वाली मध्याह्न भी इसके क्षेत्र में आ जाती है। (२) उन साधारण और अनुसूचित बैंक भी राज्य निगमों की अंश पूँजी में भाग ले सकती हैं। (३) ऋण की अधिक केवल २० वर्ष रखी गई है।

सन् १९५१ का अधिनियम पास होने में अब तक कुल १३ अर्थ निगम बन चुके हैं। इनका कार्य कुछ अधिक सतोपजनक नहीं रहा है और वे लघु एवं मध्यम उद्योगों की विशेष सहायता नहीं कर पाये हैं। इस असफलता के लिए कुछ तो अधिनियम की दुर्बलाताएँ उत्तरदायी थीं और कुछ सीमा तक लघु उद्योगों का स्वभाव एवं संगठन भी बाधक हुआ। ये उद्योग भली प्रकार संगठित नहीं थे, अतः व निगम से सहायता माँगने में समर्थ नहीं हुए। फलतः सन् १९५६ में सन् १९५१ के राज्य वित्त निगम अधिनियम में संशोधन किए गए, जिनके उद्देश्य निम्न थे :—

(१) अधिनियम के कार्योन्वित करने में जो कठिनाय कठिनाइयों पर कुछ वर्षों में अनुभव हुई उन्हें दूर करना।



(२) दो या दो से अधिक राज्या को पारस्परिक समझौते द्वारा एक सङ्घुत्त वित्त निगम की स्थापना करने के लिए अनुमति देना ।

(३) एक राज्य के विद्यमान वित्त निगम का क्षेत्र दूसरे राज्य पर एक पारस्परिक टहराब के अन्तर्गत विस्तृत करना ।

(४) राज्य वित्त निगम को केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार या अखिल भारतीय वित्त निगम की ओर से एजन्सी कार्य लेन की अनुमति देना ।

(५) रिजर्व बैंक से सघुकासीन ऋण लेन की अनुमति देना ।

(६) सघु एवं कुटीर उद्योगों को जिनके पास यथेष्ट सम्पत्ति नहीं है किसी राज्य सरकार या अनुसूचित्र बैंक या सहकारी बैंक की प्रयाभूति देन पर आर्थिक सहायता देन की अनुमति प्रदान करना ।

(७) निगमों को अपन अधिकार में की गई औद्योगिक मस्थाओं के कुशल प्रबन्ध मचालन के लिए अधिकार प्रदान करना ।

(८) रिजर्व बैंक को केन्द्रीय सरकार की आज्ञा पर राज्य वित्त निगमों की काय प्रणाली को जाँचन की अनुमति प्रदान करना ।

यह अनुभव किया गया है कि लघु उद्योगों के विकास से रोजगार में विशेष वृद्धि होगी और आय में अममानता घटगी अतः इनकी उत्तति पर सरकार बड़ा ध्यान दे रही है । लघु उद्योगों की उत्तति के लिए वित्तीय सहायता बड़ी आवश्यक है जो केवल राज्या के वित्त निगम ही दे सकते हैं । राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम इनको अधिक सहायता नहीं दे सकना क्योंकि लघु उद्योग सारे देश में बिखरे हुए हैं ।

प्रबन्ध—

प्रत्येक प्रांतीय सस्था के प्रबन्ध के लिए १० सदस्यों की एक सभा होगी जिसके सदस्यों की नियुक्ति इस प्रकार की जायगी —

( क ) प्रांतीय सरकार द्वारा मनोनीत सचालक	३
( ख ) रिजर्व बैंक	१
( ग ) औद्योगिक प्रबन्ध निगम	१
( घ ) प्रांतीय सरकार द्वारा नियुक्त प्रबन्ध सचालक	१
( ङ ) अनुसूचित्र बैंक, सहकारी बैंकों तथा आर्थिक व्यवसायों तथा अशधारिया में से प्रत्येक का अलग अलग प्रतिनिधि सचालक	४

कुल १०

राज्य वित्त निगमों के काय—

राज्य वित्त निगम को निम्न के लिये अधिकार दिये गये हैं

- ( १ ) औद्योगिक संस्थाओं को ऋण देना या उनके ऋण पत्र खरीदना, जो कि २० वर्षों में वापस लिये जा सकते हैं ।
- ( २ ) औद्योगिक संस्थाओं द्वारा खुले बाजार में ( २० वर्ष की अवधि में चुकता किये जाने वाले ) ऋण निर्गमनों की प्रत्याभूति देना ।
- ( ३ ) औद्योगिक संस्थाओं के अग्रे, ऋण पत्रों, बॉण्ड आदि का अभिगोपन करना, दबर्नो जो अग्रे आदि निगम को लेने पड़ें उन्हें ७ वर्ष के अन्दर बाजार में बेच दिया जाय ।

पहले दो प्रकार की अर्थ सहायता निगम औद्योगिक संस्थाओं को तभी देगा जबकि उसके लिए पर्याप्त प्रतिभूति दी जाय, जोकि सहकारी या अन्य प्रतिभूतियों, स्वर्ण, चल या अचल सम्पत्ति के रूप में हो सकती है । हाँ, जब किसी राज्य सरकार या अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक ने प्रत्याभूति दी हो तो बिना पर्याप्त प्रतिभूति लिये ही निगम उक्त सुविधाएँ दे सकता है । एक औद्योगिक संस्था को निगम की दत्त पूँजी के १०% से या १० लाख रु० से, जो भी कम हो, अधिक सहायता नहीं दी जा सकती । यही नहीं, बल्कि निगम का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक संस्थाओं को पूँजी प्राप्त करने में सहायता देना है, न कि एक सूत्रकारी कम्पनी या विनियोग प्रन्धास का कार्य करना, अतः निगम प्रत्यक्ष रूप से किसी कम्पनी के शेयर या स्टॉक नहीं खरीद सकता ।

**राज्य वित्त निगमों के अब तक किए गए कार्यों की आलोचना—**

यद्यपि कई राज्यों में अभी वित्त निगम अभी प्रकार स्थापित नहीं हो पाये हैं, तथापि कुछ वित्त निगमों के कार्यों से यह प्रकट होता है कि यदि उनकी संरचना एवं कार्य प्रणाली में कुछ परिवर्तन कर दिये जायें तो वे अधिक उपयुक्त बन सकते हैं । निगमों की प्रमुख कठिनाइयाँ निम्नलिखित हैं :—

( १ ) इन निगमों की रचना ऐसी है कि उद्योगों को अपने विस्तार के लिये अतिरिक्त स्थायी सम्पत्तियाँ ( मशीनों, इमारतों आदि के रूप में ) खरीदने के हेतु पूँजी की सहायता मिल सकती है, किन्तु अधिकांश लघु उद्योगों को कार्यशील पूँजी चाहिए, जिसे देने में राज्य निगम सकोच करते हैं ।

( २ ) अधिकांश लघु उद्योगों का समूहन छोटे पैमाने पर हुआ है । उनकी वित्तीय आवश्यकताएँ निगम के कार्य क्षेत्र में परे रह जाती हैं, क्योंकि राज्य निगम एक न्यूनतम राशि से कम आर्थिक सहायता नहीं देते ।

( ३ ) लघु उद्योगों द्वारा उचित रूप में हिसाब किताब नहीं रखा जाता । ये उद्योग प्रायः एकल स्वामित्व या साझेदारी के आधार पर समूहित किये गये हैं । अतः इन पर हिसाब किताब सम्बन्धी कोई वैधानिक प्रतिबन्ध भी नहीं है । जब निगम किसी

उद्योग को सहायता स्वीकृत करता है तो वह यह आशा करता है कि उचित हिसाब-किताब रखा जायगा। छोटे छोटे उद्योग इसके लिये अपन को अगम्य पाने हैं।

( ) लघु उद्योगों के पास प्रतिभूति के रूप में देने के लिए पर्याप्त स्थायी सम्पत्ति (Block assets) नहीं है। भूमि और भवन प्रायः किराये का हाता है, मशीनें भी कम होती हैं। यही नहीं, स्थायी सम्पत्ति का ५०% मजिन भी निगम छाड़ता है। परस्वरूप उद्योग निगम को पर्याप्त प्रतिभूति नहीं दे पाते।

(५) अधिकांश राज्य वित्त निगमों ने कर मुक्त २३% न्यूनतम लाभान की गारन्टी के आधार पर पूँजी प्राप्ति की है, जिसके कारण वे स्वयं उद्योगों से ६% या ७% व्याज लेने के लिये विवश हो जाते हैं, किन्तु यही अन्त नहीं है। उद्योगों को ऋण लेने में कुछ व्यय करना पड़ता है, जिसको मिलाकर कुल व्याज लगभग ६-१०% पड़ जाता है।

## STANDARD QUESTIONS

1. How far do you think the establishment of the Industrial Finance Corporation has been able to remove the drawbacks of Indian industrial finance and has helped in the growth of large scale industries in the Indian Union? Examine critically in the light of its working for the last year.
2. Review the working of State Finance Corporations during the few years and offer suggestions for their better working

# औद्योगिक अर्थ प्रवन्धन के लिये विशिष्ट संस्थायें (II)

(Special Institution for the financing of Industries)

## अन्य विशिष्ट अर्थ संस्थायें

### (१) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम •

हमारे देश में बहुत दिनों से राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (National Industrial Development Corporation) की चर्चा चल रही थी। मौलभारत का विषय है कि २० अक्टूबर सन् १९५४ को इस संस्था की स्थापना देहली में हो गई है। यह एक विगुद्ध राजकीय संस्था है, अतः यह पूर्ण रूप से सरकारी स्वामित्व एवं नियन्त्रण में रहेगी, किन्तु औद्योगिक विकास तथा आधारभूत उद्योगों की स्थापना के हेतु आवश्यक तात्त्विक अनुभव प्राप्त करने के लिये वह व्यक्तिगत उपक्रमियों (Private Enterprise) का सहयोग भी प्राप्त करेगी। यह सहकारिता इसी दृष्टि से प्राप्त की जा रही है, क्योंकि देश की औद्योगिक विकास की तीव्र आवश्यकता है तथा उपभोक्ता उद्योगों (Consumer Industries) में व्यक्तिगत उपक्रमों ने बहुत कुछ कार्य किया है एवं भविष्य में भी वे देश की आवश्यकता को पूरा करने में काफी सहायक हो सकते हैं।

पूँजी—

‘राष्ट्रीय औद्योगिक विकास’ निगम की पूँजी एक करोड़ रुपये है, किन्तु प्रारम्भिक अवस्था में केवल १० लाख रुपये की दत्त पूँजी होगी, जो सरकार देगी। इस निगम का रजिस्ट्रेशन भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है। इस निगम को जो अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी वह केन्द्रीय सरकार निम्न रीति में प्रदान करेगी—

- (१) औद्योगिक योजनाओं के अध्ययन, अनुसन्धान एवं औद्योगिक निर्माण के लिए तथा ऐसी ही अन्य औद्योगिक योजनाओं की पूर्ति के लिए देश में आवश्यक तात्त्विक एवं आसक्तिय कर्मचारियों का दल तैयार करने

के लिए वार्षिक अनुदान द्वारा । अनुदान की इस राशि का आयोजन वार्षिक बजट में किया जायगा ।

- (२) औद्योगिक विकास निगम की प्रस्तावित औद्योगिक योजनाओं की पूर्ति के लिये आवश्यकता के समय देकर ।

**प्रबन्ध—**

औद्योगिक विकास निगम का प्रबन्ध एक संचालक मभा द्वारा होगा, जिसमें २० सदस्य ह । वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्री इसके सभापति ह । इन संचालकों को केन्द्रीय सरकार ने मनोनीत किया है । औद्योगिक अनुभव तथा तात्त्विक एवं इन्जीनियरी कार्यक्षमता की दृष्टि से संचालक मभा में १० उद्योगपति, ५ अधिकारी तथा ४ इन्जीनियर ह ।

**उद्देश्य—**

- ( १ ) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम का प्रमुख उद्देश्य देश की औद्योगिक उन्नति के लिए आवश्यक मशीनरी एवं यंत्र प्रदान करना तथा आधारभूत उद्योगों का प्रवर्तन एवं उनकी स्थापना करना ।
- ( २ ) देश के औद्योगिक विकास में सहायक बतयान व्यक्तिगत उद्योगों को तात्त्विक एवं इन्जीनियरिंग सेवाओं की सुविधा देना तथा यदि आवश्यक हो तो पूँजी देना ।
- ( ३ ) व्यक्तिगत उपक्रमियों को सरकार द्वारा स्वीकृत औद्योगिक योजनाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक तात्त्विक, इन्जीनियरिंग, आर्थिक प्रयत्न अन्य सुविधायें प्रदान करना ।
- ( ४ ) प्रस्तावित औद्योगिक योजनाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक अध्ययन करना, उनको तात्त्विक, इन्जीनियरिंग तथा अन्य सुविधायें प्रदान करना तथा उनकी पूर्ति के लिए धन देना ।

इस प्रकार राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम का उद्देश्य लाभार्जन न होते हुए देश के मुख्य औद्योगिक कलेवर के निर्माण में सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करना है, ताकि जल्दी में देश का औद्योगिक विकास हो सके ।

इस उद्देश्य में निगम के बोर्ड ने २३ अक्टूबर सन् १९५४ को हुई अपनी पहली मीटिंग में उद्योगों की अस्थायी सूची तैयार की, जिससे अध्ययन में निगम को इस बात का पता लग जाय कि नया औद्योगिक विकास सीमा तक आवश्यक है और विद्यमान उद्योगों को किस सीमा तक बढ़ाना चाहिए ? चुने गये उद्योग इस प्रकार ह :—

- ( १ ) कुछ उद्योगों के लिए (जिसमें लूट कपास वस्त्र चीनी कागज सीमेंट, रासायनिक छपाई खान निर्माण एवं यांत्रिक आवागमन आदि उद्योग) मशीनरी और साज सज्जा ( Machinery and Equipment ) का निर्माण ।
- ( २ ) लौह मिथुन और मगनीज फरोक्रम ।
- ( ३ ) अलूमिनियम ।
- ( ४ ) तांबा जस्ता और धसोह धातुय ।
- ( ५ ) डोजल ईंजन और जनरेटर ।
- ( ६ ) भारी रासायनिक द्रव्य ।
- ( ७ ) खाद और उर्वरक ।
- ( ८ ) कोयले और कोलतार का सामान ।
- ( ९ ) मधानाल, फोरमेसडिहाइड ।
- ( १० ) काजल ।
- ( ११ ) कागज आवागारी कागज आदि वनान के लिये लकड़ी की लुगदी ।
- ( १२ ) कुत्रिम दवाय विटामिन और हारमोन ।
- ( १३ ) एकमर और डाक्टरों औजार आदि ।
- ( १४ ) हाइड्रोड और इंसुलेशन वाड आदि ।

लेकिन यह स्पष्ट है कि मशीनरी और साज सज्जा के निर्माण पर काफी जोर दिया गया है क्योंकि हमने कुछ वर्षों में औद्योगिक विकास के विशाल कार्यक्रम पूरे करन पड़े हैं । स्थूल मशीनरी एवं उद्योग की स्थापना के अलावा निगम कुछ विद्यमान उद्योगों को उनसे विनाश पैमान पर उनके विकास के हेतु भी सहायता करेगा । उदाहरण के लिए भारत सरकार देश में ३० नये चीनी मिल स्थापित करके चीनी का उत्पादन १२ लाख टन से बढ़ाकर १८ लाख टन करन का विचार कर रही है मत नये चीनी कारखानों की स्थापना के लिए उद्योगतापूर्वक साइसे ॥ दिये जा रहे हैं । सूती वस्त्र उद्योग की क्षमता में भी १०० गुनाई मिलों के बराबर वृद्धि करन आवश्यक है । सीमेंट का उत्पादन भी सन् १९६१ तक ४५ मिलियन टन से १० मिलियन टन तक बढ़ना चाहिए अतः निगम इन क्षेत्रों में अतिरिक्त इकाइयाँ स्थापित करन चाहता है ।

कुछ उद्योगों में जहाँ प्राइवेट और पब्लिक प्रयत्नों द्वारा कुछ उन्नति दिखाई गई है जैसे कि अलूमिनियम और फर्टिलाइजर उद्योगों में, निगम कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा । वह केवल तब ही सामान आवेगा जब अधिक सहायता या कार्य की आवश्यकता हो । फरोमेगनीज उद्योग में भी यदि प्राइवेट प्रयत्नों द्वारा प्रस्तावित और मर

कार द्वारा स्वीकृत योजनाएँ पूरी हो जाती हैं तो निगम कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। हाँ, धोष्य पदार्थों के उपयोग और कच्चे माल के बिकाने में काही टैक्नीकल ध्यानवान और सहायता की आवश्यकता है, अतः निगम ने अपने उद्योगों की सूची में रेपों, वागन, अश्वदारी वागन आदि के उत्पादन में काम आने वाले कोयला, कोयलार, मकड़ी की सुगदी आदि शामिल कर लिये हैं। इन काम के लिए एक जनन विनियम भी शामिल किया गया है।

निगम के बोर्ड ने अनुभव किया है कि इन के शोत्र औद्योगिकरण के लिए सबसे पहली बात उद्योगों को ठोस टैक्नीकल सहायता प्रदान करना है, अतः उसने परामर्शदाता इंजीनियरों की एक समूह स्थापित करने पर जोर दिया है। धोष्य कार-कर्मियों का देश में भिना कठिन होने के कारण उसने यह मुन्त्रव दिना कि प्रारम्भिक अवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय स्थाति प्राप्त किमो फर्म को भारत में अपना कार्यालय खोलने के लिये आमन्त्रित किया जाय और यदि आवश्यक हो तो उसे कुछ फीस भी दी जाय। इस फर्म की मेसार्स प्राइवेट उद्योगों के लिए भी मुन्त्रन की जावेगी। इसके अतिरिक्त बोर्ड ने यह भी निश्चय किया है कि व्यापक अनुभव वाले ३ या ४ इंजीनियर भी रखे जावें, जो निगम को उसके सामने आने वाली टैक्नीकल समस्याओं के हल करने और निगम द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं की व्य-रेखा तैयार करने के लिए उपयुक्त सलाह देंगे। इन प्रारम्भिक नियमों में यह प्रगट होता है कि निगम का दृष्टिकोण बड़ा व्यावहारिक है और यह अपन करणों को वास्तविक रूप में हल करना चाहता है।

## (२) औद्योगिक ऋण एवं अर्थ निगम

(Industrial Credit and Finance Corporation)

यह एक विपुल कैरुग्यारी मस्या है, जिसके स्यादना जनवरी सन् १९५५ में २५ करोड रुपये की अतिष्ठत पूंजी में हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य नये उद्योगों के प्रवर्तन की प्रासाहित करना, विद्यमान उद्योगों का विस्तार तथा आधुनिकीकरण करना एवं तात्विक तथा प्रबन्ध सम्बन्धी सहायता देना है, जिसने राष्ट्रीय उत्पादन 'दिन हूनी रात चीनी' उन्नति करे और रोजगार के अवसरों की वृद्धि हो।

उद्देश्य—

औद्योगिक ऋण एवं अर्थ निगम का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तिगत क्षेत्रों के औद्योगिक उद्योगों को सहायता प्रदान करना है। यह सहायता निम्न रीति में दी जावेगी :—

( १ ) ऐसे उद्योगों के निर्माण, विस्तार एवं आधुनिकीकरण में आर्थिक सहायता देना।

- ( २ ) एमे उपक्रमों में देशी एव विदेशी व्यक्तिगत पूँजी के विनियोग को प्रोत्साहन देना ।
- ( ३ ) विनियोग विपणि का विस्तृत करना एव औद्योगिक विनियोगों के व्यक्तिगत स्वामित्व को प्रोत्साहित करना ।
- ( ४ ) व्यक्तिगत उपक्रमियों को मध्यकालीन एव दीर्घकालीन आर्थिक सुविधाएँ देना अथवा उनके निश्चित साधारण अंशों को खरीद कर आर्थिक सुविधाय देना ।
- ( ५ ) नई कम्पनियों का अंश एव प्रतिभूतियों का अभिगोचन करना ।
- ( ६ ) व्यक्तिगत उपक्रमाँ के लिए व्यक्तिगत विनियोग श्रोतों से प्राप्त ऋणों की जमानत देना ।
- ( ७ ) चर्जित विनियोग द्वारा पुन विनियोग के लिए व्यक्तिगत उपक्रमों को राशि प्रदान करना ।
- ( ८ ) व्यक्तिगत उपक्रमाँ को प्रबन्ध सम्बन्धी तात्त्विक एव शासकीय सलाह देना एव उनके उद्योगों को इस हेतु आवश्यक विशेषज्ञ प्रदान करना ।

#### प्रश्न—

इस निगम का प्रबन्धक सचालक सभा द्वारा होगा, जिसमें ११ सदस्य तथा १ जनरल मैनेजर होगा । इन सचालकों में ७ भारतीय, २ ब्रिटिश, १ अमरीकी तथा १ सचालक बाणिज्य एव उद्योग मंत्रालय की आर से है । इसके जनरल मैनेजर बैंक आफ इण्डिया के प्रमुख कोषाध्यक्ष पी० एस्० बील है तथा चेयरमैन श्री रामास्वामी मुदालियर है ।

निगम न प्रारम्भ म १००) वाले ५,००,००० पूरात शोधित साधारण अंश निगमित किये हैं, जो निम्न प्रकार से सिंये गये हैं—

- |  |          |
|--|----------|
| ( १ ) कई भारतीय बैंक तथा बीमा कम्पनियाँ और कुछ सचालक तथा उनके मित्र  | २,००,००० |
| ( २ ) अमरीका के कुछ नागरिक और निगम   | ५०,०००   |
| ( ३ ) ब्रिटिश ईस्टन एक्मचेज बैंक और ट्रिप्ल तथा कामनवैल्व के कुछ अन्य देशों की बीमा कम्पनियाँ तथा अन्य ब्रिटिश कम्पनियाँ | १,००,००० |
| ( ४ ) शेप ग्राम जनता को प्रस्तुत   | १,५०,००० |

भारत सरकार न कम्पनी को ७३ करोड रुपए की राशि देना स्वीकार कर लिया है, जिस पर कोई ब्याज न होगा । यह राशि कम्पनी को धन मिलने की तिथि से १५ वर्ष बीत जान के बाद स शुरू होने वाली १५ वार्षिक किस्तों में चुकाई



जावेगी । सरकार को एक संचालक नामांकित करने का अधिकार है । विश्व बैंक ने कम्पनी को समय समय पर विभिन्न मुद्राओं में १ करोड़ डालर की राशि उधार देना स्वीकार कर लिया है । इस प्रकार निगम को १७½ करोड़ रुपये की कार्यशील पूँजी मिल गई है । यह भी आशा है कि इस निगम के माध्यम से विदेशी पूँजी को ऋणों के रूप में आने में मदद मिलेगी और कुछ ही समय में निगम के पास ५० करोड़ रुपये हो जायेंगे ।

निगम के अग्रधारी दूर-दूर तक फैले हुए हैं और इसके कार्यों तथा पूँजी नियोजन के अन्तर्गत छोटे-बड़े सब तरह के उद्योग घन्घे आ जायेंगे । निगम दीर्घकालीन और मध्यकालीन ऋण देगा, अग्र पूँजी में भाग लेगा और प्रतिभूतियों के नये निर्गमन का प्रागोपन करेगा । निगम का प्रारम्भिक धन और वह धन जो इसको विश्व बैंक से मिलता है, यदि विवेक से काम में लाया जाय तो वह देश में व्यक्तिगत पूँजी बाजार के साधनों को और भी बढ़ा सकता है तथा भविष्य में उपलब्ध सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी सुविधाओं को प्रोत्साहित कर सकता है ।

**निगम के कार्य और उनकी आलोचना—**

सन् १९५६ के अन्त में कम्पनी ने २४ योजनाओं के सम्बन्ध में सहायता देना स्वीकार किया था और दोष विचाराधीन थी । बाद में कुछ और योजनायें स्वीकृत की गई । इस प्रकार कुल २८ योजनाओं के लिए ८ करोड़ से अधिक रुपया स्वीकृत किया जा चुका है । निगम के लिए यह कोई बड़ी सफलता नहीं कही जा सकती । यह भी दोष बताया जाता है कि निगम का कार्य बहुत धीमा है और अपनी ऋण एवं विनियोग नीति में वह अत्यधिक कृपणता से काम ले रहा है ।

इस सम्बन्ध में कम्पनी की द्वितीय वार्षिक ध्यापक सभा में जोकि २२ अप्रैल सन् १९५७ को बम्बई में हुई, अध्यक्ष पद से धरने भाषण में श्री रामास्वामी मुदालियर ने पर्याप्त प्रकाश डाला है । उन्होंने बताया है कि निगम के विरुद्ध आक्षेपों की जाँच कराई गई है और वे सही नहीं लगे । उन्होंने बताया कि कम्पनी को प्रारम्भ हुए अभी थोड़ा समय हुआ है, अतः सगटित होने व अनुभव प्राप्त करने में कुछ समय लगना अनिवार्य है । ऐसा ही कारोबार करने वाली भारत और विदेशों की अन्य कम्पनियों का भी रिकार्ड उनकी प्रारम्भिक अवस्थाओं में बहुत कुछ इस निगम के ही समान था । फिर निगम का कार्य क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत है । वह कुछ ऐसे कार्यों को भी कर रहा है, जो कि अन्य कम्पनियों ने भारत में नहीं किये । निगम कोई पूर्णतः ऋण देने वाली कम्पनी मात्र नहीं है, जिसका सम्बन्ध केवल उस प्रतिभूति से हो जोकि बदले में उसे दी जा रही है । इसने अशो के अभिगोपन का कार्य भी किया और वस्तुतः कई कम्पनियों की अग्र पूँजी में भाग लिया है । इस सबके लिए यह स्वाभाविक है कि कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किए गये आवेदन पत्रों की निकट से जाँच की जाय ।

( १ ) जहाँ उचित अर्थों पर यथेष्ट प्राइवेट पूँजी सुलभ नहीं है वहाँ अनुमानित तान के सम्बन्ध में सरकारी गारंटी की अपेक्षा बिना और प्राइवेट विनियोगकों के सहयोग में उत्पादक प्राइवेट उपक्रमों में विनियोग करना ।

( २ ) विनियोग के मुख्यबसरो प्राइवेट पूँजी ( देशी एवं विदेशी ) एवं अनुभवी प्रबंधकों परस्पर समन्वित करने के लिए वित्तीय हाउस का काम करना ।

( ३ ) प्राइवेट पूँजी के उत्पादक विनियोग को प्रोत्साहित करना ।

कारपोरेशन भर्तार्राष्ट्रीय बचक साथ मिल कर काम करेगा यद्यपि उनका एक पृथक् वैधानिक अस्तित्व है और उसके कोष भी बचक से बिल्कुल पृथक् हैं । जो सरकार बचक की सदस्य है वे ही निगम की सदस्य बन सकती हैं । बचक के वे एजेंट क्यूटिव डाइरेक्टर जो कम से कम एक सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, निगम के डाइरेक्टर का भी काम करेंगे । बैंक का प्रसीडेण्ट इस बोर्ड का चेयरमैन होगा । निगम का प्रसीडेण्ट बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स द्वारा चेयरमैन की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है और निगम का अपना स्टॉक है ।

**विनियोग सम्बन्धी प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए योग्यता गुण—**

निगम विनियोग सम्बन्धी उही प्रस्तावों पर विचार करेगा जिनका उद्देश्य किसी उत्पादक प्राइवेट उपक्रम (Productive Private Enterprise) की स्थापना विस्तार या सुधार करना है । निगम में वित्तीय सहायता पान वाले उपक्रम किसी सदस्य देश में ही स्थापित होना चाहिए । प्रारम्भिक वर्षों में कारपोरेशन केवल अविश्वसित देशों के बारे में ही अपना ध्यान केन्द्रित करेगा । निगम यह माना करता है कि प्राइवेट विनियोग भी आवश्यक पूँजी का कम से कम आधा होगा । वस्तुतः निगम वित्तीय सहायता के लिए तभी हाथ बढ़ायेगा जबकि प्राइवेट विनियोग यथा सम्भव पूँजी दे चुके हों और तब पूँजी समुचित अर्थों पर प्राप्त करना असम्भव हो । प्रारम्भिक वर्षों में निगम ऐसे ही विनियोग प्रस्तावों पर विचार करेगा जिनमें उपक्रम का नया विनियोग कम से कम ५ लाख अमेरिकन डॉलर है और निगम से कम से कम १ ०० ००० डॉलर की सहायता माँगी गई है । सहायता की अधिकतम मात्रा दो अरबों निर्धारित नहीं की गई किन्तु सामान्य नीति यह होगी कि कुछ इन गिन उपक्रमों में बड़ी राशियाँ लगान की अपेक्षा पर्याप्त सत्या में समुचित मात्रा के विनियोग किये जाय ।

यों तो कार्यक्रमों में औद्योगिक कृषि विज्ञान व्यापारिक एवं अन्य प्राइवेट उपक्रम सभा सहायता ले सकते हैं वहाँ उनका कार्य उत्पादन में सम्मिलित रहता है तथापि प्रारम्भिक वर्षों में कारपोरेशन, राष्ट्रीय, राज्य, को, चुनाव, जाति, धर्म, प्रभृति के हो । वह बृहत् निमाण अन्वयता स्मृत आदि सामाजिक उपक्रमों या मात्र

जनिक उपयोगिता क उपक्रमों में विनियोग नहीं करेगा। निगम किसी ऐसे वित्त प्रबन्ध में भी भाग न लेगा जोकि पुनर्प्रबन्धन (re financing) के लिए हैं।

निगम केवल प्राइवेट उपक्रमों को सहायता देगा, सरकारी उपक्रमों को नहीं। किसी उपक्रम में सरकारी कोष लगे रहने से ही वह निगम की सहायता से वंचित नहीं होगा, बशर्ते उसका स्वभाव एक प्राइवेट उपक्रम जैसा हो।

विभिन्न विचार-योग्य प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय देते समय कॉरपोरेशन निम्न बातों का ध्यान रखेगा —

(१) निगम की सहायता से अन्य विनियोगों द्वारा प्राइवेट पूँजी का विनियोग कितना बढ़ जायगा ?

(२) निगम व उसके सहयोगियों को विनियोग से लाभ की क्या सम्भावनाएँ हैं ?

(३) निगम क विनियोग करने से उत्पादन की कितना प्रोत्साहन मिलेगा, वित्तीय रूप के प्रबन्ध एवं ढंग—

कॉरपोरेशन को यह अधिकार है कि वह किसी भी रूप में विनियोग कर, किन्तु केवल एक शर्त यह रखा गया है कि वह पूँजी प्रश्नों में विनियोग नहीं कर सकता, अतः निगम के विनियोग ऋण के समान होंगे, किन्तु साधारण ऋणों की भाँति नहीं होंगे। कॉर्पोरेशन अपना विनियोग निरन्तर बदलता रहना चाहता है, अतः प्रत्येक दशा में उसका प्रमुख उद्देश्य विनियोग के सम्बन्ध में ऐसा अधिकार प्राप्त करना होगा कि ऋण को प्रश्नों में बदला जा सके। कॉर्पोरेशन स्वयं इस अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा, किन्तु जिसे वह अपने ऋण बेच देगा वह ऐसा कर सकेगा। इस प्रकार निगम अपने सफल विनियोगों को लाभ पर बेच सकेगा। कॉरपोरेशन यह भी चाहता कि स्थायी व्याज के बजाय उसे लाभों में भी कुछ भाग दिया जाय, जिससे उपयुक्त ज़ेना मिलने तक वह लाभ ग्रहण कर सके।

व्याज की दर प्रत्येक दशा में विशिष्ट परिस्थितियों एवं जोखिम के अनुसार निश्चित की जावेगी। निगम द्वारा दिये गये ऋणों की अवधि प्रायः ५ से १२ वर्ष तक हुआ करेगी। किश्तों में भी विनियोग के भुगतान की व्यवस्था की जा सकती है। निगम ऋण जमानत पर या बिना जमानत के दे सकता है। यदि वह जमानत लेगा तो उसका क्या रूप होगा, यह प्राप्ति की हैसियत एवं विनियोग की शर्तों पर निर्भर है।

वित्तीय सहायता की रकम इकट्ठी की जा सकती है या किश्तों में। इस रकम का प्रयोग प्राप्ति उपक्रम अपने सामान्य व्यापारिक कार्यों में कर सकता है, किमी विशिष्ट सेवा या माल के भुगतान में उसका प्रयोग किया जाय, ऐसा कोई प्रतिबन्ध

नहीं है। साधारणतः ऋण का अमरीकी डालर में मूल्यांकन किया जावेगा किंतु उपर्युक्त देशों में वह अग्र्य कर लो म भी किया जा सकता है।

निगम तब ही विनियोग करेगा जब उसे यह संतोष हो जाय कि प्रार्थी उपक्रम का प्रबन्धक बगैर योग्य एवं अनुभवी है। किन्तु आवश्यक देशों में निगम उपयुक्त प्रबन्धक खोजने में सहायता दे सकता है किन्तु वह स्वयं प्रबन्ध का उत्तरदायित्व ग्रहण नहीं कर सकता। निगम सामान्यतः अपने प्राइवेट सहयोगियों से ही प्रबन्धक उपलब्ध करने की अपेक्षा रखता है। हाँ इतना वह अवश्य चाहेगा कि प्रबन्ध में कोई बड़ा परिवर्तन करने से पूर्व उसकी राय ले ली जायगी। वह बौद्ध भाक डा रैबटस में अपने प्रतिनिधि भी रख सकता है।

निगम इस बात का संतोष प्राप्त करना चाहेगा कि उपक्रमों को वास्तव में उस ऋण की आवश्यकता है और प्रबन्धकों में एक उपयुक्त कार्यक्रम भी तैयार कर लिया है। वह सत्या द्वारा प्रोजेक्ट सामान और सेवाओं के खरीदने का ढंग भी जान सकता है जिससे उसके विनियोग सुरक्षित रहे। यह भी आवश्यक है कि उपक्रम के हिसाब किताब का सरकारी अफेयर्स से निरीक्षण कराया जाय तथा वे निगम के प्रतिनिधियों के लिये खुले रहे। निगम को वार्षिक खाते प्रगति विवरण एवं अग्र्य सूचनाएँ भजी जाय। निगम के प्रतिनिधियों को सहायता लेने वाले के उपक्रम प्लान्ड कारखाना आदि को देखने का भी अधिकार होगा।

कापारेण सरकार की गारंटी नहीं मायेगा। हाँ यदि देश की सरकार को आपत्ति है तो कापारेण विनियोग नहीं करेगा। सम्बन्धित देश की सरकार को आपत्ति करने के लिये उचित अवसर प्रदान किया जाय। यदि किसी सदस्य देश की सरकार ने विदेशी विनिमय पर प्रतिबन्ध लगा रखा हो तो एक साधारण विनियोग के रूप में निगम अपने विनियोग एवं सम्बन्धी लाभ के ट्रान्सफर के लिये सरकार के साथ उचित समझौता करेगा। इन सब मामलों में निगम को विशेष अधिकार नहीं चाहेगा।

## (५) पुनर्ग्रथ प्रबन्धन निगम

( Refinance Corporation )

इस निगम की स्थापना का मुभाव बड़ा महत्वपूर्ण है। यद्यपि दीर्घकालीन साख की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई सरथाय इस देश में हैं तथापि ऐसी कोई सरथा नहीं है जोकि बवल मध्यकालीन साख देने के लिए हो अतः ऐसी सरथा की आवश्यकता है। अधिकांश वकान अपने मुवविला को जो ऋण दे रख हैं वे कागज पर तो अल्पकालीन ऋण हैं परन्तु व्यवहार में उन्हें मध्यकालीन ऋण वह सकते हैं क्योंकि उन्हें समय पर नया करा लिया जाता है किन्तु यह एक समस्याई युक्ति

है और फिर द्रव्य बाजार की आजकल जैसी गिरी दशा है उसे देखने हुए तो बैंकों को बड़ी कठिनाइयाँ हैं ।

निगम अपना काय १२.५ करोड़ रुपये की साधारण अग पूँजी से प्रारम्भ करेगा । रिजर्व बैंक इनमें ५ करोड़, स्टेट बैंक २.५ करोड़, लाइफ कॉर्पोरेशन २.५ करोड़ तथा अन्य बैंक २.५ करोड़ लगायेंगे । भारत सरकार इस २६ करोड़ ५० ३० वर्ष के लिये ब्याज पर देगी । निगम ३ से ७ वर्ष तक के लिये ऋण दिया करेगा । ये ऋण मध्यम पैमाने की औद्योगिक इकाइयों को दिये जायेंगे और किसी भी एक सस्या का ५० लाख ६० से अधिक ऋण नहीं मिलेगा । निगम के कुल ३६.५ करोड़ ५० के कोष में से प्रत्येक भाग लेने वाले बैंक को एक कोटा निश्चिन कर दिया जायगा । इस बाटे की न्यूनतम एवं अधिकतम सीमार्य क्रमशः एक करोड़ एवं ५ करोड़ रुपया होगी । यदि कॉर्पोरेशन ५ % ब्याज लेता है तो बैंक औद्योगिक सस्याओं को दिये ऋणों पर ६.५% ब्याज से अधिक नहीं ले सकेंगे । उधार लेने वाले बैंक निगम को डिस्काउन्ट करने के लिये प्रस्तुत किये गये ऋणों पर पूर्ण जोखिम उठावेंगे ।

निगम के मार्ग में निम्न कठिनाइयाँ आने की संभावना है :—

(१) यदि बैंक अपने मुबक़्क़िनों को मध्यकालीन ऋण दिलाते हैं तो उनका सारा जाखिम अपने ऊपर लेना होगा । वास्तव में मध्यकालीन ऋण का क्षेत्र उनके लिये नवीन है और उनका अनुभव इस बारे में बहुत सीमित है, अतः स्वाभाविक है कि वे कुछ हिचकिचाये । हमारी सम्मति में सरकार को चाहिये कि इस जोखिम का कुछ अंश अपने ऊपर ले ।

(२) बैंकों का १.५% का मार्जिन जो ब्याज के रूप में छोड़ा गया है, वह जोखिम को देखने हुए कम है ।

(३) बैंकों के पास अभी इस क्षेत्र में सफल प्रयोग के हेतु कोई सन्तोषजनक आधारा नहीं है । आवश्यक तो यह था कि पहले जनता में दीर्घकालीन निधियों का विकास किया जाय । यदि भारतीय बैंक ३ से ६ वर्ष तक परिपक्वता वाले बॉन्ड सफलतापूर्वक निर्गमित कर सकें तो उद्योगों को मध्यकालीन साधन देने का आधार स्थापित हो जायगा ।

(४) मध्यकालीन ऋण देने की किमी भी योजना की सफलता सरकार की प्रयुक्त एवं सार्विक नीतियों पर निर्भर है, जो इस प्रकार की होनी चाहिए कि औद्योगिक समस्याओं को विस्तार के लिये उधार लेने का प्रेरणा मिले तथा शीघ्र चुकाने में सुविधा हो ।

## (६) मध्यम वित्त निगम की स्थापना

इन सन् १९५८ में मध्यम वित्त निगम की स्थापना हो गई है । प्रधान

कार्यालय बम्बई है। यह निगम पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित निर्जी क्षेत्र के मध्यम कारखानों को आर्थिक सहायता देगा।

निगम की पूंजी ३१ करोड़ रुपया होगी जिसमें ॥ ४ करोड़ रुपया पंद्रह वको में प्राप्त होगा। इन वकों के प्रतिनिधि निगम के संचालक मण्डल में होंगे।

वकों के नाम ये हैं - सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक, पञ्जाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया, हैदराबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, नेशनल बैंक ऑफ इण्डिया, यूनाइटेड कामर्सियल बैंक, चारटर्ड बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया तथा देना बैंक।

इन बैंकों के प्रतिनिधि विशेष प्रशिक्षण के लिए भ्रमरोका भ्रम जायेंगे।

रुप २६ करोड़ रुपया भारत सरकार से निगम को ऋण के रूप में मिलगा।

निगम को यह ऋण भ्रमरोका में भारत को प्राप्त होने वाले १४० करोड़ रुपये में से दिया जायगा जिसके बारे में आजकल भ्रमरोकी अधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है।

रुप ११४ करोड़ रुपया विभिन्न योजनाओं पर खर्च किया जायगा।

माना है कि भारतीय रिजर्व बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी श्री ई० रामसुब्रह्मण्यम मध्यम वित्त निगम के अध्ययन बनाये जायेंगे।

वह उद्योगों को औद्योगिक निगम से सहायता मिलती है।

### STANDARD QUESTIONS

- 1 Describe the functions of (a) National Industrial Development Corporation and (b) National Small Industries Corporation
- 2 Attempt a lucid note on the International Finance Corporation
- 3 What do you know about Refinance Corporation ?
- 4 What is Industrial Credit and Investment Corporation of India ? What part is it expected to play in the provision of Industrial Finance in India ?
- 5 Describe briefly the principal factors which inhibit private investment in industries at the present time in India
- 6 What do you mean by Investment Trusts ? Describe its classifications

# भारत में जन-संख्या के वितरण की समस्या

( Problem of Distribution of Population in India )

‘जन-संख्या के घनत्व’ से आशय—

‘जनसंख्या के घनत्व’ से हमारा आशय यह है कि किसी दश अथवा किसी देश के राज्य में एक वर्ग मील में कितनी व्यक्ति रहते हैं। यदि हमको किसी देश की जनसंख्या का घनत्व जानना हो तो यह पता लगाना चाहिये कि उसका क्षेत्रफल कितना है और वहाँ की जनसंख्या कितनी है। फिर जनसंख्या को क्षेत्रफल से भाग देना चाहिए और जो भजनफल निकले वही उस जनसंख्या का घनत्व होगा।

भारत में जनसंख्या का घनत्व—

हमारे देश में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग मील ३१२ है। यह समस्त देश का औसत घनत्व है; किन्तु देश के विभिन्न भागों की भाँकी करने से पता लगता है कि भारत के विभिन्न राज्यों में जनसंख्या का घनत्व अलग अलग है—दिल्ली में ३,०१७, केरल में १,०१५, बङ्गाल में ८४१, बिहार में ५७२, उत्तर प्रदेश में ५६२, पंजाब में ३३८, राजस्थान में ११६, अडमान व निकोबार द्वीपों में ११० इत्यादि। जनसंख्या के घनत्व की इस प्रादेशिक विभिन्नता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :—

भारत में जनसंख्या के घनत्व में प्रादेशिक विभिन्नता के कारण—

( १ ) प्राकृतिक रचना—जनसंख्या का घनत्व किसी देश की प्राकृतिक रचना पर निर्भर करता है। जो स्थान पहाड़ी अथवा पठारी हैं अथवा जहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं है वहाँ घनत्व कम होता है और उपजाऊ मैदानी क्षेत्रों में प्रायः जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। पंजाब, उत्तरप्रदेश एवं बङ्गाल राज्यों में भूमि की उर्वरता के कारण ही जनसंख्या का घनत्व अधिक है एवं राजस्थान के मरुस्थल और दक्षिण के पठारी प्रदेशों में घनत्व कम है।

( २ ) जलवायु—भूमि की रचना के साथ साथ सुन्दर जलवायु का होना भी आवश्यक है। जनवायु पर लोगों का स्वास्थ्य ही नहीं बरन् फसलों का उत्पादन भी निर्भर करता है। यही कारण है कि जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ उत्पादन अधिक

हो सकता है यदि भूमि भा उपजाऊ है। एम प्रदेग अधिक यक्तियों के लिए जीवन निर्वाह का साधन प्रस्तुत कर सकता है। यहाँ कारण है कि भारत के दक्षिणी-पूर्वी भाग में आपश्चात् जन संख्या अधिक है।

( ३ ) चावल की उपज के क्षेत्र—बङ्गाल तथा बिहार में भी जन संख्या का घनत्व अधिक है यद्यपि —

( अ ) अ य अताजा की अपेक्षा चावल का उनका मात्रा में अधिक प्रादमिथी की उपरपूति हो जाती है।

( आ ) चावल में भाजन के अधिक पोष्टिक तत्व हान है।

( इ ) चावल का प्रति एकाद पंदावार भी अधिक होती है।

( ई ) चावल की फसल तयार भा बहुत गीम हो जाती है।

( ४ ) सिचाई—जन संख्या का घनत्व सिचाई के साधनों पर निर्भर करता है। जिन स्थानों में मनुष्य ने कृत्रिम परिश्रम करके सिचाई के लिए नहरें बना ली हैं वहाँ भी घनत्व अधिक है जम—पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में।

( ५ ) औद्योगिक उन्नति—एम प्रदेश जहाँ उद्योग धंधों का प्रगति के लिए समस्त नैसर्गिक साधन उपलब्ध हो तथा अधिक दृष्टिकोण में भी जा भाग समृद्धि पाती है वहाँ भी जन संख्या का घनत्व अधिक देखा जाता है जैसे—बिहार उड़ीसा इत्यादि।

( ६ ) सुरक्षा—जिन प्रदेशों में मनुष्य की घनत्व जान व माल का भय नहीं होता वहाँ भी घनत्व अधिक होता है जैसे—मध्य प्रदेश। इसके विपरीत पनतीम तथा सीमावर्ती राज्यों में जान व माल का भय होने के कारण जन संख्या का बहुत कम घनत्व है।

( ७ ) विभाजन के परिणामस्वरूप आवास—भारत के बंटवार के बाद हमारे देश में अनन्त व्यक्ति पाकिस्तान में आय और व एम प्रदेश में बस गये जहाँ कि जनसंख्या उनके अनुकूल थी अतः उन प्रदेशों में जन संख्या का घनत्व बढ़ गया जम—दिल्ली राज्य में।

( ८ ) प्रवासी प्रवृत्ति का अभाव—भारतवर्ष में प्रवास प्रवृत्ति का अभाव भी अधिक घनत्व के लिए उत्तरदायी है। अय क्षेत्रों में प्रवास करने की अपेक्षा लोग अपने ही क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते हैं। फलतः उन्हें निम्न जीवन स्तर अपना पड़ता है। भाषा घम एवं संस्कृति की विषमता भा प्रजातीय प्रवृत्ति में बाधक है।

( ९ ) सिचाई के साधन का अभाव—जिन प्रदेशों में वर्षा का अभाव है वहाँ के मध्यम उपलब्ध है वहाँ भी प्रायः जन संख्या का घनत्व दृष्टा जाता है।



है। उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग राजस्थान के उत्तरा और पश्चिमी भाग और दक्षिणी पंजाब में यद्यपि अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है परन्तु मिचाई की उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार इन भागों में अच्छी जन सख्या है।

( १० ) नदियों के उद्ग—नदियों के उद्ग में भी अनक सुविधाय होन के कारण जन सख्या के घनत्व में वृद्धि हो जाती है जैसे—यहानदी कृष्णा गोदावरी तथा कावेरी नदियों के उद्गों में अच्छी आबादा है।

( ११ ) विशाल वस्तुओं के उत्पादन केन्द्र—कुछ प्रदेशों में किंचित महत्व पूर्ण व्यापारिक वस्तुओं का उत्पादन होता है जिससे आकर्षित होकर लोग वहां बस जाते हैं। जैसे अमर में चाय के हरे भरे बगीचों में अनक व्यक्तियों की आकर्षित कर लिया है। इसी प्रकार बंगाल में जूट के उत्पादन और काशी मिट्टी के धान में रुई के उत्पादन के कारण उन क्षेत्रों में जन सख्या का अधिक घनत्व है।

( १२ ) खनिज पदार्थों के क्षेत्र—जिन भागों में खनिज पदार्थ पाये जाते हैं वहां अथ कठिनाइयाँ के हाते हुए भी लोग जाकर बस गये हैं। उदाहरणार्थ छोटा नागपुर का पठार खनिज सम्पदा की दृष्टि से अत्यंत धनी है अतः वहां अनक लोग आकर बस गये हैं। इसी प्रकार राजस्थान में जैसलमेर के निकटवर्ती क्षेत्र में पेट्रोलियम की खोज हो रही है। यदि वहां पेट्रोल मिल जायगा तो जन सख्या के घनत्व में अवश्य वृद्धि हो जायगी।

( १३ ) यातायात के साधनों की सुविधा—जिन भागों में यातायात के साधनों का जाल बिछा हुआ है वहां भी प्रायः जन सख्या का केन्द्रीयकरण देखा जाता है। जैसे गंगा एवं सतलज के मैदान में तटीय मैदान एवं उल्हा क्षेत्रों में थल एवं जल की सुविधा होने के कारण वहां घनी आबादा पाई जाती है। इसके विपरीत पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों में मरुस्थला भागों एवं घन वनों में यातायात के साधनों की अपर्याप्तता अथवा अभाव के कारण जन सख्या की मात्रा बहुत ही कम है।

( १४ ) अनुकूल स्थिति—जिन नगरों अथवा क्षेत्रों का भौगोलिक स्थिति अनुकूल होती है वहां भी जन सख्या का आधिक्य हो जाता है। उदाहरणार्थ दिल्ली कानपुर आगरा इलाहाबाद आदि नगरों की अनुकूल स्थिति होने के कारण ही वहां जन सख्या का अधिक घनत्व है।

( १५ ) अथ कारण प्रायः ऐसा भी देखा जाता है कि जो स्थान सुरक्षा का दृष्टि से अधिक श्रेष्ठ होत है वहां भी जन सख्या का केन्द्रीयकरण हो जाता है। भारत और पाकिस्तान की सीमा काश्मीर व आजाद काश्मीर की सीमा तथा गोम्रा में सुरक्षा की मात्रा कम होने से आबादी भी कम है। इसी प्रकार घन जंगलों में जंगलाप आ के भय से वहां मनुष्य नहीं रहते। चम्बल के खण्डहरा में चोर व डाकूओं के भय के कारण लोग रहना पसंद नहीं करते।

## जन सख्या का घनत्व और आर्थिक समृद्धि —

जन सख्या का घनत्व और आर्थिक समृद्धि आवश्यक रूप से सम्बंधित बात ही नहीं बात नहीं है। उदाहरण के लिए भारत और सयुक्त प्रवेश्य राज्य (विशेषतः मिचि) अपनी जन सख्या के घनत्व में बहुत अंतर होना भी दोनों ही आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। मिचि में जन सख्या का घनत्व केवल ३५ है, जबकि भारत में ३१२ है। इसी प्रकार ब्रिटिश और अमेरिका की जन सख्या के घनत्व में भी भारी अंतर है (क्रमशः ७१० एवं ४२)। इतना अंतर होना भी दोनों देशों में लाया जा जीवन स्तर लगभग समान है। यह उल्लेखनीय है कि ये दोनों ही देश भारत की तुलना में (जिसकी जन सख्या का घनत्व ३१२ है) अधिक समृद्धिवाला है। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी देश की जन सख्या और उसकी आर्थिक समृद्धि में कोई सम्बंध स्थापित नहीं किया जा सकता। वास्तव में दो देशों की आर्थिक समृद्धि के विषय में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हम वहाँ के लोग के भौतिक प्रसाधन और कार्य कुशलता पर भी ध्यान देना होगा।

भारत में जन सख्या के वितरण की विशेषताएँ—

(१) प्रादेशिक विभिन्नता—यद्यपि हमारा देश में जन सख्या का घनत्व प्रति बग मील २१२ है किन्तु देश के विभिन्न राज्यों में जन सख्या का घनत्व अलग अलग है जैसे—दिल्ली में ३०१७, करल में १०१५, बंगाल में ८४१, बिहार में ४७२, उत्तर प्रदेश में ५६२, पंजाब में ३३८, राजस्थान में ११६, अठमान निकोबार द्वीपों में ११०, इत्यादि। देश के विभिन्न भागों में विभिन्न भौतिक एवं आर्थिक सुविधाओं के कारण ही यह प्रादेशिक विभिन्नता पाई जाती है।

(२) निरन्तर वृद्धिशील—जन सख्या के अनुसार विश्व में चीन के बाद भारत का दूसरा नम्बर है। निम्न तालिका में भारत की जन सख्या की वृद्धि की गति का अनुमान लगाया जा सकता है —

वर्ष	जन सख्या ( दस लाख में )	दशाब्दी का वृद्धि ( दस लाख में )	वृद्धि का प्रतिशत
१८८१	२३५५	—	—
१९०१	२३५६	०४	+ ०.२
१९११	२४६०	१३५	+ ५.६
१९२१	२४८१	०६	— ०.६
१९३१	२७५५	२७४	+ १०.४
१९४१	२९२८	३७३	+ १२.७
१९५१	३५६८	४४१	+ १३.०

उपरोक्त तालिका से यह विदित होता है कि सन् १९०१ से १९२१ तक भारतीय जन-संख्या में मद गति में वृद्धि हुई, किन्तु उसके बाद वृद्धि की गति तेज रही है। सन् १९५१ की जन गणना के अनुसार देश की कुल जन-संख्या (पाकिस्तान को छोड़ कर) ३५.६६ करोड़ थी। सन् १९५८ के मध्य में भारत की जन-संख्या अनुमानतः ३६.७५ करोड़ थी और सन् १९६१ में यह बढ़ कर लगभग ४१ करोड़ हो जायगी। योजना आयोग ने प्रथम दो पंच वर्षीय योजनाओं की अवधि और बाद की अवधियों के लिये जन-संख्या में वृद्धि की निम्न दर का अनुमान किया है —

सन् १९५०-६० के लिये वृद्धि की गति १२.५% प्रति दशक।

सन् १९६१-७० के लिये वृद्धि की गति १३.३% प्रति दशक।

सन् १९७१-८० के लिये वृद्धि की गति १४.०% प्रति दशक।

जन गणना कमिश्नर ने यह भय प्रकट किया है कि उक्त दरों को ध्यान में रखते हुए हमारी जन-संख्या सन् १९५१ में ३६ करोड़ में बढ़ कर सन् १९६१ में ४१ करोड़, सन् १९७१ में ४७ करोड़ और सन् १९८१ में ५२ करोड़ हो जायगी।

(३) जन-संख्या का ग्रामीण एवं नगरीय आधार पर विभाजन—देश की ३५.६६ करोड़ की कुल जन-संख्या में से ६.१६ करोड़ अथवा १७.३% व्यक्ति नगरों और कस्बों में रहते हैं, जबकि शेष २९.५० करोड़ अथवा ८२.७% व्यक्ति गांवों में निवास करते हैं। सन् १९४१-१९५१ के दशक में शहरी जन-संख्या में ३.४% की वृद्धि हुई तथा ग्रामीण जन-संख्या में ३.४% की कमी हुई है। नगरीय जन-संख्या की वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं —

- (अ) गांव में व्यक्ति अधिक है तथा भूमि कम है। इसका प्रतिरिक्त सहायक उद्योग धंधों की भी कमी है, अतः पेट की खातिर गांवों से नगरों की ओर प्रवास बढ़ रहा है।
- (आ) आर्थिक नियोजन के परिणामस्वरूप भी नगरों में औद्योगिकरण का अधिक विकास हुआ है, जिससे नगरों की ओर लोगों का आकर्षण बढ़ गया है।
- (इ) ग्रामीण जीवन की अपेक्षा अनेक सुख सुविधाओं की दृष्टि में भी नागरिक जीवन सुविधाजनक होता है, अतः प्रायः सभी लोगों में नागरिक जीवन के प्रति रुचि होती है।
- (ई) जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् जमींदार कुटुम्बों का गांव से नगरों की ओर प्रवास बढ़ रहा है।
- (उ) देश के बंटवारे के बाद व्यवस्थापित न अधिकतर नगरों में ही रहना पसन्द किया है, क्योंकि वहाँ उनको जीवनोपार्जन की अधिक सुविधाएँ थीं।

(४) स्त्री-पुरुष का अनुपात—सन् १९५१ म १००० पुरुषों के पीछे ६४७ स्त्रियाँ थीं। प्रति हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों का अनुपात सबसे कम उत्तर-पश्चिम भारत में (५८३) और सबसे अधिक दक्षिण भारत में (६६६) था। भारत के १० बड़े नगरों में प्रति हजार पुरुषों के पीछे सन् १९५१ में स्त्रियों की संख्या इस प्रकार थी— बृहत्तर कलकत्ता ६०२ बृहत्तर बम्बई ५६६ मद्रास ६२१ दिल्ली ७५० हैदराबाद ६८६ अहमदाबाद ७६४ बंगलौर ८८३ कानपुर ६६६ पूना ८३३ और लखनऊ ७८३। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की कम संख्या होने का प्रमुख कारण है। भारतवर्ष में जन्म से ही लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के प्रति उदासीनता का व्यवहार किया जाता है। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा के कारण भी उन्हें प्रजनन क्षमता का सामना करना पड़ता है। प्रेम के पुत्र एवं बाद की अपेक्षा अप्रवा दैनिक जीवन में अपर्याप्त या अनुचित आहार भारतीय स्त्रियों के निम्न स्वास्थ्य स्तर के लिए उत्तरदायी है। सौभाग्य का विषय है कि गत कुछ समय से शिक्षा प्रसार के साथ साथ स्त्रियों के प्रति अपेक्षापूर्ण व्यवहार कम होता जा रहा है। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का भी धीरे-धीरे लोप हो रहा है और महिला डाक्टरों एवं प्रसूति गृहों की भी संख्या बढ़ रही है।

(५) आयु के आधार पर जन संख्या—यदि आयु के आधार पर भारतीय जन संख्या का अध्ययन करें तो हम निम्न आकृति उपलब्ध होगी —

शिशु व बच्चे	३८.३%
युवा स्त्री पुरुष	३३.०%
श्रीमं स्त्री पुरुष	२०.४%
वृद्ध स्त्री पुरुष	८.३%

इन आकृतियों के विश्लेषण से हम निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं —

(अ) भारत में शिशु तथा बच्चे की जन संख्या अधिक है यद्यपि यह प्रभा सक्षम नहीं है किंतु वास्तव में देश की प्रगति का बाधक इन्हीं के कारण बन जाना है।

(आ) भारत में वृद्ध स्त्री पुरुषों की संख्या बहुत बड़ी है अर्थात् वृद्ध जन से पहले ही प्रायः लोग मर जाते हैं। इससे देश का बड़ी हानि होता है, क्योंकि एक तो अनुभव वृद्ध व्यक्तियों के उचित पथ प्रदर्शन का लाभ नहीं मिल पाता। दूसरे उनका अभाव में उत्पादनशक्ति भी घटती है।

(इ) हमारी औसत आयु भी अल्प देशों की अपेक्षा बहुत कम है।

(ई) देश में युवा एवं वृद्धों की जन संख्या  $(३३.० + २०.४) = ५३.४\%$  है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि देश के ३६.६७ करोड़ व्यक्तियों में से

केवल १८ करोड़ व्यक्ति ही काम करने वाले हैं, अतः जितने व्यक्ति उत्पादन में सलग्न हैं उनके अतिरिक्त लगभग उतने ही व्यक्तियों का पोषण भी उन्हीं को करना पड़ता है।

(ऊ) भारत में बच्चों का अनुपात ३८% और बुढ़ों का केवल ८% यह संकेत करता है कि देश में जन्म एवं मृत्यु दर दोनों ही अधिक हैं।

(६) भाषाओं के आधार पर विभाजन—सन् १९५१ की जन गणना के अनुसार देश में कुल ८४५ भाषाएँ अथवा बोलियाँ बोलती जाती हैं, जिनमें ७२० भारतीय भाषाएँ या बोलियाँ (इनमें से प्रत्येक के भाषियों की संख्या १ लाख से कम है) तथा ६३ गैर भारतीय भाषाएँ हैं। ६१ प्रतिशत जनता संविधान में उल्लिखित १४ भाषाओं में से किसी न किसी एक भाषा को बोलती हैं। दिल्ली, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश को छोड़कर दोष भारत में हिन्दी बोलने वालों की संख्या १०० करोड़ थी। हिन्दी, उर्दू, हिन्दुस्तानी तथा पंजाबी बोलने वालों की संख्या १४६६ करोड़ थी।

(७) व्यावसायिक आधार पर विभाजन—सन् १९५०-५१ में ३५.६३ करोड़ जन संख्या में से देश में १४.३२ करोड़ व्यक्तियों के रोजगार में सलग्न होने का अनुमान लगाया गया है—१०.३६ करोड़ व्यक्ति कृषि सम्बन्धी कार्यों में, १.५३ करोड़ व्यक्ति खनिज तथा हस्तशिल्प उद्योगों में, १.११ करोड़ व्यक्ति वाणिज्य, बीमा, बैंकिंग, यातायात तथा परिवहन उद्योगों में, ६४ लाख व्यक्ति विभिन्न व्यवसायों में, ३६ लाख व्यक्ति सरकारी नौकरियों में तथा २६ लाख व्यक्ति घरेलू नौकरियों में। अतः स्पष्ट है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी लगभग ७०% जन-संख्या कृषि पर अवलम्बित है अथवा दोष व्यवसायों में लगी हुई है।

**भारतीय जन-संख्या का व्यावसायिक वितरण—**

व्यावसायिक आधार पर जन संख्या के वितरण में इस देश के आर्थिक विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। सन् १९५१ की जन-गणना के अनुसार भारत की ३५.६३ करोड़ की जन-संख्या में से देश में १४.३२ करोड़ व्यक्तियों के रोजगार में सलग्न होने का अनुमान लगाया है—१०.३६ करोड़ व्यक्ति कृषि सम्बन्धी कार्यों में, १.३३ करोड़ व्यक्ति खनिज तथा हस्तशिल्प उद्योगों में, १.११ करोड़ व्यक्ति वाणिज्य, बीमा तथा बैंकिंग और यातायात तथा संचार साधनों में, ६४ लाख व्यक्ति विभिन्न व्यवसायों में, ३६ लाख व्यक्ति सरकारी नौकरियों में तथा २६ लाख व्यक्ति घरेलू सेवाओं में लगे हैं।

प्रत्येक १०० भारतीयों (आर्थिक व्यक्ति सहित) में से ४७ भूमिधर किसान, ६ वास्तुकार, १३ भूमिहीन मजदूर तथा १ जमींदार था, जबकि उद्योगों या अन्य कृषि

जय व्यवसायो बाणिज्य परिवहन और विविध व्यवसायो म क्रमश १० ६ २ और १० यत्ति लगे हुये स ।

व्यावसायिक वितरण का आर्थिक महत्व—

मन् १९५१ की जन गणना सम्बन्धी आँकड़ो म यह स्पष्ट है कि हमारा दग मुख्यत कृषि प्रधान दग है जिनकी लगभग ७०% जन सख्या कृषि पर अवलम्बित है तथा उद्योग ध धा म लगे हुए यत्ति १०% से भी कम है । आर्थिक विकास की दृष्टि स एसी व्यवस्था श्रुत नही वही जा सकती क्योंकि यदि दुर्भाग्य से किसी वष कृषि की फसल खराब हा जाव तो ममरत देश का आर्थिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है । कृषि म सलग्न व्यक्तियो का दसा भी सतोषजनक नही कही जा सकती । उनम प्रति १००० कृषका के पाछे ४०२ एस किमान है जिनके पास अपनी भूमि नही है । इहे जमादारा से भूमि लनी पडती है । जमींदारी उन्मूलन के पहल जमींदारो द्वारा इनका अत्यधिक लोपण किया जाता था । बिना खती के थमिक जिनकी सख्या लगभग ४९ करोड है इसम दथनीय दगा म है । एम श्रमिको की सख्या उत्तर की अपेक्षा दक्षिणी भारत म अधिक है । इन श्रमिको की वार्षिक आय का औसत २०४) है । इतनी कम आय इन व कारण इह अनक प्रकार की कठिनाइयो का सामना करना पडता है । लक्षेप म हम यह कह सकते है कि कृषि म सलग्न लगभग २५ करोड लागो म न अधिकांश यत्तियो की आर्थिक दगा खराब है । कृषि पर जन सख्या का अत्यधिक भार हान व कारण देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग ४६% कृषि म ही प्राप्त हाता है । भारतवर्ष की अपेक्षा इङ्गलंड एव संयुक्त राष्ट्र अमेरिका म कही कम लोग कृषि का काय करत है । जबकि भारत के १००० व्यक्तियो म से ७०६ कृषि पशु वन तथा मछली व्यवसाय म लगे हुये है तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका म केवल १२८ तथा ग्रट ब्रिटेन म केवल ५६ लोग इस काय में लगे है । इङ्गलंड अथवा अमेरिका की अपेक्षा भारत म बहुत कम लोग उद्योग तथा अय सेवाधा म लगे हुए हैं । जबकि १००० व्यक्तियो म से भारत के केवल १५३ व्यक्ति ही खानो उद्योगो तथा बाणिज्य म लगे हुए है तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका म ४५६ तथा ग्रट ब्रिटेन म ५५५ व्यक्ति लगे हुए है । अय उद्योगा तथा सेवाधो म सलग्न लोगो का अनुमान हमारे दग म प्रत्येक १००० म से केवल १४१ है जबकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा ग्रट ब्रिटेन म यह आंकडा ४१६ तथा ३६५ है । यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अथवा इङ्गलंड का अपेक्षा भारतवर्ष का अय व्यवस्था असंतुलित वही जाती है । इङ्गलंड तथा अमेरिका म लगभग आधे लोग कृषि पर और गेप उद्योगो म तथा अय कायों म लगे है अत यत्ति इन देश म वभी कृषि की दगा बिगडती है ता कोई बिशेष चिन्ता नही करनी पडता परंतु हमारा देश म एसा परिस्थिति होन पर आर्थिक संतुलन ही बिगड जाता

है। यही कारण है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के द्वारा कृषि पर जनता के भार को कम करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण हमारे देश के खेत बहुत छोटे हैं एवं प्रति एकड़ उत्पादन भी अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है, इसी कारण दरिद्रता एवं बेकारी बढ़ रही है तथा लोगों का जीवन स्तर बहुत नीचा है। आशा है कि आर्थिक नियोजन के द्वारा यह समस्या भविष्य में हल नहीं हो सकेगी।

**ग्रामीण अर्द्ध-रोजगारी को दूर करने के उपाय—**

हमारे देश में जहाँ एक ओर पूर्णतः बेरोजगार लोगों की भारी समस्या है, वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले अधिकांश कृषक ऐसे हैं, जिन्हें वर्ष में ३-४ महीने खाली रहना पड़ता है, क्योंकि उस काल में कोई फसल नहीं होती। इस अर्द्ध-रोजगार का प्रमुख कारण खेती करने का पुरातन ढङ्ग तथा कृषि का वर्षा पर निर्भर होना है। कृष्णामाचारी जाँच समिति के अनुसार लगभग ८०% कृषक वर्ष के लगभग ८ महीनों में बेकार रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग धंधों की कमी तथा जनसंख्या की अधिकता इसका मूल कारण है। ग्रामीण अर्द्ध-रोजगारी की समस्या को हल करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं :—

( १ ) कृषि को जीवन निर्वाह का साधन न मान कर एक व्यापारिक व्यवसाय समझा जाय। षकवन्दी के द्वारा बड़े आकार के खेतों में आधुनिक ढङ्गों से उन्नत बीज, उन्नत खाद एवं नवीनतम सिंचाई की सुविधाओं के द्वारा कृषि उत्पादन किया जाय।

( २ ) कृषि का वैज्ञानिक होना चाहिए। 'वैज्ञानिक' से हमारा तात्पर्य यह है कि खेती करने में विज्ञान के नये-नये तरीकों का उपयोग किया जाय, फसलों का हेरफेर हो, आपानी ढङ्ग से चावल उत्पन्न किया जाय, उपयुक्त क्षेत्रों में ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाय, इत्यादि।

( ३ ) कृषि के सहायक उद्योगों को बढ़ावा दिया जाय। यदि हमारे देश में कृषि के साथ साथ डेरी फार्म, मुर्गी पालन, रेशम के कीड़े पालना, मधुमक्खी पालन आदि सहायक धंधे अपनाये जायें, तो किसान वर्ष पर्यन्त काम में लगा रह सकता है।

( ४ ) कृषि से जनसंख्या का भार कम करने के लिए कुटीर उद्योगों को विकसित किया जाय। इससे उनके खाली समय का सदुपयोग होगा तथा अतिरिक्त आय होगी।

( ५ ) कुटीर उद्योगों के अलावा लघु उद्योगों की स्थापना को भी प्रात्नाहण

मिलना चाहिये । ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण की योजनाओं से छोटे मोटे उद्योग-धंधों की स्थापना को प्रेरणा मिलेगी ।

( ६ ) व्यक्तिगत कृषि के स्थान पर सहकारी ढांच को प्राथमिकता देना चाहिए ।

### STANDARD QUESTIONS

1. What is 'Density of Population' ? What are the factors that determine the density of population in India ? Does a high density of population in a country indicate prosperity ?
2. Briefly summarise some of the principal peculiarities regarding the distribution of population in India
3. Discuss the economic Significance of the occupational distribution of population in India Suggest measures to remove rural under employment in India



## क्या भारत में जन-संख्या का आधिक्य है ?

( Is India Over Populated ? )

### प्रारम्भिक—

कुछ लोगो के मतानुसार भारत में जन सख्या का आधिक्य नहीं है, क्योंकि यहाँ जन सख्या का घनत्व केवल ३१० व्यक्ति प्रति वर्ग मील है, जबकि हालैंड का ८२५\*३, बेल्जियम का ७३४\*४, जापान का ५७५\*४ और इङ्गलैंड का ५३७\*८ है। इस विचारधारा के समर्थक यह दलील देने हैं कि भारत के प्राकृतिक प्रसाधनों का अभी पूर्णरूपेण उपयोग नहीं हुआ है, अतः जन सख्या अधिक प्रतीत होती है। यदि हम अपने नैसर्गिक साधनों का पूर्ण उपयोग करके उत्पादन में वृद्धि करें, तो वही अधिक जन सख्या का पालन कर सकते हैं। इसके विपरीत, दूसरी विचारधारा के समर्थक यह कहते हैं कि जन सख्या के आधिक्य की कोई समस्या न समझना, वास्तव में सत्यता का गला घोटना है। जहाँ तक पहली दलील का सम्बन्ध है, उत्तरी पश्चिमी भारत व मध्यवर्ती भारत के राज्यों को छोड़कर भारत के शेष राज्यों में जन सख्या का घनत्व यूरोप के घन आबाद देशों की तुलना में कम नहीं है, जैसे—दिल्ली में ३,०१७ व्यक्ति प्रति वर्ग मील, केरल में १,०१५, बंगाल में ८४१, बिहार में ५७२, उत्तर प्रदेश में ५६२ और पंजाब में ३३८ है। इस द्वितीय विचारधारा के समर्थक निम्न दलीलों के आधार पर ऐसा कहते हैं कि भारत में जन सख्या का आधिक्य है।

**भारत में जन-सख्या का आधिक्य एवं उसके कारण—**

( १ ) मालयस के सिद्धान्तानुसार—मालयस के जन सख्या के सिद्धान्तानुसार यदि किसी देश में निवारक प्रतिबन्धों (जैसे ब्रह्मचर्य पालन, कम आयु में विवाह न करना, गर्भ निरोधक साधनों का प्रयोग, जीवन स्तर में सुधार, प्रादि) का अभाव होता है और इनके ग्यान पर प्राकृतिक प्रतिबन्ध (जैसे क्षीमारी, बेकारी, भूकम्प इत्यादि) क्रियाशील होते हैं, तो ऐसा समझा जाता है कि देश में जन-सख्या का आधिक्य है। भारत में निवारक प्रतिबन्धों का अभाव है। छाटी उम्र में विवाह होने

के कारण एव दूषित सिने वातावरण के कारण लोग ब्रह्मचर्य पालन में असमर्थ होते हैं। यहाँ विवाह एक धार्मिक कर्तव्य एव सन्तानोत्पत्ति एक सामाजिक आवश्यकता समझी जाती है। आजकल देश में केवल वाल विवाह एव बहु विवाह का ही प्रश्न नहीं है, वरन् वृद्ध विवाह का प्रचलन भी हमारे देश का बहुत बड़ा अभिगाथ है। फलतः मिद्वान्तानुसार प्राकृतिक प्रतिबन्ध देश में अधिक क्रियाशील रह रहे, जैसे—महामारियाँ, दुर्भिक्ष, बाढ़, भूकम्प, दमो इत्यादि। यहाँ मलेरिया से प्रति वर्ष १५ लाख व्यक्ति मर जाते हैं। सन् १९४३ के बङ्गाल दुर्भिक्ष में ३५ लाख व्यक्तियों की वलि चढ़ी। सन् १९५७ के ग्रीष्म काल में फ्लू के दानव ने अनेक व्यक्तियों के प्राण लिए। सन् १९५५ में रेल दुर्घटनाओं एव बाढ़ की आपत्तियों से भी सहस्रों व्यक्तियों की जानें चली गईं। अतः स्पष्ट है कि निवारक प्रतिबन्धों के अभाव में प्रकृति अपना कार्य तीव्रता से कर रही है। यह जन-संख्या के आधिक्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

(२) खाद्य समस्या के आधार पर—हमारे देश में जैन संख्या जिस गति से बढ़ी है, भोज्य सामग्री का उत्पादन उस अनुपात में नहीं बढ़ा है। सन् १९३८ में श्री बी० के० वत्सन ने अखिल भारतीय जन संख्या सम्मेलन के समक्ष अपने प्रव्यक्षीय भाषण में बताया था कि सन् १९१४ और सन् १९४० के बीच की अवधि में भारत में जन संख्या की वृद्धि १% हुई, परन्तु भोज्य सामग्री में वृद्धि केवल ०.६५% हुई। द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त हमारी खाद्य समस्या ने एक उग्र रूप धारण कर लिया और देश के विभाजन ने बटे पर नमक छिड़कने का काम किया। बँटवारे के परिणाम-स्वरूप यद्यपि भारत की कुल क्षेत्रफल का ७७% भाग मिला, किन्तु जन संख्या ८१% मिली। भारत से पाकिस्तान में केवल ७५ लाख लोग गये, किन्तु वहाँ में हमारे देश में १ करोड़ से भी अधिक व्यक्ति आये। राष्ट्रीय योजना समिति सन् १९४७, पंच-वर्षीय योजना आयोग सन् १९५३ एव खाद्यान्न जीवन समिति सन् १९५७ की रिपोर्टों के अनुसार भी इसी मत की पुष्टि होती है कि जन संख्या की वृद्धि के अनुपात में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है।

(३) वृद्धि की अत्यधिक गति—निम्न आंकड़ों से स्पष्ट है कि देश में जन-संख्या बढ़ी तेजी से बढ़ रही है—सन् १९११—२५२३ मिलियन, सन् १९३१—२७६.२ मि०, सन् १९५१—३६१.२ मि० तथा सन् १९५८ में ३९६.९ मि०। परन्तु जहाँ जन संख्या में वृद्धि हो रही है, वहाँ प्रति व्यक्ति बाई गई भूमि निरन्तर घटती जा रही है। यही नहीं, हमारे देश में गेहूँ और चावल उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है, जितनी तेजी से अन्य माले अनाजों का उत्पादन। खाद्य सामग्रियों के अतिरिक्त हमारे देश में चीनी, सब्जी, दूध इत्यादि का उपभोग भी निरन्तर कम होता जा रहा है।

(४) बेकारी की समस्या—यदि जन संख्या अनुकूलनम विन्दु से कम होनी,

तो बेकारी की समस्या इतनी भीषण न होती, जितनी कि आज है। योजना आयोग ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों ही वर्गों में बेकारी बढ़ रही है और समस्या इतनी विशाल है कि इसको थोड़े समय में हल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका सम्बन्ध जन सख्या के आधिक्य से है।

(५) प्रोफेसर कैनन का अनुकूलतम जन सख्या का सिद्धान्त—यदि देश की जन सख्या अनुकूलतम जन सख्या से अधिक है, तो जन सख्या की अत्यधिक वृद्धि के साथ प्रति व्यक्ति आय में उन्ही अनुपात में वृद्धि न होगी, जैसा कि भारत में घटित हो रहा है, अतः कैनन के सिद्धान्तानुसार भी हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हमारे देश में प्रति जन सख्या की समस्या विद्यमान है।

**जन-सख्या की वृद्धि को रोकने की आवश्यकता—**

बढ़ती हुई जन सख्या को रोकने की आवश्यकता इसलिये उत्पन्न होती है कि हमारा उपभोग स्तर बहुत नीचा है, जिसे ऊपर उठान का विशेष आवश्यकता है। जब तक हम इस अनावश्यक वृद्धि को न रोकेंगे, तब तक हमारी प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ सकती।

**जन-सख्या की वृद्धि को कैसे रोकें जाय ?—**

(१) शिक्षा का प्रचार—प्रोफेसर महालानोबीस ने अभी अपन अनुसन्धान में यह बताया है कि जिन परिवारों का प्रति व्यक्ति व्यय बढ़ता है, उनमें कम बच्चे होते हैं। हमारे देशों में, उच्च जीवन स्तर होने पर जन सख्या में कमी होने की सम्भावना है। शिक्षित लोग प्रायः गृहस्थी का भार उस समय तक नहीं उठाना चाहते जब तक कि उनमें स्वयं अपने पैरों पर खड़े होने की सामर्थ्य न हो "मोटरकार अथवा बच्चे" में वे बहुधा प्रथम वस्तु को ही प्राथमिकता देते हैं।

(२) आत्म-संयम—स्टेट सेन्सस कमिशनर ने यह सुझाव दिया है कि स्त्रियों का विवाह २० वर्ष से पहले नहीं होना चाहिए। जब तक कि किसी में अपन पैरों पर खड़े होने की सामर्थ्य न हो, तब तक उसको विवाह नहीं करना चाहिये और यदि विवाह करे भी तो आत्म-संयम द्वारा सन्तानोत्पत्ति से दूर रहना चाहिये।

(३) स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं को सुलभाना—विभिन्न रोगों के निवारणार्थ यहाँ अस्पतालों एवं प्रसूति गृहों की स्थापना होनी चाहिए। देश में सफाई का भी उत्तम प्रबन्ध होना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि लोगों को अधिक मात्रा में सतुलित भोजन दिया जाय एवं हमारे उपभोग के पदार्थ पीठिक हों।

(४) औद्योगीकरण—बड़े पैमाने के उद्योग की प्रगति के साथ साथ लघु एवं कुटीर उद्योगों की उत्पत्ति करना नितान्त आवश्यक है, जिससे कि पूरा राजगार सम्भव

हो सकें। औद्योगीकरण से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, जीवन स्तर ऊँचा होगा एवं प्रजनन की दर में भी ह्रास होगा। योजना आयोग का मत है कि जबसे द्वितीय पंच-वर्षीय योजना, जिसका प्रमुख उद्देश्य शीघ्र औद्योगीकरण करना है, प्रारम्भ हुई है, तब से जन-संख्या का भार कुछ कम प्रतीत होता है।

(५) कृषि में सुधार—हमारे देश के ६७% लोग कृषि पर निर्भर हैं, किन्तु भूमि की अनाधिक इकाई और कृषि के अर्वाञ्जित तरीकों के कारण प्रति एकड़ उत्पादन बहुत कम है। कृषि योग्य क्षेत्र को बढ़ाकर एवं कृषि ऋला में उन्नति द्वारा कृषि उपज को बढ़ाया जा सकता है।

(६) अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास—जन संख्या की समस्या को हल करने के लिए बङ्गाल, केरल, उ० प्र०, आदि अधिक जनत्व वाले राज्यों से राजस्थान, आसाम, उड़ीसा आदि कम जनत्व वाले राज्यों में लोगों के प्रवास का भी सुझाव दिया जा सकता है। कम जनत्व वाले क्षेत्रों में यदि हमारी सरकार रोजगार के विभिन्न साधन उत्पन्न कर दे, तो अधिक आकर्षण से वहाँ जनसंख्या का प्रवास हो सकता है।

(७) अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास—इसी प्रकार देश के बाहर विदेशों में भी जाकर हम जनसंख्या की समस्या सुलझा सकते हैं, किन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि विदेशों में भारतियों के प्रवास पर जो कठ प्रतिबन्ध लगे हुए हैं उनकी शिथिलता के लिए हमारी सरकार आवाज उठाए।

(८) कृत्रिम साधनों का उपयोग—पाश्चात्य देशों में इन साधनों का उपयोग का बड़ा बालगाला है, किन्तु भारतवर्ष में लोगों की अधिदा, अज्ञानता एवं रुढ़िवादिता इनकी लोक प्रियता में बाधक हो रही है। कुछ साधन के विचारानुसार इनका उपयोग ही अनुचित है, क्योंकि यदि इनके प्रयोग पर उचित नियंत्रण न रखा जाये, तो जनता में अनीतिवृत्तता फैलने का डर है। दूसरे, इनका प्रयोग अप्राकृतिक भी बताया जाता है। जहाँ तक प्रथम आरोप का सम्बन्ध है, उन साधनों के लोके प्रयोग की नीति तो देश के लिए अहितकर ही होगी, किन्तु राजकीय संस्थाओं के नियंत्रण में केवल अधिष्ठित व्यक्तियों को इनके प्रयोग के सम्बन्ध में यदि उचित परामर्श देना आरम्भ कर दिया जाये, तो लाभ हो सकता है। दूसरा आरोप है कि इनका उपयोग अप्राकृतिक है, जो निराधार प्रतीत होता है। यदि हमको प्रकृति के अनुसार ही चलना है, तब तो गमिया में वस्त्र न पहन कर नग्न रहना चाहिए, इसी प्रकार दवाइयों का प्रयोग भी अप्राकृतिक है, परन्तु वर्तमान युग में हमारी सभ्यता प्रकृति में दूर होती जा रहा है। जनसंख्या की समस्या को हल करने के लिए कृत्रिम साधनों का

प्रयोग प्रतुष्टि नहीं कहा जा सकता। पंचवर्षीय योजना आयोग ने भी कृषि मन्त्रालय के प्रयोग सम्बन्धी सूचना एवं प्रचार करने वाली अनेक समितियों की सहायता देने का समर्पण किया है।

(६) पारिवारिक नियोजन—इसके लिए कृषक अथवा मध्यम पद्धति।

### STANDARD QUESTION

1. Is India overpopulated ? What measures do you suggest to solve the problem ?

अध्याय २०

## परिवार नियोजन

( Family Planning )

परिवार नियोजन—प्राज की आवश्यकता—

गांधारी जब अपने सौ पुत्रों की मृत्यु पर विस्मय करती है, तो उपहास के साथ भौतिक कहता है कि 'जो सन्तानें मक्खियों की तरह पैदा होगी वे मक्खियों की तरह ही नष्ट होगी।' भारत में वर्तमान जनसंख्या की समस्या को लेकर प्रसिद्ध अंग्रेज वैज्ञानिक जूलिएन हक्सले का कहना है कि यदि भारत अपनी जनसंख्या की समस्या को हल न कर सका, तो यह बहुत बड़ी राजनीति और सामाजिक दुष्टता हो जायेगी।

वर्तमान विज्ञान के युग में हमारी जितनी समस्याएँ हैं उतनी कभी भी न थीं। मध्यम अंगी क लोगों में शिक्षा की बात तो दूर रही, उन्हें भोजन, धन, मकान, आदि की कमी बुरी तरह सता रही है। यद्यपि आर्थिक समृद्धि के हेतु पंच वर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया है, परन्तु जैसा कि प्रधान मंत्री नेहरू ने 'नियोजित विश्व के छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन' (सन् १९५६) का उद्घाटन करते हुए कहा था, यदि जनसंख्या बढ़ती रही तो पंच वर्षीय योजनाओं का कोई अर्थ नहीं। यदि हमें वास्तविक भौतिक उन्नति करनी है, तो अनिवार्यतः परिवार नियोजन पर विचार करना पड़ेगा।

सर्व प्रथम हम अपनी गिनतियाँ अपने सम्मुख रखें। बंगाल में प्रत्येक ४० सेंकिन्ड में एक बालक जन्म लेता है और हर एक मिनट में एक मरता है। २०,००० बालक भारत में प्रति दिन जन्मते हैं और प्रायः १२,००० व्यक्ति प्रति दिन खान के लिए देश में अधिक हो लाने हैं। इस प्रकार हमारी बढ़ोतरी ५० लाख प्रति वर्ष है। अनुमान है कि इस गति से तीस वर्ष में हम दुगुन हो जायेंगे। हम लोग अनुत्तरदायित्व पूर्ण ढङ्ग से कांड मछलियों की भाँति उत्पादन में लगे हैं। भाग्यहीन निम्न मध्यम वर्ग सन्तानोत्पत्ति को अपना मनोरन्जन मानता है। फिर सन्तान भंड बकरियों की भाँति तो पलंगी हो। न कोई लड़की 'लक्ष्मी' है, न कोई लड़का 'नागयरा' हो सकता है। यदि किसी के केवल पुनिया हो तो भी कोई भय नहीं। प्राज पुत्र और पुत्री दोनों कानून की दृष्टि में समान हैं, दोनों को सम्पत्ति में भाग मिलता है। वास्तव

में केवल एक ही सन्तान वरदान है, वही यथेष्ट होनी चाहिए। अधिक सन्तान धनवान और निर्धन, गाताओ और बालको सभी के लिए अभिशाप है। किन्तु उच्च व मध्यम वर्ग इस ओर पर्याप्त सचेत और सचेष्ट हैं। निम्न मध्यम और निर्धन वर्ग, जो देश का ८० प्रतिशत है, सोया हुआ है। इस सोने का एक परिणाम यही होगा कि उच्च वर्ग कम होता जायगा और निम्न वर्ग अधिक—अर्थात्, उच्च वर्ग और अधिक धनी और निम्न वर्ग और अधिक निर्धन। इस प्रकार निम्न वर्ग का शारीरिक और मानसिक स्तर और भी गिर जायगा। सन्तति को प्रकृति की देन समझना हमारी एक बड़ी भूल है। यह लकीर के फकीर बनने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। अच्छा हो, यदि हम युग के साथ चलें और शीघ्रातिशीघ्र बढ़ने।

**परिवार नियोजन क्या है ?—**

परिवार नियोजन के अन्तर्गत 'काम-निष्ठा', विवाह सम्बन्धी परामर्श, विवाह-स्वास्थ्य शिक्षा, बालक होने की अवधि का निश्चय करना और परिवार के बजट पर परामर्श देना सम्मिलित है। राजकुमारी अमृतादेवी ने जो कुछ समय पूर्व हमारी स्वास्थ्य मन्त्राली थी, मुरझित अवधि प्रणाली अथवा ऐसे सभोग की पद्धति का प्रचार किया है जब सभोग में प्रसव की सम्भावना नहीं होनी। यह न्यूनतम व्यय का साधन है। इसमें स्त्री के स्वास्थ्य को भी कोई मक्कट नहीं, जैसा कि अन्य विधियों में हो सकता है।

**परिवार नियोजन के साधन—**

भले ही हम गर्भ निरोधक कृत्रिम साधनों का प्रयोग न भी करें, फिर भी हम पारिवारिक नियोजन के अन्य सिद्धान्तों पर चलकर परिवारों के आकारों को सीमित रखने में सफल हो सके हैं। उदाहरण के लिए, यदि लड़कियों का विवाह १४ वर्ष की अवस्था में न करके २० वर्ष की आयु पर किया जाय, तो १४ वर्ष में २० वर्ष तक होने वाली मृत्यु न हो सकेगी। इसका एक सुन्दर प्रभाव यह भी होगा कि कच्ची आयु में गर्भ धारण करने से स्वास्थ्य पर जो बुरा प्रभाव पड़ता है वह न पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जन्म दर में भी कमी होगी। पारिवारिक नियोजन के सिद्धान्तों के प्रचार के साथ साथ यदि आत्म संयम की भावना भी बढ़ाई जाये, फिर तो 'सोने में सुहागा' है। हमारा देश ब्रह्मचर्य पालन के लिए विख्यात रहा है। आज हम स्वतन्त्र हैं, भ्रतः आरम्भ में ही लोगों के चरित्र एवं व्यक्तित्व के विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जाय, तो गृहस्थ जीवन में भी वे सफल कर अपनी पत्नियों को संतान देने में सक्षम होंगे। वही आयु में विवाह करके तथा समय का जीवन व्यतीत करते हुए यदि लोग अपने परिवारों के आकारों को छोटा रख सकें, तो स्वतः ही कुछ वर्षों में जन-संख्या की समस्या को हल कर सकते हैं। पारिवारिक नियोजन की विचारधारा का प्रचार मुख्यतः ग्रामीण जनता में करना

चाहिए। यह भी आवश्यक है कि यरीव लोगों का बच कटार के माधन या तो मुफ्त दिए जाय अथवा कम दामों पर दिए जाएं जिससे कि वे भी अपने परिवार को याजनापूर्वक चला सकें। सरकार को अविवाहितों एवं कुआरों को पारितोषण देना चाहिए। मरम वग के लिए मनोरंजन के साधन बनाए जाय। मनोरंजन केंद्रों पर जान के लिए आधे किराये लग पहला पर ठहरने का मरता प्रबंध हो। गहर म नाटक सिनमा वतमान मूल्या में चौथाई दर पर हा इत्यादि। देण का भुखमरी बेवारी और वरवादी म बचान के लिए कृत्रिम साधना को भी अपनाना चाहिये। फिर काफी समय स गल्य चिह्न म भी हाली है जो इस देण म पूरत सहायक है। वह ही पुरुष दानों के लिए सभव है। साथ ही गर्भाधान रोकन के लिए सस्ता औषधिया (जिन फौम गोल्या) निशुल्क बाटनी चाहिये।

**परिवार नियोजन की दिशा में राजकीय प्रयत्न—**

सरकार ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना में परिवार नियोजन को ब्र खालन के लिए चार करोड़ की धन राशि स्वीकृत की है। गावों में २००० के ब्र खुलन है। गहरों में पहले से ही ३०० खुलन है। प्रत्येक केन्द्र को मुफ्त बाटन के लिए १००० रुपए की गम निरोधक औषधिया दी जाती है। वहा परामर्श भी दिया जायगा। दिल्ली में ४० केन्द्र चल रहे हैं और एष बड़ी सख्या उनमें लाभ उठा रही है। वहां सतति निरोधक आधुनिक साधन भी सस्ते मूल्य पर उपलब्ध है।

यह हप का बिषय है कि परिवार नियोजन को सरकारी कार्यक्रम में स्थान मिला है। पर ग्रामों में अधिक प्रचार की आवश्यकता है क्योंकि अमली भारत ग्रामों में ही बसता है। साथ ही परामर्श कक्ष स्त्रिया को ही नहा पुरुषों को भी दिया जाना चाहिए। उसकी उह स्त्रियों में भी अधिक आवश्यकता है। परिवार नियोजन का प्रचार हमारे प्रोग्राम का एक महत्वपूर्ण भाग होना चाहिए। वास्तव में शिक्षात्मक प्रचार का एक विस्तृत देणायपी कार्यक्रम बनाए बिना काम न चलेगा।

यहां १५ नवम्बर सन् १९५८ को स्वास्थ्य मंत्री श्री दत्तात्रय परमुराम करमर कर की अध्यक्षता में परिवार आयोजन मण्डल का बैठक हुई जिसमें परिवार आयोजन कार्यक्रम की प्रगति तथा भावी याजना पर विचार किया गया। मंडल ने सरकार में इस कार्यक्रम को तालू करने के लिए सन् १९५६-६० में १ करोड़ रुपया देन का सिफारिश की है। इस कार्यक्रम की मुख्य मुख्य बात इस प्रकार है अधिक लोगों को इस कार्य में प्रगति कराना तथा शिक्षा देना दवाखान खालना परिवार आयोजन के बारे में शिक्षा देन के लिए कार्यक्रमों का निपुर्ति सभी स्वास्थ्य केंद्रों तथा चिह्न म सस्थाओं द्वारा गमनिरधक उपकरणों का वितरण तथा निरीक्षण और अनुमानन काम में तेजी।



मण्डल ने इस कार्यक्रम की प्रगति पर भी विचार किया। इस समय तक ७१८ क्लिनिक खोले जा चुके हैं। मार्च सन् १९५६ तक शहरों में १५० तथा गांवों में ६०० क्लिनिक खोलने का लक्ष्य था। उसमें ने शहरों में १७१ तथा गांवों में ४०० क्लिनिक खोले जा चुके हैं। विभिन्न राज्य सरकारों ने कन्द्रीय सरकार को यह सूचना दी है कि वे इन दवाखानों के अभाव का अर्थ यहाँ मार्च सन् १९६६ के पहले १५१ क्लिनिक और खोलने का विचार कर रही हैं।

मण्डल ने परिवार आयोजन के बारे में कुछ चुन चुन लागू का ट्रेनिंग देने के लिए थोड़े समय के शिविर खोलने का भी सुझाव दिया। ये शिविर सामुदायिक विकास केंद्रों के कन्दो में या हर जिले में किसी उपयुक्त स्थान पर लगभग ७ दिन तक लगाए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य हर गांव या कुटुम्ब में कुछ लोगो को परिवार आयोजन प्रचारक की ट्रेनिंग देना है।

### STANDARD QUESTION

1. Give your considered view regarding Family Planning with special reference to Indian conditions.

अध्याय २१

## भारत में श्रम-संघ आन्दोलन ( Indian Trade Union Movement )

श्रम संघ का अर्थ—

सदस्यी सिडनी तथा बीट्रिस वेब (Sidney and Beatrice Webb) के गद्यों में, श्रमिक संघ वास्तव में मजदूरी पर निर्वाह करने वाले व्यक्तियों के उनके काम की दगाए विगड़न न देने तथा उन्हें मुधारन के लिए बनाये गये स्थायी संगठन है। इस प्रकार इनके दो प्रमुख उद्देश्य हैं—प्रथम, जो कुछ प्राप्त हो चुका है उस बनाये रखना और दूसरे अधिक मुधार के लिए प्रयत्न करना।

मेवायोजक की तुलना में श्रमिक की स्थिति बड़ी दुबल होती है। वह अकेले अपनी आवश्यकताओं को अपने स्वामियों के सम्मुख रखने में हिचकता है। इसका कारण उसकी आर्थिक अवस्था का खराब व शिक्षा का अभाव होता है। परिणामस्वरूप उसे बड़ी हानि सहनी पड़ती है। श्रमिक के हित की रक्षा के लिए ही श्रमिक संघ का जन्म हुआ। वे मांग एवं पूर्ति के अभाव प्रस्ताव को सामूहिक रूप देते हैं। फ्रैंक टनबाम (Frank Tannen Baum) के मतानुसार— श्रम आन्दोलन परिणाम है और मनीनी का प्राविष्कार इसका प्रधान कारण है। मनीनी के प्राविष्कार से एक व्यक्तिगत श्रमिक की सुरक्षा का बड़ा भारी आघात पहुँचा है अतएव अपने बचाव के उद्देश्य से उसने संघ का निर्माण किया। श्रम संघ द्वारा वह मनीनी के दुष्परिणामों पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। श्रम संघों का प्रमुख उद्देश्य पूँजीवाद व्यवस्था के स्थान पर औद्योगिक जनतन्त्रवाद की स्थापना करना होता है। राबर्ट एफ० हावमी (Robert F Howe) के विचारानुसार, श्रम संघ वास्तव में भग मनोवृत्ति (Group Psychology) का उत्पाद है। 'प्रायः सभी श्रमिक-संघों का अंतिम उद्देश्य सामान्य होता है—अर्थार्थ व श्रमजीवियों की सौदा करने की शक्ति को बढ़ाते हैं, जिसमें कि वे मिलकर अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने में समर्थ हों सकें। सेलिय पलमैन (Selig Pearlman) ने एक स्थान पर लिखा है कि किसी देश के श्रम आन्दोलन

की शक्ति वहाँ के रहने वाले श्रमिकों की जागरूकता पर निर्भर करती है। कार्ल मार्क्स (Karl Marx) के शब्दों में, 'श्रमिक-सघ वास्तव में श्रमजीवियों में संगठन का केन्द्र बिन्दु है।' सघ शक्ति में श्रमिकों में परस्पर बन्धुत्व एवं सहयोग की भावना का विकास होता है। संगठन के अभाव में श्रमजीवियों में स्वयं विषम प्रतियोगिता की भावना पैदा हो सकती है, अतः पारस्परिक प्रतियोगिता की भावना का उन्मूलन करने एवं बन्धुत्व की भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य में ही अधिक सघों का जन्म हुआ।

कुछ लोग श्रमिक सघों को 'सड़ाका संगठन' (Militant Organisations) समझते हैं, जो सदैव धोखागिक युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, किन्तु यह धारणा सही नहीं है। श्रमिक सघ वास्तव में सामाजिक अशांति नहीं, बल्कि सामाजिक प्रगति के प्रतीक हैं।

श्रमिक सघ के उद्देश्य—

( १ ) श्रमिकों में परस्पर बन्धुत्व एवं सहयोग की भावनाओं का विकास करना एवं उन्हें संगठित करना।

( २ ) उनके काम एवं भुगतान के सम्बन्ध में उनकी विभिन्न प्रक्षमताओं पर सोच-विचार करना तथा उन्हें वैधानिक रूप में दूर करने का प्रयत्न करना।

( ३ ) श्रमिक एवं उनके अधिकारियों में सहयोग की भावना उत्पन्न करना।

( ४ ) अपने सदस्यों की बीमारी तथा अन्य मुसीबत के समय के लिए कोष रखना।

( ५ ) रोग बीमा, प्रोवीडेंट फंड, सहकारी साख, डाक्टरी मदद आदि लाभदायक योजनाओं की व्यवस्था करना।

( ६ ) हड़ताल घोषित करना, संगठित करना तथा उन्हें चलाना, सेवायोजकों से घात करना और भगडों को शान्ति से तय कराना।

( ७ ) आवश्यकता पड़ने पर कानूनी सहायता देना।

( ८ ) अन्य ऐसे कार्य करना जो श्रमिकों तथा उनके आश्रितों के सामाजिक, आर्थिक एवं शिक्षा सम्बन्धी दशाओं को सुधार के लिए हो।

उपरोक्त विवरण स्पष्ट है कि श्रमिक सघों का प्रारम्भिक उद्देश्य अपने सदस्यों का आर्थिक एवं सामाजिक हित साधना है। इस उद्देश्य से ही वे समस्त कार्य करते हैं।

श्रमिक सघ के कार्य—

श्रमिक सघ के कार्यों को निम्न तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है—

( १ ) श्रमिकों की काम की दशाओं से सम्बन्धित कार्य, ( २ ) काम की दशाओं से सम्बन्धित, किन्तु उनके सामान्य जीवन स्तर से सम्बन्धित कार्य, और ( ३ ) राज-नीतिक कार्य।

( १ ) काम की दशाश्रो से सम्बन्धित कार्य (Intra mural Functions)—  
 श्रमजीवियों की काम की दशाश्रो से सम्बन्धित कोई भी कार्य इस शीर्षक के अन्तर्गत आता है जैसे—पर्याप्त मजदूरी दिलाने के लिए प्रयत्न करना, कारखाने के अन्दर काम करने की दशाश्रो में सुधार करना, काम के घंटों में कमी करना, सेवायोजकों में उचित व्यवहार प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना आदि। लाभअंश भागिता एवं सह भागिता की दिशा में किए हुए प्रयत्न भी इस शीर्षक के अन्तर्गत सम्मिलित किये जा सकते हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए श्रमिक सघ सामूहिक रूप से अपने सेवायोजकों में व्यवहार करने हों और माँग की अस्वीकृति की दशा में हड़ताल तथा अनहयोग करते हैं। यही कारण है कि कभी कभी श्रमिक सघ के इन कार्यों को 'लड़ाकू कार्य' (Militant or Fighting functions) कहते हैं।

( २ सामान्य जीवन-स्तर से सम्बन्धित कार्य (Extra-mural activities — इस शीर्षक के अन्तर्गत उन कार्यों का समावेश किया जा सकता है, जिनमें कि श्रमिकों के सामान्य जीवन स्तर में वृद्धि हो, जैसे—श्रमजीवियों में परस्पर बन्धुत्व एवं सहयोग की भावना प्रोत्साहित करना, उनका शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विकास करना, बीमारी, बेकारी अथवा हड़ताल आदि की अवधि में श्रमिकों की रक्षा तथा सहायता करना, कानूनी परामर्श देना, श्रमजीवियों के लिए कल्याण कार्य की व्यवस्था करना, पुस्तकालय, वाचनालय, मनोरंजनालय आदि का प्रबंध करना, सस्ते भोजन, सस्ते अनाज एवं वृह आदि की व्यवस्था करना। इन कार्यों को 'बन्धुत्व प्रेमक कार्य' (Fraternal functions) भी कहा जा सकता है और ये सदस्यों के सहयोग तथा उनकी आर्थिक दशा पर निर्भर करते हैं। आर्थिक दृष्टि से श्रमिक सघ जितने ही बलशाली होंगे, ऐसे कार्यों की मात्रा उतनी ही अधिक होगी।

( ३ ) राजनैतिक कार्य (Political activities) — देश के शासन प्रबंध में भाग लेने के उद्देश्य के लिए निर्वाचन आदि में श्रमिक सघ के प्रतिनिधियों का लड़ा करना 'राजनैतिक कार्यों की श्रेणी में आता है।

## भारत में संघ आन्दोलन

पारस्परिक सामान्य लाभ के लिए श्रमिकों का संगठन होना भारत में अभी थोड़ा समय में ही आरम्भ हुआ है। सबसे प्रथम बार सन् १८८४ में मामूहिक प्रतिनिधित्व किया गया, जबकि फँक्टरी कमीशन को प्रस्तुत किये जाने वाले स्मरण पत्र को तैयार करने के लिये श्रमिकों का एक सम्मेलन बुलाया गया, परन्तु सफाई कार्य-सम का विचार श्रमिकों में देख में आया। सन् १८९० में श्री सोखण्डे ने श्रमिकों को संगठित किया। इस संगठन का नाम बम्बई मिल हेल्थ एसोसियेशन था, जो सरकार को कारखाना अधिनियम के सशोधन के विषय में स्मरण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए

आयोजित किया गया था परन्तु यह बड़ा ढोला ढाना समठन था । इसका न तो कोई निश्चित विधान था और न निश्चित चढ़ा दन वाले सदस्य ही । सन् १८६७ में धर्मल गेमेटड सोमायर्टी आर्क रेल्वेमन आर्क इण्डिया एण्ड आर्क वर्मा की स्थापना हुई जो अब भी वर्तमान है परन्तु इसका कय व्रम भाई चारे का कम था एवं लड़ाका अधिक ।

बोसबी गतन्नी ने प्रारम्भिक वर्षों में कुछ सघ जस—सी मन यूनियन कल कत्ता एवं पोस्टल यूनियन बम्बई स्थपित हुए । एक मुहम्मदन एसोसियेशन बंगाल में थी परन्तु उसे कठिनता से एक श्रमिक सघ कहा जा सकता है । इसी प्रकार इण्डियन लेबर यूनियन यद्यपि नाम से बड़ा उचित समठन जान पड़ता है बहुत क्रिया मक नहीं रहा । सन् १९१० में श्रमिकों के कल्याण की गढ़ि के लिए कामगार हितवद्धक सभा स्थापित हुई जो सन् १९५५ तक बनी रही परन्तु इसमें भी अधिक काम नहीं किया ।

वास्तव में श्रमिक सघ आन्दोलन भारत में सन् १९१८ से प्रारम्भ होता है जबकि घनाप मनाय कीमत बढ़ने से उ पन हुई आर्थिक कठिनाइयाँ सामान्य राजनतिक कामकाज एवं श्रमिकों की बढ़ती हुई विश्व व्यापी चेतना न श्रमिकों के दिमाग में घपन हितों के लिए संगठित होन की आवश्यकता की बात भर गी । पहली यूनियन मद्रास में स्थापित हुई । इसके बाद अन्य स्थानों में भी यूनियन स्थापित हुई । इनमें अधिकतर ता क्वल हड़ताल ममिति मात्र थी जिनका ज में समस्या को जीतन या हारन पर या उसमें पूव ही समाप्त हो जान के लिए हुआ था । वे एक दूसरे से असम्बन्धित थी परन्तु जब उनके एकीकरण का आवश्यकता अनुभव हुई क्योंकि इही दिनों विन्व श्रमिक सघ के तिन किसी केन्द्रीय एवं प्रतिनिधि सघ से प्रतिनिधि जान को थ अस्तु स्थानीय यूनियन सघ में परिवर्तित हो गई और फिर प्रांतीय सघ की स्थापना हुई । सन् १९२० में आल इण्डिया ट्रेड यूनियन काँग्रेस जो समस्त यूनियनों का राष्ट्रीय फड रेगन थी बुलाई गई । सन् १९२२ में केन्द्रीय श्रमिक समिति की स्थापना हुई और उनी वष आल इण्डिया रेल्वेमन फडरगन पोस्ट एन्ड टेलीग्राफ यूनियन स्थापित हुई । इस अवधि की विशेषता यह थी कि उपयुक्त नता श्रमिकों में ही मुलभ न थ अस्तु उह बाहरी व्यक्तियों के नष्टव पर निर्भर रहना पड़ता था ।

सेवायोजकों ने इन यूनियनों को मायता प्रगन करन में इकार कर दिया । श्रमिका को मताया जान लगा । भारतीय अपराध दण्ड सन्निधम संगोधित किया गया और श्रमिक सघों के काय अवध घोषित कर दिये गये । सन् १९२० में बकिङ्गम मिल्स क मामले में मद्रास यूनियन के विरुद्ध आदग जारी किये गये और तब श्रमिक नताओं ने दखा कि थ सच्चे श्रमिक सघ कायों व लिये भी उत्तरदायी ठहराये जा सकते हैं । श्री एम० एम० जागी ने श्रमिका क लिए सरक्षण प्राप्त करन का उद्योग किया परन्तु उनका यह परिश्रम पाँच साल बाद उस समय सफल हुआ जबकि सन् १९२६ में ध्यापार सघ अधिनियम पास किया गया । तब से सघों की संख्या में तेजा से वृद्धि हुई है ।

सन् १९२८-२९ में आन्दोलन बड़ी तेजी पर था। कम्युनिस्टों का सघो पर प्रभाव बढ़ गया। ऐसे सघों में बिरनी कामगार यूनियन ( सदस्य संख्या ५०,००० से अधिक ) प्रमुख थी। इन्होंने बम्बई में सन् १९२८ में हड़ताल संगठित की और सफलता भी प्राप्त की। परन्तु कम्युनिस्ट सदस्यों की कुछ कायवाहिया से मुनीबत पदा हो गई। शहर में दह्रा हा गया कई प्रमुख नेता पकड़ लिए गये और उन्हें सजायें दी गई। सन् १९२९ में उन्होंने फिर दूसरी हड़ताल की और वह काफी समय तक जारी रही। तब एक नया अदालत बठी। उसकी रिपोर्ट के अनुसार कामगार यूनियन ही हड़ताल के लिए पूरा रूप से उत्तरदायी थी। एक प्रमुख सघ के विरुद्ध ऐसी रिपोर्ट न आन्दोलन को अन्त में बंद दिया और उस बहुत धनका पहुँचा। आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सन् १९२९ के अधिवेशन में उसकी कार्य समिति पर कम्युनिस्टों ने अधिकार कर लिया तथा उग्र कायवाहा का और विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन में सम्बंध स्थापित करने का निश्चय किया। इस पर नम्र दलीय सघों ने श्री एम० एम० जोशी की अध्यक्षता में इस कांग्रेस से सम्बंध विच्छेद कर लिया और इण्डियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाया। रेल्वे में फेडरेशन ने भी उस कांग्रेस से सम्बंध तोड़ लिया। सन् १९३१ में तो उपदलियों ने स्वयं अपनी अलग आल इण्डिया रेट ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना ली। सन् १९३१ के विश्व श्रमिक सघ को इण्डियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन से ही प्रतिनिधि भेज गये थे। इस फूट से आन्दोलन में बड़ी कमी आई। एकता लाने के प्रयत्न एक बार फिर किये गये। सन् १९३३ में नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन बना जिसमें कम्युनिस्टों का छोड़कर और सब सघ सम्मिलित थे। सन् १९३५ में एकता का अंतिम आधार भी निश्चित हो गया और सन् १९४० में तो काम चलाऊ समझौता भी हो गया था। परन्तु प्रभावशाली उसी समय युद्ध आरम्भ हो गया। युद्ध ने सहायता दी जाये या नहीं इस प्रश्न पर फिर तीव्र मतभेद पदा हो गया। फलस्वरूप कई सघ अलग हो गये।

वर्तमान समय में इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस देश के श्रमिक सघों की सबसे अधिक प्रतिनिधित्व संस्था है। इसमें लगभग ८०० सघ सम्मिलित हैं जो लगभग १२ लाख श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है जो किसी समय श्रमिकों की प्रतिनिधि संस्था थी परन्तु कम्युनिस्टों के घुस आने पर सबसे भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक सघ कांग्रेस उसमें अलग हो गई तब से उसकी सदस्य संख्या घटती जा रही है। आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अतिरिक्त सोशलिस्ट पार्टी द्वारा आयोजित हिंद मजदूर सभा भी है तथा सन् १९४९ में यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की और स्थापना हुई। इस प्रकार भारत में आज ४ प्रमुख अखिल भारतीय भ्रम संगठन हैं जिनके सदस्यों की संख्या निम्न तालिका से जानी जा सकती है —

रजिस्टर्ड भ्रम-संघ तथा उनकी सदस्यता

विवरण	राज्यीय संघ			राज्यीय संघ	
	१९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८	१९५६-५७	१९५७-५८
१. रजिस्टर्ड में दर्ज संघों की संख्या	१७४	१७३	२२३	७६२१	८८२२
२. प्रत्याय (Returns) प्राप्त करने वाले संघों की संख्या	१०५	१०२	१२६	५२६७	५१८५
३. प्रत्याय प्राप्त करने वाले संघों की संख्या	२,१२,८५८	१,८७,६५	५,००,१६६	२०,६१,८८५	२६,७२,८८३

तालिका II\*  
अखिल भारतीय संघों की सदस्यता

संघों का नाम	सम्बन्धित संघों की			सदस्यता		
	संख्या					
	१८५६	१९५७, १९५८		१९५६	१९५७	१९५८
१. भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस	६१७	६७२	७२७	१,७१,७४०	१,३४,३८५	१,१०,२२१
२. हिन्दू मजदूर संघ	११६	१३८	१५१	२,०३,७६८	२,३३,६८०	१,६२,६४२
३. अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस	५५८	—	८०७	४,२२,८५१	—	५,३७,५६७
४. यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस	२३७	—	१८२	१,५६,१०६	—	८२,००१
योग	१५३१	—	१,८६७	१७,५७,४६८	—	१७,२२,७३१

भारत में श्रमिक संघों की सफलताएँ—

भारत में श्रमिक संघों का इतिहास नया है, इसनिये व्यवहार में उनका बरत-विषय महत्व प्राप्त। दुष्परिणामों की कठिन अवस्था है। यह तो निम्नकोच कहा जा सकता है कि उन्हें पर्याप्त सफलताएँ प्राप्त हुई हैं। उदाहरण के लिए, श्रमिकी स्थापना के प्रथम वर्ष में ही वे मजदूरी बढ़वाने और काम के घण्टे कम करवाने में सफल हुए और सन् १९२६ में उन्होंने मजदूरी में कटौती होने से रोकी। इसके प्रतिरूप वे मानिका का श्रमिकों के प्रति व्यवहार बदलने में भी सफल हुए हैं। वे अब पहले की तरह उनके प्रति उदासीन एवं विरुद्ध नहीं रहे। कमचारी संघ ने सन् १९२५ में बी० एन० आर० की हड़ताल एवं १९२७ में खडगपुर बकाया की 'तालाबन्दी' में सफलतापूर्वक हस्तक्षेप किया।



दूसरे देशों की अपेक्षा हमारे देश के श्रमिक सघों की प्रगति लगभग नगण्य है। वृद्धि-दर से ५% श्रमिक इन सघों के सदस्य होंगे। दुर्भाग्यवश हमारे अधिकतर सगठन केवल खाँवने आश्रय मात्र हैं, जिन्हें अर्थसंकट और जाली सदस्य सख्या और बाहरी लोगों के उत्साह द्वारा ही जीवित रखा जा गया है। बहुत कम श्रमिक सघों ने बेरोजगारी, बीमारी व बुढ़ापे के लाभ दिये हैं। उनमें 'गारस्पिक सहायता' की प्रवृत्ति तो लगभग अविकसित है और उन्होंने अपने को केवल लड़ाकू कार्यों तक ही सीमित रखा है। ग्रहमदायक का वस्त्र सघ अवश्य ही श्रमिकों के लिए कई कल्याण कार्यों—अस्पताल, शिक्षा, समेत भोजन, सहकारी ऋण एवं मनोरंजन की सुविधाओं के रूप में, चला रहा है। प्रति सप्ताह वह एक पत्र भी प्रकाशित करता है।

यह धारणा की जाती है कि शिक्षा के फैलने पर देश और मुश्किलें, श्रमिक अपने अधिकार एवं कल्याणों को समझेंगे, अनुशासन बढ़ेगा, सगठन के महत्त्व का उन्हें ज्ञान होगा व श्रमिक सघों के सदस्यों की सख्या भी बढ़ेगी, वे स्वयं अपने वर्गों में से ही नेता प्रकट कर सकेंगे, बाहरी लोगों की स्वायत्तता वालों से छुटकारा पावेंगे और अपना कार्य अधिक चतुरता एवं बुद्धिमत्ता से चला सकेंगे। वह दिन दूर नहीं है, जब कि भारत हम बात पर गर्व कर सकेगा कि उनके श्रमिक सघ भी अब अन्य देशों से किसी भी प्रकार पीछे नहीं हैं।

**भारतीय श्रमिक सघों के मार्ग में बाधाएँ—**

भारत में श्रमिक सघ आन्दोलन की प्रगति बहुत सी बाधाओं के कारण धीमी रही है। कुछ महत्वपूर्ण बाधाएँ ये हैं—

(१) शिक्षा व अज्ञानता—भारतीय श्रमिक प्रायः अशिक्षित हैं, अस्तु वे अनुशासन के महत्त्व को नहीं समझते और न सघ की बुद्धिमत्ता और चतुरता से चला ही सकते हैं।

(२) विचित्र समुदाय—भारतीय श्रमिक वर्ग विभिन्न प्रकार के धर्मों, विचारधाराओं, रीति रिवाजों और भाषाओं के मजदूरों का मिश्रण है, इसलिए उनके सगठन होने में देर लगती है।

(३) प्रवासी प्रवृत्ति—वे दूर दूर के गाँवों से नौकरी की खोज में आते हैं और चले जाते हैं, अतः वे अपना कार्य प्रत्येक उद्योग परिवर्तित करते रहते हैं, इस कारण वे किसी सघ में स्थायी उत्साह नहीं लेते।

(४) कम वेतन—भारत में मजदूरों का बहुत कम वेतन मिलता है, इस कारण बहुत से लोग चन्दाने नहीं दे पाते। यदि कुछ दे भी सकें तो ऐसा शुल्क इतना न्यून होगा कि उससे सघ को यथेष्ट द्रव्य प्राप्त नहीं हो सकेगा, अतः वे फिर अच्छा कार्य,

जिसकी उनसे आशा की जाती है, नहीं कर पाने । यही नहीं, भारतीय मजदूर केवल समस्यात्मक लाभ के लिए श्रुत्य देने में सकोच करता है और अपने श्रुत्य के बदले में अपनी सब आपत्तियों से अचाब अथवा थोड़ी अवधि ही में वेतन वृद्धि की आशा रखता है ।

(५) न्यून श्रुत्य—न्यूनतम श्रुत्य भी वसूल करने में कठिनाई होती है, क्योंकि उसे मिल मालिक तनख्वाह बांटते समय उगाहने नहीं देते । बाद में वह या तो सरलता से कोषाध्यक्ष तक पहुँचना नहीं और यदि पहुँचना भी है तो बीच में ही उसका कुछ भाग इधर उधर कर दिया जाता है ।

(६) कम अवकाश—मजदूरों का अवकाश इतना कम रहता है कि वे अन्य बातें, जैसे—सघ आदि के विषय में सोच ही नहीं पाते ।

(७) नियोजताओं व ठेकेदारों की विरोधी प्रवृत्ति—सेवायोजकों एवं कर्म कारियोजकों का विरोध सघ आन्दोलन की प्रगति में एक अन्य बाधा है । उन मजदूरों को जो सघ के प्रति कुछ सहानुभूति रखते हैं, तरह तरह से परेशान किया जाता है । वे मजदूर सघों को मान्यता प्रदान नहीं करते हैं और यदि करने ह तो ऐसी शर्तों के साथ कि फिर सगठन व्यर्थ रहता है । कभी-कभी सच्चे सघों के विरोध में सेवायोजकों द्वारा भूटे सघ स्थापित कर दिये जाते हैं और इनकी सहायता से उनकी कार्यवाहियों में विघ्न डालन का प्रयत्न किया जाता है । सघ के कार्यकर्त्ताओं को घूम देकर फौड़ सेना तो एक साधारण सी बात है ।

(८) विशाल क्षेत्र—हमारे देश में मजदूर एक बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं और कुछ दशाओं में तो उन तक पहुँच भी नहीं हो पाती, जैसे—आसाम के चाय बागान आदि । अस्तु इनसे सम्बन्धित सूचनायें दवाई जा सकती हैं और बाहर वालों को उनकी जानकारी नहीं हो पाती । यह दशा सघों की प्रगति में बाधक है ।

(९) नेतृत्व का अभाव—सबसे बड़ी बाधाओं में एक बाधा अच्छे नेतृत्व का अभाव होना भी है । श्रमिक अण्ड है, वे अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों में अपरिचित हैं, इसलिए उन्हें बाहरी नेतृत्व पर निर्भर रहना पड़ता है । यह उनकी बड़ी दुबलता है, क्योंकि ऐसी दशा में प्रायः अपने राजनैतिक अथवा सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वार्थी लोग नेतृत्व संभाल लेते हैं । इन्हें श्रमिकों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उन्हें कभी कारखानों में काम नहीं करना पड़ा । वे उद्योग की आवश्यकताओं से भी अपरिचित होते हैं । उन्हें श्रमिकों से सच्ची सहानुभूति भी नहीं होती । कुछ पड़े लिखे वकील आदि, जिन्हें काम नहीं मिलता, बैठे ठाले इस कार्य को संभाल लेते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के प्रयत्न में सलग्न रहते हैं । कहीं कहीं तो ऐसे लोगों ने मजदूरों के चन्दे भी हजम कर लिए । कुछ नया कई सगों का काम संभालने

रहने हे, इसलिए वे प्रत्येक सघ का पर्याप्त समय भी नहीं दे पाते। रॉयल कमीशन ने यह स्पष्ट कहा है जब तक ये सघ इस विषय में आत्म-निर्भर नहीं हो जाते, तब तक किसी विशेष प्रगति की आशा करना व्यर्थ है।

(१०) श्रमिक नेताओं के प्रति द्वेष—अधिकांश श्रमजीवियों में अपने नेताओं के प्रति सद्भावना नहीं होती। जनमानसों भी उन्हें प्रायः विघ्नप्रकारी, आग उगलने वाला कहकर बदनाम करते हैं।

(११) श्रमिकों में अनुशासनहीनता—अशिक्षा, अज्ञानता एवं रुढ़िवादिता के कारण भारतीय श्रमिक नियन्त्रण व शासन के अन्तर्गत रहने का आदी नहीं होता, अतः श्रम सघ की ओर से प्रायः लापरवाह रहना है।

(१२) नियोजताओं का अमहानुभूतिपूर्ण आचरण—मिल मालिकों का अमहानुभूतिपूर्ण आचरण भी श्रम सघ आन्दोलन की एक बड़ी कठिनाई है। भारतीय नियोजताएँ यह नहीं समझते कि स्वस्थ एवं सुदृढ़ सघवाद हड़ताल के विरुद्ध बीमा का कार्य करता है। इसके फलस्वरूप अनियमित, अनाधिकृत तथा विनसी की तरह क्षणिक हड़तालों नहीं हो पाती।

राष्ट्र निर्माण में सघों का भाग—

किसी भी देश की कल्याणकारी राज्य बनान में श्रमिक सघ बहुत लाभकारी हो सकते हैं। श्रमिक सघों को मजदूरों में यह भावना व प्रवृत्ति पैदा करनी चाहिए कि वे राष्ट्र हित की दृष्टि में उत्पादन को बहुत बढ़ावें। मिल मालिकों का भी यह कर्त्तव्य है कि वे उत्पादन बढ़ाने के उपायों को श्रमिक (अर्थात् श्रमिक सघ के प्रतिनिधियों) के सामने रखें और उनका सहयोग प्राप्त करें। श्रमिक प्रतिनिधि उन्हें राष्ट्रीय समृद्धि में जहाँ अपने सहयोग का विश्वास दिलायेंगे वहाँ अपने लिए भी मिल मालिकों से निम्न लिखित आश्वासन चाहेंगे,—

- (१) उत्पादनक्षमता में हुई वृद्धि के कारण जो लाभ होगा उसमें मजदूर भी बँटन वृद्धि और अन्य सुविधाओं के रूप में भागीदार होंगे।
- (२) नये उपायों का अर्थ मजदूर पर कार्य का अनुचित भार डालना नहीं होगा।
- (३) नये उपायों का परिणाम मजदूरों की छुट्टी और वेकरो भी नहीं होंगे चाहिए।

इनके बाद श्रमिक सघ मजदूरों को राष्ट्रीय उत्पादन में अधिकाधिक हार्दिक सहयोग देने के लिए समझावेंगे, मजदूरों को मशीना का काम अधिक कुशलता से करने की ट्रेनिंग भी देंगे और शिक्षण की व्यवस्था भी करेंगे। श्रमिकों के प्रतिनिधि मिल इंजीनियरों के साथ बैठ कर उत्पादन की नई योजनाओं पर विचार करेंगे और उप

युक्त व्यवस्था का निर्माण करने में सहयोग देंगे। इस तरह श्रमिक सघ राष्ट्रीय समृद्धि में महत्वपूर्ण भाग ले सकते हैं।

शिक्षा प्रचार देश की उन्नति के लिए अत्यन्त आवश्यक है। आज श्रमिक सघ ४५% व्यय अपने कार्यक्रमों के वेतन पर करते हैं और केवल ७% शिक्षा प्रसार पर व्यय करते हैं। यह बहुत असन्तोषजनक स्थिति है। शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

निम्नलिखित अन्य दिशाओं में काम करके भी श्रमिक सघ राष्ट्र-निर्माण में सहायक हो सकते हैं—

- ( १ ) श्रमिक सघ सहकारी समितियाँ बना कर मजदूरों के लिए घर बनवा सकते हैं।
- ( २ ) मजदूरों में बचत की भावना पैदा की जा सकती है और विभिन्न कार्यों के लिए सहकारी समितियों का संगठन किया जा सकता है।
- ( ३ ) मजदूर परिवारों में तथा बयोवृद्ध पुरुषों में ग्रामोद्योग का प्रसार करके आमदनी बढ़ाई जा सकती है।
- ( ४ ) शारीरिक ध्यायाम, खेल कूद आदि का प्रचार करके मजदूरों को स्वस्थ बनाने में श्रमिक सघ सहाय्य दे सकते हैं।

सक्षेप में, श्रमिक सघ विभिन्न क्षेत्रों में रचनात्मक कार्य करके राष्ट्र-निर्माण में सहायक हो सकते हैं। इससे मजदूरों का शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्तर भी ऊँचा उठेगा, वे अच्छे नागरिक बनेंगे और जो सामाजिक व्यवस्था वे लाना चाहते हैं उसमें भी इससे सफलता मिलेगी।

**श्रम-सघों की मान्यता के सिद्धान्त—**

भारतीय धर्म सम्मेलन सन् १९५८ ने मजदूर सघों की मान्यता प्रदान करने के लिए निम्न सिद्धान्त निर्धारित किये—

( १ ) जहाँ १ से अधिक मजदूर सघ हैं, वहाँ यदि कोई सघ मान्यता के लिए दावा करे तो वह रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम १ वर्ष तक सक्रिय होना आवश्यक है। जहाँ केवल एक ही संगठन है वहाँ यह शर्त लागू नहीं होती।

( २ ) सम्बद्ध उद्योग में इसकी सदस्य संख्या कम से कम १५ प्रतिशत आवश्यक होती चाहिए।

( ३ ) यदि किसी मजदूर सघ की समस्या की समस्या सम्बद्ध स्थानीय उद्योग के मजदूरों की समस्या का २५ प्रतिशत है, तो वह उस क्षेत्र के लिए मान्यता प्राप्त करने का दावा कर सकता है।

( ४ ) जब किसी मजदूर सघ की मान्यता मिल जाय तब इस स्थिति में दो वर्ष तक कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

( ५ ) जहाँ किसी उद्योग या सम्भान में कई मजदूर संगठन हों वहाँ जो सबसे बड़ा सघ हो उसे मान्यता प्रदान की जाय ।

( ७ ) किसी क्षेत्र के उद्योग की प्रतिनिधि मजदूर यूनियन उस क्षेत्र के उस उद्योग के सभी कामगारों का प्रतिनिधित्व करेगी, परन्तु यदि किसी विनोय उद्योग की यूनियन का सदस्य संख्या ५० प्रतिशत है, तो वह उस उद्योग की सीमा तक प्रतिनिधित्व कर सकती है ।

( ७ ) प्रतिनिधियारमकस्वरूप के निश्चय के लिए प्रक्रिया और अधिक सम्पूर्ण होनी चाहिए । जहाँ पर विभागीय तन्त्र के विनिश्चयात्मक निर्णय अन्य पक्षों को स्वीकार न हो वहाँ सभी केन्द्रीय मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाई जाय, जो मामले पर विचार करे तथा निर्णय दे । इसके लिए केन्द्रीय सरकार मजदूर संगठन, जो स्थायी तन्त्र के रूप में कार्य करेगा, स्थानीय प्राधार पर व्यक्ति और धन प्रदान करेगा ।

( ८ ) केवल उन्हीं मजदूर सघों को मान्यता दी जायगी जो अनुशासन की मजिना का पालन करेंगे ।

( ९ ) ऐसे मामलों में, जहाँ कोई मजदूर सघ केन्द्रीय सरकार के संगठनों में से किसी से भी सम्बद्ध न हो, मामले को अन्तग रूप में ही तय किया जायगा ।

अथ सघ तथा द्वितीय पंच-वर्षीय योजना—

अम सघों के दोषों को दूर करने के लिए द्वितीय योजना अवधि में निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैं —

- ( १ ) अम-सघों में बाहरी व्यक्तियों को शामिल न होने देना;
- ( २ ) आवश्यक शर्तों को पूरा करने पर उन्हें मान्यता प्रदान करना,
- ( ३ ) अम सघों के कार्यकर्ताओं की उत्पीड़न (Victimization) से रक्षा करना, और
- ( ४ ) अम सघों की व्यक्तिगत माघनों द्वारा उत्पन्न करना ।

## STANDARD QUESTIONS

- 1 Define a 'Trade Union' and briefly enumerate its aims, objects and functions.
- 2 Sketch the growth of trade unionism in India pointing out its defects and suggesting remedies.

## हमारी कुछ प्रमुख श्रम समस्याएँ ।

( Labour Problems I )

भारत में श्रम समस्याओं का उदय—

भारत में श्रम समस्याएँ अपेक्षाकृत कुछ नवीन ही हैं। प्राचीन काल में श्रमिकों की क्या स्थिति थी, उनकी काम करने की दशाएँ कैसी थी और उनका जीवन-स्तर कैसा था, इस विषय में कोई ध्येयस्थित विवरण नहीं मिलता। हाँ, ऐतिहासिक ग्रन्थों, साहित्य तथा रीति रिवाजों के आधार पर अनुमान से यह कहा जा सकता है कि प्राचीन श्रमिक असंगठित, अरक्षित किन्तु कार्य कुशल थे। पुश्तैनी कलाकारों तथा दस्तकारों द्वारा वे गाँवों व नगरों में कला व दस्तकारी के उद्योग धन्धे किये जाते थे। ये लोग गाँव के सेवक भी होते थे तथा नगरों में दस्तकारी संघों (Craft Guilds) में संगठित होते थे। प्रवीण दस्तकारी (Master-craftsmen) के यहाँ कुछ लोग (Apprentice) दस्तकारी का काम सीखते थे। काम सीखने के बाद वे स्वयं पृथक् व्यवसाय करने लगते थे। श्रमिक का जो आधुनिक अर्थ लिया जाता है, वह १९वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ही प्रारम्भ हुआ। मन् १८५७ के उपरान्त देश में नई शासन व्यवस्था स्थापित हुई और आधुनिक उद्योगों व यातायात तथा आधुनिक अव्यवस्था का विकास होना प्रारम्भ हुआ। जैसे जैसे देश में उद्योगों का विकास हुआ और नए कारखानों की स्थापना हुई, रेल, तार, डाक, चाय, खड, सूत, लूट, लोह, इत्यादि सभी प्रकार के उद्योगों का विकास होने लगा। औद्योगिक क्रांति तथा यन्त्रों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन के आधुनिक कारखाने की पद्धति ने ही श्रम की समस्याओं का जन्म दिया। २०वीं शताब्दी में इन समस्याओं का रूप उग्रतर होता गया। एक ओर तो आधुनिक उद्योगों के विकास और दूसरी ओर कुटीर उद्योगों के विनाश तथा कृषि भूमि पर जन-बहुला के उत्तरोत्तर बढ़ने वाले भार के कारण, गाँवों से झुंड वा झुंड कारीगर व किसान नगरों में जाकर श्रमिकों के रूप में आवाद होने लगे। औद्योगिक नगरों का विकास हुआ और देश में बम्बई, अहमदाबाद, कलकत्ता, कानपुर, मद्रास और टाटानगर जैसे श्रमिक प्रधान नगर विकसित हुए।

इस प्रकार जो एक नया श्रमिक वर्ग उत्पन्न हुआ उसकी कुछ अपनी विशेषतायें थी। उसके पास न धन था न भूमि और न कोई अन्य सम्पत्ति। उनके निवास की भी जटिल समस्या थी। पर्याप्त व उपयुक्त घरा के अभाव में भारतीय श्रमिक वर्ग को नगरों की तंग अंधेरी और दुर्गन्धपूर्ण गलियों में नारकीय जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य होना पड़ा। प्रारम्भ में उसकी नौकरी की सुरक्षा के लिये कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी। उसके काम करने के स्थान की दूराय बड़ी अनुपयुक्त व स्वास्थ्य के प्रतिकूल थी। उसे १२ से १५ घण्टा तक काम करना पड़ता था। उसके स्वास्थ्य व चिकित्सा तथा दुर्घटनाओं से रक्षा करने के लिये कोई प्रबंध न था। उद्योगपति श्रमिका का निन्द्यतापूर्वक गोपण करते थे और श्रमिक अपने स्वामी की दया पर निर्भर एक बेवश व असहाय शोषित प्राणी था।

किन्तु समय बदला। प्रथम विश्व युद्ध ने श्रम समस्याओं को ऊपर लाकर रख दिया। श्रम तथा पूँजी के बीच खाई वर्गीय भेद भाव तथा धन व धन की बड़ती असमानता के कारण श्रमिका और मिल मालिकों के बीच तीव्र व मनस्य तथा द्वेष की आग भड़क उठी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान में भारतीय उद्योगपतिगण ने भारी लाभ कमाये और श्रमिकों से शक्ति में भी अधिक काम लिया। इससे मजदूरों में कुछ जागृति हुई और उन्होंने अपनी दूगा सुधारन के लिए आवाज उठाई यद्यपि इस आवाज में बल न था। युद्ध तथा युद्धोत्तर तेजी में मूल्यों में असंतुलन वृद्धि के कारण जीवन यापन की लागत बढ़ गई थी और इससे श्रमजीवियों में बड़ा श्रम तोष छाया हुआ था। महंगाई भक्तों से भोजन या नाभाना और अधिक मजदूरी प्राप्त करने के लिये हड़तालों की देश में एक बाढ़ आ गई थी। श्रम सभा का संगठन हुआ श्रमिकों को अपने महत्त्व तथा अपनी शक्ति का ज्ञान हुआ। यही नहीं अंतर्राष्ट्रीय श्रम सभों व सम्मेलनों में भी भारतीय श्रम सभा के प्रतिनिधि भाग लेने लगे। संयुक्त राष्ट्र सच न भारत को विश्व का आठवाँ औद्योगिक देश घोषित किया तथा भारतवर्ष को अंतर्राष्ट्रीय श्रम नियमा को स्वीकार कर लागू करना पड़ा।

कुछ श्रम कल्याणकारी कानूनों का भी निर्माण किया गया किन्तु श्रमिकों में संगठन का अभाव होने के कारण उनके हितों की उचित रक्षा न हो सकी। सन् १९२६ में श्रम सच अधिनियम के पास होने से उनकी दूगा में सुधार की आशा बड़ी। सन् १९२६ में भारत सरकार ने रायल श्रम कमिशन की नियुक्ति की जिसने अपना प्रतिवेदन सन् १९३१ में प्रस्तुत किया। इसके आधार पर श्रमिका के निवास काय दूगाओं काय अर्वाध नौकरी की सुरक्षा तथा उनके हितकारी कार्यों के सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने अनेक अधिनियम पास किए। तत्पश्चात् सन् १९३७ में कांग्रेस मंत्रिमण्डल ने श्रम हित की एक प्रगतिशील नीति को कार्यान्वित कर न्यूनतम भृति नौकरी की सुरक्षा क्षतिपूर्ति इत्यादि की व्यवस्था की।

के लिये ही छोड़ते हैं। औद्योगिक केन्द्रों के अधिकांश श्रमिक असल में ग्रामीण ही होते हैं, जिनकी प्रारम्भिक शिक्षा गावों में ही होती है और ग्रामीण रीति रिवाजों में ही उनकी आस्था होती है। उनका अभीष्ट भाव लौटना ही होता है तथा ऐसा करने में वे प्रायः सफल ही होते हैं।

**प्रवासी प्रवृत्ति के कारण—**

श्रमिकों के गाव से शहर आने के कारणों पर दृष्टिपात करने पर हम देखेंगे कि कृषि पर पड़ने वाली विपत्ति का पहना असर भूमिहीन खतिहर मजदूरों पर ही पड़ता है अतः उन्हें गाव छोड़ कर कारखाना, नौका निर्माण स्थाना बगीचा तथा रेल निचाई आदि सरकारी निर्माण काय वाले स्थानों में अधिक वेतन के लिए काम ढूँढना पड़ता है। उन्नत आवागमन के साधन उनके इस प्रवास में सहायक होने हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश बिहार उड़ीसा आदि राज्यों तथा बम्बई के रत्नगिरि आदि कुछ जिलों में जन घनत्व तथा भूभार इतना अधिक है और अनापिन्न जोतों इतना भयानक रूप धारण कर चुकी है कि साधारण कृषक जीविकोपार्जन के हेतु शहर में जान को बाध्य हो जाते हैं। हम प्रवास काय में समुचित परिवार प्रणाली भी सहायक होती है। परिवार के कुछ सदस्य अपने घर तथा खेत से सम्बन्ध विच्छेद किए बिना ही उसे परिवार के अन्य व्यक्तियों की देख रेख में छोड़ कर गाव से चले जाते हैं। कभी कभी कृषक गाव के साहूकार से बचन या भूमि और पशु खरीदने के लिए पर्याप्त धन कमाने के उद्देश्य से शहरों में नौकरी तलाश करते हैं। फिर वहाँ अपनी जीविका और भावी जीवन को उत्तम बनाने की आशा से निम्न श्रेणी के ग्रामीण श्रमिक (जो कि दलित वर्ग में सम्बन्ध रखते हैं) शहरों और कस्बों को चले जाते हैं। तब कि उनके नगर जान का प्रधान कारण कष्ट है न कि महत्वाकांक्षा अतः हम यह कह सकते हैं कि गावों में नगरों को प्रवास करने वाले सबसे कम कुशल और अत्यंत निश्वाय ग्रामीण होते हैं। धन कमाशन के शब्दों में—

‘प्रवास की प्रत्येक शक्ति एक सिरे से आती है, अर्थात् गावों से। औद्योगिक श्रमिक नागरिक जीवन की आकर्षण से शहरों में नहीं जाता और न उसके प्रवास का कारण महत्वाकांक्षा ही होता है। शहर स्वयं उसके लिए कोई आकर्षण की वस्तु नहीं है और अपना गाव छोड़ने के समय उसके मन में जीवन की आवश्यकताओं की प्राप्ति के अतिरिक्त और कोई भावना नहीं रहती। बहुत ही कम औद्योगिक श्रमिक शहर में रहना चाहेंगे, यदि वह गाव में जीवनयापन के लिए पर्याप्त भूत और वस्त्र मिल जाय। वे नगर की ओर आकर्षित नहीं होने बरन् ढकेले जाते हैं।’

**प्रवासी प्रवृत्ति के आर्थिक एवं सामाजिक परिणाम—**

( १ ) प्रवासी प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप कारखाना में काम करने वालों के



कितन ही वग अपन का एकदम अपरिचित रीति रिवाजा और परम्पराओं के मध्य पाते हैं। यह भा भा मकना है कि वहाँ भाषा भा दूसरी है।

( २ ) पुरानी प्रथाओं और मान्यताओं के बचन धान पड़ जाते हैं, नवीन सम्प्रदाय शीघ्रता से नहीं स्थापित हो पाते। पुराने जावन अधिकाधिक वैयक्तिक हो जाता है।

( ३ ) पनवासु के अत्यधिक परिवर्तन, दासपूर्ण भाजन, स्थानाभाव के कारण अत्यधिक भाड़ भाड़, मर्यादा का अभाव तथा पारिवारिक जीवन से विच्छेद ज्ञान के बाद पुन मिलन का प्रभाव इन सबका मधुन प्रभाव धमिक के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा पड़ता है।

( ४ ) कुछ दुःखमयता के कारण धमिक के नैतिक जीवन का और भी पतन होता है। शराब और दुष्सा इन दुःखमयता के उदाहरण हैं, जिनके गाँवों में प्रचलित अज्ञान है।

( ५ ) चूँकि धमिक के मन में गाँव जीवन की उच्छा मईव बना रहती है, अतः वह अपना नागरिक वृत्ति में श्यावा रुचि उत्पन्न नहीं कर पाता। यहाँ कारण है कि वह उच्च कला के प्राविधिक कुशलता नहीं प्राप्त कर पाता।

( ६ ) उसी बार बार गाँव लौटने तथा अथ कारणों से धार्मिक और धमिक के बीच सम्पर्क का धनित्वता नष्ट हो जाता है और उनमें प्रभावपूर्ण संगठन का भी अभाव हो जाता है।

( ७ ) धमिक जब लम्बी अनुपस्थिति के बाद लौटता है तो यह निश्चित नहीं होता कि उस काम मिलता है। पुन काम मिलने का कठिनाईयें उत्पन्न माहृकार, मजदूरों के ठेकेदार शराब बचन बाल आदि की दया पर प्रतिष्ठित कर देता है।

क्या धमिकों का गाँव में सम्पर्क उचित है ?—

जैसा कि हम पहले मकत कर चुके हैं, धमिकों का अभीष्ट गाँव लौटना ही होता है। प्रचलित धमिक अपना परिवार गाँव में ही रहते हैं। शहर में अपने पति के साथ धान बीज व ना भा प्रमथ के समय प्राय गाँव ही चली जाती है। शहर में रहते हुए उनका सम्बन्ध गाँव में उसीग भी नहीं हो पाता कि वहाँ उनका अपने परिवार किंवा सम्बन्धी या अपने माहृकार का कुछ रकम भेजना ही होती है।

धर्म आयोग के मतानुसार धमिकों का गाँव में सम्पर्क लाभहीन नहीं है। शहर की अपरा गाँव के अधिक स्वास्थ्यप्रद वातावरण में स्थापित होना के कारण आभासी धमिकों का स्वास्थ्य अधिक उत्तम होता है। समय-समय पर गाँव जान से खाद हृद मानसिक और शारीरिक शक्ति फिर से जीत आता है। बायारी और वृत्ति होनेवाले के अवनर पर गाँव का घर एक शरण स्थान का काम देता है। जिस प्रकार

गावा के आर्थिक भार को नगर प्रवास हल्का कर देता है उसी प्रकार गाँव नगरो की वृत्तिहीनता के प्रति एक प्रकार की सुरक्षा प्रदान करते हैं। ग्रामीण और नागरिक जीवन का संयोग दोनों (नगरों और गावों) के लिए हितकर होता है। इससे ग्रामीण जीवन में बाहरी दुनिया का थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है तथा पुरानी जंजर प्रथाओं की शृंखला को तोड़ने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार नागरिकों को भारतीय जीवन की वास्तविकताओं का सूक्ष्म ज्ञान हा जाता है अतः हमारा मत है कि इस समय गावा से सम्बन्ध की कड़ी को बनाये रखना लाभदायक है। हा यह ध्यान रखना चाहिए कि वह सुनियमित और स्वास्थ्यप्रद हो।

### ( २ ) एकता का अभाव—

भारतीय उद्योगों में श्रमजीवी प्रायः बहुत दूर दूर से काम करने आते हैं। ऐसे विरले ही औद्योगिक नगर हैं जिन्हें निकटवर्ती क्षेत्रों में ही समस्त श्रमिक प्राप्त हो जाते हैं। परिणामस्वरूप, मजदूरों का वर्ग एक ऐसा विचित्र समुदाय बन गया है जिसमें भिन्न भिन्न धर्मों के भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले, भिन्न भिन्न रहन सहन एवं रीति रिवाज के लोग होते हैं। मजदूर वर्ग में इन अनेक भिन्नताओं के कारण संगठन नहीं है। संगठन तो दूर रहा पारस्परिक मेल जोल भी उनमें बहुत कम है।

### ( ३ ) अनियमित उपस्थिति—

जसा हम ऊपर सकल कर चुके हैं भारतीय श्रमिक कारखानों में निकटवर्ती गावा अथवा अन्य राज्या से काम करने के लिए नगरों में आते हैं, अतः अपने गावा के प्रति उनका आकर्षण बना रहता है। वे समय समय पर गाव जाते रहते हैं। कृषि क्षेत्रों से आने वाले श्रमिक कृषि मौसम में अथवा फसल पर, जब गावा में अधिक काम होता है, अपने काम छोड़ कर चल जाते हैं, इससे उनकी उपस्थिति कारखानों में अनियमित रहती है। निकटवर्ती गावों से आने वाले श्रमिक तो प्रायः प्रति मास ही अपने गाव जाया करते हैं जिससे कारखाने के काम में बड़ी बाधा पड़ती है।

### ( ४ ) अज्ञानता एवं शिक्षा का अभाव—

भारत की सम्पूर्ण जन संख्या में से केवल १७% व्यक्ति पढ़ लिख हैं। इन पढ़ लिखे व्यक्तियों में से औद्योगिक श्रमिकों का भाग तो नाममात्र को ही होगा। सामान्य शिक्षा का अभाव होने के कारण श्रमजीवी पूँछ उत्तरदायित्व के साथ अपने कर्तव्य का निष्पादन नहीं कर पाते। साथ ही, भारतीय श्रमजीवियों में जब सामान्य शिक्षा का अभाव है तो औद्योगिक शिक्षा का अभाव हो, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। यही कारण है कि हमारे श्रमजीवी लापरवाही के साथ यन्त्र औजारों का उपयोग करते हैं तथा अपने काम का महत्व नहीं समझते।

( ५ ) भारतीय श्रमिकों की प्रति उद्योगों को उनकी आवश्यकतानुसार नहीं मिलती—

भारत में श्रमिकों में कुशल श्रमिकों की अपेक्षा अकुशल श्रमिकों का संख्या अधिक है। इसका एकमात्र कारण यही है कि हमारी अधिकांश जन संख्या कृषि उद्योग में लगी हुई है। सन् १९५१ की जन संख्या के अनुसार भारत की २५ करोड़ जन संख्या कृषि पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में निर्भर है तथा शेष जन संख्या संगठित उद्योग खान उद्योग घाताघात व्यापार एवं वणिज्य पर निर्भर है।

(६) रहन सहन का निम्न स्तर —

भारतीय श्रम जावियां कर न सहन का स्तर अत्यंत गिरा हुआ है। इसका प्रधान कारण यह है कि उनका पारिवारिक बहुत कम मिलता है। कोई भी व्यक्ति जब तक उसके पास अपना समस्त धन व्ययताओं की सहायता के हेतु साधन न हो अपन रहन सहन का स्तर ऊंचा नहीं कर सकता अतः यह दोष श्रमिकों का नहीं बरन् उन परिस्थितियों एवं वातावरण का है जिनके अंतर्गत वे पड़े हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं।

(७) श्रमिकों की क्षमता—

भारतीय श्रमिकों की एक महत्वपूर्ण विपत्ति यह है कि अल्प दणों का तुलना में हमारे श्रमिकों की कार्य क्षमता बहुत कम है। श्री एक्वार्डर मकरावट के अनुसार भारतीय श्रमिकों की अपेक्षा एक अग्रज श्रमिक ४ गुना काम करता है परन्तु भारतीय श्रमिकों की क्षमता का विचार करने हुए हम में भी स्मरण रखना चाहिये कि श्रमिकों की कुशलता निम्न घाता पर निर्भर करता है—जलवायु भूमि पद्धति काम करने की परिस्थिति रहन सहन का स्तर तथा श्रम प्रबंध। इन घटकों के विवेचन से ही किसी देश के श्रमिकों की क्षमता का विषय में समुचित निष्कर्ष दिया जा सकता है। काम करने की परिस्थिति काम के घण्टा मात्र सामान्य औद्योगिक गति एवं श्रम प्रबंध आदि कुछ ऐसी बातें हैं जो श्रमिकों के ऊपर निर्भर न रहती हैं, उद्योगपतियों और निर्यातकों के ऊपर निर्भर रहती हैं तथा जावियों समुचित व्यवस्था का पूर्ण जिम्मेदारी उनका ही ऊपर होता है। इसलिए यह कहना यथार्थ है कि किसी भी देश का औद्योगिक क्षमता की जिम्मेदारी उद्योगपतियों पर निर्भर होती है। इस दृष्टि में यदि हम कम्पटी पर भारतीय श्रमिकों का तुलना अल्प दणों के श्रमिकों के साथ कार्यक्षमता में की जाय तो यह स्पष्ट है कि भारतीय श्रमिकों की कार्य करने की परिस्थिति तथा उनको दी जाने वाली सुविधाएं अल्प दणों की तुलना में नहीं करवाकर दे सके श्रमिकों की क्षमता उनका व्यक्तिगत क्षमता नहीं है बल्कि उस परिस्थिति का रूप है जिसमें भारतीय श्रमिक रहता है एवं जिस परिस्थिति में उसे काम करना पड़ता है।

## (८) भाग्यवादिता—

भारतवासी (विशेषतः यहाँ का श्रमिक वर्ग) बड़े भाग्यवादी हैं। अपने जीवन के सुख-दुख को वे भाग्य की दन समझते हैं। “हुई है सोई जा राम रवि राम्हा” में उनका इतना विश्वास है कि वे अपनी उन्नति के लिए पुण्यपात्र करने का प्रयत्नशील भी नहीं हान। भाग्य में हाथा तो मिन जायगा, ऐसा मोचकर के हाथ पर हाथ रखकर बैठ जान ह।

## भारतीय श्रमिकों की कुशलता

(Efficiency of Indian Industrial Labour)

क्या भारतीय श्रमिक वास्तव में कुशल हैं ?—

भारतीय श्रमिकों की कुशलता उनकी लोकप्रिय विशेषता है। साधारणतः यही कहा जाता है कि भारतीय श्रमिक अक्ष एवं अकुशल हैं। औद्योगिक कमीशन के सम्मुख सर अलेक्जेंडर मैक राबर्ट (Sir Alexander Mac Robert) ने अपनी माफ़ी में यह कहा कि एक अग्रज श्रमिक भारतीय श्रमिक में चौगुना कुशल होता है। सर क्लेमेंट सिम्पसन (Sir Clement Simpson) के अनुसार सड़ामायर की सूती मिल का एक श्रमिक भारतीय सूती कपड़ की मिल में काम करने वाले २६७ श्रमिकों की योग्यता के बराबर है, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय की धार से की गई जाँच इस धारणा को गलत सिद्ध कर देती है। इस जाँच में यह प्रकट है कि योरोप की तुलना में हमारे श्रमिकों की अक्षमता निर्विवाद सत्य नहीं है। कुछ उद्योगों में तो वह अन्य दशों के श्रमिकों के बराबर कुशल है। अन्य उद्योगों में भी वह पूरी तरह अक्षम नहीं कहा जा सकता। यदि योरोपीय श्रमिक भारतीय श्रमिकों की अपेक्षा अधिक उत्पादन करते हैं तो वे अधिक शिक्षा प्राप्त भी हाने हैं, उनको अधिक नृत्ति एवं अन्य सुविधायें भी मिलनी ह। दूसरे शब्दों में, भारतीय श्रमिक यदि अक्षम हैं तो अपने दोषों के कारण नहीं, अपितु उन परिस्थितियों के कारण हैं जिनमें वह रह रहा है। अक्षमता के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं :—

भारतीय श्रम की अक्षमता के कारण एवं उन्हें दूर करने के उपाय—

( १ ) प्रवासी प्रवृत्ति—इस प्रवृत्ति के कारण श्रमिक फसल के समय तथा अन्य विशेष उत्सवों पर अपने गांव आन-जान रहत हैं, जिससे भारत में अभी तक स्थायी श्रमिक वर्ग का उदय नहीं हो पाया है। इनकी इस प्रवृत्ति का यह परिणाम होता है कि वे प्रायः कारखानों में अनुपस्थित रहते हैं। इससे उत्पादन बड़ा अनिश्चित हो जाता है।

इस दोष को दूर करने एवं औद्योगिक केन्द्रों में श्रमिकों को स्थायी रूप से

रहने का प्रोत्साहन देने के लिए गहरी जीवन का सुधार कर उस अधिक आवश्यक बनाना चाहिए ।

( २ ) शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव—सामान्य ज्ञान का स्तर हमारे श्रमिकों में बहुत नीचा है । माना पिता की अधिका के कारण घर का वातावरण शिक्षाप्रद नहीं होता । इसके अनिश्चित उपलब्ध शिक्षा प्रणाली बहुत संकुचित है । अन्तःप्रारम्भिक शिक्षा भी गरीब जगह में ठीक तथा अनिवार्य नहीं हुई है । शिक्षा में मित्रों में बहुत अर्थविश्वामी भावबला और साहसहीन हो गये हैं । इन सब बाधाओं में श्रमिकों की अक्षमता बढ़ती है । सामान्य शिक्षा के अनिश्चित हमारे श्रमिकों को शिक्षा के लिए निश्चित प्रशिक्षण का मुख्यतः भी नहीं मिलता । श्रम प्रगतिशील राज्यों में उच्च श्रमिकों का पर्याप्त रूप में प्रशिक्षण दिया जाता है श्रमिक जटिल में जटिल मशीनों का प्रयोग करने में कर सकते हैं किन्तु भारत में ऐसा नहीं है । हमारे श्रमिकों को मशीनों का उपयोग जानने तथा श्रम देना में होने वाली श्रमिकों की गति विविधता का सम्मान में अधिक समय लगता है । उनकी इस अक्षमता के कारण उच्च दक्षता गिर जाती है ।

श्रम प्रगतिशील देशों की भाँति भारत में भी प्राथमिक शिक्षा का कम से कम अनिवार्य होना चाहिए । इसके अनिश्चित अधिक में अधिक शिक्षण सहायकों खोलकर गति प्रशिक्षण की सुविधाय सुगम एवं सुलभ करनी चाहिए । सामान्य शिक्षा में श्रमिकों का मानविक विकास होना और औद्योगिक शिक्षा में आवश्यकताओं को दूर होकर कार्य समता बढ़नी ।

( ३ ) निधनता और निम्न जीवन स्तर—भारतीय श्रमिकों की दरिद्रता सब विनिश्चित है । दरिद्रता के कारण उस घर पर भोजन एवं पर्याप्त वस्त्र उपलब्ध नहीं होता । ऐसा परिस्थिति में दूध फल आदि निपुणतावद्ध के वस्तुओं का वह उत्पन्न भी कर सकता है ? परिणामस्वरूप कार्य समता गिर जाती है ।

अन्तु श्रमिकों की निधनता को दूर करके उनका जीवन स्तर ऊँचा करने का उपाय सोचना चाहिए । बुटीर उद्योगों का प्रगति में यह समस्या काफ़ी सीमा तक हल की जा सकती है ।

( ४ ) अल्प वेतन—इसका भी भारतीय श्रमिकों की क्षमता पर बुरा प्रभाव हुआ है । दरिद्रता के कारण वे अपना प्रकाश पैट भी नहीं भर सकते । परिस्थिति में उनकी आय का काफ़ी भाग उन्हें चुकाने एवं नगद करने में निकल जाता है और जो पैसा रहता है वह उनकी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं होता । अपना स्वास्थ्य बनाए रखना तो दूर रहा पैट भरने की पर्याप्त रोटी भी उन्हें नहीं मिल पाता । इस प्रकार कार्य समता दिनांक कम होना जानी है ।

इस दोष को दूर करने के लिये श्रमिकों को कम से कम इतनी मजदूरी अवश्य दी जाय जिससे कि वे अपना तथा अपने परिवार का उचित भरण पोषण कर सकें।

( ५ ) शारीरिक दुबलता—निधनता एवं अल्प वेतन के कारण श्रमिकों का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य खराब रहता है। अधिक समय तक वे निरंतर कठिन परिश्रम करने के लिए अपने को अयोग्य पाते हैं। एक बार रोगी होने पर वे अच्छी तरह अपना इलाज भी नहीं करा सकते। भारत के अनेक क्षेत्रों में मलेरिया आदि रोगों से अधिकांश श्रमिक पीड़ित रहते हैं। वसस उनकी कार्यक्षमता गिरती है और उत्पादन की भी क्षति पहुँचती है। मनु १९५१ में बम्बई के एक कारखाने में हिमाव लगा कर देखा गया था कि वहाँ २५.१% श्रमिकों को जुकाम तथा फफूँड सम्बन्धी रोग २६.०% श्रमिकों को दस्त पेशिया व हैजा आदि ५.३% को गठिया या घात सम्बन्धी रोग ०.८% को मलेरिया ७.८% को चोट (काम करते समय नहीं) ०.०% को छून के तथा ३४.२% श्रमिकों को विविध प्रकार के रोग हुए। निम्नलिखित तालिका में हम कारखाने में ये प्रकार हुई समय की क्षति का अनुमान लगा सकते हैं। यही स्थिति प्रायः भारत के सभी कारखानों और उद्योगों में है\* —

रोग	प्रत्येक रोग के कारण समय के विनाश का प्रतिशत	प्रत्येक रोग के कारण अनुपातिक दिनों का क्षति
( १ ) फफूँड सम्बन्धी रोग	४०.१	६.२
( २ ) पाचन सम्बन्धी रोग	२६.६	६.०
( ३ ) मलेरिया	५.४	७.८
( ४ ) मूत्र सम्बन्धी रोग	०.२	६.०
( ५ ) छून के रोग	१.१	११.७
( ६ ) चोट ( काम पर नहीं )	२.७	६.४
( ७ ) विविध	२०.४	७.४

इसके अतिरिक्त गाँव के स्वतंत्र और स्वच्छ वातावरण से आकर नगरों की गंदी व सकोण गलियाँ में रहने नगरों की विचित्र परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की नतिक बुराईयाँ का साख्त हान मंदिरा जुआ और भ्रष्टाचार में फँस जान तथा घायल सम्बन्धी विपमताओं के परिणामस्वरूप श्रमिकों की क्रियात्मक शक्तियाँ का पतन हो जाता है। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के इस प्रकार नष्ट हो जाने से उनकी कार्यक्षमता पर बड़ा घातक प्रभाव पड़ता है।

\* देखिये इण्डियन लेबर ईयर बुक (१९५१-५२) पृष्ठ २५४।

इस दोष को दूर करने के लिए थमिक के लिए चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं का प्रबंध करना चाहिए और मनोरंजन के स्वस्थ माधन उपलब्ध कर उनका मद्य-पान एवं जुए का व्यसन छुड़ाना चाहिये ।

( ६ ) जलवायु—इसका भी कार्यक्षमता पर निगुणान्तरक प्रभाव पड़ता है । परिश्रम के क य क लिए शानोष्ण जलवायु उपयुक्त होती है, न किन हमारे देश की जलवायु गर्म प्रदेश की है । गर्मी के मौसम में तिनमिलानी धूप में देर तक बड़ा परिश्रम करना सम्भव नहीं होता । बहाना तथा तराई प्रदेशों की जलवायु तो बड़ी खराब है ।

बिजली के पड़ो एवं नमीकरण यन्त्रों (Humidifiers) आदि दुर्घिम साधनों की सहायता से यह कठिनाई भी कुछ सीमा तक दूर की जा सकती है ।

( ७ ) स्वतन्त्रता और भाषा का अभाव—इसका भी थमिकों की कार्यक्षमता पर विशेष प्रभाव पड़ता है । बड़े निरीक्षण और भाषा के अभाव में थमिक की कार्यक्षमता में कमी होना स्वाभाविक है ।

इस दोष के निवारण के लिये प्रेरणात्मक भूति पद्धति (Progressive Wage System) का अनुकरण करना चाहिये ।

( ८ ) ऋणग्रस्तता—अर्थ-शास्त्री डॉनिंग के अनुसार भारतीय थमिक ऋण में ही जन्मता है, ऋण में ही उगवा पालन पोषण होता है और ऋण में ही उनकी मृत्यु हो जाती है । ऋण प्रगति में बाधक होने है ।

अस्तु, थमिकों को दीर्घ से शीघ्र ऋण मुक्त किया जाय और सहकारी आ दा लन द्वारा उन्हें मितव्ययता का पाठ पढ़ाया जाय ।

( ९ ) काम के दीर्घ घंटे—यद्यपि कारखाना अधिनियम द्वारा काम के घण्टों का अधिकतम निश्चय कर दिया गया है, किन्तु भारत की गर्म जलवायु को देखते हुए वे घण्टे भी अधिक हैं । वर्तमान समय में सदा अत्यन्त गर्म कारखानों में ४८ घण्टों का सप्ताह और मौसमी कारखानों में ५४ घण्टों का एक सप्ताह होता है, लेकिन यह अधिनियम अनेक छोटे कारखानों में लागू नहीं होता । अमण्डित उद्योगों, कुटीर उद्योगों तथा कृषि में थमिकों के काम करने के घंटे दीर्घ, अनियमित तथा मालिक की इच्छा पर निर्भर करते हैं । ऐसी परिस्थिति में भारतीय थमिकों की कार्यक्षमता कम होना स्वाभाविक है ।

अतः उचित सत्रिमय द्वारा इस दोष का निवारण किया जाय ।

( १० ) काम करने की दशाएँ—भारतीय कारखाना की दशाएँ, जहाँ हमारे थमजीवी कार्य करते हैं, सन्तोषजनक नहीं हैं ।

काय कुशलता को स्थिर रखने के लिये स्वच्छ जल, वायु, विश्राम आदि की पूर्ण व्यवस्था होना आवश्यक है ।

(११) भरती की दोषपूर्ण पद्धति—इसके कारण भी श्रमिकों की कार्यक्षमता गिरी हुई है। श्रमिकों की भरती जाबर करते हैं जो प्रत्येक भरती होने वाले से दस्तूरी लते हैं। श्रमिकों की नियुक्ति, उन्नति एवं एक विभाग से दूसरे विभाग को स्थानांतर सब कुछ इस जाबर पर ही निर्भर है अतः श्रमजीवियों को नाना प्रकार से उनकी सेवा शुश्रूषा करते रहना पड़ता है। जाबरा की आय नई नियुक्तियों पर ही निर्भर होती है अतः वे तरह-तरह के धमकाने बना कर पुराना को निकालते और नये को भरती करते रहते हैं। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि श्रमिकों की कार्यक्षमता कम हो जाती है और उद्योग का उत्पादन व्यर्थ बढ़ जाता है।

इस दोष का दूर करने के लिए जाबर पद्धति का अन्त करके श्रमिकों की भर्ती वैज्ञानिक आधार पर करनी चाहिये।

(१२) दोषपूर्ण प्रबंध—बहुत सीमा तक यह भी श्रमिकों की क्षमता के लिये उत्तरदायी है। प्रबंधकों का दुर्व्यवहार काम का दोषपूर्ण विभाजन घिसी हुई मात्र सामग्री आदि ऐसे दोष हैं जिनसे कार्य में जा नहीं सकता।

अस्तु भारतीय श्रमिका का कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए उत्तम मशीनों और कच्चे माल का प्रयोग आवश्यक है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि कुशल प्रबंध के निरीक्षण में उनसे कार्य लिया जाय।

## भारतीय औद्योगिक श्रमिकों की गृह-समस्या

भोजन और वस्त्र के उपरांत मकान अनुप्य की तृतीय प्रमुख आवश्यकता है। या तो हमारी ये तीनों ही समस्याएँ गम्भीर हैं किन्तु मकानों की समस्या मुख्यतः औद्योगिक नगरों में बड़ा विकराल रूप धारण करती जा रही है। नगरों की बढ़ती हुई जनसंख्या तथा गृह निर्माण की मंद गति इसके लिए विरोध रूप से उत्तरदायी है। प्रत्येक बड़ा औद्योगिक नगर में एक इंच भी भूमि कही खाली नहीं और आबादी बहुत घनी है। नगर निवासियों में कारखानों में काम करने वाला श्रमिक वर्ग सबसे बुरे मकानों में रहता है। अनेक नगरों में तो उनके निवास स्थानों को मकानों की संज्ञा देना ही सज्जा की बात है। उन्हें मानव के योग्य नहीं कहा जा सकता। कानपुर में भारत के प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने २ अक्टूबर सन् १९५२ को श्रमिकों के निवास स्थान का निरीक्षण करते हुए उन्हें नरक कुंड कहा था। पंडित नेहरू ने कहा कि भारतीय श्रमिका की निवास समस्या बहुत ही जटिल है और उनके रहने का स्थान मन्त्री कुर्सी गनी (Stumps) से अच्छे नहीं कहे जा सकते। ग्रामीण औद्योगिक केंद्रों में भी उनका भेदी बस्तियाँ होता हैं जहाँ सफाई का नाम नहीं बोटरी में मूय का प्रकाश नहीं पहुँचता, फल में नहीं रहती है रोगनिदान का पता नहीं तथा स्वच्छ



वायु आ ही नहा सकती। अधिकांश श्रमिक ऐसे गन्दे वातावरण में जीवन व्यतीत करत है। एम मकाना में रहने वाले श्रमिका में कायगमता की कंटे आशा की जा सकती है ? एम म्याना को बम्बई में (Chawl), मदास में चरा (Cherry), बन वत्ता में बस्ता (Basta) तथा कानपुर में अहाता (Ahatas) कहते हैं। अब हम श्रम जाच समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारत के प्रमुख औद्योगिक नगरों की औद्योगिक वस्तियों का संक्षिप्त परिचय दगे।

बम्बई में श्रमिका की चाली (Chawls) अत्यन्त ही अस्वास्थ्यकर हैं, जहाँ एक ही कमरे में ६७ श्रमजीवी रहते हैं। उन्हें न तो कौटुम्बिक वातावरण ही मिलता है और न स्वच्छ वायु तथा प्रकाश ही। श्री हर्स्ट (Hurst) ने इस प्रकार मजदूरों के वस्त्रों की गंदगी में आम भरण के समान बताया है। बम्बई में ७०% में अधिक श्रमिक एक कमरे वाले मकान में रहते हैं, जबकि लंदन के क्वेन ६% श्रमिक १ कमरे वाले मकान में निवास करते हैं। बम्बई के श्रमिका में मकानों को पुनः किराये पर देने की प्रथा है, जिससे घनी आबादी की समस्या और भी बढ़ जाती है। किराये में वृद्धि करने के विचार से ४ या ६ श्रमिक एक काठरा किराये पर ले लेते हैं। उन्हीं के अन्दर चारों कोनों में छाना पड़ा जाता है। श्री शिवाराव ने लिखा है कि जब बम्बई में मजदूरों की बस्ती में एक लड़ा डाक्टर मराज दखन गईं तो उसने देखा कि एक कमरे में ४ गृहस्थियाँ रहती थीं जिनके सदस्यों की संख्या २४ थी। चारों कोनों में चूल्हे बने हुए थे मारा कमरा घुंघुं में काटा हुआ रहा था। बम्बई के औद्योगिक श्रम जीवियों के रहने की दशा के सम्बन्ध में श्रीयुन हर्स्ट का निम्न वर्णन बड़ा हृदय स्पर्शी है—“रहने की दशायें यहाँ सबसे खराब हैं। एक सक्की गली में, जिनमें कि दो व्यक्ति एक साथ नहा जा सकते, (तबक के) घुमने के पदचान् इतना अंधेरा था कि हाथ में टटोलने पर कमरे का दरवाजा मिला। उस कमरे में श्रम का लेशमात्र भी प्रकाश न था। ऐसी दशा दिन के १२ बजे थी। एक दियामलाई तेलान के पदचान् ज्ञान हुआ कि एम कमरे में भी अनेक श्रमिक रहते हैं। श्रम के आदमी कथोचन न तो बम्बई की चाली के सम्बन्ध में यहाँ तक लिखा है कि उनका पूर्णतया तोड़ने के अतिरिक्त इनमें सुधार के लिए लेशमात्र भी गुंजायग नहीं है।

अहमदाबाद के श्रम निवास स्थानों में अधिक संतोषजनक नहीं कहे जा सकते। यहाँ की नगरपालिका ने हरिजन तथा अन्य श्रमिका के लिए कुछ मकानों का निर्माण किया है। इससे अतिरिक्त अहमदाबाद में ही हाउसिंग कम्पनी एवं सूनी बन्द मिल श्रम-मण्डल का द्वार से भी अच्छा व्यवस्था की गई है। श्रम सच द्वारा निर्मित कालोनी में रहने वाले श्रमजीवियों में १०) मासिक किराया लिया जाता है और २०) वर्ष के उपरान्त निम मकान में वे रहने ह वह उनका हा जाता है। प्रत्येक मकान में दो कमरे,

एक रसाईघर तथा एक बरामदा है। अहमदाबाद में श्रमिका की गृहनिर्माण सहकारी समितियाँ भी हैं।

कलकत्ता की दशा भी बम्बई से अच्छी नहीं है। यहाँ बम्बई की अपक्षा कम दाम पर भूमि मिल जाती है। यहाँ मजदूरों के घर झोपड़ियों की कतारें हैं, जिन्हें 'बस्ती' कहा जाता है। ये झोपड़े मिल मालिकों द्वारा नहीं बनाए गए हैं वरन् सरदार (Sirdar) एवं कुछ मकान मालिकों ने बनवाए हैं। कलकत्ता नगर निगम की रिपोर्ट में यह स्पष्ट है कि इन झोपड़ियों का निर्माण बिना किसी योजना के हुआ है। प्रायः सभी निवास स्थान कच्चे हैं और श्री केस (Casey) के शब्दा में "काई भी मानव वहाँ रहना पसन्द न करेगा।" चारा और गन्दगी का साम्राज्य है। मलारवा और तृपदिक का काफ़ा जार रहता है। धरो म न नल ह न सप्टायम्। पूरे मुहल्ले के लिए एक या दो नल तथा एक सप्तास हागा, जिस पर बिचाये श्रमजीवी लाइन लगाकर खड़े रहन हैं। छोटी छोटी बाता पर जैस—पानी के लिए, नित्य झगड़ फसाद होते रहत हैं। मङ्गें और गलिया खराब, गन्दी, पतली तथा प्रकाशहीन हैं, जिन पर रात्रि में बनना खतरनाक है। गन कुछ वर्षों में मजदूरी झिझला जी के सद्प्रयत्ना के परिणामस्वरूप कुछ मिल कम चारिया के लिये अच्छे घरों की व्यवस्था की गई है, जिनमें लगभग ५०% छूट मिल श्रमिक रहते हैं किन्तु दोष वस्तियों में ही निवास करत हैं, जिनकी दशा अत्यन्त दयनीय है।

कानपुर उत्तरी भारत का 'मैनचेस्टर' कहलाता है अतएव यहाँ श्रमिकों के निवास के लिए समुचित व्यवस्था होना नितांत आवश्यक है। यद्यपि कानपुर में नगर पालिका, इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट एवं कुछ सेवायोजकों ने श्रमिकों के निवास के लिए आदश व्यवस्था की है, किन्तु फिर भी आज यहाँ 'ग्रहाते' तथा 'बस्तिया' दृष्टिगोचर होनी हैं, जिनकी दशा अत्यन्त शोचनीय है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रत्यक्ष रूप में गृह समस्या के निवारणार्थ यहाँ कुछ भी नहीं किया है। हा, सन् १९४३-४४ में राज्य सरकार ने २,४०० परिवारों के लिए क्वाटर बनवाने के लिये इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को ३०३ लाख रुपये का ऋण दिया। तब से प्रति वर्ष यह संस्था कुछ न कुछ मकान बनावती रही है, जिनका किराया ४) प्रति माह है। सन् १९३८ की कानपुर श्रम जाच समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि यहाँ सेवायोजकों की ओर से कबल ३,००० मकान बनाए गए, जिनमें १०,००० श्रमिक रहत हैं। सन् १९३८ से सन् १९४३ तक स्थिति में काई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। सन् १९४३ में यहाँ श्रमिकों की संख्या १,०३,००० थी। इसमें से केवल १०% श्रमजीवियों के रहने लिये के सेवायोजकों ने व्यवस्था की। यहाँ के सेवायोजकों में ब्रिटिश इण्डिया कॉरपोरेशन का नाम विशेष उल्लेखनीय है जिसने मैक राइटगन्ज तथा अनेकगन्ज में १,६६० श्रम क्वाटर बनवाए। इन क्वाटरों में जन, प्रकाश, स्वच्छ वायु आदि की तो सुव्यवस्था है हा, इनके अतिरिक्त प्रत्येक

कॉलोनी के लिये एक विशाल सस्था एव डिस्पेंसरी भी है। सर्वे श्री बंग मूदरलण्ड एण्ड कम्पनी लि० के प्रबन्ध के अन्तर्गत एलगिन मिन्स ने भी अपने श्रमजीवियों के लिये सुन्दर मकानों का निर्माण करवाया है। एलगिन मिन्स के बग़ारों में अन्य सुविधाओं के साथ साथ बिजली की रोज़नी का भी प्रबन्ध है। इसी प्रकार सर्वेधी जुगोमल-कमलापति की ओर से भी उनके श्रमियों के निवास के लिए एक पृथक कॉलोनी का निर्माण किया गया है, जिसमें प्रायः सभी सुविधायें उपलब्ध हैं। कानपुर की नगर पालिका ने भी निम्न कोटि के श्रमिकों के लिये (जैसे भगी एव पाक तथा सावजनिक उद्यानों में काम करने वाले कर्मचारी) निवास की अच्छी व्यवस्था की है।

इतना होते हुए भी कानपुर की श्रम बस्तियों एवं महातों में सहस्रो श्रमिक रहते हैं। श्रम के शाही कमीशन ने महातों का वर्णन इस प्रकार किया है—'प्रायः प्रत्येक मकान एक एक कमरे का है, जिनकी लम्बाई-चौड़ाई ८ फीट × १० फीट है। किसी भी कमरे के आगे बरामदा नहीं है और प्रत्येक कमरे में ३-४ परिवार रहते हैं। फर्श कच्चा है तथा नमी रहती है। कहीं भी स्वच्छ वायु, प्रकाश आदि का प्रबन्ध नहीं है।' पण्डित नेहरू ने तो इन महातों को 'नरक कुण्ड' की संज्ञा दी है।

टाटानगर यहाँ मध्यी टाटा की ओर से लोहे एवं स्पात उद्योगों में काम करने वाले श्रम जीवियों के लिये लगभग ८,५०० मकान बनवाये गये हैं। प्रत्येक मकान में दो कमरे, एक रमोईघर तथा एक बरामदा है। इसके अतिरिक्त स्नानागार एवं फलम-सन्डास भी हैं। सभी मकान पक्के हैं तथा कुछ में बिजली के पखे भी हैं। यह सब व्यवस्था दक्ष कारीगरों के लिये है, अनुकूल श्रमजीवियों के निवास स्थान बड़े गन्दे एवं असन्तोषजनक हैं।

मद्रास में भी श्रमिकों के निवास स्थान बड़े असन्तोषजनक हैं। कुछ मिल मालिकों ने श्रमिकों के लिये बग़ारें बनवाये हैं, परन्तु उनमें अनेक श्रमिक रहना पसन्द नहीं करते, क्योंकि उनके विरुद्ध खुफिया जाँच होती रहती है और यदि वे अभी हड़ताल में भाग लेंगे तो वे बग़ार में निकाल दिये जायेंगे। ऐसे वातावरण में वे रहना पसन्द नहीं करते।

शोलापुर में श्रमिकों की गृह व्यवस्था सन्तोषजनक है। इसी प्रकार मदुरा में भी श्रमिकों के लिये सुन्दर मकान बने हैं, जिनमें प्रायः सभी वर्तमान सुविधायें उपलब्ध हैं। नागपुर की एम्प्रेस मिल तथा बगनौर की सूती, ऊनी तथा रेशमी वस्त्र मिल के श्रमजीवियों के लिए बड़ी सुन्दर गृह व्यवस्था है। रानीगंज तथा भरिया की कोयले की खानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए जो मकान बनवाये गये हैं वे Mines Board of Health के आदेशानुसार बनवाये गये हैं, अतः सन्तोषजनक बड़े जा सकते हैं। आसम में चाय के बगीचों में काम करने वाले श्रमिकों की गृह दशा असन्तोषजनक है। वहाँ कहीं भी स्वच्छता नहीं तथा मलेरिया का ख़तरा बोलबाला है।

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि किंचित क्षेत्रों को छोड़कर देश सभी नगरों में औद्योगिक श्रमिकों की गृह समस्या अत्यन्त जटिल है। श्रमिकों के निवास स्थानों को देखकर कभी कभी मसानी (Masani) के शब्द स्मरण हो आते हैं—“विश्व की रचना ईश्वर ने की है, नगरों की मानव ने और श्रम वस्तुओं की शैतान ने।”

**बुरी गृह व्यवस्था के दुष्परिणाम—**

अच्छे घरों का अर्थ है शूद्र जीवन की सम्भावना, सुख और स्वास्थ्य तथा बुरे घरों का अर्थ है, गन्दगी, शराबखोरी, बीमारियाँ, आचारहीनता, ध्वनिचार और अपराध। इनके लिए अस्पताल, जेल और पागलखानों की आवश्यकता होती है, जहाँ समाज के भ्रष्ट एवं पतित लोगों का छिपाया जाता है, जो स्वयं समाज की लापरवाही के ही परिणाम हैं। अनुपयुक्त एवं सुविधाहीन घरों के कारण श्रमिकों का घरेंलू जीवन नीरस एवं आनन्दरहित हो जाता है। गन्दगी के कारण मलेरिया और तपेदिक जैसी भयानक बीमारियों का जोर रहता है, श्रमिकों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, उनके मस्तिष्क संकुचित हो जाते हैं तथा मानसिक विकास का कोई अवसर नहीं रहता। अपूर्ण और गन्द मकान औद्योगिक अभ्यान्ति के भी कारण हैं। एक सबसे बड़ी बुराई अधिक मकानों में शिशु मृत्यु है, जो बम्बई की गन्दी वस्तियों में पाई जाती है। मृत्यु सख्या निवास के कमरों के विपरीत अनुपात में है। उदाहरण के लिए सन् १९३६ में एक कमरे वाले निवास-स्थानों में मृत्यु सख्या ७८-३०% थी। सबसे गन्द स्थानों में मृत्यु दर २६८ प्रति हजार थी, जबकि साधारण दर २०० से २५० प्रति हजार ही थी। अन्त में बॉन के जीवन की भयङ्कर दशाएँ तथा गायनीयता के अभाव के कारण लोग अपने कुटुम्ब को नहीं ला पाते, जिससे श्रम की स्थिरता तथा कार्यक्षमता पर कुप्रभाव पड़ता है। एकान्ती जीवन व्यतीत होने के कारण उनमें वैश्यामयन जैसी बुरी आदतें पैदा हो जाती हैं। जो श्रमिक परिवार सहित रहते हैं वे भी एक कमरे हॉ के कारण गायनीयता नहीं रख सकते। एक ही कमरे में पुरुष-स्त्री के साथ रहने के कारण समय से जीवन व्यतीत नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थितियों में महिला श्रमिकों के नैतिक पतन की बड़ी आशंका रहती है। डा० राधाकमल मुक्ती के शब्दों में, “भारतीय औद्योगिक केन्द्रों की श्रम वस्तियों की दशा इतनी भयङ्कर है कि वहाँ मानवता का विध्वंस होता है, महिलाओं के सतीत्व का नाश होता है एवं देश के भावी आधार-स्तम्भ—शिशुओं का गला घुट जाता है।” अतः श्रम जांच समिति ने सिफारिश की है कि शिक्षा और औपधि सम्बन्धी सहायता की भाँति सरकार को औद्योगिक आवागमन का भी उत्तरदायित्व सम्भालना चाहिये।

**गृह समस्या को हल करने के लिए किए गए प्रयत्न—**

यद्यपि भारत में ‘घर’ सम्बन्धी सुविधायें न्यून हैं और इस सम्बन्ध में दशा बड़ी शोचनीय है, किन्तु ऐसी भी सस्याएँ तथा सेवायोजक हैं, जिन्होंने बड़ी सुन्दर व्य-

वस्थाय का है। बम्बई में गृह समस्या के निवारणार्थ सुधार प्रयास (Improvement Trust) की स्थापना हुई। इसका काम नई गलियों का निर्माण घन क्षेत्रों का विस्तार समुद्र में भूमि को निकालना जिससे प्रसार कायम सुविधा हो तथा गरीबों के लिये स्वच्छ मकानों का निर्माण करना था किन्तु ट्रस्ट की सीमित शक्ति नगर निगम से सम्पर्क में कभी तथा भूमिपतियों के विरोध के कारण इस कुछ विषय सफलता नहीं मिली। फिर में ट्रस्ट ने कुछ सीमा तक प्रशंसनीय कार्य किया। सन् १९२० तक नगरपालिका ने भाषपन कमचारियों के लिए ५२०० मकान बनवाये तथा २००० के लिए श्रद्धांश दी। पोर्ट ट्रस्ट ने ५००० व्यक्तियों के लिए मकान बनवाये। नगर नगर का जन मख्या बढ़ाती है वहाँ रहती थी किन्तु सहायता न अपन श्रमजातियों के रहने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। सन् १९१४-१८ के युद्ध के उपरान्त बम्बई सरकार द्वारा इस समस्या को मुनिसिपल के लिए सुविस्तृत योजना तयार की गई। इसके लिए ६ करोड़ रुपये के विकास ऋण तथा बम्बई घात वाला सभी कपास पर १ प्रतिशत की दर से नगर कर लगाकर आवश्यक धन एकत्रित किया गया किन्तु इस प्रकार निर्मित चान (मुख्यतः खोरला की चान) दम दप तक खाली पड़ा रहा। इनमें रहने के लिये श्रमिका के आकर्षित न होने के निम्न कारण थे—बड़ा तक पहुँचने की कठिनाई बाजार मन्त्रणा सुविधाओं का अभाव उनका सीमांत में बसा जाना—नितक कारणों के समीप अधिक गम तथा जाड़ में अत्यन्त गर्म रहता है किराये का ऊँचा दर तथा प्रकाश सम्बन्धी व्यवस्था और पूर्ण सुरक्षा का अभाव। इन दोषों को दूर करने के लिए कुछ प्रयास किये गये हैं। नगर निगम तथा पोर्ट ट्रस्ट भाषपनी विकास योजनाएँ कार्यान्वित करने में प्रयत्नशील हैं। मई सन् १९४७ में बम्बई सरकार ने बारला पर भवन निर्माण योजना प्रारम्भ की जिसमें काम करने वाले एक व्यक्ति तथा परिवार दोनों को रहने के लिए मकान बनवाये गये हैं। अब बम्बई में एक कमरे वाले मकान न रहेंगे।

जहाँ तक मिल मालिकों का प्रश्न है, कुछ मित्रों ने जवाब दिया—जब नामन मिल ने अपना श्रमजातियों के लिये मकान देने की व्यवस्था की है। उचित दर पर कारखाना के समीप स्थान मिलने की कठिनाई इस बात की सुरक्षा का अभाव कि मकान मिलन पर श्रमिक मकान देने वाली मिल में ही काम करेंगे तथा स्वयं कमचारियों का उन मकानों में रहने की अनिच्छा—इन सब कारणों से काम के प्रसार में बाकी गिधि लता आ गई है। कमचारा डरते हैं कि उनकी स्वतंत्रता में बाधा पड़ेगी तथा हस्तान्त के समय वे निकाल लिये जायेंगे। वे स्वच्छता और अनुगमन के नियमों को भी पसन्द नहीं करने क्योंकि वे उनका महत्त्व ही नहीं समझते। वानपुर नागपुर आदिपर अहमदाबाद मद्रास आदि नगरों में श्रमजातियों के अस्तित्व पर अधिक ध्यान दिया है। इस सम्बन्ध में एम्प्रेस मिल्स नागपुर जावाजाराव काप्ले मिल्स

१,०३ ६६० मकानों के लिए स्वीकृति दी गई। अगस्त सन् १९५८ के अंत तक लगभग ७७,००० मकान बनाए जा चुके थे।

सन् १९५४ में कम आय वालों के लिए सरकारी आर्थिक व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था के अन्तर्गत लोगों को एक लम्बी अवधि के लिए बहुत कम व्याज पर ऋण देन का प्रबंध किया गया। प्रथम योजनावधि में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में गृह निर्माण की दिशा में जो प्रगति हुई, उसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

विवरण	मकानों की संख्या
(I) सार्वजनिक क्षेत्र में	
(i) औद्योगिक भावास .....	७७,०००
(ii) कम आय वालों के लिए भावास	४०,०००
(iii) पुनर्वास भावास***	३,२३,०००
(iv) केन्द्रीय व राज्य सरकारों द्वारा भावास	३,००,०००
(II) निजी क्षेत्र में***	७,४०,०००
	७,५०,०००
कुल योग	१४,६०,०००

श्रमिकों के हेतु निर्मित प्रत्येक मकान में १२' X १०' का एक रहने का कमरा एक बरामदा, ७२ वर्ग फीट का एक रसोईघर, १६ वर्ग फीट का एक स्नानगृह तथा १२ वर्ग फीट का एक पलत चौचालय है। गृहस्थों का सामान रखने के लिए अलमारियों व टाँबों की भी अच्छी व्यवस्था है। दो कमरे वाले मकानों में पहला कमरा १२० वर्ग फीट का, दूसरा कमरा ६६ वर्ग फीट का, रसोईघर तथा बरामदा १०० वर्ग फीट का, स्नानगृह १६ वर्ग फीट का, चौचालय १२ वर्ग फीट का तथा १० वर्ग फीट का एक भण्डारगृह है।

द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में गृह समस्या का एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है और उसमें १२० करोड़ रुपये की स्थाई व्यवस्था की गई है। ऐसा अनुमान है कि सन् १९६१ तक नागरिक क्षेत्रों में लगभग ५३ लाख मकानों की कमी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग ५४० लाख मकानों की मरम्मत व पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। दूसरी योजना में १२ लाख मकान सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा और १० लाख मकान प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा बनाये जाने की आशा है। इसके अतिरिक्त कम आय वाले और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए आवास, बागान और छानो तथा दरिद्र बस्तियों

को हटान और भागियों के नये आवास पर भी विचार करके निश्चित कार्यक्रम बनाये गये हैं।

**वागान मजदूर आवास योजना**—सन् १९५१ के वागान मजदूर अधिनियम के अनुसार प्रत्येक वागान मालिक के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वह अपने सभी मजदूरों के नये आवास की व्यवस्था करे। द्वितीय योजना में ११ ००० मकानों के निर्माण के लिये २ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। सन् १९५६ ५७ में वागान मालिकों को देन के लिये केरल सरकार ने १ ५० लाख रुपये लिये और इसी कार्य के लिये मद्रास सरकार भी ८३ ५०० रुपये ले चुकी है।

**श्रम बस्तियों में मकानों के निर्माण की योजना** टोसी सन् १९५८ के मुद्दा—

गद्दा बस्तियों में सुधार कर मकान बनाने के लिये म राष्ट्रीय विकास परिषद की योजना समिति ने जो योजना ताली बनाई थी उसके मुद्दा निम्न है—

(१) गद्दी बस्तियों की सफाई के लिये सबसे अच्छा तरीका यही है कि इस काम के लिए कानून द्वारा निगम पटल बनाये जाय जो स्वायत्त हो और जिनके ऊपर कार्यक्रमों को चलाने का उत्तरदायित्व हो। वे अपने क्षेत्रों में योजनाओं के लिए नीति निर्धारित करें।

(२) आयोजन में मकान बनाने के लिये जो राशि रखी गई है वह केन्द्रीय मकान निगम का दे दी जाय जिससे वह उस राज्या के मकान निगमों को बांट सकें। केन्द्रीय निगम, राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन और केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान माला के साथ भी निकट सम्पर्क रखें।

(३) गद्दी बस्तियों की बाढ़ का रोकने के लिये गांव से नगरों की ओर जान की प्रवृत्ति को रोका जाय तथा केन्द्रीय सरकार नगर में नये उद्योग खोलन या किसी उद्योग को बढाने की अनुमति तभी दे जब स्थानीय संस्थानों भी इसे स्वीकार कर लें।

(४) जहाँ आबादी बहुत घनी है वहाँ अधिक रोजगार न दिये जाय। प्रत्येक नगर में गद्दी बस्तियों की सफाई के लिए बृहत योजना बनाई जाय।

(५) मकानों के लिए न्यूनतम स्तर स्थापित किया जाय और गद्दी बस्तियों में सभी मकानों की जांच की जाय।

(६) मकानों के निर्माण का व्यय कम होना चाहिए।

यद्यपि गृह समस्या पर अब उचित ध्यान दिया जा रहा है तथापि जो कुछ हो रहा है उससे समस्या कम भले हो जाय कि नु पूर्णतः नहीं सुलभ सकता। ग्रामीण आवास और मध्यम आय वाले लोगों के लिए आवास के हेतु बहुत कम अर्थ व्यवस्था की गई है। औद्योगिक गृहों के किराये भी इनमें अधिक हैं कि साधारण श्रमिक उनको वहन नहीं कर सकता अतः कार्यक्रम में उपयुक्त सुधार करने आवश्यक है।

**STANDARD QUESTIONS**

1. Briefly trace the origin of labour problems in India.
2. Summarise carefully the principal characteristics of Indian Industrial labour.
3. Write a full note on the Migratory character of Indian Industrial labour
4. Indian Industrial labour is proverbially inefficient. Comment and suggest measures to improve the efficiency of Indian labourers
5. Write an essay on Industrial Housing in India.
6. Discuss the housing problem of industrial workers in India with special reference to the industrial towns of the country. What are the consequences of bad housing ?



## हमारी कुछ प्रमुख श्रम-समस्यायें II

( Labour Problems II )

### श्रम-कल्याण-कार्य

( Labour Welfare )

श्रम कल्याण कार्य की परिभाषा एवं क्षेत्र—

श्रम कल्याण कार्य का अर्थ बड़ा लचीला है। देश और समय की परिस्थितियाँ तथा आवश्यकताओं के अनुसार ही इसके अर्थ तथा विस्तार में परिवर्तन किया जा सकता है। प्रारम्भ में कल्याण कार्य से आशय सहायकता द्वारा स्वतः दी हुई ऐसी सुविधाओं से था, जिससे कि श्रमजीविता की सामाजिक एवं मानसिक उन्नति हो। ये सुविधाएँ श्रमिका की मजदूरी के अतिरिक्त उनके आराम के लिये होती हैं। वर्तमान समय में, कल्याण कार्य की परिभाषा काफी विस्तृत है। आज इससे हमारा आशय यह है कि कारखानों के भीतर और बाहर दोनों ही दशाओं में श्रमिकों के आराम और सुविधा का उचित प्रबन्ध होना चाहिए। श्रमिक-कल्याण कार्य के क्षेत्र की व्यवस्था करते हुए श्रम जाँच समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि श्रम कल्याण कार्यों के अन्तर्गत श्रमिकों के बौद्धिक, धारीरिक, नैतिक एवं आर्थिक विकास के कार्यों का समावेश होना चाहिए। ये कार्य चाहे नियोजता, सरकार या अन्य संस्थाएँ द्वारा किये जायें तथा साधारण अनुबन्धात्मक सम्बन्ध अथवा विधान के अन्तर्गत श्रमिकों को जो मिलना चाहिए उसके धराया किये गये हों। इस प्रकार इस परिभाषा के अन्तर्गत हम आवास व्यवस्था, चिकित्सा एवं शिक्षा सुविधाएँ, अच्छा भोजन (केन्टीन के आयोजन सहित), आराम एवं मनोरंजन की सुविधाएँ, सहकारी समितियाँ, धाय घर एवं शिशु गृह, शौचालय की व्यवस्था, श्रमिकों के छुट्टियाँ, सामाजिक बीमा, प्रावीडेंट फण्ड, सेवा निवृत्ति वेतन आदि सुविधाएँ का समावेश कर सकते हैं।

कल्याण कार्यों का प्रधान उद्देश्य श्रमिक को वेतन व काम के घण्टों की सुविधाओं के अतिरिक्त उसे अन्य सांस्कृतिक व सामाजिक लाभ पहुँचाना होता है। वास्तव में एक सन्तुष्ट, जागरूक, कर्तव्यपरायण व आत्म गौरवपूर्ण श्रमिक ही राष्ट्र की आर्थिक

प्रगति में सहायता कर सकता है। रायन श्रम-वर्षादन न श्रमिकों के लिये किये गये कल्याण कार्यों का 'विवेकपूर्ण ताणन' कहा है, जिसका प्रतिफल श्रमिका की बढ़ी हुई कार्यक्षमता के रूप में मिलता है। श्रम कल्याण कार्यों का तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है — ( १ ) वैधानिक ( २ ) स्वच्छापूर्ण एवं ( ३ ) पारम्परिक। वैधानिक कल्याण कार्यों में तात्पर्य उन सभी कार्यों में है जो श्रमिका के हित के लिये सरकार की आरंभ में विभिन्न कानूनों के रूप में किये जाते हैं। द्वितीय श्रेणी के कार्यों में उद्योगपतियों द्वारा किये हुए प्रथम तथा तीसरी श्रेणी में श्रमिक मण्डलों द्वारा किये हुए कार्य सम्मिलित किये जा सकते हैं।

भारत में श्रम कल्याण-कार्यों की आवश्यकता—

भारतवर्ष में श्रमिकों के हेतु कल्याण कार्यों की बहुत आवश्यकता है। यहाँ का श्रमिक प्रकुशल है और अन्य देशों की तुलना में उसकी कार्यक्षमता ग्लून है। श्रमिकों को सन्तुष्ट और सुखी बनाने के लिए उनकी परिस्थिति में सुधार करना चाहिए। हमारी दृष्टि में श्रमिकों की केवल नकद मजदूरी वृद्धि ही से कोई विनाश लाभ न होगा, क्योंकि इसमें उनकी कार्य-निपुणता पर कोई गम्भीर प्रभाव नहीं पड़ता। सम्भव है कि नकद राशि का बँटवड़ा और नग्न में उन्नत है। इसका विपरीत यदि कल्याण कार्यों के द्वारा उनकी लाभ पहुँचाया जायगा तो हमें विश्वास है कि उनकी कार्य-क्षमता प्रवर्धित होगी। दूसरे, जितनी अधिक श्रम-कल्याण की सुविधाएँ श्रमिकों को मिलेंगी उतना ही आकषण कारखाना के प्रति अधिक होकर कारखाना जीवन की तीव्रता कम होगी, अर्थात् श्रमिका का नैतिक स्तर भी ऊँचा होगा। तीसरे, श्रमिका में नागरिक उत्तरदायित्व की भावना जागृत होकर वे देश के आदर्श नागरिक बन सकते हैं। इन लाभों से ही प्रेरित होकर टंकमण्डल लबर इन्क्वायरी कमिटी ने कहा था—“कार्यक्षमता का उन्नत स्तर केवल यही ही सक्षमता है, जहाँ श्रमिक शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ तथा मानसिक दृष्टि में सन्तुष्ट हो। इसकी तात्पर्य यह है कि कबल वहीं श्रमिक कुशल हो सकते हैं जिनके लिये शिक्षा, आवास, भोजन तथा वस्त्रादि का उचित प्रबन्ध हो।” हमारी दृष्टि में हमारे देश में बम्बई विश्वविद्यालय ने श्रम समस्याओं एवं कल्याण कार्यों के अध्ययन तथा शिक्षा के लिए विनाश प्रबन्ध किया। धा टाँग ने भी बॉम्बे स्कूल आफ इकॉनॉमिक्स एवं मीडियम माइन्स की स्थापना इसी उद्देश्य से की है।

भारत में श्रम-कल्याण कार्यों का विकास—

कल्याण कार्य की भावना वास्तव में एक नवीन स्फूर्ति है, जिसमें प्रथम महा युद्ध के पश्चात् से अधिक आरंभ पड़ा। प्रथम महायुद्ध युग में जब निर्मित वस्तुओं की माँग बढ़ी, आवश्यक वस्तुओं के दाम चढ़ गये। नगरों में गृह समस्या उत्पन्न हो गई, श्रमिका की कार्यक्षमता में कमी आ गई तो ऐसी परिस्थितियों में उद्योगपतियों के

ध्यान श्रम-कल्याण की ओर आकर्षित हुआ। सन् १९२२ में बम्बई में एक अखिल भारतीय श्रम-कल्याण सम्मेलन आयोजित किया गया था, किन्तु प्रस्ताव पास करने के अनिश्चित इमने कोई भी रचनात्मक कार्य नहीं किया। सचभुच में द्वितीय महापुद्ग के उपरान्त ही सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। सर्व प्रथम उन कारखानों में श्रम-कल्याण कार्य आरम्भ किये गये जिनमें युद्ध सम्बन्धी सामग्री का निमाण किया जाता था। सन् १९४२ में, कन्द्रीय सरकार ने एक श्रम-कल्याण मलाहकार (Labour Welfare Adviser) नियुक्त किया और उसकी सहायता के लिये कुछ अन्य अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई। सन् १९४४ में कौयल की खानों में कार्य करने वाले श्रमिकों के कल्याणार्थ सनियम बनाये गये। इस कार्य के लिये एक कल्याण काप (Labour Welfare Fund) भी स्थापित किया गया। इन श्रमिकों के लिये टी० बी० अस्पताल में ६ स्थान सुगृहित कर दिये गये। सन् १९४३ में एक अन्य अधिनियम अन्नक की खानों में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिये पास किया गया। सन् १९४७ में उनके ही लाभार्थ एक कल्याण कोष स्थापित किया गया। अन्य अधिनियमों द्वारा सरकार ने काम के घण्टे कम कराये गये सिगुह, मकान, जल इत्यादि का प्रबन्ध कराया। उन कारखानों में जहाँ ५०० से अधिक श्रमजीवी कार्य करते हैं, श्रम-कल्याण अधिकारी (Labour Welfare Officer) की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है।

सन् १९४८-४९ में सरकार ने एक श्रम-कल्याण कोष स्थापित किया, जिसमें उसकी ओर से १ लाख रुपये का अनुदान दिया गया। इस काप से उन संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी, जो श्रम-कल्याण कार्य करती थी।

कारखाना अधिनियम सन् १९४८ के अनुसार ऐसे प्रत्येक कारखाने में जहाँ २५० से अधिक श्रमजीवी कार्य करते हैं, कैंटीन का होना अनिवार्य है।

सन् १९५२-५३ में मध्यप्रदेश के चादा नगर में १० स्त्रियों के लिए एक प्रसूनालय बनाया गया। कौयल की खानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए ७ बहु-उद्देशीय कल्याण केन्द्र और विध्यप्रदेश में ३ बहु उद्देशीय कल्याण केन्द्रों की स्थापना की गई। सन् १९५२-५३ में ही प्रॉब्लिडेंट फण्ड योजना चलाई गई, जो पहले बिजली, लोहा व स्पात, इन्जनियरिंग, कागज, कपड़ा, सीमेंट तथा मिगरेट उद्योगों पर लागू की गई। ३१ जुलाई सन् १९५६ को यह योजना १३ अन्य उद्योगों पर लागू की गई और सितम्बर सन् १९५६ को ७ अतिरिक्त उद्योगों पर लागू की गई, जिनमें दियासलाई, चीनी, चाय, प्रेस, सीसा, भारी रसायन तथा तेल सम्मिलित हैं। ३१ दिसम्बर सन् १९५६ को समाचार पत्रों पर तथा १३ जनवरी सन् १९५७ से खनिज तेलों पर भी यह योजना लागू कर दी गई है। अब यह योजना उन सभी उद्योगों पर लागू होगी जिनमें ५० से अधिक श्रमजीवी कार्य करने हैं और जिन्हें स्थापित हुए ३ वर्ष हो चुके ह।

सन् १९५३ में केन्द्रीय सरकार ने एक केन्द्रीय कल्याण मण्डल (Central Welfare Board) स्थापित किया, जो सारे देश में कल्याण कार्यों का समन्वय करता है। सन् १९५३ ५४ में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने श्रम-अधिकारियों के प्रशिक्षण के हेतु एक नया विभाग स्थापित किया।

**भारत में आयोजित श्रम-कल्याण कार्य—**

भारतवर्ष में अभी तक जितना भी श्रम कल्याण कार्य किया गया है उसका ध्येय मुख्यतः तीन संस्थाओं को है—( १ ) सरकार, ( २ ) उद्योगपति और ( ३ ) श्रमिक संघ। अब हम इन संस्थाओं द्वारा किये गये कार्य का विवेक विवेचन करेंगे।

**केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोजित कल्याण कार्य—**

मुद्रोपरान्त ( सन् १९३६ ४५ ) केन्द्रीय सरकार ने श्रमिकों की ओर ध्यान दिया। उसके पूर्व सन् १९२२ में बम्बई में एक अखिल भारतीय श्रम हितकारी सम्मेलन के मुद्दामों के प्रतिरिक्त कोई महत्वपूर्ण प्रयत्न उसने नहीं किया था, लेकिन अब उसने कुछ ठोस कदम उठाये हैं। सन् १९४२ में एक श्रम हितकारी समझौता और उसकी सहायता के अन्तर्गत श्रम हितकारी नियुक्त किए। सन् १९४४ में कोयला खानों के श्रमिकों के लिए एक हितकारी कोष खोला, जिसके द्वारा श्रमिकों के मनोरंजन, चिकित्सा और शिक्षा का प्रबन्ध किया गया। सन् १९४६ में अग्रक खान श्रमिक हितकारी कोष अधिनियम पास कर दिया गया। साथ ही, सरकार ने अन्य कानूनों का निर्माण किया जिनके आधार पर कारखानों के श्रमिकों के लिए मकानों की व्यवस्था, कान के घंटे, रोशनदान, मशीनों को ढँक कर रखना, चिकित्सा, उपहार गृह और शिशु-गृहों की व्यवस्था की गई। देखभाल के लिए निरीक्षक रखे गये। ५०० या इससे अधिक श्रमिक वाले कारखानों में श्रमिक हितकारी समिति की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई। सरकार अपने कारखानों में श्रम हितकारी कोष स्थापित करने के साथ व्यक्तिगत औद्योगिक कारखानों में कोष स्थापित कराने के प्रयत्न कर रही है। यह कोष श्रमिकों के लिए हितकारी सेवाएँ छुटाने में व्यय किया जाता है। सन् १९५४ में स्थायी श्रम समिति ने भी श्रम हितकारी कोष की स्थापना पर बल दिया। यह कोष केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित करना चाहिए। इसमें अन्तर्गत कारखाने, ट्रामवे तथा मोटर बस सेवाएँ, आन्तरिक स्टीम जलयान, बायला व अग्रक की खानों के प्रतिरिक्त सब छानें, तेल कूप, उद्यान, जन क्लब, मिर्चाई तथा विद्युत सम्मिलित किये गये हैं। वाचनालय, रेलवे कर्मचारियों तथा बन्दरगाहों पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए भी विभिन्न प्रकार की हितकारी सुविधाएँ कर दी गई हैं।

योजना कमिशन ने भी श्रम कल्याण कार्यों के महत्त्व का भलीभाँति समझा है, अतः उन्होंने पंचवर्षीय योजना में इन कार्यों के लिए ७ करोड़ रुपये व्यय करने

का निश्चय किया था । द्वितीय आयोजन में केवल श्रमिकों के कल्याणार्थ २६ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । प्रथम पंच-वर्षीय योजनाकाल में देश में १३ लाख घर बनवाये गये। युद्धोत्तर काल में सरकार ने श्रमिकों के लिए सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों, सहकारी गृह निर्माण समितियों, उद्योगपतियों तथा गृह निर्माण बोर्डों को आर्थिक सहायता देकर गृह बनवाये । प्रथम आयोजन काल में कुल ३८५ करोड़ रुपये गृह निर्माण पर व्यय किया गया और द्वितीय आयोजन में १२० करोड़ की व्यवस्था की गई है । उद्यानों तथा भ्रमक व कोयले की खानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिये घर बनवाये जा रहे हैं । ये घर श्रम मन्त्रालय के अन्तर्गत बन रहे हैं । इसी प्रकार अन्य केन्द्रीय तथा राज्य मन्त्रालय अपने अपने विभागों में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए घर बनवाने की योजनायें चला रहे हैं । द्वितीय आयोजन काल में देश में कुल १६ लाख घर बनवाये जायेंगे ।

**राज्य सरकारों द्वारा किये गये श्रम-कल्याण कार्य—**

केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त राज्य सरकारों ने भी श्रमिकों के कल्याण के लिए बहुत कुछ किया है । इस दिशा में कार्य का श्रीगणेश तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही हो गया था और सन् १९३७ में भी कॉंग्रेसी सरकारों ने इन कार्यों के प्रति बड़ी रुचि दिखाई थी, किन्तु कोई सहायनीय कार्य नहीं हो सका । हाँ, युद्धोत्तर काल में अवश्य प्रान्तीय सरकारों का ध्यान इस ओर गया और स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद तो राज्य सरकारों ने इस दिशा में बड़ा प्रयत्न किया है । अब हम भारत के कुछ औद्योगिक राज्यों में होने वाले श्रम कल्याण कार्यों पर प्रकाश डालेंगे ।

**बम्बई राज्य—**बम्बई राज्य में श्रम कल्याण के लिये सबसे पहले सन् १९३६ ४० के बजट में १,२०,००० रु० का आयोजन किया गया था, जिससे कल्याण केन्द्र स्थापित किये गये । सन् १९४६ ५० के बजट में इसी कार्य के लिये १०,६८,०८३ रु० स्वीकार किये गये । सन् १९५१ ५२ में इस राज्य में ५४ कल्याण केन्द्र थे—५ 'क' श्रेणी के, ११ 'ख' श्रेणी के, ३६ 'ग' श्रेणी के और २ 'घ' श्रेणी के । ये चार श्रेणियाँ सुविधाओं के आधार पर वर्णित हैं । 'क' श्रेणी के कल्याण केन्द्रों में निम्न सुविधायें प्रदान की जाती हैं—पुरुषों के लिए मँदानी तथा भीतरी खल, स्त्रियों की सिलाई तथा कढ़ाई, बच्चों के लिए नर्सरी स्कूल, स्त्री-पुरुषों के लिए अलग-अलग स्नानागार, औषधालय, पुस्तकालय, वाचनालय तथा आदि । १. आर. फ़िल्म, टिक्काने, का, प्रबन्ध । अन्य श्रेणी के केंद्रों में सुविधायें कम होती हैं । बम्बई नगर में १८ केंद्र हैं, शोलापुर और अहमदाबाद में ६-६ केंद्र हैं । सन् १९५३ ५४ में बम्बई राज्य ने श्रम कल्याण का अधिनियम पास कर दिया । श्रम कल्याण के कार्य संचालन के लिए

१४ सदस्यों की एक सभा बनाई गई। सन् १९५७ व बजट में ₹८७८ लाख रुपये का अनुदान दान स्वीकार किया गया, जिसमें स २७६७ लाख रुपये श्रीयोगिब प्रायश्चित्त व लिए दिए गए। एक सराहनीय कार्य बम्बई राज्य न यह किया है कि धर्मियों में स ही नताश्रा का निर्माण किया जाय और इसके लिए उन्हें बम्बई, घटमदावार तथा शालापुर में शिक्षा दी जाती है। सभी वर्ष में राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत ५,२७,६१८ धर्मिका का सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य बीमा इत्यादि की सुविधा प्रदान की गई। धर्म-कल्याण काया द्वारा हम प्रदान व धर्मियों को काफी लाभ पहुंचा है और उनकी क्षमता में विशेष वृद्धि हुई है।

उत्तरप्रदेश—इस प्रदेश में सन् १९५७ में प्रथम बार काँग्रेस मंत्रिमंडल की स्थापना हुई तथा कानपुर में ४ कल्याण केंद्र स्थापित किये गये। सन् १९५७ क बाद इस दिशा में सराहनीय प्रगति हुई है। सन् १९५५ में हम राज्य में धर्म-कल्याण केंद्रों की संख्या ४४ थी। सुविधाओं के विचार से उनकी ३ श्रेणियां की गई हैं—अ, ब और स। प्रथम श्रेणी के केंद्रों में एक एंजेलोर्षी का चिकित्सालय, पुस्तकालय व वाचनालय, स्त्रियों के लिए सिलाई व नक्काई की कक्षाएँ, भीनरी और बाहरी तेल, सगीन, रेडियो, प्रभृति गृह इत्यादि की व्यवस्था होती है। द्वितीय श्रेणी के केंद्रों में भी लगभग यही सुविधाएँ होती हैं। यहाँ होम्सोर्षी का चिकित्सालय होता है। तृतीय श्रेणी के केंद्रों में पुस्तकालय व वाचनालय, खेल-कूद तथा रेडियो इत्यादि होते हैं। धर्म हितकारी केंद्रों पर मुफ्त में सिनेमा भी दिखाये जाते हैं। कभी कभी धर्मियों का कार्यक्रम प्रखिल भारतीय रेडियो लखनऊ व इलाहाबाद पर भी होता है। टूर्नामेन्ट व दण्ड आयोजित किये जाते हैं, जिनमें विजेता धर्मियों का पुरस्कार व प्रमाण-पत्र देकर प्रोत्साहित किया जाता है। चर्चा कक्ष, प्राद शिक्षा कक्षाएँ तथा स्त्रियों के लिये व्यावसायिक शिक्षा की कक्षाएँ भी इन केंद्रों द्वारा चलाई जाती हैं।

सन् १९५४ में कानपुर में धर्मियों के हितार्थ एक टी० बी० का अस्पताल खोला गया है। इसके अतिरिक्त चिकित्सकों के एक मंचन दल का भी निर्माण किया गया है। जुलाई सन् १९५४ में केन्द्रीय सामाजिक हितकारी बोर्ड व आधार पर U. P. Social Welfare State Advisory Board की भी स्थापना कर दी गई है। यही नहीं, धर्मियों के रहने के लिए हजारों घरों का भी निर्माण किया गया है। गृह-निर्माण कार्य को उत्तरप्रदेश में नील श्रेणियों में विभक्त किया गया है। प्रथम श्रेणी में धर्मियों के लिए कानपुर तथा लखनऊ में क्रमशः २,२१६ व २६० घर सन् १९५४-५६ में बने, जो धर्मियों को आ दिए गए हैं। द्वितीय श्रेणी में कानपुर में ३,७५० गृहों का निर्माण किया गया है। तृतीय श्रेणी में कानपुर, आगरा, फिरोजाबाद, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सहारनपुर तथा बनारस में ७,४०० मकान बनाने की योजना है, जिनमें स पाँच हजार घरों का निर्माण हो चुका है। धर्मिक राज्य बीमा योजना, जो सन् १९५०

में कानपुर में लागू की गई थी, अब उस नगर के लाखों श्रमिकों को लाभ पहुँचा रही है। सन् १९५५-५६ में अगरा, लखनऊ तथा सहरनपुर में २० हजार श्रमिकों को भी इसके अन्तर्गत ले लिया गया है। स्त्रियों की देखभाल के लिये एक महिला अधिकारी (Woman Labour Welfare Superintendent) की नियुक्ति की गई है। उत्तर प्रदेश की द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत २५३.१ करोड़ रुपये की निर्धारित धन राशि में से श्रम कल्याण पर १४२.५ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

**पश्चिमी बंगाल**—सन् १९४० में बंगाल राज्य में १० श्रम कल्याण केन्द्र खोले गये, जिनकी संख्या बढ़ने लगी सन् १९४५ में ४१ हो गई। विभाजन के बाद इनकी संख्या ३० रह गई। इन केन्द्रों पर भी चिकित्सा, मनोरंजन, खेल कूद, शिक्षा और सिलाई इत्यादि की सुविधायें उपलब्ध हैं। लगभग ४५ हजार व्यक्ति प्रतिदिन इन केन्द्रों पर जाते हैं तथा लगभग १६,९६४ बच्चे और ६,४४८ प्रौढ़ प्रातः तथा सन्ध्या कालीन कक्षाओं में शिक्षा पाते हैं। कलकत्ता, हावड़ा तथा सीरामपुर में श्रमिकों के लिये क्वार्टर बनवाये जा रहे हैं। राज्य में इस समय १५ चिकित्सालय श्रमिकों के लिये कार्य कर रहे हैं। चाय के बगीचा में काम करने वाले श्रमिकों के लिये केन्द्रीय चाय बोर्ड ने सन् १९५५-५६ में एक लाख रुपये का कल्याण कार्यों के लिये दिया था। इससे मुख्यतः स्त्रियों तथा बच्चों का कल्याण होगा। सन् १९५७ में पुर्खरियाबाग तथा बाग-बोगरा में दो कल्याण केन्द्र खोले गए हैं। जूट मिल्स के श्रमिकों की आर्थिक तथा सामाजिक दशा में काफी सुधार हो गया है और उनकी कार्यक्षमता में भी वृद्धि हुई है।

**अन्य राज्य**—भारत के अन्य राज्यों में भी श्रम कल्याण केन्द्र स्थापित किये गये हैं। पंजाब के नगरों (अमृतसर, लुधियाना, अम्बाला, बटाला, जालंधर तथा अजुल्लापुर) में इनकी स्थापना हुई है। मध्य प्रदेश में हिंगनघाट, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, इन्दौर, रतलाम में—मद्रास में नीलगिरि, कोयम्बटूर तथा करियार रोड (उड़ीसा) राजस्थान के गयासगर, जोधपुर और कृष्णगढ़ में भी केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि श्रम कल्याण कार्यों की ओर केन्द्रीय व राज्य सरकारों का ध्यान बढ़ता ही जा रहा है। भारत का प्रत्येक राज्य अपने-वो 'कल्याणकारी राज्य' (Welfare State) कहता है, किन्तु समस्या की गुरुता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना शेष है।

**उद्योगपतियों द्वारा कल्याण-कार्य—**

सन्धे भारत की उदासीनता के बाद उद्योगपतियों ने श्रमिकों के प्रति कुछ विशेष जागरूकता दिखाई है, लेकिन उनके श्रम कल्याणकारी प्रयत्न अधिकांश में श्रमिकों के हित के प्रति दया भावना पर आधारित हैं। बड़ा उद्योगपतियों के दृष्टि कोण का प्रश्न है, वे अब तक क्या याण क्या-वो श्रमजीवियों को फँसाने के लिये ए-

‘मृग मरीचिका व जाल’ के रूप में उपयोग करते रहे हैं। इन कार्यों को करते हुए वे एक प्रकार से श्रमिकों के ऊपर मानों अहसान-सा करते हैं। यद्यपि अधिकांश में उद्योगपति आज भी बड़े अनुदार हैं और वे कल्याण-कार्यों में होने वाले व्यय को अधिक लागत नहीं मानते, किन्तु कुछ उद्योगपति उदार व प्रगतिशील भी हैं, जो इस व्यय को विनियोग समझ कर करते हैं, जो भविष्य में उनकी बड़ी हुई उत्पादन क्षमता के रूप में उन्हें पुनः मिल जाता है। अब हम ऐसे ही उद्योगपतियों द्वारा किए हुए कल्याण कार्यों की भाँकी करेंगे।

### सूती-शस्त्र-मिल-उद्योग—

बम्बई में भूमी मिलों में चिकित्सालय, जलपानगृह स्थापित किये गये हैं। कुछ मिलों में आधुनिकतम अस्पताल भी हैं। इनके अतिरिक्त बाहरी भीतरी खेलों की सुविधा, सहकारी समितियाँ, बाग एव प्रीठ सिंहालय, प्रॉवीडेंट फण्ड की योजना आदि सुविधाओं की व्यवस्था भी देश के लगभग सभी मिलों में की गई है। इस दृष्टि से नागपुर का एम्प्रेस मिल, दिल्ली का देहली कर्बोण एण्ड जंतरल मिल्स व बिडला कॉटन मिल्स, खालियर का जीवाजीराव कॉटन मिल्स, मद्रास के बकिंघम एण्ड कर्नाटक मिल्स, बगलौर का बगलौर बुलियन कॉटन एण्ड मिल्स तथा मदुरा मिल्स कम्पनी ने अत्यन्त सराहनीय कार्य किये हैं।

### जूट-उद्योग—

जूट-उद्योग में श्रम हितकारी कार्यों को करने वाली एक मात्र संस्था भारतीय जूट मिल संघ है, जिसने हजारीबाग, कनकी नाटा, सीरामपुर टीटागढ़ और भद्रावर में श्रम हितकारी केंद्रों की स्थापना की है। इन केंद्रों पर बाहरी भीतरी खेल कूदों की व्यवस्था की जाती है। संघ की ओर से पाँच प्राथमिक पाठशालायें भी चल रही हैं। जूट मिलों ने व्यक्तिगत रूप से भी हितकारी कार्यों में योग दिया है। सभी जूट मिलों में एक चिकित्सालय है। सात मिलों में प्रमूताओं के लिये निम्निक है। ५१ मिलों में शिशुगृह एव ४५ जूट मिलों में जलपान गृह खोले गये हैं।

ऊँची मिलों में बड़े कारखानों में सभी उत्तम व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं और छोटी मिलों में न्यूनतम कानूनी सुविधाओं का प्रबन्ध है।

इंजीनियरिंग उद्योग में १,००० या इसके अधिक श्रमिक वाले सभी कारखानों में चिकित्सालय हैं। जहाँ जहाँ स्त्री श्रमिक हैं वहाँ शिशु गृह भी बने हैं। जलपान-गृह तो सभी कारखानों में मिलेंगे। १०० से ऊपर श्रमिक वाले कारखानों में प्रॉवीडेंट फण्ड योजना लागू है। टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी जमशेदपुर विशेष उल्लेखनीय है। इसमें ४०० पलङ्ग वाला अस्पताल, प्रमूता-गृह एव ६ प्रमूति निम्निक हैं। कंपनी की ओर से ३ हार्डस्कूल, १० मिडिल स्कूल और २५ प्राथमिक स्कूल खोले गये हैं।



२ बड़े जलपान गृह हैं । विशाल क्रीडा स्थल, मुक्त सिनेमा, सहकारी उपभोक्ता भण्डार व डाकखाने आदि की आदर्श व्यवस्था है । अन्य कारखानों में भी इसी प्रकार व्यवस्था करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

कोयला तथा अभ्रक की खानों में श्रमिक हितकारी कोष कानून द्वारा बनाये जा चुके हैं, जिनके अन्तर्गत अनेक श्रम-हितकारी कार्य किये जा रहे हैं । कोलार की सोना खानों में भी श्रम हितकारी कार्य हो रहे हैं ।

आसाम तथा पश्चिमी बंगाल के अधिकांश बड़े चाय उद्योगों में बड़े बड़े अस्पताल बने हैं । इनमें अभी जो व्यवस्थाएँ की गई हैं वे अत्यन्त अपर्याप्त हैं ।

इसी प्रकार की न्यूनाधिक व्यवस्थाएँ अन्य उद्योगों में भी की गई हैं, परन्तु श्रमिकों की आवश्यकताओं को देखते हुये ये प्रयत्न अपर्याप्त हैं ।

**श्रमिक सघों द्वारा हित-कार्य—**

श्रम-सघ धन की कमी के कारण अधिक कार्य नहीं कर सके हैं । तथापि कुछ सघों ने साराहनीय कार्य किया है जिसमें अहमदाबाद टैंकसायल श्रम-सघ, मजदूर मभा कानपुर एव मिल मजदूर सङ्घ इन्दौर प्रमुख हैं । इन्होंने पुस्तकालय, चिकित्सालय, शिक्षालय ( प्रौढ एव बाल ), क्लबों आदि की व्यवस्था की है ।

**समुक्त राष्ट्र सघ द्वारा भारत में कल्याण कार्य—**

कल्याण-कार्य के क्षेत्र में समुक्त राष्ट्र सङ्घ द्वारा की हुई सेवाओं का उल्लेख करना अनावश्यक न होगा । इस संस्था ने भारतीय बालकों के कल्याण कार्य के लिए मार्च सन् १९५४ तक लगभग ६० लाख डालर तक व्यय कर दिया है । भारत सरकार की प्रथम पञ्च वर्षीय योजना के अन्तर्गत कल्याण कार्यों का समुक्त-राष्ट्र सघ के मातृ तथा बाल कल्याण कार्यों से सम्बन्धित योजना से समन्वय कर दिया गया है । इस योजना के अन्तर्गत आगामी दो वर्षों में स्वास्थ्य निरीक्षकों तथा दाइयों के प्रशिक्षण एव उन्हें चिकित्सा सम्बन्धी पर्याप्त सज्जा से सुसज्जित करने में बीस लाख डालर व्यय किये जायेंगे । 'समुक्त राष्ट्र सघीय अन्तर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष' (United Nations International Children and Emergency Fund—U. N. I. C. E. F. ) भारत में माताओं तथा बच्चों को दूध वितरित करने तथा प्रसूति गृह और बाल कल्याणकारी केन्द्रों की स्थापना के उद्देश्य से आरम्भ किया गया था । इनमें से १० लाख डालर मलेरिया नियन्त्रण, दूध वितरण और दुग्धिक्ष निवारण में खर्च किया जा चुका है । इस धन का अधिकांश भाग भारतीय गांव तथा श्रमिक बस्तियों में व्यय होता है ।

**उपसंहार—**

उक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि भारत में श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि

करन तथा उनके लिए कल्याण कार्यों की व्यवस्था के बहुत कुछ प्रयत्न किये जा रहे हैं, किन्तु समस्या की गम्भीरता एवं श्रुता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस दिशा में अभी तक जो कुछ भी किया गया वह बहुत ही थोड़ा है। सच बात तो यह है कि विभिन्न धार्मिक सन्प्रियाओं में जो गई कल्याण सुविधाओं का पूनर्गठन भी धार्मिक श्रमिकों को अधिकांश में नहीं मिल पाता, अतः सर्व प्रथम तो पूर्व स्थित सन्प्रिया को ही सन्धे अथवा कार्योन्वित करन की आवश्यकता है। दूसरे धार्मिकों की समस्याओं को मुनभान के लिए यह भी नितान्त आवश्यक है कि एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाय। सभी भारतीय धार्मिक विश्व के अन्य देशों के धार्मिकों के समान निपुण व वलिष्ठ होकर देश का धार्मिक उत्थान कर सकेंगे।

**संयुक्त राष्ट्र-संघ एवं भारत में धर्म-कल्याण कार्य—**

संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के सभी देशों के धार्मिकों के कार्यों में सहायता देता है। इस समस्या में भारत तथा अन्य दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के धर्मजीवियों के धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए सहायनीय कार्य किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारतीय बालकों के कल्याणार्थ मार्च सन् १९५४ तक लगभग ६० लाख डालर व्यय किया। भारत की प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत कल्याण कार्यों का संयुक्त राष्ट्र संघ के मातृ तथा कल्याण कार्यों से सम्बन्धित एक योजना से समन्वय कर दिया गया था। इस योजना के अन्तर्गत सन् १९५५-५६ में स्वास्थ्य निरीक्षकों तथा दाइयों के प्रशिक्षण तथा उन्हें चिकित्सा सम्बन्धी पर्याप्त सज्जा से सुसज्जित करन में २० लाख डालर व्यय किये गये।

संयुक्त राष्ट्र संघीय अन्तर्राष्ट्रीय बाल सङ्कट काष्ठ (U. N. I. C. E. F. —United Nations International Children's Emergency Fund) भारत में माताओं तथा बच्चों को दूध वितरित करन तथा प्रभूतिगृहों एवं बाल कल्याण केंद्रों की स्थापना के उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया था। इसमें स १० लाख डालर दूध वितरण, मलेरिया निःशरण एवं दुर्भिक्ष निवारण पर व्यय किया जा चुका है। इस धन का अधिकांश भाग भारतीय मातृ तथा धार्मिक वस्तियों में व्यय हो रहा है।

इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्य सरकारों को कोष राशि में स उनका भाग देती है। इसमें से पश्चिमी बंगाल को १ २५ लाख डालर, केरल को ११० लाख डालर बिहार को २ लाख डालर तथा उत्तर प्रदेश को भी २ लाख डालर दिये जा चुके हैं। ये राज्य सरकारें पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत कल्याणकारी कार्यों को अपनी योजनाओं पर इस धन का उपयोग माताओं तथा बच्चों के कल्याण कार्यों पर कर रही हैं। मातृ के लिए दाइयाँ को प्रशिक्षित करके उन्हें सज्जा (Kit)

प्रदान करना, योजना का मूल उद्देश्य है। इस सञ्चा में वे सभी वस्तुएँ सम्मिलित होंगी, जिनकी कि प्रसव के समय आवश्यकता पड़ सकती है। उक्त संस्था ने ऐसी १४,००० सञ्चायें विद्व के २७ राष्ट्रीयों को देने की योजना बनाई है, जिसमें अकेले भारत को ६,००० सञ्चायें मिलेंगी। आशा ही नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इन प्रयत्नों में भारतीय श्रमिकों का बड़ा लाभ होगा। इस समय श्रमिक वस्तियों में मातृ-मृत्यु तथा बाल मृत्यु के ऊँचा होने के कारण अपार मानव सहार हो रहा है, अतएव इस योजना के परिणामस्वरूप सहार न होकर मानवीय कल्याण की वृद्धि होगी।

**श्रम-सघों द्वारा किये हुए कल्याण-कार्य—**

भारतीय श्रम सघों की शक्ति अभी तक अधिकांशतः अपने वेतन तथा काम करने की दशाओं के सम्बन्ध में उद्योगपतियों से संघर्ष करने में ही लगी रही, अतएव कल्याण-कार्य की दिशा में रचनात्मक कार्य करने के लिए उन्हें कम मुद्रवसर मिला। यही नहीं, दयनीय आर्थिक परिस्थितियों के कारण भी वे इस दिशा में कुछ करने में असमर्थ रहे। जब श्रमिक स्वयं अपना पेट नहीं भर सकता तो उसके सघ किस प्रकार सम्पन्न हो सकते हैं? कल्याण-कार्य की व्यवस्था के लिए काफी धन की आवश्यकता पड़ती है। फिर कुछ श्रम-सघों ने इस दिशा में अनुकरणीय कार्य किये हैं, जिनमें से ग्रहमदावाद मूती बल मिल श्रम-सघ, मजदूर-सभा कानपुर एवं मिल मजदूर संघ इन्दौर के नाम उल्लेखनीय हैं।

**ग्रहमदावाद टैक्सटाइल श्रम-सघ—**

इस सघ की लगभग ७५% आय कल्याण-कार्यों पर ही व्यय होती है। इस संघ के तत्त्वावधान में २५ ऐसे केन्द्र स्थापित किये गये हैं, जहाँ श्रमिक एकत्रित होकर सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं। प्रत्येक केन्द्र में एक पुस्तकालय तथा वाचनालय है। इसके अतिरिक्त यह ७५ सहायता अनुदान प्राप्त वाचनालयों एवं सचल पुस्तकालयों का भी संचालन करता है। ग्रहमदावाद की प्रमुख श्रम वस्तियों में श्रीहास्पल भी सघ की ओर से स्थापित किये गये हैं। इसके अन्तर्गत श्रम-सदस्यों की चिकित्सा के लिये एक एलोपैथिक तथा एक होमियोपैथिक तथा एक आयुर्वेदिक औषधालय है। सघ द्वारा संगठित ६ शिक्षा संस्थायें भी नगर में चल रही हैं, जिनमें से ६ स्कूल, २ अध्ययन भवन (Study Homes) तथा एक बालिकाओं के लिए छात्रावास है। प्रति वर्ष श्रमिकों के बच्चों को सहायना देकर उन्हें उच्च अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सघ द्वारा संगठित चार व्यवसायिक प्रशिक्षण-शालायें भी हैं। सन् १९५२ में इन सघ ने एक बैंक तथा एक सहकारी उपभोक्ता भण्डार भी खोला। इस विवरण से स्पष्ट है कि ग्रहमदावाद श्रम-सघ ने कल्याण-कार्य की दिशा में सहायनीय कार्य किया है।

कानपुर मजदूर-समा ने भी मजदूरो के कल्याणार्थ पुस्तकालय, वाचनालय तथा चिकित्सालय की स्थापना की है। इन्दौर मिल मजदूर सघ ने श्रम कल्याण केन्द्र की स्थापना की है। इस केन्द्र की तीन शाखाएँ हैं—बाल मन्दिर, महिला मन्दिर तथा वन्य मन्दिर। बाल मन्दिर में श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा, उनके लिए स्वास्थ्य, खेल कूद व क्रीडास्थल आदि तथा सांस्कृतिक विवास के लिए सद्गीत, नृत्य तथा अभिनव इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। वन्य-मन्दिर में श्रमिक बालिकाओं की प्रारम्भिक शिक्षा, खेल कूद व स्वास्थ्य, मिलाई कढ़ाई तथा अन्य गृह विज्ञान सम्बन्धी बातों के पढ़ाये जान, आदि का व्यवस्था है। महिला मन्दिर में महिलाओं के हेतु प्रौढ शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुधार इत्यादि की व्यवस्था की गई है।

उपयुक्त श्रम सघों के अतिरिक्त दश के रेल कमचारी सघ भी अपने सदस्यों के लिए कल्याण कार्य की व्यवस्था करते हैं—जैसे—क्वब खोलना, सहकारी समितियों की स्थापना करना, मुकद्दमों की पैरवी करना इत्यादि। उत्तर प्रदेश में भारतीय श्रम सघ (Indian Federation of Labour) ने अनेक श्रम कल्याण केन्द्रों की स्थापना की है। आसाम में चाय क बगीचों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए केन्द्रीय सरकार की सहायता से 'अखिल भारतीय राष्ट्रीय टूड यूनिपन कांफ्रस' ॥ कुछ श्रम कल्याण कार्यों का आयोजन किया है। अन्त में हम यह कह सकते हैं कि श्रम श्रमिक वर्ग काफी जागरूक हो गया है और वह स्वयं सघीय शक्ति में अपने पैरों तड़ा होन की चेष्टा कर रहा है, किन्तु अभी तक श्रमिक सघों ने जो कुछ भी किया है, उसे सन्तोषजनक एव पर्याप्त नहीं कहा जा सकता।

**प्रथम पंचवर्षीय योजना में श्रम-कल्याण—**

प्रथम पंच-वर्षीय योजना में श्रम कल्याण के लिये १०३१ करोड़ रुपये आयोजित किये गये थे। चाय बागानों के श्रमिकों के हितार्थ केन्द्रीय चाय मण्डल (Central Tea Board) को ४ लाख रुपये दिये गये थे। ७६,६७६ क्वार्टर बनवाने की योजना स्वीकार की गई थी, जिनमें से १६,१६५ बम्बई में, २१,७०६ उत्तर प्रदेश में, ५,६२६ हैदराबाद में, ५,१८१ मध्य प्रदेश में और ३,४४४ मध्य भारत व अन्य राज्यों में बनाये जाने थे। प्रथम योजना के अन्त तक ४०,००० अकान बन कर तैयार हो चुके थे।

मई सन् १९५४ में सरकार ने १२८ करो के निर्माण के लिए १,६७,६५० रुपये का अनुदान दिया था। इसमें से १८,६०० रुपये बम्बई राज्य को दिये गये और इसके अतिरिक्त ३७,८०० रुपये अणु के रूप में दिये गए थे। जुलाई सन् १९५४ में आन्ध्र प्रदेश की चीनी मिल को १,०१,२५० रुपये का अनुदान और १५८ ३४२ रुपये का ऋण दिया गया। इसी योजना के अन्तर्गत अगस्त सन् १९५४

में केन्द्रीय सरकार ने १०,२२६ मकानों के निर्माण के लिए ३,१४,३५,२६७ रुपये की आर्थिक सहायता दी, जिसमें से उत्तर प्रदेश को लगभग २ करोड़ रुपये मिले थे। निम्न तालिका से यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य में इस योजना के अन्तर्गत कितने मकानों का निर्माण किया गया।—

नगर	मकानों की संख्या
कानपुर	३,४००
आगरा	१,२६६
फिरोजाबाद	१,०००
सहारनपुर	६०४
इलाहाबाद	५०४
बनारस	५००
मिर्जापुर	६६
	<hr/>
	योग ७,४००

बम्बई राज्य को श्रमिकों के क्वार्टर बनवाने के हेतु १,०७,४६,००० रुपये दिये गये थे, जिनसे २,३८८ क्वार्टर बनवाये गये हैं।

प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत ३५२ कल्याण-केन्द्रों की स्थापना की गई।

**द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत कल्याण कार्य—**

द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत श्रम कल्याण कार्यों के लिए २६१६ करोड़ रुपये का आयोजन किया गया है, जिनमें से १८ करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार खर्च करेगी और शेष प्रदेशीय सरकारें व्यय करेंगी। श्रमिकों के क्वार्टर के निर्माणार्थ ५० करोड़ रुपये का अलग आयोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त चाय के बगीचों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए ११,००० मकान बनवाने के हेतु २ करोड़ रुपये अलग से स्वीकार किये गये हैं। श्रुह-निर्माण पर खान श्रम कल्याण कोष (Coal Labour Welfare Fund) से ८ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

श्रमिकों के जीवन स्तर ऊँचा करने, एनता और सफाई की ओर उनकी रुचि बढ़ाने के लिए एक नई शिक्षा पद्धति की आवश्यकता है। जुम्मा खेलने, शराब, ताड़ी तथा अन्य मादक वस्तुओं की लत छुड़ाने के लिए फिल्मों द्वारा शिक्षा देना अधिक हितकारी होगा और इस हेतु सन् १९६०-६१ तक १०० फिल्म (Audio Visual Films) तैयार किये जायेंगे। कारखानों के श्रम-कल्याण विभाग और राजकीय श्रम-कल्याण केन्द्र ऐसे फिल्मों को दिखाने का प्रबन्ध करते रहते हैं।

मन् १९५६ में औद्योगिक शिक्षा के लिए १०,००० व्यक्तियों का सुविधायें प्राप्त था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में १९७०० व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए और प्रवर्धन किया जायगा। प्रशिक्षण की अवधि भी बढ़ा दी गई है। काम सीखने का एक नई योजना—Apprenticeship Scheme चलाई गई है जिसके अनुसार प्रथम वर्ष में ४५० व्यक्ति भरती किए जायेंगे। उनका भत्ता प्रति वर्ष बढ़ती जायगी और मन् १९६०-६१ तक यह सराया ५,००० हो जायगी। उद्योग की आवश्यकता अनुसार २ वर्ष से ५ वर्ष तक की ट्रेनिंग रखा गई है। यह ट्रेनिंग प्राप्त व्यक्ति यदि किसी कारखाने में काम करता तो स्वभावतः उनकी दक्षता अधिक हानि के कारण उत्पादन भी बढ़ेगा।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत १,३२० अम कल्याण केंद्र खोल जायेंगे।

**कारीगरों को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था—**

कारीगरों को ट्रेनिंग देने की दृष्टि में इस समय जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वे आवश्यकता से बहुत कम हैं। आज देश में यथामात्र अधिक से अधिक ग्राम निर्भर होने का उद्देश्य अपना सामान रख है और उत्पादन के बड़े लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। इसलिए आज कुशल कारीगर अधिक से अधिक मस्या में सुलभ होने की जरूरत बढ़ गयी है। लोग में बढ़िया चीजें हा खरीदने की मांग बढ़ जायेगी से यह जरूरत और भी अधिक हानी जा रही है। इसलिए आवश्यक योग्यता वाले कारीगर तैयार करने की जरूरत न केवल अत्यधिक है बल्कि अत्यंत उत्प्रेरक है।

कुशल कारीगरों को ट्रेनिंग देने का प्रश्न बड़ा महत्व का ही नहीं बन गया है बल्कि राष्ट्रीय महत्व की चीज बन गया है। तब तक कुशल कारीगर तैयार नहीं किए जा सकते जब तक कि उपयुक्त सामान वाली ट्रेनिंग संस्थाएं या कक्षाएँ न हों और उनमें ट्रेनिंग देने के लिए योग्यता वाले प्रशिक्षक न हों। दुर्भाग्य से पहली पंचवर्षीय योजना में एस ट्रेनिंग केंद्र आवश्यक संस्था में न बनाए जा सकें। कारीगरों को ट्रेनिंग दे सकते। कारीगरों का ट्रेनिंग देने के कार्यक्रम का आवश्यकता का अनुभव करके योजना आयोग ने दूसरी पंचवर्षीय योजना का अवधि में कारीगरों को ट्रेनिंग देने का सुविधाएं कुशल के लिए धन दिया। पुनर्वास तथा निवासन मन्त्रालय का कारीगरों का ट्रेनिंग देने की योजनाएं शुरू करने का यह काम सौंपा गया।

पुनर्वास तथा निवासन मन्त्रालय (हायरसेक्टर जनरल आफ रिस्ट्रिक्टेड एण्ड एम्प्लायमेंट ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में क्रियाविध करने के लिए निम्न योजनाएँ बनाई—

- (१) औद्योगिक ट्रेनिंग संस्थाओं में ट्रेनिंग की सुविधाओं का विस्तार और उनमें सुधार करना ।
- (२) राष्ट्रीय प्रशिक्षार्थी याजना चालू करना ।
- (३) औद्योगिक कमचारियों के लिए सायकलान कक्षाएँ चलाना ।
- (४) पढ़े लिखे बेकारों के लिए काम सिखान तथा नये काम दिखान वाले केंद्र खोलना ।
- (५) अलग अलग कामों की ट्रेनिंग देने की व्यवस्था का विस्तार करना ।

अंतिम योजना को छोड़कर और सारी याजनाएँ राज्य सरकारों के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही हैं। प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग देने का व्यवस्था केन्द्रीय सरकार नहीं करती है और इसके लिए केन्द्रीय प्रशिक्षण विद्यालयों का संचालन सरकार करती है ।

#### कारिगरो को प्रशिक्षण—

पुनर्वास तथा नियोजन महानिदेशालय ने एक कार्यक्रम बनाया है जिसके अनुसार दूसरी योजना की अवधि में २०,००० कारिगरों को ट्रेनिंग देने की और व्यवस्था हो सकेगी । इस प्रकार द्वितीय योजना के अंत तक कुल २६,४० हजार कारिगरो के प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी ( इनमें से १०,५०० को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था इस समय है और २६,००० की व्यवस्था और होगी ) । मूल कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण की सुविधाएँ अभी बढ़ायी जा सकती हैं जब वर्तमान सुविधाओं का पूरा-पूरा उपयोग हो और कुछ संस्थाओं में तो दो पालियाँ चलाकर प्रशिक्षण दिलाया जाए । दूसरी योजना से पहले ५६ प्रशिक्षण केंद्र थे और उनकी संख्या में ८० की वृद्धि करने का प्रस्ताव है ।

इंजीनियरों उद्योगों के लिए ट्रेनिंग की अवधि दो वर्ष होगी, जिसमें से ६ महीने कारखानों या वकफों में काटने होंगे । इस योजना के अंतगत २६,००० कारिगरों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और योजना का अवधि समाप्त होने तक २५,००० लोगों को ट्रेनिंग और दी जा सकेगी ।

#### उम्मेदवार प्रशिक्षण योजना—

यह राष्ट्रीय योजना कारिगरो को प्रशिक्षण देने के लिए चलायी गई है । इसके अधीन उद्योगों में ७०५० प्रशिक्षार्थियों को काम सिखान, शुरू किया जायगा । लेकिन विभिन्न कठिनाइयों के कारण इस योजना पर अमल करने में विघ्न प्रगति नहीं हो पाया है ।

राज्य सरकारों ने भारत सरकार से प्रायश्चा की है कि वह एक ऐसा कानून बनवाये जिसके अधीन सरकारी एवं गैर सरकारी कारखानों के लिए यह जरूरी कर

दिया जाए कि वे ट्रेनिंग के पाने के उम्मेदवारा को अपने यहाँ नाम सीखने दें। इस पर केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है।

**सायकालीन कक्षाएँ—**

उद्योगों में काम करने वाले कमचारियों को अपने काम का संशान्तिक ज्ञान भी हो जाए और वे अपने भविष्य की और उज्ज्वल कर सकें, इस उद्देश्य से औद्योगिक नगरों तथा कस्बों में सायकालीन कक्षाएँ चालू की गयी हैं। चुने हुए कर्मचारी अपने काम के समय के बाद इन कक्षाओं में जाते हैं। पाठ्यक्रम पुरा हो जाने पर प्रशिक्षार्थियों की परीक्षा ली जाती है और उत्तीर्ण होने पर उन्हें एक प्रशिक्षण पत्र दिया जाता है। इस कार्यक्रम के अधीन ३,०५० व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना बनायी गयी है। इस मुविषा का लाभ उठान के लिए कमचारियों में काफी उत्साह है।

**पढ़े-लिखे बेकारों के लिए योजना—**

इस योजना का उद्देश्य पढ़े-लिखे बेकार लोगों को सर्वेक्षण बाबूरी के अलावा अन्य कामों के लिए तैयार करना है। पढ़े-लिखों को काम सिखाने तथा नये कामों की ओर प्रवृत्त करने के लिए दो मन्त्रों में जो कुछ सिखाया पढ़ाया जाता है, उसमें लोगों की अपनी ही वर्कशॉप खोलन या किन्हीं उद्योगों के चालू करने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं।

इनकी ट्रेनिंग की अवधि दो साल होती है और जीवन में जम जाने के लिए इन्हें उद्योग मन्त्रालय तथा लघु उद्योग संस्थाएँ सहायता देती हैं। दूसरी योजना में इस तरह की ट्रेनिंग ३,००० लोगों को देने का प्रस्ताव है।

**प्रशिक्षकों की ट्रेनिंग—**

कारीगरों को ट्रेनिंग देने के लिए आवश्यक प्रशिक्षकों का सामान्यतः अभाव ही है। इस कमी को पूरा करने के लिये केन्द्रीय प्रशिक्षण विद्यालय खोले गये हैं। जहाँ इन प्रशिक्षकों की ट्रेनिंग दी जा सके।

प्रशिक्षकों की ट्रेनिंग देने का एक ही केन्द्र है जो कोनी विलासपुर (मध्य प्रदेश) में चल रहा है और जिसमें १४० लोगों को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था है। अब इस संस्था में प्रशिक्षण की मुविषा २५८ व्यक्तियों के लिए कर दी गयी है। अस्थायी तौर पर एक और विद्यालय औष पूना में चालू किया गया है, जिसमें १४४ व्यक्तियों को शिक्षा देने की व्यवस्था है। जैसे ही इमारतें बन कर तैयार होगी, ये विद्यालय क्रमशः कलकत्ता और बम्बई को स्थानान्तरित कर दिये जायेंगे। इन विद्यालयों में प्रशिक्षण देने की अवधि ५१ महीने है।

अनुमान किया जाता है कि पुनर्वास तथा नियोजन महानिदेशालय ने जो ट्रेनिंग योजनाएँ चलाई हैं, उनके लिए ४,००० से अधिक प्रशिक्षकों की आवश्यकता होगी।



अन्य मस्याओं तथा उद्योगों को अपने प्रशिक्षण कार्यों के लिए जितने प्रशिक्षकों की आवश्यकता होगी, उनकी सख्या इनके अलावा होगी । इसलिए प्रशिक्षण की सुविधाएँ बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी । तीसरी पंच-वर्षीय योजना में प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए और अधिक केन्द्रीय ट्रेनिंग विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है ।

### STANDARD QUESTIONS

1. Define the scope of 'labour welfare work' and discuss its importance.
2. State briefly how welfare work has developed in India. Describe briefly the welfare activities undertaken by the various agencies in India for the labouring classes.
3. How far has the United Nations, Organisation promoted labour welfare in India ?
4. Briefly summarize the welfare work done by the trade union organisations in India.

## प्रथम पंचवर्षीय योजना

( First Five Year Plan )

### प्रस्तावना—

२६ जनवरी सन् १९५० को भारतीय संविधान लागू होने के बाद ही भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य भारत के आर्थिक विकास तथा लोगों के रहन सहन के स्तर में सुधार करने के लिए पंच-वर्षीय योजनाएँ तैयार करना था। पहली योजना १ अप्रैल सन् १९५१ से ३१ मार्च सन् १९५६ तक के लिए बनाई गई थी।

### उद्देश्य तथा विशेषताएँ—

योजना आयोग के शब्दों में—'योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों के रहन सहन के स्तर को ऊँचा करना तथा उन्हें एक मुन्नी और अधिक व्यापक जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करना था।' इस योजना में देश के सब प्रकार के साधनों—भौतिक तथा मानवीय—को काम में लाने के ऊपर दृष्टि रखी गई है, जिससे कि देश में वस्तुओं तथा सेवाओं की अधिक उत्पात्ति हो सके और धन वितरण की असमानता भी दूर हो सके। योजना का प्रमुख उद्देश्य एक सर्व मङ्गलकारी राज्य की स्थापना करना है।

### मिश्रित अर्थ-व्यवस्था—

इस योजना में मिश्रित अर्थ व्यवस्था की कल्पना की गई है, जिसमें सरकार का एक महत्वपूर्ण एवं क्रियाशील भाग है। राज्य का काम पूँजी का निर्माण करना, उत्पादन की वृद्धि को चालू करने की सुविधा देना तथा समाज में उत्पादन शक्ति तथा वर्ग सम्बन्धों को एक मूल में बाँटना है। जनता को भी काम करने का अवसर मिलना आवश्यक है, परन्तु उसको पूर्ण रूप से स्वतन्त्र नहीं छोड़ा जा सकता। उदाहरणार्थ, यद्यपि कृषि व्यक्ति स्वयं करते हैं, परन्तु सरकार का कर्तव्य है कि वह सिंचाई, शक्ति, यातायात आदि का प्रबन्ध करे। इसी प्रकार उद्योगों को यद्यपि निजी पूँजी द्वारा चलाया जा सकता है, फिर भी अनेक क्षेत्रों में सरकार की सहायता करनी पड़ेगी।

निम्न तालिका में प्रथम पंच-वर्षीय योजना का संक्षिप्त विवरण दिया गया है :—

व्यय का मद	करोड़ रुपये में निर्धारित व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत
कृषि एवं सामूहिक विकास	३६१	१७.५
मिचार्ड	१६८	८.१
बहु उद्देशीय सिंचाई एवं शक्ति योजनाएँ	२६६	१२.६
शक्ति	१०७	६.१
यातायात व सन्देशवाहन	४६७	२४.०
उद्योग	१७३	८.४
सामाजिक सेवाएँ	३४०	१६.४
पुनर्वास	८५	४.१
अन्य	५२	२.५
योग	२,०६६	१००.०

देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुए योजना प्रस्तुत करने के बाद उसमें कुछ संशोधन करना आवश्यक हो गया, यतः योजना में इषर-उषर कुछ वृद्धि कर दी गई और अन्त में २,३७८ करोड़ रुपये की हो गई। निजी क्षेत्र में भी १,४०० करोड़ से बढ़ा कर १,७०० करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई।

#### योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य—

प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत अनेक बहुमुखी नदी घाटी योजनाओं सम्मिलित की गई, जिनसे १६६ लाख एकड़ प्रतिरिक्त भूमि की मिचार्ड तथा १४६ लाख किलोवाट प्रतिरिक्त बिजली उत्पन्न होने का अनुमान था। देश में खाद्य उत्पादन में भी इस योजना के फलस्वरूप ७६ लाख टन की वृद्धि की कल्पना की गई। इसी प्रकार कपास, पटसन, गन्ना तथा इस प्रकार की अन्य वस्तुओं के उत्पादन में भी काफी वृद्धि का अनुमान लगाया गया। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के अलावा सहकारी ग्राम प्रबन्ध, सामुदायिक ग्राम योजनाएँ तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों के माध्यम से ग्रामीण जीवन के सर्वमुखी विकास पर जोर दिया गया। योजना में उद्योग धंधों के विकास पर १७३ करोड़ रुपया व्यय करने की व्यवस्था थी, जिसमें विशेष बल लोहा तथा स्पात उद्योग तथा भारी रासायनिक पदार्थों के विकास पर दिया गया। कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास को भी पर्याप्त स्थान मिला। अन्य उद्योगों की उत्पादन क्षमता को देखते हुए उत्पादन में वृद्धि के लक्ष्य निर्धारित किये गये। निजी क्षेत्र द्वारा उद्योगों के विकास पर २२३ करोड़ रुपये का व्यय का अनुमान था। राष्ट्रीय सड़कों के

विकास के लिए २६ करोड़ रुपये तथा राज्यों के ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए ७३.५४ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। जहाजी कंपनियों के विकास के लिये सहायतार्थ १५ करोड़ रुपया, कान्डला के नये बन्दरगाह के लिए १२.५ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। समाज सेवाओं के लिए जो धन व्यय होना था उसमें से शिक्षा पर १५.१ करोड़ रुपया, स्वास्थ्य पर ६६ करोड़ रुपया, मकानों के निर्माणों पर ४६ करोड़ रुपया, धर्म हितकारी कामों के लिए ७ करोड़ रुपया तथा पिछड़ी हुई जातियों के लिए २६ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। यह भी कल्पना की गई कि सन् १९५८ तक भारत की राष्ट्रीय आय १० हजार करोड़ रुपए हो जायगी। रोजगार के सम्बन्ध में यह अनुमान लगाया गया कि योजना काल में लगभग ५५ लाख व्यक्तियों को पूर्ण रोजगार तथा ३३ लाख व्यक्तियों को अर्द्ध रोजगार प्राप्त हो सकेगा।

**योजना की वित्त-व्यवस्था—**

योजना पर व्यय होने वाले २,०६६ करोड़ रुपयों में से विभिन्न साधनों द्वारा जो धन प्राप्त होने की सम्भावना थी, उसका अनुमान निम्न तालिका से लगाया जा सकता है :—

( करोड़ रुपए )

केन्द्रीय सरकार द्वारा बचत	१६०
रेलों की बचत	१७०
राज्य सरकारों द्वारा बचत	४०८
सार्वजनिक ऋण	११५
छोटी बचतें	१७०
डिपॉजिट एव प्रॉबोडेन्ट फण्ड	२३५
विदेशी सहायता	५२१
धाटे का राजस्वन	२६०
<b>योग</b>	<b>२,०६६</b>

**प्रथम पंच-वर्षीय योजना की सफलताएँ—**

प्रथम पंच वर्षीय योजना ने प्रारम्भ के वर्षों में बहुत थोड़ी प्रगति की। वैसे तो सशोधित अनुमान के अनुसार योजना काल में विकास कामों पर कुल २,३५६ करोड़ रुपए व्यय होना था, किन्तु वास्तव में केवल १,६६० करोड़ रुपया व्यय किया जा सका, अर्थात् प्रथम पंच वर्षीय योजना पर अनुमान से १७% कम व्यय किया जा सका।

आयोजना पर खर्च हुए १,६६० करोड़ रु० निम्न साधनों से प्राप्त हुए । ये आंकड़े पाँचवें वर्ष में हुए वास्तविक खर्च के अनुमानों पर आधारित किये गये हैं:—

	६० करोड़ों में	कुल प्रतिशत
कर और रेलों की वचत	७५२	३८
कृषि	२०५	१४
छोटी वचत और अन्य कोषों में		
जमा हुआ धन	३०४	१९
अन्य पूँजीगत साधनों से प्राप्ति	६१	५
विदेशी सहायता	१८८	१०
घाटे की व्यवस्था से	४२०	२१
योग	१,६६०	१००

२२ जून सन् १९५७ को योजना आयोग के उपसभापति ने जो विज्ञप्ति प्रकाशित करने के लिए तैयार की, उसमें प्रथम पंच वर्षीय योजना की प्रगति तथा सफलताओं की विवेचना की गई है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात की ओर सकल किया गया है, वह यह है कि यद्यपि सावजनिक क्षेत्र में अनुमान से लगभग ४०६ करोड़ रुपया कम खर्च हुआ, परन्तु निर्जी क्षेत्र ने इस दिशा में पूरी सफलता प्राप्त की, अर्थात् औद्योगिक विकास के लिए २३३ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान था, जबकि वास्तव में २३१ करोड़ रुपया व्यय किया गया। प्रथम पंच वर्षीय योजना का व्यापक प्रभाव इस बात से प्रकट होता है कि योजना काल में वास्तविक राष्ट्रीय आय में लगभग १८% की वृद्धि हुई है। इस अवधि में प्रति व्यक्ति आय में ११% की वृद्धि और उपभोग व्यय में ६% की वृद्धि हुई है।

सबसे महत्वपूर्ण प्रगति कृषि उत्पादन के क्षेत्र में हुई। खाद्यान्न का उत्पादन २०%, कपास का उत्पादन ४५% तथा मुख्य तिलहनो का उत्पादन ८% बढ़ गया। सिंचाई की छोटी और बड़ी योजनाओं के परिणामस्वरूप सिंचित भूमि में १,०६० एकड़ भूमि की वृद्धि हो गई है। विजयी का उत्पादन सन् १९५० में ७७ करोड़ ५० लाख किलोवाट घण्टे था। सन् १९५५ में बढ़कर ११ अरब किलोवाट हो गया।

औद्योगिक उत्पादन का सूचक सूचक सन् १९५० में १०५ था, जो सन् १९५५ में बढ़कर १६१ हो गया। नावजनिक क्षेत्र में योजना काल के अन्तर्गत जो नए-नए कारखाने खोले गये उनमें से मुख्य ये हैं:—(१) रासायनिक खाद का कारखाना, सिन्दरी, (२) रेल का इञ्जन बनाने का कारखाना, चित्तूरजन; (३) हिन्दुस्तान केबिल्स, दुर्गापुर, (४) हिन्दुस्तान सिपेयाई, विशाखापट्टम, (५) इटैन्ट्रॉन कोच फॅक्टरी, मद्रास;

(६) हिन्दुस्तान मशीन टूल, मैसूर, (७) नेशनल इन्स्ट्रुमेंटल फैक्टरी, कलकत्ता, (८) टेलीफोन फैक्टरी, बंगलोर । पहली योजना की प्रगति में अर्थ व्यवस्था में कुल विनियोग ३,१०० करोड़ रुपया आँका गया है । विनियोग की दर सन् १९५०-५१ में लगभग ५% थी, जो सन् १९५५-५६ में बढ़कर ७ ३% हो गई । विनियोग में हुई इस वृद्धि के साथ देश में मुद्रा स्फीति में वृद्धि हुई । इस योजना के आरम्भ के काल की तुलना में सामान्य मूल्य स्तर में योजना समाप्त होने तक लगभग १३% की कमी हो गई । विदेशी भुगतान का सन्तुलन अनुकूल ही रहा है । वरन् उसमें कुछ थोड़ी सी वृद्धि हुई ।

**उपसंहार—**

भारत के आर्थिक पुनर्स्थान के हेतु यह एक यथार्थ योजना है, जिसमें देश की प्रायः सभी समस्याओं पर विचार किया गया है । इस योजना में कृषि, सिंचाई, शक्ति, यातायात आदि को प्राथमिकता देकर देश की वास्तविक समस्या को हल करने का प्रयत्न किया गया है । देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए १७५ करोड़ की व्यवस्था की गई है और कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन पर विशेष बल दिया गया है । इस योजना को प्रजातन्त्रात्मक ढंग में चलाना इस बात का द्योतक है कि सरकार देश के सभी लोगों को इस योजना में हाथ बँटाने देखना चाहती है । इतना हुंते हुए भी हमकी कुछ कठिनाईएँ हैं ।

श्री गोरवाला ने लिखा है—“योजना कमीशन केवल ऐसी योजनाएँ बनाता है, जिनका सम्बन्ध केवल राजकीय क्षेत्र के व्यय से है, परन्तु ऊँचा नाम देने के लिए वह इसे प्रथम पंच वर्षीय योजना बनाता है ।” कुछ आलोचकों के अनुसार इस योजना के निर्माताओं ने अपने उद्देश्यों का बड़ा चड़ा कर दिखाया है । हमारे, योजना का आर्थिक आधार मुट्ठ नही है, क्योंकि इसमें आय की प्राप्ति के जो साधन प्रस्तावित किये हैं, वे अवास्तविक हैं । करो द्वारा जो आय की आशा की गई है, वह जनता की कर-देय क्षमता से कहीं अधिक है । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि मण्डल ने बताया है कि योजना में उल्लिखित विनियोग का लक्ष्य मुद्रा स्फीति के खतरे में प्राप्त किया जा सकेगा, यदि पर्याप्त मात्रा में विदेशी सहायता उपलब्ध न हो सकेगी । तीसरे, योजना में विदेशी सहमता पर बहुत आशा बाँधी गई है । चोये, योजना में कृषि को अधिक महत्व दिया गया है तथा औद्योगिक विकास को विशेष महत्त्व नहीं दिया गया, अतः योजना की पूर्ति के बाद भी हमारा देश एक कृषि प्रधान देश ही रहेगा । पाँचवे, योजना की अधिकतम राशि का व्यय आर्मीय क्षेत्र में होने का कारण राष्ट्रीय आय गाँवों में रहेगी, जिसको पुनः प्राप्त करने के लिए अथवा उनकी प्रतिरिक्त जय शक्ति को साधन के लिए कोई आयोजन नहीं है । छठे, जन सख्या की वृद्धि को रोकने के लिए, ‘कौटुम्बिक नियोजन की आवश्यकता’ के अनिवार्य याज्ञना में अथवा भी प्रभाव

शाली उपाय नहीं बताया गया है। सातवें, हमारी योजना में दीर्घकालीन योजनाओं को महत्त्व दिया गया है। रूम ने भी ऐसा ही किया था, किन्तु भारत की आर्थिक स्थिति में दीर्घकालीन योजनाओं के साथ साथ अल्पकालीन योजनाओं को भी समान महत्त्व देना आवश्यक था, जिससे कि देश को शीघ्र लाभ पहुँचे। आठवें, आर्थिक विकास की किसी भी योजना की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उसके संचालन के लिए विश्वसनीय शासन और समन्वय प्रणाली हो, किन्तु भारत का अब तक का अनुभव अधिक आशाजनक नहीं है। नदी घाटी योजनाओं का कार्य संचालन बड़ा असन्तोषजनक रहा। साथ ही, वर्तमान शासन केवल आय के साधनों का उपयोग करने में ही असफल नहीं रहा, बल्कि वह विवेकपूर्ण व्यय करने में भी असफल रहा है, अतः आवश्यकता इस बात की है कि लोक सेवा आयोग की भाँति एक यूनिटरी आर्थिक सेवा आयोग की स्थापना की जाय, जो योजना की शासन प्रणाली के लिए आवश्यक प्रशासकों की नियुक्ति करे। नवें, योजना में वितरण की असमानता को दूर करने के लिए भी कोई सन्निय मुझाव नहीं दिये गये हैं। इन आलोचनाओं के होने हुए भी हमारे देश में पञ्च-वर्षीय योजना का अभूतपूर्व स्वागत किया गया है, क्योंकि यह देश के सन्तुलित आर्थिक विकास का सच्चा प्रयत्न है। सारांश में, इसमें वास्तविकता की गन्ध है तथा योजनाओं की उपलब्ध स्रोतों से सम्बन्धित किया गया है।

### STANDARD QUESTION

1. Discuss the essential features of the First Five Year Plan. How far it has been successful in achieving its objectives ?

---

## द्वितीय पंचवर्षीय योजना

(Second Five Year Plan)

प्रस्तावना—

हमारे राष्ट्र के आर्थिक पुनर्गठन की प्रथम पंचवर्षीय योजना ३१ मार्च १९५६ को समाप्त हुई। इस योजना के फलस्वरूप अमस्त देश में आंगा का वायुमण्डन फैल गया और इसी में प्रेरित होकर हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का श्रीगणेश किया। राष्ट्रीय विकास परिषद् में भाषण करने हुए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था— हमने अपनी यात्रा का पहला खरण पूरा कर लिया है किन्तु हम तुरन्त ही अपनी दूसरी यात्रा के लिए प्रस्थान कर देना चाहिये।

द्वितीय पंच वर्षीय योजना के उद्देश्य—

द्वितीय पंच वर्षीय योजना निम्न उद्देश्यों को सामने रख कर बनाई गई है—

(१) राष्ट्रीय आय में वृद्धि—५ वर्ष की अवधि में राष्ट्रीय आय में २५% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है जिससे कि प्रति व्यक्ति आय तथा प्रति व्यक्ति उपभोग में वृद्धि हो व हमारे रहन सहन का स्तर ऊँचा हो।

(२) आधारभूत उद्योगों का विकास—द्वितीय योजना में आधारभूत उद्योग जल—सौह एवं स्वस्थ उद्योग भगान बनाने के उद्योग आदि पर विशेष महत्त्व दिया गया है क्योंकि देश के भावी औद्योगीकरण के लिए उनकी उत्पत्ति आवश्यक है।

(३) रोजगारों को दूर करना—द्वितीय पंच वर्षीय योजना में लगभग १ करोड़ व्यक्तियों को रोजगार दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(४) समाजवादी अर्थ-व्यवस्था—आर्थिक दृष्टि में समाजवादी व्यवस्था का हमने अपना ध्येय मान लिया है यद्यपि अब हम लाभ का दृष्टि में नहीं बरन् सामाजिक हित की दृष्टि में आगे बढ़ना है। आर्थिक विकास का अधिकाधिक लाभ उन लोगों को मिलना चाहिए जो अभी तक इसमें वंचित रह रहे हैं। इस प्रकार धन तथा आर्थिक शक्ति भी केंद्रित लोगों के पास इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अब हमें व्यवस्था की



आवश्यकता है जिसमें अभी तक का उपेक्षित व्यक्ति संगठित प्रयत्न से अपने को और अपने देश को धन धान्य में सम्पन्न बना सके ।

### योजना की सक्षिप्त रूपरेखा—

इस योजना में कुल ७,२०० करोड़ रुपया खर्च होगा, जिसमें से ४,८०० करोड़ ८० सरकार तथा २,४०० करोड़ रुपया निजी उद्योगपति खर्च करेंगे । इस प्रकार जहाँ प्रथम योजना में सरकार व उद्योगपतियों का भाग ५०:५०% था, वहाँ दूसरी योजना में वह क्रमशः ६१ व ३९% है । सरकारी क्षेत्र के कुल ४,८०० करोड़ रुपए में से केन्द्रीय सरकार २,५५६ करोड़ रुपया और राज्य सरकार २,२४१ करोड़ रुपया खर्च करेंगी । जिन मदों पर रुपया व्यय किया जावेगा, उनका व्यौरा इस प्रकार है—

	कुल व्यय (करोड़ रु०)	%
(१) कृषि तथा सामुदायिक विकास	५६८	११.८
(२) सिंचाई और बिजली	६१३	१६.०
(३) उद्योग और खनिज	८६०	१८.५
(४) यातायात और सन्देशवाहन	१,३८५	२८.६
(५) समाज सेवार्थ	६८५	१६.७
(६) विविध	६६	२.१
योग	४,८००	१००.०

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि द्वितीय पंच-वर्षीय योजनावर्ध में उद्योगों, खनिज, यातायात तथा सन्देशवाहन के साधनों के विकास पर पर्याप्त जोर दिया गया है । योजना के कुल व्यय का लगभग आधा इनके विकास पर व्यय किया जाएगा, जबकि प्रथम योजना में कुल व्यय का केवल ३ भाग ही इन पर व्यय किया गया था । यदि बिजली को भी औद्योगिक विकास का अङ्ग मान लिया जाए, तो यह व्यय कुल व्यय का लगभग ५६% हो जाता है ।

सार्वजनिक क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र के विकास कार्यों पर आ व्यय होगा, उसका व्यौरा इस प्रकार है—

(१) संगठित उद्योग और खानें	५७५ करोड़ रुपए
(२) बागान, बिजली उद्योग और रेलों को छोड़कर अन्य यातायात के साधन	१०५ " "
(३) निर्माण उद्योग	१,००० " "
(४) कृषि तथा मत्त और छोटे पैमाने के उद्योग	३०० " "
(५) स्टांक	४०० " "
कुल योग	२,४०० " "

इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में मिलाकर दूसरी पंच-वर्षीय योजना पर केवल ७,२०० करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है।

योजना का वित्तीय प्रबन्ध—

द्वितीय पंच वर्षीय योजना के सार्वजनिक व्यय को पूरा करने के लिये निम्न साधनों से धन प्राप्त किया जाएगा।

क्रम संख्या	विवरण	करोड़ रुपये	
१	घरेलू साधन		
	१—बालू राजस्व से बचत		६००
	(क) कर की वर्तमान दरों के अनुसार	३५०	
	(ख) मासिक करो में	४५०	
	२—जनता से ऋण के रूप में		१,२००
	(क) बाजार से ऋण	७००	
	(ख) छोटी बचत	५००	
	३—बजट के अन्य साधनों से		४००
	(क) विकास कार्य में रेलों का भाग	१५०	
२	(ख) भविष्य निधि तथा जमा खाते विदेशों से	२५०	६००
३	घाटे का बजट बनाकर		१,२००
४	कमी जो स्वदेश में नए साधनों द्वारा पूरी करनी होगी		४००
	कुल योग		४,८००

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि इस पर जो व्यय होगा उसका संपूर्ण

आधा भाग घरेलू साधनों से पूरा किया जायेगा। धेप का ५% भाग घाटे का बजट बनाकर तथा ३३% विदेशी सहायता से पूरा किया जायगा।

**द्वितीय योजना के निर्धारित लक्ष्य—**

द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि उत्पादन में १८% वृद्धि का लक्ष्य है, अनाज की पैदावार १५ प्रतिशत अथवा एक करोड़ टन बढ़नी है, कपास की ३४ प्रतिशत, दालों की २६ प्रतिशत और तिलहन की २१ प्रतिशत। इस समय ८ करोड़ आधी राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यक्रम में आते हैं। दूसरी योजना में ३२ करोड़ ५० लाख आ जायेंगे। पहली योजना में १ करोड़ ७० एकड़-भूमि में सिंचाई हुई थी, दूसरी में २ करोड़ १० लाख एकड़ अधिक जमीन में सिंचाई की व्यवस्था हो जायगी। पहली योजना में शुरू में २३ लाख किलो-वाट बिजली पैदा होती थी। सन् १९६०-६१ तक ३४ लाख किलोवाट बिजली और पैदा होने लगेगी तथा कुल मिलाकर ६८ लाख किलोवाट हो जायगी। रेलों द्वारा यात्रियों के यातायात में तथा माल की ढुलाई में ३४% वृद्धि होने का अनुमान है, यद्यपि आवश्यकता यह होगी कि इससे भी अधिक वृद्धि की जाय। सन् १९५८-५९ में १३ लाख टन होने लगेगा। इसी प्रकार कोयले का उत्पादन ३७० लाख टन से बढ़ कर ६०० लाख टन व सीमेंट का ४८ लाख टन में बढ़ कर १०० लाख टन हो जायगा। इस प्रकार उत्पादन सामग्री की तैयारी कुल १५०% बढ़ने की आशा है। राष्ट्रीय आय में भी २५% वृद्धि की आशा है, अर्थात्-सन् १९५५-५६ में १०,८०० करोड़ रुपये से बढ़कर सन् १९६०-६१ में यह १,३४,०८० करोड़ रुपये हो जायगी। प्रति व्यक्ति आय २८० रुपये से १८% बढ़कर ३३० रुपये हो जायगी।

**द्वितीय योजना की प्रगति—**

द्वितीय योजना के प्रथम वर्ष में जिस प्रकार कार्य चला उसके अध्ययन से यह प्रगट होता है कि यद्यपि इस अवधि में सामान्य दशाये बहुत अनुकूल नहीं थी तथापि कुछ क्षेत्रों में बहुत प्रगति हुई।

**कृषि कार्य-क्रम—**

खाद्य उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार, सन् १९५६-५७ में २.५ मि० टन की वृद्धि होने की आशा थी, जबकि वास्तविक वृद्धि केवल १.४ मि० टन हुई और सन् १९५६-५७ में कुल खाद्य उत्पादन ६६.२ मि० टन रहा, जबकि सन् १९५५-५६ में वह ६४.८ मि० टन था। सन् १९५५-५६ की अपेक्षा चावल और गेहूँ का उत्पादन क्रमशः १.३ मि० एवं ३ मि० टन अधिक हुआ। मोटे अनाजों का उत्पादन बिल्कुल नहीं बढ़ सका है और दालों का उत्पादन तो २ मि० टन घट गया है। व्यापारिक फसलों के सम्बन्ध में स्थिति कुछ अच्छी रही। तिलहन का उत्पादन ५.८६ मि० टन रहा,

जबकि सन् १९५५ ५६ म वह ५ ६६ मि० टन था। कपास का उत्पादन ४८ लाख गाँठ हुआ, जोकि पिछले वर्ष से ८ लाख गाँठ अधिक है। गन्ने का उत्पादन ६३ मि० टन हुआ, जाकि सन् १९५५ ५६ के स्तर में ५ मि० टन अधिक है और जूट का उत्पादन भी कुछ थोड़ा सा बढ़ा है। पिछले वर्ष उत्पादन ४१ ६७ लाख गाँठ था, जबकि इस वर्ष वह ४२ २१ लाख गाँठ हुआ।

सन् १९५६ ५७ म ४७५ बीज फार्मों की स्थापना के लिये रबीकृति दी गई। सन् १९५६ के अन्त तक जापानी ढंग से धान की खेती के अन्तर्गत १४ ५ लाख एकड़ भूमि लाई गई, जबकि सन् १९५६ ५७ के लिये सक्ष्य २० लाख एकड़ का रखा गया था। सन् १९५६ म ६७५ लाख टन अमोनियम सल्फेट और एक लाख टन फॉस्फेट प्रयोग किया गया, जबकि सन् १९५५ में यह प्रयोग क्रमशः ५ लाख टन और ७८ ००० था। के द्रीय ट्रेडर संगठन द्वारा ८७,००० एकड़ बांस और जंगल भूमि पर भूमि सुधार का काम किया जायगा। द्वितीय पंच वर्षीय योजना की अवधि म केन्द्रीय गोदाम निगम देश भर में १०० गोदाम खोलेगा, जिनमें ५ ००० टन से २०,००० टन तक माल जमा किया जा सकता है। इसी प्रकार १३ राज्य निगम मिलकर २०० गोदाम खोलेंगे, जिनमें २,००० टन से लेकर १०,००० टन तक माल रखा जा सकेगा।

**सामुदायिक योजनायें एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा—**

सन् १९५६ ५७ में ४६५ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड ( जिनमें ४६,६०० गांव और ३२ ७ मि० जनसंख्या का समावेश है) पर काम प्रारम्भ किया गया। इसके अतिरिक्त २५० सामुदायिक विकास खंड राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड से बनाये गये, जिनके अन्तर्गत ३५,७५२ गांव और १८०३ मि० जनसंख्या प्रभावित होती है। सन् १९५२ और सन् १९५३ म चालू किये गये क्रमशः ५५ सामुदायिक योजनायें और ५३ सामुदायिक विकास खंड अक्टूबर सन् १९५६ में पूरे हो गये।

**सिंचाई एवं शक्ति का उत्पादन—**

मध्यम एवं बड़ी सिंचाई योजनाओं में सन् १९५६ ५७ में १५ मि० एकड़ अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई उपलब्ध हुई तथा छोटी सिंचाई योजनाओं की पूर्ति में १६ मि० एकड़ पर सिंचाई और हुई। वर्ष के दौरान में लगभग ६० बड़ी और मध्यम योजनायें पूरी की गईं। हीराकुड योजना का सन् १९५७ म उद्घाटन किया गया। २४,००० किलोवाट का प्रथम उत्पादन यह दिसम्बर सन् १९५६ म लगाया गया। मार्च सन् १९५७ तक हीराकुड नहर व्यवस्था द्वारा १,५७,००० एकड़ भूमि पर सिंचाई की सुविधा विस्तृत की गई। सन् १९५६ ५७ के अन्त तक कुल विद्युत उत्पादन क्षमता ३६६ मि० किलोवाट हो गई थी।

### औद्योगिक उत्पादन—

सन् १९५५ की अपेक्षा सन् १९५६ में उत्पादन अधिक हुआ। औद्योगिक उत्पादन के संशोधित सूची अब ने १२२१ में १३२७ तक वृद्धि दिखाई। रेडियो रिमीवरों का उत्पादन ८६% अधिक रहा। साइकिल, ओटोमाबाइल, इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफार्मर और शक्ति संचालित पम्पों के उत्पादन में ३३ से ६०% के मध्य में वृद्धि हुई। सीमेंट, चीनी और डोजल इन्जिन आदि ८ अन्य उद्योगों के उत्पादन में लगभग १० से २५% वृद्धि हुई। मोमेंट का उत्पादन सन् १९५६ ५७ में ४.९ मि० टन था, जबकि गत वर्ष वह ४.४५ मि० टन था। इसी प्रकार चीनी का उत्पादन इस वर्ष १.६५ मि० टन हुआ, जबकि गत वर्ष १.६१ मि० टन था। निर्मित स्टील का उत्पादन १.३१ मि० टन हुआ, जो ४% अधिक था और मिल के बने मूनी कपड़े का उत्पादन ५,२८१ मि० गज था, जो गत वर्ष की अपेक्षा ४% अधिक हुआ। कमाई हुई खाली और जूता के उत्पादन में ५% वृद्धि हुई। चाय में वृद्धि नहीं के बराबर थी। हैन्डलूम उत्पादन सन् १९५५ में १,४७३ मि० गज से बढ़ कर सन् १९५६ में १,५४१ मि० गज तक पहुंच गया। सन् १९५६ ५७ में ८७ मील लम्बी नई रेलवे लाइनें ट्रैकिंग के लिए खोली गई और ५२४ मील नई लाइनों का निर्माण प्रगति में है। ७०० मील दुहरे पथ का कार्य भी चल रहा है। सन् १९५६-५७ में ५५७ लाकामोटिव, १,६३१ ट्रिबो और २७,१८४ बगना के लिये आदेश दिये गए।

१५० मील लम्बे छूट हुए टुकड़ों और ८ बठ पुलों का निर्माण, ८०० मील विद्यमान टुकड़ों का सुधार और ३०० मील सुधरे टुकड़ों का दोराहा आवागमन के लिए विस्तृत करने का लक्ष्य था जो काफी सीमा तक पूरा हो गया। नागरिक हवाई यातायात का कार्यक्रम निश्चयानुसार ही चला। सन् १९५६ ५७ में, एयर इण्डिया इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ने ३ सुपर कांस्टेलेशन प्राप्त किये और ३ बोइंग जेट एयरक्राफ्ट के लिए आदेश दिया। इण्डिया एयर लाइन्स कॉर्पोरेशन ने सन् १९५६ ५७ में ५ विक्स विस्काउट्स के लिये महत्वपूर्ण मार्गों पर चलाने के हेतु आदेश दिया है। कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता पर अधिक ध्यान दिया गया।

यद्यपि कुछ लोगों के विचार से हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना अत्यधिक महत्वाकांक्षी है, परन्तु वास्तव में ऐसा कहना भूल है। देश के विशाल स्वरूप को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि हमारे निर्धारित लक्ष्य अधिक ऊँचे हैं। अभी तक हमें जो सफलता मिली है वह सन्तोषजनक है और साथ में प्रेरणादायक भी। हमें आशा ही नहीं बरन् पूर्ण विश्वास है कि इस योजना अवधि के व्यतीत होने पर हम अपनी चतुर्मुखी प्रगति का अनुभव करेंगे।

## द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत विदेशी सहायता एवं घाटे की अर्थ व्यवस्था

द्वितीय योजना के अन्तर्गत केवल सावजनिक क्षेत्र में ४,८०० करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान है। इतनी बड़ी धतराशि प्राप्त करने के लिए जिन विभिन्न साधनों की शरण ली गई है, उनमें से विदेशी सहायता एवं घाटे का राजस्वन भी है। विदेशी सहायता से ८०० करोड़ रुपया और घाटे के राजस्वन से १,८०० करोड़ रुपया प्राप्त करने की आशा की गई है, जो कि कुल व्यय का ४२% है। प्रथम पंच-वर्षीय योजना में विदेशी सहायता से १६७ करोड़ रुपया तथा घाटे के राजस्वन से १४५ करोड़ रुपया प्राप्त किया गया था, अतः यह स्पष्ट है कि द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में इन दोनों साधनों को अधिक महत्व का स्थान दिया गया है।

द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में योजना पर १,४६६ करोड़ रुपया खर्च किया गया। चालू वर्ष के खर्च का योग ६६० करोड़ रुपया हो सकता है। इस प्रकार तीन वर्षों के खर्च का योग लगभग २,४५६ करोड़ रुपया होता है। प्रथम तीन वर्षों में होने वाले २,४५६ करोड़ रुपयों में से विदेशी सहायता एवं घाटे की वित्त व्यवस्था सन् ४३८ और ६१७ करोड़ रुपया मिलने की आशा है। आयोजन के लिए उपलब्ध साधन अब तक आशा से कहीं कम रहे हैं। सन् १९५७-५८ में वजट में ४६४ करोड़ रु० का घाटा रहा था। सन् १९५८-५९ के वजट में ऋणों तथा छोटी वस्तु में काफी अधिक धन मिलने की आशा की गई है। सन् १९५७-५८ की अपेक्षा घाटे की वित्त व्यवस्था में २५० करोड़ रु० की कमी हो जायगी, परन्तु विदेशी सहायता जहां सन् १९५७-५८ में लगभग १०० करोड़ रु० की प्राप्ति हुई थी वहाँ चालू वर्ष में वह बढ़कर ३०० करोड़ रु० हो जाने की आशा है। इन आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि योजना की सफलता में विदेशी सहायता तथा घाटे की वित्त व्यवस्था का बहुत अधिक महत्व है।

### द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत विदेशी सहायता—

जिस समय द्वितीय पंच-वर्षीय योजना का निर्माण किया गया था, उसी समय राजनैतिक क्षेत्रों में इस विवाद का बोसवाला था कि भारत सरकार के लिए ८०० करोड़ रुपये की विदेशी सहायता प्राप्त करना कठिन समस्या है। योजना के प्रारम्भिक दो वर्षों में ही कुछ ऐसा स्थिति पैदा हो गई है, जिसके कारण विदेशी भुगतान के सम्बन्ध में एक सखट सा पैदा हो गया था। इस आर्थिक सखट का दूर करने के उद्देश्य से ही सितम्बर सन् १९५७ में हमारे वित्त मंत्री श्री टी० टी० कृष्णामाचारी अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड तथा पश्चिमी जर्मनी के दौरे पर गये थे और उन देशों में उन्होंने इस बात की छान बीन की कि वहाँ से भारत को किस सीमा तक आर्थिक

सहायता मिल सकती है। अमेरिका में उन्हें लेना मात्र भी सफलता न मिली। उनकी असफलता के दो मुख्य कारण रहे। प्रथम तो, भारत की आर्थिक स्थिति, जो समाजवादी अर्थ-व्यवस्था पर आधारित है और जिसके अन्तर्गत धन शक्ति उद्योग धन्धों का राष्ट्रीयकरण तथा सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार सम्मिलित है, के कारण अमेरिका के पूँजीपति तथा अधिकांश आदि भारत में अपनी पूँजी का विनियोग करने में हिचकते हैं। दूसरे, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की वैदेशिक नीति में अमेरिका सहमत नहीं है और इसके परिणामस्वरूप वह भारत को उस सीमा तक सहायता करने के लिए तैयार नहीं है, जिस सीमा तक भारत को उसकी सहायता की आवश्यकता है। भारत को केवल दीयकालीन ऋण के रूप में विदेशी सहायता की आवश्यकता है, जिसमें वह ईमानदार राष्ट्र की भाँति कुछ समय के बाद चुका देगा। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की साख आज काफी ऊँची है, किन्तु इतना होते हुए भी अमेरिका, कनाडा अथवा इंग्लैंड में हमारे टो० टो० कृष्णामाचारी को विशेष सहायता नहीं मिली। हाँ, पश्चिमी जर्मनी, जापान तथा यूगोस्लाविया आदि देशों ने भारत को आर्थिक सहायता देने का वचन दिया है। यह सहायता किस मात्रा में और किस रूप में प्रदान की जायेगी, इस सम्बन्ध में सम्बन्धित देशों के बीच वार्ता शुरू हो गई है। विदेशी भुगतान के घाटे को कम करने के लिए भारत सरकार ने कुछ वस्तुओं, जिनमें चीनी, काली मिर्च, काजू तथा कपड़ा आदि सम्मिलित हैं, के निर्यात को बढ़ाने की व्यवस्था की है। जापान से एक समझौता किया गया है, जिसके अनुसार भारत जापान को कच्चा लोहा निर्यात करेगा और बदले में जापान हमारे देश को मशीनें देगा। श्री कृष्णामाचारी के स्वदेश लौटने के बाद विभिन्न राज्य सरकारों को ये आदेश जारी किये गये हैं कि वे खनिज पदार्थों को अधिक मात्रा में निकालने के उद्देश्य से उन सभी व्यक्तियों को उदारतापूर्वक लाइसेन्स प्रदान करें, जिनके आवेदन पर राज्य सरकारों के विचाराधीन है। १ नवम्बर सन् १९५७ को भारत सरकार ने एक आदेश द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट में कुछ आवश्यक संशोधन किये हैं, जिनके अनुसार रिजर्व बैंक के पास विदेशी प्रतिभूतियाँ तथा सोने की न्यूनतम मात्रा ३०० करोड़ रुपये से घटाकर २०० करोड़ कर दी गई है। इस प्रकार यह १०० करोड़ रुपया योजना की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयोग हो सकेगा।

घाटे की वित्त व्यवस्था—

साधनों की कमी के कारण आयोजना के शुरू के वर्षों में घाट की वित्त व्यवस्था का अत्यधिक आश्रय लेना पड़ा है। अब समय इस पाँच वर्षों में अधिक से अधिक ६०० करोड़ रु० तक रखने का था, परन्तु अब यह निश्चित लगता है कि यह राशि १,२०० करोड़ रु० तक हो जायेगी, जैसा कि पहले अनुमान किया गया था। सच तो यह है कि यदि (क) साधनों में और अधिक वृद्धि करने तथा (ख) आयोजना

व खर्चों को सीमित रखने के प्रयत्न न किये गये तो घाटे की राशि और भी अधिक बढ़ सकती है।

यदि देश के पास विदेशी विनिमय का बहुत अधिक भण्डार सुरक्षित हो तो कार्यक्रम तैयार करने में कुछ ढिलाई की जा सकती है, परन्तु वर्तमान स्थिति में तो ऐसा करना सम्भव नहीं है। अप्रैल सन् १९६० और मार्च सन् १९५८ के बीच रिजर्व बैंक का विदेशी विनिमय पाबना घट कर ४७६ करोड़ रु० रह गया। इसके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में नाम अजमा ६५ करोड़ रु० की राशि का भी उपयोग कर लिया गया है। द्वितीय आयोजन आरम्भ होने से अब तक जितनी विदेशी सहायता स्वीकृत हो चुकी है उसका योग ६७६ करोड़ रु० है। आयोजन की शेष अवधि में विदेशी विनिमय की जो आवश्यकता होगी उसे पूरा करने के लिये ५०० करोड़ रु० की विदेशी सहायता और भी मिलनी चाहिए। आयोजना की अव्यवश्यक सरकारी आयोजनाओं के लिये भी २६६ करोड़ रु० की आवश्यकता है।

इस सम्बन्ध में प्रोफेसर शिनोय ने इस बात पर ज़ार दिया था कि घाटे के राजस्वन से देश में मुद्रा स्फीति का भय है। इसके परिणामस्वरूप मूल्यों में जो वृद्धि होगी उसका योजना पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सम्भव है कि सरकार ऐसी स्थिति का सामना न कर सके। श्री शिनोय की राय के विपरीत अन्य अर्थशास्त्रियों ने घाटे के राजस्वन का समर्थन किया और यह सुझाव दिया था कि आरम्भ से ही सरकार को सचेत रहना चाहिए और मुद्रा स्फीति की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। इसी दृष्टि में सन् १९५६ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में संशोधन किया गया, जिससे बैंक को अधिक नोट छापने की स्वतन्त्रता मिल गई। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक का मास नियन्त्रण के लिए अधिक व्यापक अधिकार प्रदान कर दिये गये।

द्वितीय योजना के पहले वर्ष में ही मुद्रा प्रसार व लक्ष्य नज़र आने लगे। फलतः सरकार को अपनी नीति में कुछ परिवर्तन करना पड़ा। श्री कृष्णामाचारी ने घाटे की अर्थव्यवस्था के स्थान पर अतिरिक्त कर लगाना अधिक उपयुक्त बताया। इस नीति के अनुसार सन् १९५७-५८ के बजट में कई नये करों की व्यवस्था की गई। इतना होना पर भी योजना के अन्तिम वर्षों में सरकार को अधिक मात्रा में घाटे के बजट का महारा भेना पड़ेगा, क्योंकि आन्तरिक ऋण एवं बचत से भी आगानुकूल धन प्राप्त नहीं हो सकता।

जब से आयोजना आरम्भ हुई है, करो में काफी वृद्धि हो गई है। अब तक केन्द्र ने जो कर लगाये हैं उनमें पाँच वर्षों में लगभग ७२५ करोड़ रु० की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार इन पाँच वर्षों में राज्यों को करो में १७३ करोड़ रु० की प्राप्ति होगी। इस



प्रकार आयोजना की अवधि में करा से कुल प्राप्ति ६०० करोड़ रु० के लगभग होगी। करा में होने वाली इस प्राप्ति का बहुत बड़ा भाग आय मदा पर खच हागा जिनमें प्रति रक्षा का खच प्रमुख है। करा में इतनी अधिक प्राप्ति करने का प्रयत्न किये जान पर भी केन्द्रीय योजनाओं के खच के लिये केवल ४५ करोड़ रु० ही अधिक प्राप्त हो सकेंगे। इसका यह अर्थ हुआ कि बहुत कम राशि उपलब्ध हो सकेगा। राज्या में अनिश्चित करा से आयोजना अवधि में १७३ करोड़ रु० प्राप्त होंगे। वित्त आयोग के निश्चयानुसार राज्यों को १६० करोड़ रु० के अनिश्चित केन्द्रीय करा में भी काफी अधिक हिस्सा मिलना था। इन पर भी आयोजना पर खच करने के लिये राज्या के पास आगा में कहीं कम धन उपलब्ध हुआ है। यदि यह मान लें कि राज्य करों से २२५ करोड़ रु० प्राप्त कर सकते तो वे अपने राजस्व में से आयोजना पर सम्भवतः ३५० करोड़ रु० खच कर सकेंगे जबकि आगा ३७० करोड़ रु० खच करने की थी। पहले तीन वर्षों में केन्द्र तथा राज्यों के वज्रों में आयोजना के लिए जो धन रखा जायगा उसका योग ११०० करोड़ रु० होगा जबकि पांच वर्षों का अनुमान २४०० करोड़ रु० था इस प्रकार ४०० करोड़ रु० की कमी रह जाते हैं।

उपसंहार —

अतः यह स्पष्ट है कि ४००० करोड़ रुपए की इस योजना की सफलता के लिए धात्र की अथ व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए यदि पर्याप्त मात्रा में विदेशी सहायता न मिली तो योजना में कमी की जायगी और ऐसा अनुमान है कि निकट भविष्य में हमारे पास विदेशी मुद्रा कोष कुछ भी नहीं रह जायगा। द्वितीय पांच वर्षीय योजना की रिपोर्ट में बताया गया है कि अप्रैल सन् १९५६ में सितम्बर सन् १९५७ की अवधि में ५६१ करोड़ रुपए हम गोयनागेष में अधिक देन पड़ें। अक्टूबर सन् १९५७ में मार्च सन् १९५८ तक यह कमी २३० करोड़ रुपए की हुई। यदि विश्व मुद्रा कोष के ६५ करोड़ रुपए को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाय तो पिछले दो वर्षों में लगभग ६ अरब रुपए का हानि विदेशी मुद्रा में हुआ है। सन् १९५८ में ५६ के आधिक वर्ष के पहले दो महीना में भी हमारे विदेशी मुद्रा कोष में हानि हुई है। इन दो महीना अप्रैल और मई में हम अपने विदेशी मुद्रा कोष में ४२ करोड़ रुपया निकाल चुके हैं। ३० मई सन् १९५८ को हमारा विदेशी मुद्रा कोष २४२ करोड़ रुपया रह गया था।

## STANDARD QUESTIONS

- 1 Summarise carefully the principal objectives of the Second

**Five Year Plan** In what respects is the second plan different from the First Five Year Plan ?

- 2 Bring out clearly the essential features of the Second Five Year Plan
- 3 The Second Five Year Plan is ambitious Comment
- 4 Write an essay on deficit financing and the problem of foreign exchange with special reference to the Second Five Year Plan
- 5 Describe briefly the principal achievement of Second Five Year Plan

## तृतीय पंच-वर्षीय योजना

(Third Five Year Plan)

### प्रारम्भिक—

गत दस वर्षों में पहली और दूसरी पंच-वर्षीय योजनाओं के द्वारा देश के प्राकृतिक प्रमाणों और जनता की शक्ति को राष्ट्र के विकास में लगाने की कोशिश की गई है। प्रारम्भ में इस बात का प्रयत्न किया गया कि योजना का उद्देश्य केवल उत्पादन को बढ़ाना और देश की आर्थिक दशा सुधारना ही नहीं है, बल्कि स्वतन्त्रता और साक्षरता पर आधारित ऐसी सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था की रचना करना है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ग्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी समस्याओं को अनुपानित कर। देश की दूसरी महापुरुष और वंशवां ने जो हानि पहुँची थी, पहली योजना में उसे पूरा करने की और आर्थिक व्यवस्था की नींव मजबूत करने की कोशिश की गई और नवविज्ञान में दिए हुए निर्देशक तत्वों के अनुस्यू सामाजिक और और आर्थिक नीतियाँ भी ग्रहण की गयीं। सामुदायिक विकास योजना का प्रारम्भ और भूमि सुधार इस योजना की उल्लेखनीय बातें हैं। दूसरी योजना में पहली योजना की ही नीतियों का जारी रखने हुए पँदावार बढ़ाने, विकास में अधिक श्रम्य लगाने और लोगों को अधिक काम देने की कोशिश की गई। हमें आर्थिक उन्नति की गति को तेज करने पर, बुनियादी उद्योगों की स्थापना पर, रोडपार के साधनों को बढ़ाने पर, आय और धन की विषमताओं को कम करने पर और आर्थिक शक्ति को छोटे से लोगों के हाथ में जाने में राकने पर, जोर दिया गया। पहली योजना में राष्ट्रीय आय में प्रति वर्ष ३।१ प्रतिशत और दूसरी योजना में प्रति वर्ष ४ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

### तृतीय पंच-वर्षीय योजना की विशेषतायें

मानना प्रायाय वास्तव में वसाई का पात्र है जिसने १९२१० करोड ५० की तृतीय पंच-वर्षीय योजना की आरेखा तैयार करके भारत की जनता की मृदुति के द्वार खोल दिए हैं। हमारी तीसरी पंच-वर्षीय योजना, देश की पंच-वर्षीय यात्रनाओं की कड़ी में मध्य की यात्रना है। यह यात्रना बहुत बृद्धाकार यात्रना है। इस

योजना का लक्ष्य प्रथम और द्वितीय योजनाओं के सम्मिलित लक्ष्यों से भी बहुत ऊँचा है। पहली दो योजनाओं क्रमशः ५३ और २८ अरब रुपये की थी। तृतीय योजना १०२ अरब रुपये की है। इसका कम्युनिस्ट अप्रैल सन् १९६१ से ३१ मार्च १९६६ तक रखा गया है। इसका मुख्य लक्ष्य है, सन् १९६१ तक अन्न के मामले में देश को स्वावलम्बी बनाना। इस योजना के पूर्ण होने पर हम विदेशों से अनाज का आयात नहीं करना पड़ेगा। निम्न गतिविधियाँ तृतीय पंच वर्षीय योजना के प्रमुख पाँच लक्ष्यों का बतलाती हैं —

### तृतीय योजना के लक्ष्य

(१) राष्ट्रीय आय पाँच प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब में पाँच वर्षों में २५ प्रतिशत बढ़ा दी जाये।

(२) खाद्यान्न के सम्बन्ध में स्वावलम्बी बना जाय।

(३) कौलाद, इधन और बिजली जैसे आधारभूत उद्योगों का बढ़ाया जाय जिससे देश का औद्योगीकरण आन्तरिक स्रोतों से ही किया जा सके।

(४) रोजगारी की सम्भावनाएँ बढ़ा कर जनता के हाथों का पूरा पूरा उपयोग किया जाय।

(५) आय और संपत्ति का फर्क कम किया जाय और आर्थिक शक्ति का समुचित वितरण हो।

प्रस्तुत योजना, जो योजना आयोग द्वारा २६५ पृष्ठ की पुस्तक में विस्तार-पूर्वक समझाई गयी है, पिछली योजनाओं की अपेक्षा काफी विस्तृत है। भारत-चीन के तनावपूर्ण सम्बन्धों के कारण रक्षा व्यय अधिक बढ़ गया है जिससे अब प्लान पर कुल विनियोग १०,२०० करोड़ रु० व चानू खर्चा १,०५० करोड़ रुपये—कुल मिलाकर ११,२५० करोड़ रुपये का विनियोग भी सम्मिलित है। निम्नलिखित तालिकाएँ द्वितीय व तृतीय पंच वर्षीय योजनाओं में सरकारी व निजी क्षेत्र में किए जाने वाले व्यय के विभाजन पर प्रकाश डालती हैं —

## तालिका I

दूसरी और तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र में व्यय का विभाजन  
(करोड़ रु० में)

	व्यय		प्रतिशत	
	दूसरी योजना	तीसरी योजना	दूसरी योजना	तीसरी योजना
१ कृषि और छोटी सिंचाई-योजनाएँ	३२०	६२५	६६	८६
२. सामुदायिक विकास और सहकार	२१०	४००	४६	५५
३ बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाएँ	४५०	६५०	६८	६०
४. जोड़ १, २ ३	९८०	१६७५	२१३	३२१
५. बिजली	४१०	६२५	८६	१२८
६ ग्राम और लघु उद्योग	१८०	२५०	३६	३४
७. उद्योग और खनिज	८८०	१५००	१६१	२०७
८ परिवहन और संचार	१२६०	१४५०	२८१	२००
९. जोड़ ५ से ८	२७६०	४१२५	६००	५६८
१० सामाजिक सेवाएँ	८६०	१२५०	१८७	१७२
११ उत्पादन में रुकावट न आना	—	२००	—	२८
१२ कुल जोड़	४६००	७२५०	१००	१००

## तालिका II

दूसरी और तीसरी योजना में निजी क्षेत्र में व्यय का विभाजन

	करोड़ रु० में	
	दूसरी योजना	तीसरी योजना
१. कृषि (सिंचाई सहित)	६५५	८५०
२ बिजली	४०	५०
३. परिवहन	१३५	२००
४. ग्राम और लघु उद्योग	२५	३२५

५ बड और मध्यम उद्योग और खनिज	७००	१०५०
६ आवास और ग्राम निर्माण कार्य	१०००	११२५
७ उत्पादन में रुकावट न आने देने के लिए कच्चा		
या मद तैयार माल	५२५	६००

जोड़ ३३०० ४२००

इसमें सरकार का क्षेत्र में दिया गए २०० करोड़ रु० भा शामिल है ।

उपयुक्त तालिका के विस्तारण से पंच वर्षीय योजना की विशेषतायें स्पष्ट हो जो निम्नलिखित हैं —

**समाजवादी कलेक्टर—**

तृतीय योजना का प्रमुख उद्देश्य धन और धाय की विपमता को कम करने का उपाय निकालना है जिसमें समाज का ठांचा समाजवाद ढग (Socialistic Pattern of Society) हो सके जिसमें सब लोगो को पूरा प्रगति करने का अवसर मिल सक । समाजवादी ढांच का अर्थ यह है कि हमारी नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे समस्त समाज का कल्याण हो कबल कुछ भग धनियो का नही ।

**कृषि को प्राथमिकता—**

योजना में कृषि को प्रथम स्थान दिया गया है । अनाज में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और उद्योग तथा निर्माण के लिए कच्चे माल की पैदावार बढ़ाना तामरी योजना का मुख्य उद्देश्य है ।

### तीसरी योजना में कृषि उत्पादन का लक्ष्य

		वार्षिक	उत्पादन
		१९६०-६१ (अनुमानित)	१९६५-६६ लक्ष्य
अनाज	(लाख टना में)	७५०	१,०००-१०५०
तेलहन	( )	७२	६२- ६५
गन्ना (गुड के रूप में)	( )	७२	६०- ६३
कपास	( , )	५४	७२
पटसन	(लाख गांठ म)	५५	६५

इसके अतिरिक्त फल शर्करा, दूध मयूरी, मांस, अण्डा, नारियल, गुपारा काजू, कालाभिच, तम्बाकू, चमड़ा और लकड़ी आदि की भी पैदावार बढ़ाने का पूरी कोशिश की जायगा ।

कृषि की अधिक से अधिक उत्पत्ति होनी चाहिए, जिससे गाँव के लोग देश के अन्य लोगों की अपेक्षा पीछे न पड़ जाएँ । योजना में कृषि और सामुदायिक विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में १,०२५ करोड़ सिंचाई की बड़ी और और मध्यम योजनाओं के लिए ६५० करोड़ रु० रखे गए हैं । इसके अलावा अनुमान है कि लोग निजी और से भी इन कामों में ८०० करोड़ रु० लगायेंगे । यदि आगे चलकर यह प्रतीत हुआ कि गाँवों में और तेजी से उत्पत्ति करने और जनशक्ति का पूरा उपयोग करने के लिए और रुपये लगाने की जरूरत है तो इसका भी बन्दोबस्त किया जाएगा । खेती की पैदावार में ३० से ३३ प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी ।

इसके अलावा फल, शाक, दूध, मछली, मांस, अण्डा, नारियल, मुपारी, काजू, वालीमिर्च, तम्बाकू, चपड़ा और लकड़ी आदि की भी पैदावार बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी ।

भनाज की पैदावार बढ़ाने का लक्ष्य इस हिसाब से रखा गया है कि प्रति व्यक्ति प्रति दिन औसत १५ ग्राम्स औसत भनाज और ३ ग्राम्स दाल खाने की मिल सके तथा सकट के समय के लिए भी कुछ भनाज बच जाए कपास की पैदावार का जो लक्ष्य है उससे प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष औसत १७११ गज के हिसाब से कपड़ा मिल सकेगा और निर्यात के लिए भी कुछ बचेगा ।

तृतीय योजना के अंत तक सिंचाई का क्षेत्रफल ६ करोड़ एकड़ हो जाएगा, जबकि दूसरी योजना के अंत में यह ७ करोड़ एकड़ होगा । करीब ४ करोड़ एकड़ में बरानी खेती की जाएगी । १ करोड़ ३० लाख एकड़ और जमीन का कटाव आदि से बचाने का काम किया जाएगा । सन् १९६०-६१ तक करीब ३ लाख ६० हजार टन नैनजनयुक्त खाद का प्रयोग होने का अनुमान है, १९६५-६६ में १० लाख टन हो जाएगा । ७१ करोड़ एकड़ जमीन में पोषी की बचाने की व्यवस्था की जाएगी । अक्टूबर १९६३ तक देश के सब गाँवों में सामुदायिक विकास का काम चल पड़ेगा । सहकारी संगठन बढ़ाया जाएगा और खेती के लिए सहकारी समितियों द्वारा अधिक ऋण दिलवाये जाएँगे । पशुओं की नस्ल सुधार के क्षेत्र में कृत्रिम गर्भाधान के ३७१ केन्द्र कायम किए जा चुकेंगे ।

कच्चा पटमन ६५ लाख गाँठ, चाय ८५,००,००,००० पींड, कपास ७२ लाख गाँठ, कच्चा ८०,००० टन, तेल व तिलहन ६२ लाख से ६५ लाख टन, तम्बाकू ३,२५,००० टन, वालीमिर्च ३० हजार टन और लाख ६२,००० टन उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है । तीसरी योजना में १ लाख से अधिक की आबादी के शहरों के लिए ७५ दूध सप्लाय योजनाएँ चालू की जाएँगी । ३० ग्रामीण ग्रामरियाँ और

८ दुग्धजन्य पदार्थों के कारखाने स्थापित किए जाएंगे। मछली का उत्पादन दूसरी योजना में १४ लाख टन से बढ़ाकर १८ लाख टन किया जाएगा।

‘बड़े पैमाने के उद्योग—

तृतीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग, विजली और यातायात के विकास को भी ऊँचा स्थान दिया गया है। सरकारी क्षेत्र में बड़े उद्योगों और खानों के विकास में १,५०० करोड़ रु० लगाये जाएंगे। निजी उद्योगों में १ हजार करोड़ रु० (सहकारी सहायता को छोड़कर) लगाये जाने का अनुमान है।

लोहा और स्पात उद्योग की समता इतनी बढ़ाई जायगी कि बिजली के लिए एक करोड़ २ लाख टन इस्पात के ढोके और १५ लाख टन लोहा मिल सके। इन उद्योगों में प्रायः पूरा विस्तार सार्वजनिक क्षेत्र में होगा। भिलाई, हरकेला और दुर्गापुर के कारखानों को इतना बढ़ाया जायगा कि वे ५५ लाख टन इस्पात के ढोके बना सकें। दुर्गापुर में चौथा इस्पात कारखाना भी खड़ा किया जायगा।

### खास-खास उद्योगों के उत्पादन के लक्ष्य

	वार्षिक	उत्पादन
	१९६०-६१	१९६५-६६
अल्युमिनियम (हजार टनों में)	१६०	७५०
सीमेंट (लाख टनों में)	८८	१३०
कागज (हजार टनों में)	३२००	७००
गंधक तेजाब (हजार टनों में)	४०००	१२५०
कास्टिक सोडा (हजार टनों में)	१२५०	३४०
शक्कर (लाख टनों में)	२५	३०
कपड़ा (मिल का कपड़ा) (लाख टनों में)	५०,०००	५८,०००
साइकिल (कारखानों में) (हजार अंश)	१,०५०	२,०००
सिलाई की मशीन (हजार अंश)	३००	४५०
मोटरगाड़ी (अंश)	५३,५००	१,००,०००

मशीन बनाने के कारखाने—

तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारी मशीनें बनाने वाले, फाउन्ड्री फोर्ज (गढ़ाई प्रारंभ टनाई), कोयला खोदने की मशीन बनाने वाले और भारी मशीनों की मरम्मत करने वाले कारखानों का कायम करने की व्यवस्था की गई है। बंगलौर के हिन्दुस्तान मशीन हूबल कारखाने का उत्पादन दुगुना करने, ओपन क भागों बिजली के सामान



के कारखाने को बसाने, दो और भारी बिजली के सामान के कारखाने लगाने और ऊँच दबाव के वायलर और सूक्ष्म यन्त्रों के कारखानों को भी लगाने की योजना है। मशीन बनाने के निजी कारखानों में भी काफी काम होने की आशा है। आशा है कि कागज, सीमेंट, चीनी और कपड़ा प्रायः सब मशीन देश में तैयार होने लगेंगे।

**तेल के कारखाने—**

अभी तक जो पता लगा है उस हिसाब से नहरफटिया में प्रति वर्ष २७ लाख ५० हजार टन अशोधित तेल जर्मन से निकाला जाएगा। इस तेल को साफ करने के लिए नूनमाटी और बरीनी में सफाई के कारखाने बनाए जाएंगे। खभात में पा और जगह जहाँ पर तेल मिलने की आशा होगी, तेल की खोज की जायगी।

**बिद्युत शक्ति का उत्पादन—**

दूसरी योजना में बिजली का उत्पादन क्षमता ५८ लाख कि० वा० है। तीसरी योजना के अन्त तक यह बढ़ा कर १ करोड़ १८ लाख कि० वा० कर दी जाएगी। अणु-शक्ति से भी ३ लाख कि० वा० बिजली बनाई जायगी। आशा है कि तीसरी योजना में १५ हजार गाँवों और छोटे कस्बों में बिजली लगाई जाएगी, जिससे इनकी कुल संख्या ३४ हजार हो जाएगी। दूसरी योजना के अन्त तक १६ हजार शहरी तथा गाँव में बिजली पहुँच जाएगी। तीसरी योजना में यह संख्या ३४ हजार कर देने का लक्ष्य है। ५ हजार से २० हजार की आबादी के सब कस्बों में बिजली आ जायगी।

**रेल, जहाज और मोटर यातायात—**

आशा है कि सन् १९६५-६६ में रेलगाड़ियाँ २३ करोड़ ५० लाख टन माल ढोएँगी। यह लक्ष्य दूसरी योजना से ४५% अधिक है।

१२०० मील लम्बी नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। १९६०-६१ में पक्की सड़कों की सम्बाई १ लाख ४४ हजार मील होगी। १९६५-६६ में यह बढ़ कर १ लाख ६४ हजार मील हो जायगी। मोटर यातायात का विकास अधिकांश निजी क्षेत्र में होगा। अनुमान है कि किराये पर चलने वाली मोटर गाड़ियों और टनों आदि की संख्या २ लाख में बढ़कर ३ लाख हो जाएगी। दूसरी योजना के अन्त तक हमारे पास ६ लाख टन के जहाज होंगे। तीसरी योजना में २ लाख टन के जहाज और लिए जाएँगे।

मड़क परिवहन के लिए सन् १९६१ से ८१ तक की एक २० वर्षीय विकास योजना बनाई गई है, जिसमें मुख्य यह है कि कोई भी गाँव पक्की सड़क ५-४ मील से अधिक और कच्ची सड़क से १॥ मील से अधिक दूर न हो। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए तीसरी योजना में २५० करोड़ रु० की राशि निर्धारित की गई है। राष्ट्रीयकृत परिवहन के लिए ५,००० और बसें खरीदी जाएँगी।

जहाजरानी का लक्ष्य १४२ लाख टन का रखा गया है, जबकि दूसरी योजना के अन्त तक देश के पास ६ लाख टन के व्यापारिक जहाज होंगे ।

### संचार साधन—

तीसरी योजना में २०,००० अतिरिक्त डाकघर २,००० तारघर और २ लाख टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जायेंगे । तीसरी योजना में बम्बई में एक टेलीविजन सर्विस कायम की जायेगी ।

### छोटे और प्रामोद्योग—

छोटे और प्रामोद्योगों की उन्नति पर भी बहुत जोर दिया गया है । इनके लिए कारीगरों को सिखाने, कच्चा माल और श्रुत की व्यवस्था करने का भी अधिक प्रबन्ध किया जाएगा । हाथकरघा और घरेलू उद्योग के जरिये सन् १९६५-६६ में ३५० करोड़ गज कपड़ा बनाया जाएगा । जबकि सन् १९६०-६१ में इनसे २६० करोड़ गज तैयार होने का अनुमान है । दूसरी योजना में ६० उद्योग पुरियाँ बनाई गई हैं । तीसरी में ३६० बनाई जाएँगी । गाँवाँ और शहरों दोनों में छोटे उद्योग चलाने और उनको बड़े उद्योगों से जोड़ने का प्रयत्न किया जायगा, जिससे वे बड़े उद्योगों के लिए छोटे पुरजे आदि तैयार करें ।

२,८०,००,००,००० गज कपड़ा हाथकरघे व शक्ति करघे से बनाने तथा ७०,००,००,००० गज कपड़ा खादी के क्षेत्र में बनाने का लक्ष्य रखा गया है । प्रामोद्योग तथा छोटे उद्योगों से ५८ लाख आदमियों को रोजगार मिलने की उम्मीद है ।

### वन सम्पदा—

२० लाख एकड़ भूमि में जल्दी उगने वाले पेड़ लगा कर ग्राम-वन स्थापित किए जाएँगे । २॥ लाख एकड़ भूमि पर इमारती लकड़ी के वृक्ष तथा ४॥ लाख एकड़ भूमि पर अन्य वृक्ष बोए जाएँगे । १५,००० मील लम्बे वनमार्ग बनाए जाएँगे । तीसरी योजना में ६ लाख एकड़ भूमि पर भूक्षय रोकने का काम किया जाएगा । रेगिस्तान का फैलाव रोकने के लिए २ लाख एकड़ भूमि में वन उगाये जाएँगे ।

### शिक्षा—

तीसरी योजना में ६ से ११ वर्ष की आयु के सब बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए ४ लाख अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता होगी । सब प्राथमिक स्कूल बेसिक स्कूलों में बदल दिये जायेंगे ।

सैंकण्डरी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या १५ प्रतिशत तक पहुँचा दी जायेगी जो फिलहाल १०-११ प्रतिशत है । तीसरी योजना के अन्त में सैंकण्डरी स्कूलों की संख्या १८००० पहुँच जायेगी, हायर सैंकण्डरी स्कूलों की संख्या ६००० हो जाने की उम्मीद की जाती है ।

तीसरी योजना में हायर सैकण्डरी और विश्वविद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा पर अधिक बल दिया जायेगा । तीसरी योजना के अन्त तक ११५०० स्नातक इंजीनियरिंग कालेजों से और १८६०० स्नातक पाली टेक्नीक कालेजों से निकलने लगेंगे, जिनमें भारत की इंजीनियरो और प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता पूरी हो जावेगी ।

#### स्वास्थ्य—

दूसरी योजना की समाप्ति तक १२६०० अस्पताल व दवाखाने बन चुके होंगे जिनमें १,६०,००० पलंगों की व्यवस्था होगी । तीसरी योजना में इनकी तादाद बढ़ा कर क्रमशः १४६०० और १,६०,००० कर दी जायेगी । २२ करोड़ व्यक्तियों को बी० सी० जी० के टीके लगाये जा चुकेंगे । तपेदिक के मरीजों के लिये ३० हजार पलंगों की व्यवस्था कर दी जाएगी ।

तीसरी योजना-काल में कुल १४,००० डाक्टर तैयार हो सकेंगे । तीसरी योजना में १६,००० डाक्टर तैयार किए जाएँगे । सन् १९६६ में कुल डाक्टर ८१००० होंगे । फिर भी ६,००० व्यक्तियों पर एक डाक्टर का अनुपात कायम रहेगा ।

#### रोजगार—

रोजगार के विषय में योजना आयोग ने कहा है कि बेकारी अल्पविकसित देश का चिह्न है और भारत में जनसंख्या की वृद्धि की तीव्र गति से यह समस्या और गंभीर बनी हुई है । अनुमान लगाया गया है कि जिन लोगों को केवल आंशिक काम मिला हुआ है उनकी संख्या १।१ करोड़ है । तीसरी योजना लगभग ६० लाख व्यक्तियों की बेकारी के साथ प्रारम्भ की जा रही है और इसमें १३५ लाख व्यक्तियों को काम दिये जाने की संभावना के बाद भी बेकारी की संख्या में १५ लाख की वृद्धि और हो जाने की आशंका है ।

कृषि की उन्नति से आंशिक रोजगारों की समस्या हल होगी, बेरोजगारी की नहीं । वाणिज्य में विकास में भी आंशिक रोजगार की ही समस्या हल होगी । बेरोजगारी की समस्या केवल उद्योगों से ही दूर की जा सकती है, लेकिन वह भी अभी पूर्णतः नहीं । इसलिए वर्यो तक कृषि व उद्योगों के निरन्तर विस्तार तथा उन्नति से ही बेरोजगारी की समस्या हल हो सकती है ।

बेरोजगारी कम करने के लिये आयोग ने निम्न नीतियाँ निर्धारित की हैं—(१) बड़े-बड़े उद्योगों के उत्पादन का विकेन्द्रीकरण किया जाए, (२) गांवों में प्रोमेसिंग उद्योग खोले जायें, (३) मानव श्रम के स्थान पर मशीनों का उपयोग वही किया जाये, जहाँ उसमें लागत कम आती हो अथवा समय बचता हो, (४) जिला स्तर पर बनाये गये विकास कार्यक्रमों में रोजगार की आवश्यकताओं के अनुरूप हेरफेर किये जायें

और (५) विशेष निर्माण कार्यक्रम आरम्भ किये जायें । इनमें छोटी मिचाई, भूमि की सफाई, भंडारण की रोक-थाम, वृक्षों की बुवाई, गाँवों में सड़को का निर्माण व मरम्मत आदि कार्य शामिल हैं ।

**सामाजिक सेवा—**

६ वर्ष से ११ वर्ष तक के उम्र के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देने का प्रबंध किया जायगा । इस उम्र के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या ६० म ८० प्रतिशत बढ़ जायगी । अनुमान है कि स्कूलों के छात्रों की संख्या सन् १९६०-६१ में ४ करोड़ १० लाख से बढ़ कर १९६५-६६ में ६ करोड़ हो जायगी ।

विज्ञान और द्रव्य की शिक्षा का भी विस्तार किया जायगा । इ जीनिवरी और द्रव्य विद्यालयों में तीसरी योजना के अन्तर्गत ५३,५०० छात्र भर्ती हो सकेंगे, जब कि दूसरी योजना में ३७,८०० होने हैं ।

रजिस्टर्ड डाक्टरों की संख्या भी ८४ हजार से बढ़ कर १ लाख ३ हजार हो जाएगी । अस्पतालों और दवाखानों की संख्या १२,६०० से १४,६०० और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या २८०० से बढ़ कर ५,००० हो जाएगी । सतत निरीक्षण केंद्रों की संख्या भी १,८०० से बढ़ कर ८२०० हो जाएगी ।

**कम आय वालों के लिए मकान—**

कम आय वाले लोगों और औद्योगिक बंधुवारियों के लिए मकान बनाने, गन्दों बस्तियों की सफाई और उनमें सुधार करने और मकानों के लिए जमीन लेने तथा उनका सुधार करने के कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा । मकान बनाने के लिए धन आवास वित्त निगमों द्वारा दिया जायगा ।

**स्थानीय विकास कार्य —**

देहाती क्षेत्रों में कुछ न्यूनतम सुविधाएँ उपलब्ध हों, इसके लिए तीसरी योजना में स्थानीय विकास का एक कार्यक्रम शामिल किया गया है । इसके अन्तर्गत जिन सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी वे ये हैं : (क) पीने के पानी की सफाई, (ख) प्रत्येक गाँव को सबसे पास की मुख्य सड़क या रेलवे स्टेशन से मिलाने के लिए सड़कों का निर्माण और (ग) गाँवों के स्कूल के भवन का निर्माण, जो सामुदायिक केंद्र और पुस्तकालय का काम भी देगा ।

**निजी उद्योगों के लिए अवसर—**

तृतीय योजना में निजी क्षेत्र के लिए पर्याप्त अवसर है । योजना की रूप-रेखा में यह स्पष्ट कहा गया है कि निजी उद्योगों के क्षेत्र में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि अधिक से अधिक उद्योगपति उद्योगीकरण के इन अव

सरो का लाभ उठाएँ जिसमें आर्थिक शक्ति को मुट्ठी भर लोगों के हाथ में केन्द्रित होने से रोका जा सके। इसके लिए छोटे उद्योगपतियों को विविध रूपों में प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करने की सिफारिश की गई है।

आय तथा संपत्ति में असमानताएँ कम करने के लिए टैक्स सम्बन्धी कदमों के महत्व पर भी बल दिया गया है।

**श्रमिक नीति—**

उद्योग में शान्ति कायम रखने और उत्पादन में रुकावट न आने देने के लिए पिछले १० वर्षों में सरकार ने हस्तक्षेप का अधिकार अपने पास रखा है, लेकिन अब उद्योगपतियाँ व श्रमिकों दोनों में यह भावना बढ रही है कि उनके झगड़ों का निबटारा आपस में ही हो जाना चाहिए, जिससे न केवल उद्योग में शान्ति रहेगी, बल्कि मजदूरों की कार्यकुशलता बढेगी तथा जीवन स्तर उन्नत होगा। इस दृष्टि से सन् १९५८ में एक अनुशासन संहिता अपनाई गई, जिससे हड़ताल और तालाबंदी आदि की घटनाओं में कमी हुई है। लेकिन पंच फ़ैसलो तथा समझौतों का परिपालन न किए जाने की शिकायतें जारी हैं। यदि ये जारी रहती हैं तो अनुशासन संहिता बेकार है। इसलिए समझौतों पर अमल कराने के लिए अलग तब कायम किया गया है। मजदूरों को शिक्षित करने तथा प्रबन्ध में उनकी हिस्सेदारी के कार्यक्रम में भी प्रगति की गई है।

तीसरी योजना में इन्हो से मिलती-जुलती नीतियाँ अपनाई जाएँगी। न्यायाधिकरणों तथा अदालतों के द्वार लटखटाने का रिवाज कम किया जाएगा, ऐच्छिक पंच फ़ैसले को बढ़ावा दिया जाएगा, वरस कमेटियों को मजबूत किया जाएगा और औद्योगिक मस्थानों में शिकायतें दूर करने के लिए एक उपयुक्त प्रणाली कायम की जाएगी। ट्रेड यूनियन प्रतिद्वन्द्वताओं को कम करने के लिए और कदम उठाए जाएँगे। श्रमिकों की शिक्षा के कार्यक्रम में पर्याप्त विस्तार किया जाएगा और प्रबन्ध में मजदूरों की हिस्सेदारी की योजना भी काफी बढाई जाएगी। परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न उद्योगों में वेतन निर्धारित करने के लिए वेतन बोर्ड कायम किए जाएंगे।

**विदेशी व्यापार—**

विकास वर्षों की बदौलत हाल के वर्षों में भारत का आयात बहुत बढ गया है। दूसरी योजना के पहले चार वर्षों में औसतन १०५० करोड़ रुपये का आयात रहा है जबकि निर्यात सिर्फ ६१० करोड़ रु० रहा है। दोनों में इतने बड़े अन्तर को दूर करने के लिए आयात यथासम्भव कम करने तथा निर्यात अधिक से अधिक बढाने के लिए कहा गया है और १० वर्षों के अन्दर-अन्दर विदेशी व्यापार में पूरा सन्तुलन कायम कर देने का लक्ष्य रखा गया है।

निर्यात बढ़ाने के लिये आयोग ने सुझाव दिया है कि जिन चीजों का भारत काफी बड़ा निर्यातक है उनका निर्यात अभी और बढ़ाया जा सकता है क्योंकि विदेशों में उनकी सारी माँग को भारत पूरा नहीं कर पाता है। इसलिए इन चीजों का उत्पादन इतना अधिक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है कि वे देश की बढ़ती हुई आवश्यकता की भी पूर्ति कर सकें और निर्यात के लिए भी उनकी अधिक मात्रा बच रहे।

आयोग ने कहा है कि अगर कभी प्रतिद्वन्द्व परिस्थितियों के कारण किसी चीज का उत्पादन घट भी जाए तो भी पेट पर पट्टी बाँध कर उसका निर्यात बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिये।

परम्परागत निर्यात की बढ़ाने के साथ साथ इजीनियरिंग, रासायनिक तथा धातुशास्त्र सम्बन्धी चीजों का निर्यात बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। तीसरी योजना में इन चीजों का निर्यात ५-६ गुना बढ़ जाने की धारणा व्यक्त की गई है।

निर्यात वृद्धि के लिये उत्पादन बढ़ाना ही काफी नहीं है, उत्पादित माल की लागत भी कम होनी चाहिये। इसके लिए सुझाव दिया गया है कि वर और मुद्रा सम्बन्धी नीतियों में हेरफेर करके उत्पादित माल का मूल्य प्रतियोगितात्मक रखा जाना चाहिये। इस प्रसंग में संकेत किया गया है कि भ्रान्तरिक स्वतंत्र के लिए बनाई गई चीजों पर उत्पादन शुल्क घटाकर इस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है।

आयोग ने निर्यात का क्षेत्र बढ़ाने के लिए भी कहा है। उसने कहा है कि हमें केवल राष्ट्रमण्डलीय देशों के साथ ही व्यापार बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये बल्कि पूर्व पश्चिम के सभी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये। इस प्रसंग में आयोग ने कुछ देशों के साथ राजकीय आधार पर होने वाले व्यापार को बहुत लाभदायक बताया है।

### मूल्य नीति—

१०,२०० करोड़ रुपये के भारी पूँजी विनियोग से भेंटगाई बह जाने की धाराका के बारे में आयोजना आयोग ने कहा है कि वस्तुओं के मूल्य अनेक परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। इसलिये चीजों के दाम अपेक्षाकृत स्थिर रखने के लिये चट्टेमुखी कदम उठाने होंगे। आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार टैंकम सम्बन्धी, मुद्रा सम्बन्धी और नियन्त्रण सम्बन्धी कदम उठाये जा सकते हैं।

अनाज, कपड़ा व चीनी के मूल्य न बढ़ने देने पर विशेष बल दिया गया है और इस प्रसंग में अमेरिका द्वारा दी गई १६० लाख टन अनाज की मदद पर सतोष व्यक्त किया गया है। उपयुक्त सरकारी कार्रवाई, राजकीय व्यापार तथा सहकारिताओं द्वारा वितरण से भी मूल्यों की रीब्याम का सुझाव दिया गया है। अनाज के दाम भी अन्य औद्योगिक और उपभोक्ता सामग्रियों के मूल्यों का ध्यान रख कर तय किए जाने की

सिफारिश की गई है। मसविरे में कहा गया है कि मूल्यों का प्रवाचनीय उतार-चढ़ाव हर हानत में रोका जाना चाहिए। मूल्यों का नियमन एक जटिल प्रश्न है, जिसमें अनेक विरोधी चीजों का समन्वय करना पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि मूल्यों का नियमन करने वाले उपायों को प्रभावशाली ढंग से और तालमेल के साथ काम में लाया जाए।

अन्त में आशा व्यक्त की गई है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना देश की अर्थ-व्यवस्था को स्वयंस्फूर्ति विकास की ओर काफी दूर तक ले जा सकेगी और चौथी योजना में अधिक तेजी से विकास के लिए आधार तैयार हो जाएगा।

योजना के लिए साधन—

दूसरी योजना में लगी कुल ६७५० करोड़ रु० की पूँजी की तुलना में तीसरी योजना में १०,२०० करोड़ रु० की पूँजी लगाने के लिए धरेलू साधन जुटाने का जी जान से प्रयत्न करना पड़ेगा। तीसरी योजना में राष्ट्रीय आय ५ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ने की आशा है। अधिक पूँजी लगाने के लिए इसी साधन से धन जुटाना होगा।

योजना का उद्देश्य यह है कि तीसरी योजना के अन्त में राष्ट्रीय आय का १४ प्रतिशत हमारी अर्थ-व्यवस्था में लगे। दूसरी योजना के अन्त में राष्ट्रीय आय का ११ प्रतिशत अर्थ-व्यवस्था में लगा होगा। इस समय राष्ट्रीय आय की वृद्धि की दर लगभग ८ प्रतिशत है। इस वृद्धि की दर को भी तीसरी योजना के अन्त तक बढ़ा कर ११ प्रतिशत करना होगा।

पहली दो योजनाओं की भाँति तीसरी योजना के आरम्भ के समय भी विदेशी मुद्रा कम रहेगी। विदेशी मुद्रा कौशल से धन लेने की आगे गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा दूसरी योजना के आरम्भ में वस्तुओं का जो मूल्य था उससे अब उनका मूल्य २० प्रतिशत अधिक है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए इस बात की जरूरत है कि ऐसे खर्च न किये जाएँ जिनसे मुद्रा स्फीति हो।

इसके विपरीत, अब जैसी स्थिति है वह पिछली योजनाओं के आरम्भ की स्थिति से बड़ी प्रकार से भिन्न है। पिछले दस वर्षों में उद्योग आदि में अधिक पूँजी लगायी गयी है। सिंचाई, विजली और परिवहन में भी काफी प्रगति हुई है। दूसरी योजना में, सरकारी क्षेत्र में, अनेक कार्यक्रम अभी पूरे हो किये जाने थे, जबकि तीसरी योजना में वे पूरे हो चुकेंगे और उनसे लाभ होने लगेगा। इस लाभ को आगे पूँजी के रूप में लगाने के लिये जमा होगा, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। दे दी गयी है, वे तीसरी योजना में और भी बढ़ेंगे और इनसे भविष्य में अधिक लाभ होगा। नए-नए उद्योग धंधे शुरू करने की क्षमता रखने वाले और प्रबन्ध का अनुभव रखने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है और वे अब अधिक संख्या में उदयमान हैं।

इस बात पर जोर दिया गया है कि योजना के लिये साधन जुटाने की समस्या को ऐसा नहीं मानना चाहिये, जैसे वह किसी स्थिर और निश्चित कोष से धन लेने की बात हो। एक हद तक अर्थ-व्यवस्था के साथ साथ साधन भी बढ़ते हैं। पिछले कुछ वर्षों में जो कठिनाइयाँ रही हैं, उनके बावजूद इतनी प्रगति हुई है कि भविष्य में पहले से अधिक प्रयत्न करना सम्भव हो गया है। गरीबी और कम बचत के विपाकत चक्र को नहीं तोड़ा जा सकता है जब पूरे साधन जुटाये जायें और जो लाभ होता रहे वह निरन्तर उत्पादन के लिये लगाया जाना रहे।

सरकारी क्षेत्र में तीसरी योजना में जो खर्च होगा उसके लिये धन जुटाने की योजना निम्नलिखित मारिणी में दी गयी है :—

	(करोड़ रु० में)	
	दूसरी योजना	तीसरी योजना
१. वर्तमान करो के आधार पर राजस्व में बचने वाला धन	१००	३५०
२. वर्तमान आधार पर रेनो में मिलने वाला धन	१५०*	१५०
३. वर्तमान आधार पर सरकारी उद्योगों में मिलने वाला धन	—†	४४०
४. सार्वजनिक ऋण	८००	८५०
५. घन्य बचत	३८०	५५०
६. भविष्य निधि आदि से मिलने वाला धन	२१३	५१०
७. अतिरिक्त कर और सरकारी उद्योगों में लाभ में बढ़ती से मिलने वाला धन	१०००	१६५०
८. विदेशी सहायता जिसकी बजट में व्यवस्था की गई है	६८२	२२००
९. घाटे की पर्य-व्यवस्था	११७५	४५०
जोड़—	४६००	७२५०

अतिरिक्त कर—

पाँच वर्ष की अवधि में १,६५० करोड़ रु० के अतिरिक्त कर लगाने का जो लक्ष्य है, उसकी पूर्ति योजना की सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। भारत में इस समय करो से राष्ट्रीय आय का लगभग ८.५ प्रतिशत भाग मिलता है। कर-उपलब्धि में सामान्य रूप से जो बढ़ती होगी और तीसरी योजना में जो अतिरिक्त कर लगाए

\* यात्रियों के किराए और माल भाड़े में हुई बढ़ती को मिलाकर

† ऊपर (१) में सम्मिलित



जाएँगे, उनसे यह सख्या बढ़कर ११ प्रतिशत हो जायगी। विकास कार्यों की तज गति को देखने हुए इसको बहुत अधिक भार नहीं माना जा सकता। फिर भी १६५० करोड़ के अतिरिक्त कर लगाने का सख्य पूरा करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। इस कर राशि में से एक तिहाई के कर राज्य लगाएँगे।

तीसरी योजना के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों प्रकार के कर बढ़ाने और सरकारी उद्योगों का लाभ बढ़ाने की जरूरत होगी। जहाँ तक आय कर और निगम-कर का प्रश्न है, कर प्रशामन का कड़ा करके उनकी बमूली बढ़ानी होगी, कम्पनियों के लुच के ध्योरे पर नज़र रखनी होगी और एम कदम उठाने होंगे, जिनसे वे कर से बच न सकें। अप्रत्यक्ष करों और वस्तुओं के मूल्य में बढ़ती होने में निश्चय ही लागत और मूल्य दोनों बढ़ेंगे, पर यह ऐसा त्याग है जो करना ही पड़ेगा।

घाटे की अर्थ व्यवस्था—

अप्रत्यक्ष करों और घाटे की अर्थव्यवस्था से मूल्य पर जो असर पड़ता है, उसमें भेद करने की आवश्यकता है। अप्रत्यक्ष करों द्वारा मूल्य बढ़ जाने से मुद्रा-स्फीति की सम्भावना कम रहती है जबकि घाटे की अर्थव्यवस्था से यह सम्भावना और बढ़ती है। अतः यह विचार है कि तीसरी योजना में केवल ५५० करोड़ रु० की घाटे की अर्थ व्यवस्था की जाए जबकि दूसरी योजना में १,१७५ करोड़ रुपये की घाटे की अर्थव्यवस्था की गई थी।

विदेशी मुद्रा—

तीसरी योजना में बड़ी तेज गति से उद्योगों की स्थापना के कारण विदेशी मुद्रा की काफी मात्रा में आवश्यकता पड़ेगी। यह अनुमान है कि योजना में १,६०० करोड़ रु० विदेशी मुद्रा के रूप में व्यय होंगे। इसके अलावा लगभग २०० करोड़ रु० के पुर्जों आदि भी आयात करने की जरूरत पड़ेगी जिससे देश में मशीनों सामान का उत्पादन बढ़ाया जा सके। इस प्रकार योजना के लिए २,१०० करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी।

योजना में नए कामों के लिए जितनी विदेशी मुद्रा की जरूरत होगी उस छोटा भी दिया जाए तो भी तीसरी योजना की अवधि में पिछले ऋणों और व्याज की भदा-यगी के कारण ५०० करोड़ रु० की जरूरत रहगी। इस प्रकार तीसरी योजना में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता बढ़कर २,६०० करोड़ रु० हो जायगी। इस जोड़ में वह ६०० करोड़ रु० भी शामिल किए जा सकते हैं जो ५० एम-४८० के अन्तर्गत अम-रोना में मिलेंगे। इस प्रकार तीसरी योजना की कुल जरूरत ३२०० करोड़ रु० हो जाती है।

विदेशों से सहायता के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । योजना का रूप ऐसा रखना होगा कि उसमें घटबढ़ की जा सके । सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में कार्यक्रम इसी आधार पर शुरू किए जा सकते हैं कि बाहर से निश्चित रूप से क्या सहायता मिल सकती है । इसके लिए कार्यक्रम पहले से तैयार करके रखने होंगे, जिससे आवश्यक विदेशी मुद्रा मिलते ही उन्हें पूरा किया जा सके । विदेशी मुद्रा के उपयोग में देर करने से तीसरी योजना में उत्पादन बढ़ाने का कार्यक्रम गड़बड़ में पड़ जायगा ।

भुगतान के विषय में देश को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है वे कोई स्थायी या आकस्मिक नहीं हैं बल्कि हमारी विकास की क्रिया का ही एक अंग हैं कुछ समय तक अत्यधिक आयात की जरूरत बाहरी सहायता से पूरी की जा सकती है । परन्तु यह याद रखना जरूरी है कि यह असन्तुलन धीरे-धीरे कम होता जाय और कुछ समय बाद समाप्त हो जाय । इसका यह अर्थ नहीं है कि एक खास अवधि के बाद विदेशों से धन का आना रोक दिया जाएगा । व्यापार में लगी पूँजी आती ही रहेगी और आती ही रहनी चाहिए, परन्तु विशेष सहायता कार्यक्रमों पर निर्भरता धीरे धीरे कम हो जानी चाहिए और कुछ समय बाद समाप्त हो जानी चाहिये ।

निजी क्षेत्र में पूँजी केवल संगठित उद्योगों, खान, बिजली और परिवहन में ही नहीं लगी हुई है, बल्कि कृषि, ग्राम और लघु उद्योगों, दहात और बाहरी म मकान बनाने में भी लगी हुई है ।

तीसरी योजना में निजी पूँजी मुख्यतः बड़े और मध्यम उद्योगों में बढ़ाई जाएगी । दूसरी योजना में बड़े और मध्यम उद्योगों में ७०० करोड़ ६० की पूँजी लगाई गयी जबकि तीसरी योजना में १,०५० करोड़ २० की पूँजी लगाने का विचार है । अन्य क्षेत्रों में अधिक पूँजी लगायी जाएगी, परन्तु अनुपात से वह कम होगी ।

योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र का उद्योगों में फैलने का काफी अवसर है । इसका मुख्य कारण यह है कि अब तक की पंचवर्षीय योजनाओं के परिणामस्वरूप उद्योगों के बढ़ने के अवसर ज्यादा हो गये हैं । इन विषय में जो नीति है उसका मुख्य लक्ष्य यह है कि इन अवसरों से छोटे और मध्यम दों के उद्योगपति लाभ उठाएँ और आर्थिक शक्ति गोड़े से लोगों के हाथ में वितरित होने की प्रवृत्ति पर शुरू में ही अंकुश लग जाए ।

### जनता को लाभ

तृतीय पंचवर्षीय योजना से जनता को प्रत्यक्ष लाभ इस भाँति मिल सकेगा—

(१) एक करोड़ ३५ लाख बेकारों को रोजगार मिलेगा ।

(२) छः से ग्यारह वर्ष के प्रत्येक बच्चे की निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ।

- (३) घनाज का उत्पादन बढ़ने से प्रति व्यक्ति को प्रति दिन १५ औंस गेहूँ, चावल और तीन औंस दाल मिल सकेगी ।
- (४) प्रति व्यक्ति को प्रति वर्ष १७-५ गज मूतो कपड़ा सप्लाई किया जा सकेगा ।
- (५) दो हजार नये अस्पताल खुलने से इलाज कराने में अधिक आसानी होगी ।
- (६) ग्रामों को जनता की पानी और मफाई की व्यवस्था तथा पास के स्टेशन या कस्थे तक सड़क ।
- (७) १५ हजार अन्य ग्रामों तथा कस्थों को बिजली मिलेगी ।
- (८) प्रत्येक गाँव में स्कूल और पुस्तकालय बनेगा ।

### तृतीय योजना—एक दृष्टि—

तीसरी योजना के कुछ मोटे लक्ष्य यह निर्धारित किए गए हैं कि खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा कर दस साठे दम करोड़ टन वार्षिक कर दिया जाये, इस्पात उत्पादन की क्षमता १ करोड़ टन हो जाये, विद्युत् उत्पादन की क्षमता ५८ लाख किलोवाट से बढ़कर १ करोड़ १८ लाख किलोवाट हो जाये, १ करोड़ ३५ लाख और व्यक्तियों के लिये रोजगार का प्रबंध किया जाये, दल के तमाम गाँवों को सामुदायिक विकास योजनाओं और सहकारी समितियों के अन्तर्गत ले आया जाय, ६ से ११ वर्ष तक की उम्र के तमाम बच्चों के लिये निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाये और तमाम देहाती क्षेत्रों में पीने का शुद्ध पानी और दूसरी न्यूनतम सुविधायें सुलभ की जायें । तीसरी योजना के प्रारूप में कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई है । राजकीय और निजी दोनों क्षेत्रों में २,४५० करोड़ रुपये की राशि रखी गई है जो दूसरी योजना की राशि से काफी अधिक है । दूसरी योजना के काल में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है, किन्तु वह दल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अभी काफी नहीं है और देश की अभी भी विदेशों से अन्न का आयात करना पड़ रहा है । कृषि उत्पादन पर विशेष ध्यान देकर देश को इस सज्जाजनक स्थिति का जल्दी से जल्दी अन्त करना ही चाहिये ।

तीसरी योजना के प्रारूप में उद्योग और खनिज विकास और सामाजिक सेवामों के लिये बड़ी हुई धनराशि की व्यवस्था की गई है । उद्योग और खनिज विकास के लिये तीसरी योजना में राजकीय क्षेत्र के लिये १,५०० करोड़ और निजी क्षेत्र के लिये १,००० करोड़ की राशि रखी गई है । सामाजिक सेवामों की राशि को ८६० करोड़ से बढ़ाकर १,२५० करोड़ कर दिया गया है । विकास की रफ्तार को तेज करने के लिये तीसरी योजना का आकार स्वभावतः दूसरी की अपेक्षा बड़ा होगा और विभिन्न मदों के लिये बड़ी हुई धनराशि की व्यवस्था करनी होगी ।

तीसरी योजना के साधन जुटाने के लिए १,६५० करोड़ रुपया प्रतिरिक्त करो द्वारा संग्रह करने की कल्पना की गई है। इसमें राजकीय उद्योगों की आय भी शामिल होगी। जनता पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करो का भार काफी बढ़ा हुआ है। अतः प्रतिरिक्त करा की बात जनता के लिए विशेष रूप से चिन्तनीय होगी। यह आज नहीं कहा जा सकता कि इस साधन से इतनी बड़ी राशि का संग्रह कहां तक व्यावहारिक होगा और उसकी लोकमानस पर क्या प्रतिक्रिया होगी। तीसरी योजना में घाटे की राशि को १,१७५ करोड़ से घटा कर ५५० करोड़ कर दिया गया है। यह एक सुदि-माती का निर्णय है। कारण घाटे की अर्थ-व्यवस्था कीमतों की बढ़ाने में सहायक होती है। दूसरी योजना के काल में कीमतों में चिन्ताजनक वृद्धि हुई है और इस कारण देश को अनेक विकट समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में देश की भविष्य में अधिक सतर्क रहना होगा। तीसरी योजना विदेशी सहायता की उपलब्धि पर भी काफी हद तक निर्भर करेगी। विदेशी सहायता की राशि २,६०० करोड़ रुपया अनुमान की गई है। देश को तीसरी योजना के काल में बेरोजगारी की समस्या का भी सामना करना पड़गा, जो काफी विकट बनी हुई है। दूसरी योजना के अन्त में ६० लाख व्यक्ति बेरोजगार रहेंगे। राष्ट्रीय आय और व्यक्ति की औसत आय में जो भी वृद्धि हुई हो, किन्तु बेरोजगारी का व्यापक रूप में रहना देश के लिए चिन्ता का ही विषय होगा।

### कृषि सुभाष—

भारत की प्रथम पञ्चवर्षीय योजना में कृषि की प्रथम स्थान दिया गया था। दूसरी योजना में इसका स्थान द्वितीय था, किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि उससे सम्बद्ध विभिन्न मद्दों के लिये कुछ कम धन राशि रखी गयी थी। तृतीय पञ्चवर्षीय योजना में उद्योग और कृषि के समुलित विकास की बात कही गयी है। इससे स्पष्ट है कि कृषि पर योजना के पाँच वर्षों में विपुल ध्यान दिया जायगा। जो देश मुख्यतः कृषि पर ही निर्भर हो उसे यह ध्यान करना भी चाहिये, परन्तु इसके साथ यह देखना भी आवश्यक है कि वह तरीके से किया जा रहा है और फलदायी सिद्ध हो रहा है अथवा नहीं।

ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था तथा ग्राम जीवन और कृषि से सम्बद्ध विभिन्न साधन स्रोतों के संगठन का बहुत निकट का सम्बन्ध है। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था अस्तुतः उन्हीं संगठन पर ही निर्भर करती है। आज ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में जो दोष दृष्टिगोचर होता है और किसान सुखी एवं समृद्ध प्रतीत नहीं होता उसका एकमात्र कारण उक्त संगठन की क्षमिता है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि उसे मजबूत बनाया जाय।

ग्राम और कृषि जीवन के जिन विविध अंगों का ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में सम्बन्ध है, उनमें पशु-पालन, ग्रामोद्योग, मिर्चार्त की व्यवस्था, ऋण प्रवर्ध, बीज तथा खाद वितरण और माल की बिक्री आदि सभी आते हैं। पिछली दो पचवर्षीय योजनाओं में उन सभी मदों के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की गयी थी और इस बार तृतीय योजना में उन मदों को बहुत महत्व दिया गया है। पर अनुभव में यह स्पष्ट है कि केवल महत्व देने और धन की व्यवस्था कर देने में ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था उन्नत नहीं हो सकती। उसके लिये यह देखना होगा कि जो रुखा मुख किया जा रहा है वह कहीं अध्ययित तो नहीं हो रहा अथवा इस प्रकार तो नहीं लग रहा है कि उसमें कुछ फल की प्राप्ति न हो सके। इसके प्रतिरिक्त इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आदिमियों सहित सब माधन लोगों का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके।

सरकार कृषि क्षेत्र में जितना खयाल लगा रही है उस अनुदान में वह पन्द्रहवीं नहीं हो रहा, यह बात अत्यन्त स्पष्ट है। हमलिये और खयाल लगान में पूर्व यह विचार किया जाना चाहिये कि इसका क्या कारण हो सकता है। कारण का पता स्थिति के अध्ययन में ही लग सकता है। हमलिये श्री एम० ए० पाटिल ने दिल्ली में कृषि विषयक आर्थिक अनुसंधान केन्द्र का उद्घाटन करते हुए उक्त अध्ययन पर जो बल दिया है वह सर्वथा उचित है। इस अध्ययन में जहाँ वर्तमान ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के दोष दृष्टिगोचर हों सबके वहाँ उस उन्नत करने के लिये नयी नयी प्रेरणाएँ और सुझाव भी प्राप्त हो सकेंगे।

### तृतीय योजना की सफलता के लिये प्रशासनिक कुशलता पर बल

तीसरी योजना के समविदे में नीति सबधी वक्तव्य में यह भी कहा गया है कि सरकारी उद्योगों का संचालन खर्च कम में कम और आय अधिक से अधिक करने की दृष्टि में होना चाहिए तथा सब स्तरों पर प्रशासन में ईमानदारी और काम की शीघ्र निबटाने की भावना होनी चाहिए। प्रशासन में कुशलता खान के लिए आयोग ने सुझाव दिया है कि मंत्री, मन्त्रि तथा विभागीय अध्यक्ष सब स्तर पर लोगों के लिए काम निश्चित कर दिया जाना चाहिए और उन्हें बतल दिया जाना चाहिए कि उन्हें समुक्त समय में वह काम पूरा करना है। एक बार नीति निर्धारित कर दिए जाने के बाद उस पर समन का काम उसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर पूर्णतः छाड़ दिया जाना चाहिए। प्रशासनिक व्यक्तियों का उचित टय में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, दैनिक काम की जल्दी निबटारा जाना चाहिए, जिसके लिए प्रशिक्षणों को आमान करना जरूरी है। जिन कर्मचारियों का काम जनता से सम्बन्धित है, उनमें ईमानदारी तथा सौजन्य की अत्यन्त आवश्यकता है।

अनुत्पादन निर्माण कार्यो में अधिकतम उत्पादन की निपारिण करने हुए आयोग ने कहा है कि ठेकेदारों पर बहुत अधिक निर्भर नहीं किया जाना चाहिए। जहा

मम्ब हो वहाँ विभागीय आधार पर काम कराया जाना चाहिए और विभागीय श्रमिकों को उनके काम के हिसाब से मेहनताना दिया जाना चाहिए। श्रमिकों की सहकारी संस्थाओं तथा ऐच्छिक संगठनों को निर्माण कार्य करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

### जनता का सहयोग

आयाग के प्रस्तावों में जनसहयोग के क्षेत्र में ऐच्छिक संगठनों के महत्व को स्वीकार किया गया है। इनके लिए तीसरी योजना में १० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में पहली दोनों योजनाओं की अपेक्षा कृषि उत्पादन में वृद्धि की रफ्तार दुगुनी रखी गई है। इसके लिए सिंचाई, उपजाऊ मिट्टी की बहन से रोकने, खाद आदि के निर्माण में ग्रामीणों के सक्रिय सहयोग की जरूरत होगी। इसलिए गांवों में काम करने की इच्छा रखने वाले हर व्यक्ति को काम दिया जाना चाहिए और उत्पादन बढ़ाने में उपलब्ध मनुष्य शक्ति का अधिकतम प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए मुभाव दिया गया है कि देहाती लोगों के हर विकास खंड में किए जाने वाले कार्यों का प्रभु बनाया जाना चाहिए, फिर उस गांव-कार्यक्रम में विभक्त किया जाना चाहिए और इस प्रकार सब परिवारों को उसकी जानकारी दी जानी चाहिए।

योजना के कार्यक्रमों को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए विद्यालयों तथा कालेजों में और अधिक योजना मंच कार्यक्रम करने तथा कर्मीय व राज्य सरकारों के प्रचार कार्यक्रमों को बढ़ाने का मुभाव दिया गया है।

—

### STANDARD QUESTIONS

1. Explain clearly the principal Objectives of the Third Five Year plan. How our country is likely to be benefitted by them ?
2. Bring out clearly the salient features of the Third Five Year Plan.
3. Write an essay on "Priorities under the Third Five Year Plan."
4. Attempt a critical note on the essential features of the Draft outline of the Third Five Year Plan. Have you any suggestions to offer ?

# UNIVERSITY OF SAUGAR

B Com Preliminary Exam 1960

Economic Problems of India

GROUP II PAPER II

Time—3 hrs

Max Marks —100

*Answer any five questions All questions are of equal value*

1 Mention the causes and economic effects of endless sub division and fragmentation of land in India Discuss remedial measures

2 How did the problem of Rural indebtedness become severe in India ? What has been its effect on India's agricultural economy ?

3 Examine the role of co operative movement in Agricultural Credit in India

4 The Indian moneylender holds its own in Agricultural Finance Discuss

5 'The Community projects and Rural Extension Services are expected to revitalise the Indian villages and give a new life to the rural population' Discuss

6 Discuss the development of Iron and Steel or Sugar industry in India

7 Discuss the main problems facing the Indian Cotton or Jute industry

8 How far the establishment of the Industrial Finance Corporation has been helpful in solving the problem of long term finance for industries in India ? Discuss

9 Discuss the problem of landless labourers in India and suggest measures for solving the problem

10 Discuss the population problem in India

## VIKRAM UNIVERSITY

B Com (Part II) Three Year Degree Course Exam 1960

First Paper—Economic Problems of India

(1) What is an economic holding ? How would you judge whether a holding is an economic or uneconomic one ?

(2) 'The Indian agriculturist is born in debt, lives in debt and dies in debt' Comment

(3) How far is it true to say that credit is only a part of co-operative economic development ?

(4) Review the present and future prospects of sugar industry

(5) What are the objectives of the Industrial Finance Corporation ? Estimate its contribution to the provision of Industrial Finance

(6) What do you understand by Co operative Farming ? Does it increase the efficiency of agriculture ?

(7) Trace the history of Labour Movement in India

(8) What are the defects of rural banking in India ? In What directions have they been remedied ?

(9) Describe the essential features of Decimal Coinage ? what are the general effects of the introduction of Nava Paisa

## VIKRAM UNIVERSITY

### B Com (Part II) Three Year Degree Course

#### Supplementary Examination, 1960

### APPLIED ECONOMICS AND PLANNING

#### First Paper -Economic problems of India

Attempt any five questions All questions carry equal marks

1 Account for the low agricultural productivity in India

2 Examine the measure for the consolidation of holdings  
What is the progress in this direction in your State ?

3 Analyse the causes of rural indebtedness in India To what extent has this problem been solved successfully ?

4 The establishment of credit societies in the villages is a sine qua non of the organisation of credit in the context of planned investment in the development schemes ? Explain

5 Review the present position and the future prospects of the iron and steel Industry

6 What are the agencies providing industrial finance ? Describe the working of any one principal agency

7 What are community development projects and what are their economic consequences ?